विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन

खण्ड 1

प्रारम्भिक तथा विकास मॉडल

II Meaning of 'Under-Developed' Country
'कम-विकसित' देश–परिभाषा :

कम विकसित देश किसे कह सकते हैं और किसे हम उन्नत या विकसित देश कह सकते हैं, इसमें अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद हैं इस संबंध में हम उचित परिभाषा देने से पहले 'कम-विकसित' होने के माप-दण्ड तथा कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करें

1 साइमन कुजनेट्स :

कुजनेट्स के अनुसार कम-विकसित देश व विकसित देशों में वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जा सकता है

(i) "प्रथम, 'कम विकसित' देश वे देश हैं जो वर्तमान तकनीकी ज्ञान व जानकारी के अनुरूप वाछित उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते" अगर हम इस परिभाषा को मानें तो हर देश कम-विकसित हो जायेगा क्योंकि कोई भी देश क्षमतानुसार उत्पादन नहीं कर पाता

(ii) दूसरे, 'कम विकसित देश वे देश हैं जिनमें आर्थिक उन्नति के स्तर किसी अन्य उन्नत देश के स्तर से नीचे हों'
इस परिभाषा के अनुसार केवल एक देश को छोड़कर अन्य समस्त देश कम-विकसित देश हो जायेंगे

(iii) तीसरे, 'एक कम विकसित देश वह देश है जो अपने देश की बहुत बडी जनसंख्या को उचित जीवन स्तर प्रदान करने में असफल होता है तथा जिसमें देश की बहुत बडी जनसंख्या को गरीबी व कमी का सामना करना पडता है'
कुजनेट्स इस परिभाषा को उचित मानते हैं

2. प्रो. जे. के मेहता

प्रो जे के मेहता विकसित व कम-विकसित देशों में Biological organic

---

1. Simon Kuznets : 'Under-developed Countries and the Pre-Industrial phase in the Advanced Countries —an attempt at Comparision. of : A. N Agarwal and S P. Singh. Economics of Under-developed Countries.' P. 135-153.
2. J. K. Mehta . Foreword to H C. Gupta's book on "Problems and Process of Economic policies in under-developed Countries" p. (ii) (iii)

growth (जीवन विकास) के आधार पर वर्गीकृत किया उनका कथन है कि हर जीव या चेतनायुक्त पदार्थ 'उत्पत्ति, विकास, ह्रास तथा अन्त' के क्रम से गुजरता है

> 'कम विकसित देश एक बच्चे की भाँति है जो पूर्ण रूप से विकसित नही है परन्तु विकासशील है,' जबकि, 'एक विकसित देश अब पूर्ण रूप से विकसित है और विकास नही कर रहा है'

उपरोक्त परिभाषा की निश्चित ही आलोचना की जा सकती है क्योंकि यह कहना गलत होगा कि विकसित देश वे हैं जिनमे विकास बन्द हो गया है

अपनी इस परिभाषा के साथ प्रोफेसर मेहता ने दो और मुख्य बाते कही हैं

(i) एक कम विकसित देश हमेशा विकासशील ही नही होता कभी-कभी बीच-बीच में विकास रुक सकता है परन्तु 'युवा अवस्था का जोश' उस देश को विकास पथ पर अवश्य ले जाएगा

(ii) वैसे तो हर विकसित देश स्थैगिक अवस्था को पहुँच कर समाप्त हो सकता है, परन्तु तकनीकी ज्ञान वृद्धि तथा विज्ञान मे उन्नति के कारण यह बुढापा अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है

3 B M Niculescue बी एम निक्यूलेसक्यू :

श्री निक्यूलेसक्यू के अनुसार हर देश के विकास की एक सीमा होती है हर देश U S A की भाँति उन्नत नही हो सकता जब तक कोई देश अपने विकास की चरम सीमा तक नही पहुँच जाता तब तक वह देश कम विकसित समझा जाना चाहिए और जब वह देश इस सीमा तक पहुँच जाए (चाहे वह U S A के बराबर पहुँच पाए या नही) वह विकसित समझा जाना चाहिए उन्होंने कहा

> 'यह अजीब बात होगी कि एक पूर्ण विकसित वयस्क खरगोश को कम-विकसित माना जाए केवल इसलिए कि हाथी उससे बहुत बडा होता है'

4 Oskar Lange आसकर लैंज

आसकर लैंज के अनुसार

> एक कम विकसित देश वह है जिसमे पूँजी की मात्रा इतनी नही है

B M Niculescue : 'Under-developed, Backward or Low Income Economic Journal, Sept 1955 p 546-48.

Oskar Lange : Essays in Economic Planning p. 33.

कि वह वर्तमान श्रमशक्ति का वर्तमान तक्नीकी स्तर पर पूर्ण उपयोग नही कर पाता

5 Ragner Nurkse रेगनर नर्क्स

नर्क्स भी उन देशो को कम विकसित मानते हे जिनमें प्राकृतिक साधनो व जनशक्ति को पूर्ण उपयोग करने के लिए पूंजी की कमी हो परन्तु वे यह कहते हैं कि "पूँजी विकास के लिए आवश्यक तो हैं परन्तु उसका होना ही पर्याप्त नही होता"

6 Dr Eugene Staley डा० यूजीन स्टेली

कम विकसित देश वे हैं जिनमे व्यापक गरीबी है जो कि किसी अस्थाई सकट के कारण नही होती वरन दीर्घस्थाई कारणो मे मौजूद रहती है

7-8-9. U N-O, Meier & Baldwin, Benjamin Higgins
संयुक्त राष्ट्र, मीयर तथा बाल्डविन, बेन्जामिन हिगिन्स.

इन्होने कम विकसित देश उन्हे कहा है जो कुछ जाने माने विकसित देश (U. S A कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिमी योरोप व आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड) के अनुपात में कम आय उत्पन्न करते हैं और जहाँ प्रति व्यक्ति आय भी कम हैं

10 Walter Krause वाल्टर क्रोंज

कम विकसित देश वह है जहाँ विकसित देशो के अनुपात मे आम जनता के उपभोग व जीवन-यापन के स्तर नीचे है

11 Bauer and Yamey . बायर तथा यामें

कम विकसित देश वे हैं जहा तक्नीकी व वैज्ञानिक उन्नति के फल को कृषि व

Ragner Nurkse : Capital Formation in under-Developed countries p 1.
Eugene Staley The Future of Under-developed countries
U N. O : U N Measures for Economic Development.
Meier & Balwin Economic Development p 2 6
Benjamin Higgins Economic Development 4-7
Walter Krause . Economic Development : Wadsworth Co. p 6

1. P.T. Bauer and B S Yamey. The Economies of Under-developed Countries · p. 3.

उद्योगो में वडे पैमाने पर नही श्रपनाया गया हो इन देशा मे 'जीवन निर्वाह' स्तर पर अधिकाश उत्पादन होता है यहा के बाजार सकुचित होत हैं औद्योगिक उन्नति सापेक्षिक रुप से महत्वहीन रहती हैं इन देशों में सम्पूर्ण अफ्रीका पूर्ण एशिया (जापान को छोडकर) पूर्ण दक्षिणी अमेरिका (अर्जेन्टाइना को छोडकर) पूर्वी योरोप तथा दक्षिणी योरोप को शामिल कर सकते हैं इस प्रकार मे विश्व की तीन चौथाई जनसख्या इन देशो में रहती हैं

12 Jacob Viner जेकब वाइनर

यह वे देश होते हैं जहाँ प्राकृतिक साधनों पूजी व श्रम शक्ति का उपयोग करके जनसख्या का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सकता हैं तथा अगर उस देश का जीवन स्तर ऊँचा हो तो और जनसख्या को उस देश में वढाया जा सकता है इस प्रकार स वाइनर का आशय है कि कम विकसित देश वे हे जहाँ प्रतिव्यक्ति आय कम है और वढाई जा सकती है

> **इस प्रकार से हमने भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियो द्वारा दी गई परिभाषाओ का अध्ययन किया. पुस्तक के वर्तमान लेखक एक व्यापक परिभाषा, कम-विकसित देशो की विशेषताओ को अध्ययन करने के पश्चात् उन्हीं विशेषताओ के आधार पर देंगे**

III कम विकसित होने के माप दण्ड

Measurement of under-development

1. Low Per-capital Income ? **क्या निम्न प्रति व्यक्ति आय कम विकसित होने का मापदण्ड है?**

विश्व मे आज विकसित व कम विकसित देशो की आय में बहुत अधिक अन्तर है आज दुनियाँ के 2/3 व्यक्ति 500 रु० वार्षिक से कम पाते हैं

2. Jacob Viner : Economics of Development : A. N. Agarwal & S P Singh op. it-p. 9-31.

इस सबंध को निम्नलिखित तालिका आधुनिकतम स्थिति दर्शाती है —

देश का वर्गीकरण	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय डालरो मे	देशो की सख्या	विश्व का प्रतिशत क्षेत्रफल	विश्व की प्रतिशत जनसख्या	विश्व की आय का प्रतिशत
(A) उच्च आय के देश	750 डालर से ऊपर	36	43 6	28 6	82 00
(B) मध्यम श्रेणी आय के देश	300—750	33	8 2	6 5	5 4
(C) कम आय के दश	100—300	53	21 4	14 1	4 8
(D) बहुत कम आय के देश	0—100	36	26 4	50 8	7 8
		158	100 00	100 00	100 00

Economic Times 1 Feb 1968

$ one = Rs 7 50

अकेले सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका विश्व की 41 प्रतिशत आय का मालिक है जब कि अन्य देशों मे यह वितरण इस प्रकार है

U S A	41 %
पश्चिमी योरोप	22 %
U. S S R	11 %
अन्य योरोपीय देश	6 %
दक्षिणी अमेरिका	4 %
अफ्रीका	2 %
एशिया	11 %

1968 में (डालर में)

कुवैत (4000), सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका (3847), स्वीडेन (2801), कनाडा-(2686), स्वीटजर लैड (2519), डेन्मार्क (2340), भारत (70)

1935 में

आय	देश
1200—1500	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लम्जेम्बर्ग

For 1968 Figures Life 11-November 1968 P 74 80

1965 figures : Kindlebergu op cit

with adjustment on the basis of latest available data in newspapers.

1000—1250	यू० के०, पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी, नार्वे, वेल्जियम, फ्रान्स
800—1000	आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, यू एस एस आर
500—800	आस्ट्रिया, प्यूरटोरिको, वेनेजुएला, इजराइल, आइरलैंड
500 के लगभग	जापान, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेन्टाइना, चिली
350—500	ट्रिनीनाड, होवेगो, माल्टा, जमाइका, पनामा, ग्रीस, साइप्रस
200—300	कोस्टारिका मेक्सिको, स्पेन, पुर्तगाल, बारबेडोस, यूगोस्लाविया, कोलम्बिया, ब्रिटिश गियाना, सीरिया, अलजीरिया, मलाया, मारीशस, फिलीपीन्स
150—200	होन्डूरास, टर्की, घाना एलसालेवडार रोडशिया, गोटेमाला
100—150	पीरु, इक्वोडार ट्यूनीसिया, जार्डन, ब्राजील, लंका, फारमोसा, मोरक्को, पराागुए
75—100	सूडान, थाईलैंड केन्या
0— 75	भारत, कांगो, नाइजीरिया, युगांडा, पाकिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया व अन्य समस्त देश

क्या प्रति-व्यक्ति आय विकास या कम विकास की निशानी है ?

Benjamin Higgine ने 500 डालर से कम प्रतिव्यक्ति आय पाने वाले देशों को कम विकसित माना है जबकि W. W. Rostow ने 200 डालर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम आय वाले देशों को कम विकसित देश माना है

प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय अवश्य ही भिन्न-भिन्न देशों की उन्नति की अवस्था का मापदण्ड है परन्तु हमको इससे अनावश्यक रूप से व्यापक निष्कर्ष नही निकालना चाहिए (We sold not read too much between lines) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निम्नलिखित कारणों से सापेक्षिक तुलना का सही मापदण्ड नहीं होती

(i) कम विकसित देशो मे देश के बडे भाग मे बहुधा 'Nonmonetized transaction' या अदला बदली सौदे होते है इस कारण राष्ट्रीय आय जितनी होती है उससे कम आँकी जाती है

(ii) ग्रामीण क्षेत्र मे बहुत से उत्पादनकर्ता स्वय अपनी वस्तुओं के उपभोगकर्ता होते है इस कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुयें राष्ट्रीय आय में आंकी नही जाती, और राष्ट्रीय आय कम आंकी जाती है

(iii) इन देशों में शिक्षा की कमी के कारण बहुत से कृषक व छोटे उत्पादन कर्ता Input output का हिसाब नहीं रख पाते उसी प्रकार से व घिसावट (Depreciation) का हिसाब नहीं रखते

(iv) सबसे प्रमुख बात तो इस सबंध में यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय तुलना इसलिए कठिन हो जाती है कि विश्व के भिन्न-भिन्न देशों की विदेशी विनिमय दरें आन्तरिक मूल्य स्तरों के अनुरूप नहीं होती अगर समस्त देशों की विदेशी विनिमय दरें Fluid होती या लचीली होती तो वास्तविक स्थिति को दर्शाती

(v) कई देशों में (जैसे कुवैत) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तो अधिक है परन्तु अन्य हर दृष्टिकोण से वे कम विकसित हैं

(vi) भिन्न-भिन्न देशों में राष्ट्रीय आय आंकने की अलग अलग सांख्यकीय पद्धतियाँ होती हैं कम विकसित देशों में बहुत त्रुटियाँ भी होती हैं

(vii) कम विकसित देशों में कुछ लोग करों से बचने के लिए उत्पादन व आय छिपा जाते हैं

(viii) Max Millikan का कथन है कि 1950 में जहाँ एशिया के भिन्न-भिन्न देशों की राष्ट्रीय आय प्रतिव्यक्ति 58 डालर आंकी गई थी वास्तव में 200 डालर रही होगी और Hagan का कथन है कि बर्मा की राष्ट्रीय आय लगभग 300% से कम आंकी गई

(ix) इन देशों में बहुत सा श्रम बगैर वेतन के कार्य करता है (जैसे स्वयं का मकान बनाना या परिवार के सदस्यों द्वारा ही कार्य करना) इससे भी राष्ट्रीय आय के अनुमान कम रहते हैं

इस सब कठिनाइयों के होते हुए भी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आंकड़े सापेक्षिक विकास की स्थिति को जानने के लिए अत्यन्त सहायक होते हैं Boitinski (वोईटिन्सकी) का कथन है कि किसी देश के समस्त भागों में द्रव्य की क्रय-शक्ति एक तो नहीं होती है फिर भी हम एक ही प्रति व्यक्ति आय की दर निकाल लेते हैं उसी प्रकार से विश्व को भी हम एक देश मानकर एक ही मुद्रा में प्रति व्यक्ति आय निकाल कर तुलना कर सकते हैं परन्तु फिर भी यह पूर्ण सही मापदण्ड नहीं है

2 Is low rate of growth a sign of under-development ? क्या विकास की नीची दर कम-विकसित होने की निशानी है ?

कम विकास की दर को हम कम-विकसित देश होने से सम्बन्धित नहीं कर सकते

निम्न तालिका में हम 1962 67 के बीच भिन्न-भिन्न देशो की विकास की दर दर्शाते हैं इस तालिका से जाहिर होगा कि स्वीटजरलैंड, जर्मनी, यू के , डेन्मार्क, कनाडा, स्वीडेन, फ्रास तथा यू० एस० ए० जैसे देश भी कम-विकसित कहलायेगे जो सर्वथा अनुचित है

1962-67

देश	प्रति वर्ष विकास दर	देश	प्रति वर्ष विकास दर
जापान	8 5	स्वीडेन	3 4
फारमोसा	7 5	कनाडा	3 4
ग्रीस	6 7	आस्ट्रिया	3 4
द० कोरिया	6 3	पाकिस्तान	3 3
स्पेन	5 7	बेल्जियम	3 2
इरान	4 7	इजराइल	3 0
थाइलैंड	4 7	मलेयसिया	3 0
द० अफ्रीका	4 3	डेन्मार्क	3 0
नार्वे	4 2	यू० के०	2 2
टर्की	4 1	प० जर्मनी	2 2
नीदरलैंड (हालैंड)	4 0	चिली	2 1
इटली	3 8	स्वीटजरलैंड	2 1
फ्रास	3 7	वनेजुएला	1 5
यू० एस० ए०	3 5	भारत	1 2
मैक्सिको	3 4	अर्जेन्टिना	1 1
आस्ट्रेलिया	3 4	ब्राजील	0 5

इसलिए हम कम-विकास दर को कम-विकसित देश की निशानी नही मान सकते 'The decisive factor is not the speed but the distance already covered by an economy' (1)

For these latest figures See Life Nov, 1968 p /4

(1) See Miss Ishrat Husain Economic factors in Economic Growth Ch, I,

3 Are Poor natural resources an index of under-development ? क्या प्राकृतिक साधनों की निर्धनता कम-विकसित होने की निशानी है ?

इस दृष्टिकोण को भी हम नहीं अपना सकते अफ्रीका के देश, भारत तथा ब्राजील प्राकृतिक साधनों से भरपूर देश हैं परन्तु वे देश आस्ट्रेलिया तथा इज़राइल के मुकाबले में कम-विकसित हैं जापान भी एक ऐसा देश है जिसने बगैर किसी महत्वपूर्ण कच्चे माल की उपलब्धि के उल्लेखनीय रूप से विकास किया है साधनों का उपभोग अधिक महत्वपूर्ण है

4 Is lack of capital or low capital ratio to per head of population an index of under-development? क्या प्रतिव्यक्ति पूंजी की मात्रा का निम्न अनुपात कम विकसित होने का माप दण्ड है ?

यह निश्चित रूप में सही है कि जहाँ प्रति व्यक्ति पूंजी अधिक होगी वह देश शीघ्र विकसित हो जाएगा परन्तु पूंजी विकास के लिए आवश्यक अवश्य है परन्तु उसके होने से ही विकास नहीं हो जाता है आज अगर कम विकसित देशों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बराबर पूंजी दे भी दी जाए तो यह देश उस देश के बराबर नहीं हो जाएँगे जैसे कि प्रो० नर्क्स ने कहा है 'Economic development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditons and historical accidents Capital is a necessary but not a sufficient condition of progress.' अर्थात विकास मानव क्षमता पर, सामाजिक मनोवृत्ति तथा राजनैतिक स्थितियों और आकस्मिक ऐतिहासिक योग पर निर्भर करता है

5. Is age of a country an indication of underdevelopment ? क्या देश की 'आयु' विकास से सम्बन्धित होती है ?

सब अर्थशास्त्री इस आधार को नहीं मानते अन्यथा जहाँ भारत, चीन व मिस्र को विकसित माना जाएगा वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कम विकसित देश होगा यह बात सर्वथा अमान्य है

See Nurkse op cit.

6. Is degree of industrialization an index of development ? **क्या कम औद्योगिक होना कम विकसित होने की निशानी है ?**

इसको भी हम कम विकसित होने का आधार नही मान सकते न्यूजीलैंड, डेनमार्क तथा आस्ट्रेलिया में "प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन से औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कम रहता है," परन्तु यह देश निश्चित ही विकसित है जापान मे तथा इजराइल में उपरोक्त देशो मे अधिक उद्योग है पर वे उपरोक्त देशो के अनुपात मे प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम पाते हैं. इसलिए यह आधार भी उपयुक्त नही है

7 Is low ratio of income from export to national income an index of under-development ? **क्या निर्यात का कुल आय का कम अनुपात में होना कम-विकसित देश की निशानी है ?**

यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशो के निर्यात कुल राष्ट्रीय आय का बहुत कम अनुपात होता है, जबकि विकसित देश निर्यात से राष्ट्रीय आय का बडा भाग प्राप्त कर लेते है

परन्तु यह आधार भी सर्वमान्य नही हो सकता क्योकि वेनेजुएला तो अपनी राष्ट्रीय आय का 90 प्रतिशत भाग पेट्रोल के निर्यात से प्राप्त करता है कागो तथा चिली भी निर्यात से बहुत भाग प्राप्त करते है, परन्तु देश कम विकसित है

8. Is high density of population an index of under-development ? **क्या जनसख्या का अधिक घनत्व कम विकसित देश की निशानी है ?**

बहुधा यह कहा जाता है कि कम विकसित देश वे है जहाँ (1) जन्म व मृत्यु दरे अधिक है तथा (11) जहाँ जनसख्या का घनत्व भी अधिक है परन्तु यह मापदण्ड नही माना जा सकता बहुधा कई कम विकसित देशो मे जन्म दर अधिक नही हैं, और कई कम विकसित देशो मे घनत्व की कमी है (जैसे अफ्रीका मे)

> **कुल मिलाकर कम विकसित देशों का मापदण्ड हम इन सब मापदण्डो को मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं. कम विकसित देशो में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय उन्नत देशो के अनुपात में कम होती है तथा साथ ही यहां बहुधा (1) प्रति व्यक्ति पूँजी संचय कम होता है (11) जन्म व मृत्यु दरें अधिक रहती हैं (111) प्राथमिक उद्योगो में अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं, (1V) औद्योगीकरण कम रहता है (V) तथा प्राकृतिक साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा होता है.**

IV Economic Growth vrs Development.
आर्थिक वृद्धि व विकास

अंग्रेजी पुस्तको मे 'Economic Growth' तथा 'Economic Development' मे अन्तर किया जाता है–हालांकि दोनो शब्द पर्यायवाची शब्दों की तरह मे ही प्रयोग मे लाए जाते है हिन्दी मे 'आर्थिक विकास' शब्द चल पडा है और इसमे अ तर का प्रश्न नही उठता है फिर भी हम अंग्रेजी भाषा मे जो Economic Growth तथा Economic Development मे अन्तर निकाला जाता है उसका अध्ययन करेंगे

Joseph Schumpeter जोसेफ शम्पीटर

जोसेफ शम्पीटर सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होने हम बीसवी सदी मे विकास पर महत्वपूर्ण विचार दिए वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होने Growth व Development म अन्तर निकाले शम्पीटर का कथन है कि जो उन्नति धीरे धीरे Data (या जाने माने तत्वो) के परिवर्तनो के कारण होती है वह Growth हुई जैसे अगर अगले वर्ष मे 2 प्रतिशत जनसख्या बढती है और इसके कारण 2% उत्पादन बढे तो यह Growth हुई परन्तु जब साहसी अपनी क्रियाओ द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाते है तो वह अर्थ व्यवस्था की सख्यात्मक वृद्धि ही नही करते वरन अर्थ व्यवस्था मे गुणात्मक परिवर्तन ला देते है उनके अनुसार "अगर एक छोटी फुटकर बिक्री की दुकान धीरे-धीरे एक बडे डिपार्टमेन्टल स्टोर म परिणित हो जाती है तो यह Growth हुई विकास तो केवल क्रान्तिकारी (Revolutionary) तथा अविरल (Discontinuous) परिवर्तनो से होता है"

शम्पीटर के अनुसार Development, Growth से अधिक महत्वपूर्ण होता है

C P Kindleberger : सी पी किन्डलबेरजर

किन्डलबेरजर भी Development को Growth से अधिक महत्वपूर्ण मानते है उनका कथन है कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी देश मे Growth तो हो सकती है परन्तु Development हो ही न रहा हो Growth का अर्थ उत्पादन में वृद्धि होना है जबकि Development का अर्थ न केवल

Joseph Schumpeter के विचारो के लिए उनका माडल देखिए

C P Kindleberger ; Economic Development p 1 & 15

उत्पादन मे वृद्धि से होता है वरन् उसका अर्थ यह भी होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी व सस्थागत परिवर्तन भी हो रहे हैं

इस प्रकार से Growth का अर्थ आय मे वृद्धि होता है और Development का अर्थ सरचना व उत्पादन परिवर्तनो से होता है फिर भी Growth से ही Development नापा जाता है

'Economic growth is generally thought of as unidimensional and is measured by increases in income Economic development involves as well structural and the functional changes In the absence of effective measures of the latter, however, states of development are estimated by levels of income and the rates of development by the growth of income'

Mrs Ursulla Hicks **श्रीमती उर्सुला हिक्स :**

श्रीमती हिक्स का कथन है कि Growth विकसित देशो की समस्या है, जबकि Development कम-विकसित देशो की समस्या है विकसित देशो मे साधनो का लगभग पता लग चुका होता है उनका प्रयोग भी लगभग पूर्ण रहता है, जबकि कम विकसित देशो मे इन साधनो का प्रयोग करना ही मुख्य कार्य होता है

Everyman's Dictionary :

सामान्यतया Economic Development का अर्थ Economic Growth ही होता है परन्तु Growth में हम प्रति व्यक्ति आय मे परिवर्तन नापते है, तो Economic Development में हम उन समस्त आर्थिक, सामाजिक व अन्य परिवर्तनो का अध्ययन करते है जो स्वय Growth लाते है

Growth नापी जा सकती है तथा यह पूँजी या श्रम शक्ति व्यापार व उपभोग मे वृद्धि नापती है, जबकि Development हम उसे कहेंगे सामाजिक तकनीकी व अन्य वे समस्त घटको के परिवर्तन जो Growth लाते है, नापने है

See · Ursulla Hicks : Learning About Economic Development Oxford Economic Papers Feb. 1957.

Meier and Baldwin मीयर तथा बाल्डविन

मीयर तथा बाल्डविन Growth व Development को पर्यायवाची शब्द ही मानते है परन्तु वे Development उन परिवर्तनो को मानते हैं जो किसी देश की राष्ट्रीय आय मे दीर्घकाल म आते हैं उनके अनुसार ऐसे तो हर व्यापार-चक्र मे आय मे परिवर्तन हो जाते हैं परन्तु Economic Development के अन्तर्गत हम कम से कम 25 वर्षों म होने वाले परिवर्तनो का अध्ययन करत हैं Economic Development के अन्तर्गत हम प्राकृतिक साधनो, पूँजी निर्माण, जनसख्या वृद्धि, तकनीकी उन्नति कार्यकुशलता व सगठन मे होने वाले समस्त परिवर्तनो का अध्ययन कर लेते हैं

"The course of economic development is not a story; it is a plot, and we should discover the interconnections" अर्थात हमारे विकास के भिन्न भिन्न घटकों का सह सबध का अध्ययन Economic Development का अध्ययन हुआ जबकि राष्ट्रीय आय मे परिवर्तनो मे अध्ययन Growth हुआ

> **मीयर तथा बाल्डविन व कुजनेटस वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि को विकास की निशानी मानते हैं जबकि Jacob Viner जेकब वाइनर तथा H. F Williamson एच एफ विलियमसन प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय बढने को विकास को निशानी मानते हैं**

प्रथम अर्थशास्त्रियो का कथन है कि अगर राष्ट्रीय वृद्धि के साथ जनसख्या की वृद्धि मे समाप्त हो जाते है तो यह कहना गलत होगा कि विकास हुआ ही नही परन्तु वर्तमान लेखक के मत में Viner तथा Williamson की विचारधारा अधिक उपयुक्त है इनका कथन है कि जब तक प्रति व्यक्ति आय नही बढती और उन व्यक्तियो की कुल सख्या कम नही होती जो कि एक सीमा से नीचा जीवन-स्तर व्यतीत कर रहे है, हम विकास नही मान सकते

•

1. Meier & Baldwin : op cit : ch I
2. Viner : op cit p 15
3. Williamson : ch I of Economic Development Principles and Patterns : Introduction . Ed williamson Butrick.

अध्याय : 2

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of Under-developed Countries

भाग (1)

1 निम्न प्रतिव्यक्ति आय (प्रथम अध्याय में उल्लेख हो गया)

2. पिछड़ी कृषि-रोपण अर्थव्यवस्था

3. जनसंख्या संबंधी पिछड़ी अर्थव्यवस्था :

   (1) कम-विकसित देशों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े

   (2) कम विकसित देशों मे जन्मदर का अधिक होना कारणों का विश्लेषण

   (3) कम-विकसित देशो मे मृत्यु दर की अधिकता

   (4) ऊंची जन्म व मृत्यु दरें व आर्थिक बरबादी

   (5) कम-विकसित देशो मे जनसंख्या के शिक्षा स्तर

   (6) कम-विकसित देशो मे असंतुलित आहार, व निम्न आयु

   (7) कम-विकसित देशो मे जनसंख्या का व्यवसायिक अनुपात

   (8) कम-विकसित देशो मे घनत्व की समस्या

   (9) आशावादी व निराशावादी विचारधाराएँ

4. कम विकसित देशों में कम बचतों व कम पूँजी निर्माण का दुष्चक्र,

   कम बचतो के कारण पूंजी निर्माण और दुष्चक्र पूर्ति पक्ष व माँग पक्ष

5 कम विकसित देश व बेरोजगारी;

   (i) बेरोजगारी के अनुमान

   (ii) कम-विकसित देश व अर्ध बेरोजगारी

   (iii) छद्म बेरोजगारी

   (iv) कम-विकसित देशो में "उन्नति काल की बेरोजगारी"

   (v) संरचना संबंधी बेरोजगारी

   (vi) कम-विकसित देशो मे मौसमी बेरोजगारी

   (vii) शिक्षित लोगो की बेरोजगारी

   (viii) मौसमी व अन्य बेरोजगारी

अध्याय : 2

कम विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of Under-developed Countries

I निम्न प्रति व्यक्ति आय उसका उल्लेख प्रथम अध्याय म हो चुका है

II Backward Agriculture पिछड़ी कृषि-शोषण अर्थ-व्यवस्था

कम-विकसित देशों मे कृषि ही मुख्य उत्पादन का जरिया तथा कृषि ही मुख्य रोजगार प्रदान करने वाला व्यवसाय होती है जहाँ विकसित देशों मे 15 से 25 प्रतिशत व्यक्ति ही कृषि मे कार्यरत रहते है वहाँ कम विकसित देशों से यह प्रतिशत 65 से 95 तक पाई जाती है फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहाँ विकसित देशों म दस में से एक या दो व्यक्ति कृषि करके स्वय व अन्य को अच्छा खाना दे सकते है वहाँ 10 मे मे 7 या 8 व्यक्ति भी अपनी खाद्यान सबधी आवश्यकता पूरी नही कर पाते जहाँ 1840 मे U S A. मे दो कृषक एक अन्य व्यक्ति के लिए और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न कर देते थे. आज 15 अन्य व्यक्तियो के लिए उत्पादन कर सकते है

कृषि सबधी कुछ विशेषताएँ इस प्रकार होती है —

(1) कृषि क्षेत्र में भूमि पर कार्यरत व्यक्ति निरपेक्ष रूप से आवश्यकता से अधिक होते है अर्थात् बहुतो की सीमान्त उत्पादकता शून्य रहती है खेतो पर कार्यरत कुछ व्यक्तियो को हटा भी लिया जाए तो कुल उत्पादन मे अन्तर नही आएगा

(आगे बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी संबधी विशेषता देखिए)

(ii) कृषि-क्षेत्र के अधिकाश व्यक्ति बहुत कम पूजी से कार्य करते हैं, बहुत कम आय प्राप्त करते है तथा उनकी बचतें व पूजी निर्माण बहुत ही कम रहती है

(iii) देश मे अधिकाश कृषि-उपज दालो व खाद्यान्नो की ही होती है तथा जनता का अधिकाश व्यय भी इन्ही पर होता है

(iv) अधिकाश निर्यात भी कच्चे माल का होता है क्योंकि औद्योगिक उन्नति कम रहती है

(v) कृषि में एक तो पूजी भी कम होती है दूसरे जो भी पूजी होती है उसका भूमि के छोटे-छोटे टुकडो मे बँटे रहने के कारण पूर्ण उपयोग नही हो पाता

(vi) कृषि मे पिछडी तकनीक, पुराने किस्म के औजार तथा बहुत ही सीमित मात्रा मे अच्छे औजारो का प्रयोग किया जाता है जहाँ स्वीटजरलैंड मे प्रति 1000 हेक्टर 85 ट्रैक्टर है (प० जर्मनी 81, नीदरलैंड 45, यू० के० 60) वहाँ टर्की मे केवल 2 है U S A मे प्रति 115 व्यक्ति पर एक ट्रैक्टर है, जबकि भारत मे प्रति 21000 व्यक्ति व इन्डोनेशिया मे प्रति 2,70,000 व्यक्ति पर एक ट्रैक्टर है

(vii) कृषि क्षेत्र के पास खाद्यान्न को सचित रखने तथा उपज के लिए यातायात के साधनो की नितान्त कमी रहती है कृषि उपज को विपणन करने की सुविधाएँ भी कम रहती है बीच के मध्यस्थ लोग कृषि की उपज को किसानो से खरीदने व बेचने मे शोषण करते है

(viii) कृषि को साख का नितान्त अभाव रहता है बैंको से सहायता लगभग मिलती ही नही है दीर्घकालीन विनियोजन कार्यो के लिए भी धन की कमी रहती है देशी बैंकर उधारी क्या देते है सम्पूर्ण कृषि-क्रियाओ को गिरवी रख लेते है

(ix) देश मे भूक्षरण होता रहता है, वन सम्पत्ति का अनुकूलतम प्रयोग नही हो पाता तथा खाद व उर्वरक का बहुत कम प्रयोग हो पाता है जहाँ नीदरलैंड मे प्रति हेक्टर 500 पौंड उर्वरक प्रयोग हो पाता है, या जर्मनी, यू० के० व अन्य स्थानो पर लगभग 200 300 पौंड प्रयोग मे आता है प्रयोग होता है भारत मे यह केवल 3 पौंड है या टर्की मे केवल 1 पौंड

(x) कृषक बहुत अधिक ऋणग्रस्त रहते है

References : Meier & Baldwin, Benjamin Higginer Leibenstein, H W. Singer, W. A. lewis, kindleberger, Bauer & Yamey, D B Singh, D. S Nag, I Z Hussain, U N Publications, तथा अन्य references के लिए पुस्तक के दूसरे भाग मे कृषि सबधी अध्याय देखिए

(xi) कम विकसित देशो मे भू-नियम व यन्त्र त्रुटिपूर्ण होते हैं बड़े किसानो जमीदारो के पास बहुत खेत होते हैं जबकि असंख्य कृषक भूमिहीन मजदूरो के रूप म कार्य करते हैं

(xii) समस्त कृषि क्षेत्र सदियो म स्थगित अवस्था मे पडा है यहाँ के लोग पुरानी आस्थाओ, मान्यताओ, अन्धविश्वासो, रीति-रिवाजो आदि में फस रहते हैं

(xiii) कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम रहती हैं विकसित देशो के मुकाबले मे कम विकसित देशों में उपज प्रति एकड केवल 1/10 से 1/4 भाग ही रहती हैं भारत मे ही फार्म उत्पादकता लका, जावा, मिस्र की केवल आधी तथा ब्राजील की 1/7 भाग ही है

(xiv) सक्षेप मे कम विकसित देशों में कृषि क्षेत्र मे रत व्यक्तियो की प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम होती है, अर्थात् उत्तरी अमेरिका व योरोप में प्रति व्यक्ति कृषि उपज 10 से 20 गुनो अधिक रहती है जहाँ विकसित देशो में प्रति व्यक्ति कृषि उपज लगभग $2\frac{1}{2}$ से 3 टन है वहाँ एशिया में यह केवल 1/4 टन है व अफ्रीका में केवल 1/7 टन ही है

कम विकसित देशो मे कृषि भी व्यापार चक्रो से व्याप्त रहती हैं बहुधा इन देशो मे कृषि मौसम की मेहरबानी पर निर्भर रहती है इसीलिए Umbreit, Hunt तथा Kinter का कथन है कि कम-विकसित देशो में कृषि "Prince to pauper and pauper to prince cycles" से व्याप्त रहती है (*अर्थात आज के राजकुमार कल भिखारी, या आज के भिखारी कल राजकुमार बन जाते हैं*)

कम विकसित देशो में कृषि कई बेलोचदार स्थितियो का शिकार रहती है (1) कृषि की खेती योग्य भूमि की पूर्ति बेलोचदार रहती है (2) कृषि की उपज की माग वृद्धि के उपरान्त कृषि उपज की पूर्ति में अनुपातिक वृद्धि नही होती अर्थात् कृषि पूर्ति, माग व मूल्य वृद्धि के उपरान्त भी नही बढती (3) कृषि-क्षेत्र में लगे व्यक्तियो की पूर्ति भी बेलोचदार होती है अर्थात कृषि क्षेत्र म लगे बहुत से श्रमिक अर्ध-बेरोजगारो व कम आय होते हुए भी इसी काम मे लगे रहते हैं और दूसरे स्थानो को गतिशील नही होते

इसलिए कम-विकसित देशो मे विकास के लिए कृषि की उन्नति सर्वप्रथम आवश्यक होती है

III Demographic Characteristics Of Under-developed Countries. कम-विकसित देशों की जनसंख्या सम्बन्धी विशेषताएँ :-

1 प्रस्तावना :

बहुधा यह सोचा जाता है कि कम-विकसित देशों में जनसंख्या-वृद्धि की दर अधिक होती है और इन देशों में घनत्व भी अधिक रहता है, परन्तु यह बात ठीक नहीं है कम-विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दरें विकसित देशों से अधिक होती है, परन्तु बहुधा जनसंख्या-वृद्धि दर विकसित देशों से अधिक नहीं रहती अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के देशों में तो घनत्व भी कम होता है

हम कम-विकसित व विकसित देशों में जनसंख्या में आरम्भ व वृद्धि दर को निम्नलिखित तालिका में अध्ययन कर सकते हैं

आज से 25,000 वर्ष पहले केवल एक स्त्री व एक पुरुष था

Population in Million (दस लाख में)

	1650	1750	1850	1900	1950	1955
विश्व	470	694	1094	1550	2500	2690
अफ्रीका	100	100	100	120	199	216
उत्तरी अमेरिका	1	1	26	81	168	183
दक्षिणी अमेरिका	7	10	33	63	163	182
एशिया (रूस को छोड़)	257	437	657	857	1380	1490
जापान	23	32	32	45	84	90
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड			5	5	10	11
योरोप	103	144	274	423	574	606

U. N. Population Bulletin no. 1

विश्व में 1650 — 1850 में वृद्धि 4% प्रतिवर्ष हुई
" " 1850 — 1900 " " 7% " "
" " 1900 — 1950 " " 9% " "

Ch. II : Bowen : Population Cambridge Uni. Books.

1920-1950

इन वर्षो के बीच विश्व की जनसंख्या	9	प्रतिशत	प्रतिवर्ष	बढ़ी
अफ्रीका की ,,	1 3	,,	,,	,,
उत्तरी अमेरिका की ,,	1 3	,,	,,	,,
दक्षिणी ,, ,, ,,	1·9	,,	,,	,,
एशिया की ,,	·8	,,	,,	,,
जापान की ,,	1·4	,,	,,	,,
योरोप की ,,	6	,,	,,	,,
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ,,	1·4	,,	,,	,,

2 कम विकसित देशो में जन्म दर का अधिक होना :

कम विकसित देशो मे जन्म दर निश्चित ही विकसित देशो के मुकाबले मे अधिक होती है 1961 मे विश्व के भिन्न-भिन्न देशो मे जन्म दर इस प्रकार रही · यह जन्म दर प्रति-हजार व्यक्त की गई है.

14.	स्वीडेन
15-20	लक्जेम्बर्ग, जापान, बेल्जियम, डेनमार्क, नार्वे, यू. के, प. जर्मनी, फ्रान्स, फिन्लैंड, आस्ट्रिया, इटली, ग्रीस,
20-25.	स्पेन, आइरलैंड, नीदरलैंड, भारत, अर्जेन्टिना, आस्ट्रेलिया, यू. एस. ए. रूस, पुर्तगाल.
30-35.	पीरू, चिली, पुर्टोरिको
35-40.	थाइलैंड, लंका, फारमोसा
40-45.	जार्डन, मलाया, ब्रिटिश गुयाना, जमाइका, पनामा, कोस्टारिका, कोलम्बिया, होन्डुरास, ट्यूनीशिया,
45-50.	इक्वेडार, एल- सेल्वेडार, मेक्सिको, वेनेज्युला, ग्वेटेमाला.
56.	घाना.
७०.	नाइजीरिया.

60 प्रति हजार से ऊपर जनसख्या वृद्धि नही हो सकती, क्योंकि यह पुनरुत्पादन की अधिकतम जीव विज्ञान सबंधी सीमा है

इन देशो में जन्म दर अधिक होने के निम्नलिखित कारण होते हैं

(i) इन दशा म बहुधा विवाह कम आयु म कर दिया जाता है जहाँ विकसित दशो म बच्चे पैदा करने की आयु (15 55) में बहुधा 10 15 वर्ष गैर शादी शुदा स्थिति मे निकाल देते हैं परन्तु कम विकसित देशो म प्रजनन शक्ति की पूरी आयु बच्चे पैदा करने के प्रयोग मे आ जाती ह

(ii) इन देशो म शिक्षा की कमी, झूठी शर्म की भावना, धनाभाव, झूठी धर्मान्धता आदि के कारण परिवार नियोजन की रीतियाँ कम अपनाई जाती हैं बहुत से गरीब व्यक्ति इस सबध मे अधिक जानकारी भी नही रखते

(iii) इन देशा म भी राज्य ने हाल के वर्षो म ही परिवार नियोजन प्रसार करना शुरु किया है और आपरेशन व दवाओ तथा अन्य उपकरणो की सुविधा दी है जनता म इस सबध म जागरुकता भी नई है

(iv) कुछ Biological facts भी ऐसे है जो अधिक जन्म को उत्पन्न करत हैं जैसे

(a) इन देशो म गरीब जनता अधिक रहती है और वे अच्छे किस्म का भोजन प्राप्त नही करते जिन व्यक्तियो को उचित मात्रा में प्रोटीन नही मिलता उनके जिगर कमजोर रहते है जिससे शरीर के जो estrogens रहत हैं व neutralize नही हात और उनकी अधिकता से प्रजनन शक्ति बढ जाती है

(b) गरीब लोगो को मनोरजन के साधनो की कमी के कारण भी "यौनिक क्रिया" ही मनोरजन के साधन रह जाते है इससे वे अधिक बच्चे पैदा कर लेते है

(v) इन देशो म मृत्युदर भी अधिक रहती है इससे बहुत देशो मे बच्चे पैदा होते है और मर जात है और इसी कारण गरीबो को अधिक बच्चे पैदा करना पडता है

(vi) भारत जैसे कम-विकसित देश म हर स्त्री लडका पैदा करना जीवन की 'साध' मानती है इस कारण अगर कहीं लडकियाँ अधिक होती है तो लडके की चाह में और बच्चे पैदा करते जाते है

(vii) इन देशा में puberty (लडकियो के मासिक धर्म शुरु होने की आयु) कम होती है क्योकि यह उष्ण देश है इसलिए बच्चे भी अधिक होते है

3 कम विकसित देशो में मृत्युदर की अधिकता होना :

कम-विकसित देशो मे मृत्युदर भी अधिक रहती है जहाँ विकसित देशो म 5 से 10 प्रति हजार व्यक्ति वर्ष म मरते है वहाँ कम-विकसित देशो में यह प्रतिशत 15 से 23 प्रति हजार प्रति वर्ष तक होती है

निम्नतालिका मे इस सम्बन्ध म कुछ आकडे प्रस्तुत है

5 से 8 प्रति हजार प्रति वर्ष→ फारमोसा इजराइल, जार्डन, फिलीपीन्स, ग्रीस
→ जापान, ट्रिनीडाड टोबैगो, आइसलैंड, नीदरलैंड, कनाडा

8—12 ,, ,, → स्पेन, यूगोस्लाविया ब्रिटिश गुयाना, लंका, जमाइका, माल्टा, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, इटली, मलाया, डेनमार्क स्वीटजरलैंड, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका स्वीडेन, मेक्सिको, पुर्तगाल, फ्रांस

11—14 ,, ,, ,, → पश्चिमी जर्मनी, पीरु, कोलम्बिया, लक्जेम्बर्ग, बेल्जियम, यू के आस्ट्रेलिया, आइरलैंड

14—17 ,, , , → इक्वेडार, ग्वेटेमाला

17 से ऊपर , ,, ,, → बर्मा (19) भारत (20), टर्की (20), घाना (23), नाइजीरिया (20)

इन देशो में मृत्युदर अधिक होने के निम्नलिखित कारण होते है इन देशो में अधिकाश जनसख्या को सतुलित आहार नही मिलता जिसके कारण इनके शरीर में बीमारी को न आने देने और उससे लडने की क्षमता कम होती है दूसरे इन देशो में प्रति डाक्टर पर हजारो मरीज निर्भर रहते है जिसके कारण इलाज में समुचित ध्यान नही मिलता, तीसरे गरीबी के कारण अधिकाश गरीब जनता अच्छा व पूरा इलाज नही कर पाती, चौथे इन देशो में जनसाधारण के रहन-सहन के स्तर तथा सफाई के स्तर बहुत गिरे रहते है जिससे वातावरण कीटाणु युक्त रहता है पाचवें इन देशो की बहुत बडी जनता अशिक्षा के कारण रोगों के प्रति अवहेलना करती है और बाद में रोग ग्रस्त हो जाती है छठे बहुत से बच्चे व माताएँ प्रसव काल में मर जाते है या असतुलित आहार के कारण मर जाते है, सातवें इन देशो मे महामारियो के प्रकोप से भी लोग मर जाते है

4 ऊँची जन्म व मृत्यु दरें व आर्थिक बरबादी -

(1) ऊँची जन्म व मृत्युदरो के रहने से जनसख्या भले ही तीव्र गति से न बढती हो परन्तु इससे पूँजी निर्माण रुकता है जब बच्चे होने के पश्चात् युवा-अवस्था में पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं तो वे केवल उपभोक्ता के रूप म ही जिन्दा रहकर मर जाते है और स्वय उत्पादन में योगदान नही दे पाते इससे देश मे बचतें कम होती है और पूँजी निर्माण भी कम रहता है

(2) कम-विकसित देशो मे जन्म व मृत्यु दर दोनो का घटाने के प्रयत्न जब किए जाते है तो पहले मृत्यु दर घट जाती है थाडे से ही प्रयत्नो से मृत्यु दर आधी गिर जाती है जब कि जन्म दर इतनी तीव्रता से नही घटती **यह सक्रामक काल होता है (Transition period)** और इसमे कम-विकसित देशो मे पूँजी निर्माण की समस्या और गम्भीर हो जाती है

(3) इसकी अन्य हानियाँ यह होती है कि देश में उन्नत तकनीक नही अपनाई जा सकती अधिकाश जनता अशिक्षित रहती है

(4) देश मे बेरोजगारी तथा अर्ध-बेरोजगारी की समस्या भी गम्भीर बनी रहती है

(5) देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के स्तर निम्न बने रहते है

5 कम-विकसित देशो में जनसख्या के शिक्षा स्तर

आज विकसित देशो म केवल 5 प्रतिशत जनता अशिक्षित ह परन्तु कम-विकसित देशो मे 63 प्रतिशत जनता अशिक्षित रहती है हम इसके गम्भीर परिणाम समझ सकते है इससे इन देशो म बेरोजगारी, कम कार्य कुशलता, कुशल व्यक्तियो की कमी व अकुशल की अधिकता तथा निम्न उत्पादन, निम्न राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बनी रहती है इसी कारण देश मे बचतो का अपव्यय तथा जन्म व मृत्यु दरें भी अधिक रहती है

6 कम विकसित देशो में असंतुलित आहार व निम्न आयु :

कम विकसित देशो म आज व्यापक भुखमरी फैली हुई है Le Gros ने अपनी पुस्तक 'Four Thousand million months to Feed" म लिखा है कि सन् 2000 मे विश्व मे व्यापक भुखमरी फैलेगी, जो केवल **समस्त भूमि पर आधुनिकतम** तकनीक के अपनाए जाने पर ही टाली जा सकती है

आज विश्व मे 50 करोड व्यक्ति स्थायी रूप से भूख मे पीडित है और अन्य 150 करोड व्यक्तियो को पर्याप्त भोजन प्राप्त नही होता

जहाँ एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3000 केलोरीज की आवश्यकता होती है और 40 प्रकार के भिन्न-भिन्न तत्वो (जैसे विटामिन, नमक, धातुये, एनजाइम्स), वहाँ F A O (Food & Agriculture organisation) की 1951 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की 1/9 जनसंख्या ही यह मात्रा प्राप्त करती है शेष 8/9 भाग इसे प्राप्त नही करता मनुष्य को अगर 1000 केलोरीज प्रतिदिन से कम मिले तो वह शीघ्र ही हड्डियो का ढाँचा रह जायेगा, Hitler के Concentration Camps (बिजली के तारो से घिरे कैदियो के कटघरे) मे इतनी ही मात्रा मे खाना दिया जाता था

विश्व मे आज भुखमरी के तीन बडे क्षेत्र है

(i) प्रथम वे देश है जहा जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जैसे भारत, चीन, व सुदूर-पूर्वीय देश

(ii) वे कम-विकसित देश जहाँ घनत्व कम है पर गरीबी के कारण भुखमरी है जैसे अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका

(iii) विकसित देशो के गरीब वर्ग

कम विकसित देशो मे मुख्य समस्या प्रोटीन की कमी की है बच्चे व गर्भवती स्त्रियाँ प्रोटीन की भुखमरी से पीडित है कम-विकसित देशो मे अगले बीस वर्षों में भिन्न भिन्न देशो मे 50 प्रतिशत से लेकर 150 प्रतिशत तक केलोरीज की मात्रा में वृद्धि आवश्यक होगी जिसका अधिकाश भाग कृत्रिम साधनो से प्राप्त करना पडेगा

आयु :

जहाँ विकसित देशो मे औसत आयु 60 से ऊपर ही होती है वहाँ कम-विकसित देशों में 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रहती है निम्न तालिका मे 1968 मे औसत आयु (Life expectancy) इस प्रकार है

आस्ट्रेलिया, यू० के०, यू० एस० ए०	73 वर्ष
फ्रास	69 ,,
जापान	65 ,,
लंका	60 ,,
भारत	50 ,,
अफ्रीकी देश	20-45 ,,

भारत मे 1811–20 के बीच पुरुषों की औसत आयु केवल 19 4 वर्ष व स्त्रियो की केवल 20 9 थी इतनी अधिक स्वास्थ्य सुविधाएँ बढाने के पश्चात् ही यह दर अब 1951–60 के बीच क्रमश 42 व 40 6 आई
जहाँ यू एस ए में 1000 में से 25 बच्चे की एक वर्ष की आयु से पहले मरते है वहाँ कम विकसित देशो में 100 से 200 बच्चे मर जाते है भारत मे 1000 मे से 150 बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं जब कि नाइजीरिया मे तो 500 बच्चे मर जाते हैं

7 कम-विकसित देशो में जनसख्या का व्यवसायिक अनुपात

निम्नलिखित तालिका विकसित व कम विकसित देशो के बीच जनसख्या का व्यवसायिक वर्णन करती है जैसा कि जाहिर है कम विकसित देशो मे अधिकाश जनता प्राथमिक कार्यों म लगी रहती है और विकसित क्षेत्र में इसका उल्टा रहता है यह कितनी आश्चर्यजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कम विकसित देशो मे 10 मे 6 से 8 व्यक्ति कृषि म लगे रहते हैं फिर भी पर्याप्त मात्रा म खाद्यान नही उगा पाते

प्रतिशत मे

कार्य	यू एस ए	यू के	जापान	भारत
कृषि	12'5	5'0	19·4	72·0
उद्योग	30'6	43·0	29·3	9 7
निर्माण कार्य	6 4	6·2	6 6	1·0
यातायात व सचार	7'7	7'1	7'4	1 5
व्यापार	19 0	14'1	16'5	5 1
सेवाये	23 8	23 8	20 8	10'8
	100 0	100 0	100 0	100 0

8 कम विकसित देशो में घनत्व की समस्या :

विश्व में आज भी हर देश में अर्थशास्त्रियो को माल्थस के भय का भूत सता जाता है जहाँ 1900 मे विश्व जनसख्या केवल 155 करोड थी, वहा 1975 मे 385 करोड सम्भावित है अन्य अनुमान इस प्रकार हैं

सन् 2000 मे 627 करोड
सन् 2065 म 1000 करोड

सन् 3090 में इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल खड़े होने की जगह मिलेगी
सन 4250 मे पृथ्वी पर मनुष्यों का भार स्वय पृथ्वी के बराबर हो जाएगा

सन् 2000 म 65 प्रतिशत जनसंख्या कम विकसित देशो मे होगी 1950 और 1980 के बीच अनुमान है कि एशिया की जनसंख्या 50 प्रतिशत, दक्षिणी अमेरिका की 92 प्रतिशत, अफ्रीका की 46 प्रतिशत तथा उन्नत देशो की 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी इन्ही कारणो से श्री बी आर सेन (भूतपूर्व अध्यक्ष, F. A O.) तथा Prof Rene Dumont ने 1975-1980 के बीच भारत, पूर्वी पाकिस्तान, ब्राजील, पीरु व बोलिविया म अकाल की भविष्यवाणी की है

श्री माइकल रार्बट (Michael Robert) ने अपनी पुस्तक The state of man नामक पुस्तक मे भी डर व्यक्त किया है उन्होने बताया कि 1951 म विश्व के 5 6 करोड वर्गमील क्षेत्रफल को तत्कालिक 235 करोड की जनसंख्या मे बाँटने तो प्रति व्यक्ति 15 एकड भूमि हिस्से मे आती जिसम 5 एकड जगल, 4 एकड रेगिस्तान, 2 एकड रतीली भूमि, व 2 एकड बर्फीली भूमि शामिल थी खेती योग्य केवल 1 5 एकड भूमि थी एक सदी बाद यह मात्रा आधी से भी कम रह जाएगी

आशावादी विचारधारा

अगर कम विकसित देशो मे परिवार नियोजन व्यापक रूप मे अपना लिया जाय तो इन देशो म जनसंख्या की समस्या इतनी गम्भीर न रहे **श्री विन्सटन चर्चिल** का कथन हमे ध्यान मे रखना चाहिए

> "हर वृक्ष शुरू मे ज्योमेट्रिक अनुपात म बढता है परन्तु कोई भी वृक्ष आकाश को नही छू पाता "

IV Vicious circle of low savings and low capital-formation कम बचतो व कम पूजी निर्माण का दुश्चक्र

कम-विकसित देश, प्रो० रेगनर नर्क्स के प्रसिद्ध शब्दो में, गरीबी, कम बचत, कम पूँजी निर्माण, कम विनियोजन व रोजगार तथा कम आय के दुश्चक्र मे फसे है प्रो० नर्क्स के शब्दो मे "एक गरीब देश अपनी गरीबी के कारण ही गरीब रहता है" उन्होने कहा "The path to economic development

---

जनसंख्या समस्या समाधान व नीति अगले भाग मे है

is paved with vicious circles ", जिसका भावार्थ यह है कि विकास की राह में बहुत से अवरोध, भवरें व झंझावात हैं प्रो० नर्क्स ने कहा कि जिस प्रकार से एक गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण सन्तुलित भोजन न ले सकने के कारण कमजोर रहता हैं और कमजोरी के कारण कम कमाता है, तथा कम आय के कारण कमजोरी के दुश्चक्र मे फँसा रहता है, उसी प्रकार मे कम-विकसित देश कम बचत व कम पूँजी निर्माण के दुश्चक्र मे पडा रहता है

कम बचतें

(1) कम-विकसित देशो मे बचत की मात्रा, विकसित देशो के मुकाबले में बहुत कम होती है जहाँ *विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 18 से 25 प्रतिशत* तक जमा कर लेते है कम-विकसित देश अपनी आय का मुश्किल से 5 से 10 प्रतिशत तक ही बचा पाते है बर्मा, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, व फिलीपीन्स 1950 में अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 3 प्रतिशत बचा पाते थे

निम्नलिखित तालिका म कम बचतो की स्थिति दर्शायी गई है

देश	बचत का राष्ट्रीय आय के रूप में प्रतिशत
जापान	38
आस्ट्रेलिया	26
नार्वे	25
यू एस ए , कनाडा, पश्चिमी योरोप, स्वीडेन	17-25 प्रतिशत के बीच
श्री लका	11
भारत	10

(2) इन देशो में कम पूँजी निर्माण का मुख्य कारण गरीबी है Meier and Baldwin मीयर तथा बाल्डविन के अनुसार कम विकसित देशा मे आय के पिरामिड (△ जो इस रूप का होता है) केवल 5 प्रतिशत व्यक्ति बचत करते

(1) UNESCO 1951 . Volume and Distribution of National income in Under developed Countries p 45

(2) Yojna 29 th December 1968 p 22

है और कहीं कहीं तो केवल 2 प्रतिशत ही बचत कर पाते हैं[1]

(3) विश्व के विकसित व कम-विकसित देशों में औसत आय में बहुत अन्तर है। अमीर देशों के अमीर व्यक्तियों तथा गरीब देशों के गरीब व्यक्तियों की आय में तो जमीन व आसमान" के अन्तर कहे जा सकते हैं आज विश्व के कम-विकसित देशों में 63 प्रतिशत व्यक्ति रहते हैं पर वे विश्व की 13 प्रतिशत आय के ही भागीदार हैं[2]

(4) इसके अतिरिक्त देश के अन्दर ही आय के अन्तर बहुत अधिक रहते हैं जैसे भारत में 60 प्रतिशत जनसंख्या देश के केवल 35 प्रतिशत धन की भागीदार 20 प्रतिशत देश की 55 प्रतिशत धन के भागीदार हैं व बाकी के 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत धन के मालिक हैं[3]

(5) कम विकसित देशों में न केवल बचतों की मात्रा कम है वरन् बहुत कुछ बचतें real estates (मकान व जमीन) सोने चाँदी के रूप में संचय कर ली जाती हैं बचत करने वाले बहुधा बड़े जमींदार और व्यापारी होते हैं यह अपनी बचतों को ब्याज पर देने, और सट्टे खेलने के कार्य में ले लेते हैं[4]

(6) कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाये ऐसी हैं कि बचतों का सही प्रयोग नहीं हो पाता उदाहरणतया इन्डोनेशिया जैसा गरीब देश जहां व्यापक रूप से गरीबी है वहाँ कुछ वर्षों पूर्व वहा के तत्कालिक राष्ट्रपति विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तथा कुछ अन्य भवन बनाने में लगे थे भारत में भी पिछले 10-12 वर्षों से आगरे में लाखों रु० की लागत से राधास्वामी मन्दिर बन रहा है

(7) कुछ अर्थशास्त्रियों का कथन है कि कोई भी देश इतना गरीब नहीं होता कि वह अपनी राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत भाग नहीं बचा सके Egbert de Vries तथा Elmer का कथन है कि

(1 & 4) : Meier and Baldwin Economic Development : P. 311 ft

(2) cf Dr O S Shrivastava Economics of Wages, Productivity and Employment 1968 p 37 Kailash Pustak Sadan, Gwalior.

(3) : Simon Kuznets : "Economic Growth and Income Inequality."

Egbert de vries of International Bank of Reconstruction and Develpment and Elmer of Mutual Security programme of U S.A. quoted in "Capital formation and foreign Investment in under developed countries." by C wolf Jr. and S C. SuFrin.

"गरीबी ने गरीब देशो को युद्धो मे रत होने से नही रोका इन गरीब देशो मे कही-कही 60 प्रतिशत बचत क्षमता गरीबो तक मे पाई गई है जहाँ चाह है वहाँ बचत अधिक हो सकती है" इन देशो की 40 प्रतिशत आय सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगो द्वारा विलासिता में खर्च कर दी जाती है

पूजी निर्माण और दुश्चक्र

एक तो इन देशो मे बचते कम है और जितनी बचतें है उन सबका पूजी-निर्माण नही हो पाता इसका कारण है कि पूजी-निर्माण की पूर्ति और माँग दोनो की ओर दुश्चक्र है

(1) **पूर्ति पक्ष की ओर** कम पूजी निर्माण से कम विनियोजन होता है→कम विनियोजन से कम उत्पादन होती है→कम उत्पादन से रोजगार वृद्धि कम होती है→कम रोजगार से कम आय होती है→कम आय से बचते कम होती है क्योंकि उपभोग-क्षमता अधिक होती है→कम बचतो से पुन कम पूजी निर्माण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है

इस प्रकार स कुल राष्ट्रीय आय व प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय कम पूजी-निर्माण के कारण व परिणाम बन जाते है

(2) **माँग पक्ष की ओर** से भी दुश्चक्र पूरा रहता है देश मे जो कुछ भी माँग रहती है वह प्राथमिक आवश्यकताओ की रहती है अन्य वस्तुए बगैर बिकी रहती है या कम बिकती है इन कारणो से विनियोजन-कर्ताओं की माँग भी कम रहती है उत्पादन-कर्ताओ की माँग की कमी से पूजीसचय भी कम रहता है

(3) पूजी निर्माण की कमी के कारण औद्योगीकरण की योजनायें कार्यान्वित नही की जा पाती अधिक जनसख्या घनत्व वाले देशो मे यह समस्या और गम्भीर रहती है इस कारण यह देश पुरानी मशीनो से पुरानी तकनीक से कार्य करते रहते है और इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करने में पीछे रहते हैं

(4) कई कम विकसित देशो मे तो इतना पूजी निर्माण भी नही होता कि जन-सख्या को उसी स्तर पर कायम रखा जा सके Colin Clark के अनुसार 1 प्रतिशत जनसख्या वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आय का 4% विनियोजन की

Colin clark : Quoted from Dr. O. S Shrivastava op it p 54.

आवश्यकता, जनसंख्या को समान स्तर पर रखने के लिए ही होती है इनका अनुमान है कि अगर इन देशा मे सही माने मे व्यापक रुप मे तथा आवश्यक मात्रा म विकास करना हो तो राष्ट्रीय आय का 20 प्रतिशत से विनियोजन होना ही चाहिए

(5) इन देशो म न केवल ' भौतिक पूजी निर्माण'' की कमी है वल्कि "सामाजिक पूजी-निर्माण' की भी बहुत कमी है कम विकसित देशो में शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिग की सुविधाए कम रहती है शिक्षित, कुशल, तकनीकी ज्ञान रखने वाले स्वस्थ व दीर्घायु व्यक्ति समाज की पूंजी होते है, अन्यथा अशिक्षित, अकुशल व अल्पायु म मर जाने वाले व्यक्ति पूजीनिर्माणकर्ता के स्थान पर उपभोग-कर्ता अधिक होते है Prof Simon kuznets (साइमन कुजनेट्स) इसीलिए कहते है कि "भौतिक पूजी मे तो अधिक इन देशा मे सामाजिक पूंजी की कमी है"

(6) एक और अन्य कारण जिससे इन देशो म पूजी-निर्माण कम होता है, वह यह है कि इन देशो मे कुशल साहसियो की कमी है :

> "Capital creation may be said to be rather pulled from the side by imaginative entrepreneurs than pushed from the supply side by passive accumulation of Capital"
>
> →Howard Ellis

अर्थात् अगर बचत करने वाले बचत नही करते तो कुशल साहसी बचतो खीच लेते है

(7) Mrs Joan Robinson का भी इसी प्रकार कथन है कि कुशल साहसी ऐसी पद्धति निकाल लेते है (जैसे सयुक्त पूजी-प्रणाली) जिसमे पूजी-निर्माण हो सके "Where enterprise leads, finance follows.")

Simon Kuznets : Towards a theory of Economic growth in R. Leckacs man (Ed) National policy for Economic welfare at Home and Abroad. p. 39-40

Howard Ellis : The Fixing of Economic Dev in developing areas. The Indian Journal of Economic Jan. 1956 p 256-68.

Mrs. Joan Robinson : Cf . The Accumulation of Capital.

V Unemployment and Under-employment in Under-developed countries कम-विकसित देशो मे अर्ध बेरोजगारी व बेरोजगारी

कम-विकसित देश व बेरोज़गारी :

कम-विकसित देशो मे विकसित देशो की भाँति पूर्णरूप से अनैच्छिक बेरोजगारी की समस्या अधिक व्यापक नही है इन देशोमे Cyclical (चक्रीय) Frictional (मर्षपात्मक) तथा Technological (तक्नीकी) बेरोजगारी की समस्या प्रधान समस्या नही होती, फिर भी इस प्रकार की बेरोजगारी सख्या मे बहुत अधिक होती है, चाहे प्रतिशत मे यह मात्रा कम ही क्यो न हो इस सबध मे कुछ आँकड़े नीचे दिए जा रहे है

देश	सन्	नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	कुल सख्या	अन्य
भारत	1961	11%	6%		
,,	1968			150 लाख	11लाख शिक्षित
प० पाकिस्तान	1955	6 4% बडे शहर 3 5% नगरीयक्षेत्र	2 2%		
पू० पाकिस्तान	,,	10 3% बडे शहर 6 0% नगरीयक्षेत्र	3 1%		
फिलीपीन्स	1959	कुल आबादी के	7 1%		
	1961	,, ,, ,,	8 6%		
	1962	,, ,, ,,	9 5%		
ईराक	1956	,, ,, ,,	10 0%		
इटली	1959	,, ,, ,,	8 7%		
ब्राजील	1957	,, ,, ,,	5 2%		

Ecafe Region आजकल 10 से 15 प्रतिशत जनता बेरोजगारी से पीडित है

कम विकसित देश व अर्ध बेरोज़गारी :

कम-विकसित देशो मे समस्या यह नही कि "कितने व्यक्ति" बेरोजगार है, वरन् समस्या यह है कि व्यक्ति "कितनी मात्रा मे" बेरोज़गार है "The qestion is

See , Dr. O. S. Shrivastava : op. cit : P 3-8 & p 198-203

not" how many persons are unemployed, but "how much" they are unemployed

समस्या बेरोजगारी की संख्या से इतनी सबंधित नही जितनी "बेरोज़गारी की मात्रा मे है" (The problem is not of volume of unemployment but of degree of unemployment)

कम-विकसित देशो म समस्या यह नही है कि देश मे प्राकृतिक साधनो व जनशक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाए वरन् मुख्य समस्या रोज़गार से आय-वृद्धि की है

इन देशो मे प्राथमिक क्षेत्र मे तो कार्य मिल जाता है परन्तु द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) तथा तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) काम की बहुत कमी रहती है इन देशो मे रोज़गार प्रदान करना ही समस्या नही है वरन् रोज़गार के तकनीकी स्तर, उत्पादकता तथा Capital-output ratio पूँजी उत्पादन दर सुधारना होता है

कम-विकसित देशो मे बहुत से व्यक्ति Self-employed होते है, अर्थात अपने द्वारा सचालित कार्यो मे लगे रहते है इन देशो मे कुशल व्यक्तियो की कमी व अकुशल व्यक्तियो की बेरोज़गारी की स्थिति रहती है कभी कभी तो साहसियो और पूँजी की कमी के कारण शिक्षित व कुशल व्यक्तियो को भी बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है (Lack of co-operant factors becomes an important cause of unemployment and under-employment.

छद्मवेषी-बेरोजगारी Disguised unemployment :

Also known as (i) Under-employment (ii) Latent unemployment, (iii) Partial unemployment, (iv) Part-time employment, (v) Insufficient employment, and (vi) Abnormal unemployment

कम-विकसित देशो म छद्मवेषी-बेरोज़गारी की स्थिति मौजूद रहती है यह वह स्थिति होती है जिसमे व्यक्ति काम तो करता रहता है परन्तु वह उसकी योग्यता व क्षमता से बहुत कम आय देता है इस प्रकार के रोज़गार मे जनशक्ति का पूर्ण प्रयोग नही होता

कृषि-क्षेत्र में यह बेरोज़गारी अधिक व्यापक रहती है यह स्थिति वह है जहाँ कि किसानो के परिवार के सभी सदस्य एक खेत पर कार्य करते है जबकि अगर कुछ

लोग खेत पर से कार्य से हटा भी लिए जाएँ तो उत्पादन मे कोई अन्तर नही पडेगा इस दशा मे हम कह सकते है कि कुछ व्यक्तियों की सीमान्त उत्पादकता 'शून्य' रहती है यह बेरोजगार Self employed व्यक्तियों म अधिक होती है

अर्थशास्त्री च्याग सीह Chiag Hsieh ने तीन प्रकार की अर्ध बेरोजगारी बताई है

(i) Under - employment अर्ध बेरोजगारी अर्धबेरोजगारी की स्थिति वह होती है जिसमे एक व्यक्ति अपनी क्षमता से कम कार्य कर पाता है इस प्रकार की अर्धबेरोजगारी साफ दीख सकती है और बहुत हद तक नापी भी जा सकती है

(ii) Disguised under-employment छद्मवेषी अर्ध-बेरोजगारी कम-विकसित देश पिछडे किस्म की व्यवस्था और प्राथमिक श्रम-नियोजन मे उत्पादन करते हैं अगर इनम सुधार किये जाएँ (परन्तु पूजी की मात्रा, देश की सस्थागत सरचना व भूमि वितरण व्यवस्था वही रहे) तो निश्चय ही उनमे से कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाएँगें इन व्यक्तियो को हम Disguised under-employed मान सकते है

(iii) Potential under-employment · जब उत्पादन पद्धति मे तकनीकी सुधार व समस्त सरचना व व्यवस्था सम्बन्धी सुधार किए जाएँ तो जो लोग बेरोजगार होगे उन्हे हम बेरोजगारी से पहले potentially unemployed मानेगें (जैसे कृषि-क्षेत्र में माना 100 व्यक्ति काम कर रहे है अगर इस क्षेत्र में नई तकनीक, नए भूमि सुधार, नए औजार व मशीनीकरण, तथा नई व्यवस्था अपनाकर कार्य करें तो माना अब केवल 500 व्यक्ति काम कर उतना ही उत्पादन कर सकत है तो हम कहगे कि 500 व्यक्ति potential under-employment से पीडित हैं)

कम विकसित देशो में "उन्नति काल में बेरोजगारी"

Under-employment of expansion ·

Prof Moises T de la pena के विचार —इटली के इस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान खीचा इस प्रकार की बेरोजगारी कम-विकसित देशों मे विकास-काल मे उत्पन्न होती है, जबकि अधिकाश बेरोजगारियाँ मन्दी काल

में उत्पन्न होती है कम-विकसित देशों मे जब विकास के लिए अधिकाधिक मात्रा मे मुद्रा-प्रसार किया जाता है तो देश मे मुद्रा स्फीति फैलती है महगाई के कारण कुछ उद्योगो मे शिथिलता से बेरोजगारी उत्पन होती है गावो के रहने वाले महंगाई के कारण गाँवो से शहरो की ओर आते हैं और बेरोजगारो की सख्या बढाते है

संरचना संबंधी बेरोजगारी : Factor dis-equilibrium and structural unemployment :

Prof R. S. Eckuas' के विचार —कम-विकसित देशो मे श्रम व उत्पादन के अन्य अगो की गतिहीनता या गतिशीलता की कमी के कारण लोग अर्ध बेरोजगारी से पीडित बने रहते है और अन्य स्थानो पर रोजगार पाने के प्रयत्न नही करते गरीबी, अज्ञानता, धर्मबन्धन, जाति-भेदभाव के कारण रोजगार पाने का प्रयत्न नही करते

इन देशो मे निम्नकारणो से भी बेरोजगारी बनी रहती है

(i) एकाधिकारी कम उत्पादन करके बेरोजगारी बनाए रखते है

(ii) देश मे पूर्ति लोचदार नही होती और मूल्य वृद्धि होने पर भी पूर्ति नही बढाई जा पाती और रोजगार वृद्धि नही हो पाती

(iii) देश में आविष्कार व नव-प्रवर्तन कम होते हैं और उत्पादकता कम रहने से बाजार-विस्तार नही होता और रोजगार वृद्धि नही हो पाती

(iv) इन देशो मे राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सबधी जानकारी कम होती है. वे अपने बाजारो की क्षमता का प्रयोग नही कर पाते इसलिए इन कारणो से बेरोजगारी बनी रहती है

कम-विकसित देशो में मौसमी बेरोजगारी : Seasonal unemployment, कम-विकसित देशों में कृषि क्षेत्र मे सिचाई आदि की सुविधा कम होने के कारण, किसान साल के अन्य महीनो मे बेरोजगार रहते है. बहुत से उद्योग कुछ महीनो में ही चलते है और बाकी महीनो मे व्यक्ति बेरोजगार रहते है

कृषि क्षेत्र के व्यक्ति पूजी की कमी तथा बहुत हद तक अपनी अकर्मण्यता व गतिहीनता के कारण अन्य काम नही पाते

अन्य बेरोज़गारियाँ व कम विकसित देश :

1. Frictional unemployment. इन देशो मे श्रम अपना स्थान पाने के लिये संघर्ष करता है और कम विकसित देशो में आए दिन हडतालो व तालाबन्दी के कारण बेरोजगारी हो जाती है

2. Unemployment of the educated persons कम विकसित देशा मे यह ग्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साचरता प्रतिशत कम होते हुए भी शिचित लोग बेरोजगार रहते है इन देशो म कुछ कोटि के व्यक्तियो की कमी रहती है (जैसे तकनीकी व्यक्ति) ग्रौर कुछ कोटि के व्यक्तियो की ग्रधिकता रहती है (जैसे कला सकाय के शिचितो की) भारत मे तो तकनीकी चेत्र के विद्यार्थियो का भी भविष्य सुनिश्चित नही है ग्रौर इन्हे भी बेरोजगारी का सामना करना पड जाता है

इन देशो मे शिचित लोगो में बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नलिखित है

(1) विद्यार्थियो की सख्या वृद्धि के हिसाब से रोजगार की वृद्धि न होना

(11) शिचित व्यक्ति हमेशा white collar Jobs या "कुर्सी की नौकरियाँ" चाहते है, शारीरिक परिश्रम की नौकरियो की चाह का कम होना

(111) कला सकाय मे विद्यार्थियो की ग्रधिकता रहती है भारत मे 1962-63 मे विद्यार्थियो की सख्या इस प्रकार थी

कला सकाय	42 7 प्रतिशत
विज्ञान ,,	30 4 ,,
वाणिज्य ,,	10 0 ,,
इजीनीयरिंग व टेक्नालाजी	5 4 ,,
मेडिकल	3 9 ,,
कृषि	2 5 ,,
कानून	2 3 ,,
शिचा	2 0 ,,
ग्रन्य	6 ,,
	100

(Eastern Economist Annual No. 1965. p. 1427)

शिचित लोगो की बेरोजगारी ग्रत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथा खतरनाक होती है दुर्भा-

See . Dr. O. S. Srivastava : Employment Aspcets of Planning in Madhya Prdesh in "Development Potential of Madhya Praaesh, Ed. Dr. D S. nag. p. 169 sf"

व्यपूर्ण इसलिए कि शिक्षा म इतना समय और धन व्यय करने के पश्चात रोजगार न पा सकने मे समय व धन का अपव्यय होता है खतरनाक इसलिए कि शिक्षित व्यक्ति अपनी बेरोजगारी को भाग्य का दोष नही मानते व जानते है कि उनकी यह बेरोजगारी Socio-politico economic-defects या सामाजिक-राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था में दोषो के कारण है और फिर वे उस सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक व्यवस्था को ही उखाड फेकने का प्रयत्न करते है जो उन्हे रोजगार नही दे सकती वैसे भी वह राष्ट्र जो अपनी युवा शक्ति का उपभोग नही कर सकता शीघ्र कुठित हो जाता है

कम-विकसित देशो में अल्प-रोजगार या अर्ध बेरोजगारी के अनुमान :

आधुनिकतम अनुमानो के अनुसार पाकिस्तान, फिलीपीन्स, मिश्र, इन्डोनेशिया मे 20 से 25 प्रतिशत व्यक्ति अर्ध-बेरोजगारी से पीडित है. दक्षिणी इटली मे 45 प्रतिशत व उत्तरी इटली में 28 प्रतिशत व्यक्ति अर्ध-बेरोजगारी से पीडित है दुनियाँ के अधिकाश कम-विकसित देशो मे 25 से 60 प्रतिशत तक लोग अर्ध-बेरोजगारी से पीडित है

भारत मे भी ग्रामीण क्षेत्रो मे 1/4 व्यक्ति कृषि की आवश्यकताओ से अधिक है भारत मे जिन क्षेत्रो मे सिचाई की सुविधाएँ मौजूद है वहाँ साल के 4 से 6 महीनो तथा जहाँ सुविधाएँ मौजूद नही है वहाँ तो 8 महीनो तक कुछ व्यक्ति अर्ध-बेरोजगारी से पीडित हो जाते है तृतीय योजना के अन्त तक देश मे 1-5 करोड व्यक्ति बेरोजगार थे और 1 5 करोड व्यक्ति अर्ध-बेरोजगारी से पीडित थे

अध्याय : 3

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of under-developed countries

(भाग 2)

6. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का असंतुलन.
   (i) कुछ ही वस्तुओं के निर्यात (Narrow base of exports)
   (ii) निर्यात व राष्ट्रीय आय का भाग
   (iii) कम विकसित देशो की निर्यातित वस्तुओं के मूल्यों में उच्चावचन से इन देशो को हानि
   (iv) कम विकसित व प्रतिकूल भुगतान की शर्तें
   (v) निर्यात वृद्धि कम, आयात अधिक
7. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दुष्प्रभाव Backwash effects of international trade.
8. Duality : दुहरापन : विकसित व अविकसित होना.
9. अर्ध-विकसित मौद्रिक व्यवस्था.
10. राजकोषीय क्षेत्र व पिछड़ापन,
11. कम विकसित देश व प्राकृतिक साधन.
12. वाह्य मितव्ययताओं की कमी.
13. साहसियो व अन्य सहायक उत्पादन के अंगों की कमी.
14. पिछड़ी तकनीक व कम उत्पादकता.
15. अयोग्य, भ्रष्ट तथा उदासीन शासकीय प्रशासन.
16. सामाजिक पिछड़ापन.

अध्याय : 3

कम-विकसित देशों की विशेषताएँ

Characteristics of under-developed countries

(भाग 2)

IV International Trade Imbalances · अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार असतुलन

1 Narrow base of exports · कुछ ही वस्तुओं के निर्यात.

कम विकसित देशों के अधिकाश निर्यात एक या दो वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं यह स्थिति कम विकसित देशों के लिए हितकारी नहीं है क्योंकि अगर उस वस्तु विशेष का कम उत्पादन हुआ या कम माँग के कारण मूल्य गिरे तो इन देशों की आय एकदम गिर जाती हैं निम्नलिखित तालिका में इस वस्तु स्थितिको दर्शित की गई है [1]

देश	वस्तु	कुल निर्यात का प्रतिशत	
1. वेनेजुएला	तेल (पेट्रोल)	96	प्रतिशत
2-4. इरान, द० अरेबिया, कुवैत, वेने	तेल	90	प्रतिशत
5. मिश्र (यू० ए० आर)	रुई	80	,,
6 मलयेशिया	टीन व रबर	75	,,
7. लका	चाय व रबर	75	,,
8-9 वर्मा-थाईलैंड	चावल	75	,,
10. कोलम्बिया	काफी	75	,,
11. पाकिस्तान	जूट	70	,,
12. बोलेविया	टिन	70	,,
13-14. रोडेसिया, चिली	ताँबा	55	,,
15-16. आस्ट्रेलिया, यूरेगुए.	ऊन	50	,,

1. U N. . Measures for the Economic development of under-developed countries 1951 P 71

अफ्रीका के अधिकाश देश रुई, तांबा, मूंगफली व कोको के निर्यात से 40 से 80 प्रतिशत तक आय कमाते हैं

2. **निर्यात से राष्ट्रीय आय का भाग : Export as a percentage of national income**

कम विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 10 से 42 प्रतिशत तक निर्यात से कमाते है. इस सम्बन्ध मे स्थिति यह है टर्की (10) कोलम्बिया (12) इराक (13) मेक्सीको (17) निकारागुआ (27) क्यूबा (34) वियतनाम (36) तथा लंका (42) [1]

3. **कम-विकसित देशो को निर्यातित वस्तुओ के मूल्यो में उच्चावचन से इन देशों को हानि : Fluctuations in the prices of goods sold by under-developed countries.**

कम-विकसित देशो की निर्यातित वस्तुओ के मूल्यो में बहुत उच्चावचन हो जाते है मूल्यो मे इन परिवर्तनो से रोजगार व निर्यात आय म परिवर्तन होता है तथा इसके कारण राज्य व निजीक्षेत्र की आय, लाभ, मजदूर आदि मे भी परिवर्तन हो जाते है

1929-1932 की महान मदी के काल मे चाय व रबर के मूल्य 1/5 से 1/3 तक गिर गए थे 1901-1950 के बीच निर्यातित वस्तुओ के मूल्यो में 27 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत मूल्य मे परिवर्तन हुए [2]

4. **कम विकसित देशो की भुगतान की शर्तें विपक्ष में हो जाती हैं. Terms of trade of under-developed countries go against**

"भुगतान-शर्तो" का अर्थ आयात-निर्यात मूल्य-परिवर्तन सबध से होता है जैसे अगर किसी कम-विकसित देश के निर्यातित व आयातित वस्तुओ की मात्रा (जैसे 1 एजिन आयात, 100 रुई गाठ निर्यात) उतनी ही रहे, पर आयात की वस्तु का मूल्य बढ जाए या और निर्यात की वस्तु का मूल्य गिर जाय तो "भुगतान की शर्तें" विपक्ष मे हो जाती है [3]

---

1. Meier and Baldwin :—Op. cit P. 310.
2. Dr. O. S Shrivastava : op. Cit : p 60-65
3. I. M. F. : Fund policies and procedures in relations to the Compensatory Financing of Commodity Fluctuations 1960

1950 के अनुपात में 1961 में कम-विकसित देशों की "भुगतान की शर्तें" 14 प्रतिशत गिर गईं विकसित व कम-विकसित देशों की स्थिति इस प्रकार रही

	निर्यात की मात्रा	निर्यात का मूल्य
1 विकसित देश	112% वृद्धि	19% वृद्धि
2 कम-विकसित देश	57% वृद्धि	4% कमी

5 निर्यात वृद्धि कम, आयात अधिक : Unfavourable balance.

(1) 1956 में विश्व निर्यात 1,00,000 मिलियन डालर से बढकर 2,00,000 मिलियम डालर हो गया विकसित देशों का भाग 66 प्रतिशत से बढकर 69 5 प्रतिशत हो गया व कम-विकसित देशों का भाग 28 प्रतिशत से घटकर 19 5 प्रतिशत रह गया [1]

(2) 1928-57 के बीच कम-विकसित देशों के निर्यात 50 प्रतिशत बढे, पर आयात 100% बढ गए [2]

(3) 1950-1962 के बीच विकसित देशों के निर्यात 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढे. समाजवादी देशों के निर्यात 11 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढे, पर कम-विकसित देशों के निर्यात केवल 3 4% प्रतिवर्ष बढे और आजकल तो केवल 2 2% प्रतिवर्ष ही बढे [3]

(4) 1970 में कम-विकसित देशों को 80 000 लाख डालर का व्यापार असंतुलन भुगतान पडेगा 1953-61 में deficit पाँच गुने बढ गए [4]

(5) आजकल कुल निर्यात आय का 11 प्रतिशत तो ऋणों के ब्याज व भुगतान में ही चला जाता है भारत तो 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष Debt service charge में दे देता है [5]

References
1. World Economic Survey : 1966
2. U. N. Statistical year Book 1966 : Reviewed in Free Press Journal 5 July 1967.
3. Ecafe rigion survey : Report in Patriot 24-3-1966.
4. U. N. Economic Survey of Asia and the Far East. 1957
5. U. N. Instability in Export Markets of developed Countries 1952. p. 6.

(6) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे प्रतिकूल भुगतान संतुलन के निम्नकारण रहते हैं[1] ·

(i) कृषि का पिछडापन कृषि उपज की सचय की कठिनाईयाँ.
(ii) निर्यातित वस्तुओ के भावो मे कमी तथा कृत्रिम वस्तुओ से प्रतियोगिता
(iii) आयातित वस्तुओ के भावो में वृद्धि तथा विकास के लिए मशीनो का भारी मात्रा मे आयात
(iv) विकसित देशों मे कम-विकसित देशो से आयात पर प्रतिबन्ध व अधिक मात्रा मे कर.
(v) कम-विकसित देशों की वस्तुओ का अपेक्षाकृत किस्म मे अच्छा न होना व महँगा होना
(vi) देश मे उत्पादन कम होना जिससे निर्यात के लिए कम वस्तुओ का उपलब्ध होना
(vii) इन देशों द्वारा 'अद्रव्य आयातों' की अधिकता होना, अर्थात तकनीकी विशेषज्ञो का वेतन, जहाज आदि के प्रयोग, व सार्वजनिक ऋण के व्याज व मूलधन के लिए निर्यात का बडा अश चला जाना

VII Backwash effects of international trade · अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दुष्प्रभाव .

आज कम-विकसित देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के Backwash effects से पीडित हैं Prof Gunnar Myrdal ने यह शब्द प्रयोग मे लाए उन्होंने बताया कि जहाँ विकसित देशो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा अन्य सपर्कों मे कम-विकसित देशो मे विकास कारक तत्वो व मनोवृत्ति को जन्म दिया, वही पर इन देशो ने कम-विकसित देशो मे कुछ अन्य ऐसी मनोवृत्तियाँ व तत्वो को उत्पन्न किया जो विकास में बाधक हैं. यह तत्व हैं कम-विकसित देशों द्वारा विकसित देशो के उत्पादन की जटिल पद्धतियो की नकल करना या विकसित देशों मे प्रयोग की जाने वाली वस्तुओ का प्रयोग करना कम-विकसित देशो के पास इतनी पूँजी तो होती नहीं है परन्तु वे अनावश्यक रूप से विकसित देशो जैसे कच्चे माल, उत्पादन पद्धतियो व सगठन पद्धतियो का प्रयोग करने लगते हैं जो सर्वथा हानिकारक होता है

---

1. I. L O : Repercussions of Commodity price Fluctuations on Primary Producing Countries in I. L. Review Vol. Lxxix No 6. June 1959.

प्रोफेसर मृडाल का कथन है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जहाँ लाभ होते हैं (Spread effects) वहाँ बहुधा वे क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान नहीं देते उनमें लापरवाही के कारण विकास नहीं हो पाता और इनमें backwash effects या हानिकारक प्रभाव पडते हैं इन क्षेत्रों म पूँजी नहीं लगाई जाती अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने ही कम-विकसित देशों में दुहरी अर्थव्यवस्था (duality) उत्पन्न कर दी है

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सचालन इस प्रकार रहा है कि विकसित देशों या साम्राज्यवादी देशों का तो विकास हुआ पर अधीनस्थ कम-विकसित देशों में वही पिछडापन बना रहा यहाँ आय वृद्धि के गुणक प्रभाव नहीं हुए जिससे अन्य क्षेत्रों का विकास हो सकता विकसित देशों ने कम-विकसित देशों से व्यापार करके लाभ कमा कर अपने देश के लिये पूँजी निर्माण किया

Prof Hla Myint के अनुसार कम-विकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के अध्ययन से हमको पता चलता है कि विकसित देश ही सारे लाभ उठाते हैं उनके शब्दों म

> "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने कम-विकसित देशों को सिवाय नई वस्तुओं की माँग करने के कोई और शिक्षा नहीं दी"

सक्षेप म, इन दोनों अर्थशास्त्रियों के अनुसार विकसित देशों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने कम-विकसित देशों को निम्न हानियाँ पहुँचाई हैं जो आज विकास में बाधक हो जाती हैं

(1) विकसित देशों ने कम-विकसित देशों से केवल कच्चे माल या कच्चे खनिज आयात किए जिनके मूल्यों म अधिक उच्चावचन के कारण इन देशों को व्यापार चक्रों की हानियाँ उठानी पड़ी

---

1. Gunnar Myrdal Economic Theory and under-developed Regions, London 1957
2. H W. Singer International Development. Growth & Charge p 12-15
3 B Higgins · Economic Development; Ch 15
4 H Myint . "The gains from International trade and the backward Countries," Review of Economics studies, Vol XXII No 2

(ii) कम-विकसित देशो के प्राकृतिक साधनो का दुरूपयोग किया गया तथा उन्हे गरीब बना दिया गया

(iii) विदेशी मुद्रा की आय से कम-विकसित देशो का विकास नही किया गया

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से व अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी विनियोजन से कम-विकसित देशो से विकसित देशो की ओर धन गया उदाहरणतया दक्षिणी अमेरिका से 1925 से 1929 तक के बीच 6600 लाख डालर तो लाभ के रूप मे बाहर गए जबकि पूँजी के रूप मे 2300 लाख डालर ही आए 1950 मे यह लाभ की मात्रा 7550 लाख डालर बाहर गए जबकि पूँजी की आमद केवल 330 लाख डालर रही

VIII Duality अर्थव्यवस्था का एक साथ विकसित तथा अविकसित होना, दुहरापन.

कम-विकसित देश 'कुल मिलाकर ही' कम विकसित होते है Arthur lewis के शब्दो मे In a sea of stagnation, there are is lands of development अर्थात ' पिछडेपन के समुद्र के बीच विकास के कुछ टापू मौजूद रहते है."

इन देशो मे विकास एक तरफा होता है (Lop-sided development) देश की अधिकाश जनसख्या पिछडे किस्म के गावो मे रहती है जबकि इन देशों के आधुनिकतम शहरो की भाँति शहर मौजूद रहते है देश के असख्य अनपढ, रुढिवादी, तथा पुराने आचार-विचार के व्यक्तियों के बीच सुशिक्षित तथा आधुनिक आचार-विचार वाले व्यक्ति (Sophisticated) होते है छोटी-छोटी दुकानो के साथ बडे बडे आधुनिक "डिपार्टमेन्टल स्टोर्स" मौजूद रहते है, देश में कुछ आधुनिक व बडे फार्मास व बगान के आसपास छोटे छोटे खेत मौजूद रहते है यहाँ पर छोटे उद्योगो के साथ बडे से बडे उद्योग भी पाए जाते है

1 F. A Mehta : "The Effects of Adverse income terms of trade on the Secular Growth of under-developed Countries "Indian Economic Journal, July 1956 & Jan 1957.

See : (I) W. Arthur Lewis "Development with unlimited supply of labour see lewis model in following pages.

(II) O S. Shrivastava, "Economics of wages, productvity Employment" Kailash pustak Sadan, Gwalior p 53.

उन्नत क्षेत्रो मे साख, यातायात शिक्षा व स्वास्थ्य, आवास व रहन-सहन की सुविधाएँ मौजूद रहती हैं इन क्षेत्रो म आर्थिक प्रतियोगिता तीव्र रहती है (Marginal profits are equal in all such islands of development)

कम-विकसित देशो मे इस प्रकार से उन्नत तथा पिछडे दोनो क्षेत्र रहते हैं पिछडे क्षेत्र (Subsistence sector) मे पुराने प्रकार की अर्थव्यवस्था तथा प्रारम्भिक श्रम विभाजन ही मौजूद रहता है, जबकि उन्नत क्षेत्र मे आधुनिकतम विनिमय-पद्धतियो से कार्य होता है पिछडा क्षेत्र उन्नत क्षेत्र का भी विकास रोकते हैं, क्योकि विकसित क्षेत्रो का बाजार इन कम-विकसित क्षेत्रो मे विकसित नही हो पाता कम-विकसित क्षेत्र की जनसख्या कम उत्पादक, गरीब, आसानी से नए कार्य व कार्य पद्धतियाँ न सीख सकने वाली होती है इस क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, बचत व पूजी की कमी, निम्न उत्पादकता के कारण माँग की कमी रहती है जिसके कारण विकसित क्षेत्र के उद्योग पनप नही पाते

IX Under-developed money market · Presence of non-monetized Sector . अर्धविकसित मुद्रा व्यवस्था

कम विकसित देशो मे मुद्रा बाजार अधिक विकसित नही होते इन देशो मे "Call loans" बाजार का अभाव होता है इन देशो मे "बिल बाजार" भी कम-विकसित रहता है देश के भिन्न भिन्न मुद्रा बाजारो मे सहसम्बन्ध बहुत कम रहता है, और देश के भिन्न भिन्न बाजारा म ब्याज की दरो में एकरूपता नही होता सगठित मुद्रा बाजार तक म आपसी सहयोग की कमी रहती है

इन देशो मे Deposit banking प्रणाली भी कम प्रचलित होती है जब कि U S. A तथा U K मे चलन मुद्रा से तीन चार गुनी मात्रा म माँग निक्षेप होते है, कम विकसित देशो में व आधी मात्रा म भी नही होते

कम-विकसित देशो मे अधिकाधिक व्यक्ति अपने धन को अपने पास रखते है और बैंको का प्रयोग कम करते है इन देशो मे केन्द्रीय बैंक देश के अधिकाश साख निर्माणकर्ताओ को नियन्त्रित करने मे प्रभावहीन रहता है. इन देशो म बैंक दर मे परिवर्तनो तथा खुले बाजार की नीतियों भी उतनी प्रभावशील नही हो पाती.

इन देशो मे मुद्रा-बाजार मे मौसमी शिथिलता तथा तेजी मौजूद रहती है. इस कारण फसलो के बोनी काल मे ब्याज की दर अधिक रहती है और अन्य

समय गिर जाती है. इन देशों में बहुधा विशिष्ट प्रकार की बैंकिंग की संस्थाओं का अभाव रहता है. देश मे औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली, उपभोग साख प्रदान करने वाली, विक्रय वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएँ तथा स्वीकृति गृह व कटौती गृहो की कमी रहती है

ग्रामीण क्षेत्रो म बैंको की सुविधा का अभाव रहता है यहाँ देशी बैंकर शोषण करते है ग्रामीण क्षेत्रो मे पूँजी रखने वाले व्यक्ति सोने, चाँदी के रूप मे धन रखते है सट्टो व भमि के व्यापार म धन लगाते है यहाँ उपभोग के लिए अधिक उधार लिया व दिया जाता है और उत्पादन के लिये पूँजी का अभाव बना रहता है. ये बैंकर देश के नियन्त्रण से बाहर बने रहते है

X Backwardness in Fiscal sector : राजकोषीय क्षेत्र व पिछड़ापन

कम-विकसित देशो मे प्रत्यक्ष करो से उतनी आय प्राप्त नही होती जितनी कि अप्रत्यक्ष करो से प्राप्त होती है. U S. A. एव U K. तथा जापान जैसे विकसित देशो मे आय करो से कुल राज्य की आय का क्रमश 78, 57 तथा 50 प्रतिशत भाग प्राप्त हो जाती है, भारत मे 1968-69 मे प्रत्यक्ष करो से केवल 24 प्रतिशत आय प्राप्त हुई. 1950-51 मे यह 36 प्रतिशत थी. इस प्रकार से हम देखते है कि कम-विकसित देशो मे अप्रत्यक्ष करो से आय प्राप्त करने की विशेषता रहती है. भारत की प्रथम योजना काल में अप्रत्यक्ष करो से 1373 करोड रु० की आय हुई थी जो 1966-67 से 1968-69 के तीन वर्षो मे ही 4478 करोड हो गई

कम-विकसित देशो में कर व्यवस्था लोचदार नही रहती, अर्थात् जैसे-जैसे इन देशो में आय बढती है, वैसे-वैसे करो से आय नही बढ पाती. भारत मे जी० एस० सोहरा के अनुसार केन्द्रीय करो की यह लोच ·613 है तथा केन्द्र व राज्य दोनो की कर आय लोच ·833 है.

कम-विकसित देशो मे प्रत्यक्ष करो से कम आय प्राप्त होने तथा कर व्यवस्था के कम लोचदार होने के मुख्य कारण यह है कि इन देशो मे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय कम रहती है. बहुत से व्यक्ति उचित रूप से हिसाब-किताब नही रखते और कर प्रशासन की ढील से तथा भ्रष्टाचार के कारण कर-वंचन भी बहुत होता है भारत मे उदाहरणतया, केवल एक प्रतिशत व्यक्ति ही आय-कर देते है और केवल 7 प्रतिशत राष्ट्रीय आय पर आय-कर दिया जाता है शेष 99 प्रतिशत व्यक्ति और 93 प्रतिशत आय पर आय कर नही दिया जाता

इन विशेषताओं के अतिरिक्त कम विकसित देशों में कर का अधिकाश भार शहरी क्षेत्रों पर रहता है भारत म ग्रामीण क्षेत्र म देश की 75 प्रतिशत जनसख्या रहती है परन्तु वह केवल देश म लगने वाले 15 प्रतिशत कर ही देती है शहरी क्षेत्र के 25 प्रतिशत व्यक्ति देश म 85 प्रतिशत कर देते है इन देशो मे ऊँची आय के लोगो पर कर भार भी अधिक रहता है. भारत म अधिकतम आय-कर 89 5 प्रतिशत हो जाता है जब कि प्रोफेसर काल्डार ने चाहा था कि देश मे अधिकतम आय-कर की मात्रा 45 प्रतिशत ही रहे

कृषि क्षेत्र सबसे कम कर देता है इसका कारण यह नही है कि कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है वरन् यह भी होता है कि इस क्षेत्र पर जो लगान द्वारा आय प्राप्त होती है वह बेलोचदार पद्धति होती है लगान से प्राप्त आय अपने आप आय-वृद्धि के साथ बढ़ती नही है उदाहरणतया, नेपाल म जहाँ 1952 मे कुल आय का 42% भाग लगान से प्राप्त हुआ वहाँ 1958 म केवल 24% भाग प्राप्त हुआ अफगानिस्तान मे 1951 म लगान का कुल आय मे से योगदान 12% से घटकर 1959 मे 3% रह गया और भारत मे यह प्रतिशत क्रमश 1939 मे 20% तथा 1968 म 7% ही था

कम-विकसित देशो मे न्यूनतम छूट की मात्रा भी अधिक उँची रहती है कम-विकसित देशो मे यह छूट प्रति व्यक्ति आय का 11 गुना से लेकर 19 गुना तक पाई गई है

XI Under-developed natural resources : कम-विकसित प्राकृतिक साधन

बहुधा यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशों में साधनो की कमी रहती है, परन्तु यह बात ठीक नही है वास्तव मे पिछडी तकनीक, भूगर्भ व प्राकृतिक साधनो सबधी व्यापक सर्वेक्षण की कमी के कारण ही इन देशो मे साधनो के प्रयोग की कमी रहती है तकनीक, पिछडेपन तथा पूजी, साहसियों और कुशल व्यक्तियो की कमी के कारण जो प्राकृतिक साधन है, उनका पूर्ण प्रयोग नही हो पाता

W. S Woytinsky तथा E. E. Woytinski के अनुसार केवल सिचाई सुविधाओ के बढा देने से ही ईराक मे खेतीहर भूमि की मात्रा 6 मिलियन एकड

W. S. Woytinsky and E E. Woytinsky, world population and production, Twentieth century fund, N Y 1953
See chapter on "Natural Resources" in next last.

से बढ़कर 20 मिलियन एकड हो जाएगी सीरिया मे भी 4 मिलियन एकड भूमि से बढ कर खेती योग्य भूमि 10 मिलियन एकड हो जाएगी तथा टर्की में 25 से 40 मिलियन एकड हो जाएगी भारत मे अभी भी 75 मिलियन एकड भूमि खेतिहर बनाई जा सकती है

A L Banks के अनुसार कम-विकसित देशो में पानी से पर्याप्त मात्रा में बिजली प्राप्त की जा सकती है परन्तु इन साधनो का बहुत कम प्रयोग हो पाता है अफ्रीका में विश्व की बिजली उत्पादन करने के लिए 44% पानी है, परन्तु उसने इस शक्ति का केवल 1% (या 1/10 प्रतिशत) ही प्रयोग किया है यूरोप अपनी पानी की शक्ति का 60% तक प्रयोग कर लेता है जबकि दक्षिणी अमेरिका मे केवल 3% प्रयोग होता है और एशिया में 13% प्रयोग हो पाता है

कम-विकसित देशो मे शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण खनिज हो जो यहाँ नही मिलता हो वन सम्पत्ति भी अपार है धन की कमी, यातायात की सुविधाओ की कमी, साहसियो की कमी या एकाधिकारियो के कारण इनका पूर्ण प्रयोग नही हो पाता विदेशी साहसियो ने इन्हे अपने देश के स्वार्थ के लिए ही प्रयोग किया

आज भी बहुत से प्राकृतिक साधन पूर्ण रुप से प्रयोग मे नही लाए जा रहे है. निम्नलिखित तालिका मे भूमि के प्रयोग की कमी को दर्शाया गया है

1 अमेरिका, अफ्रीका, न्यूगिनी, मेडगास्कर, बोरनियो	1000	लाख	एकड
2. टर्की, मिश्र, इरान, ईराक, सीरिया, इजराइल, लेबेनान जोर्डन	850	,,	,,
3 यूरोप मे (रूस को छोडकर) केवल	15	,,	,,
4. दक्षिणी अमेरिका	70	,,	,,
5. ओसेनिया	10	,,	,,

कई अन्य कारणो से भी प्राकृतिक साधनो का पूर्ण प्रयोग नही हो पाता. इनमें यह मुख्य है (1) अन्याय सगत भू-नियम, (2) जाति व रग-भेद नीति, (3) अस्वास्थ्यप्रद जलवायु तथा स्वास्थ्यप्रद सुविधाओ की कमी (4) राज्य की उदासीनता (5) बाजार की सीमितता तथा तकनीक का पिछडापन होना है.

1. A L Banks Ed : The development of tropical and sub-tropical countries 1954. P. 70

See : Charles E kellog : Food soil and people 1951, unescs. p. 23.

XII Absence of external economies वाह्य मितव्ययिताओं की कमी (Or Lack of economic and social overheads)

External economies या वाह्य मितव्ययितायें वे होती है जिनके प्रदान करने मे अर्थव्यवस्था की समस्त या बहुत सी इकाइयो को लाभ होता है. इन मितव्ययताओं मे देश की सड़के, रेलें, बन्दरगाह, सचार-साधन, बिजली, सिचाई सुविधाएँ बैंकों व साख सुविधाएँ, शक्ति सुविधाएँ, शिक्षा व ट्रेनिंग सुविधाएँ तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ शामिल है. इनको हम आर्थिक व सामाजिक ओवरहेड्स भी कहते है. कम-विकसित देशों मे इनकी सख्त कमी रहती है

निजीक्षेत्र इन वाह्य मितव्ययिताओं के बगैर विकास नही कर सकता. इसलिए इन वाह्य मितव्ययिताएँ (Infra structure or social and economic overheads) को प्रदान करना चाहिए क्योंकि इनके प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के पास न तो इतना धन होता है और न तो इतनी प्रेरणा ही होती है. इनकी कमी के कारण विकास मे बाधा होती है.

XIII Lack of enterprise and initiative and other co-operant factors. साहसियों तथा उत्पादन मे अन्य सहायक अंगों की कमी :

कम-विकसित देशों मे शुम्पीटर की कल्पना के साहसियों की नितान्त कमी होती है. यहाँ पर साहसियो का पेशा भी कुछ परिवारों और वह भी कुछ जाति-विशेषो तक सीमित रहता है इसके कारण देश का व्यापक विकास नही हो पाता इन देशो मे बजाय इसके कि बहुत से साहसी दीर्घकालीन विकास में रुचि रखते हो, वास्तव मे बहुत ही थोडे से साहसी होते है जोकि सट्टे के व्यापार, सूदखोरी करने, वितरण क्रियाओं मे धन लगाने में तथा सम्पत्ति के व्यापार में लगे रहते है इन देशों में बहुधा 'एकाधिकारी साहसी' पद्धति रहती है और यह साहसी प्राकृतिक साधनों व देश की जनशक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं.

साहसी मनोवृत्ति की कमी तो राज्य में भी रहती है. इन देशो मे प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी कमी रहती है. संगठनकर्ता व सचालक, आयोजक व प्रबधक, तथा कुशल मौद्रिक व राजकोषीयनीति विशेषज्ञो की कमी रहती है

इनके संबधित अध्याय द्वितीय भाग मे देखिए

XIV Backward Technology & Low Productivity
पिछड़ी तकनीक व कम उत्पादकता

पिछले पृष्ठ मे हम देख चुके है कि कम-विकसित देशो मे पूँजी निर्माण की मात्रा कम होती है. इसी कारण इन देशों मे उत्पादन तकनीक भी पिछड़ी रहती है इन देशो म पूँजी की कमी व जनशक्ति की अधिकता रहती हैं इस कारण यह देश श्रम-गहन तकनीक अपनाते है जो बहुधा पिछड़ेपन के कारण कम उत्पादक होती है इसके अतिरिक्त इन देशो मे शिक्षा की कमी व अनुसधान की कमी के कारण प्रशिक्षित व्यक्ति कम रहते है और इन कारणों से भी उन्नत तकनीक नही अपनाई जा पाती. इस कारण कम उत्पादकता रहती है

कम-विकसित देशो मे उत्पादकता सबधी आँकडो की कमी रहती है, परन्तु जो भी आँकडे है उनमे पता लगता है कि कम-विकसित देश बहुत पीछे है

> "भारत मे 1939 से 1959 के बीस वर्षों मे उत्पादकता 1% प्रतिवर्ष से बढी जबकि सयुक्तराष्ट्र अमेरिका मे इसी काल मे उत्पादकता तिगुनी दर से बढी " " यह स्थिति सर्वथा पिछडी अर्थ-व्यवस्था की द्योतक है. विकास के शुरू के काल मे उत्पादकता वृद्धि की अधिक सभावनाएँ रहती है जबकि विकसित होने पर यह दर गिर जाती है (जैसे किसी बच्चे के कद मे बढने की प्रवृत्ति होती है. वयस्क कम बढते है)."

रूस मे उत्पादकता आयोजन के प्रथम 25 वर्षो मे तो 7 5% प्रतिवर्ष से बढी (1928-1955).

कम-विकसित देशो मे उत्पादकता कम होने के मुख्य कारण यह है

(1) इन देशो में पूँजी की कमी के कारण 'सेकेंड हैंड" मशीनें, जिन्हे विकसित-देश नई मशीनें लगाने के बाद बेच देते है, प्रयोग मे लाई जाती हैं. यहाँ मशीनो की मरम्मत व अच्छी हालत मे बनाए रखने की कमी रहती हैं, इसके अलावा यहाँ पर घिसावट कोषो की कमी के के कारण पुरानी मशीनो का नई मशीनो से उचित प्रतिस्थापन नही होता

See · Dr. O S. Shrivastava "Economics of wages, productivity & Employment." Kailash Pustak Sadan, p 206 and p 193, (for Russian Figure)

(ii) यहा के उद्योगों का अनुकूलतम आकार नही होता अधिकाश उद्योग छाटे होने है जिसकी वजह से बाह्य मितव्ययताओ की कमी होती है

(iii) श्रम की शारीरिक कमजोरी, कार्य-कुशलता की कमी, उनके निम्न रहन सहन क स्तर, अशिक्षा, अन्धविश्वासो, और उत्साह की कमी के कारण भी उत्पादकता कम रहती है

(iv) इन देशो मे राज्य, श्रम सघ व उत्पादनकर्ताओ मे भी उत्पादकता वृद्धि के प्रति उदासीनता पाई जाती है

(v) इन देशो मे मजदूरी कम होती है श्रम को कार्यानुसार वेतन नही मिलता यहाँ पर वेतन इतने कम रहते है कि श्रमिकों मे अधिक मात्रा उत्पन्न करने की क्षमता व इच्छा का अभाव रहता है श्रमिको को लाभ मे उचित हिस्सा नही मिलता इन देशों मे श्रम आन्दोलन कमजोर रहता है और श्रम नेता बहुधा अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहने है इससे श्रम सघ सघर्ष में अधिक विश्वास रखते है उत्पादकता बढाने में सहयोग नही करते

(vi) बेरोजगारी, श्रम की गतिशीलता की कमी व रहन सहन के निम्न स्तर के कारण व्यक्तिगत व सामाजिक उत्पादकता कम रहती है

(vii) इन देशो में कुशल साहसियों व सगठनकर्ताओ की भी कमी रहती है.

(viii) इन देशो में बाजार सकुचित रहते है. अतृप्त आवश्यकताओं और वगैर बिके सामान की स्थिति इन देशो में रहती है.

XV Inefficient, Corrupt and apathetic Governmental machinery अयोग्य, भ्रष्ट तथा उदासीन शासकीय प्रशासन .

कम-विकसित देशो मे बहुत अधिक राजनैतिक अस्थिरता पाई जाती है. जनतन्त्र तथा तानाशाही यहाँ दोनों असफल होने नजर आते हैं. बहुत से कम-विकसित देशो ने हाल के 25-30 वर्षों में साम्राज्यवादी देशो से स्वतन्त्रता पाई है. कुछ देशो को छोड कर इन देशो में योग्य व उत्साही नेताओ का अभाव पाया गया है. बहुत से कम-विकसित देशों में आए दिन राजनैतिक तख्ता पलट (Coup de tat) होते रहते हैं. कम-विकसित देशो में कालान्तर में राजनैतिक नेता अपने या अपनी जाति, वर्ग या पार्टी के स्वार्थ हित मे लग जाते है. ये स्वय भ्रष्ट होते है और समस्त सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला देते हैं. इनकी कथनी और

करनी में अन्तर होता ह और ये नेता (leaders) फिर (misleaders) गुमराह करने वाले बन जाते हैं पद लोलुपता मे पडे ये नेता, विकास की ओर कितना ध्यान दे सकते हैं

Prof Gunnar Myrdal ने 1968 मे एक पुस्तक world Corruption की समस्या पर निकाली है उसमे उन्होंने लिखा ह कि कम-विकसित देशो म विकसित देशो के मुकाबले मे सर्वाधिक भ्रष्टाचार है कम-विकसित देशो में एशिया व इन्डोनेशिया में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है

आज की स्थिति यह है कि बहुत से कर्मचारी व राजनैतिक नेता जिनके हाथ में सार्वजनिक धन व शक्ति है वे या तो अपनी शक्ति या धन या दोनो का दुरुपयोग करते हैं

Sir Winston Churchill ने एक बार कहा था

> 'सफल नेता वह होता है जो आज यह कहे कि कल वह क्या करने वाला है और फिर कल यह कह सके कि वह प्रस्तावित कार्य क्यो नही कर सका".

Shri Sanjiva Reddy ने (अध्यक्ष-लोकसभा, कांग्रेस अध्यक्ष, आन्ध्र के मुख्य-मन्त्री व केन्द्र के मन्त्री के महत्वपूर्ण पदो पर जो कार्य कर चुके हैं) एक बार कहा था

> पहले वही व्यक्ति (राजनैतिक नेता या पदाधिकारी) भ्रष्ट समझा जाता था जिसे न्यायालय भ्रष्ट घोषित कर दे आज हर उस व्यक्ति को भ्रष्ट समझा जाता है जिसे न्यायालय यह घोषित न कर दे कि वह भ्रष्ट नही है"

इन्ही कारणो से जनता का उत्साह कम होता है और देश की मनोवृत्ति धन कमाने की होती है, विकास करने से ध्यान हट जाता है

XVI Inhibitory social factors सामाजिक पिछड़ापन व विकास मे बाधाएँ

कम-विकसित देशो म बहुत से सामाजिक, धार्मिक व सास्कृतिक तत्व हैं जो विकास मे बाधक होते है. यहाँ के (विशेष रूप से एशिया के) व्यक्ति इस लोक से अधिक "परलोक" को सुधारने में अधिक रुचि रखते है ईश्वर पर अधविश्वास उन्हें निष्क्रिय बनाता है, जातिवाद या धार्मिक प्रतिबन्धों के कारण व्यवसायिक गतिशीलता की कमी रहती है

शिक्षा के प्रति उदासीनता से रूढिवादिता, अयोग्यता तथा अज्ञानता बनी रहती है (उदाहरणतया झासी जिले मे माताटीला बाध का पानी जब सिचाई के लिए छोडा गया तो कई किसानो ने उसका प्रयोग करने से इन्कार कर दिया क्योकि उनके अनुसार 'उस पानी की बिजली निकल जाने मे उसके गुण समाप्त हो गए थे," बाद मे कई नेताओ को यह भ्रान्ति दूर करनी पडी)

इन्ही कारणो से इन देशो मे धार्मिक कार्यो मे बहुत धन खर्च कर देते हैं तथा बचतो को सस्थाकरण करने के स्थान पर सोना चादी के रूप मे रखते है. इन्ही कारणो से इन देशो मे स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कार्यक्रमो को लागू करने मे बाधा उत्पन्न होती हैं

अध्याय 4

आर्थिक विकास के मॉडलों का स्वभाव व महत्व

The nature and Importance of Economic growth models

1 **मॉडल का अर्थ** ·
किन्डल बरजर, प्रो० मेहता, जी० मीयर, आदि.

2 **मॉडलो के प्रकार :**
- (1) Aggregate models (कुल मॉडल)
- (2) Sector models (क्षेत्रीय मॉडल)
- (3) Inter-industry models (अन्तर-उद्योग मॉडल)
- (4) Single period models (समय विशेष का मॉडल)
- (5) Long period models (दीर्घकालीन मॉडल)
- (6) Macro dynamic model (वृहद्-प्रवैगिक आर्थिक विकास मॉडल)
- (7) Descriptive, mathematical and econometric models, (विश्लेषणात्मक, गणित मॉडल तथा एकोनोमेट्रिक मॉडल).
- (8) Linear and non-linear models.
- (9) Closed and open models

3. **विकास मॉडलों का महत्व व सीमाएं :**

अध्याय 4

आर्थिक विकास के मॉडलों का स्वभाव व महत्व

The nature and importance of economic growth models

I परिभाषा

श्री किन्डल वर्जर[1] के शब्दों में " 'एक आर्थिक मॉडल" विभिन्न परिवर्तनशील आर्थिक तत्वों व घटकों के बीच सह सम्बन्ध की व्याख्या करता है एक मॉडल प्रमुख तत्वों में कारण व परिणाम संबंध बनाता है हम मॉडल के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की गति का अध्ययन कर सकते हैं बहुधा इस बात को शीघ्रता व सरलता से समझने के लिए हम बहुत सी जटिलताओं को निकाल देते हैं, अर्थात् कुछ सरल मान्यताओं के आधार पर अध्ययन करते हैं

हम अपने मॉडलों को गद्य मे व्यक्त कर सकते हैं, या ज्योमेट्री' के रूप मे व्यक्त कर सकते है या फिर बीजगणित व अकगणित की भाषा में व्यक्त कर सकते हैं. मॉडल की विशेषता यह होती है कि आर्थिक तत्वों व घटकों के सह-सम्बन्ध को हम साख्यकीय द्वारा नाप सकते हैं [1]

प्रो० जे० के० मेहता[2] मॉडल बनाने से पूर्व हम, कुछ वे मान्यताएँ मानते है, जिनके आधार पर अर्थ-व्यवस्था चलती है इन मान्यताओं पर आधारित सह-सम्बन्धों को हम गणित के साँचों मे ढाल देते हैं इन सह-सम्बन्धों के आधार पर एक साथ समीकरण बनाये जाते हैं और हल किये जाते हैं फिर इन गणित के सह-सम्बन्धों के समीकरणों से आर्थिक सम्बन्धों का निष्कर्षरूपी विश्लेषण हो जाता है (इसे हम उसी प्रकार मे करते है, जैसे · एक भौतिक शास्त्री "ध्वनी तरंगों" को "रेडियो तरंगों" मे बदल देते हैं और उन्हे सब तरफ फैलाकर पुन. "ध्वनी तरंगों" में बदल लेते है).

---

(1) C. P. Kindle berger : Economic Development : p. 40.
(2) J. K. Mehta ; Economics of growth · p. 5.

हमारे मॉडल के कुछ Parameters (स्थिर राशियाँ) होते है और कुछ Variables (परिवर्तनशील राशियाँ) होते हैं. यह Parameters प्राकृतिक हो सकते हैं या उत्पादन-कर्ताओं व उपभोग-कर्ताओं के निर्णयो के आधार पर निर्धारित होते हैं. विकास मॉडलो मे Parameters की सीमा मे Variables निर्धारित होते हैं. जब हम अपने मॉडल मे Variables का साम्य अध्ययन करते है तो यह स्थगिक मॉडल होता है और अगर हम इन परिवर्तनशील घटको का परिवर्तन पथ अध्ययन करते है तो यह प्रवैगिक मॉडल हो जाता है.

हम मॉडलो मे बहुधा "वृहद् प्रवैगिक तत्वों" को जो माँग और पूर्ति दोनो पक्षो के होते हैं तथा जो समाज की आय मे परिवर्तन लाते है, अध्ययन करते है

प्रो. जी मीयर :

प्रो जी. मीयर के अनुसार 'A model provides a Systematic frame work for economic programming."

प्रो. मीयर का कथन है ' एक आर्थिक मॉडल किसी भी आर्थिक इकाई (चाहे वह एक घर हो, या एक उद्योग हो या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो) को सचालित *करने वाले सगठित सह-सबधो का वर्णन करता है* वैसे तो हमारे *आर्थिक सबधो* का वर्णन हम करते ही रहते है परन्तु जब हम इन आर्थिक सबधो को गणित के शब्दो मे व्यक्त करते है तो वे explicit model होते है (स्पष्ट मॉडल) *अन्यथा "शब्दो के माध्यम से विश्लेषण" को हम* Implicit model *उपलक्षित* मॉडल कहेगे

हर देश मे कुछ आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने होते है. हमारे आर्थिक मॉडल हमको इन्ही लक्ष्यो के प्राप्त करने के रास्ते बतलाते है. The ultimate test of a model is that it should make the best use of the available information and analytical resources within the time available for its construction.

II मॉडलो के प्रकार व विभिन्न नाम .

1 Aggregate models (समष्टि मॉडल) ये वे मॉडल होते है जो

Cf : Gerald Meier : Leading Issues in Development Economics Oxford 1964, p. 465-467.

समस्त अर्थव्यवस्था के लिए होते हैं इन मॉडलो मे उत्पादन, उपभोग, विनियोजन तथा अन्य घटकों को एक पूरा aggregate माना जाता है.

2 Sector models · (क्षेत्रीय मॉडल) ये वे मॉडल होते हैं जो केवल एक Sector विशेष में लागू होते हैं और इसी प्रकार से बनाए भी जाते हैं.

3. Inter-Industry models अन्तर-उद्योग मॉडल :

इन मॉडलों में हम यह अध्ययन करते हैं कि प्रत्येक Sector model का आपस में क्या सबध है तथा इनका पूर्ण अर्थव्यवस्था से क्या सबध है.

4. A Single period model एक समय विशेष का मॉडल

एक समय विशेष के मॉडल म निम्नलिखित चार सह-सबधों के आधार पर विश्लेषण करते है और मॉडल बनाते हैं ये तो चार सह-सबध है

(i) Capital-output ratio पूंजी-उत्पादन अनुपात

(ii) The investment demand schedule. विनियोजन-माँग तालिका.

(iii) The saving supply schedule बचत-पूर्ति तालिका.

(iv) The Population Growth relations. जनसख्या वृद्धि सबधानुपात.

5 The long-period model · दीर्घकालीन मॉडल ·

किसी भी देश में ऐसा मॉडल नही बनाया जा सकता जो बहुत लम्बे काल के लिए उपयुक्त बना रहे. ऐसा मॉडल कभी नही बनाया जा सकता जिसके अनुसार एक

1—3 : See : Gerald Meier op. Cit

4 : Harvey Leibenatein : Economic Backwardness & Economic Growth p 195

5 . Prof Hoffmann : Cf. comments on Robertson's paper on "Stability and progress—Richer Country's Problem, First International Congress of International Eco. Association 1958". In I. E. A's : Stability & progress in world Economy : Ed. D. C. Hague.

देश गरीबी मे अमीरी को पहुँच जाए अल्पकालीन मॉडल मे Constant rates and ratios (अर्थात उदाहरणतया पूँजी-उत्पादन अनुपात, या आय बचत अनुपात समान माने जा सकते हैं) की मान्यता की जा सकती है परन्तु दीर्घकाल मे यह मान्यता गलत हो जाती है.

दीर्घकालीन मॉडल 'Straight line' के स्वभाव के नही हो सकते अर्थात् एक सी विकास दर के नही हो सकते इसलिए वास्तव में दीर्घकालीन मॉडल कई अल्पकालीन मॉडलो में तोडा जाता है या कई अल्पकालीन मॉडलो को मिलाकर ही एक दीर्घकालीन मॉडल बन सकता है. परन्तु हर अल्पकालीन मॉडल मे rates and ratios (दरे व अनुपात) अलग-अलग होते हैं

6 Macro dynamic economic growth Models : **वृहद-प्रवैगिक आर्थिक विकास मॉडल** ·

ये मॉडल बहुत वृहद समष्टि या सग्रह Large aggregates से सबधित होते है इन मॉडलो में हम यह अध्ययन करते है कि किस प्रकार से विनियोजन व आय बढे कि साहसियो को अपनी आकाक्षाओं और अनुमानो के अनुसार नतीजे प्राप्त हो सकें परन्तु ये मॉडल सुस्थिर रूप से विकास की समस्याओं पर प्रकाश नही डालते. (They do not throw much light on the problem of stable growth)

वृहद-प्रवैगिक आर्थिक मॉडल से अधिक व्यवहारिक महत्व के Sectoral Models या क्षेत्रीय मॉडल होते हैं.

7 Descriptive mathematical and econometric models **विश्लेषणात्मक, गणित मॉडल तथा ऐकोनोमैट्रिक मॉडल**

पहले विकास सबधी विचारो को तथा मह सबधो की व्याख्या को साधारण व सरल भाषा में व्यक्त किया जाता था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विचार इसी रूप से व्यक्त किए गए थे. ये Implicit models या Descriptive models थे.

बाद मे अर्थशास्त्र मे गणित का प्रयोग किया जाने लगा. इधर descriptive models इतने लबे होने लगे कि उनके सार को Mathematical model में परिणित करना बहुत लाभदायक रहा. Mathematical model सक्षिप्त होने के साथ साथ Precise या निश्चित या स्पष्ट भी थे

केंस न अपने माडल म Multiplier या गुणक का प्रयोग किया तत्पश्चात हरोड व डोमर न Accelerator का प्रयोग किया Prof Erich Schneider के शब्दा म गुणक तथा त्वरक का बाद म जब औपचारिक विवाह हो गया तब माडल और जटिल होन गए

8 Linear and Non linear Models

शुरू म माडल Linear हात थ अर्थात वह बतात थ कि विकास का पथ सीधा है बाद म इस अवास्तविकता को छोड दिया गया और Non linar model बनाए जान लग इन माडलों म विकास की उच्चतम सामा व न्यूनतम सामाएँ रखा जाती है इन माडला म विकास म Symmetry का मायना या विकास का यथा-समगत रूप में बढन की मायना के स्थान पर Asymmetrical रूप म बढना माना गया Non linear माडला बाह्य-तत्वा के प्रभावा का भी समावश किया गया (Exogeneous shocks were taken note of) प्रो० हेबरलर के शब्दों म आज Econometric models इस दर से बनाए जा रह ह जसे कि कारखाना से मोटरो के माडल निकल रह ह

9 Closed and open models बन्द व खुल माडल

जिन माडला म विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जाता व माडल Closed model कह जात ह तथा जिन मा लो म यह प्रभाव अध्ययन किया जाता ह व Open model होत ह

Closed model अवास्तविक होत ह परन्तु व सरल अध्ययन के लिए अध्ययन किए जात है

III Importance and limitations of growth models विकास माडलो की पद्धति का महत्व व सीमाएँ

विकास के हमशा कुछ न य रहत ह किसी भी देश म विकास का लक्ष्य देश म

Erich Schneider s quoted from his comments on prof perronx paper on The Quest for stability The real factors Ist conference of International conference of economists I E A op cit Ed D C Hague

Gottfried Haberler quoted from D C Hague s op cit The Quest for stability The monetary factors

पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना, अधिकतम आय का सृजन करना, प्रतिकूल भुगतान सतुलन को दूर करना या कुछ और भी हो सकता है.

विकास मॉडल हमको बतलाते है कि किस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न विकास घटकों के बीच सह-सबध है या होना चाहिए तथा वे यह भी बतलाते है कि विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने का कौन सा पथ सुगम व सरल है. अगर हम मॉडलो से सह-सबधो के परिवर्तनो की मात्रा में परिवर्तन का अन्दाज लगा सकें तो हम आवश्यक सुधार भी कर सकते है.

मॉडल हमेशा कुछ मान्यताओ पर आधारित रहते है अगर मॉडलो को वास्तविक होना है तो इन मान्यताओं को भी वास्तविक होना चाहिए अन्यथा मॉडल अवास्तविक रह जाएगा

सीमाऐ

मॉडल अध्ययन पद्धति की कुछ सीमाऐ भी है

(1) अगर मॉडल अवास्तविक मान्यताओ पर आधारित हो तो मॉडल भी अवास्तविक हो जायेगें

(11) मॉडलो मे मुद्रा, बैंक, साख मुद्रा व मुद्रा सस्थाओ को, ब्याज की दर तथा मूल्य परिवर्तनो को मुख्य स्थान नही मिलता इनमे बचत व विनियोजन, उत्पादन अनुपातो को प्रमुख स्थान मिल पाता है प्रोफेसर हेबरलर के अनुसार इसके परिणाम निराशाजनक होते है.

(111) प्रो जे के मेहता ने अपनी पुस्तक "Economics of growth" की प्रस्तावना मे लिखा है 'गणित विश्लेषण का महत्वपूर्ण साधन है, परन्तु उसको उस आर्थिक प्रष्टि विषय, जिसका उसे विश्लेषण करना है, उसे ही आच्छादित नही कर देना चाहिए"

See also : "We can-not approve of a model that yields income increasing at an exponential rate, nor any that makes it increase evenly and smoothly with mathematical precision, what is needed, therefore, is a model that gives us uneven oscillations of income around an unevenly rising trend"

J K Mehta : op. cit p. 167.

प्रो० मेहता का कथन है कि हर वह मॉडल जो आय परिवर्तनों को पूर्ण शुद्धता से बतलाता है हमको मान्य नहीं हो सकता मानव आचरण को कभी भी पूर्ण शुद्धता से व्यक्त नहीं किया जा सकता

> पूर्ण यथार्थता का मॉडल अवास्तविक होगा और वास्तविक मॉडल हम बना नहीं सकते

(IV) एवसी डोमर भी इसी प्रकार कहते है "हम विकास मॉडलों को व्यवहारिक पथ प्रदर्शक के रूप में प्रयोग करने का प्रलोभन हमेशा रहता है पर ऐसा करने मे हम गहरी खाइयों मे गिर सकते है. हमारे मॉडल जो विकास की दरें दिखलाते है वे कागज पर ही रह जाती है. हमारी मान्यताएँ बहुधा गम्भीर रूप से अव्यवहारिक (Heroic abstractory) होती है

Evsey domar, "Essay in the theory of Economic growth" oxford N 7 1957. P. 13.

5

अध्याय : 5

एडम स्मिथ का विकास मॉडल

(Adam Smith on growth)

I प्रस्तावना

1 विकास भूमि, श्रम, पूंजी व सगठन के सहयोग का फल है

2 आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है

3 विकास के लिए निर्बाधवादी नीति या स्वतन्त्रता आवश्यक है राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए

4 विकास अधिक लाभ पर निर्भर है लाभ, मजदूरी व ब्याज में सबध.

5 विकास सतुलित होना चाहिए कृषि व उद्योग को समान महत्व

6 विकास के लिए स्वतन्त्र व्यापार आवश्यक है

7 निम्नकोटि' के व्यक्तियो की जनसख्या वृद्धि पर नियन्त्रण होना चाहिए.

8 विकास प्रक्रिया उत्तरोत्तर और सचीय रूप से होने वाली प्रक्रिया है.

II आलोचनात्मक समीक्षा

मॉडल के गुण

मॉडल के दोष ·

अध्याय : 5

एडम स्मिथ का विकास मॉडल

(Adam Smith on growth)

प्रस्तावना

एडम स्मिथ ने, जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते है, 'वेल्थ ऑफ नेशन्स" नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होने विकास दटाने वाले आर्थिक व सामाजिक तत्वो का गहन अध्ययन किया Wealth शब्द का प्रयोग उन्होंने उस अर्थ म किया था जिसमें आज हम national income शब्द का प्रयोग करते है. अगर एडम स्मिथ आज उस पुस्तक को लिखते तो उस पुस्तक का नाम 'National income of Nations" रखते

एडम स्मिथ के विकास सबधी सिद्धान्तो की हम निम्नलिखित विवेचना कर सकते है.

1 विकास, भूमि, श्रम, पूंजी व सगठन के सहयोग का फल है Growth is a function of land, labour, capital and organisation

एडम स्मिथ विकास को भूमि, श्रम, पूजी व सगठन के सहयोग का फल मानते थे, भूमि निष्क्रिय होती है श्रम, भूमि से अधिक महत्वपूर्ण होता है पर पूँजी व श्रम में वे किसको महत्वपूर्ण मानते थे, इसका सही अन्दाज उनकी पुस्तक में नही मिलता क्योकि कही उन्होने श्रम को अधिक महत्वपूर्ण और कही पूँजी को अधिक महत्वपूर्ण माना. श्रम के बारे में उन्होंने एक जगह लिखा

> **"श्रम ही वह खजाना है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाओं और आवश्यकताओं को प्रदान करता है"**

पर जैसे जैसे हम स्मिथ के विकास के सिद्धान्त का अधिक अध्ययन करते है, तो हम पाते है कि वे बचत व पूंजी को ही विकासकारक प्रमुख तत्व मानते थे (Capital was regarded by him as engine of growth)

---

1. देखिये,
 Introduction to his book 'Wealth of Nations" (Edwin Cannan Edition) 1950

एडम स्मिथ विवेकपूर्ण व्यय व किफायतसारी या मितव्ययिता को विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, उन्होने लिखा

> "पूंजी मितव्ययिता से बढती है और फिजूलखर्ची व दुराचरण से घटती है मेहनत से अधिक मितव्ययिता से पूंजी संचित होती है."
> "Capitals are increased by parsimony and diminished by prodigality and misconduct... . parsimony and not industry is the immediate cause of the increase of capital "[1]

एडम स्मिथ मुद्रा व श्रम-विभाजन के बाद, पूंजी को ही विकासकारक सबसे महत्वपूर्ण घटक मानते थे उन्होने लिखा

> "यह जाहिर है कि किसी भी देश में उत्पादक श्रमिको की संख्या उसी मात्रा में बढ सकती है जिस अनुपात मे देश में पूंजी का सचय बढ सकता है .. देश में पूंजी वृद्धि या कमी के अनुपात में ही देश में उत्पादक श्रमिको, उद्योगो, श्रम व भूमि का उत्पादन, वास्तविक धन व देशवासियों की आय बढती या घटती है "[1]

2 आर्थिक विकास श्रम विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है :
(Economic growth takes place through the principle of division of labour)

एडम स्मिथ के अनुसार विकास श्रम-विभाजन के विस्तार व सफलता पर निर्भर है वे श्रम-विभाजन को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होने अपनी पुस्तक का पहला अध्याय ही 'श्रम विभाजन' पर लिखा उनके अनुसार श्रम-विभाजन वृहत् समाज के सहयोग का ही एक अग है श्रम विभाजन विनिमय पर आधारित होता है और दोनो के होने से ही उत्पादन व राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है श्रम विभाजन से ही श्रमिको की दक्षता व कुशलता बढती है उत्पादन का समय बचता है व अच्छी व अधिक वस्तुऍं कम लागत मे बैठती है इसी से लाभ बढते है, बाजार विस्तृत होते है तथा आविष्कारो की संख्या बढती है

श्रम-विभाजन का विस्तार बाजार के विस्तार पर निर्भर करता है इसी कारण एडम स्मिथ बाजार विस्तार के लिए साम्राज्य के विस्तार की सिफारिश करते थे और अधिक पूंजी सचय की सलाह देते थे

1. See volume I Book. II.
2 Op Cit : Ibid.

3 विकास के लिए निर्बाधवाद नीति या स्वतन्त्रता आवश्यक राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए (Freedom and policy of laissez faire necessary for growth Role of the government to be minimum

एडम स्मिथ का विश्वास था कि निजी क्षेत्र के विकास से ही देश का विकास होता है वे चाहते थे कि राज्य केवल देश मे न्याय व सुरक्षा का प्रबन्ध करे तथा कुछ आवश्यक सार्वजनिक निर्माण कार्य भी (जैसे सडक निर्माण, बन्दरगाह बनाना, नहरें व यातायात विस्तार) हाथ में ले स्वास्थ्य व शिक्षा विकास का कार्य भी राज्य अपने हाथ में ले सकता है वे नहीं चाहते थे कि राज्य आर्थिक क्षेत्र मे दखल दे या स्वय उद्योग चलाए क्योंकि राज्य के कर्मचारी अकुशल, लापरवाह, भ्रष्ट तथा अकर्मण्य होते है राज्य चलाने वाले व्यापारिक जगत की वास्तविकता से परे रहते है इस कारण गलत काम करते है और फिजूलखर्ची करते है उन्होने कहा था

> "The government are always and without any exception and greatest spendthrift in society."[1]

एडम स्मिथ बहुमुखी कर चाहते थे, पर वे लाभ पर कर नही चाहते थे क्योंकि इसमे पूँजी निर्माण कम होता है. उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति अपने भले के लिये जो कार्य करेगा उससे देश मे विकास होगा अगर हर व्यक्ति को अपना पेशा, विनियोजन चुनने और मूल्य निर्धारण करने की स्वतन्त्रता हो तो देश मे आर्थिक विकास स्वय होगा उन्होने कहा

> "किसी भी देश को निम्नकोटि की बर्बरता से उच्चतमकोटि की समृद्धि की स्थिति में पहुँचने के लिये सिवाय देश में शान्ति, कम व सरल कर, व उचित न्य य के किसी और चीज की आवश्यक्ता नहीं है ऐसी स्थिति में विकास तो प्राकृतिक रूप से होगा अर्थात स्वय चालित होगा"[2]

4. विकास अधिक लाभ पर निर्भर है · लाभ व मजदूरी और व्याज · (Growth a function of high profits · profits vs wages and interest)

एडम स्मिथ लाभ व पूँजी निर्माण को परस्पर सम्बन्धित मानते थे. लाभ अधिक

1. Cf : His book. I op Cit Vol I
2 Cf · Book IV : Ch IX

होंगे, पर उनको भय था कि दीर्घकाल मे, प्रतियोगिता के कारण, लाभ कम होते जाएँगे. उन्होने लिखा :

> **"जब स्टाक (पूँजी में वृद्धि) होती है, तो मजदूरी बढती है, पर लाभ गिर जाते हैं जब बहुत से धनी व्यापारी अपनी पूँजी एक ही व्यापार या उद्योग में लगा देते हैं, तो उनकी परस्पर प्रतियोगिता से लाभ कम हो जाते हैं '[1]**

एडम स्मिथ का विश्वास था कि लाभ और मजदूरी मे प्रतिकूल सबध होता है. अर्थात अगर मजदूरी कम हो तब ही लाभ अधिक होंगे. केवल एक नये उपनिवेश दोनो एकसाथ बढ सकते है. इसी डर उन्होने अपनी पुस्तक मे अधिक स्थानो पर कम मजदूरी देने की सिफारिश की. उनका कथन था कि अगर मजदूरों को अधिक मजदूरी दी गई तो वे अधिक बच्चे पैदा करेंगे और इसलिए उनको जीवन निर्वाह के बराबर ही मजदूरी दी जाए ताकि लाभ अधिक रहे.

परन्तु अन्य स्थानों पर उन्होंने मजदूरों के अन्य सिद्धान्तो का भी विश्लेषण किया. कही कही पर तो उन्होंने मजदूरो के प्रति बहुत उदारता दिखाई. उनका कथन था कि अगर देश मे विनियोजन की मात्रा व दर अधिक बनाई रखी जाए तथा अगर उत्पादन, उत्पादकता व रोजगार के स्तर ऊँचे रखे जाएँ तो अधिक मजदूरी दी जा सकती है और यह विकास में बाधक नही होगी. उन्होने यह भी कहा

> "यह आवश्यक है कि जो दूसरो को खिलाते हैं व कपडे पहनाते है, वे स्वय भी अच्छा खाएँ व पहने."

परन्तु एडम स्मिथ को भय था कि दीर्घकाल मे लाभ कम हो जाएँगे, मजदूरी जीवन निर्वाह के स्तर के बराबर रह जायगी और अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाएगी, जिसके आगे विकास सभव नही होगा

5. **एडम स्मिथ "संतुलित विकास" चाहते थे (Growth to be 'balanced') कृषि व उद्योग को समान महत्व :**

आमतौर से यह धारणा है कि एडम स्मिथ औद्योगीकरण के प्रबल समर्थक थे. हालाँकि वे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रान्ति के युग के प्रथम द्रष्टा थे, वे "फिजियोक्रेट्स" के प्रभाव मे थे, और कृषि की उन्नति को विकास मे महत्वपूर्ण मानते थे. उन्होने लिखा :

> "जितने व्यक्ति कृषि मे कार्य करते है, अगर उतने ही औद्योगिक

1. Cf : Op. cit. : P. 70 100

> उत्पादन में भी लगा दिए जाएँ तो वे कभी भी उतना पुनरुत्पादन नही कर सकते. उद्योगो मे प्रकृति का कोई योगदान नही होता, सब कुछ मनुष्य ही करता है."[1]

कृषि के बाद, वे उद्योगों व व्यापार के विस्तार को विकास के लिए आवश्यक मानते थे, पर वे उद्योगों व व्यापार में लगे व्यक्तियों की धाखाधडी व शोषण की प्रवृत्तियों के आलोचक थे. विकास के लिए वे बाह्य-मितव्ययिताओं के सृजन को आवश्यक मानते थे, अर्थात् यातायात सचार के साधनों का विकास चाहते थे. उनका विश्वास था कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र का विकास-कारक हो.

6. **विकास के लिए स्वतन्त्र व्यापार आवश्यक : (Free trade promotes growth)**

एडम स्मिथ मुक्त व्यापार के समर्थक थे और उनका विश्वास था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता है. वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अनावश्यक नियमों, बन्दिशों, तटकरों और प्रतिबन्धों से मुक्त कराना चाहते थे जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हैं और आवश्यकतानुसार विदेशी वस्तुएँ मगाई जा सकती हैं. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बाजार बढता है, श्रम विभाजन का विस्तार होता है, उत्पादन प्रणाली के विशिष्टीकरण में वृद्धि होती है तथा बहुउद्देश्योय विनिमय बढता है यह सब आर्थिक विकास को बढावा देते है. उन्होंने लिखा :

> **"यह सब समझदार परिवारों के मुखियो (Masters of families) का सिद्धान्त है कि जो कुछ वस्तु वे बाहर से सस्ता खरीद सकते हैं वह उन्हे घर पर महंगा नहीं बनाना चाहिए यह बात अगर एक व्यक्ति के लिए विवेकपूर्ण व अक्लमंद बात है तो राज्य के लिए मूर्खतापूर्ण नही हो सकती."[2]**

वे केवल सुरक्षा उद्योगों के लिए 'संरक्षण' की नीति को उचित मानते थे. क्योंकि वे 'सुरक्षा' को समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे. (Defence is more important than opulence).

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वे किसी विशेष मुद्रा-व्यवस्था को नही चाहते थे. वे तो केवल 'स्वर्णमान' चाहते थे. और वे सोने व चाँदी के निर्यात या आयात पर

1. Ibid. p. 161.
2. Vol. I : Book II.

भी, वस्तुओं के निर्यात या आयात की भांति, कोई प्रतिबन्ध नही चाहते थे. उनका विश्वास था कि स्वर्णमान स्वय संचालित होता है. जैसे अगर देश में *आयात अधिक होता है और स्वर्ण बाहर जाता है तो मूल्य गिर जाएँगे* (वस्तुओ के बाहर से आने व मुद्रा की कमी से) और मूल्य गिरने से लोग देश की वस्तुओ का प्रयोग करेंगे और विदेशी भी देश से सामान मँगाएगे, और निर्यात बढेगें, व आयात कम होगे तथा स्वर्ण वापिस आ जाएगा. वे कहते थे .

> "Look after trade and gold will look after itself." (**आप व्यापार पर ध्यान दीजिए सोना खुद अपने पर ध्यान रखेगा**).

7. **"निम्नकोटि" के व्यक्तियो की जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण हो.** (Population growth of the "inferior ranks" to be controlled)

एडम स्मिथ के "प्रकृतिवाद व आशावाद" के कारण वैसे तो उनका विश्वास था कि जनसख्या जब कभी भी अधिक हुई तो मृत्यु दर की अधिकता से जनसख्या *का स्तर फिर सतुलित हो जाएगा*, फिर भी वे चाहते थे कि *"निम्न श्रेणी"* के लोगो को जनसख्या नियन्त्रित रखना चाहिए, अन्यथा विकास रुक जाएगा.

8. **एडम स्मिथ विकास प्रक्रिया को उत्तरोत्तर और संचित रूप से बढने वाली प्रक्रिया मानते थे.** (Growth is a gradual and cumulative process).

एडम स्मिथ का विश्वास था कि एक बार विकास शुरू हो गया तो देश मे विकास होता ही रहेगा. विकास की राह मे कोई मन्दी की बाधा नही आयेगी. उनका विश्वास था कि माँग और पूर्ति सतुलित रहेंगे और पूर्ति अपनी माँग स्वय पैदा कर लेगी, इस कारण देश में कभी बेरोजगारी का भय नही होगा

उन्होने विकास की प्रक्रिया की *अन्तर-खण्ड वृत्तीय रूप से सबन्धित माना* (He emphasized that there is inter-sectoral relationship in growth) जो कि इस प्रकार होती है.

अगर हम अधिक बचतें कर सकते है तो अधिक पूँजी निर्माण होगा, श्रम विभाजन मे विस्तार होगा, अधिक विनियोजन होगा, उत्पादकता बढेगी, लाभ बढेंगे, रोज़गार बढेगा, राष्ट्रीय व प्रतिव्यक्ति आय बढेगी, माँग या बाजार बढेगा, विशिष्टीकरण

उन्नत होगा तथा इससे और अधिक श्रम विभाजन बढ़ेगा और बचत व पूँजी निर्माण मे वृद्धि होगी

उनका विश्वास था कि स्थिर वास्तविक मजदूरी पर असीमित श्रम शक्ति जब तक प्राप्त है पूँजी निर्माण से विकास हो सकता है और मजदूरी स्थिर रखना चाहिए व लाभ बढ़ते रहने देना चाहिए जब मजदूरी बढ़ेगी तब इस पद्धति से विकास रुक जाएगा [1]

C : आलोचनात्मक समीक्षा

मॉडल के गुण :

(1) एडम स्मिथ ने बचता की वृद्धि के लिए जो मितव्ययिता से रहने की आवश्यकता बताई है वह आज के विकासशील देशो के लिए महत्वपूर्ण है

(2) एडम स्मिथ ने पूँजी निर्माण को engine of growth बताया यह भी आज के विकासशील देशो को ध्यान देने योग्य बात है

(3) एडम स्मिथ ने growth from bottom अर्थात नीचे (आधार) से विकास की सिफारिश की, अर्थात उन्होंने कृषि को सर्वप्रथम उन्नत करने की सिफारिश की यह बात आज भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है जहाँ कि 10 व्यक्तियो मे से जो 7 व्यक्ति कृषि मे लगे है वे न तो अपने लिए और न बाकी तीन व्यक्तियों के लिए उत्तम, पर्याप्त मात्रा में सतुलित आहार प्रदान कर पाते है और करोड़ो रुपये के अनाज बाहर से मँगाना पड़ता है जिससे हम विदेशों से मशीनें मँगा सकते थे

(4) एडम स्मिथ ने विकास को सतुलित रूप में बढ़ाने की सिफारिश की, उनके माडल की यह अच्छाई थी कि उन्होंने श्रम विभाजन के विस्तार को महत्व दिया व अन्तर-खण्डवृत्तीय के निर्भरता को समझाया

(5) कुछ हद तक हम उनकी निर्बाधवादी नीति को भी अच्छा मान सकते है भारत में ही राज्य के अधिकाश कारखाने व व्यवसाय हानि में चल रहे है और पूँजी निर्माण के स्थान पर पूँजी ह्रास के कारण बने हुए हैं श्री ब्रह्मानन्द प्रसाद ने लिखा, "Adam Smith's advention for creation of suitable climate for

---

1 : इसकी और अधिक व्याख्या के लिए Nurkse-Lewis model देखिए.

a freer expression of 'self-interest' for achieving general well-being has some relevance for our conditions unimaginative pursuance (of planning) can be the cause of showing down of enterpreneurial efforts and ultimately the econony may slide back to stagnation [1]

मॉडल की कमियाँ व दोष :

(1) उन्होंने अपने विकास मॉडल म साहसी को महत्व नही दिया जो सर्वथा गलत था

(2) वे राज्य को जो कम महत्व देते हैं वह ठीक नहीं हैं राज्य ही आज कम-विकसित देशो म विकास का कार्य शुरु करता है उसकी सहायता व प्रत्यक्ष कार्यो के बगैर आज के युग मे विकास सभव नही है

(6) एडम स्मिथ के व्यापार चक्रो के सम्बन्ध में जो आशावादी विचार थे वे सर्वथा त्रुटिपूर्ण थे इनके विकास के सिद्धान्त म इस बात का कोई जिक्र नही है कि व्यापार चक्र कैसे उत्पन्न होते हैं तथा इनको कैसे ठीक किया जा सकता हैं अथवा अर्थ-व्यवस्था मे स्थायित्व कैसे लाया जा सकता हैं वे यह नही मानते थे कि देश में कभी अनैच्छिक वेरोजगारी उत्पन्न हो सकती हैं. आज ऐसा विकास का सिद्धान्त जिसमें बेरोजगारी को दूर करने का समाधान न हो अर्थ-शास्त्र में कोई स्थान नही रखता.

(4) वे अनावश्यक रूप से 'गतिहीन अर्थ व्यवस्था" Stationary state से भयभीत थे. उनका विश्वास था कि साधनो के पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने पर तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण "स्थिर अर्थ-व्यवस्था" की स्थिति पर पहुँच जायेगे. लाभ के गिरने पर अर्थ-व्यवस्था विकास हीन हो जाएगी और समस्त अर्थ-व्यवस्था का विकास दुखो की स्थिति मे परिणत हो जाएगा (*Progress of societies must* end in shallows and miseries

1. Brahmanand Prasad, Adam Smith and Economic growth and its relevance to India" I E Association's number on economic growth XIV

(5) एडम स्मिथ का यह विचार था कि विकास में सब वर्गों का लाभ होता है मार्क्स ने गलत सिद्ध किया अगर राज्य हस्तक्षेप नही करता है तो समाज के कुछ ही वर्ग विकास का लाभ उठाते हैं

References

1 Adam Smith Wealth of Nations
2 „ „ „ , (Summary form in ' studies in Economic Development Ed Burnard Okun & R W Richardson, Holt Rimart & Winston
3 Meier and Balidwin Economic development Theory History and policy
4 Benjamin Higgins Economic development
5 Kindleberger Economic development
6 Nasir Khan Problems of growth in an under developed Economy
7 Gide & Rest A History of Economic Thought
8 Alexander Gray The development of Economic Doctrine
9 Eric Roll History of Economic Thought
10 D Bright Singh Economic development
11 Haney History of Economic Thought
12 O H Taylor A ,
13 Spiegel (Ed) *The development of* Economic Thought
14 Frank Neff Economic Doctrine

अध्याय : 6

रिकार्डो का विकास मॉडल

(Ricardian Growth Model)

I प्रस्तावना

II मॉडल के तत्व

1. विकास को जन्म पूजी देती है
2. अधिक पूजी निर्माण के लिए लाभ अधिक व मजदूरी कम होना चाहिए
3. लाभों को अधिक रखने के लिए वे चाहते थे कि राज्य लाभ पर कर न लगाए व उसके राजकोषीय कार्य कम से कम हो.
4. अधिक लाभ के लिए मुक्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक.

III मॉडल के गुण व दोष .

अध्याय : 6

रिकार्डो का विकास मॉडल

(Ricardian Growth Model)

I प्रस्तावना

प्रो एच टेलर[1], रिकार्डो को "अथशास्त्र का जनक" मानते थे उनके अनुसार एडम स्मिथ तो "अर्थशास्त्र के बाबा" (Grand-father) थे. मियर और बाल्डविन के अनुसार[2] "एडम स्मिथ जो कुछ विकास के सिद्धान्त मे ठीक से नही समझ पाया उसी को रिकार्डो न ठीक से समझाया, (explained the theory of economic development in rigourous fashion)."

सी. पी. किण्डल बग्जर[3] रिकार्डो को विकास पर लिखने वालो मे महत्वपूर्ण नही मानते है उनका कथन है, "रिकार्डो आय के वितरण व विदेशी व्यापार के सिद्धान्त मे अधिक दिलचस्पी रखते थे उन्होने विकास के सिद्धान्त प्रतिपादित करने मे कोई महत्वपूर्ण योगदान नही दिया वे अपनी पुस्तक म यही बताते रहे कि अगर और अधिक खेती योग्य भूमि की खोज नही की जाती या विदेशो से सस्ते खाद्यान्न के मँगाने का प्रबन्ध नही होता तो विकास रुक जाएगा "

रिकार्डो का विकास का सिद्धान्त न तो युक्ति सगत रहा और न तो उसकी ठीक से व्याख्या ही की गई उनके विकास मॉडल के मुख्य तत्व नीचे दिए जाते है

1 O. H. Taylor History of Economic Thought

2. Meier & Baldwin : Economic Development, Asia publishing House 1962 p 27-49.

3. Kindleberger : Economic Development, p 41-42.

II मॉडल के तत्व

(1) विकास को पूंजी सचय जन्म देती है (Capital is engine of growth)

किसी भी देश का आर्थिक विकास, रिकार्डो के अनुसार, पृजी की मात्रा पर निर्भर करता है अधिक पूजी सचय अधिक लाभ पर निर्भर है, अधिक लाभ जीवन स्तर पर स्थिर मजदूरी पर निर्भर है, स्थिर मजदूरी खाद्यान्न की प्राप्ति पर निर्भर रहती है, खाद्यान्न की प्राप्ति भूमि की मात्रा या आयात पर निर्भर रहती है. उन्होने लिखा :

> "अगर किसी देश मे श्रमिको की मात्रा अधिक है, तो इसका अर्थ सही माने मे यह है कि उन्हें काम पर लगाने के लिए पर्याप्त पूँजी नही है "[1]

विकास मे पूँजीपति का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है रिकार्डो के अनुसार पूँजीपति ही सगठन करता है और जोखिम उठाता है वे ही बचत करके पूजी निर्माण करते हैं वे ही जमीदार से भूमि लेकर उसे लगान देते हैं पूँजीपति ही श्रमिको को रोजगार देते हैं व राष्ट्रीय आय बढाते है

पूँजीपति ही विकास को जन्म देते है तथा उसे बनाए रखते है वे ही देश का औद्योगीकरण करते हैं पूजीपति हमेशा अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं इसके लिए नए आविष्कार करते है और बाजार का विस्तार करते है पूजीपति अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रो मे लगे विनियोजन से समान सीमान्त लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते है और इसके लिए वे अपने साधनो का अनुकूलतम वितरण करते हैं (They try to secure optimum allocation of resources)

रिकार्डो के विचार मे पूजीपति के अतिरिक्त और कोई भी बचत करके पूजी निर्माण नही करता—(भूमिपति भी नही) और इस कारण पूजीपति के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति या सस्था विकास को न तो जन्म देता है और न आगे बढाता है

---

1 Ricardo Notes on Malthus principles of Political Economy p 241.

(2) अधिक पूंजी निर्माण के लिए लाभ अधिक व मजदूरी कम होना चाहिए (High capital accumulation is a function of high profits which in turn is a function of low wages always being equal to subsistence level)

रिकार्डो का कथन था कि लाभ अधिक होने पर ही पूंजी निर्माण अधिक हो सकता है, और अधिक लाभ केवल कम मजदूरी रखने पर ही प्राप्त हो सकता है. रिकार्डो लाभ व मजदूरी को एक दूसरे से प्रतिकूल दिशा मे सबंधित मानते थे इसलिए वे चाहते थे कि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर आवश्यक स्तर पर स्थिर रहना चाहिए वे माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त से भयभीत हो गए थे और विश्वास करते थे कि अगर मजदूरी की मात्रा बढ़ाई गई तो मजदूर और बच्चे पैदा कर लेंगे जिससे वास्तविक मजदूरी पुन गिरकर जीवन निर्वाह स्तर पर आजाएगी

रिकार्डो न केवल मजदूरी को जीवन निर्वाह के स्तर पर स्थिर रखना चाहते थे वरन् वे मजदूरों को "सामाजिक सुरक्षा" के लाभ देने के भी विपक्ष में थे (इसीलिए वे इंगलैंड म Poor Laws को, जिसके अन्तर्गत बेरोजगारों को राहत दी जाती थी, समाप्त कराना चाहते थे) उनका कथन था

> ' ऐसे लोगों के खाने का प्रबन्ध करके आप मानवों की असीमित माँग को उत्पन्न करते हैं "[1]

रिकार्डो को इस बात का कभी भी डर नहीं था कि मजदूरी को जीवन निर्वाह स्तर पर रखने से देश में कभी प्रभावशाली माँग कम होगी

रिकार्डो के मॉडल में अन बिके सामान की कोई सर्वव्यापी समस्या नहीं है (There is no problem of a general glut of commodities in the Ricardian model) उनके विचार में राष्ट्रीय आय का जो भी भाग मजदूरी लगान, ब्याज या लाभ के रूप में दिया जाता है, वह पूर्ण रूप से व्यय में आ जाता है और जो बचतें होती है वे पूर्ण रूप से विनियोजित हो जाती है इस प्रकार ये व विकास के लिए मजदूरी को स्थिर रख जाने व लाभ को अधिकाधिक बढ़ाने की सिफारिश करते थे

---

1 P. Sraffa (Ed) The Works and Correspondence of David Ricardo. Cambridge University press, 1951 p. 125

(3) लाभो को अधिक रखने के लिए वे चाहते थे कि राज्य लाभ पर कर न लगाए व उसकी राजकोषीय कार्य कम से कम हो (For maintaining high profits fiscal activities of the State should be minimum and profits should not be taxed)

(1) रिकार्डो ने अपनी पुस्तक मे विस्तार से अध्ययन किया कि किन मदो पर कर लगाना चाहिए और किन पर नही इसमे कोई आश्चर्य नही कि वे लाभ पर कोई कर नही चाहते थे क्योकि, उनके विचार से इससे पूँजी निर्माण पर बुरा असर पड़ता है (2) वे कच्चे माल पर भी इसी कारण से कर लगाने के विपक्ष मे थे, क्योकि इसके कारण मूल्य बढेगे जिससे मजदूरी बढानी पडेगी, और फिर लाभ कम हो जाएँगे और यह कर भी लाभ पर कर हो जाएगा (3) इसी कारण से वे आवश्यक उपभोग वस्तुओ पर भी कर नही चाहते थे (4) वे तो लगान पर भी कर लगाने के विपक्ष मे थे क्योकि इससे अगर खेती मे कमी की गई तो खाद्यान्न के भाव बढेंगे और मजदूरी बढानी पडेगी जिससे लाभ कम होगे

वे तो केवल विलासिताओ की वस्तुओ पर अधिक कर चाहते थे

(4) अधिक लाभ के लिए मुक्त राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक (High profits—a function of free commerce and free international trade, based on comparative cost advantage)

रिकार्डो विकास के लिए मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार चाहते थे जिसमे कई लाभ होते है : (1) मुक्त व्यापार से सस्ते दामो पर खाद्यान्न मँगाया जा सकता है जिससे मजदूरी दर नीची व लाभ ऊँचे रह सकते है (2) इससे देश को प्राकृतिक साधनो का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है व राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के विस्तार से विशिष्टीकरण बढता है (3) इससे राष्ट्रीय व विश्व आय मे वृद्धि होती है इस आय से पूँजी निर्माण होती है और फिर और अधिक विनियोजन व आर्थिक विकास होता है रिकार्डो के अनुसार मुक्त व्यापार से उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है, विलक्षण कुशलता पुरस्कृत होती है तथा प्राकृतिक साधनो का अनुकूलतम उपयोग व वितरण होता है, जिससे आर्थिक विकास होता है

रिकार्डो इन्ही लाभो को ध्यान मे रखकर, एडम स्मिथ की भाँति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर किसी प्रकार के तटकरो को नही चाहते थे वे भी अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए स्वर्णमान चाहते थे तथा स्वतन्त्र मुद्रा विनिमय प्रणाली चाहते थे

III आलोचनात्मक समीक्षा :

मॉडल के गुण

(1) रिकार्डो के मॉडल मे पूँजी सचय पर अधिक महत्व दिया है और पूँजी सचय के लिए उन्होने बचत बढाने को महत्व दिया

(2) लाभ की मात्रा को अधिक बनाए रखने के लिए भी वे अधिक जोर देते थे वे राज्य द्वारा व्यापारिक सस्थानो के लाभ पर प्रहार के पूर्ण रूप से विरोधी थे

(3) उन्होने जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढाने पर महत्व दिया है वह भी उचित है

(4) रिकार्डो का मॉडल Macro dynamic है अर्थात यह गतिशील है परस्पर आर्थिक सबधो का अध्ययन करता है तथा पूरी अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन करता है

मॉडल के दोष [1]रिकार्डो के इन्ही विचारो ने अर्थशास्त्र को 'निराशा का विज्ञान' की सज्ञा दिलाई Schumpeter ने इसे a big detour कहा

(1) रिकार्डो ने अपने मॉडल म श्रम व तकनीक का विकास मे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसपर समुचित ध्यान नही दिया

(2) वे घोर निराशा-वादी थे उन्हे बढती हुई जनसख्या व घटती हुई उपज का भय हमेशा सताता था व प्रकृति को कृपण मानते थे, और उनका विश्वास था कि अन्त मे उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण 'स्थिर या गतिहीन व विकासहीन" अर्थ व्यवस्था, पहुँच जाने से भयभीत थे

(3) गतिहीन व विकासहीन अर्थव्यवस्था

रिकार्डो का विश्वास था कि दीर्घकाल मे लगान बढता जाएगा, मजदूरी की मौद्रिक मात्रा बढती जाएगी, क्योकि गल्ले का मूल्य उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार बढता रहेगा (पर वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है) और लाभ गिरते जाते है लाभ के गिरने से पूँजी सचय भी गिर जाता है बगैर लाभ के पूँजी सचय सभव नही होगा इस प्रवृत्ति को हम इस प्रकार से दर्शा सकते है .

1 Kindleberger. op cit. p 44
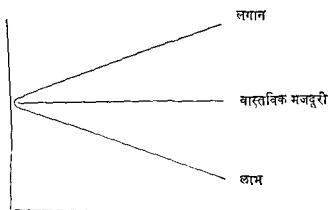
रिकार्डो ने इस प्रकार से भूमि की कमी व उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण स्थिर अर्थ-व्यवस्था की कल्पना की उन्होने लिखा

> 'जैसे-जैसे समाज म धन वृद्धि होती है और अधिक खाद्यान्न के उत्पादन के लिए अधिकाधिक आदमी लगते है इससे लाभ गिर जाते हैं आवश्यकताओ के मूल्य बढते है व मजदूरी बढती है और जब कृषक की उपज का मूल्य उसके द्वारा दी जाने वाली मजदूरी के बराबर हो जाता है तो कृषि का आगे विस्तार बन्द हो जाता है और पूँजी सचय रुक जाता है श्रमिकों की माँग कम हो जाती हैं और इसके आगे जनसख्या भी नही बढ पाती "
>
> Long indeed before this period, the very low rate of profits will have arrested all accumulation, and almost the whole produce of the country, after paying the laboures will be the property of the owners of land and the receivers of tithes and taxes" (See :—Principles of Political Economy Everyman's edition London 1911, p. 71-72

(4) रिकार्डो का कथन था कि 'उत्पादन के अध्ययन से अधिक वितरण' की समस्याओ का अध्ययन महत्वपूर्ण है फिर भी आश्चर्य है कि व मजदूरो को कम मजदूरी देते रहने की ही सिफारिश करते रहते थे

और उन्हे प्रभावशील माँग के गिरने और मन्दी व glut का भय नहो था.

(5) गरीब वर्ग की जनसख्या को उन्होंने income elastic माना था, अर्थात् आय बढने से जनसख्या बढ जाएगी. पर अधिक आय वालो के यहाँ जन्म दर कम रहती है वे तो माल्थस से बढ़कर माल्थस थे

(6) उन्होंने विकास को जन्म देने मे राज्य के महत्व को नही समझा.

(7) उनकी गतिहीन अर्थव्यवस्था की कल्पना निर्मूल थी.

•

References : Adam Smith के अध्याय मे उद्धृत references के अतिरिक्त यह और

(1) Oswald St. Clair : A key to Ricardo

(2) Nag, D. S. : Economics of under developed countries.

(3) Mark Blaug : Recardian Economic.

अध्याय 7

माल्थस का विकास मॉडल

Malthus on Economic growth

I प्रस्तावना

II मॉडल के मुख्य तत्व

1 विकास के लिए पूजी आवश्यव

2 श्रम विभाजन, आन्तरिक व

3 वाह्य बाजार का विस्तार आवश्यक

4 तकनीक उन्नति आवश्यक

5 देश में उचित राजनैतिक व सामाजिक स्थिति आवश्यक

6 जनसख्या नियत्रण आवश्यक, जनसख्या व विकास

7 विकास के लिए प्रभावशील माग अधिक होना चाहिए व बचत की भी अधिकतम सीमा होना चाहिए

8 कम विकसित देश व विकास

III माल्थस के मॉडल की समीक्षा उनका आशावाद व उदारता

अध्याय 7

मालथस का विकास मॉडल

Malthus on Economic growth

I. प्रस्तावना

माल्थस अर्थशास्त्र की आधार शिला रखने वाले परम्परागत अर्थशास्त्रियों के निर्मातियों में से एक थे. वे "जनसंख्या के अर्थशास्त्र" Economics of Demography के जनक थे. अर्थशास्त्र में वे निराशावादी प्रवृत्ति को भरने वाले माने जाते है. परन्तु यह दुर्भाग्य है कि हम माल्थस को केवल उनके जनसंख्या के सिद्धान्त से ही जानते है विकास सबन्धी उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण थे और अगर हम कहे कि वे केन्स के प्रेरणा स्रोत थे, तो गलत न होगा. उनका विकास मॉडल रिकार्डो की भाँति निराशापूर्ण नही था हम जो उनके विकास के सम्बन्ध में विचार पढ़ेंगे तो हमको स्वय ही भ्रम पैदा हो जाएगा कि क्या यह विचार इतने पुराने अर्थशास्त्री के हो सकते है.

विकास मॉडल के मुख्य तत्व

1. **विकास के लिए पूंजी आवश्यक** . Growth, a function of capital
एडम स्मिथ व रिकार्डो की भाँति वे भी विकास को जन्म देने और कायम रखने के लिए पूँजी सचय को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. उन्होंने कहा

> "पूँजी निरन्तर वृद्धि के बगैर देश के धन में कभी भी निरन्तर व स्थायी वृद्धि नही हो सकती."

इस कारण माल्थस पूँजीपति के योगदान को विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते है.

There is scarcely any inquiry more curious, or, from its importance *more worthy of attention, than that which traces the* causes which practically check the progress of wealth in different countries, and stop it, or make it proceed very slowly while the power of production remains comparatively undiminished, or at least would furnish the means of a great and abundant increase of produce and population
Principles of Political Economy, 2nd Ed (London : William Pickering 1836, IV. 309.

2. **श्रम विभाजन, आन्तरिक व बाह्य बाजार का विस्तार आवश्यक :** extension of division of labour, and internal and external market necessary for growth.

वे भी श्रम विभाजन के विस्तार को महत्व देते थे. उनका कथन था "Internal and external commerce increases exchangeable value"

3 **बाह्य मितव्ययिताएँ आवश्यक** · Investment in economic and social overheads important for growth.

"बाह्य मितव्ययिताएँ' यह शब्द हमारे अर्थशास्त्र मे मार्शल की देन है, पर बहुत पहले माल्थस ने देश म economic overheads (जैसे सडक यातायात, सचय साधन बैंक आदि) के विकास पर बल दिया और वे Social overheads का मौजूद होना भी विकास के लिए आवश्यक मानते थे (Social overheads पर व्यय का अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग पर व्यय से है)

4 **तकनीकी उन्नति आवश्यक :** Technological advance necessary

माल्थस ने 'तकनीक' को विकास का एक अलग से महत्वपूर्ण घटक माना (Independent factor growth) उनका कथन था कि नई मशीन से वस्तुएँ सस्ती पैदा होती है, जिससे देश मे प्रभावशील माँग बढती है, तथा मालिको के लाभ बढते है और बाजार के विस्तार से श्रमविभाजन का विस्तार होता है अधिक माँग होने से देश मे रोजगार वृद्धि होती है वे मशीनो के लगाने से बेरोजगारी फैलेगी, ऐसा नही मानते थे उन्होने लिखा

> 'There is little reason to apprehnd any permanent evil from the increase of machinery,"

5 Favourable state of politics and morals necessary, **देश में उचित राजनैतिक व सामाजिक स्थिति आवश्यक ·**

माल्थस ने विकास के तीन मुख्य तत्व माने थे (1) अच्छी उपजाऊ भूमि, (ii) पर्याप्त पूँजी व (iii) अधिकाधिक उन्नत तकनीक, साथ ही उन्होने विकास के लिए निम्नलिखित तत्वो को महत्वपूर्ण माना

(i) देश में अच्छा सविधान, अच्छे नियम तथा अच्छा प्रशासन
(ii) निजी सपत्ति को बनाने की सुविधा व सुरक्षा

Malthus : (i) Principles of Political Economy.
(ii) An Essay on Population.

(iii) जनता मे मेहनत की आदत
(iv) जनता का न्यायपूर्ण व सदाचारी होना (Rectitude of character and moral standard)
(v) उत्पादन व वितरण के कार्यों मे समन्वय

6. जनसख्या नियत्रण आवश्यक · Population control–a must

माल्थस ने विकास को अवरुद्ध करने मे जनसख्या वृद्धि को सबसे बड़ा दोषी माना. सक्षेप मे हम उनका विश्व-विख्यात 'जनसख्या का सिद्धान्त' अध्ययन करें

माल्थस ने बताया कि जनसख्या, की वृद्धि को रोका न गया, तो वह 'ज्योमेट्रिक प्रोगरेशन' मे बढेगी, अर्थात 1 2 4 8 16 32 64 128 आदि के अनुपात म बढेगी, और हर 25 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी इसके विपरीत खाद्यान्न 'अर्थमेटिक प्रोगरेशन' से बढेगा, 1 2 3 4 के अनुपात मे बढेगा जनसख्या की इस प्रकार से, खाद्यान्न वृद्धि से तेजी से बढने की प्रवृत्ति है और जब जनसख्या अधिक हो जाएगी तो प्रत्यक्ष अवरोधो के कारण (बीमारियाँ, युद्ध, अकाल आदि) जनसख्या पुन घट जायेगी माल्थस का विश्वास था कि उत्पत्ति मे ह्रास नियम के लागू होन पर जनसख्या के तेजी से बढने से देश की जनसख्या का बडा भाग हमेशा जीवन निर्वाह के बराबर स्तर पर रहेगा.

माल्थस के इस विचारो की ऐसे शब्दो मे आलोचना की गई कि उनके पहले या बाद मे किसी अर्थशास्त्री के लिए इतने कठोर अपशब्दो का प्रयोग नही किया गया उनको "मानवता की आशाओ पर पानी फेरनेवाले काले राक्षस" तक कह डाला गया माल्थस के जनसख्या के सिद्धान्त की निम्नलिखित मुख्य आलोचनाएँ की गई .

(1) विश्व के कई देशो में जनसख्या 25 सालो मे दुगुनी हुई है पर अगर हम पूरे विश्व को लें तो जनसख्या 25 वर्षों मे दुगुनी नही होती अगर ऐसा हुआ होता तो आज विश्व मे खडे होने की जगह न होती शिक्षा के विस्तार से, स्त्रियो की सामाजिक उन्नति से, ऊच्च स्तर के जीवन यापन की चाह के कारण, अच्छे खाने के कारण, Increased social capillarity (समाज में ऊपर जाने की चाह), तथा परिवार नियोजन सबधी उपकरणो की उपलब्धि के कारण जन्म दरो मे भारी कमी आई है फ्रान्स में तो घटती जनसख्या की समस्या सामने है

(ii) आधुनिक युग मे पुराने युग की "औद्योगिक क्रान्ति" की भांति "कृषि क्रान्ति" होने के लक्ष्य है कीटनाशक दवाओ के प्रयोग, उत्तम

बीज की प्राप्ति, बड़ी सिंचाई योजनाओं के शुरू होने से तथा अन्य उर्वरकों की उपलब्धि से खाद्यान्न के उत्पादन में कई गुनी वृद्धि की सम्भावनाएँ सामने आई हैं पिछले कुछ वर्षों पहले तक अमेरिका को अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को बेचने की समस्या सामने थी

(iii) जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष अवरोधों के परिणामस्वरूप मृत्युदर में वृद्धि का डर भी आज उतना नहीं है चिकित्सा विज्ञान में चमत्कारी उन्नति, राज्य के कल्याणकारी कार्यों में विस्तार, व अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के कारण आज अकाल मौतें नहीं होने दी जाती हैं.

(iv) आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या का स्थिर रहना जरुरी नहीं हैं. संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, तथा आस्ट्रेलिया में विश्व के कई अन्य देशों के मुकाबले में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही हैं, फिर भी यह देश विश्व के प्रतिव्यक्ति आय के अनुसार, सबसे प्रमुख देशों में हैं. अधिक जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि दर से विकास दर गिरी नहीं और न ही अधिक विकास दर से जनसंख्या वृद्धि ही रुकी[1].

केवल जनसंख्या के सिद्धान्त के आधार पर माल्थस को निराशावाद का अवतार माना गया. परन्तु उनके न केवल 'विकास के सिद्धान्त'' पर विचार बहुत ही सही थे, वरन् स्वयं जनसंख्या पर उनके विचार सही थे. अपने जनसंख्या सिद्धान्त के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के बाद उन्होंने जनसंख्या सम्बन्धी और जाँच व खोज की और धीरे धीरे उनके विचार वास्तविकता की ओर अधिकाधिक आ गए विकास व जनसंख्या के संबंध के बारे में उन्होंने लिखा

> "That a continued increase of population is a powerful and necessary element of increasing demand, will be readily conceded, but that the increase of population alone or more properly speaking, the pressure of population against limits of subsistence does not furnish an effective stimulus to the continued increase in wealth, is not only evident in theory but is confirmed by universal experience"[2] अर्थात्, जन-

1. Henry Villard Economic Development
2. Okun & Richard . Condensed version of Malthus principles p 50.

> सख्या वृद्धि से प्रभावशील माँग वढेगी परन्तु निरन्तर जनसख्या वृद्धि से खाद्य सामग्री की कमी सामने आएगी और राष्ट्रीय आय की वृद्धि रुकेगी–यह बात न केवल सैद्धान्तिक रूप से ठीक है, वरन् समस्त विश्व के अनुभव पर भी आधारित है

कम-विकसित देशो (जिनमे उन्होने एशिया व अफ्रीका को शामिल किया) में उन्होने बढती हुई जनसख्या को asset (पूजी या विकास वर्धक) नही माना वरन् liability (उत्तरदायित्व) के रूप म देखा और कहा कि इन देशो मे दरिद्र व अविवेकी तथा अदूरदर्शी व्यक्ति सर्वथा अधिक बच्चे उत्पन्न करते रहते है और विकास में बाधक होते है इन देशो म जन्म व मृत्यु दर अधिक रहती है और बहुत से बच्चे युवा होने से पहले मर जाते है यह केवल उपभोग कर्ता रहते है और उत्पादन में वृद्धि योग्य होने से पहले ही मर जाते है

> "Thus, there is nothing automatic about economic growth" according to Malthus "A high rate of capital accumulation and a sustained rate of economic growth will dependupon our capacity to control population, among other things"

उन्होने यह भी लिखा

> "A man whose only possession is his labour make can effectual demand if his labour is not wanted It will be found that those states often make the slowest progress in wealth where the stimulus arising from the population"[1] alone is the greatest. (अर्थात् एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति केवल उसकी श्रमशक्ति है, देश की प्रभावशाली माँग मे जब तक वृद्धि नही कर सकता जब तक कि उसके श्रम की माँग न हो उन देशो मे धन में वृद्धि (आय में वृद्धि) सबसे कम होगी जहाँ कि विकास को प्रवृत्त करने वाले तत्वो मे जनसख्या वृद्धि ही प्रमुख हो)

आज के युग में भी माल्थस के जनसख्या और विकास सम्बन्धी विचार पूर्ण रूप से ठीक है आपने "जनसख्या सिद्धात के सातवें सस्करण मे वे जनसख्या नियत्रण

1. Malthus . Principles . ch vii see (iv) p.

व खाद्य सामग्री को हर 25 वर्षों मे दुगना कर सकने को भी सभव मानने लगे थे

7. विकास के लिए प्रभावशाली माँग अधिक रहना चाहिए
Growth, a function of high effective demand.
(Malthus Theory of glut aud Malthus on optimum propensity to save.)

जब कि एडम स्मिथ व रिकार्डो, जे बी से के इस विचार से सहमत थे कि "हर पूर्ति अपनी माँग पैदा कर लेती है" और इस लिए कभी भी समस्त क्षेत्रो मे या सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था मे मन्दी नही आ सकती, माल्थस इस बात को नही मानते थे उनका विश्वास था कि देश मे प्रभावशाली माँग की कमी के कारण विकास रुकेगा और अगर प्रभावशाली माँग बनी रहे तो विकास होता रहेगा इसी विचार के लिए आज हम केन्स को अधिक श्रेय देते है, जब कि यह श्रेय वास्तव मे माल्थस को मिलना चाहिए था उन्होने लिखा

> 'Master manufacturers and merchants produce very largely and consume sparingly...... It is, therefore obvious that without an expenditure which will encourage commerce manufactures, and personal services, the possessors of land would have no sufficient stimulus to cultivate well. ...and a country rich and populous, would, with too parsimonius habits, infallibly become poor and comparatively unpeopled" [1]
>
> (अर्थात् श्रेष्ठ उत्पादनकर्ता और व्यापारी आय तो बहुत करते है पर उपभोग कम करते है (सापेक्षिक रूप से) जाहिर है कि बगैर अधिक व्यय के अधिक उद्योग, व्यापार व कृषि विस्तृत नही हो सकता एक देश, चाहे वह धनी व जनपूर्ण ही क्यो न हो, निश्चय ही अपनी कृपणता या अल्पव्ययी होने के कारण, गरीब व जनरहित हो जाएगा)

बचत की अधिकतम सीमा जबकि एडम स्मिथ व रिकार्डो बचत को हमेशा व हर स्थिति मे एक गुण मानते थे, माल्थस ने बताया कि अधिक बचतो से बचत

1. Okun & Richardson : p cit p. 49-58.

व विनियोजन म असतुलन हो जाएगा, और बेरोजगारी फैलेगी क्योंकि अविक्रय वस्तुओं के कारण उत्पादन रुक जाएगा इनके पूर्व के अर्थशास्त्री बचत और विनियोजन को बराबर मानते थे उनका कथन था कि अगर अधिकाधिक बचतो को खर्चों को कम करके, प्राप्त करने के स्थान पर हम अधिकाधिक उत्पादिकता व आय से प्राप्त करे तो इसमे कोई हानि नही होगी उन्होने लिखा

> "The future of a country.. .is made by...... savings, certainly, but by savings which are furnished from increased gains, and by no means involve a diminished expenditure on objects of luxury and enjoyment "[1]

उन्होने लिखा कि इस प्रकार की बचतो स लाभ व पूँजी निर्माण दोनो कम हो जाएँगे इसलिए देश म बचतो को एक सीमा के बाद नही बढने देना चाहिए .

> "Where the state of demand for commodities was such as to afford much less than ordinary profits to the producer, and the capitalists were at a loss, where and how to employ their capitals to advantage, the saving from revenue to add still more to these capitals would only tend prematurely to diminish the motive to accumulation, and still further to distress the capitalists, with little increase of a wholesome and effective capital.

बेरोजगारी व मन्दी दूर करने के लिए, माल्थस ने अनुत्पादक उपभोग कर्ताओं" को भी महत्वपूर्ण माना

8. कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में उन्होने लिखा :

> "An inferior mode of living is a cause and consequence of poverty " (निम्नजीवन यापन गरीबी का कारण का परिणाम होता है)

यह "आर्थिक दुष्चक्र" बाद में Ragner Nurkse ने जोरदार शब्दो में

1. Okun Richardson · op. cit Malthus's "Principeples of Economics."

समझाया वे उन्होने कम-विकसित देशो के विकास की समस्याओ को two section model मे अध्ययन किया, और वे सतुलित विकास चाहते थे उन्होने लिखा था कि इन देशो मे औद्योगिक क्षेत्र इसलिए विकसित नही हो पाता कि कृषि क्षेत्र गरीब होता है

भूमि सुधार इन देशो के लिए उन्होने भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया पर साथ ही यह भी कहा कि एक सीमा के बाद अगर भूमि वितरण मे समानता लाने की कोशिश की गई तो इससे धन वृद्धि के स्थान पर कमी आएगी अधिक समानता से भूमि में पूँजी लगाने वाले नही रहेगे

> "With an excessive proportion of small proprietors both of land and capital all great improvements in land, all great enterprizes in commerce and manufactures, as resulting from division of labour, would be at an end and the progress of wealth would be checked by a failure in the powers of supply" (पृ० 373)

माल्थस ने इन देशो के बारे मे वह बातें भी कही जो हमारे काल मे कोलिन क्लार्क (Colin Clark) ने कही अर्थात (1) विकास जैसे जैसे बढता है कृषि का राष्ट्रीय आय मे योगदान कम हो जाता है (माल्थस प्र० 334) तकनीकी उन्नति से रोजगार बढता है (प्र० 352) विकास की दर गिरने से बरोजगारी बढती है (प्र० 312)

III माल्थस के मॉडल की समीक्षा उनका आशावाद व उदारता

माल्थस के मॉडल की व्यापकता व महत्व को हम ऊपर के वर्णन को अध्ययन करके समझ ही गए है Warren S Thomson के अनुसार

> "माल्थस मानव जाति के कल्याण मे उतनी ही दिलचस्पी रखते थे जितनी कि कोई और रख सकता है परन्तु उनका उत्साह, वास्तविकता पर आधारित था वे अविवेकी निराशावादी नही थे उनको आशा व विश्वास था कि मानव जाति का आर्थिक स्तर ऊँचा होगा"

माल्थस ने अपनी पुस्तक के सातवें सस्करण मे लिखा

> "जनसख्या की समस्या जनसख्या के बढ़ने से ही नही देखना चाहिए

Warren S. Thomson . Population problems : ch. II.

> यह तो हमेशा खाद्यान्न से सम्बन्धित है आने वाले समय में आशा की जा सकती है कि जनसंख्या की वृद्धि की बुराइयाँ घटेंगी और हम आशा कर सकते हैं कि जनजीवन म उन्नति होगी "
>
> "On the whole, therefore, though our future prospects respecting the mitigation of the evils arising from the principles of population may not be so bright as we could wish, yet they are far from being entirely disheartening, and by no means preclude that gradual and progressive improvement in human society which before the late wild speculations on this subject, was the object of national expectation..."

उपरोक्त वाक्यो से स्पष्ट है कि हम एडम स्मिथ क आशावादी मानते हैं जब कि वे स्थिर अर्थ व्यवस्था" की कल्पना करते थे, और माल्थस को निराशावादी अर्थशास्त्री के रूप में याद करें, जबकि वे ऐसे नही थे

मजदूरी के सम्बन्ध म भी उनके विचार रिकार्डो की भाति न तो कठोर थे और श्रम विरोधी उन्होने मालिको के स्वार्थ व लालच की भर्त्सना की 'Who treated their employees as chattels for their own good" अर्थात् जो अपने मजदूरो को अपने लाभ के लिए माल-असबाब जैसा मानते थे वे श्रम को उचित हिस्सा दिलाने के पक्ष मे थे

James Bonar के शब्दों में

> "Of all the applications of the doctrine of Malthus, their approach to pauperism was probably, at the time, of the greatest public interest.. . .Malthus is the father not only of the new poor law, but of all our latter day societies for the organisation of charity "

●

Other references . (than those mentioned previously)

(1) James Bonar . Malthus & His works p. 305

(2) Coontz : Population theories & Economic Interpretation

(3) Bowen Population.

(4) Spengler & Duncan : Population theory & policy

(5) Duncan & Hauser . The Study of Population.

अध्याय 8

जॉन स्टुअर्ट मिल का विकास मॉडल

John Stuart Mill on Growth

I प्रस्तावना

II विकास मॉडल

(A) जीवन के प्रारंभिक वर्षों के आधार पर

1. विकास के मुख्य स्रोत भूमि, श्रम व पूंजी हैं.
2. मिल ने भौतिक वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन को ही विकासकारक माना.
3. मिल विकास के लिए पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था व निर्बाधवादी नीति चाहते थे
4. विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विनियोजन आवश्यक.
5. जनसख्या नियन्त्रण व 'मजदूरी कोष' बढाना आवश्यक है.
6 राज्य को निजी विनियोजन प्रोत्साहित करने के लिए समस्त सहायता देना चाहिए.

(B) जीवन के उत्तरार्ध काल के विचार

1. वितरण के नियमो में परिवर्तन आवश्यक हो
2. उत्पादन पद्धति में मजदूरी पद्धति की समाप्ति तथा सहकारिता संघो की स्थापना.
3 लगान का समाप्त होना व कृषि विकास के लिए भू-सुधार आवश्यक.
4 कम-विकसित देशों के सम्बन्ध में विचार.

III समालोचना

अध्याय 8

जान स्टुअर्ट मिल का विकास मॉडल

John Stuart Mill on Growth

I प्रस्तावना

मिल ने अपने जीवन काल में एडम स्मिथ से भी अधिक ख्याति पाई उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र को परिपक्वता की सीमा तक पहुँचा दिया था उन्होंने एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो व जेम्स मिल के विचारों को सुधारा और अच्छी तरह से प्रस्तुत किया (Mill brought the writings of Adam Smith uptodate, confirmed the doctrines of Malthus and wrote a "readable Ricardo, as also presented the ideas of his own father, James Mill.

II विकास मॉडल

(A) जीवन के प्रारंभिक वर्षों के विचारों के आधार पर :

1 विकास के मुख्य स्रोत भूमि, श्रम व पूँजी हैं

अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति मिल भी विकास को भूमि, श्रम व पूंजी के सहयोग का प्रतिफल मानते थे जहाँ श्रम व भूमि उत्पादन के अनिवार्य अंग हैं, वहाँ पूँजी "आधुनिक उत्पादन पद्धति" के लिए अनिवार्य अंग है मिल का कथन था "उद्योग की उन्नति की सीमा पूँजी की मात्रा पर निर्भर है पूँजी ही समस्त आर्थिक क्रियाओं के उत्पन्न करने वाला उत्पादन घटक है जहाँ मनुष्य के श्रम से भूमि की बंजरता नष्ट नहीं होती वहाँ पूँजी खाद का कार्य करती है" पूँजी की मात्रा अधिक होने के लिए, मिल बचत को प्रोत्साहित करने की सलाह देते हैं

मिल का विश्वास था कि अगर उत्पत्ति के ह्रास नियम लागू होने से बचना है तो श्रम की कार्य कुशलता में वृद्धि आवश्यक होगी शिक्षा के विकास से ज्ञान, बुद्धि और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है मिल ने श्रम की कार्य कुशलता, नैतिक आचार-विचार, व उत्पादकता को उन्नत करने पर विशेष बल दिया

2 मिल ने भौतिक वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन को ही विकास कारक माना :

मिल सेवाओ के उत्पादन मे वृद्धि को विकास कारक नही मानते थे. उनका विचार था कि केवल भौतिक वस्तुओ के निर्माण से ही विकास होता है उनका विचार था कि जब तक बुद्धि, योग्यता, और बौद्धिक व सास्कृतिक उपलब्धियाँ भौतिक कल्याण मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहायक नही होती तब तक हम इन गुणो को विकास-कारक नही मान सकते

> "A country would hardly be said to be rich, except by a metaphor, however precious a possession it might have in the genius, the virtues or the accomplishments of its inhabitants, unless indeed they were looked upon as marketable articles by which it could attract the material wealth of other countries"

3, मिल विकास के लिए पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था व निर्बाधवादो नोति चाहते थे

मिल का विचार था कि केवल पूर्ण-प्रतियोगिता की व्यवस्था मे अधिकतम विकास की सम्भावनाएँ है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मे ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन होता है इस व्यवस्था मे ही न्याय और समानता के लक्ष्यो को प्राप्त किया जा सकता है. मिलका विचार था

> "पूर्ण प्रतियोगिता व्यवस्था में कोई भी निरोध निश्चित ही पाप है, और उसको बढावा देना निश्चित ही कल्याणकारी है"

मिल, अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की भाँति पूर्ण स्वतन्त्रता मे विश्वास रखते थे उनका Hedonistic principle (वह सिद्धान्त जिसके अनुसार आनन्द ही मनुष्य के सब कार्यो का अन्तिम लक्ष्य माना जाता है) में पूर्ण विश्वास था वे इस सिद्धान्त को "Golden rule of Jesus" अर्थात "प्रभु ईसा मसीह का स्वर्ण सिद्धान्त" की भाँति पवित्र मानने थे उनका कथन था :

> "व्यक्तिवाद ही जो कि मानव विकास मे विभिन्नता का द्योतक है, समस्त विकास का स्रोत है और इसकी हमे "पूर्ण ईर्ष्या" से रक्षा करना चाहिए"

मिल "व्यक्तिगत हित की भावना" को Achilles lance मानते थे (Achilles lance या माला वह माला था जिससे उत्पन्न घाव स्वय ठीक हो जाते थे)

उनका विश्वास था कि व्यक्ति अपने हित करने के लिए समाज का अहित नही करेगा शिक्षा और सामाजिक भावना के विकास से हर व्यक्ति निजी स्वार्थ से ऊपर काम करेगा

4 विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विनियोजन आवश्यक है :

वेस्टियट व रिकार्डो की भाँति मिल का भी विश्वास था कि पूर्ण स्वतन्त्रता व तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कम-विकसित देशों को निश्चित लाभ होता है परन्तु वे नए व प्रारम्भिक अवस्था के उद्योगो को आवश्यकतानुसार सरक्षण देने के पक्ष मे थे मिल का कथन था कि अगर कोई देश-विदेशो से सस्ती दर पर खाद्यान व कच्चे माल को मँगा सकता है तो इससे देश म मजदूरी व लागत दोनो कम रहेगे परन्तु वे यह नही चाहते थे कि साम्राज्यवादी देश अपने उपनिवेशो का शोषण करें उन्होने लिखा

> "अधीनस्थ देशो मे आयोजन केवल अपने (साम्राज्यवादी देश) स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, वरन् इस प्रकार से करना चाहिए कि इस देश के लोगो का भी स्थायी कल्याण हो"

मिल ने किसी भी देश मे गिरती हुई लाभ की दर को रोकने के लिए सलाह दी कि ऐसे देश को अपनी पूँजी विदेशो में लगाना चाहिए अगर स्वदेश मे पूँजी की उत्पादकता कम हो (लाभ गिर रहे हो) तो विदेशो मे पूँजी से भेजने से पूँजी की सीमान्त उत्पादकता बढ जाएगी जब देश म अधिक लाभ की सम्भावनाएँ घट जाएँ तो 'स्थिर अर्थ-व्यवस्था" की स्थिति विदेशी व्यापार से लाभ कमाकर ही टाली जा सकती है

5. जनसंख्या नियन्त्रण व "मजदूरी कोष" बढाना आवश्यक :

मिल भी एडम स्मिथ की भाँति "स्थिर अर्थव्यवस्था' की सभावित स्थिति से भयभीत थे, और इस अवस्था को ले जाने वाली चीज वे अनियन्त्रित जनसख्या वृद्धि को ही मानते थे

मिल पुरुषो से नाराज थे क्योंकि वे ही स्त्रियों पर, बगैर स्त्रियो की सहमति लिए, मातृत्व लाद देते है

मिल का विश्वास था कि विकास के लिए सीमित परिवार का होना अत्यन्त आवश्यक होता है मिल वैसे तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बडे समर्थक थे, पर इस सबन्ध मे वे इतना तक कह गए कि बहुत गरीबो व दीन-दरिद्रो (Poor and Indigents) को तो विवाह करने तक की अनुमति नही होना चाहिए मिल

अधिक बच्चे पैदा करने को "अधिक शराब पीने के व्यसन" मे भी बुरा मानते थे इस कारण वे अधिक समय तक कुँवारे रहने व गरीबो का बन्ध्याकरण Sterilization and onanism of the proletariat) तक चाहते थे इसीलिए मिल का कथन था कि मज्दूरो को चाहिए कि वे उत्पादनकर्ताओ के लाभ बढाएँ और जनसख्या कम रखे ताकि वे देश म उत्पादन पद्धति को बनाए रख सकें, देश का विकास कर सकें और स्वय मजदूरो को मजदूरी अधिक दे सकें

6 राज्य को निजी विनियोक्ताओं को समस्त सहायताएँ देना चाहिए :

मिल का विश्वास था कि किसी देश का विकास बहुत हद तक देश की सरकार पर निर्भर करता है पर मिल राज्य को प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन व्यवस्था को हाथ म लेने मे विवश थे वे चाहते थे कि राज्य (i) करो को कम रखे, (ii) सम्पत्ति की सुरक्षा प्रदान करे, (iii) उचित भू-राजस्व प्रणाली स्थापित करे वे चाहते थे कि देश में जितनी भी दकियानूसी मान्यताएँ व परम्पराएँ, जो विकास म अवरोधक हो, उन्हे राज्य दूर करने म मदद दे राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह देश मे शिक्षा, कौशल व कला के विकास म सहायता करे राज्य को पूँजी निर्माण मे भी किसी किस्म की बाधा उत्पन्न नही करना चाहिए यह बाधा अत्यधिक व अनावश्यक करो की वृद्धि से उत्पन्न होनी है

मिल श्रम सघो को भी विकास की राह मे एक बाधा मानते थे वे चाहते थे कि इन सघो के स्थान पर मालिको व श्रमिको के सहकारी सघो की स्थापना होनी चाहिए

II मिल के जीवन के उत्तरार्ध काल मे उनके विकास सम्बन्धी विचार

1. वितरण के नियमो में परिवर्तन :

जैसा कि सर्वविदित है कि मिल के जीवन के उत्तरार्ध म उनके विचार समाजवाद की तरफ झुक गए इस काल म उनका पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था के नियमों मे विश्वास कायम रहा परन्तु मानव निर्मित वितरण के नियमो से उनका विश्वास उठ गया और व कहने लगे यह वितरण के नियम विकास मे बाधक है उन्होंने लिखा

> "उत्पत्ति के नियम व शर्तो का स्वभाव भौतिक सत्यो की भाँति अटल है उनमें किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता या वैकल्प नही है परन्तु यह बात वितरण के नियमो पर लागू नहीं होती यह तो केवल मानव सस्थाओ के हाथ की बात है"

मिल चाहते थे कि राज्य ऐसे नियम बनाए जिससे आर्थिक विकास के साथ सामाजिक न्याय भी उत्पन्न हो उन्होंने अपनी सामाजिक नीति की रूपरेखा इन शब्दों में व्यक्त की

> 'सामाजिक विकास नीति का लक्ष्य है कि किस प्रकार से अधिकतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्राकृतिक साधनों की सार्वलौकिक मालकियत को समन्वित रूप में कार्यान्वित किया जा सके और किस प्रकार से सगठित मेहनत के लाभ सब लोगों को प्राप्त हों"

2 मजदूरी पद्धति की समाप्ति तथा सहकारिता सघो की स्थापना :

मिल अब सोचने लगे कि 'मजदूरी प्रणाली" ही विकास में बाधक होती है मजदूर अपने श्रम द्वारा निर्मित वस्तुओं की उत्तमता पर प्रसन्न तक नहीं हो सकते इस प्रणाली में श्रमिक का व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है मिल इसीलिए चाहते थे कि श्रमिको को, समानता के आधार पर, सहकारी सघ या सस्थान बनायें वे ही पूँजी के सामूहिक रूप से मालिक रह तथा व ही मैनेजरो को नियुक्त करें व निकाल बाहर कर सकें

3 लगान समाप्त हो :

एडम स्मिथ व **निर्बाधवादी** अर्थशास्त्री लगान को प्रकृति के साधन के सहयोग प्राप्त करने का पारितोषक मानते थ **माल्थस** व **रिकार्डो** लगान को जनसख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न भूमि की कमी का व उत्पत्ति के ह्रास नियम के लागू होने का प्रतिफल मानते थे **सीनीयर** इसे आकस्मिक लाभ के रूप मे देखते थे परन्तु **मिल,** अपने जीवन के उत्तरार्ध काल म, लगान को गैर कमाई हुई आय" कहने लगे और उनका कथन था इस आय पर कर लगाकर इस आय का "समाजीकरण" कर लेना चाहिए

मिल कहते थे कि विकास के लिए (जिसम सामाजिक न्याय भी स्थापित हो) निम्नलिखित सुधार कार्य आवश्यक है

(i) किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति को उत्तराधिकार मे देने का अधिकार सीमित होना चाहिए

(ii) देश में शिक्षा का अधिकाधिक *विकास किया जाना* चाहिए और गरीबो व स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना सुलभ बनाना चाहिए

(iii) देश मे जितनी भी भूमि पर कृषि न हो रही हो, राज्य को उसे तत्काल हाथ मे लेकर छोटे किसानो मे बाँट देना चाहिए और उन्हें सहकारिता के आधार पर कृषि करने को प्रोत्साहित करना चाहिए

(IV) ऐसे नियम बनाए जाएँ जिससे वे व्यक्ति जिनके पास कम साधन हो वे अगर बच्चे पैदा करें तो उसे अपराध माना जाय

4 कम-विकसित देशो के सम्बन्ध में विचार :

कम-विकसित देशो के विकास के सम्बन्ध मे मिल ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए जो इस प्रकार है

> "ऐसे देशो मे जहाँ पूँजी सचय कम हो, (जैसे एशिया के देशो मे), जहाँ के लोग न तो बचत करते हो और न ही बचत के लिए मेहनत करते हो, जहाँ उत्पादन बहुत थोडी माना मे होता हो, जहाँ पूँजी की कमी के कारण शारीरिक परिश्रम अधिक करना पडता हो, और जहाँ के व्यक्तियो मे इतनी दूर दर्शिता न हो कि वे प्राकृतिक साधनो का समुचित प्रयोग कर सकें, उन देशो में सर्वप्रथम मेहनत व पूँजी-निर्माण बढाना होगा और तदुपरान्त औद्योगीकरण आवश्यक होगा "

> "इसके लिए—अच्छी सरकार, सम्पत्ति की सुरक्षा, स्थायी व लाभदायक भूमि-सुधार, जन-शिक्षा व ज्ञान मे वृद्धि,पुराने रीति-रिवाजों व अन्ध विश्वासो को समाप्त करना,—विदेशी पूँजी का आयात करना आवश्यक होगा विदेशी पूँजी के आयात करने से देशवासियो द्वारा बहुत अधिक मितव्ययिता के बगैर ही अधिक उत्पादन वृद्धि सम्भव हो सकेगी विदेशी सहायता, देशवासियो के समक्ष उत्साहवर्धक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, नये विचारो को जन्म देती है, पुरानी आदतों को तोडती है, नयी आवश्यकताओ को जन्म देती है, नयी लालसाओ को उत्पन्न करती है और देशवासियो को अपने भविष्य सुधारने के लिए अधिक चिन्तनकर्ता बनाती है "

III. विकास सम्बन्धी विचारो की समालोचना

(1) मिल का विकास मॉडल एडम स्मिथ व रिकार्डो के मॉडल से निश्चित ही अधिक उन्नत था जब कि प्रथम दो अर्थशास्त्रियो का मॉडल केवल "आर्थिक" था, मिल का मॉडल "सामाजिक-आर्थिक" मॉडल था

देखिए ·

Principle of Political Economy, London 1842, 3rd Edition p. 230-31.

(ii) मिल के विचार, अपनी पुस्तक के हर नवीन संस्करण के साथ, समाजवादी होते गए. जहाँ वे पहले राज्य के हस्तक्षेप को विकास मे अवरोध मानते थे वहाँ बाद मे वे राज्य को विकास सबधी कई जिम्मेदारियाँ सौंपने लगे थे वे चाहते थे कि राज्य अधिकतम लोगों का अधिक कल्याण करे उन्होने बाद मे राज्य को (1) मजदूरी दरो का नियमन करने, (2) सार्वजनिक कार्यो को करने, (3) शिक्षा व तक्नीकी आविष्कारो को बढावा देने, (4) उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा करने व (5) गरीबो की सहायता करने के कार्य सौंपे, परन्तु उन्होने Derived Development के सिद्धान्त को प्रतिपादित नही किया, अर्थात् राज्य को विकास की जिम्मेदारी नही सौंपी

(iii) इतना होते हुए भी वे पूर्ण निराशावाद-रहित नहीं थे वे भी जनसख्या वृद्धि के भय व उत्पत्ति ह्रास नियम के भय के कारण "स्थैतिक अर्थ-व्यवस्था" के आने की पूर्ण सम्भावनाएँ देखते थे. उन्होने तो इगलैण्ड के लिए 19 वी सदी के अन्त तक ही इस अवस्था के आ जाने की भविष्यवाणी कर दी थी उन्होने तक्नीकी व साहसिक कार्यों को महत्व नही दिया था

अध्याय : 9

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास मॉडल

The Classical Model of Growth

I प्रस्तावना

II मॉडल

1. भौतिक वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि (जो भूमि, पूँजी व संगठन के सहयोग से होती हैं) से विकास होता है
2. पूँजी विकास का एंजिन होती है : बचतों का महत्व.
3. अधिक पूँजी निर्माण : अधिक लाभ पर निर्भर
4. अधिक लाभ के लिए मजदूरी कम होना चाहिए· जनसंख्या नियन्त्रित होना चाहिए.
5. विकास 'निर्बाधवादी नीतियों' के अपनाने से ही सभव है
6. विकास "उत्तरोत्तर बढने वाली प्रक्रिया है" इस प्रक्रिया में बेरोजगारी केवल अल्पकालिक विपदा मात्र है. Growth process is linear and homogeneous activity and there can be no under-employment equilibrium
7. लचीली मजदूरी दरो से बेरोजगारी दूर हो सकती है : स्थैगिक अवस्था का आना निश्चित है.

III समालोचना.

अध्याय : 9

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विकास मॉडल (संक्षेप में)

The Classical Model of Growth (In nutshell).

I प्रस्तावना

यूरोप मे १८ वी सदी के उत्तरार्ध में तथा 19 वी सदी के पूर्वार्ध मे औद्योगिक क्रान्ति हो रही थी यूरोप जिस काल मे Take off (आत्म स्फूर्ति) की स्थिति से Sustained growth (निरन्तर विकास) की अवस्था मे गया, उस काल के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्क्स प्रत्यक्ष द्रष्टा थे इनके आर्थिक विकास सम्बन्धी विचार इन्ही विकास की समस्यायों व तथ्यों से प्रभावित हुए थे साथ ही साथ तत्कालिक प्रशासक व राजनीतिज्ञ भी इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विचारो से बहुत प्रभावित हुए तथा उनके बताये हुए रास्ते पर चले, और इससे इन देशों मे आर्थिक विकास हुआ

हम इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारो को संक्षेप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते है

II मॉडल के मुख्य तत्व

1. भौतिक वस्तुओ की उत्पादन वृद्धि, जो भूमि, पूंजी व सगठन के सहयोग से होती है, से विकास होता है :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भौतिक वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि को ही विकास का सूचक मानते थे जब यह उत्पादन बढता है तो राष्ट्रीय आय बढती है. इन अर्थशास्त्रियो के अनुसार उत्पादन भूमि, श्रम, पूजी व सगठन के सहयोग के परिणामस्वरूप होता है. यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री 'सगठनकर्ता' और 'साहसी' में भेद नही निकालते थे और सगठनकर्ता को ही साहसी मानते थे उन्होंने साहसी को उतना

महत्व नही दिया जितना कि आगे चलकर शम्पीटर ने दिया. "उन्नत तक्नीक" को भी उन्होने एक अलग से महत्वपूर्ण घटक नही माना

2. पूंजी "विकास का एंजिन" : बचत का महत्व

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूँजी को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अग मानते थे उनके अनुसार अगर देश मे पूँजी निर्माण अधिक है तो विकास भी अधिक होगा

अधिक पूँजी निर्माण के लिए अधिक बचत होना आवश्यक होता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बचतों को व्यक्तिगत व सामाजिक दोनो प्रकार का गुण मानते थे इन अर्थशास्त्रियो का विश्वास था कि अगर मितव्ययिता से खर्च करके अधिक बचत होगी (पर माल्थस ऐसा नही सोचते थे) तो अधिक पूँजी निर्माण व अधिक विकास होगा पूँजी निर्माण से ही उन्नत तक्नीक अपनाई जा सकती है

3. अधिक पूँजी निर्माण : अधिक लाभ पर निर्भर :

प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियो का कथन था कि अधिक पूँजी निर्माण तब ही सभव है जब कि पूँजीपति वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त हो लाभ तथा लाभ की आशा से ही विनियोजन की मात्रा मे वृद्धि होती है इसलिए इन अर्थशास्त्रियो का कथन था कि राज्य को कोई भी ऐसा कार्य नही करना चाहिए जिससे देश के पूँजीपतियो के लाभ कम हो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसीलिए कम से कम कर लगाने की सिफारिश करते थे, और इसी कारण वे चाहते थे कि देश में श्रम-सघो को मजदूरी बढाने की स्वतन्त्रता नही होना चाहिए

4. अधिक लाभ के लिए मजदूरी कम : मजदूरो में जनसख्या वृद्धि भी कम होना चाहिये :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री चाहते थे कि मजदूरी की दरो मे वृद्धि नही होना चाहिए उनका मजदूरी के "जीवन निर्वाह सिद्धान्त" मे पूर्ण विश्वास था उनका कथन था कि वास्तविक मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह के बराबर रह सकती है, उससे अधिक नही हो सकती अगर वास्तविक मजदूरी को बढा दिया गया (अर्थात् मजदूरी केवल उस समय बढाना चाहिए जब खाद्यान्न का भाव बढे और जिस अनुपात मे यह भाव बढे उसी अनुपात मे "मौद्रिक मजदूरी" बढाना चाहिए) तो इससे वस्तुओ की लागत बढेगी, फिर वस्तुओ का मूल्य बढेगा, फिर उनका आन्तरिक उपभोग कम होगा व निर्यात कम होगे तथा इसके कारण उत्पादन कम करना पडेगा और फिर बेरोजगारी फैलेगी इसके पश्चात् वास्तविक मजदूरी स्वय कम करना पडेगा, क्योकि बेरोजगारी के दिनो मे मजदूरी के स्तर अधिक नही

रह सकने दूसरी ओर, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विश्वास था, कि मजदूरी बढने से मजदूर वर्ग अधिक बच्चे पैदा करेंगे जिससे मजदूरों की सख्या बढेगी और उनकी इस पूर्ति वृद्धि से वास्तविक मजदूरी पुन गिर जाएगी

इन्ही सब कारणों से यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्रम-सघो को विकास मे बाधा डालने वाली सस्थाएँ मानते थे

5. विकास "निर्बाधवादी नीतियों" के अपनाने से ही संभव होगा.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि राज्य को आर्थिक मामलो मे कम से कम दखल देना चाहिए उनके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह निजी क्षेत्र को विकास में हर सभव मदद दे उनके अनुसार राज्य को यह कार्य करना चाहिए

(1) देश में सम्पत्ति को बनाने की स्वतन्त्रता हो तथा उसकी पूर्ण सुरक्षा का प्रबन्ध हो.

(111) कर कम से कम हो तथा राज्य को सार्वजनिक ऋण न्यूनतम मात्रा मे लेना चाहिए क्योकि इनसे कर भार भविष्य मे बढता है राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र म केवल शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओ के विस्तार व कुछ आवश्यक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करना चाहिए

(111) देश मे श्रम-सघो को मजदूरी बढाने की स्वतन्त्रता प्रदान नही करना चाहिए

(1v) देश मे स्थायी सरकार की स्थापना होना चाहिए जिसकी प्रशासन पद्धति कुशल व भ्रष्टाचार रहित हो देश की वित्तीय सस्थाएँ विकसित हो व पूर्ण सगठित हो देश मे उचित न्याय की प्रणाली होनी चाहिए व न्यायपूर्ण भूमि-मालकियत पद्धति हो.

(v) देश में जो भी धार्मिक या सामाजिक रीतिरिवाज विकास मे बाधक हो, राज्य को चाहिए कि उनमें धीरे-धीरे समुचित सुधार हो

(v1) देश मे पूँजीपतियों को उत्पादन की मात्रा, व किस्म निर्धारित करने, उसके लिए अपनी इच्छानुसार उत्पादन के अगो की मात्रा व मूल्य निर्धारित करने तथा मूल्य लेने की स्वतन्त्रता होना चाहिए.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल को अगले अध्याय में देखिए

6. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अनुसार विकास "उत्तरोत्तर बढने" वाली प्रक्रिया है : इस प्रक्रिया में 'बेरोजगारी केवल अल्पकालिक विपदा मात्र है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मत मे विकास प्रक्रिया Linear and homogeneous (सीधी और एक सी) होती है, अर्थात् अगर हम उत्पादन के अगो को मात्रा दुगुनी कर दे तो उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के इस मत को तो कई नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी मानते थे. मार्शल ने भी आर्थिक विकास को उसी रूप मे होने की कल्पना की जिस रूप मे एक वृक्ष धीरे-धीरे, परन्तु निरन्तर, बढता रहता है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के इस विचार को मार्क्स व शम्पीटर ने नही माना था. उनके अनुसार विकास Fits and starts अर्थात् कभी अधिक दर से व कभी कम दर से तथा कभी कभी तो पीछे हो जाने की प्रक्रिया के साथ साथ होता रहता है

There can be no under-employment equilibrium
स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी सम्भव नहीं है

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का स्पष्ट मत था कि अर्थ-व्यवस्था, अगर उसमे कोई 'वाह्य' हस्तक्षेप न हो तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति मे रहेगी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने बेरोजगारी की समस्या को अध्ययन योग्य ही नही समझा प्रतिष्ठित व नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के दोषो को छिपाने के लिए इस समस्या के अध्ययन की अवहेलना करते रहे इन अर्थशास्त्रियो का मत था कि देश मे बेरोजगारी केवल इसलिए उत्पन्न होती है कि श्रम-सघ मजदूरी बढवा लेते है या इसलिए उत्पन्न होती है कि राज्य अधिक कर लगा कर उत्पादनकर्ताओ को पर्याप्त लाभ नही लेने देता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने रोजगार की समस्या को Micro या सूक्ष्म अर्थशास्त्र (From the point of view of individual firm) पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थितियो मे अध्ययन किया

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री 'पूर्ण रोजगार" को प्राप्त करने से अधिक "पूर्ण उत्पादन" की स्थिति को प्राप्त करने को अधिक महत्व देते थे.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का यह विचार "Downward in flexibility

---

See : O S. Shrivastava, "Economics of Wages, Productivity and Employment." chapter 6

of demand" अर्थात मांग की कमी की स्थिति के न उत्पन्न होने के विश्वास पर आधारित था उनका विश्वास था कि मांग व उत्पादन एक ही राह पर आगे बढ़ते हैं जे० बी० से (J B Say) के इस कथन में कि "पूर्ति अपनी माँग स्वय उत्पन्न कर लेती है" उनका पूर्ण विश्वास था

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का विश्वास था कि अगर मजदूरी की दरो को लचीला रखा गया तो कभी भी बेरोजगारी न होगी, न उत्पादन में व विकास में रुकावट आएगी

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विकास पथ में सबसे बडी रुकावट अधिक मजदूरी मानते थे "अधिक" का अर्थ उनके अनुसार जीवन निर्वाह से अधिक मजदूरी से था उनका कथन था कि मजदूरी घटा दी जाए तो उत्पादन, रोजगार व विकास के ऊँचे स्तर बने रहगें सब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रिया म पीगू सर्वप्रथम प्रभावशील अर्थशास्त्री थे जिन्होने मजदूरी गिराने की सिफारिश की थी उन्होंने मजदूरी दर कम रखने या घटाने के निम्नलिखित लाभ देखे

(1) इससे लागत घटेगी, व माँग बढेगी, जिससे उत्पादन व रोजगार में वृद्धि होगी

(2) इससे लाभ व लाभ की आशा बढेगी जिससे विनियोजन बढेगा

(3) जब मजदूरी की दरें कम होगी तो उत्पादनकर्ताओ को कम चल पूंजी की आवश्यकता होगी, इससे व्याज की दर कम रहेगी और लागत भी कम रहेगी

(4) कम मजदूरी की दरो से निर्यात बढेगा और देश में विदेशो से जो धन आएगा उससे विकास बढेगा

(5) कम मजदूरी से उत्पादनकर्ता श्रमगहन तकनीक अपनाकर रोजगार बढा सकेगें

सक्षेप में, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का मत था कि कम मजदूरी रखने व उत्पादन कर्ताओ को अधिक लाभ लेने देने से ही विकास सम्भव होगा

7. विकास प्रक्रिया का अन्त . स्थैतिक आर्थिक स्थिति का उत्पन्न होना

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का विश्वास था कि जब तक किसी देश में जनसख्या तुलनात्मक रूप मे कम है, तब तक भूमि से अनुपात से अधिक दर मे उत्पादन प्राप्त हो सकेगा, परन्तु जैसे जैसे जनसख्या बढेगी वैसे वैसे उत्पत्ति ह्रास नियम

प्रभावशील होता जाएगा जब अर्थ-व्यवस्था "परिपक्वता" की अवस्था मे पहुँच जाएगी तब उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण श्रम लागत बढ जाएगी. इन अर्थ-शास्त्रियो को भय था कि श्रम लागते इतनी बढ जाएगी कि तकनीकी उन्नति के लाभ भी उनसे कम हो जाएँगे इसके कारण लाभ कम हो जाएँगे तब विनियोजन कम हो जाएगा, तकनीकी विकास रुक जाएगा, मजदूरी कोष कम हो जाएँगे और स्वय जनसख्या वृद्धि रुक जाएगी.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विकास मॉडल मे "पूँजीवादी विकास व्यवस्था" का अन्त स्थैगित स्थिति मे पहुँचना होगा इस अवस्था में राष्ट्रीय आय, रोजगार, लाभ, पूँजी, व जनसख्या सब स्थिर हो जाएगे परन्तु यह "स्थैगित अवस्था" समृद्धि की अवस्था रहेगी, जिसमे पूर्ण रोजगार सम्भव होगा

III समालोचना

(A) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण थे वे विकास की दीर्घकालीन समस्याओ मे अधिक रुचि रखते थे उनकी अध्ययन शैली प्रवैगिक थी. उन्होने विकास के घटको म चक्रीय सम्बन्ध अच्छी तरह समझा उन्होने वतलाया कि उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन पर आधारित होती है, अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर होता है, व अधिक लाभ उन्नत तकनीक पर आधारित हाते है. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने पूँजी-निर्माण, बचतो विनियोजन, लाभ, व राष्ट्रीय आय मे परस्पर सह सम्बन्ध देखा.

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विकास सम्बन्धी विचारो में सबसे महत्वपूर्ण विचार पूजी निर्माण पर जोर देना रहा उन्होने पूजी को विकास का एंजिन बनाया कुछ हद तक हम उनकी अहस्तक्षेप की नीति को भी उचित ठहरा सकते है. आजकल कई कम-विकसित देशो मे राज्य की मौद्रिक व राजकोपीय नीतियो से निजी चेत्र के उत्पादनकर्ताओ को ईमानदारी से आय कमाना सम्भव नही हो पाता

(B) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विकास सम्बन्धी विचारो मे बहुत सी त्रुटियाँ थी, जिनमें मुख्य यह है

(1) उन्हे उत्पादन मे उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने का बेबुनियाद भय था. उन्होने उन्नत तकनीक को अधिक ध्यान में नही रखा.

(2) उनका जनसख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि का डर भी निर्मूल था

(3) उन्होने व्यापार चक्रो और बेरोजगारी की समस्या पर उचित ध्यान नही दिया. आज के युग मे कोई भी विकास नीतियाँ, जिनमें व्यापार

चक्रों से बचने की योजना न हो तथा जिनमें बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी की समस्या के समाधान की सम्भावना न हो, सफल नहीं हो सकती।

(4) मजदूरी कम रखकर पूंजी निर्माण करने तथा रोजगार व उत्पादन बढ़ाने की योजना आर्थिक, सामाजिक व नैतिक सभी दृष्टिकोणों से आज व्यवहारिक नहीं है. आज के युग में लचीली मजदूरी नीति से न तो रोजगार बढ़ सकता है और न उत्पादन. मजदूरी कम रखने से उत्पादकता कम रहती है प्रभावशील माँग गिरती है और देश में आर्थिक दुश्चक्र अभेद्य बना रहता है [1]

1. देखिए : मजदूरी नीति सम्बन्धी अध्याय तथा केन्स का मॉडल.

अध्याय · 10

मार्क्स का विकास मॉडल

(Marxian Model of Growth)

1 प्रस्तावना

2 मॉडल

1 विकास उत्पादन वृद्धि से होता है और उत्पादन भूमि, श्रम, पूँजी, सगठनकर्ता व तकनीक के सहयोग का प्रतिफल होता है

2 पूंजीवादी व्यवस्था में तकनीक आर्थिक विकास का एन्जिन हैं

3 उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन से सभव है, और अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर है

4 अधिक लाभ कमाने के लिए पूंजीपति "अतिरेक मूल्य' प्राप्त करता है—कम मजदूरी देता है और बरोजगारी फैलाता है

5 जनसंख्या व विकास

6 कम मजदूरी से उपभोग गिरता है और इससे जब लाभ व विनियोजन गिरता है तो बड़े पूंजीपति छोटे पूंजीपति का शोषण करते हैं, और अन्त में पूंजीवाद समाप्त हो जाता है (The Law of concentration of capital The Accumulation of capital The Law of crises The Theory of Economic Development Theory of Automatic Expropriation)

II Marxian Theory of Socio economic revolution मार्क्स का सामाजिक आर्थिक क्रान्ति का सिद्धान्त

1 देश के आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नैतिक व राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित करते हैं

2 विश्व में हर चीज परिवर्तनशील है

3 समस्त महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रान्ति से ही आते हैं

III Marxian Stages of Economic Growth मार्क्स और उनकी विकास की अवस्थाएँ

1 प्राथमिक और असभ्य साम्यवाद

2 दास प्रथा

3 सामन्तवादी समाज

4 पूंजीवाद

5 साम्राज्यवाद

6 समाजवाद

7 साम्यवाद

IV Critical Appraisal of Marxian Model मार्क्स मॉडल की समालोचनाएं

समालोचनाएं तथा मेयर व बाल्डविन, बेन्जामिन हिगिंस एवं अन्य महत्वपूर्ण अर्थ शास्त्रियों के विचार

अध्याय : 10

मार्क्स का विकास मॉडल

Marxian Model of Growth.

1. प्रस्तावना :

मार्क्स 19वी सदी के सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री थे वे जेना यूनीवर्सिटी से डाक्टर की उपाधि प्राप्त करके समाचार पत्रो का सम्पादन, शिक्षण कार्य करते रहे. पर मुख्यत. बाद मे वे लेखन का कार्य करते रहे उनका जीवन काल बहुत गरीबी मे बीता

मार्क्स "वैज्ञानिक" समाजवाद के जनक थे उन्होने जो कुछ लिखा उसने न केवल विकास अर्थशास्त्र मे नया मॉडल दिया वरन् विश्व मे नई विकास व्यवस्था को ही जन्म दिया. "आज समाजवादी देशो मे मार्क्स की आलोचना करना न केवल गलत है वरन् पाप है"

2. मार्क्स का विकास मॉडल :

1. विकास उत्पादन की वृद्धि से होता है, जो कि भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन व तकनीक के क्रियास्वरूप होता है. Production, function of land, labour, capital, organisation and enterprise.

परम्परागत (प्रतिष्ठित) अर्थशास्त्रियो की भाँति, मार्क्स भी उत्पादन को भूमि, श्रम, पूँजी, सगठन व साहसी के कार्य का परिणाम मानते थे. ग्रे (Alexander Gray) इसीलिए कहते है कि मार्क्स अन्तिम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे. मार्क्स इन उत्पादन के अगो मे श्रम को ही सर्वोपरि मानते थे. भूमि श्रम के बगैर निष्क्रिय होती है. पूंजी तो "सञ्चित श्रम" ही होती है. मार्क्स पूंजी व पूंजीवाद को विकास मे महत्व मानते थे, क्योकि इससे ही उन्नत तकनीक का अपनाया जाना सम्भव होता है. साहसी को भी महत्वपूर्ण योगदान मानते थे. साहसी ही अपने लाभ के लिए तकनीकी उन्नति लाता है तथा उत्पादन संचालन की व्यवस्था करता है.

2 पूंजीवादी व्यवस्था में तकनीक आर्थिक विकास का 'एन्जिन' है. Technical progress 'motor' of capitalistic growth.

मार्क्स ने तकनीकी उन्नति को विकास का 'एन्जिन' माना. उन्होंने तकनीकी उन्नति व विनियोजन में परस्पर पूरक सम्बन्ध देखा उनके अनुसार उन्नत तकनीक से अधिक पूँजी निर्माण होता है तथा फिर विनियोजन भी अधिक होता है. जहाँ विनियोजन अधिक होता है वहाँ ही उन्नत तकनीकें अपनाई जा सकती हैं.

3. उन्नत तकनीक अधिक विनियोजन से सम्भव है : अधिक विनियोजन अधिक लाभ पर निर्भर है : Technical progress depends on investment Investment on the rate of profit

मार्क्स के अनुसार अधिकाधिक विनियोजन तब ही सम्भव होता है जबकि उत्पादनकर्ता अधिकाधिक लाभ कमा सकते हैं. अधिक लाभ से ही तो अधिक पूंजी निर्माण हो सकता है और तब ही अधिक विनियोजन करना व उन्नत तकनीक अपनाना सम्भव होता है मार्क्स के अनुसार अधिक लाभ सर्वप्रथम श्रम के शोषण से प्राप्त होते हैं इसके लिए उत्पादनकर्ता (i) मशीनें लगाकर श्रमिकों में बेरोजगारी फैलाता है, (ii) श्रमिकों की बेरोजगारी का लाभ उठा कर, उन्हें केवल जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी देता है, तथा बाद में वह (i) छोटे पूंजीपतियों का शोषण करता है और तदुपरान्त वह (ii) साम्राज्यवाद फैलाने में मदद देता है.

4. अधिक लाभ कमाने के लिए पूँजीपति "अतिरेक मूल्य" प्राप्त करता है. The rate of profits depends on the exploitation of workers by paying low wages.

मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में द्रव्य का रूप पूंजी में परिणत हो जाता है, और द्रव्य एक शोषण का साधन बन जाता है. पूंजीवाद से पहले के युग में विनिमय पद्धति इस प्रकार से थी – C→M→C. अर्थात् लोग वस्तु (Commodity or 'C') का उत्पादन करते थे. फिर उसे द्रव्य में परिणत करते थे (Money or 'M') तदुपरान्त फिर अपने लिए आवश्यक वस्तु खरीद लिया करते थे अर्थात् इस विनिमय प्रक्रिया में द्रव्य केवल 'माध्यम' के रूप में प्रयोग में लाया जाता था.

परन्तु पूंजीवादी व्यवस्था में यह प्रक्रिया M→C→M हो गई. जिन लोगों के पास द्रव्य होता है (चाहे वे उत्पादनकर्ता न हों) वे वस्तुएँ खरीद लेते हैं और उसे महँगा बेचकर और अधिक धन कमाने का साधन बना लेते हैं.

इस पद्धति मे वस्तु और अधिक धन बढाने के लिए 'माध्यम' बनी. प्रथम प्रकार की व्यवस्था मे मुद्रा का प्रयोग use values या सन्तुष्टि बढाने के लिए किया जाता था, द्वितीय मे इसका प्रयोग धन बढाने के लिए किया जाता है पहली पद्धति मे उत्पादनकर्ता लाभान्वित होता है दूसरी मे व्यापारी लाभान्वित होता है. प्रथम पद्धति मे शोषण नही है, दूसरी पद्धति मे है मार्क्स प्रथम व्यवस्था चाहते थे.

अतिरेक मूल्य (Surplus Value) मजदूरी के सम्बन्ध मे मार्क्स ने रिकार्डो का यह कथन माना कि किसी वस्तु का मूल्य उसमे निहित श्रम मूल्य के बराबर होता है. परन्तु श्रम को यह पूरा मूल्य नही मिलता. उसे तो केवल जीवन-निर्वाह के बराबर मजदूरी दी जाती है

मार्क्स ने मजदूरी के सम्बन्ध मे रिकार्डो की दूसरी बात को, (मजदूरो को केवल उनके जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी ही मिलना चाहिए) उन्होने तिरस्कार करके नही माना

मार्क्स ने बताया कि पूजीवादी अर्थ व्यवस्था मे पूजीपति मजदूरी कम देकर लाभ कमाता है मजदूर जितना कार्य करता है उसको उतने कार्य का पारितोषिक नही मिल पाता. जैसे अगर एक श्रमिक 10 घण्टे कार्य करता है तो वह केवल 6 घण्टे के कार्य के बराबर वेतन पाएगा. 4 घण्टे के उत्पादन के मूल्य को मार्क्स अतिरेक मूल्य (Surplus value) कहते है और पूजीपति इस मूल्य को स्वय रख लेते है.

मार्क्स का कथन है कि प्रत्येक उत्पादनकर्ता अपने इस शोषण धन (अतिरेक मूल्य) को बढाना चाहता है और इसके दो उपाय है (i) एक तो मजदूरो से अधिक घण्टो तक कार्य कराया जाये इसको absolute increase in Surplus value (अतिरेक मूल्य मे निरपेक्ष वृद्धि) कहेंगे. मार्क्स का कथन है कि पूजीपति पहला तरीका नही अपनाता क्योकि इसमे उसके द्वारा शोषण धन कमाने की रीति का भण्डाफोड होता है. (ii) दूसरी रीति यह है कि *पूजीपति मशीनो को लगाकर श्रम की उत्पादकता बढाता है* परन्तु मजदूर का वेतन नही बढाता. मार्क्स के अनुसार पूजीपति की पूजी दो प्रकार की होती है : Constant Capital या स्थिर पूजी (जैसे कच्चा माल) इससे पूजीपति को अतिरेक मूल्य प्राप्त नही होता. दूसरे प्रकार की पूजी Variable capital या परिवर्तन योग्य पूजी (जैसे श्रम) होती है और समस्त अतिरेक मूल्य इसी से प्राप्त होता है. अगर उद्योग में Organic composition अधिक है

(पूंजी अधिक व श्रम कम) तो उस उद्योग में लाभ कम रहेंगे परन्तु अगर उद्योग में Organic composition कम है (पूँजी कम, श्रम अधिक) तो लाभ अधिक होंगे इसका कारण यह है कि समस्त लाभ तो श्रम से ही उत्पन्न होते हैं अब, मार्क्स कहते हैं कि पूँजीपति जब मशीन लगाकर श्रम की उत्पादकता बढाता है तो श्रम जो पहले 6 घंटे में उत्पादन करता था वह 4 घंटे में ही कर देता है और 'अतिरिक्त मूल्य' 4 घंटे के श्रम के स्थान पर 6 घंटे के उत्पादन मूल्य के बराबर हो जाता है,

इसके पश्चात् मार्क्स ने बताया कि पूँजीपति मशीनें लगाकर कई श्रमिकों को बेरोजगार कर देता है और देश में औद्योगिक क्षेत्रीय बेकारों की सेना" बन जाती है (Industrial reserve army of unemployed persons) इस बेरोजगारी के कारण मजदूरी की दर नीची बनी रहती है और श्रमिकों के शोषण से अधिकाधिक अतिरिक्त धन कमाता है

> "Accumulate, accumulate, accumulate, that is Moses and the Prophet."
>
> (अर्थात् धन संचित करते रहना ही पूँजीपति का धर्म रह जाता है।

5 जनसंख्या व विकास :

मार्क्स ने 'जनसंख्या का भय' अधिक जन्मदर में नहीं देखा उनके अनुसार जनसंख्या समस्या खाद्य सामग्री की उपज की दर से अधिक बढ़ने से नहीं उत्पन्न होती वरन् बेरोजगारी और गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं. बेरोजगारी व गरीबी की बुराई स्वयं पूँजीवाद के कारण उत्पन्न होती है. मार्क्स के अनुसार देश में जिस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था होगी उसी प्रकार का उस काल के लिए जनसंख्या का सिद्धान्त होगा उत्पादन व्यवस्था बदलेगी तो जनसंख्या के नियम भी बदल जाएँगे मार्क्स ने कहा

> "The Law of population under industrial capitalism is the law of a relative surplus population."

उन्होंने 'अधिक' जनसंख्या का यह कारण बताया

> "मेहनतकश जनता पूँजीपतियों को पूँजी संचित करने में सहायता देती है और साथ ही साथ अपने आप को अतिरिक्त या फालतू बना-

लेने का साधन भी पूंजीपति को प्रदान करती है यह है पूंजीवाद का जनसख्या का सिद्धान्त"[1]

मार्क्स का कथन था कि श्रम व गरीब वर्ग की गरीबी का कारण जनसंख्या की अधिक जन्मदर नहीं होता उन्होंने समाजवाद म "जनसख्या समस्या" की कोई सम्भावना नही देखी

6. कम मजदूरी से उपभोग गिरता है, क्योंकि उपभोग मजदूरी बिल पर निर्भर होता है इससे लाभ व विनियोजन कम होते हैं, फिर बडे पूंजीपति छोटे पूंजीपतियो का शोषण करते हैं और अन्त में पूंजीवाद समाप्त हो जाता है. (Wages fall and so do profits and investment : The Law of Concentration of capital / The Accumulation of Capital / The Law of Crises / The Theory of Economic developoment / Theory of automatic expropriation)

मार्क्स ने अपने अतिरेक मूल्य के सिद्धान्त के आधार पर मदी के सिद्धान्त को समझाया. मार्क्स के अनुसार गरीब वर्ग के मुकाबले मे धनी वर्ग का उपयोग नगण्य होता है. अगर देश के बडे वर्ग (गरीबो व मजदूरो) का उपयोग गिरेगा तो कुल प्रभावशील माँग भी गिरेगी और इस प्रकार से उत्पादन व राष्ट्रीय आय भी कम होगी मजदूरी स्तर जब तक गिरा रहेगा, विकास सभव ही नही हो सकता इस उपभोग के कम होने से ही औद्योगिक मदी आती है एक तरफ तो उत्पादनकर्ता अपना शोषण धन बढाता और दूसरी ओर बेरोजगारी तथा गरीबी व दु ख बढाता है

जब पूंजीपति श्रमिको का और अधिक शोषण नही कर पाते तो लाभ के लोभ में वे छोटे पूंजीपतियो को प्रतियोगिता मे नही रहने देते

> "बडा पूँजीपति छोटे पूंजीपतियो को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार एक बडे तालाब में बडी मछली छोटी मछलियो को निगल जाती है"

पूर्ण प्रतियोगिता नष्ट हो जाती है बडे बडे पूंजीपति एकाधिकार स्थापित कर लेते है और वे छोटे पूंजीपतियो को रहने नही देते

---

1 देखिये ·
Eden & Cedar Pant translation N york 1929 p 697-8
Coont . op cit p 120-28 and 189.

"पूंजीपति एक Vampire (बडी चमगादड) है जो दूसरो के खून पर जिन्दा रहता है और पनपता है और जितना अधिक खून चूसता है उतना ही मोटा होता जाता है."

मार्क्स ने लिखा

"Along with the constantly diminishing number of magnets of capital who usurp and monopolise all advantages of this process of transformation grows the mass of misery, oppression, slavery, degradation, exploitation but with this two grows the revolt of the working class always increasing in numbers, disciplined, united, organised by the very mechanism of the process of capitalist production itself The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production, who has sprung up and flourished along with, and under it. Centralisation of the means of production and socialisation of labour at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument This integument is burst asunder The knell of capitalist private property sounds. . The expropriators are expropriated' [1]

इन पक्तियो का हिन्दी भावार्थ है

"बडे पूंजीपतियो की सख्या धीरे धीरे कम होती जाती है और वे आर्थिक विकास के परिवर्तनो के समस्त लाभो को हडप जाते है इसके विपरीत साथ-साथ वृहत् मात्रा मे दु ख, जुल्म, गुलामी, पतन व शोषण बढता है--इसके कारण सख्या मे बढते हुए मजदूरो की बगावत (विद्रोह) बढता है. ये श्रमिक अब सख्या मे ही अधिक नही

1. Capital vol I. p. 837

होते वरन् वे अधिक अनुशासित, सगठित व संयुक्त होते हैं स्वयं पूँजीवाद ही इन्हे सगठित कर देता है--पूँजी का एकाधिकार होने से उत्पादन पद्धति मे बन्धन पड़ता है उत्पादन के अगों के कुछ हाथो मे केन्द्रित होने से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सम्पूर्ण पद्धति पूँजीवाद के आवरण मे छिप नही सकती. पूँजीवाद का पर्दाफाश हो जाता है. निजी सम्पत्ति व पूँजीवादी व्यवस्था की अरथी के साथ बजने वाले घण्टे के स्वर गूँजने लगते हैं शोषणकर्ताओ का ही *शोषण हो जाता है.*

मार्क्स के अनुसार पूँजीवाद एक अस्थिर व विस्फोट की सम्भावनाओ से भरी प्रणाली है. यह जिस रफ्तार से श्रमिको को काम पर लगाती है उससे अधिक रफ्तार से श्रमिको को बेकार करती है मार्क्स के अनुसार अगर पूँजीवादी "स्थिर तकनीक" अपनाये तो मजदूर किसी हद पूजी सचय के साथ साथ अपनी स्थिति भी सँवारें रह सकते. परन्तु पूँजीपति तो अधिकाधिक मशीनें लगाते हैं और "बेकारो की सेना" को उत्पन्न कर देते हैं परन्तु जब इन पूजीपतियों के शोषण से जनता त्रस्त हो जाती है तो उन्हे उखाड फकती है

> 'What the capitalists produce after all, are their own grave-diggers"
>
> "पूंजीवादी वास्तव मे अपनी कब्र खोदने वाले उत्पन्न करते हैं पूंजीवादी अब मजदूरो के ऊपर राज्य करने के लिए नाकाबिल हो गए है"

मार्क्स ने बताया कि जहाँ अल्पकाल मे उन्नत तकनीक उत्पादनकर्ता के अतिरेक मूल्य व लाभ को बढाते है, दीर्घकाल मे उन्नत तकनीक से बेरोजगारो की सख्या बढ जाती हैं जिससे श्रमिको का उपभोग कम होता है और इसके कारण उत्पादनकर्ता के लाभ कम होते हैं और विकास रुक जाता है पूजीपति उन्नत तकनीक के दीर्घकालीन दुष्प्रभावो से, अपने निजी स्वार्थ के कारण, अनभिज्ञ रहते हैं केवल दीर्घकालीन महान मन्दी ही उन्हे मजदूरो की वास्तविक मजदूरी गिराने की मूर्खता की सचाई सामने लाती है, परन्तु तब तक उनका महाकाल उन्हे ग्रस्त कर चुकता है.

मार्क्स के अनुसार व्यापार चक्र केवल एक अल्पकालीन घटना नही होते वरन् वे तो दीर्घकाल मे पूजीवाद के समाप्त होने के अनिवार्य नियम के अग है पूजीपति इन परिस्थितियो मे अपनी हानि को पूरा करने के लिए सट्टेबाजी का सहारा लेते

है और अधिक बर्बाद होते है इन्ही व्यापार चक्र के कारण समस्त साख व्यवस्था और वित्तीय सगठन नष्ट हो जाता है

II Marxian Theory of Socio economic revolution
मार्क्स का 'सामाजिक-आर्थिक' क्रान्ति का सिद्धान्त

1. देश के आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक, नैतिक व राज नैतिक सम्बन्ध निर्धारित करते हैं

मार्क्स के अनुसार देश की उत्पादन व्यवस्था से आर्थिक सम्बन्ध निर्धारित होते है (जैसे जमीदार और किसान, स्वामी व दास पूजीपति व मजदूर) यही सम्बन्ध किसी भी युग की सास्कृतिक व्यवस्था, उसके नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एव राजनैतिक विचार एव सस्थाओ का मुख्यत निर्धारण करते है उत्पादन शक्ति मे जब परिवर्तन होता है तो उत्पादन सम्बन्ध बदलता है और उत्पादन सम्बन्ध के परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन घटित होते है

वैसे उत्पादन सम्बन्ध भी उत्पादन शक्ति पर प्रभाव डालते है. वे वास्तव मे एक दूसरे पर निर्भर है मार्क्स ने इनका उदाहरण दिया और बताया कि बिजली व मशीनो के आविष्कार ने ही सामन्तवाद को बदल कर पूजीवाद को जन्म दिया इसी आधार पर मार्क्स ने लिखा

> "The mode of production in material life determines the character of the Social political and spiritual processes of life It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their consciousness"

2 विश्व में हर चीज परिवर्तनशील है (Nothing, except constant change, is constant in this world)

मार्क्स के अनुसार परिवर्तन एक अनोखी नही, वरन् एक स्वाभाविक घटना है, (Change is not an unique but a natural phenomenon) यही प्राकृतिक नियम है कि सब कुछ अपने आन्तरिक स्वभाव के कारण विकसित व परिवर्तित होगा मई पीढी के आने व नए नए आविष्कारो के कारण, नवीन उत्पादक शक्तियो का जन्म स्वत अचेत रूप म तथा मानव इच्छा से स्वतन्त्र रह

---

(1) See . Communist Manifesto

कर होता है "सामाजिक परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली का 'सामाजिक परिणाम' होते है"

3 समस्त महत्वपूर्ण परिवर्तन क्रान्ति से ही आते हैं

यह समस्त परिवर्तनो मे सघर्ष व उथल पुथल भी होती है उत्पादन शक्तियो का विकास तथा उत्पादन सम्बन्धो में परिवर्तन कुछ समय तक तो स्वाभाविक गति से तथा स्वतन्त्रतापूर्वक होता रहता है. पर जब वे सम्बन्ध परिपक्व अवस्था मे पहुँच जाते है तो 'प्रसव की पीडा' की भाँति उत्पीडन के पश्चात् नये सम्बन्ध स्थापित हो जाते है. पुराना वर्ग विकास म अलङ्घनीय (Insuperable) बाधा बन जाता है जब नया वर्ग इनको हटाना चाहता है तो पुराना वर्ग उनपर अत्याचार करता है परन्तु नया वर्ग उन्ह क्रान्ति के द्वारा अन्त मे हटा ही देता है जब यह सम्बन्धो की वेडियाँ तोड दी जाती है तब समाज की सरचना भी परिवर्तित हो जाती है

मार्क्स के अनुसार .

> "नये विचार और सिद्धान्त नयी भौतिक परिस्थितियो मे उत्पन्न होते है इनके द्वारा जन साधारण को भौतिक जीवन की त्रुटिया और आन्तरिक विरोधो का ज्ञान हो जाता है. जब ये विचार जनता की निधि बनते है, तो वे सामाजिक परिवर्तनो के लिए बेशकीमती हो जाते है इनकी पृष्ठभूमि मे ही जनता उन शक्तियो को विध्वस कर सकती है जो समाज की प्रगति में बाधक है"

कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने परिपक्व होने के बाद ही समाप्त होती है मार्क्स के अनुसार

> "उत्पादन के नवीन तथा उच्चतर सम्बन्ध तब तक कदापि उत्पन्न नही होते जब तक उनके अस्तित्व की भौतिक दशाये पुराने समाज के गर्भ में परिपक्व नही हो जाती है"

III Marxian Stages of Economic Growth मार्क्स और उनकी विकास की अवस्थाएँ

> 'Marx was a 'Stages-man' par excellence Hegel's thesis, anti- thesis, and synthesis becoming in Marxian Economics Feudalism, capitalism and socialism"
>
> (Meier and Baldwin op. cit p !48)

मार्क्स ने Communist Manifesto मे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का उल्लेख किया यह विकास की अवस्थाएँ पूर्ण रूप से संघर्ष पूर्ण होती है. इसीलिए रोस्टोव ने (W. W Rostow) ने अपनी संघर्षहीन अवस्थाओं को A Non-communist Manifesto कहा

मार्क्स की यह विकास की अवस्थाएँ इस प्रकार से थी

1. प्राथमिक और असभ्य साम्यवाद : (Primitive Communism)

मार्क्स का कथन था कि सर्व प्रथम मानव जाति असभ्य थी. वह जगलो में जानवरो की तरह रहती थी और जो कुछ वे पाते थे (न कि पैदा करते थे) उस पर निर्वाह करते थे बाद मे कृषि आदि जो कुछ भी विकसित हुई उसके तरीके पुराने थे परन्तु इस 'समाज' मे भी साम्यवाद था. समस्त उत्पादन व वितरण सामूहिक ढग से होता था. यह साम्यवाद परन्तु, "गरीबी की स्थिति" का था.

2. दास प्रथा Slave Society.

इस प्रथा मे भूमि कुछ लोगो के हाथ चली जाती है और इस युग मे कृषि उत्पादन दासो द्वारा किया जाता है न केवल भूमि कुछ लोगो की सम्पत्ति रहती है वरन् स्वय श्रमिक इन मालिको की सम्पत्ति बन जाते है. वे अपना श्रम ही नही बेचते बल्कि स्वय को भी बेच देते है.

3. सामन्तवादी समाज : (Feudal Society)

यह विकास की तीसरी पर कुछ ऊँची अवस्था होती है इस प्रथा मे श्रमिको को दास के रूप से नही रखा जाता था, परन्तु वेतन आदि के रूप मे रखा जाता था. उनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी नही रहती थी भूमि के मालिक जमीदार रहते थे. छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग चलते थे उत्पादन व्यवस्था कुछ उन्नत थी, सामाजिक व आर्थिक जीवन भी कुछ उन्नत था.

4. पूँजीवाद : (Capitalism)

मार्क्स ने पूँजीवाद को विकास की श्रृखला की महत्वपूर्ण कडी माना. मार्क्स पूँजीवाद के विकास मे योगदान के बहुत प्रशसक रहे. उनके अनुसार "पूँजीवाद ने संकुचित विचारधारा को कम किया. सामन्तवाद की राख पर पनपनेवाले पूँजीवाद ने विश्व की जनता के बडे भाग को गाँव की 'बेवकूफी भरी' जिन्दगी से छुडाया. पूँजीवाद ने उन्नत तकनीक दी और विशाल मात्रा मे राष्ट्रीय आय व उत्पादन बढाने की सम्भावनाएँ सामने लाई कुछ ही पीढियों मे पूँजीवाद ने समस्त पिछले इतिहास से अधिक धन पैदा कर दिया."

पूँजीवाद मे उत्पादन के अगो के मालिक वे व्यक्ति हो गए जो या तो कुछ भी मेहनत नही करते या बहुत कम मेहनत करते है. जो सक्रिय है व उत्पादन की जान है (श्रमिक) उनसे उनके औजार छीन लिए गए. उनके रोजगार के मालिक पूँजीपति हो गए. ऐसी उत्पादन व्यवस्था मे मजदूरी श्रम (Wage Labour) के आधार पर उत्पादन कराया जाता है. ऐसे उत्पादन से प्राप्त लाभो को पूँजीपति वर्ग ही हड़प लेते है.

पूँजीवादी उत्पादन पद्धति अधिकाधिक जटिल होती जाती है श्रम विभाजन पर आधारित इस पद्धति मे वर्ग सघर्ष मुख्य अग रहता है. मार्क्स ने लिखा

> Freeman and slave, patrician and plebeian, baron and serf, guildmaster and journey man. in one word, oppressor and oppressed, Standing constantly in opposition to each other carried on an uninterrupted warfare, now open, now concealed, a warfare which always ended either in a revolutionary transformation of the whole Society or in the common ruin of the contending classes."[1]
>
> (अर्थात् स्वतन्त्र व्यक्तियो व गुलामो मे, सामन्तो और साधारण व्यक्तियो मे, मालिक और दासो मे, एकाधिकारियो व मजदूरो मे, सक्षेप में शोषणकर्ता व शोषित व्यक्तियो मे एक न समाप्त होने वाली लडाई, जो कभी प्रत्यक्ष व कभी छिपी हुई रहती है, चलती रहती है. इस लडाई मे या तो एक नए क्रान्तिकारी समाज की स्थापना होती है या फिर दोनो बरबाद हो जाते है.)

मार्क्स ने अपनी इन अवस्थाओ मे द्वन्दात्मक भौतिकवाद समझाया इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषताएँ यह है

(i) ससार मे पहले एक 'वाद' का जन्म होता है (first a thesis is propounded),

(ii) फिर उसका प्रतिवाद होता है (Then there is anti-thesis),

(iii) तत्पश्चात् इन दोनो का सम्वाद होता है (Then there is synthesis of both).

1. Manifesto of the Communist party.

इस प्रकार का यह क्रम चलता रहता है उत्थान परिवर्तन और विनाश का यह क्रम विरोधी शक्तियों के कारण चलता है.

मार्क्स ने समझाया कि समाज मे गुणात्मक एव गणनात्मक दोनो प्रकार के परिवर्तन होते है ये परिवर्तन धीरे-धीरे नही वरन् एकदम होते है

प्रत्येक द्वन्दात्मक परिवर्तन मे हम ऊपर उठ जाते है. विकास की प्रक्रिया चक्रवत् नहीं होती वरन् आगे बढाती है समस्त परिवर्तन क्रान्तिकारी रूप से आते है और समाज में जो कुछ भी परिवर्तन या विकास होता है वह विरोध एव संघर्ष द्वारा ही होता है

> "Force is the midwife of every old society pregnant with a new one."

और उन्होंने कहा

> "माता की प्रसव पीडा द्वारा ही बालक का जन्म होता है, उसी तरह क्रान्ति, (परिवर्तन रूपी शिशु) का जन्म समय समाज रूपी माता की प्रसव पीडा है"

इस प्रकार मार्क्स का कथन है कि इतिहास का निर्माता वीर नायक नही वरन् वीर जनता होती है मेहनतकश जनता का इतिहास ही विकास का इतिहास होता है

मार्क्स इस प्रकार से पूंजीवाद को विकास की अवस्थाओ की एक कड़ी मानते थे जिसको टूटना पड़ेगा पूँजीवाद मे वर्ग-सघर्ष रहेंगे और जब तक पूंजीवाद समाप्त नही होगा, वर्ग-सघर्ष भी समाप्त नहीं होंगे

मार्क्स ने बताया कि पूँजीवाद के समाप्त होने से पहले पूँजीवाद साम्राज्यवाद का रूप लेगा. परन्तु कालान्तर मे दोनो समाप्त हो जाएँगे

5. साम्राज्यवाद : (Imperialism)

मार्क्स ने साम्राज्यवाद को पूँजीवाद का विपुल रूप माना उनका कथन था कि पूँजीवाद नष्ट होने से पहले देश मे एकाधिकारी पूँजीवाद का रूप लेता है तदुपरान्त वह अन्तर्राष्ट्रीय पूँजीवाद या साम्राज्यवाद का रूप लेता है. एक बडे पूँजीपति देश के उत्पादन कर्ताओ के लाभ के लिए पूँजीपति देश के राज्य गरीब देशो को अपने आधिपत्य मे लाते है.

यह पूँजीपति वर्ग अपना धन इन गरीब देशो मे लगाते है पर उनका लक्ष्य उन देशो का आर्थिक विकास करना नही होता वरन् अपने देशो के लिए सस्ते कच्चे

माल के पूर्तिकर्ता के रूप मे इन देशों का प्रयोग किया जाता है. पूँजीपति देशो के उत्पादनकर्त्ता अपने अधीनस्थ देशो के श्रम का शोषण करते है इनको न केवल जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी देते हैं. इनको सगठित नही होने देते

पूँजीवादी देशो के उत्पादनकर्ता उपनिवेशों के देशो मे व्यापार की लूट से अपने देश के विकास के लिए पूँजी निर्माण करते है साम्राज्यवादी, इन देशो मे सस्ता सामान लेते है और बहुधा उन्ही के कच्चे माल से बने सामान को अधिक मूल्य पर बेचते है साम्राज्यवादी भुगतान की शर्तो को हमेशा अपने पक्ष मे रखते है इन देशो से सस्ता खाद्यान्न मँगाकर अपने देश की मजदूरी बढने से रोकते है इन देशो से आयातो पर प्रतिबन्ध लगाते है जबकि अपने देशो के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नही लगाते

मार्क्स का कथन था साम्राज्यवादी देश इस प्रकार से अपने देश मे पूँजीवाद के अन्त होने को केवल टाल सकते है, बचा नही सकते बाद म साम्राज्यवादी देश इन उपनिवेशो पर अपना अपना आधिपत्य जमाने के लिए सघर्ष युद्ध करते है और स्वय नष्ट होते है दूसरी ओर गरीब देशा की गरीब जनता इनके खेलको समझ जाती है वे सगठित होते है और फिर वे इस साम्राज्यवादियो को समाप्त कर देते हैं अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष और युद्ध साधारण जनता म राष्ट्रीयता का उदय करते है और इसके साथ ही पूँजीपति तथा श्रमिक वर्ग का सघर्ष छिड जाता है.

साम्राज्यवाद जब समाप्त हो जाता है तो पूँजीवाद पूरी तरह नष्ट हो जाता है और फिर समाजवाद आशा का सूर्य लेकर उदय होता है

6 समाजवाद : (Socialism)

पूँजीवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के बाद समाजवाद का युग आएगा समस्त उत्पादन पूँजी–भूमि व उद्योग–राज्य के अधिकार व मालकियत मे आजाएँगे. देश व किसान व श्रमिक ही वास्तव मे इनके मालिक होगे, वे सामूहिक रूप से इन पर कार्य करेंगे और व्यय को काट कर जो कुछ लाभ होगा वह राज्य व श्रमिको को मिलेगा राज्य प्रशासन व सुरक्षा आदि के व्यय को खर्च करने के पश्चात् लाभ के बाकी भाग से और अधिक पूँजी निर्माण करेगा और जनता के आर्थिक सामाजिक व सास्कृतिक विकास मे लगाएगा. समाजवाद मे सबको शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने व कार्यानुसार पारिश्रमिक पाने का अधिकार होगा वर्ग-सघर्ष, शोषण व असुरक्षा समाप्त हो जाएगी.

समाजवादी देश अन्य देशो के पूँजीवाद व साम्राज्यवाद के खिलाफ सघर्ष में सहायता देंगे

7 साम्यवाद . (Communism)

समाजवाद में जहां 'कार्यानुसार" वतन मिलता है, साम्यवाद में "आवश्यकता अनुसार' वतन मिलेंगे समाजवाद सबके लिए इतनी समृद्धि ला देगा कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हो जाएँगी ऐसे शोषण विहीन तथा समृद्ध समाज में राज्य या शासन की ही आवश्यकता नहीं रहेगी और जब विश्व में सब जगह समाजवाद स्थापित हो जाएगा तब हमारी कल्पना का स्वर्ग यही आ जाएगा

(The state will wither away)

IV Critical Appraisal of Marxian Model

As a formal model Marxian economics is weak The "internal contradiction" of the model are more pronounced than in capitalism itself (Meier and Baldwin op. cit p. 66)

मार्क्स का विकास मॉडल आर्थिक विकास के सबसे महान् "क्रान्तिकारी मॉडलों म से एक ह मार्क्स के मॉडल मे कुछ बातें तो बहुत ही गलत हैं, जैसे

(1) मार्क्स का कथन है, पूंजीपतियों समस्त लाभ श्रम से प्राप्त होते हैं पूंजी से नहीं श्रम ही समस्त आय व लाभ का साधन है (High organic composition of more capital and less labour yields leser surplus value than low organic composition of less capital and more laboures). अगर वास्तव मे ऐसा है तो पूंजीपति मूर्ख होगा कि वह अधिकाधिक मशीने लगाकर श्रमिक को बेरोजगार करे

(2) मार्क्स का कथन है अल्पकाल म पूंजीपति मशीनें लगाकर व उन्नत तकनीक मे लाभान्वित होता है, और दीर्घकाल में "तकनीकी बेरोजगारी" के कारण ही जब प्रभावशील मांग कम होती है तो पूंजीवादी लाभ समाप्त हो जाते हैं

यहाँ पर मार्क्स के तर्क वास्तविकता के विपरीत है. वास्तव मे मशीनों मे अल्प काल मे बेरोजगारी उत्पन्न होती है दीर्घकाल मे तो मूल्य सस्ते होने के कारण जो अधिक मांग उत्पन्न होती है उससे अधिक लोगों को वापिस काम मिल जाता है और स्वय मशीन के निर्माण मे व्यक्ति काम पर लग जाते है

"अगर हम पिछला इतिहास देखें तो पाएँगे कि विश्व में अप्रत्याशित रूप से तकनीकी उन्नति हुई है—यातायात मे जानवरों से वायुयानों

तक, औजारो मे पत्थर के टुकडो से स्वचालित स्क्रू-मशीनो तक, सचार में धुएँ द्वारा सूचना देने की रीति से रेडियो तक, मशीनो मे हाथ से चलने वाली मशीनो से बिजली की मशीनो तक, परन्तु जन-सख्या की वृद्धि के बाद भी आज कितने अधिक व्यक्ति खानो, मिल व कारखानो खेत व दुकानो व यातायात मे कार्य कर रहे हैं दीर्घ-काल मे तकनीकी बेरोजगारी केवल कोरी कल्पना का डर है."[1]

(3) मार्क्स की बहुत सी भविष्यवाणियाँ सत्य नही निकली आज मजदूरो के वेतन केवल जीवन निर्वाह के बराबर नही है. उन्नत देशो मे सगठित श्रमसघो, राज्य के प्रयत्नो से मजदूरी के स्तर ऐसे हैं कि श्रमिक भी अच्छा जीवन यापन करते हैं उत्पादन मे मजदूरो को लाभ मे भी हिस्सा मिलता है मजदूरो का स्तर गुलामो का नही रह गया है उन्हे *सामाजिक सुरक्षा* के अधिकाधिक लाभ मिल रहे है (पेन्सन, बेरोजगारी का मुआवजा, छुट्टियाँ, इलाज की सुविधाएँ, प्रोविडेन्ट फड, मातृत्व दिनो मे लाभ आदि)

(4) पूँजीवाद में तो श्रमिक भी पूँजीपति बन सकते है. समस्त देशो मे तो बडे बडे सस्थानो के शेयर स्वय श्रमिक भी अधिक मात्रा मे खरीद लेते है.

(5) पूँजीवाद मे आज सारे सस्थान "एकाधिकारी" सस्थान नही है. छोटे उत्पादनकर्ता आज भी है और वे बडे उत्पादनकर्ताओ के द्वारा निगले नही गए है. उन्नत से उन्नत देशो मे एकाधिकार विरोधी नियम है.

(6) स्वय समाजवादी देशो मे श्रमिक सघर्ष करते हैं वहाँ बडे पार्टी अफसर व राजनीतिज्ञ ही बडे पूँजीपति का रूप ले लेते है हगरी व जेकोस्लोवेकिया के श्रमवर्ग का समाजवादी व्यवस्था के शिकजे से निकलने या कम से कम उसे ढीला कर देने के आन्दोलन से हम परिचित है सच तो यह है कि विकसित देशो मे समृद्धि मे रहने के स्वय श्रमवर्ग आदी हो गया है और आज बेकार ही समाजवादी देशो के व्यक्ति मार्क्स की भविष्यवाणी के पूरा होने की आशा रखते है.

---

1. Translated : See. p. 2 'Economics of Wages, Productivity and *Employment" by Dr. O S. Shrivastava*, Kailash Pustak Sadan, Gwalior 1968.

(7) Meier & Baldwin के अनुसार

(i) मार्क्स के हम इस विचार को नही मान सकते कि सभी परिवर्तन संघर्ष से आते है

(ii) मार्क्स का विकास का सिद्धान्त "भावात्मक" अधिक है उसमें उनके क्रोध की झलक है [1]

उन्होने कहा

"Like all single factor theories, the Marxian interpretation of history has the appeal of simplicity and generality, But this is a multi-factor world, and truer though less spectacular explanation involve a recognition of complex interactions among many variables The Marxian theory is too crude to pass the test of being able to predict accurately."

(8) Benjamin Higgins के अनुसार मार्क्स का कथन था कि समाजवाद उन देशो म आएगा जहाँ पूँजीवाद विकास की चरम सीमा पर आ जाता है परन्तु वास्तव म समाजवाद वहाँ आया है जहाँ पूँजीवाद विकसित नही हुआ था. आज विकसित देशो मे मध्यम वर्ग के परिवार भी आगे बढ रहे है. जबकि समाजवादी देशो में न तो गरीबी पूर्ण रूप से दूर हुई है और न राज्य का ही अस्तित्व समाप्त हुआ है.

मार्क्स यह भी नही समझ पाए थे कि उन्नत तकनीक व बढती हुई उत्पादकता की स्थिति मे लाभ व मजदूरी दोनो एक साथ बढते है

Higgins कहते है

"Marxian Model is based upon a diagnosis of the social situation of the 1840 s and 1850's that was ideologically vitrated at its roots, hopelessly wrong in its prophecy of ever increasing mass misery, inadequately substan-

1. Meier & Baldwin op cit. 51-66.

tiated both factually and analytically." अर्थात् मार्क्स का मॉडल 1840 व 1850 के बीच की आर्थिक-सामाजिक स्थिति पर आधारित था इसकी बौद्धिक जडे दूषित थी, इनकी भविष्यवाणी कि अधिकाश जनता दुखी रहेगी पूर्णतया असत्य रही और सैद्धान्तिक विश्लेषण व ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर इनके मॉडल की सत्यता प्रमाणित नही हो सकी.[1]

(9) Subratesh Ghosh के अनुसार 'मार्क्स" ने कभी भी विकास का सिद्धान्त प्रतिपादित नही किया, परन्तु उन्होने जो कुछ लिखा उसमे विकास प्रक्रिया समझने मे मदद मिलती है. मार्क्स 'शुद्ध अर्थशास्त्री" तो नही थे उनके लिखने का उद्देश्य न तो अध्यापन सबधी था और न ही बुद्धि सम्बन्धी था. (His objective were neither pedagogic nor intellectual) उन्होने अपने किसी भी विचार को सामाजिक पहलू से अलग नही किया" इसलिए उन्होने आर्थिक कारणो का विकास मे ज्यादा अध्ययन किया.

(10) मार्क्स के जनसख्या सम्बन्ध मे विचार त्रुटिपूर्ण थे कि वे अधिक जनसख्या को पूंजीवाद की समस्या ही मानते थे आज समाजवादी देश भी जनसख्या नियन्त्रण की बात सोचते है. उनका यह कथन एकदम अवास्तविक है कि समाजवादी प्रथा अपनाई जाए तो जनसख्या की अधिकता कभी महसूस नही होगी और न ही जनसख्या वृद्धि विकास मे बाधक होगी

(11) मार्क्स का यह भी कथन सही सिद्ध नही हुआ कि अगर विकासशील देशो मे साम्राज्यवादी हट जाएँगें तो विकास स्वय शुरू हो जाएगा. हालांकि साम्राज्यवाद समाप्त होना अत्यन्त आवश्यक है परन्तु कई देशो मे साम्राज्यवादियो के जाने के बाद वे अपनी पूँजी भी वापिस ले गए या विदेशी पूंजी व तकनीकी सहायता के कम हो जाने से उनका विकास रुक ही गया

मार्क्स जैसे व्यक्ति के लिए निम्नलिखित बात कहना आश्चर्यजनक लगता है .

"समस्त देश एक जैसी पूंजी निर्माण व उत्पादन की क्षमता नही रखते. कुछ पिछडे राष्ट्रो मे जैसे तुर्की में न तो प्रेरणा और न ही इस बात की रुचि होती है."[2]

---

1. Benjamin Higgins : op-cit. p. 117-120
2. See · I E A Number on Economic Growth Models.

इन देशों में तक्नीकी उन्नति के कारण या व्यापारिक चक्रों के कारण बेरोजगारी नही आती वरन् पूंजी की कमी व जनसख्या की जन्म दर के अधिक होने के कारण होती है.

महत्व

आज मार्क्स के विकास मॉडल को अपनाने से ही विकास नहीं हो सकता. स्वय समाजवादी देशों मे उस 'घृणित अर्थशास्त्र" (Vulgar Economics) के सिद्धान्त, जिनको मार्क्स ने तिरस्कार किया पूर्ण रूप से छोड नही जा सके वहाँ भी आज बाजार की स्थितियों को ध्यान म रखना पड़ता है परन्तु यह सब कुछ होते हुए मार्क्स के मॉडल मे महत्वपूर्ण तत्व व सुझाव है

Schumpeter के अनुसार

> "No social scientist has so deeply understood the impact of capitalistic machine and shown in so grand a vision of its immense power to transform human civilization in the process of technical and social change"

Benjamin Higgins ने मार्क्स के मॉडल में निम्नलिखित तत्वों को महत्व-पूर्ण बताया

(i) उन्होने ही बेरोजगारी की समस्या को सर्वप्रथम विकास मॉडल म स्थान दिया.

(ii) उन्होंने स्थायी विकास के लिए उपभोग व विनियोजन तथा बचत व विनियोजन में सन्तुलन रखने पर जोर दिया.

(iii) उन्होंने पूंजीवाद म विकास की ऐतिहासिक अवस्थाओ का अध्ययन किया जो कि हमको किसी देश के विकास का भूत व भविष्य समझने में मदद करता है.

Nasir Khan

> "Marx was the fist among the older economists who gave a model of expanded reproduction and introduced the cycle in his analytical scheme...This was a static economic analysis... ...He even guessed of 11—12 years of cycles. but formulated no precise trade cycle theory"

Meier Baldwin

मार्क्सवाद को हमको समझना चाहिए क्योंकि यह आज भी सबसे अधिक अपील करने वाला राजनैतिक धर्म है जो विकसित व विकासशील दोनों के भविष्य सुधारने में सहायक हो [1]

Marx Capital & Communist Manifesto

1 Benjamin Higgins op cit
2 Meier & Baldwin op cit
3 D B singh op cit
4 Nasir Khan op cit
5 Okun & Richardson op cit
6 J K Mehta op cit
7 Haney op cit
8 Gide & Rist op cit
9 A Gray op cit
10 Eric Roll op cit
11 Schumpeter op cit
12 Taylor op cit
13 Neff op cit
14 Joan Robinson Marx as an Economist
15 R N Mukerjee समाज शास्त्र की विचार धारा

अध्याय : 11

नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्री मार्शल

Neo-Classical Economist Marshall

A प्रस्तावना

B विकास पर विचार

1. राष्ट्रीय आय उत्पादन के पाँचो अगो के सहयोग का परिणाम है
2. कृषि व उद्योग का सापेक्षिक महत्व
3. जनसख्या व पूँजी
4. मजदूरी, ब्याज, लगान व लाभ
5. विकास की प्रक्रिया सतत तथा धीमी
6. विकास की प्रक्रिया में कोई सघर्ष नहीं

नव-प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियो का विकास मॉडल

Neo Classical Model As a whole

A प्रस्तावना

B विकास मॉडल

1. विकास पूँजी सचय पर निर्भर
2. इनके अनुसार (i) तकनीक की उन्नति (ii) श्रम विभाजन के विस्तार (iii) लाभ की वृद्धि तथा (iv) उत्पादन के अगों को सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के अनुसार कार्य पर लगा कर (v) राष्ट्रीय आय बढाने में विकास होता है
3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास आर्थिक विकास में सहायक
4. विकास प्रक्रिया समन्वित व सचयी होती है

C नव-प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्रियो के विकास सबधी विचारो की समीक्षा
कमियाँ

अध्याय : 11

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल

Neo-Classical Economist Marshall

A प्रस्तावना

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो मे मार्शल मुख्य अर्थशास्त्री थे उनके बारे मे कहा जाता है कि उन्होने पुरानी शराब को नई बोतलो मे भरा इन्होने सर्वप्रथम तो अर्थशास्त्र को 'भौतिक कल्याण का शास्त्र' कहकर कल्याणकारी शास्त्र बनाया इसलिए मार्शल के अनुसार किसी देश के विकास का मापदण्ड यही नही होता कि उस देश मे कितना उत्पादन होता है (या कितनी राष्ट्रीय आय म वृद्धि होती है) वरन् मापदण्ड यह है कि इससे कितना सामाजिक कल्याण बढता है .

इनके विकास सम्बन्धी विचारो को हम निम्न सूत्रो मे बाँध सकते है

B विकास पर विचार

1. राष्ट्रीय आय उत्पादन के पाँचो अगो के सहयोग का परिणाम है राष्ट्रीय आय की वृद्धि विकास सूचक है

मार्शल के विचार मे उत्पादन के तीन प्रमुख साधन प्राकृतिक साधन, श्रम व पूँजी है उन्होने सगठन और साहसी को भी महत्वपूर्ण माना, पर विकास प्रक्रिया मे साहसी का जितना महत्व आगे शम्पीटर ने आँका था उतना मार्शल नही बता पाए श्रमको उन्होने उत्पादन का साधन व साध्य माना

मार्शल ने उत्पादन के अगो के परस्पर प्रतियोगी व पूरक होने की बात कही कभी कभी यह अग पूरक होने के स्थान पर प्रतियोगी हो जाते है, जैसे एक मशीन कुछ श्रमिको को बेरोजगार कर देती है पर मार्शल के अनुसार अत मे सब उत्पादन के अग एक दूसरे के पूरक हो जाते है (जैसे विस्थापित श्रमिक बाद मे मशीनो के उत्पादन मे काम पा लेते है या मशीनो के कारण जो चीजे सस्ती होती उनसे बढी हुई माँग को पूरा करने के लिए काम पा जाते है)

उन्होने स्वय राष्ट्रीय आय को विकास का द्योतक माना और उसकी सर्वप्रथम सर्वग्राह्य परिभाषा दी, जो इस प्रकार थी

"राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की वह वार्षिक शुद्ध आय है जिसको उस

देश के प्राकृतिक साधनो का प्रयोग करके उस देश के पूँजी व श्रम भौतिक व अभौतिक वस्तुओ के रूप मे एक वर्ष में पैदा करते है "

मार्शल ने बताया कि किसी देश का विकास उचित वितरण (सीमान्त उत्पादकता के अनुसार) पर ही निर्भर नही करता वरन सर्वप्रथम इस आय को बढाने से बढता है (We should not clamour too much for having a greater share from a cake but should try to increase the size of the cake itself) (यह मार्शल के शब्द नही हैं).

इस प्रकार मार्शल अधिक राष्ट्रीय आय व उचित वितरण दोनो को विकास के लिए आवश्यक मानते थे

2 **मार्शल ने भी तक्नीक व श्रम-विभाजन का विकास प्रक्रिया में महत्व माना कृषि व उद्योग का सापेक्षिक महत्व :**

मार्शल उन्नत तक्नीक को बहुत महत्व देते थे इसके कारण वे तो यह भी मानते थे कि कृषि में भी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से रोका जा सकता है और काफी समय तक टाला जा सकता है इस सबध मे उनके विचार रिकार्डो की भाँति निराशापूर्ण नही थे, और इसी कारण वे हर जनसख्या वृद्धि को रिकार्डो की भाँति भय से नही देखते थे वे कहते थे' 'भूमि की उर्वरता स्थिर नही है. वह समय, स्थान व तकनीक के साथ साथ बदलती है और उन्नत तक्नीक से भूमि की उत्पादकता दुगुनी भी हो सकती है खाद्य सबधी समस्या के सबध मे उन्होने बताया कि समुद्र से मछली तो उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुसार प्राप्त हो सकती है

मार्शल का कथन था कि "जहाँ उत्पत्ति में मनुष्य का योगदान अधिक होता है वहाँ उत्पत्ति वृद्धि नियम और जहाँ प्रकृतिका योगदान अधिक होता है वहाँ ह्रास नियम लागू होता है " इस प्रकार से अगर कृषि मे मनुष्य का योगदान बढा दिया जाए (अर्थात् उन्नत तक्नीक अपनाई जाए) तो इसम उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू हो सकता है

मार्शल उपरोक्त कारण से ही उद्योग को कृषि से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे मार्शल मशीनीकरण के पक्ष मे थे क्योंकि इससे श्रम-विभाजन और विस्तृत किया जा सकता है इसकी वृद्धि मे उत्पादकता व राष्ट्रीय आय, अर्थात् विकास बढता है

Marshall . Principles of Economics & Economics of Industry
p 116, 434, 550-3
p 125-140 p 220.
p. 150-170.

मार्शल ने उत्पत्ति मे समता के नियम के कार्यान्वित होने की सम्भावना व्यक्त की.

3 जनसंख्या व पूँजी :

वे भी पूँजी-सचय को विकास की सर्वप्रथम आवश्यकता मानते थे, इसी की मात्रा वृद्धि से तकनीकी उन्नति सभव है

जनसख्या के सबध में मार्शल माल्थस के विचारो से सहमत नही थे शिक्षित लोगो मे वे बडे परिवार को बुरा नही मानते थे. उनका पूर्ण विश्वास था कि अगर जनसख्या में गुणात्मक वृद्धि (अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी शिक्षा) होती है तो इससे देश मे विकास बढेगा उनका विश्वास था कि उत्पत्ति-वृद्धि नियम के कार्यान्वित होने पर उत्पत्ति जनसख्या से भी अधिक बढाई जा सकती है

4 मार्शल के विकास मॉडल में मज़दूरी, ब्याज, लगान व लाभ :

(a) मार्शल ने जब वितरण की समस्याओं पर लिखा तब मार्क्स लिख चुके थे, इसलिए वे मजदूरी को जीवन निर्वाह के बराबर रखने को बोल ही नही सकते थे फिर उनका माल्थस के जनसख्या के सिद्धान्त मे विश्वास भी नही था उन्होंने लिखा

> "Free human beings are not brought upto their work on the same principles as a machine, a horse or a slave"

उन्होंने मज़दूरी निर्धारण मे मानवीयता दिखाने व न्याय करने की माँग देखी और उनके अनुसार "मज़दूरी की अधिकतम दर मज़दूरो की सीमान्त उत्पादकता व न्यूनतम मात्रा जीवन स्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित होती है. व मजदूरी-प्रणाली ऐसी चाहते थे जिससे श्रम की कार्यक्षमता व उत्पादकता बढे जिससे कि राष्ट्रीय आय बढे और विकास हो.

(b) ब्याज को भी वे माँग व पूर्ति या सीमान्त उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होना मानते थे. ब्याज को वे बचत व विनियोजन में साम्य लाने वाला तत्व मानते थे अगर कभी भी देश मे विनियोजन की मात्रा के लिए अधिक पूँजी न हो तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है और फिर इसी मे बचतें बढ जाती है, व विनियोजन के लिए पर्याप्त पूँजी प्राप्त हो जाती है

लगान के सम्बन्ध मार्शल के विचार रिकार्डो की भाँति ही थे

लाभ को वे जोखिम उठाने का पारितोषिक, व्यवसायिक योग्यता का पुरस्कार तथा मूल्य की स्थिति पर निर्धारित होने वाला तत्व मानते थे उनका विचार था

कि अल्पकाल में लाभ की दर मूल्य की अधिकता, साहसिकों की कमी के कारण ऊँची रहती है परन्तु दीर्घकाल में सामान्य मूल्य की प्राप्ति व साहसिकों की पूर्ति की अधिकता के कारण, लाभ की दर कम हो जाती है, वे लाभ को पूँजी-संचय का प्रमुख स्रोत मानते थे, इस कारण वे इसका अधिक होना चाहते थे

5. मार्शल विकास की प्रक्रिया को सतत तथा धीमी प्रक्रिया मानते थे

मार्शल के विचारों पर डारविन व स्पेन्सर की जीव-विज्ञान व सामाजिक क्रमिक विकास सिद्धान्तों का बहुत अधिक प्रभाव था मार्शल ने इसी कारण आर्थिक विकास प्रक्रिया को जीव-विज्ञान प्रक्रिया की भाँति देखा उन्होंने कहा

> "The Mecca of the economists lies in the economic biology rather than economic dynamics."
>
> (इसका भावार्थ है कि अर्थशास्त्री का निर्माण अर्थशास्त्र को जीव-विज्ञान की भाँति अध्ययन करने मे है न कि गति विज्ञान के रूप म अध्ययन करने मे)

उन्होंने लिखा

> "यह सर्व विदित तथ्य है कि प्रकृति स्वेच्छा से छलाग मारकर आगे नही बढती यही बात आर्थिक विकास के सम्बन्ध मे भी लागू होती है"

उन्होंने आर्थिक विकास की तुलना जगलों मे पेडों की वृद्धि से की जो धीमे होती है (इस सम्बन्ध मे आगे चलकर हम शम्पीटर के विचार पढ़ेंगे जो इन विचारों से बिल्कुल भिन्न हैं)

वैसे तो Marshall के काल मे ही बहुत से महत्वपूर्ण नव-प्रवर्तन तेजी से हो रहे थे फिर भी *उनका कथन था कि विकास धीरे-धीरे ही होता है*

उन्होंने कहा

> "यह हो सकता है कि एक नव-प्रवर्तक अथवा एक सगठनकर्ता या एक प्रतिभावान पूँजीपति एक ही बार मे पूरी अर्थ-व्यवस्था मे महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दे, फिर भी अगर हम निकट से अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि इस कार्य की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी"

6 मार्शल विकास की प्रक्रिया में कोई संघर्ष नहीं देखते थे :

मार्शल यह मानते थे कि विकास प्रक्रिया मे एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग

His Book VI P 335 onwards.
p. 6.

के विकास मे सहायक होता है उनका विश्वास था कि इस प्रकार से हर उद्योग का विकास एक दूसरे उद्योग के विकास मे पूरक व सहायक सिद्ध होता है

मार्शल ने हमको सर्वप्रथम "वाह्य मितव्ययिताओं का विचार दिया" यह वाह्य मितव्ययिताएँ वे है जो एक उद्योग के विकास से दूसरे को मिलाती है, जैसे यातायात के विकास से सभी उद्योगो को लाभ होता है उनके इस विचार से "सतुलित विकास पद्धति" के प्रवर्तको को बहुत बल मिला और आगे चलकर नर्क्स ने इन्ही तथ्यो के आधार पर सतुलित विकास-पद्धति की सिफारिश की

मार्शल का विचार था कि अगर एक बार विकास-प्रक्रिया शुरू हो गई तो वह सचयी होगी, अर्थात् देश विकास-पथ पर आगे बढता जाएगा

नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का विकास मॉडल
Neo-classical Model As a whole.

A प्रस्तावना :

सन् 1870 के पश्चात् प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विकास सम्बन्धी विचारो की प्रतिष्ठा कम हो गई. उन्होने जिन बातो को विकास मॉडल का आधार बनाया था वे सही सिद्ध नही हुई. जैसे उनको भय था कि गिरते हुए लाभ के कारण विकास रुक जाएगा और स्थिर अर्थ-व्यवस्था की दशा आ जाएगी जिसमे लगान अधिक व मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर रहेगी पर तकनीकी उन्नति ने यह सब गलत सिद्ध कर दिया मजदूरी के स्तर उत्पादकता-वृद्धि के साथ बढे, लगान प्राप्तकर्ता राष्ट्रीय आय का छोटा हिस्सा ही प्राप्त करते थे वैसे इन नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो में विकसैल (Knut Wicksell) को भी स्थिर अर्थव्यवस्था का बहुत डर था, और मार्शल भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्ति मे कमी की आशका से ब्रिटेन में ऐसी स्थिति की कल्पना करते थे, फिर भी, यह डर सामान्य रूप मे नही रह गया था

आय वितरण के सिद्धान्त, या मूल्य सिद्धान्त अथवा सामान्य साम्य के सिद्धान्त को अध्ययन करने में इन लेखकों ने समय परिधिको कम कर दिया अर्थात् इन्होने अल्पकाल मे विकास कारक तत्वो को अध्ययन किया.

B. विकास मॉडल .

1. विकास पूंजी संचय पर निर्भर :

उनके अनुसार उत्पादन मे श्रम व पूँजी का अधिक महत्व होता है. पूँजी-सचय पर ही श्रम-विभाजन व तकनीक निर्भर रहते है. तकनीक की उन्नति पर ही आर्थिक

विकास निर्भर रहता है अगर कभी पूँजी की कमी हो तो, नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अनुसार ब्याज की दर बढ जाएगी और बचतें बढ जाएँगी इस प्रकार से वे पूँजी व विनियोजन मे असाम्य की स्थिति को दूर करने के कार्य मे ब्याज को साम्य लाने वाला महत्वपूर्ण तत्व मानते थे

ल्युस के अनुसार :

> "In Neo-classical model capital can be created by withdrawing resources from consumption goods industries In this model an increase by a corresponding fall in the output of consumer goods, since scarce resources can do one or the other."
>
> (अर्थात् नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अनुसार, अगर देश मे पूँजी की कमी है तो उपभोग वस्तुओ के उत्पादन मे लगी पूँजी को कम कर के उत्पादन क्षेत्र की पूँजी बढाई जा सकती है).

2. जैसा कि हम मार्शल के मॉडल में पढ चुके हैं, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार (i) तकनीक की उन्नति (ii) श्रम विभाजन के विस्तार (iii) लाभ की वृद्धि, (जिसके लिए श्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि आवश्यक होती है) तथा (iv) उत्पादन के अर्गों को सीमान्त उत्पादकता के सिद्धान्त के अनुसार कार्य पर लगाकर, (v) राष्ट्रीय आय बढाने से विकास होता है

   इन अर्थशास्त्रियों ने जनसख्या वृद्धि को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की तरह भय से नही देखा

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास आर्थिक विकास में सहायक :

नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति यह विश्वास था कि अगर 'तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त' के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार किया गया तो इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की वास्तविक आय बढती है वे भी यह मानते थे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास से नए बाजार खुलते है. इन बाजारों के खुल जाने

Lewis : Capital Formation with Unlimited Labour A. N Agrawal and S P. Singh. op cit. p 421.

से देश को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं, तथा इसके कारण देश मे बचत व पूंजी निर्माण मे वृद्धि होती हैं

परन्तु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की भाँति वे मुक्त या स्वतन्त्र व्यापार के कट्टर समर्थक नही थे वे चाहते थे कि या तो देश को अपनी "भुगतान की शर्तों" को सुधारना चाहिए (अपनी वस्तुओ के दामो को बढाना व आयात की वस्तुओ का भाव कम करना) या फिर आयात व निर्यात पर कर लगाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए

वे सरक्षण को भी उचित अवस्थाओ मे प्रदान करने की सिफारिश करते थे लेकिन आम तौर पर वे स्वतन्त्र व्यापार को ही अच्छा मानते थे इन विचारो को हम दो नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के निम्नलिखित उद्धरणो से आँक सकते हैं

एजवर्थ का कथन था :

> **'संरक्षण की नीति से आर्थिक लाभ व विकास बढ सकता है बशर्ते कि राज्य इतना विवेकी हो कि वह उन उद्योगो का सही चयन कर सके जिनको सरक्षण देना चाहिए तथा फिर वह अपने इस चयन पर कायम रहे.''**

निकलसन का कथन था

> **"स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, ईमानदारी की नीति की भाँति, सर्वोत्तम नीति होती है."**

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री देश के विकास मे विदेशी पूँजी के योगदान को भी महत्वपूर्ण मानते थे उन्होने उधार लेने व कर्ज लेने के दृष्टिकोण से विकास काल को पाँच कालो मे विभाजित किया

(1) प्रथम काल इस काल मे एक देश विदेश से पूँजी का शुद्ध आयातकर्ता होता है इस काल मे देश के वस्तु व सेवाओ के आयात, निर्यात से (हम ब्याज व लाभाश देनदारियो को छोड भी दे) अधिक रहते हैं.

(II) द्वितीय काल इस काल मे फिर देश की उन्नति इतनी हो जाती है कि उसके वस्तु व सेवाओ के निर्यात, आयात से अधिक होते हैं पर अगर पूँजी पर दिए जाने वाले ब्याज व लाभाश को मिला दें तो विदेशी व्यापार का आधिक्य नही रहता (There is surplus of current exports over imports).

(111) तृतीय काल जब एक देश म विकास और आगे बढ़ता है तो वह देश पूँजी निर्यात करने की स्थिति म आ जाता है इस स्थिति म आयात में निर्यात अधिक रहते है, चाहे हम व्याज व लाभाश को भी शामिल कर ले चालू व्यापार खाते म इस प्रकार से देश आधिक्य प्राप्त करता है

निर्यात = अधिक होन है = आयात + लाभाश व व्याज भुगतान से परन्तु इस काल म यह देश जितना विदेशी पूँजी पर व्याज व लाभाश देता है उसकी तुलना म उसको अपनी पूँजी (जो विदेशो में भेजी है) पर प्राप्त होने वाला व्याज व लाभ अधिक होता है इस प्रकार से कुल मिलाकर देश शुद्ध कर्जदार ही रहता है

(ıv) चतुर्थ काल जब देश और आगे विकास करता है और चौथी अवस्था मे पहुँचता है ता विदेशो से निर्यात आय व व्याज व लाभाश प्राप्ति देश से जाने वाले धन से (आयात मूल्य व व्याज व लाभाश देनदारिया) अधिक रहती है. इस अवस्था मे देश Young creditor वन जाता है

(v) पञ्चम काल इस काल म देश के विकास की परिपक्व अवस्था आती है और जितना धन जाता है उससे कही अधिक आता है अर्थात् निर्यात आयात से अधिक व व्याज व लाभाश प्राप्ति इन्ही देनदारियो से बहुत अधिक होती है इस प्रकार से देश एक Mature creditor वन जाता है

4. विकास प्रक्रिया समन्वित व संचयी होती है

(a) **सचयी** —इस सम्बन्ध म हम मार्शल के विचार पढ चुके है लगभग समस्त नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की विचारधारा भी मार्शल जैसी थी.

एक अन्य नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, जे एस. निकलसन का कथन था

> "इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आविष्कारो से आते है, उन्हे धीरे-धीरे ही कार्यान्वित किया जाता है. आविष्कारो में अविरल छलाँग से अधिक धीमे-धीमे होने की प्रवृत्ति होती है."[1]

इन अर्थशास्त्रियो के अनुसार, विकास से समस्त वर्गो को लाभ होता है. मार्क्स की भाँति वे वर्ग-सघर्ष की सम्भावना को नही देखते थे. उनको बेरोजगारी का भय

1. The Effects of Machinery on Wages, 1892 P. 33.

नही था. उन्होंने माना था कि आर्थिक प्रणाली मे पूर्ण रोजगार उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता होती है. केवल अल्पकाल मे बेरोजगारी हो सकती है पर दीर्घ काल में ऐसा नही होगा

सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो कि इन अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की विचारधारा मे किया वह यह था कि ये अर्थशास्त्री यह नही मानते थे कि मजदूरी बढ़ने से लाभ कम हो जायेगा. इसका कारण यह था कि "इगलैंड मे 1850 के बाद जब फैक्ट्री एक्ट लागू किये गए जिनके अन्तर्गत मजदूरी बढाई व कार्य के घटे घटाए गए" तो सब अर्थशास्त्रियो ने आश्चर्य मे देखा कि इससे उत्पादकता व लाभ बढे, और तब से "अधिक मजदूरी, सस्ती मजदूरी" सिद्धान्त सर्वमान्य बन गया इस प्रकार से इन्होंने अर्थशास्त्र से यह एक महान निराशावादी व त्रुटिपूर्ण विचार-धारा को हटा दिया.

(b) समन्वित :—मार्शल के विचार हम पढ ही चुके हैं. उन्हीं की भाँति एलिन यंग (Allyn Young) ने भी विकास के सचंयी व समन्वित होने पर बल दिया. उन्होंने कहा .

> "विकास, श्रम-विभाजन पर निर्भर करता है, श्रम-विभाजन बाजार के विस्तार पर निर्भर होता है, बाजार का विस्तार स्वय श्रम विभाजन पर निर्भर होता है. श्रम-विभाजन मे विशिष्टीकरण उत्पन्न होता है और लागत कम होती है. इससे साधनो का भौगोलिक व व्यवसायिक वितरण (Allocation) उन्नत होता है और माँग बढती है. इस प्रकार से एक क्षेत्र व उद्योग का विकास एक दूसरे के विकास का कारण व परिणाम हो जाते है "[1]

C. नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के विकास सम्बन्धी विचारो की समीक्षा

गुण :

(i) वे आशावादी थे .

1 हम मार्शल के आशावादी विचारों को पढ ही चुके है. संक्षेप में यह विचार इस प्रकार थे .

(a) जनसंख्या की वृद्धि हमेशा उस गति से नही बढती जिस दर से माल्थस ने बताया था

1. O. S. Shrivastava, "Economics of Wages, Productivity and Employment", Kailash Pustak Sadan, Gwalior, P. 74, 1968.

(b) तकनीकी उन्नति से न केवल उद्योगों में बल्कि कृषि में भी उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार उत्पादन हो सकता है.

(c) मजदूरी बढ़ने से लाभ कम नहीं होते और लाभ को अधिक रखने के लिए मजदूरी कम रखना उचित व आवश्यक नहीं है

(d) उनका विश्वास था कि स्थिर (पर उन्नत) तकनीक होते हुए भी मजदूरी अधिक रह सकती है, बशर्ते कि पूँजी-निर्माण अधिक हो और पूँजी-निर्माण को बढ़ाने के लिए उनका विश्वास था कि यह कभी भी ब्याज की दर को बढ़ाकर किया जा सकता है.

2 उन्होंने सर्वप्रथम बाह्य मितव्ययिताओं के महत्व को समझाया तथा सतुलित विकास की विचारधारा की नीव रखी.

कमियाँ

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों में कुछ कमियाँ भी थी जो इस प्रकार से रही

(a) इन्होंने यह गलत मान्यता मानी थी कि इनके पूर्ण प्रतियोगिता वाली अर्थ-व्यवस्था में बेरोजगारी नहीं रहेगी—यह बात केन्स ने अपने मॉडल में गलत सिद्ध की

(b) इन अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता भी ठीक नहीं थी कि केवल ब्याज की दर में आवश्यक परिवर्तन कर के पूँजी की माँग व पूर्ति या विनियोजन व बचत में साम्य लाया जा सकता है

(c) इनके विकास के सचयी व समन्वयी होने के विचार भी सत्य नहीं है. विकास में वर्ग संघर्ष की सम्भावना को न मानना "आँख बन्द करके" बात करना है.

स्पीटर—केन्स के मॉडल में और आलोचनाएँ देखिए.

अध्याय : 12

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास मॉडल

The Neo-classical Model of Economic Growth

(मुख्य रूप से J. E Meade का)

1. प्रस्तावना
2. श्री मीड की मान्यताएँ
3. मॉडल
   - (a) विकास का प्रथम सूत्र व समीकरण
   - (b) ,, ,, दूसरे रूप में समीकरण.
   - (c) ,, ,, तीसरे रूप में समीकरण.
   - (d) विकास दर में परिवर्तन.
   - (e) स्थायी विकास पथ
   - (f) स्थायी विकास पथ से अलग दरें.
   - (g) वास्तविक विकास की दर.
4. आलोचना

अध्याय : 12

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विकास मॉडल

The-Neo classical Model of Economic Growth

1 प्रस्तावना

नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री वे हैं जिन्होंने Micro-Statics (सूक्ष्म स्थैतिक) दृष्टि-कोण अपनाया जेवन्स मेन्जर एजवर्थ, मार्शल क्लार्क, वालरा, (Walras) परेटो, विक्सटीड फिशर, पीगू तथा विकसैल उनमें मुख्य हैं. इसी काल के वे अर्थशास्त्री जिन्होंने Micro analysis किया अथवा जो Institutionalists थे, वे नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों म नही लिए गए हैं.

इन नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जटिल सूक्ष्म-स्थैतिक मॉडल जो निगमन नीति पर आधारित था, प्रस्तुत किया (They produced a complex and deductive micro Static model). उन्होंने उन घटकों व तत्वों का जो विकास करते हैं बडा ही सुलझा हुआ विश्लेषण किया. उन्होंने अपने मॉडल में सामाजिक राजनैतिक तत्वों का भी समावेश किया

उन्होंने गणित की तकनीक का प्रयोग करके Theorems प्रस्तुत की. उन्होंने बहुत सी नई Theorems प्रस्तुत की जो नई मान्यताओं व विश्वासों पर आधारित थी उन्होंने तर्क तथा खोज का समन्वय किया. उनके मॉडल की मुख्य बातें यह थी

(1) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार "अधिक उपयोगिता" को प्राप्त करना या उत्पन्न करना विकास है Achievement of greater utility without distortion (paretian optionality of Marginal utility = Marginal cost) be interpreted as growth.

(1) See · The Neo-classical Theory of Economic Growth J E. Meade.

(2) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अनुसार राष्ट्रीय आय मे वृद्धि ही विकास व कल्याण वृद्धि की निशानी है.

(3) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अनुसार अगर देश मे उचित सामाजिक राजनैतिक वातावरण मौजूद हो तो विकास हो सकता है उनका विचार था कि पूर्ण-प्रतियोगिता से ही विकास सम्भव है. नव-प्रतिष्ठित मॉडल "पूर्ण-प्रतियोगिता मॉडल" है उनका विश्वास था कि एकाधिकारी व्यवस्था से Paretian optionality की स्थिति (सीमान्त आयोगिता = सीमान्त लागत) को नही पहुँच सकते.

(4) नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मॉडल म तकनीक मे परिवर्तन, रुचि, फैशन व उपभोग परिवर्तन, राज्य व सस्थाओ की नीति मे परिवर्तन को ध्यान मे नही रखा परन्तु जनसख्या सम्बन्धी परिवर्तनो को ध्यान मे रखा.

(5) नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री सन्तुलित विकास के पक्ष म थे उन्होने बडी मात्रा में विनियोजन करने पर जोर दिया (They emphasized the importance of indivisibilities or lumpy growth, through external economy and public works)

(6) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का विश्वास था कि जब तक जनसख्या अनुकूलतम स्तर तक नही पहुँच जाती तब तक विकास होता रहेगा. परन्तु तकनीकी उन्नति से स्वय अनुकूलतम जनसख्या स्तर बढ जाएगा परन्तु अन्त मे, उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण (जिसका मुख्य कारण साधनो का ह्रास होगा) विकास रुक जाएगा. जनसख्या के सम्बन्ध मे कुछ अर्थशास्त्री तो, माल्थस की भाँति, जनसख्या की अप्रत्याशित वृद्धि के प्रति आशकित थे जबकि कुछ अन्य अर्थशास्त्रियो का विश्वास था कि नागरीकरण से जन्म दर मे कमी आ जाएगी. वे शिक्षा को जन्म दर घटाने व विकास वृद्धि में सहायता करने का मुख्य साधन मानते थे.

---

(2) "The Neo-classical Contribution to the Theories of Economic Growth." John Buttrick from "Theories of Economic Growth" Ed by Bert E Hoselitt A Free Prcs, Paperback Macmillan Company, 1965

Prof. J E Meade's Model ·

केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो जे ई. मीड ने नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मॉडल की सरचना की है. यह मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित हैं :

(i) देश मे अर्थ व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतियोगिता वाली अर्थ-व्यवस्था है. देश की इस अर्थ-व्यवस्था मे राज्य के नियन्त्रण नही हैं.

(ii) देश में उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू नही हो रहा है.

(iii) देश में पूर्ण रोजगार का साम्य मौजूद है.

(iv) देश मे मूल्य स्थिर है.

(v) मॉडल मे केवल दो प्रकार की वस्तुओं की कल्पना की गई है और यह माना है कि उत्पादन मे पूर्ण प्रतिस्थापन सभव है.

(vi) देश मे श्रम की भिन्न-भिन्न ईकाइयाँ या मशीनो की ईकाइयो की उत्पादकता क्षमता एक सी मानी गई है और उन्हे एक दूसरे का पूर्ण रूप से पूरक माना है

The Model

(a) Growth means more national income and is expressed by production function. विकास का अर्थ अधिक राष्ट्रीय आय का सृजन है और इसे हम "उत्पादन सूत्र" से दर्शाते हैं :

$Y = F' (K\ L.\ N\ T.)$

Y = राष्ट्रीय आय

F' = (Function of) या परिणाम स्वरूप

K = पूँजी (Capital)

L = श्रम (Labour)

N = प्राकृतिक साधन (Natural resources)

T = Time or Technical progress. समय या तकनीकी उन्नति.

(b) देश के प्राकृतिक साधन तो स्थिर होते हैं. इसलिए विकास K. L. T में परिवर्तन को परिणामस्वरूप होता है. इस सम्बन्ध को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं. :

$$\triangle Y = V \triangle K + W \triangle L + \triangle Y'$$

(i) △ डेल्टा का अर्थ परिवर्तन से है $\triangle Y$ का अर्थ है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन.

(ii) V का अर्थ पूजी की सीमान्त उत्पादकता से है
$V\triangle K$ का अर्थ हुआ पूजी की सामान्त उत्पादकता × पूंजी की मात्रा में परिवर्तन

(iii) W का अर्थ है श्रम की सीमान्त उत्पादकता $W\triangle L$ का अर्थ हुआ श्रम की मात्रा में परिवर्तन या वृद्धि × श्रम की सीमान्त उत्पादकता.

(iv) $\triangle Y'$ का अर्थ तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन मे परिवर्तन से है. इस प्रकार मे किसी वर्ष म शुद्ध उत्पादन मे परिवर्तन ($\triangle Y$), पूजी के स्टाक मे वृद्धि × पूजी की सीमान्त उत्पादकता + श्रम की सख्या म वृद्धि × श्रम की सीमान्त उत्पादकता + तकनीकी उन्नति के कारण उत्पादन म वृद्धि के बराबर होता है

(c) अब उत्पत्ति की वार्षिक अनुपातिक विकास दर को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है :

$$\frac{\triangle Y}{Y} = \frac{VK}{Y} \cdot \frac{\triangle K}{K} + \frac{WL}{Y} \cdot \frac{\triangle L}{L} + \frac{\triangle Y'}{Y}$$

(i) $\frac{\triangle Y}{Y}$ का अर्थ उत्पादन मे अनुपातिक विकास दर से है जिसे अब Y से लिखेगे

(ii) $\frac{\triangle K}{K}$,, पूजी ,, ,, ,, ,, ,, ,, K ,,

(iii) $\frac{\triangle L}{L}$,, श्रम ,, ,, ,, ,, ,, ,, L ,,

(iv) $\frac{\triangle Y'}{Y}$,, एक वर्ष में तकनीकी परिवर्तन से है ,, R ,,

(v) $\frac{VK}{Y}$ का अर्थ Y के अनुपात के रूप मे पूंजी की सीमान्त उत्पत्ति से है.
और इसे हम U से प्रस्तुत करेंगे.

(vi) $\frac{WL}{Y}$ का अर्थ Y के अनुपात में श्रम की सीमान्त उत्पादकता मे परिवर्तन से है. इसे हम Q लिखेंगे.

(d) Factors on which charges in growth rate depends
अगर देश में जनसख्या स्थिर है ($L=O$) तो विकास की दर इस प्रकार होगी :

$$Y = VS + R$$

अर्थात् विकास की दर बचत, पूजी की सीमान्त उत्पादकता तकनीकी उन्नति पर निर्भर होगी और साम्य की स्थिति मे Y = बचतें × पूजी की सीमान्त उत्पादकता + तकनीकी उन्नति.

अगर जनसख्या के स्थिरता के साथ तकनीकी उन्नति भी स्थिर हो तो विकास की दर VS में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होगी.

(e) Conditions of Steady Economic Growth. स्थायी विकास की आवश्यक स्थितियाँ.

नव-प्रतिष्ठित मॉडल में स्थायी विकास का आशय है कि राष्ट्रीय आय (Y), बचत (S), जनसख्या (L), तकनीकी उन्नति (R), मजदूरी (Q), लाभ (U), लगान (Z) मे होने वाली परिवर्तन दरें स्थिर है.

हम यह देख चुके है कि $Y = UK + QL + R$ के बराबर है. इनमें से U, Q तथा L व R को हम स्थिर मान चुके हैं इस प्रकार से अगर K भी स्थिर दर से बढे तो स्थायी दर से विकास होगा.

The growth rate of income will be constant if the growth rate of capital stock (K) is equal to the growth rate of national income (Y).

(f) Critical Growth Rates

इसका अर्थ यह होता है कि वास्तविक विकास दर या तो 'स्थायी विकास दर' से अधिक है या वह इससे कम है इस स्थिति में Y और K बराबर नही होते J. E. Meade का विश्वास था कि Critical growth rates मे यह दीर्घकालीन प्रवृत्ति होती है कि वे स्थायी विकास की दर के बराबर हो जाएँ. अब हम इस सूत्र को $Y = U.\,K + QL + R$ के रूप में भी लिख सकते हैं. इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय में विकास की दर तीन अन्य दरो का भार-युक्त जोड है. ये तीन दरें है

(i) पूजी स्टाक मे वृद्धि (K) जिसमें सीमान्त उत्पादकता का भार हो (U)

+ (ii) श्रम की वृद्धि दर (L) जिसमें सीमान्त उत्पादकता का भार हो (Q)

+ (iii) तकनीक में विकास दर (R)

(g) Real growth rate depends on the growth of real Income.

नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मॉडल में विकास वास्तविक पूँजी मे (K) वृद्धि का परिणाम होती है. विकास श्रम की उत्पादकता (Q) पूजी की उत्पादकता (U) तथा तकनीकी उन्नति में वृद्धि (R) भी प्रभाव डालते हैं यह विकास दर (L) या जनसख्या में वृद्धि दर से घटती है

इस प्रकार से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि दर को हम निम्नलिखित सूत्र से प्रस्तुत कर सकते हैं :

$$Y-L=UK-(L-Q)\,L+R$$

उपरोक्त समीकरण में जनसख्या के depressant effect या विकास को गिराने के प्रभाव को अध्ययन किया गया है इस सूत्र में—(L—Q) L से हम उत्पत्ति में ह्रास नियम की प्रवृत्ति को दर्शाते है [1]

अगर हम Critical growth rate के लिए (a) का प्रयोग करें तो समीकरण इस प्रकार होगा

$$A=UA+QL+R$$

$$\text{or}\quad A=\frac{QL+R}{L-U}$$

---

(1) इसी समीकरण को हम निम्नरूप में भी लिख सकते है .

$$Y-L=VS-(L-Q)\,L+R$$

यहाँ UK के स्थान पर VS रख दिया गया है क्योंकि U का अर्थ $\frac{VK}{Y}$ तथा K का अर्थ $\frac{\triangle K}{K}$ होता है.

$UK=\frac{VK}{Y}\times\frac{\triangle K}{K}$. हम यह भी जानते है कि $\frac{\triangle K}{K}$ वास्तव मे SY या आय का वह भाग जो बचत हुआ है, होता है

इसलिए $UK=\frac{VK}{Y}\times\frac{SY}{K}$ or Y से Y तथा K से K काटने के बाद UK=VS

अगर स्थायी विकास दर में कुछ परिवर्तन होता है तो स्वय ही वह पुन. उस स्तर पर आ जाएगी पूँजी-स्टाक की विकास दर भी साम्य के स्तर पर आएगी, अर्थात् $\frac{QL+R}{L-U}$ स्तर पर आएगी

अगर, हम मानते है, KOR $\frac{SY}{K} > \frac{QL+R}{L-U}$ तो निम्न प्रतिक्रिया होगी इस स्थिति म आय, पूँजी स्टाक वृद्धि से कम दर से बढेगी इससे बचतें कम होगी और इससे पूँजी स्टाक में भी कमी आ जाएगी इसके परिणामस्वरूप $\frac{SY}{K}$ फिर Critical level तक आ जाएगी

अगर इसका उल्टा होता है अर्थात् अगर $\frac{SY}{K} < \frac{QL+R}{L-U}$, तो आय, पूंजी स्टाक से अधिक दर से बढेगी बचतें बढ जाएगी इससे $\frac{SY}{K}$ भी Critical level $\frac{QL+R}{L-U}$ तक बढ जाएगी

इस प्रकार राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की दर तथा पूँजी-स्टाक मे वृद्धि दर दोनो $\frac{QL+R}{L-U}$ के बराबर हो जाएगे.

Critical Appraisal

श्री जॉन बटरिक. (John Buttrick) ने नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मॉडल की बहुत आलोचनात्मक समीक्षा की है जिसमें मुख्य ये हैं :

(i) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने उनके काल के बाद के अर्थशास्त्रिया को बहुत गुमराह किया. उन्होने बहुधा अर्थहीन समीकरण प्रस्तुत किए.

(ii) उन्होने साम्य को लाने वाले मॉडलों की रचना की. ये मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित मॉडल थे जिनमे यह गलत मान्यता थी कि समस्त उत्पादन इकाइयाँ स्वतत्र होनी है

(iii) नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की यह मान्यता भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है कि उत्पादन मे केवल उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा और उत्पत्ति वृद्धि के नियम की मान्यता की सभावना को ही निकाल दिया

उन्होंने अपने मॉडल मे "अनिश्चितता" को कोई स्थान नही दिया उनकी भविष्य वाणियाँ तिथि से सम्बन्धित नही थी उनके मॉडल मे समस्त सहसम्बन्धो को सुनिश्चित मान लिया था और यह कोई अच्छी बात नही थी वरन् एक कमजोरी थी [1]

नव प्रतिष्ठित मॉडल व्यवहारिक नही थे वे तथ्यो व वास्तविकता से दूर थे उनको समझने के लिए बहुत मेहनत चाहिए समाजशास्त्र के विषयो के लिए, उनके द्वारा प्रयोग मे लाए गए गणित के समीकरण जटिल थे उन्होंने ऐसे समीकरण प्रस्तुत किए जिन्हे बहुत से अर्थशास्त्री समझ ही नही पाए और इस कारण आलोचना ही नही कर पाए.

उन्होंने जिन मान्यताओ पर मॉडल बनाया वे न केवल सही ही नही थी वरन् वे बडो लम्बी-लम्बी मान्यताएँ थी.

उन्होंने अपने मॉडल मे से बहुत से तत्वो को बाहर निकाल फेका—जैसे उन्होंने राज्य की नीति को ध्यान म नही रखा उनका मॉडल तो Robinson Crusoe मॉडल रहा. और जब कभी उनके मॉडल के अनुरूप विकास नही होता था तो उसका दोष वे किसी और को मढ देते थे

1. A model in the social sciences in which no stochastics are present ie one in which relationships among variables are presumed to be exact and in which the variables themselves can be measured, is a model constructed for heuristic rather than practical purposes,

अध्याय • 13

जोसेफ एलोइस शम्पीटर का विकास मॉडल

Joseph Alois Schumpeter on Development

A प्रस्तावना

B विकास मॉडल

1 'आर्थिक वृद्धि' व आर्थिक विकास' में अन्तर

2 उत्पादन भूमि, श्रम, पूजी तकनीक, सगठन व साहसी के कार्य स्वरूप होता है पर विकास 'साहसी' का कार्य है

3 विकास, स्वेच्छिक विनियोजन व प्रोत्साहित विनियोजन के परिणाम स्वरूप होता है साहसियो के नवीन प्रवर्तन से ही विकास उत्पन्न होता है

4 पूँजी सचय व वृद्धि विकास कारक अधिक पूँजी अधिक विकास

5 पूजी को उपलब्धि के लिए मुद्रा बाजार विकसित होना चाहिये

6 विकास 'साख' या बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली पूँजी पर ही निर्भर है

7. साहसी लाभ के प्रलोभन में नवीन प्रवर्तन करते हैं. लाभ की मात्रा व आशा ही विकास बढाने वाली क्रियाओं को जन्म देती है लाभ का महत्व

8 आर्थिक विकास Swarm-like movements के (झुण्ड या समूह रूप में) या spurts में (बडे प्रयत्न के कारण) होता है तथा नवीन प्रवनन इकट्ठे के इकट्ठे (पिण्डीभूत रूप में) होते हैं (innovation occurs in clusters तेजी मन्दी का चक्र ही विकास की ओर ल जाता है

9 पूंजीवादी विकास व्यवस्था का भविष्य

C शम्पीटर के मॉडल की समीक्षा

1 बन्जामिन हिग्गिन्स, 2 ऑस्कर लेन्ज, 3 रिचर्ड बी क्लीमेन्स तथा फ्रान्सिस एस डूडी, 4 मियर तथा बाल्डविन, 5 हेनरी सो वेलिच, 6 हेबरलर

अध्याय : 13

जोसेफ एलोइस शम्पीटर का विकास मॉडल

Joseph Alois Schumpeter on Development.

A प्रस्तावना

शम्पीटर ऑस्ट्रिया के मोराविया प्रान्त (जो आज कल जेकोस्लोवकिया मे है) पैदा हुए थे. उन्होने रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी कोलम्बिया व अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालयो मे पढाया उनके विकास के सिद्धान्तो को हम तीन पुस्तको से लेते है

(i) The Theory of Economic Development (1912)

(ii) Business Cycles (2 volumes, 1939)

(iii) Capitalism, Socialism and Democracy

बेन्जामिन हिगिन्स के अनुसार शम्पीटर बीसवी सदी म विकास मॉडल देने वाले प्रथम अर्थशास्त्री थे

B विकास मॉडल

(i) Meaning of Economic growth' and 'Economic development' **शम्पीटर के अनुसार 'आर्थिक वृद्धि' व 'आर्थिक विकास' में अन्तर**

शम्पीटर के अनुसार दो प्रकार की अर्थ व्यवस्थाएँ होती है एक स्थिर अर्थव्यवस्था (Static economy or circular flow) जिसमे हर आर्थिक अग स्थिर रहता है, अर्थात जनसख्या में जितने व्यक्ति मरते है बस उतने ही पैदा होते है, या माँग, पूर्ति, रोज़गार, विनियोजन, उत्पादन के अगो का पारितोषिक आदि स्थिर रहते है ऐसी अर्थ-व्यवस्था हमेशा 'साम्य' की स्थिति म रहती है हर बेचने वाला अपना खरीदार पा लेता है, और एक वर्ष की आर्थिक गतिविधियाँ दूसरे वर्ष म भी होती है

"स्थिर व्यवस्था को (in circular flow) हम जीवात्माओ की

शरीर रचना से तुलना कर सकते है जिनमे खून निरन्तर एक ही रास्ते से एक ही रफ्तार से बहता रहता है "

ऐसी अवस्था मे जो भी परिवर्तन होते है वे धीरे-धीरे होते है और इनसे विकास नही उत्पन्न होता है यह 'क्रमिक उन्नति" evolutionary change विकास नही है केवल 'क्रान्तिकारी परिवर्तनो' से ही विकास का जन्म होता है उनके अनुसार :

> "क्रमिक परिवर्तनो से, कालान्तर मे, यथाकाल व्यवस्था से, एक छोटी फुटकर बिक्री की दुकान एक बड़े डिपार्टमेन्टल स्टोर में परिणत हो सकती है, पर यह तो स्थिर अर्थ-व्यवस्था की ही बात रहेगी केवल क्रान्तिकारी (revolutionary) तथा अविरल (discontinuous) परिवर्तनों से ही विकास होता है और यही हमारे अध्ययन का विषय है "[1]

Schumpeter ने growth व development के बीच अन्तर निकाला उनके अनुसार growth मे हमारा अभिप्राय देश की अर्थ-व्यवस्था में सख्यात्मक वृद्धि से है, जैसे देश मे जनसख्या वृद्धि के कारण अधिक मांग व उत्पादन का बढ जाना Development का अर्थ देश की अर्थ-व्यवस्था में गुणात्मक उन्नति से है उन्होंने लिखा

> 'By development, we shall understand only such changes in economic life as are not forced upon it from without but arise by its own initiative, from within."[2]

---

(1) Theory of Economic Development : by Joseph Schumpeter. translated by Dr. Revers Opie from German : Oxford University Press, 1961 New York p. p 64, 7, 8, 63 & 62.

(2) "Nor will the mere growth of the economy, as shown by the growth of population and wealth be designated as a process of development. For it calls forth no qualitatively new phenomenon but only possesses of adaptation of the same kind as the changes in the natural data . It Is . occurrence of the 'revolutionary' changes that is our problem. p. 62-63-64

देश मे जब Data मे परिवर्तन होते हैं अर्थात् जनसख्या बढ जाती है या धीरे धीरे मांग बढती है तो अर्थ-व्यवस्था भी धीरे-धीरे बढती है इससे अर्थशास्त्रियो को कोई मतलब नही होता गुणात्मक परिवर्तनो से ही हमको मतलब होता है और वही विकास है.

ऐसी ही स्थिर परिस्थितियो से क्रान्तिकारी परिवर्तन आता है और अर्थशास्त्रियो का इसी प्रकार के विकास से सम्बन्ध होता है

2. उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक, संगठन व साहसी के कार्य स्वरूप होता है, पर 'विकास' साहसी का कार्य है.[1]

शम्पीटर से पहले जे. बी से, मटाजा, वालरा, व मार्शल ने साहसी के महत्व को बताया पर उतना नही जितना कि शम्पीटर ने स्थिर अर्थ-व्यवस्था मे साहसी अपनी पूंजी प्रदान करने वाला, व्यवस्थापक, तकनीकी विशेषज्ञ, व खरीदने बेचने वाला होता है उस व्यवस्था मे उसे सब चीजें निश्चित मिलती हैं पर गतिशील व्यवस्था मे उसका कार्य महत्वपूर्ण होता है उसे New combinations of production (उत्पादन के नए समर्ग) जुटाने पढते है.

> "स्थिर अर्थ-व्यवस्था मे साहसी बहाव के साथ तैरता है, गतिशील व्यवस्था मे उसे बहाव के विपरीत तैरना पडता है"

गतिशील अर्थ-व्यवस्था मे साहसी को पुरानी व्यवस्था तोड कर नई व्यवस्था पैदा करना पडता है साहसी की स्थिति अर्थव्यवस्था मे वही होती है जो कि युद्ध मे युद्ध के 'कमान्डर' की होती है. ये साहसी हमेशा धनी वर्ग से ही नही आते, यह गरीब वर्ग से भी आते है

> "यह साहसी सबसे विवेकपूर्ण, आत्माभिमानी होता है. उसमे जूझने की प्रवृत्ति होती है, वह जीतने का सकल्प रखता है, और उसमे अपने आप को दूसरो से उत्तम साबित करने की इच्छा रहती है वह केवल लाभ के लिए ही कार्य नही करता वरन् "सफलता" प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य होता है."

3. विकास, स्वेच्छित (Autonomous) विनियोजन व प्रोत्साहित (Induced) *विनियोजन के परिणामस्वरूप होता है. साहसियों के नवीन* प्रवर्तन (Innovations) से ही विकास उत्पन्न होता है.[2]

शम्पीटर के अनुसार साहसियो के नवीन प्रवर्तन कार्यस्वरूप जो स्वेच्छित

(1) साहसी के सम्बन्ध मे देखिए उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 79 से 94 के बीच.
(2) Innovations के लिए देखिए उपरोक्त पुस्तक के पेज 66 व 156.

विनियोजन होता है, उससे तकनीकी उन्नति होती है और साधनो का और अधिक अच्छा प्रयोग होता है शम्पीटर के अनुसार यह नवीन प्रवर्तन पाँच प्रकार के हो सकते है

(i) बाजार मे नई वस्तु लाना,
(ii) नई उत्पादन पद्धति को जन्म देना जिससे अधिक व अच्छा सामान कम लागत मे बने,
(iii) नए बाजार की खोज करना या उत्पन्न करना,
(iv) कच्चे माल का नया स्रोत खोजना,
(v) व्यवस्था का इस प्रकार से सगठन करना कि साहसी अपने क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर सके

इन नवीन प्रवर्तनो के कारण जो विनियोजन होता है वह Autonomous विनियोजन हुआ. अन्य उत्पादनकर्ताओं को भी इनके अनुसार अपने पुराने उत्पादन तरीकों को बदलना पड़ता है और उन्हे भी इन नवीनताओ को अपनाने के लिए जो विनियोजन करना पड़ता है वह induced investment कहलाता है और इन दोनो के परिणामस्वरूप विकास होता है.

4 पूंजी सचय व वृद्धि विकास कारक . अधिक पूँजी अधिक विकास[1]

विकास, शम्पीटर के अनुसार, तब ही सम्भव होता है जब कि देश मे पूंजी पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होती है और इन्ही से साहसी नवीन प्रवर्तनो को बाजार में लाता है. पूंजी वह उत्तोलन दण्ड है जिससे साहसी अपनी आवश्यक वस्तुओं पर नियन्त्रण पाता है (Capital is nothing but the lever by which entrepreneur subjects to his control the concrete goods which he needs) शम्पीटर के अनुसार "पूँजी के बगैर विकास नही होता, विकास के बगैर पूंजी निर्माण नही होता"

5. पूंजी की उपलब्धि के लिए मुद्रा बाजार विकसित होना चाहिए.[2]

शम्पीटर मुद्रा बाजार को पूँजीवाद का "मुख्यालय" (Headquarter of Capitalist System) कहते है इसी बाजार से साहसी पूँजी प्राप्त करते है. विकास इसी पूँजी बाजार या मुद्रा बाजार पर निर्भर करता है और विकास के साथ साथ इस बाजार का भी विकास होता है, और बाद में तो यह बाजार समस्त आय का स्रोत बन जाता है

(1) पूँजी सम्बन्धी विचारो को शम्पीटर की पुस्तक के पृष्ठ 116-122
(2) मुद्रा बाजार पर शम्पीटर की पुस्तक के पृष्ठ 124 127.

6 विकास 'साख' या बैंकों द्वारा उधार दी जाने वाली पूँजी पर ही निर्भर है.[1]

जहाँ कि परपरागत अर्थशास्त्री यह मानते थे कि पूँजीनिर्माण देश मे बचतों की मात्रा पर आधारित हैं, शम्पीटर का कथन था कि यह पूँजी बैको से उधार मिल सकती हैं बचते भी महत्वपूर्ण है, पर 'साख' उससे अधिक महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा :

> "हम यह नही कहते कि सिक्के, नोट या बैंक जमा से ही विकास आ सकता हैं, और जानते हैं कि श्रम, कच्चे माल व मशीनो से ही उत्पादन होता है, पर यह चीजे तो साख से प्राप्त होती हैं."

शम्पीटर के मॉडल मे बैंकर ही सबसे बडा पूँजीपति है. बैंकर ही धन प्रदान करता है जिससे नवीन प्रवर्तन का लाना सम्भव होता है. (A banker is essentially a phenomenon of development······He is the ephor of the exchange economy.) साख से देश मे नई पूँजी व नई क्रयशक्ति का उदय होता है. यह गतिशील अर्थ-व्यवस्था को गतिशील रखने का प्रमुख साधन है.

शम्पीटर का कथन है कि साहसी वास्तव मे जोखिम नही उठाता. जोखिम उठाने वाला तो बैंकर होता है.

> "अगर एक नवीन उद्यम असफल होता है तो बैंकर, जिसने धन उधार दिया था, सकटग्रस्त होता है, साहसी की तो इज्जत सकट में आती है"

शम्पीटर का साहसी **'ऋणों को पीठ पर लाद कर सफलता की ओर बढ़ता है'** पूँजीवादी व्यवस्था मे विकास इसी साख पर निर्भर है. धीरे-धीरे 'साख' समस्त विनियोजनो के लिए पूँजी का साधन हो जाती है, और फिर वे लोग भी, जो हमेशा यह अभिमान करते थे कि वे उधार नही लेते, साख लेकर विकास कार्यो मे लग जाते हैं

7. साहसी लाभ के प्रलोभन में नवीन प्रवर्तन करते हैं. लाभ की मात्रा व आशा ही विकास बढ़ाने वाली क्रियाओं को जन्म देती है.[2]

लाभ का महत्व :

शम्पीटर के अनुसार स्थिर अर्थ-व्यवस्था मे लाभ नही होते. इस व्यवस्था मे तो

---

(1) साख पर देखिए पृष्ठ 71, 73, 101 107 तथा 137

(2) लाभ के सम्बन्ध मे देखिए पृष्ठ 129, 153-154.

साहसी केवल "व्यवस्था का वेतन" पाते हैं, और ये सुनिश्चित होते हैं. गतिशील अर्थ-व्यवस्था में ही "प्रलोभन दायक लाभ विकास कार्यो के प्रेरणा स्रोत होते हैं शम्पीटर ने कहा

> "विकास के बगैर लाभ नही होता, लाभ के बगैर विकास नही होता. पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ के बगैर धन व सम्पत्ति व पूँजी सचय सम्भव नही है"

गतिशील व्यवस्था में कुछ साहसी कम व कुछ अधिक लाभ कमाते हैं. कुछ हानि भी उठा सकते हैं पर Circular flow (स्थिर व्यवस्था) में अगर "व्यवस्था का वेतन" बढता है तो सबको प्राप्त होता है यह 'वेतन' कभी शून्य नही होता पर गतिशील व्यवस्था में लाभ शून्य हो सकता है जब कोई वस्तु नई होती है तो खूब लाभ होता है बाद में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है व नवीनता समाप्त हो जाती है और लाभ घट जाते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं. जब फिर कोई नवीनता उत्पन्न की जाती है तो लाभ फिर उदय हो जाते हैं शम्पीटर के अनुसार

> 'Profit is at the same time the child and the victim of development"

ब्याज को शम्पीटर "Brake on development" विकास मे रुकावट डालने वाला तत्व मानते हैं वे उसे Tax on profit (लाभ पर कर) मानते हैं पर वे ब्याज को Condemn या निन्दा नही करते क्योंकि पूंजीपति के कार्य को वे महत्वपूर्ण मानते हैं.

8. आर्थिक विकास Swarm-like movements में (झुण्ड या समूह रूप में) या Spurts में (बडे प्रयत्न के कारण) होता है तथा नवीन प्रवर्तन इकट्ठे के इकट्ठे (पिण्डीभूत रूप) में होते हैं. (Innovation occurs in clusters) तेजी मन्दी का चक्र ही विकास की ओर ले जाता है [1]

पिछले मॉडलो में हमने देखा था कि परम्परागत अर्थशास्त्री व नव-परम्परागत अर्थशास्त्रियों का विश्वास था कि विकास धीरे-धीरे बगैर किसी वर्ग को हानि पहुँचाए, सुनिश्चित रूप से होता रहेगा पर शम्पीटर विकास को समयान्तर से एकदम बडे प्रयत्न के कारण समूह रूप मे एकदम बढने वाली प्रक्रिया मानते

(1) ब्याज के सम्बन्ध में देखिए पृष्ठ 158, 174, 175, 210, 211.

थे कुछ समय तक अर्थ-व्यवस्था स्थिर सी रहती है फिर एक-एक नवीन प्रवर्तन क्रियायें शुरू हो जाती है और हर इस प्रकार के 'बड़े प्रयत्न' के कारण अर्थ-व्यवस्था आगे बढ जाती है समस्त नवीन प्रवर्तन अविरल (discontinuous) रूप से होते है

नवीन प्रवर्तन और तेजी काल :

एक बार जब नवीन प्रवर्तनो मे स्वेच्छित विनियोजन होता है तो उसके नक्ल के रूप मे अन्य विनियोजन भी प्रोत्साहित होने है सट्टे की क्रियायें भी बढ जाती है. बैंको के द्वारा साख निर्माण बढ जाता है इस काल मे उपभोग वस्तुओ के उद्योगों के मुकाबले मे पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अधिक विकास होता है नए उद्योग स्थापित होते है, नई वस्तुएँ बाजार मे आती है और उत्पादन के नए तरीके निकलते है. पुराने उद्योग या तो बन्द हो जाते है या निम्न दर्जा स्वीकार कर लेते है. इस प्रकार से जो औद्योगिक सस्थान हानि उठाते है उन्हे शम्पीटर "सृजनात्मक बरबादी" कहते है तेजी व विकास के काल मे प्रभावशील माँग, नई वस्तुओ के आने से, बढ जाती है और इसके कारण लाभ बढते है

मन्दी :

जब नए विनियोजन, जो कि नवीन प्रवर्तनो के परिणामस्वरूप हुए थे, समाप्त हो जाते है, तब फिर मन्दी आती है सट्टे के कार्य भी शिथिल हो जाते है. दूसरी ओर बाजार मे नई वस्तुओ की बाढ सी आ जाती है, जिसके कारण मूल्य गिरने लगते है.

मूल्य इसलिए भी गिरने लगते है कि साहसी लोग अपने कार्य समाप्त हो जाने पर बैंको को ऋण वापिस करने लगते है, जिससे बाजार मे मुद्रा का चलन कम हो जाता है.

सबसे पहले पुराने संस्थान हानि उठाना शुरू कर देते है क्योकि उनकी वस्तुओ की माँग पहले गिरती है

धीरे-धीरे मन्दी पूरी अर्थ-व्यवस्था मे जा जाती है

पुनः विकास :

एक बार अर्थ-व्यवस्था मे से कमजोर व्यापारिक सस्थान व साहसी निकल जाते है तो पुन नए साहसी उत्पन्न होते है या पुराने साहसी फिर से नवीन प्रवर्तन कार्यो में जुट जाते है

हर तेजी व मन्दी के चक्र से अर्थ व्यवस्था ऊँचे स्तर पर पहुँच जाती

उपरोक्त विवेचना के लिए देखिए पृष्ठ 62-65 तथा 232-33.

है. राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय बढ जाती है और जन साधारण व श्रमिक वर्ग सस्ती चीजो से लाभान्वित होते हैं

विकास अविरल रूप से पिण्डीभूत रूप में क्यो होता है :

शम्पीटर ने अपने इस विचार के पक्ष म निम्नलिखित तर्क दिए :

(1) पूंजीपति अपनी पूँजी बहुधा एकदम व एक साथ विनियोजित करते है

(2) आर्थिक विकास एक पेड के विकास की भाँति धीरे-धीरे नही होता विकास की राह म हमेशा रुकावटे आती है व सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही कभी-कभी नीचे आ जाती है इसमे जब वह इन रुकावटो को दूर करती है तो फिर एकदम आगे बढ जाती है

(3) मन्दी भी धीरे-धीरे नही आती मन्दी का कोई एक कारण नही है. हर मन्दी के अलग-अलग कारण हो सकते है. हर मन्दी के अलग-अलग परिणाम भी होते है हर मन्दी म अलग-अलग वर्गो के लोग प्रभावित होते है. Sometimes there may be crisis without panic and sometimes there may be panic without crisis

इस प्रकार से जब विकास की तेजी आती है तो साहसी कच्चे माल व पूंजीगत सामानो के लिए एकाएक व एकदम अधिकाधिक मात्रा मे 'आर्डर' देते है फिर उत्पादनकर्ता एकाएक व एकदम अपने उत्पादन कार्यो का विस्तार करते है, दूसरी ओर जब मजदूरो व कच्चे माल के बेचने वालो के पास क्रय-शक्ति बढती है तब वे भी फुटकर व्यापारियो की बिक्री बढाते है. सब वर्गों को, युद्ध व मुद्रा स्फीति काल की भाँति लाभ प्राप्त होते है The symptoms of prosperity themselves finally become a factors of prosperity

और जब मन्दी आती है तो एक के बाद एक साहसी को हानि होने लगती है. समृद्धि ही मन्दी का कारण बन जाती है क्योकि सामान की बहुतायत हो जाती है (The only cause of depression becomes this prosperity itself)

9 पूंजीवादी विकास व्यवस्था का भविष्य[1] :

शम्पीटर मार्क्स के विश्लेषण से अधिक प्रभावित हुए थे, पर वे साम्यवाद को

(1) तेजी व मन्दी के सम्बन्ध मे शम्पीटर की उपरोक्त पुस्तक के पृष्ठ 214 228 देखिए तथा पृष्ठ 255 तक.

नापसन्द करते थे "वे किस राजनैतिक व्यवस्था को पसन्द करते थे यह हमेशा अनिश्चित सा रहा". एक बार तो उन्होंने रोमन केथोलिक चर्च के अन्तर्गत साम्यवाद के खिलाफ "सहकारी राज्य" की स्थापना की कोशिश करने की सिफारिश की कभी वे समाजवाद के आने की भविष्यवाणी करते थे

मार्क्स की भाँति शम्पीटर भी पूँजीवाद के उस योगदान की जो उसने विकास बढ़ाने में दिया, बहुत ही प्रशंसा करते हैं पूँजीवाद ने व्यक्तियों के सोचने विचारने व कार्य करने की पद्धति को वैज्ञानिक बनाया सामन्तवादी युग की मान्यताओं व उत्पादन की रीतियों को समाप्त किया

उन्होंने कहा

> 'Capitalism exalted the monetary unit a unit of account and adopted a cost-profit calculus which facilitated the logic of business enterprise and development"

पूँजीवाद के पहले के युग में कोई भी व्यक्ति शासक वर्ग से अधिक धनी नहीं हो सकता था. पूँजीवाद में यह सम्भव ही नहीं वरन् यथार्थ है। पूँजीवाद ने नई कला व जीवन यापन के उच्च तरीकों को जन्म दिया

> "It chased away mystic and romantic ideas. Capitalist civilization is rationalistic and anti-heroic."

पूँजीवाद ने नई उत्पादन रीतियाँ दी नई वस्तुएँ दी, नये सुख दिए, नई तकनीक दी, नया सामाजिक व औद्योगिक संगठन दिया तथा संक्षेप में नई सभ्यता दी

इतना सब कहने के पश्चात् शम्पीटर कहते हैं कि पूँजीवाद में दोष भी इतने हैं कि विकास की यह पद्धति ही समाप्त हो जाती है.

उन्होंने कहा .

> "पूँजीवाद के पक्ष में इतना कहने का आशय यह नहीं है कि मैं यह कहना चाहता हूँ पूँजीवादी पद्धति को रहने दिया जाए. यह पद्धति मानव जाति के कन्धों से गरीबी का भार नहीं उठा सकती"

शम्पीटर भी, मार्क्स की भाँति कहते थे कि पूँजीवाद का अन्त सुनिश्चित है. बेरोज़गारी, वस्तुओं की अधिकता व माँग की कमी, गिरते हुए लाभ आदि पूँजीवाद को समाप्त कर देंगे उनके इस सम्बन्ध में तर्क इस प्रकार थे .

(1) पूँजीवाद मे प्रतियोगिता 'पूर्ण' नही होती वरन् एकाधिकारी प्रतियोगिता होती है. इसके राजनैतिक परिणाम गम्भीर होते है. बड़े उद्योगपति व व्यापारी जब छोटे उद्योगपति व व्यापारियो को प्रतियोगिता मे नही रहने देते तो व्यक्ति राजनैतिक चुनावो मे ऐसे व्यक्तियो को चुनते है जो इनकी रक्षा करते है व बड़े पूँजीपतियो के सघो को तोड़ते है

(2) पूँजीवादी पद्धति म विनियोजक पूँजी शेयरो म लगाने व शेयरो के खरीदने व बेचने म अधिक दिलचस्पी लेते है अगर पूँजीपति फैक्ट्रियो के दीवारो व मशीनो म विनियोजन करने म अधिक दिलचस्पी लेते तो वे वास्तविक विनियोजन करते (Such investment takes life out of property and is responsible for bringing downfall of capitalism) इस कारण भी पूँजीवाद का पतन होता है.

(3) इस प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था मे 'साहसी' केवल 'व्यवस्थापक' या मैनेजर बनकर रह जाते है, और ये व्यक्ति गतिशील व्यवस्था को गतिहीन कर देते है, और जैसे शान्तिकाल में जेनेरल (General) का कोई महत्व नही रह जाता है, उसी तरह इस प्रकार की स्थिर व्यवस्था मे साहसी महत्वहीन हो जाते है

(4) बेरोजगार व्यक्ति तथा देश के बुद्धिजीवी धीरे-धीरे पूँजीवादी व्यवस्था के वैरी हो जाते है पूँजीवाद रूपी किला रक्षाहीन रह जाता है. पूँजीपति अपने कुछ आलोचको को धन से खरीद कर अपनी ओर कर सकते है पर वे सब आलोचको को नही खरीद सकते है बेरोजगार व्यक्तियो की वर्तमान कठिनाइयो से देश क राजनैतिक अपनी शक्ति प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा को पूरी करने क लिये इनको उकसाते है और इससे पूँजीवाद अर्थव्यवस्था के पैर उखड़ने लगते है आए दिन झगड़े, हड़तालें, ताला बन्दियाँ व सघर्ष उत्पन्न होते है.

(5) धीरे-धीरे जनता समाजवादी विचारधारा के व्यक्तियो को चुनकर सरकार बनाने का मौका देती है. वे समाजवादी विचारधारा के प्रशासको को कार्य चलाने के लिए नियुक्त करते है

देखिए
Capitalism, Socialsm and Democracy, P. 125-26

(6) ऐसे वातावरण में पूँजीपति बचत करने के लिए हतोत्साहित होते है. उन्हे अपने परिवार के लिए सम्पत्ति बनाने मे डर लगता है (A business man's time horizon shrinks to his life expectation) वह अपने ही जीवन-काल तक ही अपनी भविष्य की योजना सीमित रखने लगता है.

इस कारण शम्पीटर कहते है

> "Bourgeois order is now meek It is fighting defensive battle and now concedes demands of even small groups It s own thinking has now become subservient to the radical thinking "

वे इस कारण समाजवाद का आना निश्चित मानते है पर कहते है

> "अगर एक डाक्टर यह कहता है कि उसका मरीज मर जायेगा, तो इसका अर्थ नही है कि वह यह चाहता भी है. इसी भाँति हम समाजवाद से नफरत कर सकते है पर उसके आ जाने को रोक नही सकते है."

C: शम्पीटर के मॉडल की समीक्षा

1. बेन्जामिन हिगिन्स :

बेन्जामिन हिगिन्स शम्पीटर के मॉडल की बहुत सराहना करते है उनका कथन है कि शम्पीटर ने जो नवीन प्रवर्तनो का विकास शुरु करने मे जो महत्व बताया है उसका विश्लेषण अद्वितीय है" वे भी शम्पीटर से सहमत है कि विकास अविरल रूप से ही होता है वे तो इस मॉडल को विकासशील देशो के लिए भी महत्वपूर्ण मानते है इन देशो के स्वय स्फूर्ति अवस्था में पहुँचने मे साहसियो की कमी भी प्रमुख बाधक होती है हिगिन्स का कथन है, 'Tautological though the theory may be, there can be little doubt of its relevance (to under-developed countries)'

2. ऑस्कर लेन्ज (Oscar Lange)

शम्पीटर के इस विचार से कि विकास अविरल रूप से होता है, पूर्णतया

उपरोक्त पुस्तक के यह पृष्ठ मुख्य रूप से देखिए 61, 145-156, 161-62 अध्याय X-XIV

(1) Benjamin Higgins : op cit p 135-36

(2) Oscar Lange : Review of Joseph Schumpeter's 'Business Cycle' in Review of Economics & Statistics No. 1941. p. 192.

सहमत है स्थिर अर्थ-व्यवस्था की स्थिति में जब अर्थ-व्यवस्था पहुँच जाती है तब ही साहसी नवीन प्रवर्तन करते. इसमें कोई सदेह नही होता, क्योंकि इस अवस्था में नवीन प्रवर्तन करने में कम से कम जोखिम होता है.

3. रिचर्ड वी. क्लीमेन्स तथा फ्रान्सिस एस. डूडी. (Richard V. Clemence and Francis S Doody)

इनका भी विचार है कि विकास पिण्डीभूत रूप म'' होता है. जब साम्य की स्थिति होती है तब ही नवीन प्रवर्तन होते है क्योंकि इसकी प्रेरणा इसी समय ही होती है तथा जोखिम भी कम स कम होता है.

4 मियर तथा बाल्डविन (Meier & Baldwin)

शम्पीटर के मॉडल की आलोचना मुख्यतया रूढिवादी अर्थशास्त्रियो द्वारा उन्हीं कारणो से की जाती है जिन कारणो से मार्क्स के मॉडल की आलोचना होती है, अर्थात् इन अर्थशास्त्रियो को शम्पीटर द्वारा पूँजीवाद के भविष्य को अन्धकारमय बताया जाना अच्छा नही लगता मियर व बाल्डविन ने शम्पीटर के मॉडल की निम्नलिखित मुख्य आलोचनाएँ की

(1) आज के युग म साहसी व नव-प्रवर्तक एक आदर्शभूत व्यक्ति नही रह गया है. उसके कार्य आज नित्यकर्म में आ गए है.

(2) आज नव प्रवर्तन के अर्थ-व्यवस्था मे आघातात्मक प्रभाव नही हो पाते आज के बडे-बडे औद्योगिक सस्थान नव-प्रवर्तनो के अनुसार अपनी उत्पादन पद्धति को ठीक करने व यथाकाल व्यवस्था करने की क्षमता रखते है और नव प्रवर्तन मन्दी व तेजी नही ला पाते

(3) किसी भी देश मे मन्दी व तेजी के नव प्रवर्तन ही कारण नही होते. बहुत से वास्तविक (real), वित्तीय, मनोवैज्ञानिक तथा प्राकृतिक कारणो से भी मन्दी व तेजी का चक्र आता है

(4) शम्पीटर ने अपने विकास मॉडल में "बचतो" को पूँजी-निर्माण का मुख्य स्रोत नही माना. उन्होने 'साख' के योगदान को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया

मियर व बाल्डविन के अनुसार

"शम्पीटर ने जो विकास का वृहत् सामाजिक आर्थिक विश्लेषण किया उसको सर्वत्र सराहा जाता है, परन्तु बहुत कम व्यक्ति उनके निष्कर्षो

(3) Clemence and Doody . The Schumpeterian System, Cambridge. Mass 1950. p 54,

को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. उनके तर्क उत्तेजक हैं, उनका विश्लेषण उद्दीपक है, पर वे पूर्णतया विश्वसनीय नही हैं. उनका विश्लेषण एकतर्फा है व उन्होंने कई बातों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया.

5. हेनरी सी. वेलिच (Henry C. Wallich)

इन्होंने अपने एक लेख (Some Notes Towards a Theory of Derived Development) में शम्पीटर के मॉडल का अध्ययन किया

उन्होंने लिखा कि शम्पीटर का सिद्धान्त "आन्तरिक एकता से परिपूर्ण है" (It is full of internal unity)" पर विकासशील देशो के लिए उतना प्रासंगिक महत्व का नही है इसके उन्होंने कई कारण दिए जिनको निम्नलिखित रूप मे प्रस्तुत कर सकते हैं

(1) कम विकसित देशो मे साहसियो की कमी नही रही है उन्हें तो अनुकूल आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक वातावरण नही मिलता. आज की परिस्थितियो मे इन देशो मे केवल राज्य ही विकास शुरू कर सकता है साहसी यह नही कर सकते

(2) विकास जब एक अवस्था को पहुँच जाएगा तब ही साहसियो का महत्व होगा

(3) इन देशो मे बहुत से साहसी स्वार्थी तथा (estateminded) सम्पत्ति मे विनियोजन करने वाले होते हैं. वे अपने लिए अवसर पैदा नही कर पाते और उनका पूरा उपयोग नही कर पाते.

(4) इन देशों में विकास 'स्वय स्फूर्ति' की अवस्था मे तब ही पहुँच सकता है जबकि देश मे Social and Economic overheads (अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग तथा यातायात, सचार आदि) मे पर्याप्त विनियोजन हो यह कार्य साहसियो के बस का नही है.

(5) कम विकसित देशो मे 'नव प्रवर्तन क्रियाओं' से अधिक महत्वपूर्ण विश्व के अन्य देशो में हुए नव प्रवर्तनो का देश मे नकल कर के, या थोडा बहुत परिवर्तन करके अपने देश में अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है

(6) शम्पीटर के मॉडल में शम्पीटर ने निर्बाधवादी नीति को अपनाने की

Cf : Ed A. N Agarwal and Singh "Economics of Under-developed Countries. oxford 1958, p. 190-201.

सलाह दी आज के युग मे कम विकसित देशो में निर्बाध नीति के गम्भीर सामाजिक परिणाम हो सकते है

परन्तु इसका अर्थ यह नही कि 'शम्पीटर के साहसी' का इन देशो मे कोई महत्व ही नही है स्वय हेनरी सी वलिच ने कहा

> "The de emphasis of the role of entre preneurs in the theory of derived development does not imply that the entrepreneur does not fulfil a vital function"

6. हेबरलर (Haberler) :

शम्पीटर किसी के शिष्य नही थे और न उन्होने कोई शिष्य छोडे. उनके विकास मॉडल में विश्लेषण था, पर कोई कार्यक्रम नही था, जैसा कि केन्स के मॉडल में था. वे वालरा (Walras) व मार्क्स से ही अधिक प्रभावित थे

> "शम्पीटर ने हमको बहुत सी मौलिक तर्क व तथ्य दिए पर उनकी जटिलता व विभिन्नता के कारण उन मे सार्वभौमिकता नही है"

See also

1. Meier & Baldwin : op cit.
2. Benjamin Higgins : op. cit.
3. Spiegel : op. cit.
4. Nag : op cit.

अध्याय : 14

केन्स का मॉडल

Keyne's Model

1. प्रस्तावना :

केन्स के विकास मॉडल की विवेचना.

A उपयोग नही गिरना चाहिये.

1. वचत क्यो अधिक व उपभोग क्यों कम होता है.
2 परिणाम.
3. उपभोग बढाने के उपाय.
4. गुणक प्रभाव.

B I. निजी विनियोजन बढाना चाहिए. इसके लिये ब्याज की दर कम और पूँजी की कुशलता मे वृद्धि होनी चाहिये.

B II सार्वजनिक विनियोजन से 'मन्दी की खाई' को भरना चाहिए.

2. केन्स के 'उत्पादन के अगो को पुरस्कार' के सम्बन्ध मे विचार.

1 मजदूरी कम नहीं होना चाहिए.
2. ब्याज की कम दर होना चाहिये.
3. लगान प्राप्तकर्ताम्रो को समाप्त होना चाहिये.
4. लाभ अधिक होना चाहिए.

3 केन्स के अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन व व्यापार के सम्बन्ध मे विचार.

4 उपयुक्त मौद्रिक एव राजकोपीय नीतियाँ .

केन्स का मॉडल—सामाजिक अथवा पूंजीवादी, केन्स मॉडल की समीक्षा, कम विकसित देशो मे केन्स के मॉडल का महत्व, विभिन्न अर्थ-शास्त्रियो के तर्क

1. दासगुप्ता.
2. एच० डब्ल्यू सिगर.
3 डॉ० वी० के० आर० वी० राव.

डॉ० राव द्वारा केन्स मॉडल की अन्य आलोचनाएँ, मियर तथा बाल्डविन का विश्लेषण, जोसेफ शम्पीटर, केन्स मॉडल की अन्य संक्षिप्त समीक्षाएँ, गुण, दोष.

अध्याय : 14

केन्स का मॉडल

Keyne's Model

1 प्रस्तावना

"Keynes dominates what has come to be known as the "New Economics" in much the same manner as Einstein dominates the "New Physics" —Dudley Dillard

केन्स (जॉन मेनार्ड तथा बाद में लार्ड) निश्चय ही बीसवी सदी के महानतम अर्थशास्त्री हुए हैं मार्क्स को अगर हम "Prophet of doom" या "नाश होने की भविष्यवाणी करने वाला" कह सकते हैं तो केन्स को "Prophet of boom" कह सकते है क्योकि इन्होने यह बताया था कि विकसित पूँजीवादी देशो में किस प्रकार से मदी को दूर करके पूर्ण रोजगार विकास की स्थिति कायम रखी जा सकती है केन्स सही मायनो में २० वी सदी के एडम स्मिथ कहे जा सकते है आज स्थिति यह है कि समस्त अर्थशास्त्री या तो केन्स के समर्थक है या केन्स के विरोधी, पर वे सब केन्स के रग में रगे हुए है.

केन्स के बाद केन्स की विचारधारा का बहुत लोगो ने बहुत तरीको से विश्लेषण किया, उसमे सुधार किये तथा उन्हें सराहा केन्स के मॉडल को न केवल उन्नत देशो मे सराहा गया तथा उम पर अमल किया गया वरन् समाजवादी देशो व कम विकसित देशो मे भी केन्स की विचारधारा का गम्भीर अध्ययन किया गया Hicks (हिक्स), Harrod (हरोड) Tinbergen (टिंबरजन) आदि Ecometricians ने भी अपने मॉडलो को केन्स के मॉडल पर आधारित किया.

1929-30 की महान मदी ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मॉडल व उनके आशा वाद को खोखला सिद्ध कर दिया. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का कथन था कि दीर्घकाल मे कोई बेरोजगार नही रहेगा और अगर बेरोजगारी फैलती भी है तो मजदूरी की दर कम करके उसे कभी भी फैलने से रोका जा सकता है उनका

विश्वास था कि "पूर्ति अपनी माग स्वय उत्पन्न कर लेती है" केन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की 'निर्बाधवादी नीति का तिरस्कार किया. उन्होने यह सिद्ध कर दिया कि पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे ही सुधार करके पूर्ण रोज़गार का विकास पाया जा सकता है. "जब युद्ध जीता जा सकता है तो शान्ति भी जीती जा सकती है" अर्थात् शान्ति काल मे भी पूर्ण रोज़गार आ सकता है

केन्स के विकास मॉडल की विवेचना .

केन्स के अनुसार देश मे पूर्ण रोज़गार बनाए रखने से ही विकास होगा. केन्स चाहते थे कि विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि देश मे पूर्ण रोज़गार कायम रहे. केन्स के अनुसार देश मे पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए देश में राष्ट्रीय आय में कमी नही आना चाहिए (Y) या राष्ट्रीय आय, केन्स के अनुसार, 'प्रभावशील माँग' के बने रहने पर निर्भर रहती हैं. अन्य शब्दो मे देश मे पूर्ण रोज़गार प्रदान करने वाले विकास के लिए = Y नही घटनी चाहिए या E D (effective demand) अर्थात् प्रभावशील माँग नही घटना चाहिये.

(पृ० 168 पर दिया हुआ चार्ट प्रभावशील माँग को निर्धारित करने वाले तत्वो को बताता है.)

A उपभोग नही गिरना चाहिए. Consumption should not fall.

(1) केन्स ने बताया कि विकसित देश मे जैसे-जैसे राष्ट्रीय आय बढती हैं, वैसे-वैसे उपभोग क्षमता घट जाती हैं और बचत करने की क्षमता बढ जाती है जब आय बढती है तो पूरी खर्च नही हो पाती इसके कुछ कारण होते है (1) उन्नत जीवन स्तर को अपनाने मे देर लगती है तथा कोई व्यक्ति उन्नत जीवन स्तर को उसी समय अपनाता है जबकि उसको इस बात का विश्वास हो जाए कि बढी हुई आय स्थायी रूप से रहेगी, (11) इसके अतिरिक्त, केन्स के अनुसार लोग स्वय बचत करते हैं. यह बचत निम्नलिखित आठ उद्देश्यों से की जाती है :

(1) भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए Motive of precaution
(11) भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए Motive of foresight.
(iii) ब्याज कमाने के लिए · Motive of price

Keynes . (इनको Canes के रूप मे अर्थात् केन्स बोलते हैं).
"The General Theory of Employment, Interest and Money."

Full Employment या पूर्ण रोजगार → Y या राष्ट्रीय आय → प्रभावशील मांग

- (A) उपभोग Consumption
  - राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय Y
  - उपभोग क्षमता Propensity to consume
    - औसत उपभोग क्षमता Average Propensity to Consume
    - Marginal Propensity to Consume सीमान्त उपभोग क्षमता
    - Multiplier गुणक
- (B) विनियोजन Investment
  - (B-I) Private Investment निजी विनियोजन
    - ब्याज की दर Rate of Interest
      - द्रव्य की मात्रा Quantity of Money
      - तरलता पसंदगी Liquidity preference
    - पूँजी की सीमान्त क्षमता Marginal efficiency of Capital
      - लाभ की आशा Expectation of profits
      - नई मशीनों की लागत Replacement costs
  - (B-II) Public Investment सार्वजनिक विनियोजन

(iv) धीरे-धीरे सुख प्राप्त करने के लिए : Motive of Improvement.
(v) आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए Motive of Independence.
(vi) सट्टे के लाभ प्राप्त करने के लिए Motive of enterprise
(vii) उत्तराधिकारियों को देने के लिए Motive of Calculation
(viii) अपनी कजूसी को सतुष्ट करने के लिए Motive of advance

(2) परिणाम :

इन सब बचतो का परिणाम यह होता है कि यह बचतें Deflationary gap या मन्दी की खाई उत्पन्न कर देती है जब खर्च कम होते है तो देश म प्रभावशील माँग कम हो जाती है एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होता है. (हमारे कपडा पर खर्च, कपडे बेचने वाले की आय होती है) बचत इस प्रकार से व्यक्तिगत गुण हो सकती है परन्तु सामाजिक दुर्गुण हो जाती है, इसके कारण ही समृद्धि में गरीबी पैदा होने लगती है निम्नलिखित चित्र इस स्थिति को दर्शाता है
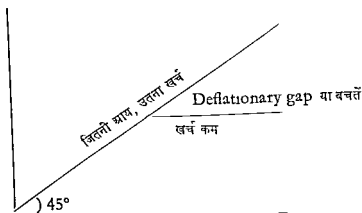
(3) उपभोग बढाने के उपाय :

केन्स के अनुसार अगर उपभोग को Unity रखा जाए, अर्थात् आय के अनुपात में बढाया जाए तो मन्दी नही आएगी और विकास होता रहेगा उपभोग को हम दो रूप से बढा सकते है

(1) Through objective changes या प्रत्यक्ष परिवर्तनो द्वारा और

(2) Through subjective changes या कुछ मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों द्वारा

पहली रीति के अन्तर्गत हम उपभोग निम्नलिखित तरीकों से बढ़ा सकते हैं :

(i) अमीरों पर कर लगा कर गरीबों को इस आय का हस्तान्तरण करें

(ii) वस्तुओं का मूल्य घटाएँ, विशषरूप से गरीबों के उपभोग बढ़ाने को

(iii) एकाधिकारियों के लाभों को कम किया जाए, जिससे वे कम मूल्य लें और माँग बढ़े

(iv) मुद्रा स्फीति न होने दी जाए तथा

(v) राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा पर व्यय बढ़ा दें.

दूसरी रीति के अन्तर्गत, उपभोग बढ़ाने के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुओं के उपभोग बढ़ाने के लिए समाज में, विज्ञापन व प्रचार से नई रुचियों, फैशनों व आदतों को उत्पन्न किया जाए

(4) गुणक प्रभाव :

अगर उपभोग बढ़ सकें तो इसके गुणक प्रभाव होते हैं 'गुणक प्रभाव' का अर्थ यह होता है कि उपभोग वृद्धि में जो विनियोजन पर प्रभाव होते हैं उनसे रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे केन्स का कथन है कि अगर देश में M P C (Marginal propensity to consume या सीमान्त उपभोग क्षमता) अधिक हो, गुणक भी अधिक होगा और विनियोजन में थोड़े से परिवर्तन से रोजगार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेंगे अगर M P C कम है तो विकास कायम रखने या रोज़गार कायम रखने के लिए, बहुत अधिक प्रयत्न करने पड़ेंगे

उपभोग का महत्व तो इतना अधिक है कि अगर M P C अधिक हो और चाहे विनियोजन (I) उतना ही रहे तो रोज़गार बढ़ जाएगा पर अगर M P C स्थिर है तो I के बढ़ने पर रोज़गार बढ़ाना कठिन होगा, जब तक कि I, M P C के कम होने की खाई पूरी न कर दें

केन्स का कथन है कि अल्पकाल में (जिसमें हमें पूर्ण रोजगार कायम करना है) इतना उपभोग बढ़ाना सम्भव नहीं होगा कि Deflationary gap पूर्ण रूप से घट जाए. इस लिए हमको विनियोजन बढ़ा कर यह 'अन्तर' पूरा करना पड़ेगा.

B. निजी विनियोजन बढ़ाना चाहिए. इसके लिए ब्याज की दर कम और पूंजी की कुशलता में वृद्धि होना चाहिए.

विकसित देशों में उपभोग व्यय से ही पूर्ण रोज़गार कायम नहीं रह सकता

उत्पादन की समस्त लागतें (या राष्ट्रीय आय) उपभोक्ताओं के ही पास नही पहुँच जाती इसमें से कुछ भाग राज्य के पास करो के रूप मे व कम्पनियों के पास लाभाश के बाकी भाग के रूप मे (depreciation allowances and undisbursed profits) बचा रहता है यह तो विनियोजन के रूप में ही प्रभावशील माँग बढा सकता है.

ब्याज की दर कम करना चाहिए (r)

विनियोजन बढाने के लिए, कम ब्याज की दर सहायक होती है. ब्याज की दर या तो मुद्रा की मात्रा बढा कर कम की जा सकती है या फिर तरलता पसदगी को कम कर के कम की जा सकती है. केन्स के अनुसार हर व्यक्ति अपने धन को कम या अधिक मात्रा मे तरल रूप में (या नगद रूप में) रखना चाहते है. अगर उनसे यह तरलता पसदगी छुडाना हो (या धन उधार लेना हो) तो उन्हें ब्याज का प्रलोभन देना पडेगा अगर समाज में तरलता पसदगी अधिक है तो ब्याज अधिक होगा. और अगर कम है तो ब्याज की दर भी कम होगी

केन्स का कथन है कि ब्याज की दर उपरोक्त दोनो रीतियों से कम तो की जा सकती है परन्तु गिरती हुई ब्याज की दर से ही विनियोजन नही बढ जाता है अगर लाभ की आशा क्षीण हो तो शून्य ब्याज की दर पर भी लोग धन लेकर विनियोजन नही करेंगे इसलिए ब्याज की दर घटा कर विनियोजन, आय, रोज़गार व विकास के स्तर न तो कायम रखे जा सकते और नही बढाए जा सकते है.

पूँजी की सीमान्त कुशलता बढाना चाहिए. (MEC)

केंस ने रोजगार स्तर व विकास की रफ्तार को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान तो उपभोग को दिया था उसके पश्चात् उन्होंने M. E. C या पूँजी की सीमान्त कार्य कुशलता को महत्व दिया (The M. E C is the rate at which prospective yields are expected.) M E. C. वह दर है जिस दर से लाभ अपेक्षित होते है.

यह M. E. C या तो मशीनो की लागत मूल्य के कम करने से बढेगी या फिर लाभ की आशा बढने से बढती है केन्स का कथन है कि मशीनो की लागत घटाना सरल कार्य नही है. इसके लिए तकनीकी उन्नति की आवश्यकता पडती है और यह स्वय विनियोजन बढाने से सम्भव होगा इसलिए लाभ की आशा बढाना ही आवश्यक होगा.

केन्स के मॉडल में या अर्थशास्त्र म M E C का महत्वपूर्ण स्थान है M E C की अल्पकाल मे वहुत अधिक परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है और दीर्घकाल म घटने की प्रवृत्ति होती है अगर M. E. C वढ जाय तो विनियोजन बट जाना है

केन्स ने बताया कि विकास प्रक्रिया म M E C खल नायक का पार्ट अदा करती है (M E C is the villain of piece अर्थात् जब विकास प्रक्रिया म M E C का एकाएक क्षय होता है या जब M. E C. गिरती है तो मदी शुरू हो जाती हैं केन्स ने बताया कि लाभ की यह सम्भावित आशा (M E. C) वहुत कुछ उत्पादन कर्ताओं की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है अगर गिरती हुई उपभोग क्षमता के कारण उत्पादनकर्ता निराश हो जाते है या भयभीत हो जाते है तो M E C गिर जाती है

केन्स का कथन है कि अगर हम M E C बढा सकें तो निजी विनियोजन बढ सकता है परन्तु किसी भी व्यक्ति को डरा देना अधिक सरल है और डरे हुए व्यक्ति का पुन सामान्य स्थिति मे लाना अधिक कठिन है व्यापारी केवल कह देने मात्र से या समझाने से ही आशावादी नही बन जाते. (It is much harder to make businessmen optimistic than to alarm them It is not easy to make businessmen optimistic by mere persuation.)

केन्स का यह कथन ह कि आज के युग म यह बात उद्योग जगत मे dormant capital owners (निष्क्रिय पूंजीपति या मालिक) होने की वजह से व्यापारिक ज्ञान कम होता है और ये लोग अफवाहो व व्यापारिक भय के जल्दी शिकार हो जाते है

इस कारण यह निश्चित है कि निजी विनियोजन इतनी मात्रा में नहीं बढ सकता कि 'मंदी की खाई' पूरी हो सके. इस कारण सार्वजनिक विनियोजन से ही यह खाई पाटी जा सकती है.

B II सार्वजनिक विनियोजन से Deflationary gap या 'मदी की खाई' को भरना चाहिए

केन्स ने बताया कि Deflationary gap को न तो उपभोग बढाकर भरा जा सकता है और न ही निजी विनियोजन बढाकर, क्योंकि ये दोनो अपेक्षित मात्रा में बढ ही नही पाते अब इस मदी-खाई को पाटने के लिए सार्वजनिक विनियोजन बढा देना चाहिए

सार्वजनिक विनियोजन हीनार्थ प्रबन्धन करके बढाया जा सकता है यह सार्वजनिक विनियोजन वृद्धि लाभ-हानि के हिसाब किताब पर आधारित नही होती वरन् पूर्ण रूप मे राजनीतिज्ञ या देश के नेताओ के हाथ मे होती है. केन्स के मॉडल में राज्य का विशिष्ट स्थान है केन्स के अनुसार, राज्य के प्रत्यक्ष कार्य के बगैर न तो देश मे प्रभावशील माग बढ सकती है और न निजी विनियोजन ही बढ सकता है.

राज्य के सार्वजनिक विनियोजन से गुणक प्रभाव होते है राज्य जब व्यय करता है तो निजी क्षेत्र वालो को भी "आर्डर" मिलते है राज्य के विनियोजनो से निजी विनियोजनकर्ताओ को वस्तुओ की माँग प्रत्यक्ष रूप से बढने लगती है. इसके अप्रत्यक्ष लाभ भी थोडे समय बाद सामने आने लगते है. जब राज्य के सार्वजनिक कार्यों मे मजदूरों को मजदूरी मिलती है तो उससे देश मे प्रभावशाली माँग बढती है. इससे निजी क्षेत्र वालो की वस्तुओ की भी माग बढती है.

फिर जिस प्रकार से तालाब में पत्थर फेंकने से एक के बाद दूसरी लहरे उठती है उसी प्रकार एक विनियोजन से दूसरे विनियोजन बढने लगते है

इस प्रकार जब पुन व्यय करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है तो वे व्यक्ति भी, जिन्हें कोई प्रत्यक्ष लाभ नही हुआ है, आशावादी वातावरण मे अपना निराशावाद छोड देते है और व्यय करने लगते है

केन्स ने बतलाया कि सार्वजनिक व्यय को चक्रविरोधी रूप से किया जा सकता है जैसे जैसे मदी कम होती जाय सार्वजनिक व्यय को कम किया जा सकता है और उसका स्थान निजी विनियोजन ले सकता है. इससे चक्रीय बेरोजगारी दूर की जा सकती है, परन्तु Chronic Unemployment या पुरानी बेरोजगारी आशिक रूप से दूर की जा सकती है. इसके लिए उपभोग भी बढना चाहिए

Keynes on rewards to factors of production.

केन्स के 'उत्पादन के अगो को पुरस्कार' के सबध मे विचार.

Wages मजदूरी · Wages not to be reduced.

केन्स से पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने यह मत व्यक्त किया था कि अगर देश मे विकास प्रक्रिया को कायम रखना हो तो मजदूरी की दरो को लचीला रखना होगा, अर्थात् आवश्यकतानुसार उन्हे घटा सकने की सुविधा होना चाहिए इस सुविधा के प्राप्त होने पर ही देश में पूर्ण रोजगार बना रह सकेगा और इसी के होने से देश के निर्यात बढ सकगे सक्षेप मे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री निम्नलिखित कारणो से मजदूरी दर कम रखना चाहते थे

(i) मजदूरी कम रखने या कम कर देने से लागत घटेगी. इससे वस्तुओं की माग, विक्री व उत्पादन बढ़ेगा और तदनुसार लाभ बढ़ जाएगा.
(ii) इससे विनियोजन व रोजगार बढ़ेगा.
(iii) विदेशी व्यापार मे निर्यात वर्धन से भुगतान सतुलन पक्ष मे आयेगा और देश मे विकास होगा
(iv) मजदूरी कम रखने से उत्पादनकर्ताओ को कम चल पूँजी की आवश्यकता होगी और इससे व्याज की दर भी गिरेगी
(v) मजदूरी कम होने से श्रम गहन तकनीक अपनाई जा सकेगी
(iv) मजदूरी घटने से मजदूरों की आय नही घटेगी उन्हें जो अतिरिक्त रोजगार मिलेगा. उससे मजदूरो की कुल आय (Wages bill) कम नही होगा

केन्स ने इस विचारधारा का इतना कड़ा विरोध किया कि उन्हें समाजवादी तक माना गया केन्स ने बताया कि इस नीति मे बहुत दोष हैं. इस नीति को अपनाने से न तो पूर्ण रोजगार को स्थापित करने मे मदद मिलेगी और न ही इससे विकास में सहायता मिलेगी उन्होने इसको निम्नलिखित कारणो से गलत बताया

(1) मजदूरी केवल लागत ही नही है वह किसी की आमदनी भी है अगर देश के सबसे बड़े वर्ग की आय घटा दी गई तो इससे प्रभावशील माँग गिरेगी, इससे देश मे उत्पादन विनियोजन व रोजगार गिर जाएगा
(ii) मजदूरी गिराकर व्याज की दर कम करने के केन्स बिल्कुल पक्ष में नही थे उनके अनुसार एक तो मजदूरी की दर घटाने में व्याज की दर घटाना 'मूर्खता का कार्य" होगा, क्योकि इसमे आसान रीति तो मुद्रा की पूर्ति बढाना हो सकती है और दूसरे व्याज की दर गिराने मे विनियोजन व रोजगार बढता नही है. जैसा कि हम देख चुके हैं व्याज की दर गिराकर विकास नही किया जा सकता.
(iii) केन्स ने इसके पश्चात् यह बताया कि आज के युग मे मजदूरी कम करना सम्भव नही होगा. मजदूर लोगो को चाहे मार-मार कर बिछा क्यो न दिया जाए वे मजदूरी की दरो मे कमी कभी मजूर नही करेंगे.

(i) See Part II of the book for "Wage policy for growth."
(ii) Cf keynes : op. cit. 267-9.
(iii) See also ch. VI of "Economics of wages, productivity and Employment" by O. S SHRIVASTAVA, Kailash pustak sadan, Gwalior.

(iv) केन्स ने इसकी अन्य हानियाँ यह बतलाई कि मजदूरी घटाने से उत्पादकता घटेगी, हड़तालो के कारण उत्पादन घटेगा और राष्ट्रीय आय घटेगी.

(v) मजदूरी के घटाने से श्रमिको की जो माँग घटेगी उससे M. E. C. कम होगी

संक्षेप में केन्स का मजदूरी के सम्बन्ध में यह मत था कि पूर्ण रोजगार युक्त विकास प्राप्त करने हेतु मजदूरी घटाना अनुचित होगा इससे रोजगार बढेगा नहीं वरन् उसका कम हो जाना सुनिश्चित है. केन्स मजदूरी घटाने के कट्टर विरोधी थे. उनका मत था कि मजदूरी के स्तर ऊँचे रखना ठीक है, परन्तु वे मजदूरी को बढाकर पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की सिफारिश नहीं करते थे.

Interest to be low for economic growth

केन्स ने ब्याज की दर को कम रखने की सलाह दी. किसी भी कम विकसित देशो में ब्याज की दर के दो कार्य होते है. एक तो उसकी दर इतनी कम नही होना चाहिए कि बचतें हतोत्साहित हो जाएँ और दूसरे इतनी अधिक नही होना चाहिए कि विनियोजन ही हतोत्साहित हो जाये.

केन्स ने अपनी "General Theory" विकसित देशों को ध्यान में रख कर लिखी. उनके मॉडल में बचतें, ब्याज की दर निर्भर नही करती. (Saving is not a function of rate of interest but of high income) बचतें तो आय बढने के साथ-साथ M. P. S के अधिक होने या M P. C. के कम होने के कारण हो जाती है. इसलिए पूँजीनिर्माण के लिए बचतो व साधनो की कमी तो है ही नही. इसलिए केन्स ब्याज की दर को कम चाहते थे.
ब्याज की दर को कम रखने में केन्स के अनुसार विकास प्रक्रिया मे निम्नलिखित मदद मिलेगी

(i) विनियोजन प्रोत्साहित होगा, (हालाँकि वे इसे M E C. की वृद्धि से कम महत्वपूर्ण मानते थे):

(ii) बचतें कम रहेगी व उपभोग बढेगा तथा

(iii) गैर कमाई आय कम होगी और धन की असमानताएँ कम होगी और देश की M. E C. बढेगी.

संक्षेप में, केन्स के अनुसार, विकसित देश में, नीची ब्याज की दर, ऊँची ब्याज की दर के मुकाबले में विकास प्रक्रिया मे अधिक सहायक होती है.

Rent : Euthenasia of the rentier will be helpful
लगान and necessary लगान प्राप्तकर्ताओं को समाप्त होना चाहिए.

केन्स ने लगान आय पर प्रहार किया. उनके अनुसार इससे देश मे गैरकमाई आय बढती हैं और धन की असमानताओं के बढने के कारण देशो की प्रभावशील माँग कम रहती है परन्तु, केन्स लगान को "क्रान्तिकारी कारण" से समाप्त नही करना चाहते थे वे चाहते थे कि धीरे-धीरे यह प्रणाली समाप्त हो जाएगी.

Profits Profits to be high लाभ अधिक होना चाहिए
केन्स जहाँ लगान व ब्याज को कम रखना चाहते थे वहाँ वे लाभ को अधिक ही चाहते थ न केवल लाभ अधिक होना चाहिए वरन् लाभ की आशा भी अधिक होना चाहिए इससे M E C. अधिक रहती ह तथा विनियोजन अधिक रहेगा और पूर्ण रोजगार युक्त विकास सभव होगा

3 Role of International Trade and Investment

केन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन व व्यापार के सम्बन्ध मे बहुत ही व्यापक विचार रखे वे Multilatiral trading या अधिकाधिक देशों के बीच अधिकाधिक व्यापार के पक्ष मे थे इसी कारण उन्होने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी सस्थाओं की स्थापना कराने में पहल की

केन्स चाहते थे कि अगर विकसित देश अपने निर्यात बढाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हे विकासशील देशों की आयात करने की क्षमता बढानी होगी वे कम विकसित देशो के लिए सरक्षण नीति की भी सिफारिश करते थे. वे कम विकसित देशा पर ऋण भार कम रखने या करने की सिफारिश करते थे

केन्स ने बताया कि अगर विकसित देश कम विकसित देशों को सहायता या पूंजी ऋण देते है तो इसमे कम विकसित देश इन देशों से खरीदेंगे और प्रभावशील माँग की कमी पूरी हो जाएगी कम विकसित देशो मे भी विकास होगा

केन्स का कथन था कि अगर एक अधिक बचत वाला देश मन्दी की बेरोजगारी से पीडित हो तो यह देश अगर ऋण, अनुदान व पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान कम-विकसित देशों को दे तो इससे उन देशो म भी बेरोजगारी दूर होगी क्योंकि कम-विकसित देशो मे माँग उत्पन्न होगी.

केन्स ने विकसित देशो से कम विकसित देशो को सहायता देने में विकसित देशो के भले के लिए बताया

4 Suitable monetary and Fiscal policies.

(1) केन्स ने ऐसी मौद्रिक नीति की सिफारिश की जिससे मन्दी के दिनो में मुद्रा चलन की पूर्ति बढे वे चाहते थे मन्दी के दिनो मे ब्याज की दर कम कर दी जाए ताकि विनियोजको को उधार लेना सरल हो.

(2) केन्स सार्वजनिक विनियोजन की अधिकतम मात्रा पर बल देते थे और वे चाहते थे कि यह विनियोजन हीनार्थ प्रबन्धन' से अर्थात् नए नोट छाप कर, किया जाए

(3) केन्स चाहते थे कि मन्दी काल म राज्य जो अतिरिक्त व्यय करे वह ऋण लेकर करे, अधिक कर लगाकर नही करे. ऋण लेकर खर्च करने से बचतें व्यय का रूप धारण कर लेती है और देश मे प्रभाव शील माँग बढती है केन्स 'हीनार्थ प्रबन्धन'' को Income creating finance कहते थे

(4) केन्स के मॉडल के प्रकाश म आने से पहले, मन्दी दूर करने के लिए मौद्रिक नीति को ही अधिक महत्व दिया जाता था केन्स ने राजकोषीय नीति को Anti cyclical चक्र विरोधी नीति के रूप मे प्रयोग करने की सफल सलाह दी.

(5) केन्स चाहते थे कि मन्दी के दिनो म आवश्यकतानुसार कुछ अप्रत्यक्ष करो को कम किया जाए ताकि उपभोग बढ सके

(6) उपरोक्त विश्लेषण का अर्थ यह नही है कि केन्स मुद्रा स्फीति चाहते थे. वे मुद्रा स्फीति को भी नियन्त्रित रखना चाहते थे उनका कथन था कि मुद्रास्फीति को मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिग के स्थान पर, मौद्रिक व राजकोषीय नीति से नियन्त्रित करना चाहिए समृद्धि के दिनो मे समस्त राजस्व क्रियाये करो से चलाना चाहिए इन दिनो में अनिवार्य रूप से बचतें भी कराई जा सकती है केन्स सही मायनो मे मुद्रा स्फीति और मन्दी दोना पर मौद्रिक, राजकोषीय व विनियोजन नीति से "सामाजिक नियन्त्रण" चाहते थे

क्लाईन ने इसीलिए लिखा है

> 'The versatility of Keynes general system of theory was demonstrated by the fact that the same frame-work could be used to analyse inflation and unemployment "

अन्य शब्दो मे केन्स ने policy of pump priming (हीनार्थ प्रबन्धन) तथा मौद्रिक नीति (Credit regulation and control of rate of interest) के द्वारा व्यापार चक्रो की तीव्रता को समाप्त कर, पूर्ण-रोज़गार सहित विकास करने की नीति सुझाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया

Keynesian Model Socialistic or Capitalistic ?

केन्स ने अपनी General Theory म जो कुछ लिखा उससे हम उनका विकास मॉडल निकाल सकते हैं परन्तु इस सम्बन्ध मे मतभेद हो सकता है कि वे अधिक समाजवादी थे या अधिक पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे

A उन्होने मजदूरी न घटाने तथा ब्याज व लगान के कम रखने के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा उससे उनके समाजवादी होने का दावा किया जा सकता है केन्स ने धन व आय म समानता के पक्ष मे बहुत कुछ लिखा क्योंकि अधिकाधिक समानता से देश मे प्रभावशील माँग बढती है जिससे कि पूर्ण रोजगारयुक्त विकास सम्भव होता है उन्होंने अपनी सार्वजनिक नीति मे भी (i) अमीरो पर अधिक कर लगाकर गरीबो को सहायता पहुँचाने (ii) मूल्य नियन्त्रण रखने, तथा (iii) सामाजिक सुरक्षा सुविधाओ को बढाने के लिए भी सिफारिश की

उनके यह तर्क प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के तर्को से एकदम भिन्न थे. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री धन की असमानताओ को उत्पन्न करने पर जोर देते थे क्योंकि केवल धनी लोग ही बचत करके विनियोजन कर सकते थे. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की यह मान्यता पूर्ण रोजगार-सहित विकास की स्थिति मे ठीक हो सकती है परन्तु केन्स ने तो अपूर्ण-रोज़गार को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता माना.

जैसा कि हमने देखा, केन्स "अमीरी को ही गरीबी का कारण" मानते थे (जैसे बहुत मोटापा शरीर को लाभ न पहुँचाकर हानि ही पहुँचाता है) । उन्होने कहा था कि जो देश जितना अधिक समृद्ध होगा उतना ही उस देश मे विनियोजन वृद्धि प्रभावशील माँग की इकाई से कम होने के कारण, कठिन होगी.

उनका यह विश्लेषण मार्क्स के विश्लेषण की भाँति था. उन्होने निर्बाधवादी नीति को विकास व सामाजिक कल्याण वृद्धि के लिए अनुपयुक्त बताया उन्होने यह लिखा कि :

> "The classical theory (of development) is a special case which is misleading and disastrous if we attempt to apply it to the facts of experience"

B. परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि केन्स मार्क्स की तरह यह चाहते कि समाजवाद आए. मार्क्स के अनुसार स्थायी विकास की सम्भावना तब ही उत्पन्न हो सकती है जब कि देश मे निजी सम्पत्ति पद्धति पूर्ण रूप से समाप्त होकर समाजवाद की स्थापना हो जाए. वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के अर्थशास्त्र को "घृणित अर्थशास्त्र" कहते थे.

केन्स ने पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को कायम रखकर भी पूर्ण-रोजगारयुक्त विकास की सम्भावनाएँ देखी. वे तो पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था को केवल Mend (सुधार) करना चाहते थे, वे उसे end (समाप्त) नही करना चाहते थे वे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की समस्त विचारधारा को त्रुटिपूर्ण नही मानते थे. उनकी मृत्यु के बाद एक लेख ("The Balance of Payment of United states." in Economic Journal, June 1946) मे उन्होने लिखा.

> 'I find myself moved not for the first time to remind contemporary economists that the classical teachings embodied some permanent truths of great significance "

केन्स की स्थिति और उनके विकास सम्बन्धी विचारो की निम्नलिखित समीक्षा, जो कि डडले डिलार्ड ने की है, अत्यन्त उपयुक्त है

"केन्स "औद्योगिक पूंजीवाद" (Industrial capitalism) के समर्थक थे, परन्तु वे "वित्तीय पूंजीवाद" (financial capitalism) के विरोधी थे. वे व्यक्ति की आर्थिक स्वतन्त्रता व निजी उद्योग के समर्थक थे पर वे "निर्बाध-वादी नीति" के विरोधी थे "[1]

उनका स्पष्ट मत था कि अगर पूंजीवाद के वित्त सम्बन्धी दोषों व वितरण सम्बन्धी दोषो को दूर कर दिया जाए तो इसमे अच्छी विकास की सम्भावनाएँ कही और नही होगी.

Evaluation of Keynesian Model with particular reference to The Relevance of Keynesian Model in underdeveloped Countries.

See · "Economic Thinking of Lord Keynes, Socialist or Capitalist ? by Prof. Dudley Dillard. Forum of Free Enterprise." p—16

केन्स मॉडल की समीक्षा.

कम विकसित देशो मे केन्स के मॉडल का महत्व

केन्स के मॉडल का कम-विकसित देशो मे क्या महत्व है इस सम्बन्ध में अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने जो तर्क दिए है वे इस प्रकार है

(1) केन्स के मॉडल म अनैच्छिक तथा मन्दी की बेरोजगारी दूर करने के उपाय सुझाए गए है परन्तु कम-विकसित देशो मे तो संरचना-सम्बन्धी (Structural unemployment) बेरोजगारी तथा Chronic under-employment या पुरानी अर्ध बेरोजगारी की समस्या होती है. केन्स का मॉडल इस प्रकार की बेरोजगारी को दूर कर विकास पथ नही बताता. दास गुप्त के अनुसार कम-विकसित देशो मे मुश्किल से o 5 प्रतिशत व्यक्ति ही अनैच्छिक बेरोजगारी के शिकार पाए जाएँगे.

(2) केन्स का मॉडल पूर्ण रूप से मुद्रा-चलित अर्थ-व्यवस्था (fully monetized economy) म लागू होता है कम-विकसित देशो मे मुद्रा बाजार इतना अधिक विकसित नही होता यहाँ तो बहुत सी मौद्रिक नीति सम्बन्धी कदम अपना असर अपेक्षित रूप से नहीं दिखाते. देश के कुछ भागो मे "अदला-बदली" (batter) प्रणाली मौजूद रहती है

(3) विकसित देशो में मन्दी लाने वाली मुख्य चीज M E. C. का गिरना होता है. कम-विकसित देशो मे Liquidity preference तरलता पसन्दगी की अधिकता होता है यहाँ के अधिकाश लोगों की आय कम होती है जिसके कारण ये व्यक्ति अपनी आय को तरल रूप मे (या नगद रूप मे) 'आडे दिनो' के लिए रखते है इससे देश मे विनियोजन व पूंजी-निर्माण कम होता है. स्वय केन्स ने लिखा

> 'भारत के इतिहास ने हमेशा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार एक देश तरलता पसन्दगी के कारण गरीब बना रहता है. यहां तरलता पसदगी एक प्रेम है (Passion) जिसके कारण इस देश में इतना अधिक सोना चांदी आने पर भी ब्याज की दर, देश में वास्तविक धन की मात्रा के माफिक, कम नहीं होती

---

1. See . A K Das Gupta's Keynesian Economics and Under-developed Countries ch. 2 Planning and Economic Growth. George Allen & Unwin
2 Keynes . op cit ch 23, p. 337.

2 H W. Singer हॉन्स डब्ल्यु सिंगर :

केन्स के मॉडल मे बचतो की कमी की समस्या नही है उनका मॉडल विकसित देशों के लिए है जहाँ बचतें स्वय आय के साथ बढ जाती हैं. केन्स के मॉडल मे बचतो की अधिकता ही विनियोजन के अवसर कम करती है क्योंकि बचतो की अधिकता ही उपभोग चमता की कमी का द्योतक है.

परन्तु कम विकसित देशो में यह समस्या नही होती यहाँ तो एक तो राष्ट्रीय आय बढने से उपभोग बढता है, यहाँ तो बचतो को बढाने के लिये प्रयत्न करना पडता है. यहाँ अधिक बचते समस्या पैदा नही करती वरन् उनसे जो पूँजी निर्माण होता है, वह विनियोजन को बढाता है और विकास होता है

The fact of Keynesian thinking, that an excessive propensity to save may kill off the inducement to invest as incomes rise, obviously is not applicable in underdevdoped countries where the increase in savings is conceived as itself the result of the emergence of new investment opportunities

Keynes as stagnationist · विकास पर जिन लेखको ने लिखा उन्हे किसी न किसी कारण से "स्थैगिक अवस्था" का भय सताता रहा. जहाँ रिकार्डो को यह भय उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण सताता था, माल्थस को जनसख्या की वृद्धि के कारण इस अवस्था के आने का डर था मार्क्स को पूँजीवाद की समाप्ति का डर (या आशा कहे ?) था तो शम्पीटर को यह डर था कि साहसियों के बच्चे "कवि बन कर रह जाएँगे" केन्स को M E C के गिरने के कारण स्थैगिक अवस्था के पहुँच जाने का भय था

केन्स को मुख्यतया दो बातो का भय था एक तो उनको इस बात का भय था कि गिरती हुई उपभोग चमता से विनियोजन, रोजगार व राष्ट्रीय आय गिरते चले जाएगे और दूसरा उन्हें यह भय था कि अगर गिरते हुए उपभोग चमता के दुष्प्रभावो को विनियोजन व गुणक प्रभावो से दूर भी किया जा सके तो M E C के प्रभाव दिखाई देंगे

See : H. W. Singer · "International Development Growth and Change." Mc Graw Hill series 1964, p. 4-5, 6, 7 and 27-28

3. Dr. V. K. R V. Rao : डा० वी० के० आर० वी० राव

डा० वी० के० आर० वी० राव ने केन्स के मॉडल के कम विकसित देशों में लागू होने के सम्बन्ध मे बहुत अच्छा विश्लेषण किया है. उन्होने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि इन देशो मे केन्स की नीतियाँ लागू नही की जा सकती क्योकि केन्स का गुणक इन देशो मे लागू नहीं होता.

इस सबंध मे वे यह कहते है कि स्वय केन्स ने यह मॉडल विकासशील देशो के लिए नही बनाया वरन् यह तो अन्य लोगो ने गलत कार्य किया कि उन्होने केन्स की नीतियों को कम विकसित देशो मे लागू किया

कम विकसित देशो मे केन्स के मॉडल मे बताए "गुणक प्रभावों" के लागू न होने के डा० राव ने निम्नलिखित कारण बताए

1. किसी भी देश में "गुणक प्रभावो" के अधिक होने के लिए निम्नलिखित चार बातें आवश्यक होती है
   - (a) M P C. उपभोग क्षमता अधिक होना चाहिए.
   - (b) देश मे अनैच्छिक बेरोजगारी मौजूद होना चाहिए.
   - (c) देश में Excess capacity मौजूद होना चाहिए अर्थात् कल-कारखानो मे उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन होने की स्थिति होना चाहिए तथा
   - (d) पूर्ति को मूल्य वृद्धि की अवस्था मे बढना चाहिए.
2. डा० राव का कथन है कि निश्चित ही कम विकसित देशो मे 'सीमान्त उपभोग क्षमता' अधिक होती है परन्तु इन देशो में (b), (c), (d) स्थितियाँ मौजूद नही होती.

डा० राव ने बताया कि कम विकसित देशो में Involuntary unemployment या अनैच्छिक बेरोज़गारी नही होती वरन् मुख्यतया अर्ध बेरोज़गारी होती है विकसित देशा मे जब विनियोजन बढाया जाता है तो उत्पादन बढता है और बेरोज़गारी दूर हो जाती है परन्तु कम विकसित देशो मे विनियोजन के बढाने से अर्ध-बेरोज़गारी उतनी शीघ्र दूर नही हो पाती इसके दो मुख्य कारण है

(1) एक तो बहुत से अर्ध बेरोज़गार व्यक्ति इतने अधिक गतिहीन होते हैं कि वे काम के अवसर प्राप्त नही कर पाते तथा

Cf: Dr. V. K R V. Rao : Investment, Income and the Multiplier in Under-developed Economy, as ch II, p. p. 35-49 in "Essays in Economic Development".

(ii) दूसरे वे उत्पादन उस मात्रा मे नही बढा पाते.

3 विकसित देशो मे राष्ट्रीय आय का अधिक प्रतिशत विनियोजित किया जाता है, जिसके कारण, कम M. P C होने हुए भी गुणक अधिक होता है.

कम-विकसित देशो म M P. C तो अधिक होती है परन्तु विनियोजन की मात्रा कुल राष्ट्रीय आय की मात्रा का बहुत कम प्रतिशत होती है, इस कारण गुणक प्रभाव कम रहते है

इस प्रकार से कम विकसित देशो मे प्राथमिक विनियोजन से जो रोज़गार वृद्धि होती है उतनी ही Secondary (उद्योग आदि) तथा Tertiary (आर्थिक-सामाजिक सिरोपरी क्षेत्र जैसे यातायात, वैंकिंग आदि) मे रोज़गार वृद्धि नही हो पाती.

4 डा० राव ने एक और कारण जिसमे केन्स का गुणक कम-विकसित देशो म लागू नही होना यह बताया कि इन देशो म पूर्ति लोचदार नही होती. इसका कारण यह है कि जब इन देशो में प्राथमिक विनियोजन बढने से उपभोग्य वस्तुओ की माँग बढती है जिन मे पूर्ति आसानी से बढाई नही जा पाती और इस कारण इनमे रोजगार वृद्धि केन्स के गुणक के अनुरूप नही हो पाती. कम विकसित देशो में आय बढने से खाद्य वस्तुओ की माँग अधिक बढती है या फिर मोटे अनाज के स्थान पर उत्तम अनाज की माँग होने लगती है.

डा० राव का कथन है कि इन देशो में मूल्य परिवर्तन से उपज की किस्मो मे परिवर्तन हो जाता है परन्तु कुल पूर्ति मे विशेष परिवर्तन नही हो पाता इसका मुख्य कारण, जैसा कि सर्वविदित है कृषि का पिछडापन होना तथा उन्नत तरीको की सुविधाओ की कमी होना है इस कारण डा० राव कहते है

> "The income multiplier is much higher in money terms than in real terms and to that extent prices rise much faster than an increase in aggregate real income."
>
> (अर्थात् इन सब कारणो से वास्तविक आय वृद्धि मे मौद्रिक आय वृद्धि अधिक रहती है.)

5 डा० राव आगे कहते है कि न केवल कृषि क्षेत्र में प्राथमिक विनियोजन के गुणक प्रभाव नगण्य होते है वरन् Secondary तथा Tertiary क्षेत्र मे

भी यह प्रभाव विकसित देशो की भाँति नही होते इन क्षेत्रों मे Excess capacity या इस्तेमाल म न आने वाली उत्पादन क्षमता नही रहती, जैसा कि विकसित देशा म होता है. डा० राव का अर्थ है जहाँ विकसित देशो मे काम म न आने वाली मशीनों को काम मे लेकर तुरन्त उत्पादन बढाया जा सकता है वहाँ कम विकसित देशा में ऐसा नही हो पाता. यहाँ पर इसी प्रकार से कुशल श्रमिको की भी कमी रहती है और भिन्न भिन्न प्रकार की रुकावटो से उत्पादन, रोजगार व आय वृद्धि विकसित देशो की भाँति नही हो पाती अर्थात् *गुणक प्रभाव कम रहते है*

6 डा० राव का कथन है कि विनियोजन वृद्धि से इन देशो मे जिस मात्रा में आय (मौद्रिक आय) बढती है उस मात्रा मे उत्पादन व रोजगार नही बढता

डा० राव द्वारा केन्स मॉडल की अन्य आलोचनाएँ :

7 केन्स ने विकसित देशो मे पूर्ण रोजगार तक पहुँचने की बात कही है, इसके बाद इसे कैसे कायम रखें इसको नही बताया यह कार्य बाद मे हरोड व डोमर ने Acceleration principle की सहायता से किया

8 केन्स ने बचतो की अधिकता को सारी कठिनाईयो की जड बताया, परन्तु कम विकसित देशो में बचत करके ही विकास प्राप्त किया जा सकता है. यहाँ तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो द्वारा कथित महत्व को मानना पडेगा

9. इन देशो मे हम केन्स द्वारा बताई "हीनार्थ प्रबन्धन" की नीति को अधिक अपनाएगे तो बचतें बढने के स्थान पर, मुद्रा स्फीति के कारण, घट सकती है यहाँ तो "अधिक काम करके अधिक बचत करो" का सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण है इन देशो म प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो द्वारा बताई हुई नीतियाँ ही अधिक महत्वपूर्ण है

Meier and Baldwin's analysis.

मियर तथा बाल्डविन के अनुसार :

1. यद्यपि केन्स की पुस्तक (General Theory) ने 'व्यापारिक उच्चावचनो के विश्लेषण म नवक्रान्ति लाई, फिर उनका विश्लेषण अल्पकालिक समस्याओं का था उन्होंने अपने विश्लेषण में, (i) श्रमकी मात्रा व कार्य कुशलता, (ii) पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा व किस्म (iii) वर्तमान तक-

---

1, Meier and Baldwin : op cit · p. 102-3. & pp. 1, 13, 90, 97, 545 and 546.

नीक, (iv) प्रतियोगिता की मात्रा व (v) उपभोगकर्ताओं की आदतों व रुचि को स्थिर माना

2. केन्स का मॉडल "स्थैतिक मॉडल" रहा और उसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, मार्क्स व शम्पीटर की भाँति दीर्घकालीन विकास समस्याओं का विश्लेषण नही किया गया था

3. यद्यपि केन्स के मॉडल मे बचत-विनियोग की समस्या तथा प्रभावशील माँग की समस्या पर पहले के अर्थशास्त्रियों के मुकाबले मे अधिक ध्यान दिया, परन्तु उन्होंने Capacity अर्थात् उत्पादन क्षमता की समस्या को ध्यान नही दिया. (इस पर हरोड व डोमर ने लिखा)

   मीयर तथा बाल्डविन केन्स के (i) प्रभावशील माँग बढाने, (ii) ब्याज की दर को विकास क्रिया में कम महत्त्वपूर्ण बताने, (iii) मजदूरी पर प्रहार न करने की सलाह देने, (iv) जनसंख्या वृद्धि को बुरा न समझने (वे उससे प्रभावशील माँग बढने की गुंजाइश देखते थे) तथा (v) guided or planned capitalism अर्थात् आयोजित पूँजीवाद अपनाने की सलाहों की सराहना करते है

Joseph Schumpeter

सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री शम्पीटर का कथन है कि मार्क्स का मॉडल केवल इंगलैंड मे लागू हो सकता है अन्य देशों मे नही हो सकता.

उन्होंने कहा

> "प्रायोगिक केन्सवाद एक ऐसा पौधा है जो विदेशी भूमि में नही रोपा जा सकता. यह पौधा दूसरे देश मे मर जाता है, और मरने से पहले जहरीला हो जाता है परन्तु इंगलिश भूमि मे यह पौधा पनपता है, तथा फल व साया देता है"

केन्स मॉडल की अन्य संक्षिप्त सामान्य समीक्षाएँ :

गुण :

1 केन्स ने बताया कि बचतें ब्याज की दर पर निर्भर नही रहती वरन् आय के ऊपर निर्भर रहती है विकसित देश मे बचतों की अधिकता लाभदायक नही वरन् हानिकारक होती है. जहाँ बेरोजगारी व्यापक हो वहाँ अधिक खर्च लाभदायक होता है बचतें नही

2. Schumpeter . Ten Great Economists p 275.

2 केन्स ने निर्बाधवादी नीति को तिरस्कार किया और "पूर्ण उत्पादन" के स्थान पर "पूर्ण-रोजगार" को अधिक महत्व दिया उन्होंने विकास के लक्ष्यों का "मानवीय" करण किया.

3 केन्स का मॉडल भी विकास के घटको में सह-संबध अध्ययन करना है, परन्तु केन्स ने राज्य की क्रियाओ को बहुत अधिक महत्व दिया राज्य की राजस्व व मौद्रिक नीतियो को उन्होंने इस प्रकार से सचालित करने को कहा कि उससे विकास मे सहायता मिले वे तटस्थ मौद्रिक व राजकोषीय नीतियाँ नही चाहते थे

4 उन्होने पूंजी अर्थव्यवस्था के दोष बताए कि इस व्यवस्था मे "पूर्ण-रोजगार युक्त विकास केवल युद्ध काल म या युद्ध की तैय्यारी मे ही प्राप्त हो सकता है" उन्होने बताया कि अगर इन देशो म पूर्ण रोजगार युक्त विकास लाना है और स्वय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है तो थोडा समाजवाद जैसे (1) मूल्य नियत्रण (11) एकाधिकार नियत्रण (111) ब्याज प्राप्त कर्ताओं तथा लगान प्राप्तकर्ताओं की आय कम करना (1V) धन के असमान वितरण को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो से दूर करना आदि को अपनाना पडेगा.

5 उन्होने "उत्पादन के अगो का राष्ट्रीयकरण" के स्थान पर विनियोजन व कुल उपभोग का समाजीकरण" का सुझाव दिया उन्होने हमेशा याद रखे जाने वाले शब्दो मे कहा "मुद्रा स्फीति अन्याय पूर्ण है तथा मुद्रा विस्फीति अनुपयुक्त है, तथा दोनों मे मुद्रा विस्फीति अधिक बुरी है-

6. केन्स ने विकसित देशो की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे सहायता व व्यापार सम्बन्धी संकीर्णता को दूर किया और विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना मे कम विकसित देशो व विकसित देशो दोनों का भला बताया

7 उन्होंने पीगू तथा अन्य अर्थशास्त्रियों की Anti-labour मनोवृत्ति को (जिसमे वे मजदूरी दर को नीचा करके रोजगार बढाने की बात कहते थे) गलत सिद्ध कर दिया

दोष :

केन्स के मॉडल व विचारो की कुछ अर्थशास्त्रियो द्वारा दी गई आलोचनाएँ इस प्रकार हैं :

1. उन्होंने "पूर्ण रोजगार" को पूर्ण उत्पादन के मुकाबले मे अनावश्यक रूप से बल दिया. (Haney, Mantoux, and Hazlitt)

2 उनका मॉडल स्थैगिक है, प्रवैगिक नही है (Harrod, D. H. Robertson).

3. यह मॉडल "सामान्य नही है" (केन्स ने उसका नामकरण "सामान्य सिद्धान्त" किया था) बल्कि विशिष्ट परिस्थितियो में कुछ ही देशो मे लागू होता है (Rueff, Knight and Hoover)

4. इसमें 'समय' का ध्यान नही रखा गया. केन्स मॉडल मे Timelags को उचित स्थान नही दिया. (Haberler) उनका गुणक बहुत हद तक काल्पनिक है (Haberler).

5. केन्स ने तो मजदूरी और रोजगार में कोई सबध होना ही भुठला दिया. केन्स ने कन्ट्रोल व प्रगतिशील करो पर आवश्यकता से अधिक बल दिया (Von Mering O.).

6. केन्स की नीतियो में से बहुत सी नीतिया सफल नही रही कभी-कभी सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोजन वृद्धि से निजी क्षेत्रों को प्रेरणा मिलने के स्थान पर भय उत्पन्न हो जाता है (Haney).

सबसे अधिक आलोचना तो केन्स की हेजलिट (Henry Hazlitt) ने की है. वे तो avowed anti-Keynesian या उन्होंने तो केन्स का विरोध करने की शपथ ले रखी है उन्होने एक पूरी पुस्तक "The Failure of New Economics" मे केन्स के विचारो की प्रत्येक लाइन व प्रत्येक विचार व अध्याय की आलोचना की. उनका यह कथन तो बहुत ही गम्भीर है

> "केन्स ने जो कुछ भी मौलिक रूप मे प्रस्तुत किया वह सही नही था और जो कुछ भी सही कहा वह मौलिक नही था."

परन्तु, इस कथन मे हेजलिट ने अतिशयोक्ति से काम लिया. केन्स का स्थान अर्थशास्त्र मे हमेशा बना रहेगा.

अध्याय : 15

एवसी डोमर का विकास मॉडल

Evsey Domar's Growth Model

I. प्रस्तावना

II. मॉडल की मान्यतायें व आधारभूत विशेषतायें.

III विकास मॉडल.

(a) उत्पादन क्षमता व आय

(b) कुछ आधारभूत समीकरण.

(c) और अधिक व विस्तृत विश्लेषण,

IV. निर्णायक वाक्य.

अध्याय : 15

एवसी डोमर का विकास मॉडल

Evsey Domar's Growth Model

I. प्रस्तावना :

एवसी डोमर अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं. इनका नाम बहुधा हरोड के नाम के साथ जुड़ा रहता है हरोड इंगलिश अर्थशास्त्री हैं. दोनों के मॉडल अलग-अलग बनाये गए, परन्तु उनमें इतनी अधिक समानताएँ रही कि हम "हरोड-डोमर मॉडल" को एक ही नाम से बोलने लगे. डोमर ने 1947 मे American Economic Review, मार्च 1947 में इस मॉडल का विकास किया. परन्तु उनका कथन है कि उन्होंने हरोड के मॉडल को अपना मॉडल बनाने के बाद ही देखा, इसलिए उनके विचार हरोड के विचारों से प्रभावित नही है (z)

II. मॉडल की मान्यताएँ व आधारभूत विशेषताएँ

1. डोमर का मॉडल, केन्स की विचारधारा पर आधारित है, परन्तु डोमर केन्स के मॉडल में कई कमियाँ बताते हैं जहाँ केन्स का कथन था कि बेरोजगारी उदय होने का मुख्य कारण 'जमाखोरी' (hoarding) है, वहाँ डोमर का कथन है कि केवल 'जमाखोरी' समाप्त करने (अर्थात् विनियोजन करने) से पूर्ण रोजगार उत्पन्न नही हो जाएगा.
2. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने विनियोजन वृद्धि पर जोर दिया तथा उनका विश्वास था कि माँग तो कभी कम होगी ही नही. केन्स ने माँग वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया पर विनियोजन की मात्रा व दर क्या होना चाहिए इस पर ध्यान नही दिया डोमर ने विनियोजन के दोनों पक्षों, माँग उत्पन्न करने का पक्ष या आय बढाने का पक्ष व पूर्ति बढाने का पक्ष या उत्पादन क्षमता बढाने के पक्षों पर समुचित ध्यान दिया.

See · 1 Evsey Domar : Essay in the Theory of Economic Growth, Oxford 1957.

2· Evsey Domar : "Expansion and Employment", Okun Richardson op. cit.

3. डोमर की मुख्य मान्यताएँ (assumptions) यह हैं

   (a) देश में पूर्ण रोज़गार आय के स्तर मौजूद है अर्थात् इस मॉडल में मुख्य रूप से उस अर्थ व्यवस्था का अध्ययन है जो पूर्ण रोज़गार की स्थिति पर पहुँच गई है मॉडल मे यह बताया गया है कि यह स्थिति कैसे कायम रखी जा सकती है

   (b) राज्य का अर्थ-व्यवस्था मे कोई हस्तक्षेप नही है

   (c) देश का विदेशो से व्यापार नही होता है (अर्थात् closed economy है)

   (d) आर्थिक समायोजन का कार्य तत्काल हो जाता है (There are no lags in adjustments).

   (e) बचत करने की औसत व सीमान्त क्षमताएँ बराबर है

   (f) बचत की क्षमता व पूँजी—कोएफीशिएन्ट' (Capital coefficient mean ratio of capital-stock to output) समान रहते है.

   (g) हर घटक को शुद्ध रूप मे प्रस्तुत किया गया है, जैसे शुद्ध बचत, शुद्ध विनियोजन

III विकास मॉडल

III. A उत्पादन क्षमता व आय

1. डोमर ने इस बात का अध्ययन किया कि पूर्ण रोज़गार की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है और फिर कैसे कायम रहती है इसका समाधान उन्होंने राष्ट्रीय आय की दृष्टि मे पाया डोमर ने बताया कि जब हम देश में विनियोजन करते है तो देश मे उत्पादन क्षमता' (productive capacity) मे वृद्धि होती है. अगर देश म निरन्तर पूर्ण रोज़गार की स्थिति को बनाए रखना है तो इस 'उत्पादन क्षमता' के बराबर वास्तविक आय का सृजन होना चाहिए वास्तविक आय बढ़ने से विकास बढ़ता है.

2. *वास्तविक आय दो रूप से बढ सकती है (1) या तो मूल्य घटे या (2)* स्थिर मूल्यो पर मौद्रिक आय बढ जाए. डोमर मूल्यो को गिराकर वास्तविक

---

3 Evsey Domar . Capital Extension, Rate of Growth and Employment Economitica Vol. XIV p. 142-145 Apil, 1946

★ देखिए . Ref no, 2 above. p, 116

आय को बढाने के पक्ष मे नही है, क्योकि इससे सार्वजनिक ऋण का भार बढ जाते है और पूर्ण रोजगार की सम्पूर्ण योजना असफल हो जाएगी.

3. डोमर का कथन है कि अगर पूर्ण रोजगार को कायम रखना है तो (i) वास्तविक व मौद्रिक आय एक ही दर से बढना चाहिए तथा (ii) वास्तविक आय व उत्पादन क्षमता भी एक साथ बढना चाहिए.

III. B. कुछ आधारभूत समीकरण Some fundamental equations.

1. डोमर चाहते है कि विनियोजन मे जितना पूर्ति का सृजन हो (productive capacity) उतनी ही मात्रा मे माँग का सृजन हो (real income) (Procuctive capacity should generate equal amount of real income).
2. किसी भी देश मे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, विनियोजन की मात्रा (Investment or I) × सभावित उत्पादकता (potential productive average productivity of investment or δ) के बराबर होती है अर्थात् Productive capacity is equal to the amount of investment (I) multiplied (×) productivity (δ or sigma) = $I\delta$
3. देश में यह उत्पादन क्षमता जो भी आय का सृजन करती है वह माँग उत्पादन करती है माँग आय मे परिवर्तनो के प्रभावस्वरूप उत्पन्न होती है और स्वय आय मे परिवर्तन विनियोजन की दर मे परिवर्तन तथा उसके गुणक (Multiplier) पर निर्भर करते है और यह परिवर्तन उपभोग व बचत की क्षमताओ पर निर्भर करते है
4. हम अर्थशास्त्र मे राष्ट्रीय आय को Y से दर्शाते है तथा उसमे होने वाले परिवर्तनो को $\triangle$ (डेल्टा) से दर्शाते है. यहाँ हम बचत क्षमता (Propensity to save) को $\propto$ (अल्फा) से दर्शाते है तथा विनियोजन में होने वाले परिवर्तनो को $\triangle I$ से दर्शाते है.
5. अब हम विनियोजन व तदनुसार आय मे परिवर्तनो को इस प्रकार डोमर के अनुसार प्रस्तुत कर सकते है
   $\triangle Y = (\triangle I)\ 1/\propto$ अर्थात् अगर हम विनियोजन में होने वाले परिवर्तन को 'गुणक' से गुणा कर दें तो आय मे होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के बराबर होगा.

6. पूर्ण रोजगार जब कायम रहेगा तब पूर्ति (S) व मांग (d) बराबर हो पूर्ति का अर्थ उत्पादन क्षमता या $I\delta$ से है और मांग का अर्थ आय में वृद्धि से अर्थात् $(\triangle I)\ 1/\alpha$ से है

   इस प्रकार से स्थायी विकास के लिए

   $$(\triangle I)\ 1/\alpha = I\delta$$

   की स्थिति मौजूद रहना चाहिए.

7. इस समीकरण को हम सरल रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं हम दोनों तरफों को I से भाग दे सकते हैं और α से गुणा कर सकते हैं अब यह समीकरण यह हो जाएगा

   $$\triangle I/I = \alpha\delta$$

साराश के रूप में डोमर का कथन है ·

> "The maintenance of a continuous state of full employment requires that investment and income grow at a constant annual percentage (or compound interest) rate equal to the product of the marginal propensity to save and the average productivity of investment"
>
> (अर्थात् अगर अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रहना है तो यह आवश्यक है कि विनियोजन और आय को चक्रवृत्ति ब्याज की दर की भाँति बढना चाहिए अर्थात् उस दर से बढना चाहिए जो दर बचत की सीमान्त क्षमता और विनियोजन की औसत उत्पादकता दर के गुणों के बराबर हो

8. डोमर ने इसे और अच्छी तरह से समझाया : अगर उत्पादक क्षमता (δ) को 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष माने, बचत क्षमता (α) को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष मानें और राष्ट्रीय आय को (Y) 150 बिलियन डालर प्रतिवर्ष मानें, तो 18 बिलियन प्रतिवर्ष का विनियोजन आवश्यक होगा (बचत के बराबर विनियोजन हो तो $150 \times \frac{12}{100} = 18$)

अब इस विनियोजन से 4 5 बिलियन की उत्पादक क्षमता वृद्धि होगी ($I \times \delta = 18 \times \frac{25}{100} = 4\ 5$). अब मांग या आय को भी इतनी ही मात्रा में बढना चाहिए. इस प्रकार से माग व पूर्ति में समन्वय आ जाएगा.

Quoted from Okun & Richardson's book p 115-116

यहाँ मांग (आय में वृद्धि) 3 प्रतिशत है ($\frac{4.5}{150}=3\%$) और ∝δ भी तीन प्रतिशत है ($\frac{12}{100}\times\frac{25}{100}$) तब पूर्ण रोजगार कायम रहेगा.

III C : और अधिक व विस्तृत विश्लेषण Further explanation

1 डोमर का इस प्रकार से केन्म से भिन्न मॉडल है केन्स के अनुसार "पूर्ण रोजगार राष्ट्रीय आय पर आधारित है" डोमर कहते है कि यह पर्याप्त नही है कि राष्ट्रीय आय का स्तर समान रखा जाए अर्थात उसे गिरने न दिया जाए उनके शब्दो मे "आज 1941 की राष्ट्रीय आय पूर्ण रोजगार प्रदान नही कर सकती किसी भी देश मे श्रम के रोजगार की मात्रा राष्ट्रीय आय व उत्पादन क्षमता के अनुपात पर निर्भर है"

2 डोमर देश में न तो excess capacity चाहते है और न excess income चाहते है. उनके अनुसार अगर पूँजी निर्माण व विनियोजन से केवल "उत्पादन क्षमता" मे वृद्धि होती है और आय म नही होती तो इसके यह परिणाम होगे कि पूँजी व श्रम को पूर्ण रोजगार नही मिलेगा उदाहरणत अगर मकानो मे विनियोजन से केवल "क्षमता" का सृजन होता है और आय का नही होता तो

(i) नये मकान पूरी तरह से या आशिक रूप से खाली रहेंगे,

या (ii) नये मकानो में लोग पुराने मकानो को छोडकर आयेगे पर किराया वही रहेगा,

या (iii) या अगर नये मकानो को अधिक किराया मिलता है तो किसी अन्य कार्य पर (जैसे कपडो पर, खर्च पर) कम धन व्यय किया जायेगा, जिससे कपडे के व्यापार मे बेरोजगारी फैलेगी

डोमर के अनुसार जहाँ कही भी excess capacity रहेगी वहाँ या तो पूँजी को श्रम के स्थान पर प्रतिस्थापन्न के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप या फिर अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (जैसे कपडो के व्यापार के उपरोक्त उदाहरण मे) श्रम बेरोजगारी फैलेगी.

3. परन्तु डोमर हर प्रकार की excess capacity या अत्युत्पादक क्षमता को बुरा नही मानते. वे बतलाते है कि प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था म किसी न किसी क्षेत्र मे अधिक उत्पादन क्षमता हो जाएगी. जैसे, अगर प्लास्टिक के बैगो का प्रयोग बढ जाए तो चमडे के बैगो के उद्योग मे अधिक क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. यह तो विकास की निशानी है

डोमर तो यह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति नही होना चाहिए जिसमें कि एक ओर तो खाली मकान रहे और दूसरी ओर बेरोजगारी के कारण मकान को किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति उन मकानो को किराये पर न ले सकें

4. डोमर के अनुसार बेरोजगारी के फैलने का मुख्य कारण आय व विनियोजन का तीव्र गति से न बढ़ना होता है डोमर के अनुसार "आज का विनियोजन कल की बचतो से अधिक होना चाहिए" (Investment must grow at an increasing absolute rate (or constant compound interest rate) equal to the propersity to save (α) times the inverse of the capital coefficient (δ) (या देखिए III B का 7 वाँ पैराग्राफ).

5. डोमर के अनुसार अगर देश मे α या बचत क्षमता घट रही हो तो विनियोजन स्थिर रहे तो भी आय व रोजगार बढ़ सकता है (केन्स ने इस रूप मे कहा था कि देश मे बढ़ते हुए उपयोग से स्थिर विनियोजन पर भी रोजगार बढ़ सकता है– दोनो बातें एक ही हैं)

परन्तु अगर α बढ़ रही हो तो इसके गम्भीर परिणाम होते हैं क्योंकि इससे पूर्ण रोजगार बनाए रखना इसलिए कठिन हो जाएगा कि देश में पर्याप्त मात्रा मे विनियोजन नही होगा

6. डोमर का कथन है कि पूँजीवादी समाज मे जहाँ α को आसानी से परिवर्तित नही किया जा सकता, वहाँ आय व रोजगार के उच्चस्तर केवल अधिक विनियोजन मे ही प्राप्त किए जा सकते हैं परन्तु विनियोजन अपने δ प्रभावो के कारण एक 'मिश्रित वरदान' है (अर्थात् कभी-कभी अभिशाप बन सकता है) बगैर पर्याप्त विनियोजन के बेरोजगारी फैलेगी और आज जो विनियोजन पर्याप्त है कल वह अपर्याप्त हो जाएगा.

डोमर का कथन है कि विनियोजन के दोहरे प्रभाव होते है : उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और आय मे भी वृद्धि होती है जहाँ तक दोनो बराबर रहते हैं ठीक है कभी-कभी आय भी उत्पादन क्षमता से अधिक बढ सकती है परन्तु आय मे वृद्धि अस्थायी होती है जब कि उत्पादन क्षमता मे वृद्धि स्थायी रहती है इसलिए विनियोजन बीमारी (बेरोजगारी) का इलाज भी है और उसे और बढ़ा भी देता है. (So that as for as unemployment is concerned, investment is at the same time a cure for the disease and the cause of even greater ills in the future).

7 डोमर वतलाते हैं कि आजकल विकासशील समाजवादी देशो मे विनियोजन δ प्रभावो को प्राप्त करने के लिए (उत्पादन क्षमता बढाने के लिए) किया जाता है जब कि U. S A. जैसे पूँजीवादी देश मे विनियोजन "गुणक प्रभावो" multiplier effects को प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है अर्थात् आय व रोज़गार बढाने के लिए किया जाता है

रोज़गार वृद्धि व निरन्तर विकास के लिए 'हम δ को शून्य पर लाकर निर्वाण की स्थिति प्राप्त नही कर सकते" (It would be a defeatist solution to reduce δ to zero and also abolish technical progress, thus escaping from unemployment into the nirvana' of a stationary state) सही इलाज तो ∝ को कम करना होगा. उन्नत तकनीक व बचतें स्वय विकास कारक नही होती, वे तो विकास करने को शक्ति को हमारे हाथ मे देती है. सही मायनो मे विकास तो आर्थिक नीतियो पर निर्भर करता है

> "It must be remembered that neither technology, nor of course saving guarantee a rise in income what they do is to place in our hands the power and the ability of achieving a growing income And just as, depending on the use made of it, any power can become a blessing or a curse, so can saving and technological progress, depending on our economic policies, result in frustration and unemployment or in an everexpanding economy"

IV Concluding Remark.

डोमर ने निराशावादी युग में लिखा वे स्थैगिक स्थिति के आने के भय से पीडित नही थे, परन्तु उनके अनुसार "आर्थिक निर्वाण न तो असम्भव है और न ही वह सुनिश्चित है" उन्हें इस बात पर बहुत अधिक आश्चर्य था कि इतने अधिक व महान अर्थशास्त्रियो को स्थैगिक स्थिति का भय था ही क्यो

उन्होने लिखा

> "Economic salvation is not impossible, neither is it assured '. ...." why in spite of remarkable

rapid growth the vision of the stationary state hung so heavily over the thinking of the great Masters of the last century and still preoccupies many of our contemporaries, is more than I can explain Even my more broadminded colleagues who love growth, are willing to grant her only a reprieve, but not a pardon ....".[1]

1. Quoted from H. W. Singer's "International Growth and change" p. 8. Mc Graw Hill.

अध्याय : 16

हरोड का विकास मॉडल

Harod's Growth Model

I साराश : विकास का अर्थ

II बचतो की पूर्ति

- (a) ब्याज क्यों दिया जाता है.
- (b) बचतें तीन उद्देश्यो के कारण होती हैं
- (c) स्थैगिक समाज में बचतें.
- (d) प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में बचतें.

III प्रमुख मान्यताएँ.

III का साराश हरोड की तीन विकास दरो के समीकरण.

- (i) वास्तविक विकास की दर
- (ii) विकास की वाछनीय दर.
- (iii) विकास की प्राकृतिक दर.

इन दरो में भिन्नता तथा असंतुलन और विकास

IV. का साराश

विदेशी व्यापार व विकास के समीकरण या खुली अर्थव्यवस्था में विकास समीकरण

हरोड मॉडल सरल भाषा मे ·

हरोड, डोमर मॉडल की समीक्षा क्या हरोड डोमर मॉडल कम विकसित देशो मे लागू हो सकता है.

विभिन्न अर्थशास्त्रियो के विचार

1. बेन्जामिन हिगिन्स.
2. मीयर तथा बाल्डविन.
3. सी० पी० किन्डल बरजर.
4. एच० डब्ल्यू० सिंगर.
5. एस० बी० मेहता.
6. प्रो० केनेथ के० कुरिहारा.
7. इएगर.
8. ऐरिक लुडबर्ग.

अन्य आलोचनाएँ

प्रो० जे० के० मेहता की प्रशसात्मक समीक्षा.

अध्याय : 16

हरोड का विकास मॉडल

Harod's Growth Model

"हरोड का मॉडल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों व मार्क्स के मॉडलो को आगे बढाता है हरोड ने अपने मॉडल म शुम्पीटर की बहुत सी बातों को शामिल किया उनके मॉडल मे उन तत्वो का वर्णन है जो विकास कारक व विकास म बाधक हैं उन्होने यह अध्ययन किया कि विकास कैसे अनियमित होता है और फिर नियमित हो जाता है"

—बेन्जामिन हिगिन्स (प्र० 144)

हरोड का विकास मॉडल उनकी पुस्तक Towards Dynamic Economics म पूर्णरूप से वर्णित ह इस पुस्तक के पृष्ठ 20 पर उन्होंने साफ लिख दिया कि "मै सयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी योरोप व अन्य विकसित देशो में दिलचस्पी रखता हूँ '

I साराश विकास का अर्थ

विकास के सबध म उनका स्पष्ट मत है कि प्रवैगिक साम्य का उत्पन्न करना ही विकास उत्पन्न करता है वे चाहते है कि केन्स के "सामान्य सिद्धान्त" को प्रवैगिक अर्थशास्त्र के उपयुक्त बनाकर ही उसे विकास का सिद्धान्त बनाया जा सकता है

हरोड के विकास मॉडल मे तीन प्रमुख तत्त्व है, जो इस प्रकार है

- (i) देश की जनशक्ति,
- (ii) प्रतिव्यक्ति उत्पादन तथा,
- (iii) उपलब्ध पूँजी की मात्रा

हरोड के अनुसार किसी भी देश मे प्रति व्यक्ति उत्पादन देश के (i) प्राकृतिक साधनो, (ii) तकनीक व (iii) अविष्कारो (जिससे उनका आशय नव प्रवर्तनो से है) पर निर्भर रहता है

हरोड के अनुसार अविष्कार तीन प्रकार के हो सकते है

- (i) तटस्थ अविष्कार यह वे अविष्कार होते है जिनमे पूँजी गुणक (Capital Co-efficient) वही रहता है अर्थात् पूजी का उत्पादन से अनुपात वही रहता है

(ii) पूंजी-बचाने वाले अविष्कार होते हैं जिनसे पूंजी-गुणक Capital Co-efficient कम होता है.

(iii) श्रम बचाने वाले अविष्कार हो सकते है (जो वे देश अपनाते है जहाँ श्रम कम होते है) और इनसे Capital Co efficient बढता है

II. बचतो की पूर्ति :

A. ब्याज क्यों दिया जाता है ?

हरोड कहते है कि बहुत पुराने दिनो मे बचतो को प्रोत्साहन देने वाले ब्याज को बुरा माना जाता था बाद मे ब्याज के उत्पन्न होने का मुख्य कारण 'समय पसन्दगी' बताया गया (Time preference was put forward as explanation for emergence of interest). हरोड इस विचार को गलत मानते है कि 'समय पसन्दगी' ब्याज की दर निर्धारित करती है वे प्रो० पीगू के इस कथन से सहमत है कि यह विचार धारा 'दृष्टि दोष' के कारण उत्पन्न हुई है (It was explained as occuring due to defective telescopic faculty) वर्तमान समय पसन्दगी के तीन कारण बताये जाते थे

(i) भविष्य अनिश्चित होता है,

(ii) वर्तमान की भौतिक आवश्यकताओ को सतुष्ट करने की इच्छा बलवती होती है, तथा

(iii) लालच भी 'समय पसन्दगी' उत्पन्न करता है [1]

हरोड 'समय पसन्दगी' को ब्याज निर्धारण करने वाला तत्व नही मानते उनका कथन है कि ब्याज तो तब ही उत्पन्न होगा जबकि कोई भी व्यक्ति भविष्य को Discount न करता हो [2] हरोड का कथन है कि

> "समय पसन्दगी मानव कमजोरी है. यह प्राथमिक अवस्थाओ मे रहने वाले व्यक्तियो मे अधिक होती है और पिछडी हुई सभ्यता का द्योतक है" (Time preference in this sense is a human infirmity, probably stronger in primitive than in civilized man [3] A strong time preference is indicative of a low degree of civilization)[4]

हरोड के अनुसार ब्याज को उत्पन्न करने का मुख्य तत्व उत्पत्ति ह्रास नियम है लोग अपने धन का उपयोग तब करेंगे जबकि भविष्य मे उन्हे द्रव्य की उपयोगिता अधिक नजर आए [5]

---

1. Pigon quoted from Economics of welfare p. 25.
2. See : Harrod : 'Towards Dynamic Economics' p. (i) p. 37 (ii) p. 39 (iii) p. 37 (iv) p. 53 (v) p 40.

B : बचतें तीन उद्देश्यो के कारण उत्पन्न होतीं हैं.

(i) Hump savings ये वे बचते होती है जो कोई व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओ को सन्तुष्ट करने के लिए रखता है, अर्थात् वृद्धावस्था के लिए पेंशन जैसी व्यवस्था करता है

(ii) Inheritence saving विरासत में देने के लिए बचतें : कुछ बचते हर व्यक्ति अपनी सतान या उत्तराधिकारियो को देने के लिए करता है

(iii) Corporate savings औद्योगिक सस्थानो की बचतें : व्यापारिक व औद्योगिक सस्थानो द्वारा भी बचतें की जाती है जो कि वे अपने सस्थानो के विकास के लिए करते है

C · Savings in static society स्थैगिक समाज में बचतें :

स्थैगिक अर्थव्यवस्था वह होती है जिसम साधनो, जनसख्या, तकनीक, व रुचियो और आदतो मे कोई परिवर्तन नही होता

ऐसी स्थिति मे Hump savings शून्य रहेगी जो व्यक्ति आज जवान है वे बुढापे के लिए बचाएगें परन्तु बूढे आदमी अपनी बचतो को खर्च करेंगे और दोनो की माना बराबर रहेगी [1]

Corporate या औद्योगिक सस्थानो की बचतें भी शून्य रहेंगी. कुछ फर्म तो बचत कर रही होगी, परन्तु इनकी मात्रा उतनी ही होगी जितनी कि अन्य फर्म हानि उठा रही होंगी [2]

केवल कुछ Inheritence savings उत्तराधिकार के लिए बचतें होंगी क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चो के शैशव काल की सुरक्षा चाहेगा और यह चाहेगा कि उसके बच्चे कम से कम वर्तमान जीवन स्तर तो कायम रख सकें [3]

ऐसी स्थिति म स्थिर ब्याज की दर पर बचतो की माँग ही नही होगी जो भी बचतें होंगी उनके प्रयोग मे लेने के लिए निरन्तर गिरती हुई ब्याज की दर की आवश्यकता[4] तो रहेगी गिरती हुई ब्याज की दर से उत्पादनकर्ता और जटिल उत्पादन प्रणाली अपनाएगे (more and more round-about methods of production) क्योकि पूजी उधार लेना सस्ता हो जाएगा इससे Corporate बचते बढेंगी और ब्याज की दर और अधिक गिर जाएगी

Cf : Harrod : op. cit (i) p 45 (ii) p 48 (iii) p. 46. (iv) p 49.

हरोड का कथन है कि अगर ब्याज की दर बढा दी जाए तो बचतें कम हो सकती हैं :

इसका कारण यह है कि अगर ब्याज की दर बढ जाए तो एक निश्चित ब्याज की आय प्राप्त करने के लिए अब उपभोग मे कम कटौती करनी पड़ेगी (हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं माना कि एक व्यक्ति को पाँच साल बाद 1000 रु० की आवश्यकता है और 4 प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है तो लगभग 825 रु० जमा करके वह पाँच साल बाद 1000 रु० प्राप्त कर लेगा अब अगर ब्याज की दर 6 प्रतिशत हो जाए तो लगभग 750 रु० जमा करके ही वह पाँच साल बाद 1000 रु० प्राप्त कर लेगा)

परन्तु यह प्रभाव, हरोड के अनुसार जीवन के शुरू के काल मे होता है अन्त में तो अधिक ब्याज की दर पर ही अधिक बचत करने की प्रेरणा होती है अल्प काल में ही ब्याज की दर बढने मे बचते कम हो सकती हैं

D : Savings In Dynamic Societies · प्रवैगिक अर्थ व्यवस्था में बचतें :

अगर अर्थव्यवस्था प्रवैगिक है जहाँ जनसख्या बढ रही हो (परन्तु तकनीक स्थिर हो) तो तीनो प्रकार की बचते बढेंगी. ऐसी व्यवस्था मे पूजी की आवश्यकता बढेगी, और उसीके कारण 'औद्योगिक सस्थानों' की बचतें बढेंगी. जनसख्या बढने से hump savings भी अनुपातिक रूप से बढेगी और अधिक बच्चो के लिए विरासत मे देने के लिए भी बचतो को बढाना होगा (हरोड यह सब धनी देशो के संदर्भ मे कहते हैं)

ऐसी अवस्था मे बचते पूँजी की आवश्यकता से बढ जायेंगी और ब्याज की दर गिर जायेगी परन्तु यह इतनी नही गिरेगी जितनी कि स्थैगिक अर्थव्यवस्था मे गिर सकती है

जिस प्रवैगिक अर्थव्यवस्था मे जनसख्या व तकनीक दोनो बढती है वहाँ भी तीनो प्रकार की बचतें बढेंगी

III. The Fundamental Equations.

1 प्रमुख मान्यताएँ :

हरोड ने जो अपने समीकरण प्रस्तुत किए वे कुछ मान्यताओ पर आधारित है, जो इस प्रकार है

इस प्रश्न का वर्णन हरोड की पुस्तक के पृष्ठ 49-54 पर आधारित है.

(i) हरोड यह मानते है कि लोग जितनी मात्रा मे बचत करने का सोचते है उतनी ही कर लेते है. जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार फल प्राप्त हो जाते है अर्थात्

(a) Intended savings (ex-ante savings) अपेक्षित बचते = Actual savings (ex-post savings) या वास्तविक बचते

(b) Intended investment या अपेक्षित विनियोजन = Actual investment वास्तविक विनियोजन

(c) बचते और विनियोजन बराबर रहेगे

(ii) हर उत्पादनकर्ता (पूर्तिकर्ता) या उपभोगकर्ता (माँगकर्ता) साम्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहता है

(iii) उन्होने अपने मॉडल को लागू होने के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति के मौजूद होने की मान्यता की है

(iv) उन्होने यह माना कि राज्य कोई हस्तक्षेप नही करता

(v) उन्होने मूल्य स्तर, ब्याज की दर व पूँजी-श्रम अनुपात तथा पूँजी-उत्पादन अनुपात को स्थिर माना

(vi) उन्होने विदेशी व्यापार न होने की कल्पना की अर्थात् पहले उन्होने अपने समीकरणो को बगैर विदेशी व्यापार के परिणामो को ध्यान में रखकर लिखा, परन्तु बाद मे उसका समावेश किया है

(vii) बचत व विनियोजनो को उसी वर्ष की आय मे से होता हुआ माना तथा इनको शुद्ध रूप में (In Net terms) माना

III का सारांश

हरोड की तीन विकास दरो के समीकरण :

वास्तविक विकास की दर Actual growth rate.
को हैरोड ने निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझाया है यह वह विकास की है जिस दर पर देश विकास कर रहा है.

$$GC = S$$

G = यह आय में वृद्धि की दर है जो किसी निश्चित काल मे उत्पन्न होती है (हम इसको $\Delta Y/Y$ से भी समझ सकते हैं (Δ का परिवर्तन होता है Y आय के लिए प्रयोग किया जाता है).

C= C उस दर को बतलाती जो पूंजी-उत्पादन का संबध बतलाती है C is incremental capital output ratio (या $I/\triangle Y$ या बढ़ी हुई आय ($\triangle Y$) में से विनियोजित भाग I)

S= यह बचत को दर्शाता है अर्थात् आय म से बचाया हुआ भाग S/Y

वास्तव में इसका अर्थ यह है कि वास्तविक बचतें और वास्तविक विनियोजन बराबर होंगे (Ex post savings are equal to ex post investment)

उपरोक्त सबध आय के परिवर्तनो व आय पर निर्भर करता है बचत (S) आय (Y) पर निर्भर रहती है, विनियोजन (I) आय म वृद्धि पर निर्भर रहता है (on $\triangle Y$) और यही acceleration principle है

2 विकास की वाछनीय दर The warranted rate of growth

हरोड ने अपना दूसरा समीकरण, जो निरन्तर विकास को उत्पन्न करने वाला है इस प्रकार से दिया

$$Gw\ Cr = S$$

'यह वह विकास की दर है जो कि अगर प्राप्त करली जाय तो साहसियो की मनोवृत्ति इस प्रकार बना देगी कि वे इसी प्रकार से विकास करते रहन के लिए प्रेरित होग '

यह विकास की वह दर है जो कि साहसियों के लिए परम उपयुक्त है, वे इस विकास दर से परम सतुष्ट रहत है परन्तु यह आवश्यक नही है कि इस विकास दर को प्राप्त करने के पश्चात् समस्त 'अनैच्छिक बेरोजगारी' समाप्त हो जाए अन्य शब्दो म इस विकास की दर प्राप्त हो जाने पर भी यह बेरोजगारी बनी रहती है

$$Gw\ Cr = S$$

Gw = Warranted rate of growth, विकास की वाछनीय दर जिसमें पूजी का पूर्ण उपयोग हो जाता है

Cr = (i) The requirement of capital for warranted growth or (ii) required capital-out put ratio or (iii) The value of capital required to produce a unit of inrement of output
अर्थात् Gw को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यक मात्रा ग

(ii) आवश्यक पूँजी-उत्पादन दर या (iii) अतिरिक्त उत्पादन को पैदा करने की आवश्यक पूँजी या Value of $I/\triangle Y$.

S = आवश्यक बचत की क्षमता की मात्रा या S/Y

इस समीकरण का अर्थ है कि अगर अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास की दर से बढ़ना हो (Gw) अर्थात उस दर से बढ़ना हो जिस दर से उत्पादन क्षमता का पूर्ण विकास हो, तो आय को S/Cr प्रति वर्ष की दर से बढ़ना चाहिए या अन्य शब्दों म $Gw = S/Cr$

पूर्ण रोज़गार प्राप्त करने के लिए,

$G = Gw$ और

$C = Cr$

3. विकास की 'प्राकृतिक दर' The natural rate of growth

यह दर इस समीकरण द्वारा दर्शायी जा सकती है या इस समीकरण के प्राप्त होने पर प्राप्त होती है

$$Gn\,Cr = S$$

यह विकास की वह दर है जो किसी देश के लिए अधिकतम है. इसकी सीमा देश के प्राकृतिक साधनों, श्रम की उपलब्धि तथा तकनीकी उन्नति पर निर्भर रहती है

इस विकास दर को प्राप्त हो जाने पर देश म पूर्ण रोज़गार कायम हो जाता है, मुद्रा स्फीति नहीं रहती तथा विकास की दर स्थिर व निरन्तर प्राप्त होती रहने वाली होती है.

इन दरों में भिन्नता तथा असतुलन और विकास :

1. जैसा कि हम उपर देख चुके हैं हरोड का कथन है कि निरन्तर विकास के लिए $G = Gw$ और $C = Cr$ की दशाएँ सतुष्ट होना चाहिए अगर ऐसा रहेगा तो जितनी मात्रा में साहसियों की पूँजी की आवश्यकता होगी उतनी ही मात्रा में बचतें प्राप्त हो सकेंगी और इससे "प्रवैगिक साम्य की स्थिति" उत्पन्न होगी और यही निरन्तर व स्थायी विकास होगा
2. अगर असतुलन के कारण विकास बहुत तेज होता है तो वह होता चला जायेगा, और अगर मदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो मन्दी आती चली जाएगी
   (1) अगर 'वास्तविक विकास दर,' 'वाछनीय विकास दर' से अधिक हो (If G is more than Gw) तो वास्तविक पूँजी वाछनीय

पूंजी दर से कम पड जाएगी, इसलिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी जब और पूंजी के आर्डर दिए जाएँगे अर्थात् और मशीनो के आर्डर दिए जाएँगे तो इससे और विकास होगा अर्थात् G, Gw से और अधिक हो जाएगी जब G, Gw से अधिक हो, मुद्रा स्फीति होगी. $G > Gw$

(ii) अगर G, Gw से कम हो या विकास की वास्तविक दर, वाछनीय दर से कम हो तो वास्तविक पूंजी (C) वाछनीय पूंजी (Cr) से अधिक होगी इस कारण पूंजीगत मशीनो के आर्डर कम किये जाएँगे और इससे G की दर और गिर जायेगी तथा G, Gw से लगातार कम होती जायेगी, जब G, Gw से कम हो मदी फैलेगी

इस प्रकार से विकास साम्य पथ से एक बार हटा, अर्थात् अधिक या कम हुआ तो ऐसा होता चला जाएगा.

> 'Thus around the line of advance which, if athered to, would alone give satisfaction, centrifugal forces are at work, causing the system to depart further and further from the required line of advance"

3. Gn का विचार प्रस्तुत कर के, हरोड ने विकसित अर्थ-व्यवस्था मे उच्चावचन, बेरोजगारी व मुद्रा स्फीति की स्थितियों को समझाया. $Gw > Gn$

उन्होंने बताया कि अगर Gw (वाछनीय विकास दर) Gn से (विकास की प्राकृतिक दर) अधिक होती है तो मदी आएगी (इसी प्रकार से जब G, Gw से कम हो). ऐसा तब होता है जब कि जनसख्या मे वृद्धि बन्द हो जाए, तकनीकी उन्नति न हो या नये साधनो की खोज न हो

इसके विपरीत जहाँ Gw, Gn से कम हो (या दूसरे शब्दो मे Gn, Gw से अधिक हो) या जहाँ G, Gn से अधिक हो तो ऐसी विकास अवस्था मे तेजी आएगी. $Gn > Gw$ स्फीति

4. परन्तु विकास के उत्तरोत्तर बढने या मदी के उत्तरोत्तर बढने की सीमाएँ होती हैं. हरोड के अनुसार

   (1) G, Gn से ऊपर, बहुत अधिक मदी के काल को छोड, नही जा सकती.

See : Ch. I.I Harrod. op-cit. p 86 for above quotation

(ii) जब G, Gn तक पहुँच जाती है तो ऐसे समय मे Gw भी बढ जाती है.

(iii) इसी प्रकार से एक न्यूनतम सीमा से नीचे अर्थव्यवस्था नीचे नही जा सकती विकास शून्य की सीमा तक कभी नही पहुँच सकता क्योंकि पूँजी निर्माण कभी शून्य नही हो सकता जब G या वास्तविक विकास दर बहुत नीचे आ जाती है तो साहसियो का प्राकृतिक साधनो सबधी ज्ञान उन्हे अवगत करा देता है कि यह व्यवस्था अब और नीचे नही गिर सकती विकास सम्बन्धी अनुमानो म फिर उनमें आशावाद आने लगता है और फिर विकास स्तर उपर उठने लगता है.

हरोड के अनुसार पूर्ण रोजगार साम्य की आपेक्षित स्थिति $Gn = Gw = G$ होना चाहिए हरोड के मॉडल का साराश यह है कि मुद्रा स्फीति के दिनो मे S बढाना चाहिए (बचत अच्छी चीज है) तथा मदी के दिनो मे बचत बढाना या 'S' घटाना चाहिए

IV का साराश

विदेशी व्यापार व विकास के समीकरण या खुली अर्थ-व्यवस्था मे विकास समीकरण Foreign trade and fundamental equations or fundamental equations for an open economy.

रोड ने "विदेशी व्यापार न होने" की मान्यता को बाद मे हटाया. तत्पश्चात् न्होंने समीकरणो को यह रूप दिया

(i) $G C = S - b$

(ii) $Gw\ Cr = S - b$

(iii) $Gn\ Cr = S - b.$

'b' से यहाँ पर विदेशी व्यापार के भुगतान सन्तुलन का अर्थ लिया जाता है. एक ऐसे देश मे जहाँ Gw, Gn से अधिक रहता है वहाँ मंदी व्यापक हो जाती है ऐसे समय 'b' अगर धनात्मक हो अर्थात् भुगतान सन्तुलन पक्ष में हो तो इस मदी को दूर करने मे मदद मिलती है. इससे Gn बढती है या Gw कम होती है और सन्तुलन व स्थिर व निरन्तर विकास सभव होता है.

जिन देशो मे मुद्रा स्फीति है व 'b' के ऋणात्मक होने से अतिरिक्त क्रय शक्ति विदेशो में चली जाएगी या वस्तुएँ वहाँ से आ जाएगी.

हरोड का कथन है कि "मेरी प्रणाली मे निर्यात का प्रभाव रोजगार पर लाभदायक पाया जाएगा."

निर्यात का विकास किन तत्वो पर निर्भर है :

1 अगर देश के निर्यात अधिक होने है तो विकास अधिक हो सकता है एक देश की निर्यात करने की क्षमता वास्तव मे दूसरे देशों की आयात करने की क्षमता पर निर्भर है. हरोड बतलाते है कि बहुधा जो अमेरिका के निर्यात कम हो जाते है उसका कारण यह है कि आयात करने वाले देशो के पास धन कम हो जाता है.

2 अगर किसी देश मे उन वस्तुओ के उत्पादन वृद्धि की मात्रा, जिनके उत्पादन मे देश को लागत मे तुलनात्मक लाभ है, देश मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की मात्रा से, अधिक होगी तो निर्यात वृद्धि की मात्रा राष्ट्रीय आय की वृद्धि से अधिक होगी.

3. निर्यात वर्धन के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन के अगो को पुरस्कार दिए जाएँ (लाभ को छोडकर) वे आय मे जो वृद्धि हो उससे इनके बढने की दर कम हो. इससे लागतें नही बढेगी और भुगतान सन्तुलन बढेगा

4. हरोड के अनुसार, अगर राष्ट्रीय आय के गैर-लाभ भाग (Non-profit rewards) (अर्थात् लगान, ब्याज व मजदूरी) बहुत अधिक होगे तो आयातीत वस्तुयें घर में बनी वस्तुओ से सस्ती होगी और गृह-उत्पादन की बहुत सी लाइनें विदेशी उत्पादनकर्ताओ के पक्ष म बन्द हो जाएगी तथा देश के बहुत से विदेशी बाज़ार समाप्त हो जाएगे

5 हरोड का कथन है कि विश्व मे बहुत से देश ऐसे है जहाँ बचते लगभग नही के बराबर है जबकि बहुत से धनी देशो मे यह बचते आवश्यकता से अधिक है "इन परिस्थितियो मे पूंजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता से Gn (विकास की प्राकृतिक दर) बढ जाएगी यह आशा की जा सकती है कि जब पूजी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गतिशील होगी तो "तकनीकी ज्ञान व जानकारी" भी इन धनी देशो से निर्यात की जाएगी."

6 हरोड ने कम-विकसित देशो को सहायता देने मे न केवल इन कम-विकसित

See : 1. Benjamin Higgins op cit p 157–158
2 Harrod op cit p 103, 108 & 109
as also all pages between 103–116

देशो की भलाई देखी वरन् इसमे विकसित देशो को भी लाभ है परन्तु इन सब के होते हुए भी उन्होने कुछ हानियाँ भी बतलाई है, जो इस प्रकार है :

(i) बहुत अधिक जनसख्या वाले देशो मे विदेशी सहायता मिलने से जन-सख्या और बढ सकती है

(ii) कुछ कम-विकसित देशो मे राजनैतिक अस्थिरता के कारण पूंजी डूब सकती है क्योकि यह देश पूंजी वापिस करने मे धोखा कर सकते है

निष्कर्ष मे हरोड भुगतान सन्तुलन के पक्ष में होने को विकास मे बहुत सहायक मानते है, और व्यापार चक्रो को ठीक करने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते है.

हरोड मॉडल "सरल भाषा" मे (Harrodian Model in Common language

1. हरोड के अनुसार "प्रवैगिक साम्य" की स्थितियों को उत्पन्न करना ही विकास को उत्पन्न करना व बढावा देना है

2. हरोड के मॉडल मे विकास कारक घटको के रूप में बचत, पूंजी, विनियोजन, उत्पादकता व आय का मुख्य स्थान है. वे अपने मॉडल मे इन घटको के सह-सबध पर प्रकाश डालते है. वे अपने मॉडल म यह बताना चाहते है कि एक बार पूर्ण रोजगार मे आयी अर्थ व्यवस्था में स्थायी विकास कैसे कायम रह सकता है और किस प्रकार से देश की बचतो व उत्पादन क्षमता को पूर्ण रूप मे प्रयोग मे रखा जा सकता है

3. हरोड ने बताया कि जब बचतें बढती है तो विनियोजन बढता है, अधिक विनियोजन से आय बढती है (उत्पादकता बढने से या Through incremental capital-output ratio) इससे और बचतें बढती है और फिर यह क्रम चलता रहता है इस प्रकार से विकास चक्रवृद्धि ब्याज की भाँति बढता रहता है

4. हरोड के अनुसार विकास की दर = बचत दर ÷ पूंजी – उत्पादन दर अन्य शब्दो मे विकास बढाना हो तो या तो बचत दर बढाया जाना चाहिए या पूजी-उत्पादन दर घटाया जाना चाहिए (इसका अर्थ होता है अधिक उत्पादन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता) यह दोनो दरें ही विकास पथ निर्धारित करती है.

5. हरोड के विश्लेषण के अनुसार अगर किसी देश मे प्रति वर्ष बचतो की मात्रा 12% हो, पूंजी-उत्पादन दर 3% हो, जनसंख्या वृद्धि 2% हो, तो अर्थ व्यवस्था 2% प्रति वर्ष की दर से विकास कर सकती है

6 हरोड के अनुसार मांग की अधिकता या कमी से विकास पथ से अर्थ व्यवस्था हट जाती है एक बार जब अर्थ व्यवस्था साम्य की स्थिति से हट जाती है तो पुन उसी साम्य की स्थिति मे नही आती, वरन् एक नए साम्य की स्थिति पर पहुँच जाती है. हर नया (पर ऊँचा) साम्य विकास पथ पर ले जाता है. हरोड ने मदी व तेजी के व्यापार चक्रो को विकास कारक बताया

7 उच्चा-वचनो की अधिकतम व न्यूनतम सीमाएँ होती हैं (a) अगर देश मे आय तेजी से बढ़ने लगती है तो तेजी शुरू हो जाती है फिर और अधिक विनियोजन होता है और आय बढती है और यह क्रम वहाँ तक चलता जाता है जहाँ तक कि उसकी सीमा नही आ जाती है या स्वय यह सीमा और ऊपर नही उठ जाती यह सीमा देश मे श्रम व प्राकृतिक साधनो पर निर्भर है. (b) अगर आय धीमे बढना शुरू होती है तो बगैर बिकी चीजें रहने लगती है जिसके कारण विनियोजन और कम हो जाता है और फिर विकास पथ मदी की ओर बढ जाता है, जब तक कि वह न्यूनतम सीमा पर पहुँच कर फिर ऊपर नही आता. न्यूनतम सीमा पूजी निर्माण की न्यूनतम मात्रा पर निर्भर है, और पूँजी निर्माण की मात्रा शून्य नही हो सकती.

हरोड डोमर मॉडल की समीक्षा क्या हरोड डोमर मॉडल कम-विकसित देशो मे लागू हो सकता है ?

हरोड मॉडल की अलग अलग अर्थ शास्त्रियो ने अलग-अलग समीक्षा की है. कुछ ने तो इसे सराहा है और कुछ ने इसे जटिल व गलत बताया है. हम अलग-अलग अर्थ शास्त्रियो के दृष्टिकोणो को अध्ययन करेगे

बेन्जामिन हिगिन्स :

हरोड का मॉडल चक्र विरोधी नीति के सबध में महत्वपूर्ण विवेचना करता है और सामाजिक आर्थिक नीतियो पर महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत करता है (परतु) इस मॉडल के बीच के अध्याय "डरावने रूप से कठिन हैं" ... हरोड की एक लाइन समझाने के लिए कभी कभी पूरा लिखना पडता है परन्तु अगली लाइन समझाना फिर आसान कार्य नही होता.[1]

बेन्जामिन हिगिन्स का कथन है कि हरोड का विश्लेषण बहुत ही सामान्य (General) है. इस कारण यह हर जगह लागू किया जा सकता है और कही भी उपयुक्त नही होता

1. Benjamin Higgins · op cit p 146-47

हरोड का मॉडल हमे बहुत से तथ्य नही देता यह मॉडल तो पूर्ण रूप से विकास के सब घटको मे सह-सबध भी नही समझाता. इनके मॉडल मे राज्य की क्रियाग्रो का विकास पर क्या प्रभाव पडता है, अध्ययन ही नही किया जाता [1]

मीयर तथा बाल्डविन :

मीयर और बाल्डविन के अनुसार हरोड मॉडल मे कुछ अवास्तविक मान्यताएँ है, उदाहरणत पूँजी-उत्पादन अनुपात तथा बचत अनुपात को हमेशा निश्चित मानना और उसमे वृद्धि व कमी की अपेक्षा न करना अवास्तविक है.

दूसरी त्रुटि पूर्ण बात यह है कि इसमें "विकास पर मूल्यो के परिवर्तनो को" ध्यान मे नही रखा गया हरोड ने अपने मॉडल में यह मान लिया कि एक बार मूल्यों में परिवर्तन आता है तो या तो मूल्य बढते ही जाते है या घटते ही जाते है परन्तु वास्तव मे "मूल्य परिवर्तन स्वय ही स्थिरता ले आते हैं" (जैसे मूल्य बढने से पूर्ति बढेगी या माँग कम होगी और मूल्य स्वय कम हो सकते है)[2]

सी. पी. किन्डल बरजर :

किन्डल बरजर के अनुसार हरोड डोमर का मॉडल तकनीक मे परिवर्तन होने मे विकास मे जो परिवर्तन होते है, उनको ध्यान मे नही रखता इनका विश्वास है कि यह मॉडल व्यावहारिक रूप मे सही नही पाया गया है. इस मॉडल मे यह बताया गया है कि अगर पूँजी-उत्पादन दर स्थिर रहे और इसके बाद पूँजी की विनियोजन दर बढा दी जाए तो विकास हो सकता है, परन्तु कभी कभी पूँजी के स्थिर रहने पर विकास हो जाता है. केवल पूँजी ही विकास कारक नही है.

> "Growth as observed in concrete situation proceeds faster than can be accounted for by the rate of inputs of capital with a constant capital-output ratio, The theory can be saved by allowing the capital-out put ratio is change, but then it ceases to be a theory and becomes a mere tautology."[3]

किन्डल बरजर ने बताया कि हरोड-डोमर का मॉडल Moses Abramovitz और Robert Solow के अनुसार ऐतिहासिक रूप से सत्य साबित नही हुआ

1. p 165-66.
2. Meier & Baldwin · op, cit · p 114
3. C. P. Kindleberger · op cit : p 4, 49-53.

है उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मे जो भी विकास हुआ है वह केवल पूंजी की अधिकता या पूंजी-उत्पादन की कमी है वरन् अन्य महत्वपूर्ण घटक शिक्षा, तक्नीकी उन्नति, साहसियो की कुशलता व पर्याप्तता व राज्य की उचित नीति रहे है.

एच. डब्ल्यू. सिंगर.[1]

सिंगर का कथन है कि हरोड-डोमर मॉडल विकसित देशो के लिऐ "आशावादी मॉडल है, परन्तु कम-विकसित देशो के लिए इस मॉडल से निराशावादी विचार सामने आते है. इन देशो मे जो अधिक जन संख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण हरोड-डोमर के parameters (गणित की स्थिर राशियो) से हम दर्शा सक्ते है कि किस प्रकार से इन देशो में cumulative self-sustaining stagnation या निरन्तर बनो रहने वाली स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर इन देशों में शुद्ध विनियोजन 6% से बढ रहा हो, पूंजी-उत्पादन अनुपात 3 : 1 हो और जनसख्या वृद्धि 2% प्रति वर्ष हो, तो हरोड-डोमर समीकरण हमको बताएंगे कि, जब तक कुछ अनुकूल घटक उत्पन्न नही होते, तब तक अर्थ व्यवस्था बुरी तरह से स्थिरता की अवस्था में रहेगी. यह अनुकूल परिवर्तन या तो जनसंख्या के बढने की दर में कमी या पूंजी-उत्पादन दर में कमी हो सकती है.

एस० बी० मेहता :

श्री मेहता के अनुसार, हरोड-डोमर की जो मान्यताएँ है उनके अध्ययन से ही साफ जाहिर है कि ये मॉडल कम-विकसित देशो के लिए उपयुक्त नही है ये मॉडल तो यह बताते है कि विकसित देशो मे जब पूर्ण रोजगार की अर्थ-व्यवस्था कायम हो जाय तो यह स्थिति कैसे कायम रह सकती है कम-विकसित देशों में मुख्य समस्या तो पहले पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँचना ही है. इन देशो मे "वाछनीय विकास दर" (Warranted rate of growth) को प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण तो (Forced rate of growth) या "यत्न-पूर्वक कार्यों द्वारा विकास की दर" होती है

श्री मेहता के अनुसार "वाछनीय विकास दर" को प्राप्त करना तो तब महत्वपूर्ण होगा जबकि कम-विकसित अर्थ-व्यवस्था, विकसित अर्थ-व्यवस्था बन जाए [2]

---

1. H. W. Singer : op. cit : p 8.
2. S. B. Mehta : I. E. A's Annual no-on Growth, op cit.

प्रो० केनेथ के कुरिहारा :

प्रो० कुरिहारा का कथन है कि हरोड-डोमर का मॉडल "अनैच्छिक या मंदी की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपयुक्त हो सकता है परन्तु कम विकसित देशों की सरचना सबधी बेरोजगारी" को दूर करने के लिए यह मॉडल उपयुक्त नहीं है

हरोड-डोमर मॉडल में बचतो की कमी की कल्पना नहीं की गई है परन्तु इन देशों में पूंजी निर्माण की कमी ही इस मॉडल की अनुपयुक्तता सिद्ध कर देती है.

प्रो० कुरिहारा का कथन है कि यह मॉडल तो उन्हीं कम-विकसित देशों में कुछ उपयुक्त हो सकता है जहाँ "सतुलित विकास" व्यवस्था के अन्तर्गत पूंजी-उत्पादन अनुपात तथा बचत-आय अनुपात एक योजना काल में स्थिर रहते हों, अन्यथा नहीं [1]

इएगर : L. B. Yeager

इएगर का कथन है कि हरोड के मॉडल की "वाछनीय विकास दर" क्या होगी इसका पता लगाना असभव है वे हरोड के इस मत से भी सहमत नहीं है कि विकास की अधिकतम सीमा श्रमकी मात्रा व प्राकृतिक साधनो पर निर्धारित है. विकास की सीमा इन स्थगिता तत्वों पर निर्भर नहीं रहती वरन् उत्पादन की पद्धति, तकनीक तथा सगठन विकास की सीमा निर्धारित करते हैं

एरिक लुडबर्ग : Eric Lundberg

एरिक लुडबर्ग के अनुसार हरोड मॉडल में पूँजी को ही विकास का एजिन बनाया गया है. परन्तु उन्होंने नार्वे व यू० एस० ए० के विकास का अध्ययन करके यह बताया कि तकनीकी अनुमधान प्रशासन व शिक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने हरोड मॉडल मे इन तत्वों तथा मूल्यों के परिवर्तनो, ब्याज की दरें, मुद्रा बाजार की स्थितियों, तथा साहसियों के कार्यों को शामिल नहीं किया.

अन्य आलोचनाएँ :

हरोड मॉडल की अन्य मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

1. हरोड ने यह मान्यता की है कि राज्य विकास में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और न पहल करेगा. कम-विकसित देशों के लिए यह बात ठीक नहीं है क्यों-कि यहाँ तो राज्य ही विकास शुरू करने में पहल करता है और बगैर राज्य की सहायता के विकास सभव ही नहीं हो सकता.

1. K. K. Kurihara : The Keynesian Theory of Economics Development p 71-72

2 हरौड मॉडल में जो यह माना है कि एक बार देश (Steady growth path) सतत व नियमित राह से हटता हैं तो हटता ही जाएगा, यह वात हमेशा सत्य नही हो सकती.

3 कम-विकसित देशो मे पूँजी-उत्पादन व बचत-आय दरो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं जबकि इस मॉडल मे उन्हे स्थिर माना है.

4. यह मॉडल चक्रीय बेरोजगारी को दूर करने मे महत्वपूर्ण मार्ग-दर्शन कर सकता है. परन्तु अल्प विकसित देशो की संरचना सबधी, दीर्घ स्थायी व स्वाभाविक बेरोजगारी को दूर नही किया जा सकता

प्रोफेसर जे० के० मेहता की प्रशंसात्मक समीचा :

प्रोफेसर जे० के० मेहता हरोड के मॉडल की मान्यताओं को मोटे मोटे रूप से वास्तविक मानते हैं. उनके अनुसार यह मान्यताएँ भले ही पूर्ण रूप मे सही न हो परन्तु वे विवेक शून्य नही हैं. वे हरोड को विकास मॉडलो को बनाने का प्रवर्तक मानते हैं प्रो० जे० के० मेहता, हरोड के मॉडल को, कुछ अपवादो को छोड, व्यवहार में लागू किया जा सकता है, कहते हैं.

प्रो० मेहता का कथन है कि हरोड का मॉडल "विकास मॉडल" तथा "चक्र-विरोधी" मॉडल दोनो है उनका मॉडल यह बताता है कि आय क्यो बढती है या घटती है, यह 'विकास मॉडल' है यह मॉडल यह भी वताता है कि 'असाम्य' की स्थिति क्यो होती है और कैसे यह असाम्य और खराब हो जाता है.

किसी भी देश मे अवनति, उन्नति व उच्चा-वचन विकास प्रक्रिया के ही अग होते हैं. "Fluctuations are disappointed growth or decline tendencies" अर्थात् उच्चावचन विकास या गिरावट की विफल प्रवृत्तियाँ होती हैं. प्रो० मेहता के अनुसार हरोड ने अपने मॉडल मे खूब अच्छी तरह समझाया है.

Prof. J. K. Mehta : Economics of Growth. p. 116, 117, 118, 119, 120 & 121.

अध्याय : 17

नर्क्स का विकास मॉडल

Nurk's Economic Growth

1. प्रस्तावना :
2. दुश्चक्र को तोड़ने के लिये सन्तुलित विकास आवश्यक है.
3. सन्तुलित विकास के लिये अतिरेक जनशक्ति का पूजी निर्माण के लिये उपयोग.

अध्याय : 18

ल्युस मॉडल : असीमित श्रमशक्ति के प्रयोग से विकास का मॉडल

Lewis Model . Growth With Unlimited Supply of Labour

1 प्रस्तावना

(i) ल्युस के अनुसार कम-विकसित देशो की प्रमुख विशयताएँ

2. विकास के लिये क्या कर ?

(i) श्रमशक्ति को इकट्ठा करना

(ii) इन्हे काम देने के लिये "जीवन निर्वाह योग्य" मजदूरी देकर काम देना चाहिये

(iii) अब पूंजी निर्माण करना चाहिये

(iv) पूंजी निर्माण बढाने के लिये देश में मुद्रा स्फीति फैलाना चाहिये

3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली अर्थ व्यवस्था व उनका मॉडल

4 उपसहार

(i) ल्युस मॉडल की समालोचना

अध्याय : 18

ल्युस मॉडल : असीमित श्रमशक्ति के प्रयोग से विकास का मॉडल

Lewis Model Growth With Unlimited Supply of Labour

1. प्रस्तावना

प्रो० आर्थर ल्युस ने अपने एक लेख ' Economic development with unlimited supply of labour" म विकास की रीति पर अपने विचार व्यक्त किए उन्होने इस मॉडल मे कम विकसित देशो की समस्यायें, विशेषताएँ तथा विकास वी व्यूह रचना की व्याख्या की. उनके अनुसार उनका मॉडल Modified classical model या परिवर्तित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो का मॉडल है

ल्युस के अनुसार कम विकसित देशो की प्रमुख विशेषताएँ :

ल्युस ने बतलाया कि उन कम विकसित देशों मे जहाँ बहुधा जनसख्या घनत्व अधिक रहता है वहाँ कृषि व औद्योगिक क्षेत्र मे बहुत से व्यक्ति बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी से पीडित रहते है और कई व्यक्तियो की सीमान्त उत्पादकता शून्य रहती है ऐसे देशो मे श्रमिको की माँग से उनकी पूर्ति अधिक रहती है और हम इसको "असीमित श्रमशक्ति" कह सकते है

ऐसे कम विकसित देशो मे अर्थव्यवस्था में 'दुहरापन' पाया जाता है. इन देशो मे एक तो Capitalist sector पूँजीवादी क्षेत्र होता है और दूसरा Subsistence sector या 'पिछडा प्राथमिक क्षेत्र' होता है प्रथम मे पूँजी, उत्पाद-

---

"Economic Development with Unlimited Supply of Labour."
W. A. Lewis.

— Reproduced in A. N Agarwal & Singh · op. cit. p 400-50.
— " " Bernard okun and richard W. richard son's "Studies in economic development" Holt, rinehat & winston. 1965 p 292 onwards.

कता व आय अधिक रहती है और दूसरी मे कम रहती है. इन देशो मे "There are islands of development in the sea of stagnation" अर्थात् पिछडेपन के समुद्र मे विकास के कुछ द्वीप मौजूद रहते है अर्थात् इन देशो में छोटे छोटे खेतो पर पिछडे किस्म की खेती के साथ साथ उन्नत व बडे बडे कृषि फार्म भी मौजूद होते है उसी प्रकार छोटे छोटे उद्योगो के बीच उन्नत व आधुनिकतम उद्योग भी मौजूद रहते है इन देशो मे भी कुछ सूझबूझ वाले तथा साधनयुक्त साहसी मौजूद रहते हैं जो कुछ ही उद्योगो में ही पूँजी लगाए रहते हैं इन देशो मे अशिक्षित, अन्धविश्वासी तथा पिछडे व अकुशल व्यक्तियो के बीच बहुत सुशिक्षित, आधुनिक व कुशल व्यक्ति मौजूद रहते है विकसित क्षेत्र मे आधुनिकरण की चाह रहती है पिछडे क्षेत्र मे नही रहती

2. विकास के लिए क्या करे ?

ल्युस के अनुसार अगर इन देशो मे विकास करना है तो यह देश अपनी "असीमित श्रम शक्ति" का पूर्ण प्रयोग कर के ही विकास कर सकते है. इसके लिए ल्युस निम्नलिखित उपाय सुझाते है.

(i) श्रमशक्ति को इकट्ठा करना

1. सर्वप्रथम कम विकसित देशो म स्त्रियों की शक्ति को प्रयोग मे लाना होगा. इनमे से बहुत सी तो गृह कार्यो म लगी रहती है परन्तु उनकी क्षमता का पूर्ण प्रयोग नही होता.
2. दूसरे हमको उन व्यक्तियों को भी काम पर लेना होगा जो आज बेरोजगार है, या जो अर्ध-बेरोजगारी तथा छद्मवेषी बेरोजगारी से पीडित है तथा जो छोटे किसान या दुकानदार के रूप मे (बगैर आर्थिक लाभ के) कार्य कर रहे है.
3. इसी श्रम शक्ति के reserve या योग मे बढती हुई जनसख्या के लोगो को शामिल किया जा सकता है.

हमको इनका अनुमान लगाकर इन्हे अब काम देना होगा.

(ii) इन्हे काम देने के लिए "जीवन निर्वाह योग्य" मजदूरी देकर काम देना चाहिए.

ल्युस ने अपने विकास योजना के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की योजना को अपनाया है. प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो की योजना थी कि "असीमित श्रम शक्ति" के

Lewis का यह मॉडल Nurkse के मॉडल से मिलता हुआ पाया जाएगा.

प्रयोग के लिये देश मे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी देकर रोजगार बढाया जा सकता है. बाद में नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने इस मॉडल को छोड दिया था क्योकि योरोप मे "जीवन निर्वाह" बराबर मजदूरी मान्य नही थी. केन्स ने "Current rate of wages" पर (या वर्तमान मजदूरी पर) कार्य देने को कहा था ल्युस का कथन है कि कम-विकसित देशों में बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी की मौजूदगी के कारण जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी ही देना ठीक होगा परन्तु इस विचार मे वे सशोधन भी करते है

वे कहते है कि शहरो मे जीवन निर्वाह व्यय चूँकि अधिक होता है इसलिए आवास, यातायात व अन्य व्ययो को पूरा करने के कारण पूंजी क्षेत्र में मजदूरी 30 प्रतिशत तक अधिक हो सकती है.

(iii) अब पूंजी निर्माण किया जाना चाहिए.

ल्युस के अनुसार अब देश मे पूँजी निर्माण की आवश्यक्ता होगी ल्युस का कथन है कि मुख्य समस्या यह है कि किस प्रकार से यह 4 या 5 प्रतिशत बचत करने वाले देश अपनी राष्ट्रीय आय का 12 से 15 प्रतिशत बचत करने लगें ल्युस कहते हैं कि कम विकसित देशो म लगभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो बचत कर ही नही पाते. बचत तो इन देशा के वे धनी व्यक्ति (लगभग 90 प्रतिशत) करते है जो देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत भाग प्राप्त करते है.

पूँजी निर्माण बढाने के लिए इन्ही धनी व्यक्तियों की आय बढायी जानी चाहिए

(iv) पूंजी निर्माण बढाने के लिए देश मे मुद्रा स्फीति फैलाना चाहिए.

ल्युस का कथन है कि कम-विकसित देशों में पूँजी निर्माण देश मे मुद्रा स्फीति फैला कर किया जा सकता है. राज्य को चाहिए कि वह देश मे नई मुद्रा छाप कर देश मे मूल्य वृद्धि होने दे. ऐसे समय मे मजदूरी के स्तर बढने नही देना चाहिए और जो मूल्य वृद्धि से धनी व्यक्तियो को, विशेष रूप से उत्पादन कर्ता वर्ग को लाभ हो उन्हें उन व्यक्तियो को प्राप्त करने दिया जाना चाहिए.

ल्युस का कथन है कि इस प्रकार की मुद्रा स्फीति से देश को दीर्घकाल मे कोई हानि नही होगी. इस प्रकार की मुद्रा स्फीति Self Liquidating या स्वयं समाप्त हो जाने वाली होगी ल्युस का कथन है युद्ध के काल में हीनार्थ प्रबन्धन

Lewis के अनुसार पूँजी निर्माण No. of workers to be provided with work X Amount equal to subsistence wages पूजी निर्माण की मात्रा होगी.

से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है वह स्वय समाप्त नही होती परन्तु विकास के लिए की जाने वाली यह मुद्रा स्फीति स्वयं समाप्त हो जाएगी. इसके उन्होंने निम्नलिखित कारण बतलाए.

(i) सर्व प्रथम तो उत्पादनकर्ता बढे हुए मूल्य पर अधिक कमा कर अधिक विनियोजन करेंगे और इसमे उत्पादन बढेगा और मूल्य कालान्तर में गिर जाऐंगे. और

(ii) दूसरे राज्य की करो से आय बढ जाएगी और राज्य को बाद मे हीनार्थ प्रबन्धन नही करना पडेगा.

ल्युस इस प्रकार की योजना का एक उदाहरण देते है

> "माना कि £ 100 के विनियोजन करने से एक वर्ष मे £ 20 का लाभ होता है, जिसमे से माना कि £ 10 प्रति वर्ष बचा लिया जाता है. अब अगर इस विनियोजन को पूँजीपति साख निर्माण से करते है तो ग्यारहवें (11 वें) साल के शुरू होने पर कुल लाभ £ 200 प्रति वर्ष से बढ जाएँगे और हर वर्ष £ 100 अधिक बचते हुआ करेंगी, और देश की मुद्रा पर कोई दबाव नही रहेगा. इस घटना का अंत केवल इतना रहेगा कि देश मे £ 1000 की अधिक पूँजी हो जाएगी अगर साख निर्माण नही किया गया होता तो देश में यह सब नही होता"

ल्युस यह मानते है कि इस नीति से गरीबो के सामने कठिनाइयाँ आएगी, परन्तु इससे उन्हे रोजगार मिलेगा और कालान्तर मे उनकी वे कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी

3. His Model in Open Economy : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली अर्थ व्यवस्था व उनका मॉडल :

ल्युस ने कहा कि कम विकसित देशों को यह मॉडल अपनाने मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की भुगतान समस्या सामने आएगी. पहले ही यह देश प्रतिकूल भुगतान सतुलन के शिकार रहते है. यह समस्या इस नीति से और बढ सकती है जैसे (i) मुद्रा-स्फीति से देश में जो मूल्य वृद्धि होगी उससे विदेशी विनिमय दर गिरेगी. अथवा (ii) उससे निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होगे. (iii) अगर राज्य में राजनैतिक हिम्मत न हो तो वह पर्याप्त मात्रा में कर न लगा सकने की स्थिति मे देश मे धन की असमानताओ मे वृद्धि कर देगी.

इसलिए ल्युस का कथन है राज्य को विदेशी विनिमय पर कडा नियंत्रण रखना चाहिए और विदेशो से आर्थिक सहायता या ऋण प्राप्त करना चाहिए.

Quoted from Okun & Richardson's op-cit p. 294

4. उपसंहार

ल्युस का दावा है कि अगर इस मॉडल को अपनाया गया तो देश मे पूंजी निर्माण के लिए उपभोग घटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी (जैसी कि नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो के मॉडल मे की गई थी) इस प्रकार से पूंजी निर्माण किया जाएगा तो उपभोग वस्तु उद्योग व भारी उद्योग एक साथ पनप सकते है.

ल्युस ने यह भी बताया कि

> "विकास की यह प्रक्रिया उस समय समाप्त हो जाएगी और यह नीति उस समय कारगर नही रहेगी जबकि पूंजी निर्माण की वृद्धि मात्रा व दर जनसख्या की वृद्धि दर के बराबर हो जाएगी. अगर मजदूरी बढने दी गई तो यह नीति और पहले ही कारगर नही रहेगी."

★ Critique of lewis model ल्युस मॉडल की समालोचना :

ल्युस मॉडल की अगर हम समालोचना करें तो हम इस मॉडल मे बहुत सी कमियाँ पाएग इन कमियो मे मुख्य निम्नलिखित है

1 Shult तथा Leibenstein यह नही मानते कि कम विकसित देशो में श्रम की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है. उनका कथन है कि अगर ऐसा होता तो मजदूरी दरें भी लगभग शून्य पर आजाती. इस कारण यह पता लगाना कठिन है कि कितने लाग Surplus या आवश्यकता से अधिक है.
2. दूसरी कठिनाई जो इस माडल को कार्यान्वित करने मे आएगी वह यह है कि "अतिरेक (Surplus) जनसख्या" को शहरो मे ले जाना आसान नही होगा. कम विकसित देशा मे जनता इतनी गतिशील नही होती. जाती व धर्म के बन्धना के कारण व्यवसायिक गतिशीलता कम रहती है. भाषा, जन का अभाव, आवास की समस्या, उत्साह की कमी, स्थान व वातावरण से प्रेम आदि के कारण भौगोलिक गतिशीलता कम रहती है. कुशलता के अभाव, प्रशिक्षक की कमी, व अवसर की समानता न होने से horizontal (क्षैतिज) व Vertical (खडी) गतिशीलता कम रहती है. इस मॉडल को कार्यान्वित करने में पहले बृहत् मात्रा में ट्रेनिंग सुविधाओ को बढाना होगा.
3. तीसरे आज कम विकसित देशो में "जीवन निर्वाह" के बराबर मजदूरी देते रहना सभव नही है. आज के युग में सम्पूर्ण विकास क्रिया काल में

* Based on Dr. A C Minocha's Paper : "Capital formation in under developed countries—Validity of lewis model" Later published in I E J Vikram university Economists Seminar at Bhopal in 1966

श्रम जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर कार्य नही करेगा. वह भी बढती हुई महंगाई का मुआवजा मांगेगा और वह भी लाभ में अपने हिस्से की मांग करेगा. आज श्रम आंदोलन, श्रम सघो की मौजूदगी व अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सघ की मौजूदगी के कारण "न्यूनतम मजदूरी" से लेकर श्रम कल्याण के बहुत से महत्वपूर्ण नियम मौजूद रहते है. ये आजकी सामाजिक व राजनैतिक दशा में हटाए नही जा सकते. इस कारण ल्युस का 'जीवन निर्वाह' के बराबर मजदूरी देते रहकर पूंजी निर्माण करके विकास करना संभव नही होगा.

4. चौथी आलोचना यह की जा सकती है कि कम-विकसित देशो के औद्योगिक क्षेत्र मे श्रमिको की मांग इतनी तेजी से नही बढेगी, जितनी तेजी से कि कृषि क्षेत्र मे अतिरेक श्रमिको को काम देना पडेगा. हमको चाहिए कि हम कृषि क्षेत्र को भी सम्पूर्ण रुप से विकसित करे.
5. पाँचवी : कम-विकसित देशो मे कृषि क्षेत्र कृषि मे रत व्यक्तियो को वह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जो औद्योगिक क्षेत्र प्रदान नही करता. इस कारण कृषि क्षेत्र से श्रमिको के निकलने की प्रवृत्ति लोचदार नही होती, अर्थात् मूल्य या मजदूरी वृद्धि के अनुरूप नही होती.
6. छटी : **कुजनेट्स** ने बताया है कि कम-विकसित देशो मे धन की असमानताएँ पहले से ही अधिक होती है और ल्युस मॉडल को अपनाने से ये और बढ जाएँगी. **प्रो० मीयर और बाल्डविन** के अनुसार "धन की असमानताएं बढने से ही उत्पादक विनियोजन मे वृद्धि नही हो जाती, क्योंकि कम-विकसित देशो मे बचत करने वाले बहुधा जमीदार और अन्य पूँजीपति होते है. ये व्यक्ति अपने धन को भूमि के सट्टो, अन्य सट्टो तथा सामान व सोना-चाँदी के संचय मे लगा देते है.
7. सातवी : **श्री एस० जे० पटेल तथा यू० एन० ओ० के विश्व सर्वेक्षण** 1960 के अनुसार, ल्युस की यह धारणा गलत है कि कम-विकसित देशो मे केवल धनी व्यक्ति ही बचत करते है जापान, बर्मा, कागो आदि देशो में कम आय वाले भी बचत करते पाए गए है जब कि अन्य कम-विकसित देशो मे जैसे चिली, प्यूरहो टिको मे अधिक आय वाले भी कम बचत करते पाए गए.
8. आठवी : कम-विकसित देशो मे कुशल साहसियो का सर्वथा अभाव होता है जब ये साहसी नही होगे तो अतिरेक जनशक्ति को प्रयोग मे लाकर विकास करना सम्भव नही होगा.
9. नवी : ल्युस ने अपने मॉडल में ऐसे Corporate sector की कल्पना की

है जो अधिक लाभ कमा कर उसे पुन विनियोजित कर देता है परन्तु कम विकसित देशो मे यह क्षेत्र बहुत सीमित होता है भारत मे 1958-59 i इस क्षेत्र ने देश की राष्ट्रीय आय का केवल 2 8% भाग उत्पन्न किया अधिकाश बचतें ' घरेलु क्षेत्र" से आई. स्वय सार्वजनिक क्षेत्र व बडे औद्योगिक क्षेत्र ही इन 'घरेलु क्षेत्र" की बचतो का प्रयोग करते हैं

10 दसवी त्युम के इस दावे को कि कम-विकसित देशो में मुद्रा स्फीति स्वय नष्ट हो जाएगी, Julio H G Olivers ने अमान्य किया है इन देशो म विभिन्न सरचना सम्बन्धी जटिलताओ से उत्पादन उतनी आसानी से नही बढता जितनी शीघ्रता से इन देशो म मुद्रा स्फीति फैल सकती हैं. कृषि उपज इन देशो मे बेलोचदार रहती है.

11 ग्यारह इसी प्रकार से इन देशो मे राज्य की कर व्यवस्था इतनी परिपक्व नही होती कि बढी हुई आय को समुचित रूप से करो द्वारा किया जा सके. इस प्रकार से इन देशो मे मुद्रा स्फीति मे Built-in brakes की नितात कमी रहती है

मुद्रा स्फीति से देश मे, Dr-Roberto Campos, आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी मदो मे विनियोजन रुक जाएगा.

●

Select references

(i) See . Meier & Baldwin . op cit. p. 307-8.

(ii) Kuznets Quantitative aspects of Economic Growth of Nation . Distribution of income by size—Eco. Dev & Culteral change Dec. 68 p 80

(iii) Yasusuke Mrakami and Maclriko rubo, Migration of Agrarian Labour force and the theory of disguised equilibrium I. E. J Oct. & Dec. 1964.

(iv) S. J Patel · The Distribution of Income in India, I. Eco. Review Feb. 1956.

(v) Vakil & Bramhanand : Capital Supply & Growth-Sources of Savings : International Eco. Association.

(vi) Julio H. G Olivers : On structural inflation & latin American Structuralism : Oxford Eco Papers. Nov. 1964

(vii) Robert D. Oliveria Campos , inflation & Balanced Growth all from Dr. A. C. Minocha's op cit.

अध्याय : 19

विकास की अवस्था का सिद्धान्त

Stage Theories of Growth

I. List

II Hidler brand

III. Biker

IV. Gras

V. Marx

VI. W. W. Rostow

1. पूर्व औद्योगिक अवस्था या प्राथमिक अर्थ व्यवस्था की अवस्था
2. आत्म स्फूर्ति-विकास के पूर्व की स्थिति की स्थापना की अवस्था
3. आत्म स्फूर्ति की अवस्था
4. उत्तरोत्तर विकास की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था : पुरोगामी क्षेत्र का महत्व
5. अत्यधिक उपभोग की अवस्था

B

रोस्टोव की विकास की अवस्थाओं की समीक्षा

1. Gerald M. Meier
2. Simon Kuznet
3. A. K. Cairncross
4. Alexander Gerschenkron
5. H. J. Habakkuk
6. Benjamin Higgins

अध्याय : 19

विकास की अवस्था का सिद्धान्त

Stage Theories of Growth

(With particular reference to Rostow's Stages)

विकास पर लिखने वाले बहुत से अर्थशास्त्रियों ने विकास को भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से गुजरने की कल्पना की या ऐतिहासिक विवेचना की इनमें लिस्ट, हिडिलब्रान्ड, ब्यूकेर, ऐशले, ग्राम, तथा मार्क्स ने विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया

I List :

लिस्ट ने पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया

(i) वहशीपन की अवस्था जब कि व्यक्ति जो कुछ पाता वह खाता है न कि जो कुछ वह उगाता है

(ii) चरागाह अवस्था, जबकि प्राथमिक कृषि उन्नत होती है व जनता खानाबदोशों जैसी रहती है तथा जानवरों की भांति चरागाह युग में रहती हैं.

(iii) कृषि अवस्था जबकि देश में कृषि ही मुख्य व्यवसाय व कृषि ही आय का मुख्य स्त्रोत होती है

(iv) इसके पश्चात कृषि उद्योग की अवस्था आती है औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता है व आय का मुख्य साधन हो जाता है. और सबसे अन्त में

(v) कृषि-उद्योग व व्यापार सब उन्नत हो जाते हैं

लिस्ट के अनुसार पाँचवी अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें जनसंख्या भार नहीं रहती और सबको उच्च स्तर पाना सम्भव होता है, तथा जब कि विदेशी व्यापार तथा राष्ट्रीय आय उच्चस्तर पर होते हैं हर देश इस अवस्था को पहुँचने का प्रयत्न करता है

इस अवस्था पर पहुँचना बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है उन्होंने इस सम्बन्ध में यह सलाह दी

See : Standard works on history of Economic Thought cited above.

प्रथम तो एक देश को कृषि उन्नत करना चाहिए, फिर औद्योगिक विकास पर ध्यान देना चाहिए आवश्यकतानुसार उद्योगो को 'सरक्षण'' प्रदान किया जाना चाहिए, और जब देश मे अन्तिम अवस्था आजाए तो पुन देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतन्त्र होना चाहिए

II Hidlerbrand

हिडलरब्राड ये भी जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होने विकास की तीन अवस्थाएँ बताइ .

(1) अदला बदली की अवस्था
(11) मुद्रा के माध्यम से विनिमय की अवस्था तथा
(111) साख के प्रयोग से विकास की अवस्था

यह विश्लेषण अत्यन्त सरल था और आज के युग म जो विकास की जटिल समस्यायें है उन्हे समझाने व सुलझाने का कोई महत्व नही है

III Buker

विकर के अनुसार विकास की ये अवस्थाएँ होती है

(1) घरेलु अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन व उपभोग स्वतन्त्र रूप से छोटे पैमाने पर होता है.
(11) नगरीय अर्थ व्यवस्था, जिसमें छोटे या थोडे बडे पैमाने पर उत्पादन होता है, पर सम्पूर्ण देश में नाके-चुगी पद्धति रहती है तथा
(111) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमे सम्पूर्ण देश मे उत्पादन व वितरण व्यवस्था का एकीकरण रहता है.

IV Gras

ग्रैस ने उपरोक्त अवस्थाओ में चौथी अवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था जोड दी, जिसमे देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे मुख्य स्थान हो जाता है
इन अवस्थाओ में सरलता ही उनका दोप है और हमारी आलोचनाएँ वे ही है जो हिल्डेब्रान्ड के सम्बन्ध मे हमने की थी

V Marx :

मार्क्स के सबध मे हम पढ ही चुके है कि उन्होने समस्त देशो के विकास को इन अवस्थाओ से गुजरने की कल्पना की

(1) सामन्तवाद. (11) पूजीवाद. (111) समाजवाद तथा (v) साम्यवाद.

हम देख चुके है कि मार्क्स पूजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास बढा सकने की सम्भावनाओं को मानते है, पर वे उसकी सामाजिक विकास न कर सकने की सम्भावनाओ के कारण उस पद्धति को उखाड फेंकने की सिफारिश करते हैं और मानते है कि यह व्यवस्था कायम ही नही रह सकती वे साम्यवाद को विकास की अन्तिम अवस्था मानते थे.

VI W W. Rostow :

विकास की अवस्थाओं के अध्ययन मे रोस्टोव का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है. श्री मीयर के अनुसार "His efforts were more substantial than of others His approach more analytical and related to a wider range of issues than any of the approaches of his predecessors "

1 Pre-industrial phase or the stage of traditional society. पूर्व-औद्योगिक अवस्था या प्राथमिक अर्थव्यवस्था की अवस्था

ऐसी अवस्था, रोस्टोव के अनुसार, वह थी या होती है जिसमे कि न्यूटन के पूर्व की तकनीक व विज्ञान मौजूद हो योरोप में 'औद्योगिक क्रान्ति' के पूर्व का काल यही काल था. इस प्रकार की अवस्था में जन्म व मृत्यु दरें अधिक रहती है. जनसंख्या में वृद्धि नही होती क्योकि यहाँ 'माल्थस के अवरोध' कार्यान्वित होते हैं

उत्पादन व उत्पादकता दोनो कम स्तर पर रहते है देश में कृषि ही मुख्य व्यवसाय व कृषि ही राष्ट्रीय आय का मुख्य जरिया होती हैं. एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने मे गतिशीलता कम रहती है. ऐसी अवस्था में देश मे यातायात, संचार, व्यापार, राज्य के कार्य, राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय सब कम होते है.

2. Pre-conditioning phase : आत्म-स्फूर्ति-विकास के पूर्व की स्थिति की स्थापना की अवस्था :

1. इस अवस्था मे विकास की राह में आनेवाले समस्त राजनैतिक कारणों को दूर कर दिया जाता है. देश का राजनैतिक एकीकरण हो जाता है जिससे संगठित अर्थव्यवस्था स्थापित हो जाती है.
2. इस अवस्था मे मुख्यत Social overheads (शिक्षा, ट्रेनिंग व स्वास्थ्य

VI See : W. W. Rostow : The stages of Economic Growth Cambridge University press, 1960.

सुविधाएँ) का विस्तार होता है. Economic overheads का भी (सड़कें, रेलें, संचार साधन, बिजली, बैंक आदि) विस्तार हो जाता है.

3 इस अवस्था मे भी विकास संभव है पर उसकी गति धीमी होती है.

4. व्यावसायिक, भौगोलिक व सामाजिक गतिशीलता बढ जाती है. यातायात के साधन सुलभ व सस्ते हो जाते है.

5. कृषि के उत्पादन मे आधुनिकता आ जाती है.

6 उद्योगो की भी स्थापना हो जाती है पर विकास की रफ्तार धीमी रहती है.

7. रोस्टोव के अनुसार कोई भी देश इस अवस्था में 100 वर्ष (एक सदी) तक रह सकता है.

8. इस अवस्था मे उत्पादन के अंगो का अनुकूलतम रूप मे एकत्रित हो जाते है. तक्नीक भी उन्नत होने लगती है, तथा साहसियो का कार्य व प्रभाव क्षेत्र बढ जाता है.

9. देश में शिक्षा के विकास व अन्य प्रभावो से देश की जनता मे विकास के प्रति रुचि व जागरूकता हो जाती है.

10. इस काल मे कृषि का सापेक्षिक महत्व कम होता, व उद्योग, यातायात, व्यापार एव विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यो में जनसख्या का प्रतिशत बढ जाता है. कुशल श्रमिको की माँग बढने लगती है देश मे विनियोजन की मात्रा भी बढ जाती है.

3 The take-off आरम-स्फूर्ति की अवस्था

1. यह अवस्था महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल होती है. यह अवस्था किसी देश मे 20 से 30 वर्षो तक रहती है. इस काल मे पहले तो पिछले काल में जो कार्य बाकी बच जाते है, उन्हे पूरे किए जाते है.

2. यह शब्द Aeronautical शब्दावली का है. जैसे एक हवाईजहाज एक बार अपने Runway पर दौडकर ऊपर उठ जाता है और फिर एक निश्चित ऊँचाई पर पहुँच कर उडता जाता है. उसी प्रकार अर्थव्यवस्था एक बार आरम-स्फूर्ति की अवस्था मे पहुँचती है तो फिर वह विकास पथ पर बढती ही जाती है.

3. इस अवस्था में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ जाता है. आधारभूत उद्योगो की स्थापना हो चुकती है. इससे पूर्व अवस्था कृषि मे 75 प्रतिशत लोग लगे

रहते थे इस काल में उनकी संख्या केवल 40 प्रतिशत या इससे कम हो जाती है.

4. इस अवस्था मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की दर, जनसंख्या मे वृद्धि की दर से अधिक हो जाती है. राष्ट्रीय आय बढने से देश में विनियोजन की मात्रा भी बढने लगती है देश की समग्र राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत या इससे अधिक विनियोजित होता ही रहता है

5 इस काल मे परिवर्तन बहुत तेजी से होता है तथा वह अविरल रूप में होता है. यह काल एक प्रकार से "औद्योगिक क्रान्ति" का युग होता है. अल्प काल मे ही उत्पादन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं.

6 आत्म-स्फूर्ति की अवस्था म पहुँचने के लिए विदेशी पूंजी का होना या न होना बहुत अधिक निर्णायक नही होता है जहाँ कि अमेरिका, कनाडा व रूस मे आत्म-स्फूर्ति की अवस्था विदेशी पूंजी की सहायता से प्राप्त की गई वही ब्रिटेन व जापान ने बगैर इस सहायता को प्राप्त किए आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त किया

7. रोस्टोव के अनुसार ' Nationalism becomes an engine of modernisation " अर्थात राष्ट्रीयता की भावना ही विकास को आत्म-स्फूर्ति की ओर ले जानेवाली मुख्य घटक बन जाती है.

8. इस काल मे सामाजिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र मे भी क्रान्ति आ जाती है इस काल मे नव-प्रवर्तनो की बहुतायत होने लगती है नए बाजार उत्पन्न होते है सभी आर्थिक सस्थान लाभ कमाते है, और कुछ क्षेत्रो का विकास बहु क्षेत्रीय विकास मे परिणित हो जाता है

9. इस काल में बचतो की मात्रा बढ जाती है. 'साख' देश की मुद्रा प्रणाली का महत्वपूर्ण अग बनकर पूँजी निर्माण मे सहायक होती है

10 इस काल मे देश के प्राकृतिक साधनो का और अधिक अच्छा प्रयोग होने लगता है, प्रति व्यक्ति आय बढने लगती है और निर्यात बढने लगते है

11 इस काल मे ऐसे व्यक्तियो की आय बढने लगती है जो बचत करके पूंजी निर्माण करते है और अधिकाधिक विनियोजन बढाते है इस काल में बाह्य मितव्ययताओं की उपलब्धि समस्त अर्थ व्यवस्था मे बढ जाती है और इनमे देश मे कुछ Leading Sectors पुरोगामी क्षेत्र की स्थापना हो जाती है जो स्थाई विकास की ओर ले जाते है :

12 रोस्टोव ने भिन्न-भिन्न देशों की आत्म स्फूर्ति के काल इस प्रकार से दिए :

ब्रिटेन	1783–1802	जापान	1878–1900
फ्रान्स	1830–1860	रूस	1890–1914
बेल्जियम	1833–1860	कनाडा	1896–1914
सयुक्त राष्ट्र अमेरिका	1843–1860	चीन	1952–
जर्मनी	1850–1873	भारत	1952–
स्वीडेन	1868–1890		

कम विकसित देशो को अगर आत्म स्फूर्ति अवस्था को पहुचना है, तो रोस्टोव उन्हें यह सलाह देते हैं

> 'कम विकसित देशों को उपभोग स्तर से ऊपर की आय को पूजी निर्माण के लिए प्रयोग करना चाहिए उन्हे उद्यमी व्यक्तियो को व्यापार व उधार देने के व्यापार से हटाकर उद्योगो म लगाना चाहिए इन लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय मौद्रिक व अन्य नीतियो (शिक्षा नीति भी) का प्रयोग करना चाहिए"

C P. Kindleberger ने रोस्टोव की आत्म-स्फूर्ति अवस्था की सुन्दर व्याख्या की है

> "Take off is the great watershed resistances and blocks to development are over come, particularly in one or more leading sectors where technical change is strongly felt"

4 The stage of self-sustained growth or derive to maturity The role of leading sectors उत्तरोत्तर विकास की अवस्था या परिपक्वता की अवस्था . पुरोगामी क्षेत्र का महत्व :

आत्म-स्फूर्ति की अवस्था के पश्चात परिपक्वता की अवस्था आती है जिसमे उत्तरोत्तर विकास होता जाता है इस काल मे उन्नत तकनीकी तरीके व उन्नत उत्पादन व्यवस्था सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था मे फैल जाती है अर्थ व्यवस्था मे "विकास करने की आदत ही पड जाती है"

इस काल मे जनसख्या वृद्धि से राष्ट्रीय आय कही अधिक बढती है हर क्षेत्र में विकास होने लगता है इस काल मे सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था का स्वभाव ही बदल जाता है. देश का उन्नत राष्ट्रो मे नाम आ जाता है

इस काल मे कृषि मे रत व्यक्तियो की सख्या कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत ही रह जाती है देश की ग्रामीण जनसख्या का प्रतिशत घट जाता है शहरो का विकास होता है कुशल व अर्धकुशल श्रमिको की सख्या बढ जाती है

देश में विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय की 10 से बढकर 20 प्रतिशत तक पहुँच जाती है आयात घट जाते है व निर्यात अधिक हो जाते है
रोस्टोव के अनुसार इस अवस्था को पहुचने मे 60 वर्ष लग सकते है

Leading sectors . They are his analytical bone structure of his stages of growth.

रोस्टोव के अनुसार देश का आर्थिक विकास कुछ परोगामी क्षेत्रो में विकास के कारण होता है यह वे क्षेत्र होते है जिनमें उत्पादकता अधिक होती है इन क्षेत्रों के विकास से अन्य क्षेत्रों का विकास होता है.

रोस्टोव बताते है कि विकास प्रक्रिया में देश मे कुछ क्षेत्र व उद्योग पिछड़ने लगते है (decelerate) पर यह तो इन क्षेत्रो के विकास का ही परिणाम है कि समूची अर्थ व्यवस्था आगे ही बढती रहती है

विकास प्रक्रिया मे (In growth metabolism) ह्रास (Katabolism) विकास (Anabolism) साथ-साथ चलता रहता है. इन क्षेत्रों के कारण anabolism, katabolism से अधिक होता है यह परोगामी क्षेत्र ऐसे होते है कि समस्त अर्थ व्यवस्था को ही बदल देते है (भविष्य में अणु शक्ति का क्षेत्र ऐसा हो सकता है)

5 The stage of mass consumption : अत्यधिक उपभोग की अवस्था

जब देश इस अवस्था में पहुच जाता है तो न केवल पूजीगत वस्तुओ का अत्यधिक उत्पादन व उपभोग होता है बल्कि उपभोग उद्योग भी अधिकाधिक उत्पादन करते है टिकाऊ वस्तुओ का उपभोग बढता जाता है सबकी व सब किस्म की मागे अधिकाधिक पूरी होती है देश में अधिकतम आर्थिक कल्याण स्तर पर जनता होती है और हम कह सकते है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाती है

Kindleberger : op. cit 54-57.
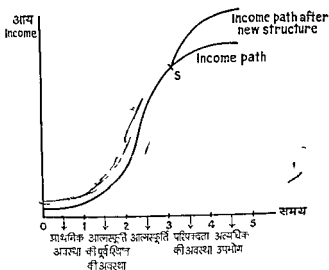
रोस्टोव की इन पाच अवस्थाओं को किन्डलबरजर ने इस चित्र मे दिखाया है. विकास की अवस्थाएँ Gompertz या 'S' curve से दिखाई गई है. (1) विकास धीरे-धीरे शुरू होता है, फिर स्तर ऊपर उठता है, फिर तेजी से ऊपर जाता है, और फिर स्थिर हो जाता है पर उच्च स्तर पर (Curve becomes asyomptotic).

B. रोस्टोव की विकास की अवस्थाओ की समीक्षा.

1. Gerald M. Meier.

(A) रोस्टोव ने विकास की इन अवस्थाओ को इसलिए दिया कि वे यह बता सकें कि मार्क्स की बताई हुई अवस्थाए (सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व साम्यवाद) ठीक नही हैं. इसीलिए उन्होने अपनी अवस्थाओ को Non-Communist Manifesto) कहा (मार्क्स ने Communist Manifesto लिखा था.) रोस्टोव की इन अवस्थाओ में शोषण, या वर्ग संघर्ष की बात नही कही गई. जहाँ मार्क्स का कथन था कि विकास पूँजीपति के लाने के लिए ही होता है और विकास को आगे ले जाने मे पूँजीपति केवल अपना लाभ देखते है रोस्टोव का कथन है कि विकास के पीछे निजी स्वार्थ की सकीर्ण भावना ही नही होती है. सामाजिक व राष्ट्रीयता की भावना भी होती है. रोस्टोव का कथन ठीक था कि मार्क्स को "अवस्थाएँ" केवल ब्रिटेन के उदाहरण के आधार पर ही लिखी गई थी, जबकि रोस्टोव ने वहुत से विकासशील देशो को ध्यान में रखकर यह सब लिखा.

(B) पर प्रा० मीयर न रास्टाव की इन अवस्थाओ की आलोचना भी की उनके अनुसार रोस्टाव की यह बात सही नही है कि सब दश इही अवस्थाओं से गुजरत है

> "Stage making" approaches are misleading when they succumb to a linear conception of history and imply that all economics tend to pass through the same series of stages every country cannot have the same past and same future"

प्रो० मायर का कथन है कि हा सकता ह कि विकास में कोई देश एक अवस्था को पूरी तरह नाघ कर अगली म पहुँच जाय और फिर हर देश का पाँचवी अवस्था म पहुँचना जरूरी नही ह प्रो० रोस्टोव की अवस्थाओ को हम Water tight compartment म नही बाट सकत एक अवस्था की विशपताए अन्य अवस्थाओं में भी रहती है

2 Simon Kuznet

कुजनट् न रोस्टोव की आलाचना रोस्टोव के निम्नलिखित वक्तव्य पर की रोस्टोव न कहा था

> 'Both the Existence and the quick-emergence of the political social and institutional frame work favourable to exploiting the impulses to expansion in modern sector are helpful for development in take-off"

कुजनट का कथन ह कि रास्टोव की यह मा यता गलत है कि यह त व आत्म स्फूर्ति की अवस्था म उत्पन्न होत है तो फिर उनके पहल से मौजूद होन की बात गलत है रोस्टोव की अवस्थाएँ एक दूसर की overlap करती है

1 Cf Leading Issues in Development Economics G M Meier Stanford university 1968 N york Oxford university press pp 24 35

2 Cf Simon kuznets Notes in Take off I E A Septt 1960 from G M Meier op cit 26 33

दूसरी प्रमुख आलोचना यह है कि रोस्टोव ने केवल 'उद्योगों' को ही परोगामी क्षेत्र माना है. क्या कृषि, यातायात या अन्य कोई क्षेत्र परोगामी क्षेत्र नहीं हो सकता ?. रोस्टोव ने अधिक उत्पादकता वाले उद्योग को परोगामी उद्योग माना है, पर हर अधिक उत्पादकतावाला उद्योग दूसरे उद्योगों के विकास को नहीं बढाता "अगर एक दशक में हुलाहूप का उत्पादन एक हजार गुना बढ जाएँ तो यह परोगामी क्षेत्र नहीं बन जाता है." (हुलाहूप एक प्लास्टिक का बडा छल्ला होता है जो लडकियाँ अपनी कमर पतली रखने के लिए कमर के चारों तरफ घुमाती हैं). तीसरी आलोचना यह है कि आत्मस्फूर्ति काल में, जिन देशों के आँकडे प्राप्त हैं उनमें दुगने विनियोजन से राष्ट्रीय आय की उत्पत्ति दुगनी नहीं होती, जैसा कि रोस्टोव ने माना है.

अन्त में कुज़नेट कहते हैं कि स्वय उत्तरोत्तर विकास करने वाली अवस्था जैसी कोई चीज नहीं होती.

> "The concept of self-sustained growth is misleading . No growth is purely self-sustaining or purely self-financing "

परन्तु कुज़नेट यह नहीं कहते कि रोस्टोव की अवस्थाओं के अध्ययन का कोई महत्त्व नहीं है. कई देशों ने रोस्टोव की आत्म-स्फूर्ति अवस्था देखी है

3. A. K. Cairncross.

इनकी दो आलोचनाएँ कुज़नेट की आलोचनाओं की भाँति हैं (1) वे भी कहते हैं कि परोगामी क्षेत्र रेल यातायात, या फुटकर व्यापार भी हो सकता है, केवल औद्योगिक क्षेत्र का परोगामी क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है (11) दूसरे वे यह भी नहीं मानते कि इन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों का विकास होता है उदाहरणतया इगलैंड में पहले सूती वस्त्र उद्योग और आज मोटर उद्योग परोगामी चक्र रहे, पर इनमें सम्पूर्ण देश के विकास में कोई सहायता नहीं मिली.

उन्होंने भी यह आलोचना की कि रोस्टोव की अवस्थाएँ overlap करती हैं और उन्होंने कहा :

> "रोस्टोव का यह मत सर्वथा गलत है कि एक बार परिपक्वता की अवस्था में देश आजाए तो विकास अपने आप होता है"

3. Cf : The Stages of Economic Growth, in Economic History Review April 1961-454-8.

परन्तु मेर्नब्रास का कथन है कि इन कमियो के होने हुए रोस्टोव की अवस्थाओं का अध्ययन विकास प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण है.

> "A great deal of what Rostow says is helpful in spite of rather than because of "stage approach"

4 Alexander Gerschenkron ऐलेक्जेन्डर गरशेनक्रोन :

गरशेनक्रोन यह मानत है कि एक देश भिन्न भिन्न आर्थिक अवस्थाओं से गुजरता है परन्तु हर देश इन अवस्थाओं से रोस्टोव की योजनानुसार नही गुजरता

5 H J Habakkuk

श्री हबाकुक के अनुसार रोस्टोव की अवस्थाएं आसानी से पहचानी नही जा पाती प्राथमिक अवस्था की स्थिति तथा अत्यधिक उपभोग की स्थिति को तो आसानी से पहचाना जा सकता है परन्तु बीच की तीन अवस्थाओं की सीमारेखा धुंधली है कनाडा व आस्ट्रेलिया तो पाचवी अवस्था को चौथी अवस्था को पहुँचने से पहले ही पहुँच गए हबाकुक का कथन है कि रोस्टोव ने विकास अवस्थाओं म वायुयान की उडान की सज्ञा दी उसम व हवाई जहाज की उडान म टकराने व गिर पडने की अवस्थाओं को तो भूल ही गए

> "In his aeronautical conept of growth, he ignored ' the bump downs and crash landings "

6 Benjamin Higgins बन्जामिन हिगिन्स

बेन्जामिन हिगिन्स, रोस्टोव के विश्लेषण को सैद्धातिक व ऐतिहासिक रूप से सही मानते हैं

•

---

4 Alexander Gerschenkron Economic Backwardness in Historical perspective p 353-9

5 H J Habakkuk Stages of Economic Growth Economic Journal, septt—1961 p 601 4

6 See also G M Baldwin—op cit p 24-44
P D Shrivastava, I J Economics June 1964, Vol. XI. No 4

अध्याय : 20

विकास की व्यूह रचनाएँ

Strategies of Economic Growth

संतुलित व असतुलित विकास

Balanced Vrs Un-balanced Growth

I. A. संतुलित विकास : विशेषताओं का विश्लेषण

प्रो० जे० आर० हिक्स का विश्लेषण.

मीयर तथा बाल्डविन का विश्लेषण.

I. B. सतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. रैगनर नवर्स.
2. रोसेन्तीन-रोडान
3. डब्ल्यु० ए० ल्युस.

II. असतुलित विकास का विश्लेषण

असतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. रोस्टोव.
2. ए० ओ० हिरशमैन.
3. हेन्स डब्लू० सिंगर.
4. सी० पी० किन्डलबरजर.
5. मारकस फ्लेमिंग.
6. बायर तथा यामें.
7. प्रो० रूज़ीना.
8. जे० शीहान.

विकास का ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि विकास की मुख्य प्रणाली "असंतुलित विकास पद्धति" रही है.

III. "संतुलित विकास पद्धति" व "असतुलित विकाम पद्धति" के सम्बन्ध में संतुलित मत

पांच स्ट्रीटन के विचार.

अध्याय : 20

विकास की व्यूह रचनाएँ

Strategies of Economic Growth

सतुलित व असतुलित विकास

Balanced vrs Unbalanced Growth

I A सतुलित विकास सतुलित विकास की विशेषताओ का विश्लेषण .

सतुलित विकास पद्धति म समस्त क्षेत्रो का सतुलित रूप मे, एक साथ व पूर्ण समन्वय से, विकास किया जाता है. (Balanced growth requires that investment take place in clusters) सतुलित विकास व्यवस्था में अगर इस्पात का कारखाना खोला जाना है तो साथ ही साथ लोहे की खान का विकास, कोयले की खानो का विकास, यातायात का प्रबन्ध तथा बाजार के विस्तार का आयोजन एक साथ कर लिया जाता है.

इस पद्धति में इस प्रकार से विकास कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं कि न तो किसी क्षेत्र मे अनबिका सामान रहे और न किसी क्षेत्र में उत्पादन की कमी रहे

सतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक इस बात पर जोर देते है कि "अर्ध विकास के साम्य को एक स्थान पर नही वरन हर स्थान पर तोड़ना पड़ता है" Protogonists of balanced growth emphasise that under-development equilibrium cannot be broken at one point.[1]

प्रो० पेरू के अनुसार ' सतुलित विकास का सिद्धान्त वास्तव में "चक्र विरोधी नीति" का उत्तराधिकारी सिद्धान्त है. चक्र विरोधी नीति के अन्तर्गत हम मदी काल मे ब्याज की दर घटा कर, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदकर, मुद्रा प्रसार करके, करो मे छूट देकर और व्यय बढाकर तथा अन्य उपायो से विकास मे अवरोधो को दूर करते है, तो सतुलित विकास नीति के अन्तर्गत हम अन्य व दीर्घकालीन विनियोजन में समन्वय करके विकास को आगे बढाते हैं.

1. Mc Graw Hill Dictionary of Modern Economics p 32.

सन्तुलित विकास पद्धति का लक्ष्य देश मे अनुकूलतम और उचिततम आर्थिक सामाजिक सरचना को स्थापित करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना होता है.[1]

प्रो० पेरू के विश्लेषण के अनुसार सतुलित विकास में तीन बातें निहित हैं

(i) देश के कुल उत्पादन और कुल रोजगार मे वृद्धि हो और इनके स्तर में न्यूनतम उच्चावचन हो, तथा देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो

(ii) अर्थशास्त्र के भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे न्यूनतम विषमता हो, तथा

(iii) समाज के भिन्न-भिन्न वर्गो मे सघर्ष न्यूनतम हो.

प्रो० पेरू के अनुसार सतुलित विकास पद्धति एक देश मे तो अपनाई जा सकती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अपनाया जाना अत्यन्त कठिन है

प्रो० जे० आर० हिक्स का विश्लेषण :

प्रो० हिक्स के अनुसार सतुलित विकास पद्धति में अर्थव्यवस्था के 'सक्रिय क्षेत्रों' को आगे बढने से रोक लिया जाता है और निष्क्रिय या कम सक्रिय क्षेत्रों को आगे बढाया जाता है. सक्रिय क्षेत्र वे होते है जिनमे विनियोजन, बढते हुए मूल्यो के प्रभाव से, अथवा राज्य के आयोजन के कारण, या इन क्षेत्रो मे किसी नव-प्रवर्तन के कारण, पर्याप्त मात्रा में होता रहता है इसके विपरीत कम सक्रिय या निष्क्रिय क्षेत्रो में पर्याप्त मात्रा में विनियोजन नही होता. ये क्षेत्र पूँजी की कमी या पिछडी तकनीक किन्ही अन्य राजनैतिक कारणों से पीछे रह जाते है.

सतुलित विकास पद्धति मे इन पिछडे क्षेत्रो को ही विकास मे सक्रिय क्षेत्रों के बराबर लाया जाता है

मीयर तथा बाल्डविन का विश्लेषण :

सतुलित विकास व्यवस्था में विनियोजन निजीलाभ की सभावित मात्रा को ध्यान

1. "The policy of balanced growth is complete anti-thesis of the haphazard piling up and incoherent juxtaposition of measures of intervention." it's aim is to act simultaneously upon the real factors in order to secure ..the maximum productivity of a socially optimum Structure."
   Prof P Perroux : See International Economic association "Stability and Progress in the world Economy." Edited D. C. Hague. p 113-129.
2. J R. Hicks See I E A. op. cit. Ed D C. Hague p. 113-129
3. Meier & Baldwin : op. cit : p. 353-367

में रखकर नही किया जाता वरन् सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है विनियोजन केवल उन्नत चेत्रो में ही (On growing points) नही किया जाता वरन् समस्त चेत्रो को एक साथ बढाया जाता है. भिन्न-भिन्न चेत्रो में विनियोजना को एक दूसरे का प्रतियोगी नही बनाया जाता बल्कि उनको पूरक के रूप में किया जाता है. सतुन्लित विकास मे एक क्षेत्र की पूर्ति दूसरे क्षेत्र में माँग बन जाती है और इस प्रकार से न बेच सकने का डर नही रहता. संतुलित विकास पद्धति में बाह्य मितव्ययताओं का सृजन होता है.

I : B सतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक

1. Ragner Nurkse : रैगनर नक्सं

1. जैसा कि हम देख चुके है. नक्सं का कथन है कि विकासशील देशो के विकास पथ मे बहुत से "आर्थिक दुश्चक्र" है उनका कथन है कि इन आर्थिक दुश्चक्रों को तोड़ने के लिए "सन्तुलित विकास" की आवश्यकता है. नर्क्स का कथन है कि "जिस प्रकार से शरीर के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से देश के आर्थिक विकास के लिए सतुलित विकास आवश्यक होता है
2. नक्र्स के अनुसार संतुन्लित विकास पद्धति से हम माँग और पूर्ति दोनो पक्ष से आर्थिक दुश्चक्र को भेद कर समाप्त कर सकते है उनका कथन है कि अगर हम भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगो मे एक साथ समन्वयपूर्ण विनियोजन करें

See : (1) Nurkse : Capital Formation in Under-developed Countries. Oxford University Press 1964. ch I.
(2) Nurkse : "Some International Aspects of the Problem of Economic Development" in Economics of Under-developed countries. (Ed), by A. N. Agarwal and S. P. Singh.
(3) Nurkse : "The Conflict between Balanced Growth and International specialisation", lectures on Economic development, Faculty of Economics (Istanbul University) and Faculty of pol. sc. (Uni. of Ankara) 1958 of. G. Meier leading issues in Econ. Development. Oxford.

तो यह सतुलित विकास पद्धति हुई. इस प्रकार के विनियोजन से बाजार विस्तृत होता है इन उद्योगो मे काम करने वाले व्यक्ति ही एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओ के ग्राहक बन जाते हैं यह माँग पक्ष से दुश्चक्र तोड देगा

3 पूर्ति पक्ष की ओर से दुश्चक्र को तोडने के लिए अगर असतुलित विकास पद्धति अपनाई गई (जिसमे बडे उद्योगो मे पहले विनियोजन हो) तो नर्क्स के अनुसार, बहुत अधिक पूजी की आवश्यकता पड जाएगी. नर्क्स कहते हैं कि विकास पथ पर बहुत से देश बहुत देर मे आये हैं ये देश विकसित देशो के उपभोग व उत्पादन के तरीको की नकल करने लगते है, अर्थात् उच्च विलासिताओ की वस्तुओ का उपभोग करते हैं और जटिल उत्पादन पद्धतियाँ अपनाना चाहते है. परन्तु इन देशो में बचत व पूजी निर्माण तो विकसित देशो के मुकाबले में कम होता है इससे ये देश भुगतान सतुलित नही रख पाते. अगर ये देश सन्तुलित विकास पद्धति अपनाएँ तो इस प्रकार की कठनाई से बच सकते है

4. सन्तुलित विकास का यह भी अर्थ होता है कि कृषि व उद्योग दोनो को समान महत्व दिया जाये जब ऐसा किया जाएगा तो कृषि क्षेत्र की अनावश्यक जनसख्या को औद्योगिक क्षेत्र में कार्य मिल सकेगा.

5 इसके अतिरिक्त, नर्क्स कहते है, सतुलित विकास पद्धति से विदेशी व्यापार भी बढेगा सतुलित विकास पद्धति में हम कृषि व औद्योगिक विकास साथ-साथ करते है, भिन्न भिन्न उद्योगो को एक साथ उन्नत करते है तथा Social overheads (शिक्षा व स्वास्थ्य) व economic overheads (बाह्य आर्थिक मितव्ययिताये अर्थात बैंक व यातायात विकास) का विकास भी एक साथ करते है इन सब सुविधाओ की मौजूदगी से विदेशी विनियोजक इन देशो मे विनियोजन करने को प्रोत्साहित होते है नर्क्स के अनुसार सतुलित विकास पद्धति विदेशी व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के प्रतिकूल नही है उन्होंने कहा

> "वेनेज्वेला के 90 प्रतिशत निर्यात पेट्रोल के होते है फिर भी इस इस उद्योग मे देश की केवल 2 प्रतिशत श्रम शक्ति कार्य पाती हैं अगर इस देश में सतुलित विकास होता तो देश के अन्य लोग भी निम्न स्तर के जीवन व्यतीत करने के स्थान पर उच्च स्तर का जीवन यापन कर सकते थे."

नर्क्स का कथन है :

> "Balanced growth is a good foundation for

International trade the case for balanced growth is not a case for autarky."

6. इस प्रकार से नर्क्स के अनुसार केवल सतुलित विकास से ही आर्थिक दुष्चक्र टूट सकता है इससे एक क्षेत्र की पूर्ति की दूसरे क्षेत्र मे माँग होगी, दूसरे क्षेत्र की पूर्ति की माँग तीसरे या पहले क्षेत्र में होगी और यही क्रम चलता रहेगा इस प्रकार से सब क्षेत्रो का साथ-साथ विकास होगा और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा या मंदी की अवस्था मे नही रहेगा Evsey Domar ने इसीलिए कहा है

> "His theory of balanced growth has been inspired by a variant of the Keynesian analysis of the slump" अर्थात् नर्क्स के सतुलित विकास सम्बन्धी विचार केन्स के मदी सम्बन्धी विश्लेषण से प्रभावित है

2 · Rosenstein-Rodan रोसेन्तीन-रोदान

1. नर्क्स की भाँति रोदान भी सतुलित विकास के पक्ष मे है रोदान का कथन है कि अगर कम विकसित देश रूस की भाँति असतुलित विकास पद्धति अपनाएँगे तो बड़े-बड़े उद्योगो के विकास के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी उतनी पूँजी को इकट्ठा करने के लिए देशवासियो को बहुत अधिक मात्रा में उपभोग का त्याग करना पड़ेगा दूसरी बुराई इससे यह पैदा होगी कि इन बड़े-बड़े उद्योगो की स्थापना से अतिरिक्त व अनावश्यक उत्पादन क्षमता निर्मित हो जाएगी. सतुलित विकास पद्धति मे ग्राहको की कमी नही रहेगी. तीसरी बुराई यह होगी कि असतुलित विकास से पूर्ण विकास होने मे काफी समय लगेगा.

2. रोदान सतुलित विकास पद्धति के लिए 'श्रम-गहन तकनीक' Labour—intensive techniques अपनाने के पक्ष मे हैं. उनका कथन है कि

---

1. Nurkse cf G Meier op. cit p 250–254 & A N Agrawal & S. P. Agarwal. p. 256–71
2. Evsey Domar quoted from Alak Ghosh's New horizons of planning p 63.

Rosenstein Rodan : Problems of Industrialisation of Eastern and south, Eastern Europe Eco-Journal June-sept. 1943.

Rio. Round table conference of international Economics Association 1957. See : Okun & Richardson . op cit : p. 124-132.

असतुलित विकास में हम बडे उद्योगों की स्थापना करते हैं और पूँजी-गहन तकनीक से उत्पादकता वृद्धि करते हैं और इसी प्रकार से बाजार का विस्तार होता है (मूल्य कम होने से). परन्तु अगर हम सतुलित विकास पद्धति अपनाएँगे तो असख्य अर्धबेरोजगारी को, श्रम-गहन तकनीक अपनाने के कारण, रोजगार भी मिलेगा और जन साधारण की क्रयशक्ति भी बढेगी इस प्रकार से सामान न बेच सकने का जोखिम भी नही रहेगा "जोखिम" भी एक प्रकार की लागत होती है और इसके कम होने से बाह्य मितव्ययिता का सृजन होता है.

3 रोदान के अनुसार सतुलित विकास से व्यक्तिगत लाभ व सामाजिक लाभ में अन्तर कम होते है एक साथ कई क्षेत्रों म विनियोजन से निजी क्षेत्र के लाभ के स्तर नीचे हो सकते हैं परन्तु सामाजिक लाभ तो बढ ही जाएँगे (Balanced growth will reduce the divergence between the private and social marginal returns... ......Balanced growth will generate external economics and the external economics should be included in the calculus of profitability)

3. W. A. Lewis आर्थर ल्युस[1] :

1. ल्युस भी सतुलित विकास के पक्ष मे पूर्ण समर्थन देने मे बिल्कुल नही हिचकते किसी भी विकास कार्यक्रम के सफल होने के लिए यह सर्वथा आवश्यक है कि कृषि व उद्योग के बीच सतुलित विकास हो, देश मे उपभोग किए जाने वाले उत्पादन व निर्यात किये जाने वाले उत्पादन मे सतुलन हो. इसी प्रकार से आयात व निर्यात मे सतुलन होना चाहिए
2. सतुलित विकास का अर्थ यह नही होता कि समस्त क्षेत्रों की विकास दर समान हो इसका तो केवल यह अर्थ होता है कि समस्त क्षेत्रों मे वाछनीय दर से विकास हो [2]

1. W A Lewis : Theory of Economic Growth p 274-83.
2 Lipton इस सम्बन्ध में कहते है कि सतुलित विकास में सब क्षेत्रों में एक ही दर से विकास होना चाहिए. परन्तु अधिकाश अर्थशास्त्री इस मत के नही है. W. Birmingham व A. G. Ford भी ल्युस के मत के समर्थक है उनका कथन है .

"संतुलित विकास का यह अर्थ नही है कि अगर किसी क्षेत्र मे

ल्युम सतुलित विकास पद्धति को निम्नलिखित दो लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु चाहते हैं

(i) सतुलित विकास से भिन्न-भिन्न चेत्रो में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य स्तर ऐसे रहेंगे जिससे किसी भी चेत्र में मूल्य न तो अधिक गिरें और न ही अधिक बढ़ें, इससे ऐसा नही होगा कि एक चेत्र की 'व्यापार की शर्तें' इस प्रकार से सुधरे कि दूसरे चेत्र की व्यापार की शर्तें बिगड जाएँ

(ii) सतुलित विकास से भिन्न-भिन्न प्रकार के अवरोध (bottlenecks) जो विकास के मार्ग मे आते है, वे दूर हो जाते हैं भिन्न-भिन्न चेत्रो मे विकास उनकी आय की लोच के अनुसार होता है.

II. असतुलित विकास का विश्लेषण

अर्थशास्त्र के विचारो की अधिक जानकारी न रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि "असतुलित" विकास तो अवश्य ही त्रुटिपूर्ण पद्धति है. परन्तु वास्तव में ऐसा नही होता न केवल "असतुलित" विकास को बुरा नही समझा जाता वरन् बहुत से अर्थशास्त्री तो "असतुलित" विकास पद्धति के प्रबल प्रवर्तक भी है.

असतुलित विकास पद्धति म भिन्न-भिन्न चेत्रो मे पूँजी-गत विनियोजन अलग-अलग .ै से बढाया जाता है जो अर्थशास्त्री असतुलित विकास चाहते है उनका कथन कि सतुलित विकास के लिए इतने अधिक धन की आवश्यकता पडेगी कि किसी भी कम-विकसित देश को एक साथ समस्त चेत्रो मे विनियोजन करना सम्भव नही होगा इन देशो के लिए यही अच्छा होगा कि वे कुछ प्रमुख व विकासशील

---

5 प्रतिशत की दर से प्रगति हो रही हो तो सब क्षेत्रो में इसी दर से प्रगति हो कुछ चेत्र तो कम दर से व कुछ चेत्र अधिक दर से प्रगति करेंगे ही, हम समान दर मे प्रगति नही चाहते वरन् समन्वित रूप से प्रगति चाहते है देश मे Capital-output ratio (पूँजी-उत्पादन अनुपात) के अध्ययन से हम अलग-अलग चेत्रो के सापेक्षिक समन्वय को निर्धारित कर सकते है "

Lipton quoted from

See: K. N. Prasad . Balanced vs Unbalanced Growth : Indian Economic Journal Oct-Dec. 1966.

Birmingham & Ford Planning and Growth in Rich and Poor Countries. p 35

उद्योगो मे ही विनियोजन बढाएँ और जान-बूझकर असतुलन उत्पन्न करे. सतुलित विकास में विकास की दर धीमी रहेगी जब असतुलित विकास मे विकास की दर अधिक रहेगी. असतुलित विकास मे विनियोजन इस प्रकार से होगा कि उसमे आने वाली अवस्थाओ मे स्वय ही उत्पादन बढे तथा वर्तमान उत्पादन की पिछली प्रक्रियो में (जैसे कपडा मिल की पिछली प्रक्रिया रूई उगाना) भी विनियोजन बढ जाए.

> "Investment should be concentrated in industries with greatest amount of forward linkage (encouraging investment in subsequent stages of production) and backward linkage" (inducing investment in earlier stages of production)

असतुलित विकास पद्धति में बढते हुए उद्योगो को ही आगे बढाया जाता है, इससे अधिक लाभ कमाये जाते है और फिर इन्ही लाभो को विनियोजन कर के अन्त मे सतुलित विकास लाया जा सकता है.

असतुलित विकास के मुख्य प्रवर्तक .

1. W. W Rostow : रोस्टोव :

रोस्टोव का कथन है :

> "किसी भी देश मे आर्थिक विकास कुछ अग्रगामी क्षेत्रो के विकास के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों पर निर्भर करता है. इन क्षेत्रो में, जो अधिकाधिक उत्पादकता वृद्धि होती है वही सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को आगे बढा देती है."

रोस्टोव असतुलित विकास पद्धति को ही सर्वोपरि मानते है. अग्रगामी क्षेत्रो से उनका आशय उन क्षेत्रो से है जो अपनी नवीन उत्पादन पद्धति से उत्पादकता मे आगे है इस कारण इनमें लाभ अधिक होता है और इन लाभो को पुन अधिक उत्पादक कार्यो मे विनियोजित कर दिया जाता है. इस पद्धति से सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया स्वयचालित हो जाएगी.

2. A. O. Hirschman : ए० ओ० हिरशमैन

हिरशमैन सतुलित विकास पद्धति को उचित नही मानते. उनका कथन है कि

Cf : Mc Graw Hill Dictionary of Modern Economics p. 32-33.

1. Rostow : op. cit.
2. A O. Hirshman : 'The Strategy of Economic Development., Uale University Press, New Haven, 1958 p. 36 and 66
   See also Gerald M. Meier "Leading Issues ....." p. 254-9

कम विकसित देशों कुशल व तक्नीकी विशेषज्ञों की पहले ही कमी रहती है. सतुलित विकास पद्धति में एक साथ भिन्न-भिन्न उद्योगों को प्रारम्भ करना इन व्यक्तियों की कमी के कारण सम्भव ही नही होगा

हिरशमैन का कथन है कि सतुलित विकास का सिद्धान्त केवल विकसित देश ही अपना सकते हैं कम-विकसित देशों के लिए सतुलित विकास का सिद्धान्त "Is children's parallel play" हिरशमैन तो See-saw advance of growth (अर्थात् बच्चों का वह खेल जिसमे एक बच्चा जब ऊपर जाता है तो दूसरे सिरे का बच्चा नीचे चला जाता है और जब दूसरा बच्चा ऊपर जाता है तो पहला नीचे चला जाता है) अर्थात् विकास तो तब होगा जबकि अर्थ-व्यवस्था कभी आगे व कभी पीछे हो जाए सतुलित विकास, हिरशमैन के शब्दो मे Escapist solution है अर्थात वास्तविकता मे बचकर निकल भागने की योजना है

हिरशमैन का कथन है कि अगर कम-विकसित देश असतुलित विकास पद्धति अपनाले तो ही वे इन देशो मे इतने साहसियों की कमी की स्थिति से मुक्ति पा सकते है इन देशो में इतने साहसी नही होते कि प्रत्येक क्षेत्र का विकास का कार्य हाथ में ले सके.

हिरशमैन का कथन है कि सतुलित विकास पद्धति व्यावहारिक नही है उनके अनुसार हम इस पद्धति को न केवल अपना नही सकते वरन् इस पद्धति को अपनाना अनुचित भी होगा हिरशमैन का कथन है कि हमारा यह सोचना गलत है कि अर्थव्यवस्था मे साम्य की स्थिति वाछनीय व असाम्य की स्थिति अवाछनीय होती है. वास्तव मे हमारी अर्थ-व्यवस्था हमेशा असाम्य की स्थिति से साम्य की ओर जाती है और इसी से विकास होता है हिरशमैन, टाइवर साइटोवेस्की (Tibor scitovsky) के उस कथन से पूर्णतया सहमत है जिसमे उन्होने कहा था कि "लाभ असाम्य की परिस्थिति मे ही उत्पन्न होते है." इसलिए हिरशमैन असंतुलित विकास के पक्ष में है

हिरशमैन का कथन है

> "In general, development policy must keep alive rather than eliminate the disegulibria of which profits and losses are symptoms in a

Tibor Scitorsky quoted from : "Two concepts of external Economics," Journal of Political Economy April 1954 p. 148.

competitive economy If the economy is to be kept moving ahead the task of development policy is to maintain tensions, disproportions disequilibria The nightmare of equilibrium economics, the endless spinning cobweb is the kind of mechanism we must assiduously look for as an invaluable help in development process "[1]

(अर्थात किसी भी विकास नीति का लक्ष्य असतुलन व असाम्य की स्थिति को समाप्त करना नही होना चाहिए वरन इनको कायम रखना चाहिए)

3 Hans W Singer हेन्स डब्लू सिंगर

सिंगर भी असतुलित विकास के पक्षम ह व सतुलित विकास पद्धति की अच्छाइयों से भी अवगत ह परतु उससे अधिक व असतुलित विकास को अच्छा मानत ह सिंगर का कथन ह कि सतुलित विकास पद्धति निश्चय ही कम विकसित देशो म बाजार सबधी कठिनाइयो को दूर कर सकती ह परन्तु साधनो की कमी के कारण इस नीति को अपनाना सभव नही होगा सिंगर सतुलित विकास पद्धति के निम्न लिखित गुण बतात ह

(i) सतुलित विकास पद्धति अपनान पर बाजार सबधी कठिनाईया दूर होगी
(ii) इससे White elephant projects या बड व कम लाभदायक उद्योगो या कायो की स्थापना नही होगा
(iii) इस पद्धति को अपनान पर और अधिक विनियोजन करन की प्ररणा रहगी

सिंगर का कथन ह

> जिन देशो म विकास के निम्नस्तर का कारण साधनो की कमी नही बल्कि अत्यधिक निराशात्मक वातावरण ह वहा सतुलित विकास पद्धति सैद्धान्तिक व व्यवहारिक दोना रूप से उचित होगी

इन सब अच्छाइयो के होत हुए भी सिगर के अनुसार सतुलित विकास पद्धति कम देशो के लिए कई कारणो से अनुपयुक्त ह उनका कथन ह

1 Gerald Meier op cit p 257

"सतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक यह मानते है कि इस पद्धति में पूर्ति अपनी माँग स्वयं उत्पन्न कर लेगी और साधन भी प्राप्त हो जाएँगे परन्तु यह सभव नही है कि यह दोनो लाभ एक साथ प्राप्त होजाएँ इन देशो को हम "उच्च विचार" रखने की सलाह तो दे सकते है परन्तु 'बडे बडे कार्य करो" की सलाह देना अत्यन्त गलत होगा. .. . विकास की सर्वोत्तम नीति तो यह ही होगी कि हम साधनो को उन क्षेत्रो मे लगाएँ जो पहले से ही विकसित हो. जिनमें शीघ्रातिशीघ्र और अधिक विकसित होने की तथा देश की अर्थ व्यवस्था को लचीला बनाने की सम्भावनाएँ हो."

"'Think big' is a sound advice to these countries but 'Act Big' is unwise counsel if it spurs them to efforts to do more than their resources permit Therefore to recommend the balanced investment package as a devise simultaneously to solve the marketing deadlock and to solve the deadlock of insufficient resources is to be become victim of double counting trick"

सिगर का कथन है कि सतुलित विकास पद्धति विकास की शुरू की अवस्था के के लिए सर्वथा अनुपयुक्त व हानिकारक होगी (It will be incomplete, implausible and even potentially dangerous). सिगर सतुलित विकास पद्धति को गलत नही मानते वरन् उसे कम-विकसित देशो के लिए उपयुक्त नही मानते The doctrine is premature rather than wrong.

4. C. P. Kindleberger · सी० पी० किन्डलबरजर :

किन्डलबरजर भी असतुलित विकास पद्धति को ही उचित मानते है. किन्डलबरजर का कथन है कि सतुलित विकास पद्धति को अपनाने का अर्थ यह होता है

See : International Development-Growth & Change, Mc Graw Hill 1964, "Balanced Growth-Theory & Practise p. 47-55 —also "The concept of Balanced Growth and Economic Development "Theory & Facts."

(1) C. P. Kindleberger ; op. cit : p. 223-225.

कि "कही भी काम शुरू करने से पहले हर स्थान पर काम शुरू करो." उनका कथन है कि सतुलित विकास पद्धति को अगर कम-विकसित अपनाएँगे तो साधनो की कमी आएगी, मशीनो की कमी आएगी और हर क्षेत्र में त्रुटियाँ होगी.

किन्डलबरजर का कथन है कि सतुलित विकास की बात करना 'केवल नारेबाजी है" हर स्थान पर बाजार सबधी सतुलन स्थापित करने के स्थान पर हमको चाहिए कि हम असतुलित विकास पद्धति को अपनाएँ और बाजार मे स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली को प्रभावशील होने दें किन्डलबरजर का कथन है

> "But if the slogan of balanced growth helps make the authorities examine sectoral inter-relations and judge their nature, it will serve a useful purpose Balanced growth is rather an empty slogan unless it means only that agriculture merits alteration as well as industry

5 Marcus Fleming मारक्स फ्लेमिंग

मारकस फ्लेमिंग ने भी असतुलित विकास पद्धति के पक्ष म अपने विचार व्यक्त किए हैं उनका कथन है कि सतुलित विकास पद्धति के प्रवर्तक उन उद्योगो को जिनमे एक साथ विनियोजन किया जाता है परस्पर एक दूसरे का पूरक मानते हैं परन्तु साधनो की कमी के कारण वे एक दूसरे के प्रतियोगी ही रहते हैं

अगर हम सतुलित विकास पद्धति को अपनाते हैं तो हम उत्पादन वस्तु उद्योगो व उपभोग वस्तु उद्योगो का एक साथ विकास करेंगे इससे उत्पादन वस्तु उद्योगों को साधनो की कमी पड जाएगी और इससे अर्थ व्यवस्था में मितव्ययिताओं के सृजन के स्थान 'अमितव्ययिताओ' या हानियो का सृजन होगा

फ्लेमिंग के अनुसार अगर कम विकसित देशो म असतुलित विकास पद्धति के अन्तर्गत केवल उन उद्योगो म विनियोजन किया जाए जिनम उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू होता है तो इन देशो म विकास की सम्भावनाएँ बढ जाएगी.

Marcus Fleming External Economics and the Doctrine of Balanced Growth The Economic Journal June 1955 See also In A N Agrawal and S P. Singh op cit. as also in Okun & Richardson op cit.

मारकस फ्लेमिग के अनुसार सतुलित विकास पद्धति केवल उन्ही देशा मे अपनाई जा सकती हैं जहा (1) पर्याप्त मात्रा मे पजी, कम ब्याज की दर पर प्राप्त हो सकती है, (11) जहाँ श्रम सघो को श्रमिको को वास्तविक मजदूरी न बढाने दी जाती हो, और (111) जहाँ कृषि क्षेत्र मे बहुत से अर्ध-बेरोजगारी से पीडित लोग वर्तमान वास्तविक मजदूरी पर ही रोजगार प्राप्त करने को तैयार हों

अगर उपर्युक्त स्थितियाँ किसी कम विकसित देशो मे मौजूद न हो तो वहाँ संतुलित विकास के स्थान पर असतुलित विकास पद्धति ही अपनाना चाहिए

6. Bayer and Yamey बायर तथा यामें

ये अर्थशास्त्री भी सतुलित विकास पद्धति से असतुलित विकास पद्धति को उत्तम मानते हैं ये अर्थशास्त्री सतुलित विकास पद्धति की दो कारणो से आलोचना करते हैं

(1) सतुलित विकास पद्धति को अपनाने से विकास की मौद्रिक व वास्तविक लागत बढ जाएगी और इससे समस्त योजना की सफलता की सम्भावनाएँ घट जाएगी

(11) सतुलित विकास पद्धति देश के आन्तरिक व्यापार मे आने वाली वस्तुओ के उत्पादन म अपनायी जा सकती है, परन्तु अगर देश की वस्तुओ को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे स्थान प्राप्त करना हो तो इसके लिए केवल उन उद्योगो को स्थापित करना चाहिए जिन उद्योगो की वस्तुओ के उत्पादन म उस देश को विशिष्टता प्राप्त हो. और इसी कारण असतुलित विकास की पद्धति उचित रहेगी

7. Prof Rugina . प्रो रुजीना ·

प्रो. रुजीना भी असतुलित विकास पद्धति के पक्ष मे है और वे सतुलित विकास पद्धति को मुख्यत राजनैतिक कारणो से ठुकराते हैं उनका कथन है कि सतुलित विकास पद्धति राज्य के निर्देशन के बगैर नही अपनायी जा सकती इस प्रणाली को अपनाने पर राज्य का हस्तक्षेप बहुत बढ जाएगा और "इससे समाजवाद को को हम पिछले दरवाजे से आने की अनुमति दे देंगे" उनका विचार है कि यह विकास पद्धति भी चक्र विरोधी नीति की भाँति असफल रहेगी. उनका कथन है ·

> "सतुलित विकास की नीति असफल होगी, परन्तु राजनीतिज्ञ इसकी असफलता को कभी स्वीकार नही करेंगे वे इसके स्थान पर और

Bayer & Yamey . The Economics of Under developed oCuntries p 247-50.

7. Cf : I. E. A. "Economic stability... .." op cit. p 143-4.

अधिक कायदे कानून व नियन्त्रण नियम बनाएँगे, वे हमेशा इसके असफल होने का दोष जनता की 'गलत' आचरण पर मढ दगे वे अपने तथा कथित 'विशेषज्ञों' के त्रुटि-पूर्ण सिद्धान्तो की नही मानेंगे, वरन् वे सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को आयोजित करके समाजवाद की स्थापना कर देंगे "

प्रो रुजीना का विश्वास है कि सतुलित विकास प्रणाली से न तो व्यापार चक्र समाप्त होंगे और ना ही राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय बढेगी.

8. J. Sheahan : जे. शीहान .

जे शीहान सतुलित विकास-पद्धति को गलत राह पर ले जाने वाली (misleading) पद्धति मानते हैं उनका कथन है कि अगर हम सतुलित विकास पद्धति को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सकें तो यह उचित होगा परन्तु यह सभव नही है. इसलिए किसी भी राष्ट्र को अकेले ही संतुलित विकास की नीति नही अपनाना चाहिए.

विकास का ऐतिहासिक अध्ययन बताता है कि विकास की मुख्य प्रणाली "असतुलित विकास पद्धति" रही है .

आज जो पश्चिमी राष्ट्र उन्नत है उन सब मे असतुलित विकास की ही पद्धति अपनाई थी. औद्योगिक क्रान्ति से आज तक किसी भी उन्नत देश में सतुलित विकास पद्धति नही अपनाई हर देश में कुछ अग्रगामी क्षेत्र रहे है जिनमे तकनीकी उन्नति व उत्पादन के स्तर सर्वथा ऊँचे रहे है. अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा व आस्ट्रेलिया ने असतुलित विकास पद्धति अपनाई. फ्रास के हर आयोजन में अलग-अलग उद्योगो पर कम या अधिक महत्व दिया गया, पर इससे फ्रास के आयोजन ने प्रवैगिक अर्थ-व्यवस्था को जन्म दिया.

बलबीर साहनी का कथन है .

"हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के

8 J. Sheahan : International Specialisation and the concept of Balanced Growth, Quarterly Journal of Economics, Feb. 1958

See : Balbir S. Sahni . Transformation through planned development, Eastern Economist, April 19, 1968
Alak Ghosh : New Horizons in planning : 1960, p. 50, 51, 61 and 71.

> विकास सम्बन्धी लक्ष्य, किसी भी विकास की अवस्था में तब प्राप्त हो सकते हैं जब आयोजन की विभिन्न योजनाएँ 'असतुलित विकास पद्धति' पर आधारित हो."

भारतीय व रूसी आयोजन भी असनुलित विकास पद्धतियाँ पर आधारित हैं पश्चिमी राष्ट्रों मे असतुलित विकास की पद्धति "अनियोजित" रूप से अपनाई गई, अर्थात् मूल्यों की व्यवस्थानुसार विकास हुआ (अन्य शब्दों में जिन उद्योगो में अधिक लाभ होता था वे ही विकसित किये गए) परन्तु रूस में असतुलित विकास-पद्धति को 'आयोजनानुसार" अपनाया गया

रूस की प्रथम पचवर्षीय योजना मे 86 प्रतिशत पूजी का विनियोजन पूजी-गत वस्तुओं के उद्योग मे किया गया और उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में केवल 14 प्रतिशत पूजी लगाई गई भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना में भी जो श्री महलानोविस के प्रारूप पर आधारित थी, भारी उद्योगो पर अधिक बल दिया गया था योजना मे भारी उद्योगो की स्थापना (इस्पात, इन्जीनीयरिंग, शक्ति, कोयला आदि) पर अधिक बल इस विश्वास पर दिया गया कि इन उद्योगो के विकास से जो मशीनें बनगी उनसे अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं. बाद में जब पर्याप्त मात्रा मे औद्योगिक उन्नति की आधार शिला जम जाएगी, तो बाद में उपभोग वस्तुओं के निर्माण के उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं. इस प्रकार की विकास पद्धति में पहल बाह्य मितव्ययिताओं का horizontal transmission और फिर Vertical transmission होता है

थोडे समय बाद उपभोक्ता-वस्तु उद्योग भी तेजी से भारी उद्योगो की बराबरी में आ जाते हैं. (The rate of growth of the consumer goods industries would asymptotically reach the rate of capital goods sector) और इसके पश्चात् फिर स्थायी व सतुलित विकास का युग शुरू हो जाता है

> "असतुलित विकास पद्धति में आय बढने की दर से विनियोजन बढने की दर अधिक होती है, आय स्वय उपभोग वृद्धि की दर से अधिक बढती है. इसके कारण बचत-आय अनुपात व पूजी-उत्पादन अनुपात में लाभदायक परिवर्तन होते हैं. अत में जाकर समस्त क्षेत्रों में विकास सतुलित हो जाता है, और विकास दर भी सतुलित विकास से अधिक रहती है."

Li Fu Chun .

जो साम्यवादी चीन के आयोजन कमीशन के अध्यक्ष थे, 1960 मे बजट भाषण के दौरान कहा था .

> "विकास एक असतुलन की अवस्था मे दूसरी असतुलन की अवस्था में पहुँचने से होता है. अर्थ-व्यवस्था असतुलन से सतुलन की ओर और फिर पुन. असतुलन की ओर जाती है इस प्रक्रिया में हर बार उत्पादन व आय के स्तर ऊपर बढ जाते है विकास की इन्ही तरगो रूपी परिवर्तनो से अर्थ-व्यवस्था आगे बढती है."

III : "सतुलित विकास पद्धति" व "असतुलित विकास पद्धति" के सबध मे सतुलित मत :

Balanced view regarding the strategies of 'Balanced' or 'Unbalanced growth'.

Paul Streeten : पाल स्ट्रीटन के विचार :

सतुलित विकास पद्धति व असंतुलित विकास पद्धति मे से कौन सी पद्धति उत्तम है इस सबध मे एक निर्णय देना ठीक नही होगा पाल स्ट्रीटन ने इस सबध में जो विचार प्रस्तुत किए है वे बहुत ही सतुलित है और हम उन्हे यहाँ प्रस्तुत करते है

उनका कथन है कि :

> "संतुलित व असतुलित विकास की पद्धतियो के सम्बन्ध में वाद-विवाद निरर्थक है दोनो पद्धतियो के अपने-अपने दोष है. वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई भी कम विकसित देश जब विकास के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहता है तो उसे देश के राजनीतिज्ञो को सिवाय असतुलित विकास पद्धति अपनाने के और कोई रास्ता ही नही होता है कम विकसित देशो की इस नीति की अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

Li Fu Chun : Quoted from ch. VIII of Gautam Mathur's book on Planning—"Balanced vs. Unbalanced Growth." p. 113.

Paul Streeten : Balanced vis Unbalanced Growth . The Economic weekly April 28, 1963 p 669-71. G Meier : op. cit · p 259-63.

विशपज्ञा को आलोचना नहीं करना चाहिए कम विकसित देशा में अथ-व्यवस्था इतनी लचीली नही होती कि सतुलित विकास की पद्धति को अपनाया जा सके '

"All investment creates unbalances because of rigidities, indivisibilities, sluggishness of response both of supply and of demand in these low elasticity economics and because of miscalculations "

स्ट्रीटन कहते हैं कि असतुलित विकास पद्धति से निश्चित ही विकास की दर अधिक रहती हैं परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि समन्वय व पूरक विनियोजन" पक्ष की बिल्कुल अवहेलना कर दें दोनो प्रकार की विकास पद्धतियो में राज्य के आयोजन की आवश्यकता हो जाती है और दोना प्रकार की पद्धतियों के अपनाने पर बाह्य मितव्ययिताओ का सृजन होता है

"It is not surprising that both balanced growth and unbalanced growth should be more effective presuppose each (a different kind of) planning for they are both concerned with lumpy investments and complementarities "

स्ट्रीटन का कथन है कि जब कभी भी हम असतुलित विकास पद्धति अपनायें तो हमको निम्नलिखित प्रश्नों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेना चाहिए

(i) क्या असतुलन उत्पन्न करना आवश्यक है और इससे कोई हानि तो नही होगी ?

(ii) किन क्षेत्रों में असतुलन उत्पन्न करना चाहिए

(iii) कितना असतुलन उत्पन्न करना चाहिए

(iv) असतुलन की अधिकतम व अनुकूलतम सीमा क्या होगी

बलबीर साहनी ने भी इसी प्रकार लिखा :

"आर्थिक विकास के आयोजन के लिए कोई एक पद्धति ही पूर्ण रूप से उपयुक्त नही है विकास अर्थशास्त्र का स्वभाव ही ऐसा है कि कोई भी एक पद्धति, स्थैगित आय सिद्धान्त के विपरीत, लागू नही होती "

अध्याय : 21

रोसेन्स्तीन रोदान तथा उनका "बड़ा धक्का" का सिद्धान्त

Rosenstein—Rodan and His "Big Push Theory"

आलोचनात्मक विश्लेषण :

1. Jacub Viner.
2. H. E. Ellis.
3. J. H. Adler.
4. वर्तमान लेखक की नजर में.

अध्याय : 21

रोसेन्स्तीन रोदान तथा उनका "बड़ा धक्का" का सिद्धान्त

Rosenstein—Rodan and His "Big Push Theory"

आलोचनात्मक विश्लेषण

रोसेन्स्तीन रोदान सतुलित विकास के पक्ष मे है परन्तु वे चाहते है कि यह सतुलित विकास पद्धति "बडे धक्के" के रूप में अपनाया जाना चाहिए प्रो० रोदान ने अपने तर्क इस प्रकार से दिए है

प्रो० रोदान का कथन है कि कम-विकसित देशो में आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी सुविधाओ (Social and economic overheads) की नीतान्त कमी है. निजी साहसियो के पास इन्हे प्रदान करने की न तो क्षमता होती है और न ही इच्छा होती है इस कारण राज्य को (जिसमे साधनो के लिए अन्य जरियो से आय प्राप्त की जा सकती है) इन सिरोपरी सुविधाओ में (यातायात, सचार, शक्ति, बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग आदि) अधिक मात्रा में एकदम धन लगाना चाहिए इस प्रकार के व्यय से निजी विनियोजको तथा औद्योगीकरण के इच्छुक देशी व विदेशी व्यक्तियों को उद्योग खोलने की प्रेरणा व सुविधा मिलेगी

प्रो० रोदान का कथन है कि कम-विकसित देशो में धीरे-धीरे विकास करना सम्भव नही होगा यह तो केवल Big Push या "बडे धक्के" से ही सम्भव हो

See : Rosenstein Rodan : "Problems of Industrialization of Eastern and S E Europe" Economic Journal June Sept 1943. pp. 204-7 "Notes on the Theory of Big Push" in Howard S. Ellis (ed) Economic Development for Latin America, St Martins Press N. York 1966 p 57-66 See : G Meier, leading issues in Economic Development p 431-440

व्ययिताएँ तो विदेशी व्यापार से भी प्राप्त हो सकती हैं और इतनी अधिक मात्रा में विनियोजन आवश्यक नहीं होगा.

इसके अतिरिक्त Viner का कथन है कि वाह्य मितव्ययिताएँ "लागत अधिक घटाती हैं, उत्पादन उतना नहीं बढाती" कम विकसित देशों में इसलिए यह नीति उपयुक्त नहीं होगी

H E Ellis : भी रोदान की उपयुक्त नीति को अपनाने की कठिनाइयाँ बतलाते हैं. वे इस नीति की निम्नकारणों से आलोचना करते हैं

(i) कम-विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादनकर्ता होते हैं. इन देशों में बाह्य मितव्ययिताएँ बढ़ने से इन वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा.

(ii) दूसरे यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि विकास औद्योगीकरण से ही हो सकता है कृषि की उन्नति से नहीं हो सकता. कम-विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय या विदेशी व्यापार आय मे से दो-तिहाई भाग कृषि से प्राप्त करते हैं इसलिए कृषि के विकास से कुल अर्थव्यवस्था का विकास सम्भव है

(iii) अगर हम विकसित देशों का इतिहास देखे तो हम पाएँगे कि उन देशों का विकास किसी "बड़े धक्के" के कारण नहीं हुआ था. तथा

(iv) रोदान ने कम विकसित देशों में बचत की समस्या को ध्यान में नहीं रखा.

J. H. Adler भी यह सोचते हैं कि थोड़ी मात्रा में व धीरे-धीरे विनियोजन से अधिक लाभदायक परिणाम निकलेंगे

वर्तमान लेखक की नजर में प्रो० रोदान का विचार ठीक है. आज हम इसी विचार को कृषि में (Package programme या Crash programme) लागू करते हैं जबकि एक साथ हम सिंचाई, बीज, खाद, उपकरण व साख आदि का एक सघन क्षेत्र में प्रबन्ध करते हैं "बड़े धक्के" से ही निर्यात क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और अन्ततः औद्योगीकरण से ही विकास हो सकता है. सोते हुए व्यक्ति या अर्थव्यवस्था को एकदम झकझोर कर ही उठाना पड़ता है अतः हम इस नीति को उचित ही मानेंगे.

अध्याय : 22

लीबिन्स्टीन का मॉडल

Harvey Leibenstein's Thesis of Critical Minimum Effort

हार्वे लीबिन्स्टीन तथा उनका "अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास" का विचार

1. प्रस्तावना
2. कम विकसित देशों की समस्यायें
3. विकास के लिए Critical Minimum Effort अर्थात् "अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास" करना अनिवार्य है.
4. विकास के लिए उचित मनोवृत्ति तथा प्रेरणाओं का सृजन आवश्यक : Transformation of attitudes, motivation and "zero-sum" incentives necessary
5. Growth agents and entrepreneurs विकास के अंगों का महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक.
6. जनसंख्या : आर्थिक विकास तथा C. M E
7. विकास के लिए उचित 'विनियोजन मानदण्ड'
8. विकास के साथ ICOR (Incremental capital output ratio) पूंजी-उत्पादन अनुपात गिरता है और इसीलिए C. M E. करना आवश्यक है.
9. श्रम-उत्पादकता : विकास की एक कुंजी.
10. समीक्षा.

अध्याय : 22

लीबिन्स्टीन का मॉडल

Harvey Leibenstein's Thesis of Critical Minimum Effort

1. प्रस्तावना :

हार्वे लीबिन्स्टीन ने अपनी पुस्तक Economic Backwardness and Economic Growth में कम विकसित देशो के सबध में एक वाद 'Thesis' को जन्म दिया. यह विचार Critical Minimum Effort या "एक अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम प्रयास न हो वरन् प्रयास की इस मात्रा को अवश्य कार्यान्वित किया जाए यह विचार Rosenstein Rodan के 'Big push' सिद्धान्त की भाँति है परन्तु विश्लेषण व सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह कही उत्तम है.

लीबिन्स्टीन ने अपने इस शोध ग्रन्थ में उन कम विकसित देशो की समस्याएँ अध्ययन की है जिनमें जनसख्या का घनत्व अधिक है, अर्थात् भारत, चीन, इडोनेशिया जैसे देश उन्होने अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में जो लिखा है उनमें तीन बातें मुख्य है

(1) एक तो उनकी पुस्तक का लक्ष्य कम-विकसित देशो की समस्याओ को समझना है न कि कम विकसित देशो की समस्याओ के समाधान के उपाय सुझाना है (परन्तु उन्होने महत्वपूर्ण उपाय सुझाए है).

(ii) दूसरे उन्होने यह अध्ययन किया है कि पिछडेपन से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, तथा

(iii) तीसरे उन्होने अपनी पुस्तक में विकास के समस्त घटको व नीतियो को अध्ययन नही किया है उनका मुख्य लक्ष्य तो उनके Critical Minimum Effort के Thesis को समझाना है.

"Economic Backwardness and Economic Growth" by Harvey Leibenstein.
Science Edition John Wiley & Sons Inc N. Y. 1957.

पुस्तक मे Critical Minimum Effort को अब C M E लिखा जाएगा.

लीबिन्स्टीन ने बताया कि कुछ देश Stationary Equilibrium या "स्थैतिक साम्य" की अवस्था मे रहते है. ये वे देश है जो हद दर्जे के पिछड़े हुए हैं. उन्होने अपने मॉडल में इन देशो को पृष्ठ भूमि में नही रखा है लीबिन्स्टीन के अनुसार विकसित देश Non-Equilibrium State या असाम्य की स्थिति मे रहते है उनकी यह प्रवैगिक साम्य की अवस्था उन्हें हमेशा दीर्घकालीन विकास की ओर ले जाती है इन देशो में पूजी स्टाक, जनसंख्या, श्रम शक्ति, तकनीक व प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं.

लीबिन्स्टीन अपने आपको quasi-stable equilibrium या quasi-equilibrium (अर्ध स्थैगिक साम्य या अर्ध प्रवैगिक साम्य) की अर्थ व्यवस्था से सबधित बताते हैं इस स्थिति में पूजी स्टाक, श्रम शक्ति, तकनीक आदि में परिवर्तन तो होते हैं परन्तु प्रति व्यक्ति आय में बहुत कम परिवर्तन होते हैं. प्रति व्यक्ति आय स्तर 'अर्ध-स्थैगिक' अवस्था में बनी रहती है. इन देशो में अर्थ व्यवस्था अपने आप प्रगति नही कर सकती (There is no built in mechanism of indogenous influences) बाह्य प्रयत्न ही (या Exogenous influences) से ही विकास हो सकता है.

लीबिन्स्टीन के अनुसार कम-विकसित देशो की मुख्य समस्या Subsistence or near- subsistence equilibrium state या जीवन निर्वाह साम्य की स्थिति को तोड़ना है

लीबिन्स्टीन ने अपने मॉडल म मौद्रिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण घटको को छोड दिया.

उनके अनुसार :

> "No attempt has been made to consider every aspect of equilibrium (but to) shed some light on central aspects of the development problems." (p 185).

2. लीबिन्स्टीन के अनुसार कम-विकसित देशो की समस्याएँ : लीबिन्स्टीन ने कम-विकसित देशो की विशेषताओं व समस्याओ का विश्लेषण

See : Chs. 4 5 and 12 of Leibenstein's book.

(पृष्ठ 40-41 देखिए) किया है, बेन्जामिन हिगिन्स के शब्दों मे, उससे अच्छा विश्लेषण करना संभव नही है. इन विशेषताओं को उन्होंने इस प्रकार बताया है.

1 आर्थिक विशेषतायें व समस्याएँ :

A. सामान्य :

1. देश की अधिकाश, सामान्यत 70 से 90 प्रतिशत, जनता कृषि पर निर्भर रहती है.
2. कृषि में "जनसख्या आधिक्य" मौजूद रहती है. अर्थात् कुछ कृषि में रत व्यक्तियो को कृषि कार्यो से हटा भी लिया जाए तो भी कृषि की उपज घटेगी नही.
3 कृषि क्षेत्र की जनसख्या तो छद्मवेषी बेरोजगारी से पीडित रहती है और इस क्षेत्र से बाहर रोजगार के अवसर बहुत कम रहते हैं
4. प्रतिव्यक्ति पूँजी की उपलब्धि बहुत कम होती है.
5. प्रतिव्यक्ति आय कम होने के कारण निम्नजीवन स्तर होता है.
6 अधिकाश जनता की बचतो की मात्रा शून्य होती है.
7. जो व्यक्ति बचत करते हैं वे उत्पादन कार्यों में नही लगाते
8. कृषि, वन व खानो में जो रोजगार प्राप्त होता है, वह स्थानीय प्रकृति का होता है.
9. कृषि उपज मुख्यतया खाद्यान्नो की होती है. देश मे प्रोटीन पदार्थो की उपज कम रहती है.
10. जनता का अधिकाश व्यय खाद्य पदार्थ तथा आवश्यक आवश्यकताओं पर होता है
11 निर्यातीत वस्तुएँ, बहुधा प्राथमिक उत्पादन की वस्तुएँ होती हैं
12. निर्यात की प्रति व्यक्ति मात्रा बहुत कम होती है
13. देश मे साख व विपणन सुविधाएँ अत्यन्त कम होती हैं
14 देश मे आवास की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रहती है

B. कृषि की मुख्य बातें :

1. कृषि में लगी पूँजी की मात्रा न केवल कम होती है वरन् जो भी पूँजी लगी

रहती है उसका ही ढग से प्रयोग नही हो पाता, जिसका मुख्य कारण भूमि का छोटे-छोटे टुकडो मे बँटा होना होता है

2. कृषि अत्यन्त पिछडे औजारो और तकनीकी आधार पर की जाती है.
3. यातायात के साधनो तथा माँग की कमी के कारण बाजार सकीर्ण रहते है. केवल थाडी सी कृषि ही आधुनिक रीतियो के आधार पर होती है.
4 छोटे-छोटे किसान अल्पकालिक विपत्ति का भी सामना नही कर पाते कृषि इस प्रकार से की जाती है कि भू क्षरण बहुत होता है.
5. कृषको की ऋण ग्रस्तता बहुत अधिक होती है
6. कृषि उपज का बहुत थोडा भाग विपणन के लिए बचता है.
7. भू-स्वामित्व प्रणाली इस प्रकार से होती है कि अधिकाश जनता जमीन की भूखी होती है कुछ व्यक्ति अधिक जमीन के मालिक बने रहते हैं.

2 जनसख्या सम्बन्धी विशेषताएँ :

1 इन देशो मे जन्म दर बहुधा 40 प्रति हजार से अधिक होती है
2. इन देशो मे मृत्यु दर भी अधिक होती है, अर्थात् औसत आयु कम होती है
3 लोगो के आहार असतुलित होते है
4 देश की अधिकाश जनता का रहन-सहन निम्नकोटि का होता है
5. साफ-सफाई के तरीके पिछडे हुए होते है व स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएँ भी कम होती है.
6. मकानो म Over crowding होती है या प्रति व्यक्ति कम स्थान प्राप्त होता है.

3. सास्कृतिक व राजनैतिक :

1 देश मे शिक्षा का स्तर निम्न रहता है तथा शिक्षित व साक्षर व्यक्तियो की सख्या का प्रतिशत कम होता है.
2. देश के कई बच्चो को भी विद्या अध्ययन के स्थान पर कार्य करना पडता है
3. देश मे मध्यम वर्ग कम व कमजोर होता है.
4. देश में स्त्रियो का स्थान निम्नस्तर का रहता है.
5. अधिकाश जनता परम्परागत रीति-रिवाजो की गुलाम रहती है.

4. तकनीकी व अन्य विशेषताएँ :

1. देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रो में उत्पादकता कम रहती है.

B : लीविन्स्टीन मानते हैं कि हर बात मे Critical Minimum Effort नही किया जा सकता. हर बात एकदम नही की जा सकती कभी कभी यह अधिक अच्छा होता है कि किसी विनियोजन को 10 वर्षो में फैला दिया जाय न कि सारा का सारा एक ही वर्ष मे कर दिया जाय हर विनियोजन को न्यूनतम मात्रा का अनुकूलतम स्तर होता है.

> "This implies that the critical minimum effort viewed as a minimum minimorum of all possible efforts that would lead to sustained real income growth involves an optimum time pattern of expenditure or effort" (P 105)

C : C M. E. की आवश्यकता क्यो होती है ?

लीबिन्स्टीन अपने C M E की आवश्यकता तथा वाछनीयता के पक्ष मे कई तर्क देते है, जिनमे से मुख्य यह है :

1. उत्पादन मे बहुत सा विनियोजन इस प्रकार का होता है कि जिसे छोटे छोटे टुकडो मे नही किया जा सकता अगर ऐसा किया तो वाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त नही हो सकती (To overcome internal diseconomics of scale due to indivisibilities the factors of production)
2. देश में सतुलित विकास के लिए C.M E. आवश्यक होगा. (Balanced growth requires lumpy investment and because of the indivisibilities C M E will be necessary)
3. कभी-कभी विकास के परिणामस्वरूप ही विकास बाधक तत्व सामने आते है. जैसे स्वास्थ्य सुविधाओ के विकास से मृत्यु दर कम होती है और जनसख्या बढती है इसके लिए यह आवश्यक होगा कि C M E. द्वारा इतना व्यय कर दिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय बढने के साथ जन्म दर भी कम हो जाए
4. विकास पुरानी मान्यताओ, आस्थाओ, विचारो व रीति रिवाजो को भेदने से होता है C M E. से कम विनियोजन से यह नही टूटते. ये तो केवल C M. E. से ही टूटेंगे परिवर्तन से ही परिवर्तन उत्पन्न होते हैं. इसके लिए C. M. E ही जरूरी है

इसी अध्याय में जनसख्या सबधी Point देखिए

"Hence a sufficiently large minimum effort is necessary at the outset if the necessary minimum momentum is to be achieved"

4 Transformation of attitudes, motivation and "zero sum incentives necessary" विकास के लिए मनोवृत्ति तथा प्रेरणाओ मे परिवर्तन

लीबिन्स्टीन का कथन है कि आर्थिक विकास तब ही हो सकता है जबकि देश की अधिकाश जनता की पुरानी मनोवृत्तिया बदल न दी जाएँ देश की अधिकाश जनता की उदासीन मनोवृत्ति को बदल कर उन्हे आय बढाने की इच्छुक तथा जोखिम उठाने की शौकीन बनाना होगा लीबिन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशो मे दो प्रकार के Incentives या प्रेरणाएँ होती हैं

(i) Zero Sum Incentives लीबिन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशो मे उत्पादन मे रत व्यक्तियो के अनुपात में अधिक लोग वितरण कार्यों मे लगे रहते हैं इस प्रकार के उद्योगो मे लगे रहने से देश की वास्तविक आय मे वृद्धि नही होती वरन केवल भाग्यहीन साहसियो से धन भाग्यशाली साहसियो को हस्तातरण होता है इस प्रकार का कार्य केवल व्यापारिक जोखिम होता है Zero Sum Incentives मे व्यक्तिगत लाभ कम व अधिक हो सकता है परन्तु सामाजिक लाभ नही होता इस प्रकार के कार्यों मे एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास तरलता का हस्तान्तरण होता है

(ii) Positive Sum Incentives इस प्रकार के कार्यों से लीबिन्स्टीन का आशय उत्पादन कार्यों से है इनमें न केवल व्यापारिक जोखिम है बल्कि इसमे उत्पादन सबधी जोखिम भी होते हैं जब देश मे positive sum enterprises का विकास होता है तबही विकास होता है

लीबिन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशो मे आवश्यकता इस बात की है कि (i) देश में zero sum incentives व enterprises कम हो तथा (ii) positive sum incentives व enterprises बढे देश मे posi

अध्याय 9 देखिए

tive sum enterprises को कायम रहना चाहिए, उनका विकास अल्प-कालिक नही होना चाहिए

कभी-कभी positive-sum incentives स्वय ही zero-sum incentives को बढावा देते है जिसको रोकना चाहिए उदाहरणतया अगर देश में positive-sum enterprises से मुद्रा स्फीति फैलती है तो सट्टे के zero-sum enterprises उत्पन्न होते है इसी प्रकार से एकाधिकारी प्रवृत्तियो से zero-sum incentives को बढावा मिलता है. आवश्यकता इस बात की है कि देश में zero-sum incentives से positive-sum incentives अधिक हो. उन्होने कहा

> "To overcome these influences which keep the economy in a state of economic backwardness a sufficiently critical minimum effort is required to sustain a rapid rate of economic growth which should stimulate a positive-sum incentive and create forces for counteracting zero-sum incentives." (अर्थात् अर्थव्यवस्था पर पडने वाले उन दुष्प्रभावो को जो कि एक देश को गरीब रखते हैं, दूर करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम मात्रा में ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए जिससे positive-sum incentives बढे तथा zero-sum incentives के दुष्प्रभाव दूर हो)

5 Growth Agents and Entrepreneurs : विकास के अग तथा साहसी

लीबिन्स्टीन का कथन है कि 'विकास, विकास के अगो का कार्य है विकास अगो का अर्थ "जनसख्या में निहित उन क्षमताओं से है जो विकास करती हैं. जब देश में इन क्षमताओ का सख्यात्मक व गुणात्मक विकास होता है तो देश के इन विकास अगो का विकास होता है.

लीबिन्स्टीन का मत है कि growth agents के विकास से आर्थिक विकास होता है और जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे-वैसे "उत्पादन अगो" का विकास होता है और growth agents ही positive-sum incentives को जन्म देते है व उनके कारण जन्म लेते हैं.

लीबिन्स्टीन "साहसियो की क्षमता" को एक विशिष्ट प्रकार का गुण मानते हैं साहसी का मुख्य कार्य विनियोजन की मुख्य मदो को चुनना होता है. वे उत्पादन के साधनो को जुटाते हैं, वे नये उद्योग शुरु करते हैं और हर चीज को बडे पैमाने पर करते हैं. कम-विकसित देशो मे साहसियो की पूर्ति कुछ ही जातियो या वर्गों तक सीमित नही रहना चाहिए जब पिछडी जातियो या वर्गों से भी साहसी उत्पन्न होने लगें तो विकास सुनिश्चित होता है.

साहसियो का मुख्य कार्य विनियोजन के उचित अवसर खोजना होता है. उनके कार्यो की सफलता उचित मौद्रिक व राजकोषीय नीतियो, उत्पादन के अगो के मूल्यो, साधनो की खोज आविष्कारो, बाजार की स्थिति आदि पर निर्भर करता है

साहसियो के कार्यो म वृद्धि से प्रति-व्यक्ति आय बढती है और प्रति-व्यक्ति आय बढने से ही साहसियो के कार्य बढते हैं कम-विकसित देशो में सबसे बुरी बात है कि इन देशो मे साहसी के कार्यो को उचित महत्व नही दिया जाता हैं

। मे जब साहसियो की positive-sum activities बढ जाती है तो देश वास्तविक आय मे वृद्धि होती है और यह पुन उनको positive-sum activities मे लगने को प्रोत्साहित करती है.

विकास की बहुत सी दरें हो सकती हैं हर क्षेत्र में एक दर से विकास नही हो सकता किन्ही क्षेत्रो के प्रति 'विकास अग" उदासीन रहते हैं या सुस्त रहते हैं. zero-sum activities हमेशा विकास की दर को कम रखती हैं बहुत अधिक विकास की दर भी थोडे समय बाद bottlenecks (या भिन्न-भिन्न प्रकार के अवरोधो के कारण) कायम नही रह पाती विकास के मध्यम दर अच्छी होती है परन्तु शुरु मे हमको "आवश्यक न्यूनतम" प्रयास अवश्य करना चाहिए.

"The rate of growth will depend on the interaction between the plans for expansion of the various growth agents, their simultaneous attempts to carryout these plans based on anticipations about the economic environment in the future and the actual rate of growth that results from these simultaneous activities which in turn, determine the plans and activities of succeeding period "

(p. 144) p 121-150] op. cit.

6. Population : Economic Growth and C. M E.
जनसख्या : आर्थिक विकास : तथा C. M. E.

जितनी जिस देश की जनसंख्या अधिक होगी उतनी ही मात्रा मे उस कम-विकसित देश को निम्न जीवन स्तर के फन्दे से निकलने के लिए अधिक मात्रा में 'अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास' करने होंगे. (अध्याय 10)

जनसंख्या और विकास के सम्बन्ध मे लीबिन्स्टीन ने कई मुद्दो पर विचार किया, जिनमें निम्नलिखित मुद्दे मुख्य हैं.

जनसंख्या का घनत्व व विकास :

लीबिन्स्टीन अधिक घनत्व को विकास मे बाधक अथवा कम घनत्व को विकास कारक नही मानते. विकास तो देश के प्राकृतिक साधनो की किस्म व मात्रा, पूंजी की उपलब्धि, तकनीकी स्तर व उत्पत्ति के नियमो पर निर्भर रहता है. उन्होने बताया कि अमेरिका के "रेड-इन्डियन्स" का घनत्व तो बहुत कम था फिर भी पिछड़ी तकनीक के कारण वे विकास नही कर पाए.

जन्म दर व आर्थिक विकास :

लीबिन्स्टीन यह भी नही मानते कि जब तक कि जन्म दर गिरे नही तब तक विकास नही हो सकता. उन्होने कहा "हमको यह नही भूलना चाहिए कि जन्म दर में कमी भी विकास का परिणाम होता है. आर्थिक विकास वगैर कोई भी प्रत्यक्ष तरीके, जन्म दर नियंत्रण में सफल नही हो सकते. वास्तव मे पहले तो आर्थिक विकास कार्य-क्रम शुरू करना होगा".

जनसंख्या की अवस्थाएँ तथा अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास :

लीबिन्स्टीन ने कम-विकसित देशो मे जनसख्या सम्बन्धी अवस्थाओ का अध्ययन किया. उन्होने C. P Black, W. S Thompson तथा F. W. Notestein द्वारा बताई गई अवस्थाओ का अध्ययन किया* इन अर्थशास्त्रियों का, मोटे मोटे रूप से, यह विचार है कि सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक व तकनीकी उन्नति के साथ जन्म दर भी घटती जाती है. सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, स्त्रियो के समाज मे स्तर की उन्नति, नगरीयकरण आदि से जन्म दर मे कमी होती है.

---

* p. 151-152.

लीविन्स्टीन ने जनसख्या की अवस्थाओ तथा जनसख्या व विकास के सह-सबंध में स्वय के विचार प्रस्तुत किए. लीविन्स्टीन का कथन है कि कम-विकसित देशों के लोग विवेकशील नही होते वे यह नही जानते कि गर्भधारण को कैसे रोका जा सकता है वे सहवास क्रिया व प्रजनन क्रिया को अलग नही कर पाते. उनके पास जनसख्या निरोध के साधन नही होते हैं और वे बहुधा इस पर अधिक ध्यान भी नही देते

कम-विकसित देशो म मृत्युदर की अधिकता के कारण अधिक बच्चे पैदा करने पडते हैं अन्यथा बुढापे म कोई व्यक्ति औलादहीन रह सकता है. इन देशो में बच्चे पालने का खर्च अधिक नही होता गरीब के बच्चे को खर्च केवल जीवन निर्वाह के बराबर देना पडता है जब कि अमीर के बच्चे को उच्च शिक्षा व रहन-सहन के कारण अधिक खर्च करना पडता है इसलिए कम-विकसित देशो में बच्चे के उत्पन्न होने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसकी लागत से अधिक रहती है.

लीबिन्स्टीन का कथन है कि एक नवजात बच्चा तीन प्रकार की उपयोगिता देता है :

(1) वह एक Consumption goods है या वह एक उपभोग वस्तु है, अर्थात् वह माँ-बाप को उसे खिलाने (प्यार करने) का सुख देता है.

(11) वह एक Productive agent भी है, अर्थात् वह स्वय कमा कर खिला सकता है और कम-विकसित देशो मे वह यह काम कम आयु मे ही कर सकता है.

(111) वह Source of security या बुढापे का सहारा है.

लीबिन्स्टीन का कथन है कि कम विकसित देशो में बच्चे पैदा होने की मात्रा को हम माँग व पूर्ति के आधार पर दर्शा सकते है . अर्थात् यहाँ भी बच्चे पैदा होना (माँग) लाभ व (पूर्ति) लागत के आधार पर निर्धारित होता है इसे वे इस प्रकार से दर्शाते है :

जनसख्या सम्बन्धी अध्याय देखिए.
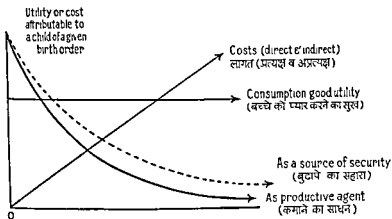
उपरोक्त चित्र में :

(i) Cost रेखा बच्चो के जन्म से बढती हैं. प्रत्यक्ष लागत का अर्थ बच्चे को खिलाने व पहनाने का खर्च होता है, तथा अप्रत्यक्ष लागत से यहाँ उनका अर्थ "अवसर लागत" से हैं. बच्चे पैदा होने के समय या बाद मे बहुधा माँ-बाप को काम से छुट्टी लेनी पडती हैं या उनकी आय व गतिशीलता कम हो जाती है इसलिए 'लागत' बढती जाती है.

(ii) बच्चे से प्राप्त होने वाली "उपभोग उपयोगिता" समान माना है. यह मानते हैं कि हर बच्चा समान आनन्द देता है और आय से इसका कोई सम्बन्ध नही है.

(iii) जहाँ तक बच्चे से प्राप्त होने वाली Productive agent utility व security utility मिलती है, यह माना गया है कि आय के बढने से हर आने वाले बच्चे का इस सम्बन्ध में महत्व घटता जाता है.

इन मान्यताओ के आधार पर लीबिन्स्टीन का कथन है कि कम-विकसित देशों मे केवल प्रति व्यक्ति आय बढने पर ही जन्म दर घटेगी, अर्थात् उनका कथन है कि

---

op cit. p. 162

पहले जन्म दर को घटा कर विकास नही होता वरन् पहले विकास होना चाहिए और फिर जन्म दर घटेगी. पहले विकास के लिए Critical Minimum Effort या 'अत्यावश्यक न्यूनतम प्रयास'' जरूरी होगे.

A. कम आय

जब अधिकाश व्यक्तियो की प्रति-व्यक्ति आय कम होती है तब मृत्यु दर अधिक होती है और इसलिए बच्चो की एक न्यूनतम मात्रा के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पडते हैं क्योकि कुछ तो मर जाते है, फिर पालने का खर्च भी तो कम होता है बच्चो के तीनो प्रकार की उपयोगिताएँ अधिक होती है. ऐसी अवस्था में अधिक जन्म दर होने हुए भी इतने बच्चे बचते है कि वे अपने माँ-बाप का प्रतिस्थापन ही कर पाते है, अर्थात् जन-सख्या वृद्धि नही होती

B. अधिक आय ·

जब देश के व्यक्तियो की प्रति व्यक्ति आय बढ जाती है तब मृत्यु दर घट जाती है. परन्तु जन्म दर तत्काल नही घटती, क्योकि अधिकाश व्यक्तियो को मृत्युदर के घटने का आभास देर से होता है. बच्चो की अनुत्पादक आयु से उनकी उत्पादक आयु बढ जाती है. इस समय मे बच्चे की ''उत्पादन उपयोगिता'' व ''सुरक्षा उपयोगिता'' एकदम बढती है इस कारण जन्म दर घटाने की कोई प्रेरणा नही रहती

C. और अधिक आय वृद्धि :

और आय बढने पर तथा अधिक बच्चो के जिन्दा रहने पर बच्चो की ''उपभोग उपयोगिता'' घट जाती है. फिर अधिक धनी व्यक्ति के बच्चे जल्दी नही कमाते तो इससे उनकी ' उत्पादन उपयोगिता'' घट जाती है, और ''सुरक्षा उपयोगिता'' की भी इतनी जरूरत नही रहती

इसके अतिरिक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपडो व अन्य खर्चो के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लागतें भी बढ जाती है

ऐसी अवस्था मे लागतें जब लाभ से बढ जाती है तो फिर जन्म दर को कम रखने की इच्छा प्रबल हो जाती है. इस प्रकार से जनसख्या की चार मुख्य अवस्थाएँ हो सकती है.

अगर किसी क्रम-विकसित देश के वर्तमान आय स्तर इस "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम हो तो विकास केवल तब हो सकता है जब अर्थव्यवस्था के बाहर से (जैसे विदेशी सहायता से) एक बडी मात्रा मे अर्थव्यवस्था में विनियोजन का " इन्जेक्शन" दिया जाए

जैसा कि हम देख चुके है कि लीबिन्स्टीन यह नही चाहते कि यह समस्त विनियोजन एक बार मे एकमुश्त कर दिया जाए. समयानुसार यह छोटी छोटी मात्रा मे भी किया जा सकता है. उनकी योजना यह है कि विनियोजन के कई "इन्जेक्शन" इस प्रकार से दिए जाएँ कि वे एक निश्चित काल मे देश की प्रति-व्यक्ति आय को "आवश्यक न्यूनतम स्तर" पर पहुँचा दे हर "इन्जेक्शन" को इस प्रकार से लगाया जाय कि इससे पहले कि प्रथम "इन्जेक्शन का प्रभाव समाप्त हो, दूसरा "इन्जेक्शन" लगा दिया जाए वे इस बात को मानते है कि एक बडे "इन्जेक्शन" के स्थान पर विनियोजन के कई छोटे छोटे इन्जेक्शन, अगर उन्हे उचित समय के अन्तर से लगाया जाये (if they are optionally spaced) तो वे अधिक प्रभावशील होगे.

परन्तु यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि बहुत छोटे छोटे विनियोजन भी प्रभावशील नही होते. हर विनियोजन के इन्जेक्शन की भी "आवश्यक न्यूनतम मात्रा" होती है जिससे कम विनियोजन नही हो सकता

लीबिन्स्टीन का कथन है कि Indivisibilities of capital goods (जैसे कोई पूजीगत मशीन स्वय में ही बडी होती है और उसे टुकडो मे तो लगा नही सकते वरन् पूरी ही लगानी पडेगी) तथा Complementarities (अर्थात् आवश्यक पूरक विनियोजन के कारण) हमेशा विनियोजन की 'आवश्यक न्यूनतम मात्रा" होती है और उससे कम खर्च नही किया जा सकता

इस प्रकार से विकास कारक विनियोजन की 'न्यूनतम' व 'अधिकतम' मात्राए निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है

Investment Criteria विनियोजन निति

जहाँ तक उचित विनियोजन नीति का प्रश्न है, लीबिन्स्टीन Kahn के The Marginal or Social Marginal Productivity Criteria (सीमान्त उत्पादकता या सामाजिक सीमान्त उत्पादकता मान दण्ड) तथा

देखिए . अध्याय 15 उपरोक्त पुस्तक का

Nurkse के The Employment Absorption Criteria (रोजगार मान दण्ड) तथा Kahn and Viner के Investment in Agriculture कृषि विनियोजन मान दण्ड को अस्वीकार करते हैं

A उनका कथन है कि Kahn की Marginal or Social Marginal Productivity Criteria के अनुसार विनियोजन करने से राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि नही हो सकती, और न ही इसमे प्रति-व्यक्ति आय अधिकतम होती है इसके अतिरिक्त विनियोजन की 'सीमान्त सामाजिक उत्पादकता" पता नही लग सकता

B. इसी प्रकार से लीबिन्स्टीन Nurkse के "रोजगार वृद्धि" मानदण्ड को भी अस्वीकार करते हैं. Nurkse का कथन, जैसा कि हम पढ चुके है, यह है कि कम-विकसित देशो में विनियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि अधिकतम लोगो को रोजगार मिल सके, और देश मे श्रम गहन तकनीक अपनाई जाए. लीबिन्स्टीन का कथन है कि अगर पूंजीगहन विनियोजन को कम रखा गया तो देश में उत्पादन विकास का निर्माण नही होगा, और इससे विकास की आमदनी धीमी रहेगी उनका कथन है

> "The full employment of those believed to be disguisedly unemployed seems pointless of other investment policies yield higher growth rates, unless it be done for its own sake" (p. 251)

C लीबिन्स्टीन Kahn तथा Viner के इस विचार से भी सहमत नही हैं कि कम-विकसित देशो को अधिकाधिक विनियोजन सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में करना चाहिए कृपि उन्नति मे ही औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार में उन्नति तथा हर क्षत्र का विकास होगा

लीबिन्स्टीन का कथन है कि इस नीति से अल्पकाल म अवश्य लाभ होगा, परन्तु कृपि क्षेत्र मे विकास से 'विकास का वातावरण" निर्मित नही होता गाँव के विकास से देश म 'श्रमिक कुशलता, तकनीक, आविष्कारो, ज्ञान तथा साहसियो की गतिविधियो में उन्नति व प्रगति नही होती"

इसके अतिरिक्त कृपि में अधिकाधिक विनियोजन से बहुधा जमीदार व बडे किसान लाभान्वित होते है. ये अपने लाभ को सोना-चाँदी, भूमि तथा सट्टो में लगा देते हैं.

D. Investment in both physical and human capital, should be on critical minimum basis

लीबिन्स्टीन के अनुसार विनियोजन भौतिक व मानवीय दोनो प्रकार की पूँजी वृद्धि मे होना चाहिए और यह "न्यूनतम आवश्यक मात्रा" म होना चाहिए जहाँ कल व कारखानो, मशीनो व खेतो मे अधिकाधिक विनियोजन हो वहाँ देश मे शिक्षा ज्ञान, तकनीक तथा कार्य कुशलता म वृद्धि होना चाहिए.

देश मे विनियोजन इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि देश मे साहसियो को बढावा मिले तथा जिससे श्रमिक की उत्पादकता म वृद्धि हो विनियोजन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे देश मे बचते भी प्रोत्साहित हो तथा जिससे जनसख्या वृद्धि भी कम हो

विनियोजन नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे और विनियोजन हो दीर्घकाल मे विनियोजन का लक्ष्य उपयोग और विलासिताओ का उपयोग बढाना होगा परन्तु अल्पकाल मे सर्वागीण उत्पादन क्षमता मे विकास करना ही सर्वोपरि होता है

> "In the long run, endless growth for its own sake does not make too much sense At some point the populace may become more concerned with enjoying the fruits of its development than maintaining the maximum rate of development...Then the problem of maximising current consumption and luxuries will be more important...But it is not our immediate problem." (p 267 8)

8 Capital-output Ratios and Critical Minimum Efforts पूजी-उत्पादन अनुपात व "आवश्यक न्यूनतम प्रयास" .

"The diminishing capital-out put ratios, as growth increases, reinforce the critical minimum effort thesis for once the initial high capital-output ratio is overcome, the obstacle to economic growth is reduced, since

See · Chapter II. p. 177-185.

a smaller rate of saving is necessary in order to induce further growth." (p 184)

लीविन्स्टीन का कथन है कि विकास के साथ-साथ पूँजी-उत्पादन अनुपात घटता जाता है. इसलिए घटते हुए पूंजी-उत्पादन अनुपात की स्थिति को पहुँचने के लिए "न्यूनतम आवश्यक प्रयास" करने ही होंगे, इससे कम मोटे मोटे रूप से जब भी हम Capital-output ratio शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारा आशय Incremental capital-output ratio से होता है. Incremental capital-output ratio (ICOR) से हमारा अर्थ **"उस दर से होता है जिस दर से विनियोजन के परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था में किसी वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है"** उदाहरणत अगर राष्ट्रीय आय का 15% भाग विनियोजित किया जाता है, और अगर यह विनियोजन राष्ट्रीय आय में 5 : 1 के अनुपात से परिवर्तन लाता है तो ICOR 3% हुआ.

लीविन्स्टीन का कथन है कि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की घटती हुई ICOR दर महत्वपूर्ण कारण हैं उनका विश्वास है कि **"अगर विनियोजन "आवश्यक न्यूनतम मात्रा" में कर दिया जाए तो ICOR घटेगा और विकास होगा"**

लीविन्स्टीन ने श्री वी बी भट्ट के इस विचार से असहमति प्रकट की कि विकास के साथ ICOR बढ जाता है श्री भट्ट का तर्क यह था कि कम-विकसित देशो मे उत्पादन म मशीनीकरण होगा और मजदूरी दर बढने से जब मजदूरों के स्थान पर मशीनें प्रतिस्थापित की जाएगी तो ICOR बढ जाएगा एक और अन्य कारण जो श्री भट्ट ने बताया वह यह है कि विकास के साथ जब प्राकृतिक साधनो की कमी आएगी (जैसे लोहे आदि की कमी) तो मशीनो की लागत बढ जाएगी और ICOR बढ जाएगा

परन्तु लीविन्स्टीन इस मत मे पूर्णत असहमत होते हुए निम्नलिखित तर्क देते हैं जिनके आधार पर वे यह साबित करना चाहते हैं कि विकास के साथ ICOR घटता है और ICOR के घटने से विकास होता है

(1) विकास के विनियोजन के कारण श्रम की कार्यक्षमता, उत्पादकता बढ जाएगी जिससे ICOR घट जाएगा

V. V. Bhatt : Capital-output ratios of certain Industries . A Comparative Study of Certain Countries. The Review of Economics & Statistics, Aug. 1954. p. 309-20.

(ii) विकास के साथ-साथ जो राष्ट्रीय आय बढती है और जो श्रम विभाजन में विस्तार होता है उससे भी ICOR घटेगा

(iii) शिक्षा व ट्रेनिंग के ऊपर होने वाले व्यय से श्रम की किस्म मे सुधार होता है, जिससे मशीनीकरण के समान स्तर पर ही श्रम के प्रयत्नो के कारण उत्पादकता बढ जाती है और ICOR घट जाती है.

(iv) विकास के साथ-साथ आर्थिक क्रियाओ का केन्द्रीयकरण कृषि के प्राथमिक क्षेत्र से हटकर Tertiary (तृतीयक क्षेत्र-यातायात सचार व व्यापार) मे लग जाता है इससे भी ICOR घटता है

(v) फिर जैसे जैसे विकास हो जाता है भारी मशीनो की आवश्यकता घट जाती है और ICOR घट जाता है

9. Labour Productivity Also A Key Factor in Promoting Growth : श्रम उत्पादकता-विकास की एक कुजी ·

अन्य समस्त अर्थशास्त्रियो की भाँति लीबिन्स्टीन भी स्वाभाविक रूपसे श्रम की उत्पादकता वृद्धि को महत्वपूर्ण मानते हैं. उनका विश्वास है कि अगर कम विकसित देशो में श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी दी जाय तो उनके स्वास्थ्य सुधार से उनके गैरहाजिर रहने की प्रवृत्ति कम होगी, उनके उपभोग वृद्धि से स्वास्थ्य सुधरेगा और उनके कार्य करने की शक्ति व इच्छा मे वृद्धि होगी.

लीबिन्स्टीन का कथन है कि केवल मजदूरी बढा देने से ही श्रम की कार्यशक्ति नही बढती अगर श्रमिक की मनोवृत्ति भी विकास के प्रति बढती है तो श्रमिक के वेतन बढने से वह अपनी कार्यक्षमता मे वृद्धि करेगा अन्यथा वह अधिक मजदूरी प्राप्त होने पर अधिक आराम करना पसद करेगा देश में कुशलता वृद्धि (Skill development) के लिए पर्याप्त धन व्यय किया जाना चाहिए शिक्षा के विकास से ही कुशलता वृद्धि होती है. देश मे पूँजी को गहन रूप से लगाने मे अधिक 'कुशलता' की आवश्यकता होती है और विस्तृत रूप मे लगाने में कम आवश्यकता होती है. (capital deepening activities require more skill than capital widening). श्रम की गतिशीलता से भी श्रम उत्पादकता बढती है जो कि विकास के लिए परम आवश्यक है.

(i) See also : Colin Clark : Conditions of Economic Progress 2nd Edition, London, Macmillan & Co. Ltd 1951 Ch-XI, Csp p. 500-4.

(ii) श्रम उत्पादकता अध्याय ६ लीबिन्स्टीन तथा पृष्ठ 141.

An Appraisal of Leibenstein Model of Growth
लीबिन्स्टीन मॉडल की समीक्षा

जैसा कि हम देख चुके हैं, लीबिन्स्टीन मॉडल की विचारधारा Rosenstein Rodan की Big push theory से मिलती है. उनका Critical Minimum Effort का विचार रोदान के "बड़े धक्के" के विचार से अधिक व्यावहारिक है उसमें जितनी पूंजी की आवश्यकता पड जाएगी उससे इस नीति को अपनाने मे कम पूंजी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लीबिन्स्टीन तो C M E. विनियोजन को कई भागो मे बाटने को भी सभव मानते हैं.

फिर भी, जैसा कि उन्होने स्वय स्वीकार किया है, उन्होंने राजकोषीय, राज्य-नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार व सहायता आदि नीतियो के विकास पर प्रभाव का अध्ययन न करके अपने मॉडल की व्यापकता कम कर दी.

•

विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन

खण्ड : 2

आर्थिक विकास नीतियाँ

अध्याय : 1

देश के प्राकृतिक साधन व आर्थिक विकास

Natural Resources and Economic Growth

विकास के लिए प्राकृतिक साधनो के प्रयोग की नीति

Resource Utilisation Policy for Growth

1. "प्राकृतिक साधनो" का अर्थ
2. विकास मे प्राकृतिक साधनो का महत्व
   प्रथम मत : (A) प्राकृतिक साधनो का महत्व नही है.
   दूसरा मत : (A) विकास में प्राकृतिक साधन महत्वपूर्ण.
   (B) सतुलित मत.
3. प्राकृतिक साधनो के प्रयोग को निर्धारित करने वाले तत्व.
   1. पूंजी, 2. साहस व संगठन, 3. तकनीक, 4. बाज़ार, 5. श्रमशक्ति 6. सामाजिक तत्व, 7. राज्य.
4. प्राकृतिक साधनो की प्रयोग नीति
   1. सर्वेक्षण करें तथा लिस्ट बनायें
   2. पूंजी का संचय पर्याप्त मात्रा में किया जाय
   3. देश की अर्थ व्यवस्था के अनुरूप तकनीक अपनायी जाय.
   4. स्थानीय साधनो का प्रयोग हो
   5. साधनो का वर्तमान प्रयोग और भविष्य में प्रयोग सतुलित रखा जाय.
   6. साधनों का बहुउद्देशीय प्रयोग होना चाहिए
   7. श्रम बाज़ार उन्नत करें.
   8. बाज़ार स्थिति के पर्याप्त व व्यापक सर्वेक्षण हों.
   9. प्राकृतिक साधनो के प्रयोग में बरबादी कम से कम होना चाहिए तथा साधनो के परीक्षण को भी ध्यान में रखना चाहिए.
   10. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग में अवरोधो व रुकावट डालने वालो को दूर किया जाये.
   11. प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लाभ अधिकाधिक व्यक्तियो को प्राप्त होना चाहिए.
   12. अनुसंधानो को प्रोत्साहित करना चाहिए.
   13. प्राकृतिक साधनों का प्रयोग तथा राज्य

अध्याय : 1

देश के प्राकृतिक साधन व आर्थिक विकास

Natural Resources and Economic Growth

विकास के लिए प्राकृतिक साधनो के प्रयोग की नीति

Resource Utilisation Policy for Growth

1. "प्राकृतिक साधनो" का अर्थ .

1. जैसा कि सर्वविदित है कि आर्थिक क्रियाओ व आर्थिक विकास के लिए तीन प्रकार के साधनो की आवश्यक्ता मुख्य है. ये साधन है
   (i) प्राकृतिक भौतिक साधन, (ii) मानवीय साधन तथा
   (iii) मनुष्य द्वारा उत्पादित भौतिक साधन (या पूंजी) Eric Zimmermann ने प्राकृतिक साधनो की परिभाषा इस प्रकार दी है ·

   "प्राकृतिक साधन भौतिक वातावरण के वे भाग होते है जिनसे मानव अपनी आवश्यक्ताओ को संतुष्ट करने के लिए साधन प्राप्त करता है."

2. प्राकृतिक साधनो के अन्तर्गत हम समस्त भूमि (जो चाहे कृषि के प्रयोग में लाई जा रही हो अथवा नही), जगल, पानी, धातुएँ आदि शामिल करते है जब कि पानी व जगल Renewable resources है या पुन. उत्पादन योग्य साधन है, धातुओ को हम Exhaustible resources या समाप्त होने वाले साधन कहेगे.

3. प्राकृतिक साधनो का हमको Dynamic या प्रवैगिक अर्थ लेना चाहिए. साधनो की माना भौतिक मात्रा के रूप मे ही नही आँकी जाती है. तकनीक

See: (i) Joseph. L. Fisher: Role of Natural Resources In Growth : in Williamson & Buttrick : Economic Development, Principles & Pattern, Prentice-Hall Inc. 1962, p. 26

(ii) Economic Development, Ed. Adamanlios Pepalasis, Leon Mears, Irma Adelman: Ch. II. Natural Resources.

में उन्नति, जनता की मनोवृत्ति मे परिवर्तन, यातायात, सचार, पूंजी की मात्रा मे वृद्धि, रुचि परिवर्तन आदि से इनके प्रयोग में वृद्धि हो जाती है और इस रूप में हम प्राकृतिक साधनो को बढता हुआ मान सकते हैं

4. हर प्राकृतिक साधन मे कुछ भाग प्राकृतिक और कुछ मानवीय रहता है, जैसे एक बजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के बाद वह आशिक रूप से 'भूमि' व आशिक रूप से पूंजी है.

2. विकास मे प्राकृतिक साधनो का महत्व :

(A) प्रथम मत प्राकृतिक साधनो का कोई महत्व नहीं है :

1. कुछ अर्थशास्त्रियो का कथन है कि प्राकृतिक साधनो के अधिक होने से विकास सुनिश्चित नही होता. अफ्रीका मे प्राकृतिक साधन भरे पडे हैं परन्तु वह बहुत पिछडा हुआ क्षेत्र है. स्वीटजरलैड व जापान प्राकृतिक साधनो की दृष्टि से पिछडे देश है परन्तु वे आज आय की दृष्टि से उन्नत देशो मे है. इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि प्राकृतिक साधनो की मात्रा तो स्थिर है, इस कारण वह अधिक महत्वपूर्ण नही है.

   Simon Kuznets साइमन कुजनेट्स के अनुसार :

   > "Any land base is sufficient to get growth started." अर्थात् विकास के लिए हर भूमि या कोई भी भूमि पर्याप्त है.

2. प्राकृतिक साधन निष्क्रिय होते है और इसी कारण उनका विकास प्रक्रिया पर प्रभाव भी निष्क्रिय होता है. उनमें गतिशीलता तब आती है जबकि देश में तकनीकी उन्नति व पूँजी वृद्धि के कारण उनका प्रयोग बढ जाता है.

   Theodore Schultz थ्योडोर शुल्ट्ज का कथन है कि '

   > "जैसे-जैसे कोई देश विकसित होता जाता है वैसे वैसे प्राकृतिक साधनो का महत्व घट जाता है क्योंकि विकसित देश के राष्ट्रीय

See : (i) Kuznets : Towards a Theory of Economic Growth in National Policy in Economic Welfare at Home and Abroad. (Ed) R. Lekachman 1955 p 76

(ii) Ch. iv : Kindleberger : op cit.

(iii) Schultz Quoted from : Pepalasis . op cit p.19

(iv) W N. Parker : J. J. Spenser (Ed). Natural Resources and Economic Growth, Washington 1961

(v) Mather quoted from Meier & Baldwin op cit p 527

आय में कृषि का योगदान घट जाता है. प्राकृतिक साधनों का राष्ट्रीय आय में योगदान "कृषि अवस्था" में वह केवल 25% रहता है परन्तु "औद्योगिक अवस्था" में वह केवल 50% तक रह जाता है."

3 Mather मायेर का कथन है कि . विश्व के आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों की कमी कभी नहीं आयेगी. यहाँ प्रकृति के भंडार हमारी आशा से अधिक भरे पड़े हैं

कभी-कभी तो प्राकृतिक साधनों की अधिकता से अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी कमी से, कृत्रिम साधनों की खोज होती है और नवप्रवर्तन की मनोवृत्ति को बल मिलता है, जैसा कि जापान व इजराइल में हुआ है.

(A) दूसरा मत : विकास में प्राकृतिक साधन महत्वपूर्ण :

बहुत से अर्थशास्त्री, रिकार्डो के समय से ही, विकास मे प्राकृतिक साधन को महत्वपूर्ण मानते हैं. इनका विचार है कि प्राकृतिक साधनों के होने से विकास होता है और कम होने या समाप्त होने से विकास कम होगा या रुक जायेगा. किसी भी देश का विकास प्राकृतिक साधनों की अधिकता या कमी पर निर्भर करता है

Osborn का विचार है कि हमारा विकास कभी न कभी प्राकृतिक साधनों की कमी से रुक जायेगा. उनका विचार है कि यह हमारे भविष्य को अन्धकार में डाल देगी. उनका कथन है कि "यह दूसरा खामोश विश्व युद्ध है."

(B) संतुलित मत :

वास्तव में प्राकृतिक साधनों की कमी से विकास का रुकना या बहुतायत से विकास का सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है. आज विश्व में 1 लाख से अधिक

(I) P. Osborn, our Plunderd Planet, Grosset and Dunlop, New York, 1948 (x)

(II) See also : Substitute Materials In War & Peace, Cecil H. Desch

(III) Ch. Iv of Bauer & Baldwin, "Natural Resources" The Economics of Under-Developed Countries." Nisbet & Combridge, 1965, (Ed).

(Iv) Dr. Miss I Z. Hussain, Economic Factors In Economic Development P. 100-101.

कच्चे माल प्रयोग में लाये जाते हैं. कोई भी देश इन सबको स्वय उत्पन्न नही कर सकता. वास्तव मे जैसा, कि Bauer and Yamey ने कहा है, "प्राकृतिक साधनो से अधिक उत्पत्ति के अन्य सहायक साधन विकास में महत्वपूर्ण हैं" वे कहते है कि U. S. A. मे रेड इण्डियन के युगो में भी तो प्राकृतिक साधन वही थे, परन्तु प्रवासी नागरिको ने ही U S A का विकास किया.

डा० (कुमारी) इशरत जेड हुसैन के अनुसार प्राकृतिक साधनो का पर्याप्त मात्रा में होना विकास मे सहायक अवश्य होता है परन्तु यह स्वय किसी देश को विकास पथ पर अग्रसर नही कर देता हैं. इनके होने से देश मे खाद्यान्न, शक्ति व धातुओं की आवश्यकता पूरी हो जाती है. विकास की उन्नत अवस्थाओं मे पूँजी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. समस्त विकास क्रिया मे तकनीक शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है.

3. प्राकृतिक साधनो के प्रयोग को निर्धारित करने वाले तत्व :

किसी भी देश मे प्राकृतिक साधनो का कम या अधिक प्रयोग कई बातो पर निर्भर करता है, जिनमे यह प्रमुख है

1 पूँजी :

पूँजी ही वास्तव मे प्राकृतिक साधनो का आकार या उपयोग परिवर्तन करती है तथा पूँजी ही उनको लाने ले जाने मे सहायता करती है उन्नत तकनीक से ही प्राकृतिक साधनो का प्रयोग बढता है और उन्नत तकनीक का अपनाया जाना स्वय अधिक पूँजी पर निर्भर करता है.

2. साहस व संगठन :

प्राकृतिक साधनो का महत्व तो साहसी ही आँकते हैं इसके लिए देश मे पर्याप्त मात्रा में आर्थिक स्वतत्रता होना चाहिए परन्तु अगर देश मे एकाधिकारी व्यवस्था है तो न तो प्राकृतिक साधनो का और न ही मानव साधन का पूर्ण प्रयोग होगा क्योंकि एकाधिकारी कृत्रिम न्यूनता बनाए रखकर ही लाभ कमाने का लक्ष्य रखता है. प्रतियोगितात्मक साहसी व्यवस्था, जो विदेशी तकनीक व पूँजी को भी प्राप्त कर सकते है, प्राकृतिक साधनो का अनुकूलतम प्रयोग कर सकते है

3. तकनीक :

तकनीक ही प्राकृतिक साधनो के प्रयोग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है. योरोप के मुकाबले में सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिक विकसित होने का कारण इसकी

उन्नत तकनीक ही है उन्नत तकनीक का अर्थ पूँजी-गहन तकनीक ही नही होता, जापान ने तो श्रम गहन तकनीक से ही बहुत कुछ कर दिखाया है

4 बाजार :

प्राकृतिक साधनो का प्रयोग बाजार के विस्तृत होने और उसमे स्थायी व अधिक माँग पर भी निर्भर करता है. बाजार के मूल्य परिवर्तन साधनो के प्रयोग की मात्रा व प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला देते है बाजार की स्थितियो में परिवर्तन होने से ही कृत्रिम साधनो की खोज होती है.

5 श्रम शक्ति :

देश मे अगर पर्याप्त मात्रा में तथा प्रशिक्षित श्रमिक है जो खानो, जगलो, कृषि मछली पालन व औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक साधनो का प्रयोग बढेगा श्रम शक्ति ही उत्पादकता निर्धारित करती है. अगर देश मे उत्पादकता अधिक होगी तो अधिक से अधिक वस्तुएँ कम से कम लागत मे बनती हैं और इससे देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती हैं.

6 सामाजिक तत्त्व :

देश की सामाजिक व सास्कृतिक स्थिति भी प्राकृतिक साधनो के प्रयोग को निर्धारित करती है जिस देश मे पढे लिखे लोगो की संख्या कम होती है वहाँ प्राकृतिक साधनो का विवेकपूर्ण प्रयोग नही हो पाता शिक्षित व्यक्तियो के सभ्य समाज मे विज्ञान व तकनीक की उन्नति से साधनो के प्रयोग का क्षेत्र बढ जाता है. कभी कभी जाति प्रथा, धर्म या रूढिवाद के कारण प्राकृतिक साधनो का उचित प्रयोग नही हो पाता.

7 राज्य :

बहुधा राज्य ही प्राकृतिक साधनो के उचित प्रयोग के लिए मार्ग दर्शन करता है और उसके लिए उचित कानूनी व आर्थिक व्यवस्था करता है. उसकी प्रशासन, राजकोषीय व अन्य नीतियाँ ही देश मे साहसियो के कार्य प्रणाली व क्षेत्र निर्धारण करती है.

4. प्राकृतिक साधनो की प्रयोग नीति :

1 सर्वेक्षण करें तथा Inventories (लिष्ट) बनाएँ :

बहुत से कम विकसित देश तो यह भी नही जानते कि उनके प्राकृतिक साधन क्या है और कितने हैं इसके लिए सर्वप्रथम, विकसित देशो या अन्तर्राष्ट्रीय

संस्थाओं की सहायता से व्यापक भूगर्भ सर्वेक्षण करना पडेगा. तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से ही प्राकृतिक साधनो के प्रयोग का लाभ-लागत पक्ष पता लग सकेगा इसके लिये पूर्ण वैज्ञानिक व इन्जीनीयरिंग सर्वेक्षण करना पडेगा.

2. पूँजी का संचय पर्याप्त मात्रा में किया जाए .

बहुत से कम विकसित देशो मे पूजी की मात्रा की कमी के कारण ही सर्वेक्षण नहीं हो पाते और इसी कारण उन्नत तकनीक नही अपनायी जा पाती. इसके लिए पूंजी निर्माण परम आवश्यक होगा. ❀

3. देश की अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप तकनीक अपनायी जा? :

हर कम-विकसित देश को "उचित" तकनीक अपनाना चाहिए यह देश मे श्रम की मात्रा, उनकी कुशलता, सगठन कर्ताओं की कुशलता, तथा पूँजी की मात्रा पर निर्भर रहेगी कम-विकसित देशों को उन्नत देशो की जटिल तकनीक नही अपनाना चाहिए, अन्यथा कम-विकसित देशो मे उनको चलाने वालो और ठीक करने वालो की कमी पड जाएगी.

4. स्थानीय साधनो का प्रयोग हो :

कम-विकसित देशो को सर्वप्रथम अपने स्थानीय साधनो का प्रयोग करना चाहिए. उसके पश्चात् ही उन्हे आयातीत कच्चे माल के उद्योग शुरू करना चाहिए

5. साधनो का वर्तमान प्रयोग और भविष्य में प्रयोग सतुलित रखा जाए :

देश में प्राकृतिक साधनो के प्रयोग की दर देश के लिए अनुकूलतम (optimum) होना चाहिए. किसी भी मँहगे साधन को प्रयोग मे लाने से पूर्व सस्ते साधन का पता लगाना चाहिए. वर्तमान मे राष्ट्रीय आय बढाने के लिए भविष्य के लिए साधनो को समाप्त नही कर देना चाहिए. दोनो कालो के लिए सतुलित प्रयोग योजना होना चाहिए

6. साधनो का बहुउद्देश्यीय प्रयोग होना चाहिए ·

कम-विकसित देशो में पूँजी साधन कम होते है इसलिए प्राकृतिक साधनो का प्रयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जैसे बाँध बनाने का कार्य ऐसा है कि इससे पानी का प्रयोग सिंचाई, बिजली उत्पन्न करना, मछली पालना, परिवहन बाढ नियत्रण व अन्य कार्यो के लिए होता है. इसके फिर अप्रत्यक्ष और प्रभाव होते है.

❀ पूँजी निर्माण के अध्याय को देखिए.

इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि साधनो के waste products (जैसे शक्कर के रस निकले गन्ने) का भी समुचित प्रयोग हो सहायक व पूरक उद्योगो को साथ-साथ निर्मित किया जाना चाहिए

7. श्रम बाजार उन्नत करें :

कम-विकसित देशो मे प्राकृतिक साधनो को प्रयोग करने के लिए, देश मे गतिशील, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए और कुशल श्रमिको का होना आवश्यक है ऐसा होने पर ही देश में उन्नत तकनीक को अपनाया जा सकता है. इसके लिए देश मे सर्वप्रथम "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम" पास करना चाहिए ताकि देश में एक सीमा से कम मजदूरी न दी जा सके इससे श्रमिको की अच्छा कार्य करने की इच्छा व शक्ति बढेगी. देश मे Incentive wages system, अर्थात् अधिक कार्य अधिक मजदूरी पद्धति, अपनाया जाना चाहिए कम-विकसित देशो मे श्रमिको को उचित हक मिलना चाहिए वहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि औद्योगिक संघर्ष एव हड़तालो और तालाबन्दियो को नही होने देना चाहिए

8. बाजार स्थिति के पर्याप्त व व्यापक सर्वेक्षण हों

साधनो के प्रयोग के लिए साहसी पूँजी लगाने से पहले यह जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओ की माँग कितनी हो सकती है, वह क्या मूल्य रख सकते है वस्तु की किस्म क्या होना चाहिए उनको बाजार मे कितनी, किस से व कैसी प्रतियोगिता का सामना करना पडेगा. इसी प्रकार से वे यह जानना चाहेंगे कि उत्पादन के अगो को प्राप्त करने के लिए (मजदूर, पूँजी व संगठन कर्ताओ को कितने मूल्य पर प्राप्त कर सकते है) उन्हे किस प्रकार की बाजार स्थिति का सामना करना पडेगा

इन समस्त चीजो के लिए व्यापक व पर्याप्त सर्वेक्षण की आवश्यकता पडेगी.

9. प्राकृतिक साधनो के प्रयोग में बर्बादी कम से कम होना चाहिए तथा साधनों के Conservation (या परिरक्षण) को भी ध्यान में रखना चाहिए.

अगर प्राकृतिक साधनो के प्रयोग मे बर्बादी कम से कम रखी जाती है तो इससे प्रति वस्तु लागत कम रहेगी. इससे मूल्य कम व काम अधिक होगे, निर्यात प्रोत्साहित होगे तथा देश में और पूँजी निर्माण हो सकेगा पानी, भूमि व वन के साधनो के प्रयोग में भविष्य के प्रयोग के लिए भी इन साधनो को बनाए रखना चाहिए.

खनिज सम्पत्ति को हम re-new नही कर सकते या समाप्त होने के बाद पुन नहीं ला सकते, इस कारण यह आवश्यक होगा कि देश मे इस सम्पत्ति का

विवेकपूर्ण प्रयोग हो और नये प्रतिस्थापन साधनो का पता लगाया जाए. इन साधनो के re-use पुनः प्रयोग सम्बन्धी अन्वेषण होना चाहिए

खनिज सम्पत्ति को हम Re-new नही कर सकते या समाप्त होने के बाद पुनः नही ला सकते. इस कारण यह आवश्यक होगा कि देश मे इस सम्पत्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग हो और नये प्रतिस्थापन्न साधनो का पता लगाया जाए. इस साधनो के re-use पुन. प्रयोग संबंधी अन्वेषण होना चाहिए.

10. प्राकृतिक साधनो के प्रयोग में अवरोधो व रुकावट डालने वालों को दूर किया जाए :

प्राकृतिक साधनो के प्रयोग के लिए कभी कभी कोई Key resource या मुख्य साधन होते है, जैसे इजराइल में कृषि करने के लिए 30% व्यय तो पानी पर ही होता है या पहाडी क्षेत्र में साधनो के प्रयोग के लिए सडके व यातायात मुख्य होते है. राज्य को चाहिए कि वह इन साधनो के जुटाने मे सहायक हो.

किसी भी देश में साधनो का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित चार मे से एक अधिक कारणो से रुक सकता है ·

(i) देश मे सहयोगी साधनों की कमी हो.
(ii) देश में मूल्य स्तर ऐसा हो, जिससे लाभ प्राप्त न हो रहे हो.
(iii) देश के प्राकृतिक साधनो को भविष्य के प्रयोग के लिए सुरक्षित रख दिया हो, और
(iv) देश मे एकाधिकारी इनका प्रयोग न होने दे रहे हो.

प्राकृतिक साधनो के प्रयोग मे Vested Interest, भी बाधक हो जाते है, जैसे कृषि को उत्तम रीति से करने के लिए जो भू-सुधार हो उनमे जमीदार लोग बाधा डाल सकते है या गामीण क्षेत्रो मे सहकारी आधार पर साख का इन्तजाम जो सहकारी सस्थाएँ करे उनमे पेशेवर साहुकार बाधा डाल सकते है. इस प्रकार के रुकावट डालने वालों को हटा देना चाहिए.

11 प्राकृतिक साधनों के प्रयोग के लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए :

प्राकृतिक साधन समूचे देश की सम्पत्ति होते है इस कारण इनके प्रयोग मे अधिकाधिक लोगो को अधिकाधिक लाभ हो. विकसित देशो में साधनो के प्रयोग को चक्रविरोधी नीति के रूप में कार्य मे लाया जा सकता है अर्थात् मंदी के काल साधनो के प्रयोग के कार्य को सार्वजनिक कार्य द्वारा बढावा दिया जा सकता है

विकासशील देश प्राकृतिक साधनो के प्रयोग पर तो ध्यान देते हैं परन्तु मानव साधनो के प्रयोग पर अधिक ध्यान नही देते. पूर्ण रोजगार की व्यवस्था भी साधनो के पूर्ण प्रयोग का अग होना चाहिए.

12. अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना चाहिए

जब तक देश में वैज्ञानिक अनुसधानों को प्रोत्साहित नही किया जाता तब तक देश में प्राकृतिक साधन सबधी जानकारी कम रहेगी, उसी प्रकार से उपयुक्त तकनीक भी नही अपनायी जा सकेगी और न ही देश में साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का पता लग सकेगा या उचित प्रतिस्थापन्न साधनों का पता लगाया जा सकेगा. इस कार्य के लिए राज्य को निजी क्षेत्र वालों को अनुसधान करने में कर संबधी छूट देना चाहिए और विदेशी विनिमय सबधी सहायता का प्रबध कराना चाहिए. राज्य को स्वय भी इस कार्य मे धन लगाना चाहिए. राज्य को चाहिए कि वह यह देखे को अनुसधान कार्य मे Duplication अर्थात् बेकार दुहरा खर्च या दुहरे प्रयत्न तो नही हो रहे हैं

13. प्राकृतिक साधनों का प्रयोग तथा राज्य :

इस सबध मे हम राज्य के उत्तरदायित्व को सीमित नही मान सकते. देश में स्वार्थी कुशल, भ्रष्टाचार स परे सरकार ही देश मे विकास करा सकते हैं. उसकी उचित मौद्रिक, राजकोषीय व मूल्य नीति पर ही साधनों का विकास निर्भर रहता है.

अध्याय : 2

विकास व कृषि

Development and Agriculture

1. कम-विकसित देशो मे कृषि की स्थिति व विशेषताएँ :

    1. कृषि राष्ट्रीय श्राय का मुख्य स्रोत है.
    2. कृषि प्राकृतिक परिस्थितियो पर श्रधिक निर्भर रहती है.
    3. देश के श्रधिकांश व्यक्तियो का रोजगार साधन है.
    4. विदेशी व्यापार का मुख्य स्रोत है.
    5. श्रधिकांश ग्रामीण श्रर्थ व्यवस्था श्रमौद्रिक भी होती है.
    6. कृषि में रत व्यक्तियो को, कृषि में प्रयोग में श्रानेवाली भूमि की प्रति-एकड़ उत्पादकता भौतिक रूप तथा मौद्रिक रूप दोनों में कम होती है.
    7. कृषि से बहुत कम "विपरान योग्य श्राधिक्य" मिलता है.

2. कम-विकसित देशो मे कृषि के पिछड़ेपन के कारण :

1 अप्रगतिशील भू-मालकियत प्रणाली व भू-सुधारो की प्रभावहीनता.
2 भूमिका अपखण्डन तथा बिखरापन तथा अनार्थिक जोतें
3. सिंचाई सुविधाओ की कमी.
4. कृषि के लिये सस्ती व सुगम साख की कमी तथा कृषकों की ऋण ग्रस्तता.
5. भू-क्षरण तथा अन्य हानिकारक प्रयोग.
6 कृषि में पिछड़ी तकनीक.
7. खाद की कमी.
8. विपणन की समुचित व्यवस्था की कमी.
9. अकुशल श्रमिक, साहसियो की कमी
10. राज्य की उदासीनता.

3 अ-कृषि का सतुलित विकास मे स्थान .

(1) पहला मत : कृषि का विकास में महत्व अधिक नही है.
दूसरा मत . कृषि के बगैर सतुलित विकास असमव है
निष्कर्ष.

(ii) विकास के साथ-साथ कृषि का महत्व घटता जाता है.

4. कम-विकसित देशो मे कृषि के आत्म-स्फूर्ति की अवस्था को पहुँचने व स्थायी विकास के लिये आवश्यक तत्व : विकास की अवस्थायें प्रथम, द्वितीय एव तृतीय

1. भूमि सुधार तथा कृषि में उन्नति.
2 भूमि की चकबन्दी, भू-क्षरण को रोकना तथा पड़ती भूमि को पाटना
3 कृषि विकास के लिये पूँजी निर्माण व साख व्यवस्था.
4 उत्तम सिंचाई, बीज, खाद और यातायात का प्रबन्ध
5 कृषि का विपणन तथा बाजार व्यवस्था उन्नत करना
6 कृषि विकास व कृषि अनुसधान
7. शिक्षा का विकास व कृषि.
8 कृषि विकास तथा मूल्य नीति
9. कृषि विकास के लिये उचित नेतृत्व व सेवाओं का प्रावधान.

अध्याय : 2

विकास व कृषि

Development and Agriculture

I. कम-विकसित देशो मे कृषि की स्थिति व विशेषताएँ Characteristics of Agriculture in Under-Developed Countries

कम-विकसित देशो में कृषि की क्या स्थिति है इस सम्बन्ध मे कम विकसित देशो के निवासी भलीभाँति परिचित है सक्षेप मे इनको निम्नलिखित ढग से वर्णित किया गया है.

1. कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है
2. कृषि प्राकृतिक परिस्थितियो पर अधिक निर्भर रहती है तथा 'Prince to pauper cycles" से पीडित रहती है
3. देश के अधिकाश व्यक्तियो का रोजगार साधन है
4. विदेशी व्यापार का मुख्य स्रोत है.
5. अधिकाश ग्रामीण अर्थव्यवस्था अमौद्रिक भी होती है Non-monetized transactions persist in agricultural sector.
6. कृषि में रत व्यक्तियो की, कृषि प्रयोग में आने वाली भूमि की प्रति-एकड उत्पादकता भौतिक रूप तथा मौद्रिक रूप दोनो मे कम होती है.
7. कृषि से बहुत कम 'विपणन योग्य आधिक्य" मिलता है

बहुत हद तक कम विकसित देशो की गरीबी की समस्या, कृषको की गरीबी की समस्या होती है. विश्व की समस्त जन-सख्या का 60% या 1500 मिलियन व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहती है. इनमें से 1200 मिलियन व्यक्ति कृषि एशिया, अफ्रीका तथा मध्य व दक्षिणी अमेरिका में है और शेष योरोप व उत्तरी अमेरिका में हैं. जहाँ योरोप मे हर तीन में से एक, उत्तरी अमेरिका में हर पाँच में से एक व्यक्ति कृषि मे लगा है, वहाँ एशिया व अफ्रिका मे हर चार व्यक्तियो में से तीन व्यक्ति कृषि में लगे रहते है

"Land Reforms" · U. N. Publications P 3

कम विकसित देशों में कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन होती है लगभग 50% राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है.

Benjamin Higgins के शब्दो मे

> "With a large proportion of the population engaged in agriculture on very small holding, the rural sector acts as an anchor sunk deep in the sands of time, so that the ship of state can never move far from its present becalmed position with low levels of productivity and income"[1]

कम विकसित देशों में कृषि सदियों से पिछड़ी व स्थैगिक अवस्था में पड़ी हुई है.[2] सयुक्त राष्ट्र अमेरिका मे 1800-1940 के बीच 100 बुशल गेहूँ पैदा करने के लिए Man-hours श्रम घटा की मात्रा 373 से घटकर 47 रह गई. वहाँ 1820 में 2 व्यक्ति मिल कर तीसरे व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध करा देते थे 1946 मे एक ही व्यक्ति 15 अन्य व्यक्तियों के लिए उत्पादन कर सकता था भारत में 4 व्यक्ति मिल कर आज भी 5वें के लिए उत्पादन नही कर पात.

कम विकसित देशों में, Umbreit, Kunt तथा Kinter के शब्दो मे कृषि 'Prince to pauper cycles" तथा "Pauper to prince cycles" से पीडित है. (अर्थात् आज के धनी कल गरीब, या आज के गरीब कल धनी बन जाते हैं)[3]

कम विकसित देशा की कृषि हर प्रकार की बेलोचदार अवस्था का शिकार होती है. यहाँ पर भूमि की मात्रा, भूमि से कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन का उपभोग तथा कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की पूर्ति सब ही बेलोचदार रहती है

जहाँ तक उत्पादकता का प्रश्न है, यह भी सर्वविदित है कि कम विकसित देशो में प्रतिव्यक्ति व प्रति एकड उत्पादन बहुत कम है कम विकसित देशा के मुकाबले 1/4 से लेकर केवल 1/10 भाग उत्पादित कर पाते है. भारत मे कृषि उत्पादकता लका, जावा, मिश्र की ही आधी तथा ब्राजील की 1/7 भाग है.

---

1. B. Higgins · op. cit p 454-5
2. D B Singh · op cit : p 471
3. Umbreit, Hunt, Kinter Ch 25 Econ by G L Bach.

U N O के अनुमानो के अनुसार जहाँ उत्तरी अमेरिका में कृषि मे रत प्रति व्यक्ति का वार्षिक उत्पादन $3\frac{1}{2}$ टन है वहाँ कम विकसित देशो मे, जैसे एशिया मे यह केवल 1/4 टन है और अफ्रीका म 1/8 टन है.

कम विकसित देशो मे कृषि ही मुख्य धन्धा, मुख्य आय का साधन तथा मुख्य निर्यात का साधन है और जब वह ही स्थैगिक व पिछडा उद्योग है तो समस्त अर्थव्यवस्था ही पिछडी रहती ह कम विकसित देशो मे कृषि मे रत व्यक्तियो की सख्या वढती जा रही है और इसका कारण यह नही है कि यह उद्योग अधिक आय या अधिक सुरक्षा या अधिक उच्च-सामाजिक स्तर प्रदान करता है वरन यह इसलिए है कि अन्य क्षेत्रा म रोजगार के अवसर ही नही वढते है, और कृषि मे रत व्यक्तियो की गतिशीलता कम होती ह

कम विकसित देशो के लगभग 50% निर्यात तो कृषि वस्तुओ के होते है और अन्य 25% कृषि वस्तुओ पर ही आधारित होते ह इसी प्रकार राज्य की आय भी कृषि क्षेत्र से आती है मालगुजारी प्रणाली बेलोचदार प्रणाली होती ह और इस कारण राज्य की आय भी नही वढती है कृषि मे प्रकृति के कोप या मेहरबानी के अनुसार राज्य की आय भी घट बढ जाती है जो वडी ही अनिश्चित परिस्थिति होती है.

कृषि ही देश के औद्योगिक विकास का आधार होती ह और अन्य क्षेत्र जैसे तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) कृषि विकास पर वढता है.

परन्तु आज भी कम विकसित देशो म कृषि से विपणन योग्य आधिक्य कम निकलता है और आज भी कृषि क्षेत्र में अमौद्रिक सौदे होते है और यह क्षेत्र अन्धविश्वास, रूढिवादिता, भाग्यवादिता, अशिक्षा, अज्ञान व सुस्ती का क्षेत्र वना है

II. कम विकसित देशो मे कृषि के पिछडेपन के कारण .

कम विकसित देशो मे कृषि पिछडी है और पिछडेपन के कारण भी सर्वविदित है. फिर भी सक्षेप में उन्हें प्रस्तुत करना, समस्या के समझने व निराकरण के लिए आवश्यक है इन कारणो में मुख्य यह है

1. अप्रगतिशील भू मालकियत प्रणाली व भू-सुधारो की प्रभावहीनता
2. भूमि का अपखडन तथा विखरापन, तथा अनार्थिक जोतें.
3. सिंचाई सुविधाओ की कमी.

Kindleberger op Cit p 218 9

4. कृषि के लिए सस्ती व सुगम साख की कमी तथा कृषकों को ऋणग्रस्तता
5. भू-क्षरण तथा अन्य हानिकारक प्रयोग.
6 कृषि में पिछड़ी तक्नीक
7 खाद की कमी.
8 विपणन की समुचित व्यवस्था की कमी.
9. अकुशल श्रमिक, साहसियों की कमी.
10. राज्य की उदासीनता

1 अप्रगतिशील भू मालक्यित प्रणाली व भू-सुधारो की प्रभावहीनता :

कम विकसित देशों मे भूमि की मालकियत कुछ व्यक्तियो के हाथ रहती है जैसे इन देशो मे आय व सम्पत्ति कुछ हाथो में केन्द्रित रहती हैं वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रो मे भूमि की मालक्यित कुछ के ही हाथो में केन्द्रित रहती है. मिश्र (Egypt) में 1952 में देश के 72% कृषकों के पास 1 या इससे भी कम एकड के खेत में और उनके पास केवल 13% भूमि ही थी, जबकि देश के केवल 1/2 (आधा) प्रतिशत किसान (या सही मायनों में जमीदार) 50 एकड या इससे अधिक के मालिक थे व उनके पास समस्त भूमि का 34% भाग था.

इराक मे हाल के वर्षो तक वहाँ के शेख बडी बडी भूमि के टुकडो के मालिक है. सिंचाई वाले क्षेत्र तो लगभग सब उनके पास है वहॉ पर Fellahin (फेल्लाहिन या Serf) 'गुलाम' काश्तकार अपनी उपज का $\frac{2}{5}$ भाग इन शेखो को दे देते है. अगर शेख बीज देता तो $\frac{2}{3}$ और पानी देता था तो $\frac{5}{7}$ भाग तक देना पडता था. तब 1952 व 1958 में भू-सुधार किए गए.

स्वय भारत मे राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के अनुसार जमीदारी उन्मूलन से पहले देश में 25 एकड से अधिक मालकियत वाले 4% परिवारो के पास कुल स्वाम्य-भूमि का 34% था और 50 एकड से अधिक स्वाम्यधारी 1% परिवारों के पास कुल स्वाम्य-भूमि (कुल मालकियत भूमि) का 16% था.

इसके विपरीत 5 एकड से कम के स्वाम्यधारी 53% परिवारो के पास लगभग 17% भूमि थी. 5 और 25 एकड के भीतर स्वाम्यधारी 22% परिवारो के पास कुल स्वाम्य-भूमि का 49% था 22% परिवारो के पास कोई भूमि न थी.

इन देशो मे हाल के वर्षो मे बहुत से भू-सुधार हुए है परन्तु आज भी स्थिति ठीक नही है. भू-सुधार न होने से कृषि पर बहुत से दुष्प्रभाव पडते है जैसे

(1) कृषि मे प्रति एकड व प्रति व्यक्ति उपज कम होती है

(ii) कृषि मे उन्नत साधनो, व सिंचाई अच्छे बीज आदि का प्रयोग नही हो पाता.

(iii) कृषको को अधिक उपज की प्रेरणा नही रहती.

(iv) कृषको का जीवन स्तर गिरता है

(v) कृषको द्वारा बचतें व पूंजी-निर्माण की कमी रहती है U.N. की एक रिपोर्ट के अनुसार :

> "भू-सुधार न होने से भूमि का उचित व अच्छा प्रयोग नही हो पाता और जिन भू-पतियो के पास कम भूमि होती है वे भूमि को अधिकाधिक जोतकर उसके क्षरण को उत्पन्न करते है."

भारत के सम्बन्ध में Prof. M.L. Dantwala ने जो बाते कही है वे अन्य देशो पर भी लागू होती है उन्होंने कहा है .

> "अगर कोई मुझसे यह पूछे कि भारत के भू-सुधार नियमों की विशेष बात क्या है तो मै यह कहूँगा कि वह उनको कार्यान्वित न करना है."

नियम बनाना आसान है पर उन्हे कार्यान्वित करना कठिन है. इन देशो मे नियम बनाने मे ढील ढाल रहती है एवं उन्हे कार्यान्वित करने मे भी ढील रहती है नियम बनाने व कार्यान्वित करने से पहले जो जोर-शोर के एलान होते है उनसे जमीदार व भूमि-पतियो को पता चल जाता है और वे उसके अनुसार कानूनी Loophole या छिद्र निकाल लेते है और बच निकलते है. राज्य का प्रशासन भी इन सुधारो को कार्यान्वित करने में सर्वथा अयोग्य व अनिच्छुक पाया गया है.

भारत मे "खुदकाश्त" कहकर बहुत से जमीदार भूमि दबाये रहे और भू-वितरण नही होने दिया. भारत के भिन्न-भिन्न राज्यो मे नियम अलग-अलग रहे परन्तु उन सब में एक ही समानता रही की उनके कार्यान्वित करने में सुस्ती से काम लिया गया. जमीदारो ने किसानो से "ऐच्छिक" रूप से बहुत सी भूमि छुड़वा ली.

See also : (i) "Land Reform" U.N. *Defects in Agrarian Structure as obstacles to Economic Development* p. 65.

(ii) "Land Reforms in India" Tokyo Conference Papers on Economic Growth M L. Dantwala.

(iii) Ford Foundation Report on Land Reforms in India.

राज्यों ने भू-सुधार की घोषणा की तो कार्यान्वित होने से पहले ही किसानों को बेदखल कर दिया गया.

भूमि की जोत की मात्रा निर्धारण से बचने के लिए परिवार के सदस्यों में ही भूमि के वितरण की कागजी कार्यवाही कर ली गई आय का एक चौथाई भाग लगान में चले जाने से बचत बहुत कम रहती है.

2. भूमि का अपखंडन तथा विखरापन तथा अनार्थिक जोतें :

कम विकसित देशों में कृषि भूमि की जोतें बहुत छोटी है. जहाँ अमेरिका में 75 एकड़ का खेत छोटा माना जाता है वहीं भारत जैसे कम विकसित देश में 5 एकड़ का खेत ही बड़ा माना जाता है जनसंख्या की अधिकता, कृषि योग्य भूमि की कमी (Leibenstein के अनुसार विश्व का $\frac{1}{3}$ भाग जो रेगिस्तान तथा और $\frac{1}{3}$ भाग कृषि योग्य नहीं है) जनसंख्या की वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र म रोजगार के अवसरों की कमी तथा उत्तराधिकार के नियमों के कारण भूमि का उपखंडन होता ही चला जाता है. जापान, चीन, इन्डोनेशिया, भारत, कम्बोडिया, वियतनाम व लंका में जन-संख्या का भार इतना अधिक है कि प्रति व्यक्ति 1/2 एकड़ से भी कम भूमि हिस्से में आती है भूमि के अपखंडन के साथ-साथ उनका विखरापन भी एक गम्भीर समस्या है कृषकों की पूरी भूमि कई टुकड़ों में बँटी रहती है (कहीं कहीं तो 25 टुकड़ों तक में) जो पास-पास नहीं होते.

भूमि-उप-विभाजन एवं अप खण्डन के दोष जाहिर है कम-विकसित देश अनार्थिक जोतों के देश बन गए हैं. इतने छोटे खेतों के कारण आधुनिक रूप से कृषि नहीं हो पाती सिंचाई की सुविधाओं का प्रयोग नहीं हो पाता, उत्पादकता कम रहती है तथा आय कम रहती है इस व्यवस्था से बहुत सी कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है. कृषकों की ऋणग्रस्तता बढ़ती है और कृषि की पिछड़ी व्यवस्था बनी रहती है

3. सिंचाई सुविधाओं की कमी :

कम-विकसित देशों की कृषि मौसमी बरसात पर ही अधिक निर्भर रहती है. पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन तथा कृषकों की अनिच्छा से सिंचाई से कृषि का अनुपात अभी भी कम है भारत में 20% से भी कम कृषि सिंचाई पर आधारित है कम-विकसित देश अपने पानी का 5-10 प्रतिशत भाग ही काम में ले पाते है W. S. Woytinsky तथा E S Woytinsky के अनुसार अगर सिंचाई

W S Woytinsky and E S. Woytinsky : World and Population and Production.

सुविधाएँ उपलब्ध कर दी जाएँ तो वर्मी में 1.9 करोड एकड भूमि और कृषि योग्य बनाई जा सकती है. इराक मे यह भूमि 60 लाख एकड से बढ कर 200 लाख एकड हो जाएगी, सीरिया मे 40 लाख एकड से 100 लाख एकड हो जाएगी तथा टर्की मे यह मात्रा 250 लाख एकड से 400 लाख एकड हो जाएगी

कम-विकसित देशो में कृषक लोग समय पर पानी देना, सही मात्रा में पानी देने के बारे मे पूर्णरूप से जानकारी नही रखते. सिंचाई की सुविधाओ की कमी के कारण एक से अधिक उपज नही ले पाते, प्रति एकड व व्यक्ति उपज कम रहती है

कृपकों में बेरोजगारी तथा छद्मवेषी बेरोजगारी बढती है उत्पादन लागत अधिक तथा कम व खराब उपज व कच्चा माल पैदा होता है. कम-विकसित देशो मे बाढो की अधिकता या सूखे का कृषि शिकार होती रहती है या पानी से निकलने वाले नमक से हानि उठा जाते है.

4. कृषि कार्यों के लिए सस्ती व सुगम साख, विशेष रूप से दीर्घकालीन विनियोजन के लिए, की कमी तथा कृपको की ऋणग्रस्तता.

जैसा कि सर्वविदित है, कम-विकसित देशो के अधिकाश कृपक अपनी पिछडी व छोटे पैमाने की खेती के कारण उनके पास "विपणन योग्य आधिक्य" कम रहता है इस कारण उनकी आय, बचत व पूंजी कम रहती है और वे पिछडे ढग से खेती करते रहते है और वे कम आय व ऋण-ग्रस्तता के दुश्चक्र में फँसे रहते है उनकी अधिक जन्म, कम आयु दर तथा कुछ सामाजिक-धार्मिक रीति रिवाज भी उन्हें इस स्थिति में बनाए रखते है और जैसा कि आमतौर से कहा जाता है

"कृपक पालने से कब्र तक ऋण में रहते है"

इस कारण जब कभी भी कृपक को कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तो उसे दूसरो से ही उधार लेना पडता है. कम-विकसित देशो मे मुद्रा बाज़ार इतना विस्तृत नही होता कि वह ग्रामीण क्षेत्रो की आवश्यकता पूरी कर सके इसलिए पेशेवर व्यापारी यह उधार देने का कार्य करते है और कृपको को चूसते रहते है. भारत के बारे में जो All India Rural Credit Survey Committee ने लिखा था वह समस्त कम-विकसित देशो के लिए अनुपयुक्त नही है. कमेटी ने लिखा था

> "To day the agricultural credit that is supplied falls short of the right quality, is not of the right type, does not serve the right purpose,

and by the criterion of need often fails to go to the right people"

कृषकों की Credit worthiness या उधार लेने की साख कम होती है जिससे वे ब्याज अधिक देते हैं साहूकार उन्हें अल्पकालिक ऋण ही देते हैं जिससे दीर्घकालीन विकास कार्य नहीं होता भारत में 70% किसान ऋणग्रस्त हैं और भारत में आज भी इन्हें राज्य व सगठित संस्थाओं से केवल 10% के लगभग ऋण मिलता है. कृषि में दीर्घकालीन विनियोजन की कमी के कारण कृषि पिछड़ी रहती है.

5. भू-क्षरण तथा भूमि के अन्य अनार्थिक प्रयोग :

कम-विकसित देशों ने अपनी मिट्टी की उर्वरता को बराबर कायम नहीं रखा. हजारों वर्षों से भूमि का जिस मात्रा में प्रयोग हो रहा है उस मात्रा में उनकी उर्वरता को बनाए रखने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं युगों युगों से वर्षा और हवाओं ने भूमि का कटाव जारी रखा है. Wind erosion जिसमें आँधी अच्छी मिट्टी को ले जाकर दूसरे स्थान पर पटक देती है और भूमि को नगा छोड़ जाती है, Gully erosion जो वर्षा के पानी की नालियों के रूप में हजारों एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य हो गई है बहुत अधिक मात्रा में हुई है. इससे भी अधिक इन देशों में पशुओं की चराई, जगलों की कटाई व वर्षा आदि के कारण उपजाऊ मिट्टी बहकर ऊपर हजारों एकड़ भूमि की उर्वरता नष्ट हो गई है और कम-विकसित देशों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया. इन कटाव के कारण इन देशों में बाढ़ों का वेग बढ़ा है. भूमि की पानी सोखने की शक्ति कम होती है जिससे सिंचाई के लिए Sub soil या भूमि के अन्दर कुओं का पानी कम होता है कृषि योग्य भूमि कम होती है जबकि इन देशों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है. इसके कारण ही कम-विकसित देशों में कृषि Creeping death (धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर) की ओर जा रही है

6. कृषि में पिछड़ी तकनीक :

कम-विकसित देशों में कृषि के पिछड़े पन का सबसे प्रमुख कारण पिछड़ी तकनीक ही है. जापान ने उन्नत तकनीक को अपनाकर ही छोटे छोटे खेतों पर भी अधिक

पाकिस्तान में विश्व बैंक ने "सेम व थोर के मसले" (अर्थात् भूमि में पानी भर जाने व नमक आजाने की समस्या) को सबसे गम्भीर माना और उसके दूर करने में सहायता की

उपज उत्पन्न करके दिखला दिया है. श्री नेहरू ने इसी कारण एक बार कहा था "While the world is now in atomic age, we are living in cow-dung age." विकसित देशों में कृषि के शुरू से आखिर तक के कार्य मशीनों से होते हैं जो अधिक उपज देते हैं और वहा आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए भी इन्तजाम हो जाता है कम-विकसित देशों में श्रम की कमी नही है इसलिए पूर्ण मशीनीकरण न तो सभव होगा और न वाछनीय होगा. परन्तु फिर भी ट्रेक्टर तथा अन्य आधुनिक उपकरण व तकनीक तो अपनाई जा सकती है. 1960 मे जहाँ स्वीटजरलैंड मे प्रति 1000 हेक्टर मे 83 ट्रेक्टर थे, पश्चिमी जर्मनी मे 81 थे, नीदरलैंड मे 44, इंगलैंड मे 59 थे वहाँ टर्की मे केवल 107 ही थे.

W. S. Woytinsky तथा E S. Woytinsky के अनुसार 1955 मे आज विश्व के समस्त ट्रैक्टरो में से 68 प्रतिशत तो उत्तरी अमेरिका मे, 23% योरोप में, 3 प्रतिशत दक्षिणी अमेरिका मे थे, सुदूर तथा पास पूर्व मे 1 प्रतिशत थे और अफ्रिका में 2 प्रतिशत थे 1951 मे U S A. मे प्रत्येक 119 एकड के पीछे एक ट्रेक्टर था, कनाडा मे 247 एकड के पीछे एक ट्रेक्टर था, भारत मे 21000 एकड के पीछे एक ट्रेक्टर था और इन्डोनेशिया मे 2, 71, 810 एकड के पीछे एक ट्रेक्टर था

कम-विकसित देशों में कृषि करने, खाद व पानी देने या भू-क्षरण रोकने आदि के सबध मे अधिकाश जनता आधुनिक तकनीक से अनभिज्ञ है

7. खाद तथा अन्य आवश्यक लागतो की कमी :

कम-विकसित देशो मे यूँ तो खाद दिया जाता है परन्तु आवश्यक मात्रा मे आवश्यक खाद नही दिया जाता कृषि के लिए नाइट्रोजन, पोटास तथा फासफोरस की आवश्यकता पडती है.

F. A. O. की Year-book of Food and Agricultural Statistics, Rome, 1956, (p 213) के अनुसार, 1954-55 में

> "1954-55 मे विश्व मे जितना नाइट्रोजन रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ उसका 45% तो योरोप मे प्रयोग मे लाया गया, 32 प्रतिशत उत्तरी अमेरिका मे प्रयोग में लाया गया, 4% दक्षिणी अमेरिका में प्रयोग में लाया गया, निकट पूर्व मे 3% कार्य में लाया

W. S. Woytinsky & E. S Woytinsky : op. cit.

गया, सुदूरपूर्व में 16% प्रयोग मे आया और सम्पूर्ण अफ्रिका में केवल 1% नाइट्रोजन की खपत हुई थी."

इसी प्रकार से Eastern Economist, Annual No. 1962 के अनुसार

> "नीदरलैंड मे प्रति हेक्टर 461 किलोग्राम का प्रयोग हुआ, पश्चिमी जर्मनी मे 278 कि० ग्रा० हुआ, स्वीट्जरलैंड मे 207 कि० ग्रा० U K. मे 180 कि० ग्रा०, ग्रीस में 31, स्पेन में 29 कि० ग्रा० भारत में 3 कि० ग्राम, व टर्की मे 1 किलोग्राम रहा"

जो कुछ भी रासायनिक खाद का प्रयोग होता है वह विशेष रूप से बडे बागान व फार्मो में प्रयोग होता है कम विकसित देशो में इस सबध मे कुछ कठिनाइयाँ है :

(1) पहले तो इन देशो म कृत्रिम खाधो का उत्पादन ही कम है भारत में ही यह निश्चय नही हो पा रहा है कि अतिरिक्त खाद उत्पादन करने के लिए विदेशी कम्पनी को इजाजत दी जाए या भारत के निजी क्षेत्र को दिया जाए, अथवा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र से उत्पादन बढे. इस प्रकार की अनिश्चितता की बहुत आलोचना की जाती है

(11) दूसरे सिंचाई सुविधाओ की कमी के कारण इनका उतना अधिक प्रयोग सभव नही है और भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि को कौन सी खाद अच्छी रहेगी इसके भी अच्छे सर्वेक्षण नही है

कम-विकसित देशो में High yielding Varieties अधिक उपज देने वाले बीजो का भी आवश्यक मात्रा मे प्रयोग नही हो पाता है

इसी तरह फसलो की रखवाली के लिए Barbed wire या कीटो से रक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयो का प्रयोग भी नही हो पाता है या बहुत कम होता है.

8. विपणन की समुचित व्यवस्था की कमी :

जैसा कि हम जानते है कि कम-विकसित देशो मे एक तो "विपणन योग्य आधिक्य" ही कम होता है और दूसरे उसके विपणन में बहुत सी कमियाँ व बुराइयाँ रहती है. कम-विकसित देशो मे फसलो का एकत्रीकरण, श्रेणी विभाजन, विधायन (processing) सग्रहण, यातायात तथा अर्थ प्रवधन ठीक से नही होता. इन देशो मे विपणन का कार्य अधिकतर "मध्यस्थ" लोग करते है और वे वास्तव मे सट्टे के रूप मे व्यापार करते है कृषको को उनका उचित मूल्य नही मिलता वरन् मध्यस्थ लोग ही (विशेष रूप से अर्थ-प्रबधक पेशेवर लोग) उनकी मेहनत का

बडा भाग ले लेते है. कृषको की फसल को रोक कर बेचने की शक्ति कम होती है इससे वे ऐसा करते हैं.

कम विकसित देशो के द्वारा निर्मित वस्तुओ के विपणन मे भी ऐसे ही दोष पाए जाते हैं इन देशो की मडियो में बेईमानी, धोखेबाजी तथा शोषण सब प्रचलित रहते हैं.

9. अकुशल श्रमिक, साहसियों की कमी

कम-विकसित देशो के कृषक अशिक्षित होते हैं. जिसके कारण उनके रहने, कृषि करने, व सोचने विचारने के तरीके पिछडे हुए हैं. इसी कारण इनके यहाँ जन्म-दर अधिक रहती है. ये कृषि के उन्नत तरीकों की आवश्यकता के प्रति अनभिज्ञ होते है या उदासीन रहते हैं. अशिक्षा के कारण वे भाग्यवादी होते हैं और फिर वे सतोषी जीवन-यापन करते है और भौतिक उन्नति के प्रति उदासीन हो जाते हैं अधिक आय प्राप्त होने पर श्रम की मात्रा कम करके आराम करने लगते है या कृषि की मात्रा कम कर देते है इसी कारण वे अपव्यय कर देते है और पूंजी निर्माण कर कृषि में अच्छा विनियोजन नही करते.

उनके अशिक्षित रहने के कारण ही वे महाजनो, व्यापारियों के चगुल मे फँस जाते है और भू सुधार नियमो के लाभ नही उठा पाते. जमीदार लोग उन्हे धोखा दे देते हैं. कृषको की अशिक्षा व पिछडेपन के कारण ही उनकी व्यावसायिक व भौगोलिक गतिशीलता कम होती है और कृषि मे छद्मवेषी बेरोजगारी बनी रहती है.

Boulding के शब्दो मे

> "कृषि मे अन्य उद्योगो की भाँति साहसियो को कार्य करने के अवसर नही है"

10. अन्य कारण : राज्य की उपेक्षा : साम्राज्यवादियो द्वारा शोषण :

कम-विकसित देशो का विकसित देशो ने खूब शोषण किया. उन देशो से कच्चा माल कम मूल्य पर लेते रहे और कृषि को उन्नत करने का प्रयत्न नही किया गया. अधिकाश कम-विकसित देश पिछले 25 वर्षो मे ही स्वतन्त्रता पाए हैं और साम्राज्यवादी देशों की सरकार कृषि की उन्नति के प्रति उदासीन ही रही. इन देशो की सरकारें सिंचाई सुविधाएँ बैठाने, किसानो को भूमि-सुधार से लाभान्वित करने, उन्हें अच्छी तकनीक सिखाने, उन्हे आवश्यक उपकरण व Inputs या लागतें प्रदान करने, उन्हें आर्थिक सहायता देने व उनके लिए विपणन सुविधाएँ देने के प्रति उदासीन रही हैं. अनुसधान के प्रति भी ध्यान नही दिया.

कृषको को प्रकृति से लडने या प्राकृतिक प्रकोपो से बचाने का कोई कार्य नही किया गया मूल्यो के उच्चावचन से भी उन्हे सुरक्षित नही रखा गया

III. A The Place of Agriculture in Balanced Growth कृषि का सतुलित विकास मे स्थान :

पहला मत : कृषि का विकास में महत्व अधिक नहीं है.

बहुत से अर्थशास्त्रियो का मत है कि कृषि के विकास के साथ-साथ महत्व घट जाता है तथा कृषि का विकास करने मे महत्व अधिक नही होता. उनमें से एक मत इस प्रकार है.

K K. Kurihara : के० के० कुरिहारा :

कुरिहारा का मत है कि कृषि म उत्पादकता इतनी कम होती है कि कम-विकसित देशो की अल्प-पूंजी को इतनी कम उत्पादकता के क्षेत्र में लगाना घातक होगा. इसके विपरीत उद्योगो में उत्पादकता अधिक होती है और इसलिए इसी क्षेत्र मे पूंजी लगाना चाहिए

इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र म व्यक्तियो की "सीमान्त उपभोग क्षमता" अधिक होती है अर्थात् उनकी बचत क्षमता कम होती है. इस कारण कृषि की समस्त उन्नति अधिक उपभोग म निकल जाती है और इस कारण विनियोजन से पूंजी निर्माण नही होती.

तीसरा कारण यह है कि उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र की "व्यापार की शर्तें" (Terms of trade) औद्योगिक क्षेत्र की व्यापार की शर्तो के मुकाबले में गिरती जाती है इस कारण यह उपयुक्त होगा कि औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत किया जाये और कृषि क्षेत्र को परिणामस्वरूप उन्नति होने दिया जाए

इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र मे उन्नत तकनीक का अपनाना अधिक कठिन होता है. कृषि क्षेत्र बृहद् क्षेत्र होता है जिसमे एक साथ उन्नति कठिन हो जाती है. इस क्षेत्र मे सामाजिक व सास्कृतिक बाधाएँ भी आती है यह क्षेत्र तो विकास के प्रति उदासीन होता है, इस कारण इस क्षेत्र का विकास इतना आसान नही है.

दूसरा मत : कृषि विकास के बिना सतुलित विकास असभव है :

अधिकाश अर्थशास्त्री, स्वाभाविक रूप से इस मत के है कि अगर कम-विकसित

K K. Kurihara : Theoretical objections to Agriculture Based on Economic Development. Indian Journal of Economics, Oct. 1958. p 163-9

देशों मे विकास करना हो तो सर्वप्रथम कृषि को विकसित होना चाहिए उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मत दिये जाते हैं

1. Giuseppe Ugo Papi . जिसेप यूगो पापी :

श्री पापी का मत है कि इससे पहले कि किसी अन्य क्षेत्र मे विकास शुरू किया जाए, सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र को सुधारना होगा इसी की उन्नति से देशवासियो को अधिक व अच्छा भोजन मिल सकेगा, उद्योगो को अधिक अच्छा व सस्ता कच्चा माल मिल सकेगा तथा देश मे अच्छा रहन सहन का स्तर होगा देश में कृषि क्षेत्र के मूल्य जब तक सस्ते न हो तब तक देश में मूल्य वृद्धि को रोका नही जा सकेगा. फिर देश में मजदूरी बढेगी और मुद्रा स्फीति फैलेगी. इसलिए विकास के लिए यह आवश्यक है कि खाद्यान्न, कच्चे माल व अन्य आवश्यक वस्तुओ के उत्पादन के लिए प्रति व्यक्ति व प्रति एकड उपज बढाई जाए.

कृषि उत्पादन में उन्नति से कपडा उद्योग, शक्कर उद्योग, तेल उद्योग तथा बहुत से अन्य उद्योग तो प्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित होते हैं. अन्य उद्योग भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं जब वे उद्योग जो कृषि उन्नति से उन्नत होते हैं बढते है तो उनसे देश के मशीन बनाने के उद्योगो तथा अन्य सहायक व पूरक उद्योगो को बढावा मिलता है

कृषि के उन्नत होने मे कृषि क्षेत्र से जो व्यक्ति हटते है वे औद्योगिक क्षेत्र को सस्ते श्रम के रूप में उपलब्ध होते है.

कृषि की उन्नति से ही औद्योगिक क्षेत्र और फिर तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) जैसे यातायात व सचार क्षेत्र, या बैंक व साख क्षेत्र का विकास होता है. सम्पूर्ण निजी क्षेत्र का विकास होने लगता है. श्री पापी का कथन है .

> "The key to development is the growth of agricultural income, and if a country fails to achieve this before all else, the whole development process may be held back" (P. 76).

2 Theodore W. Schultz :

श्री शुल्ट्ज भी इसी मत के है कि अगर किसी काम को पूरा करना हो तो उसे कायदे से शुरू से करना पडेगा. कृषि के विकास न करने पर खाद्यान्न विदेशो

1 E. A. op cit : Ch. iv : The Place of Agriculture in Balanced Growth.

से मंगाना पड़ेगा और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशों में ही चली जाया करेगी.

3-4-5 : C. P. Kindleberger, B F Johnston तथा J. W. Mellor.

ये अर्थशास्त्री भी कृषि के विकास को सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया का पहला चरण मानते हैं इनका कथन है कि कृषि विकास से उद्योगों का विकास होगा, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और खाद्यान्न के आयात का खर्च बच सकता है कम विकसित देश जितनी आसानी से कृषि उपज को निर्यात कर सकते हैं उतनी आसानी से औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुएँ निर्यात नहीं कर पाते

इसके अतिरिक्त जब तक कृषि क्षेत्र विकसित नहीं होगा, औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं की माग कहाँ से उत्पन्न होगी कृषि का विकास करके, तथा उसकी बढ़ी हुई आय को उचित राजस्व नीतियों द्वारा कर के रूप में लेकर पूंजी निर्माण भी कर सकते है. कृषि विकास से ही उपभोग व उत्पादन क्षेत्र में साथ-साथ विकास हो सकता हैं.

Dr Bright Singh

डा० ब्राइट सिंह भी कृषि विकास को प्राथमिकता देने के पक्ष में हैं उनका कथन है कि कम-विकसित देशों म विशेषकर एशिया में न्यूनतम आवश्यक जीवन निर्वाह उपभोग स्तर से भी 5 से लेकर 20% कम है. इन देशों में उपभोग का अधिकांश भाग खाद्यान्न पर व्यय होता है और जब आय बढ़ती है तो सर्वप्रथम कृषि पदार्थों की ही मांग बढ़ता है (Income elasticity of food is high......coefficients range between 0.6 to 0 7). अर्थात् अगर किसी व्यक्ति की आय 1 रुपए से बढ़ती है तो खाद्यान्न की आय 60 से 70 पैसे तक बढ जाती है

---

1. Theodore W. Schultz The Economic Organisation of Agriculture : Mc Graw Hill, New York 1953 P. 273
2. C. P. Kindleberger op cit P 218-19.
3. B. F. Johnston & J W. Mellor, "The role of Agriculture in Economic Development, American Economic Review, Sept., 1961. P. 566-593

Dr. Bright Singh (Prof. of Economics, Madras University) : op-cit. ch. XIV : p 500.

कम विकसित देशो मे जनसंख्या की वृद्धि 2 से 2 5% प्रतिवर्ष हो रही है. इस प्रकार से इन देशो मे भुखमरी रोकने के लिए ही कृषि की उन्नति आवश्यक होगी.

विकास के साथ-साथ कृषि उपज की किस्मो की माँग भी बढती है फिर अच्छे अनाज, फल, सब्जी, घी, दूध तथा गोश्त व अडो की माँग बढती है. अगर कृषि का विकास नही करेंगे तो कच्चे माल महगे होंगे और फिर देश मे महँगाई से निर्यात भी हतोत्साहित होंगे.

परन्तु डॉ० सिंह यह भी कहते है कि कृषि की उन्नति इस प्रकार से नही की जानी चाहिए कि कृषि पदार्थो की बहुतायत से मूल्य गिर जाएँ और कृषको को हानि होने लगे कृषि की उन्नति माँग के अनुरूप ही होना चाहिए.

कृषि की उन्नति से ही देश मे सडको, आवास व शहरीकरण का विकास होगा. कृषि की उन्नति से ही देश मे श्रम की सीमान्त उत्पादकता बराबर होती है अन्यथा कृषि क्षेत्र में सीमान्त उत्पादकता कम रहती है. कृषि विकास ही कृषि की बेरोजगारी समस्या का निराकरण है.

निष्कर्ष :

जैसा कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है, कृषि का विकास, विकास प्रक्रिया की पहली सीढी है तथा आवश्यक कार्य है निष्कर्ष मे हम Meier and Baldwin का मत उद्धृत कर सकते है :

> "कृषि व उद्योग का विकास एक दूसरे के प्रतियोगी नही है वरन् एक दूसरे के पूरक है बहुधा उद्योग क्षेत्र का विकास कृषि क्षेत्र के विकास पर आधारित है. कृषि क्षेत्र के विकास बिना केवल औद्योगिक क्षेत्र के विकास से मुद्रा स्फीति फैलेगी. कृषको की आय में वृद्धि किए बगैर उद्योगो का विकास नही हो सकता. विकास के लिए उन्नत कृषि की मजबूत नीव चाहिए. बहुधा यह कहा जाता है कि कृषि की उत्पादकता कम है परन्तु कृषि में जो ऊँची सीमान्त सामाजिक उत्पादकता है उसको ध्यान मे नही रखा जाता कृषि कम प्रति व्यक्ति आय के लिए उत्तरदायी नही है वरन् पिछडी कृषि इसके लिए उत्तर-दायी है और अगर कृषि को उन्नत किया जाए तो फिर देश मे प्रति व्यक्ति आय बढेगी, जो विकास का मापदण्ड है."

Meier and Baldwin : op. cit. p. 353-56 p. 407.

वास्तव मे बहुत से अर्थशास्त्री कृषि को ही प्राथमिकता देना चाहते है. उनका कथन है "you have to start somewhere before starting everywhere, and it is better to start from the beginning and from agriculture" यह मत U N reports मे हमें देखने को मिलता है.

सतुलित विकास के समर्थक तो कृषि के पक्ष मे लिखते ही है, कुछ असतुलित विकास के पक्ष में लिखने वाले अर्थशास्त्री भी कृषि मे विनियोजन को महत्व देते है

भारत ने तीसरी पचवर्षीय योजना की पूर्ण सफलता न होने पर इस तथ्य को समझा है और कृषि की तरफ पूर्ण ध्यान देने पर आज कृषि उपज की पर्याप्तता के कारण जो मूल्य गिरे है उससे अर्थव्यवस्था पर strain या भार कम हुआ है.

Benjamin Higgins ने भी इसी प्रकार कहा है

> "So far as industry vis agriculture is concerned it is not a question of balanced growth or unbalanced growth but one of balanced growth or no growth at all."

III B Declining Importance Of Agriculture In Growth Process विकास के साथ-साथ कृषि का महत्व घटता जाता है

विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण अवश्य है परन्तु जैसे-जैसे विकास होता जाता है वैसे-वैसे कृषि का महत्व घटता जाता है K.E Boulding के अनुसार "कृषि मे तकनीकी सफलता से ही उसका महत्व घट जाता है." इसका मुख्य कारण कृषि-उपज की Low-income elasticity है, अर्थात् आय बढने के साथ साथ एक सीमा के बाद कृषि पदार्थों की माँग घटने लगती है फिर राष्ट्रीय आय मे कृषि का योगदान और कम होता जाता है. श्री मारटिन एन (Martin Anne) ने कृषि पदार्थों की आय-लोच इस प्रकार आकी है

1. K.E Boulding . "Principles of Economic Policy" Agriculture Policy. ch. 13. p 314 ff
2 Martin Anne : "Economics & Agriculture, Routledeg and Kagan Paul, London 1958 P. 21.

लका	.79	स्वीडेन	.32
जर्मनी	.36	यू.एस.ए.	.27
यू०के०	.33		

डॉ०एजवर्ट दी व्रीज (Dr. Egbert de Vries) के अनुमार अगर देश में 10 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वास्तविक आय वृद्धि होती है तो कृषि का योगदान $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत गिर जायेगा. भारतवर्ष मे 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि मे लगे है जो राष्ट्रीय आय के 50 प्रतिशत भाग को उत्पन्न करते है. इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र मे व्यक्तियो का योगदान अकृपि क्षेत्र के मुकाबले मे केवल $\frac{3}{7}$ ही है. जैसे-जैसे विकास आगे बढ़ता है कृषि का कार्य राष्ट्रीय आय मे योगदान कम हो जाता है. U.S.A. मे जहाँ 18 वी सदी मे 90 प्रतिशत साधनो को लगाया गया वहाँ 1870 तक यह प्रतिशत केवल 50 था और 1960 मे यह 15% रह गया. कालान्तर में यह प्रतिशत 5 तक रह जाएगा.

कृषि क्षेत्र मे अकृषि क्षेत्र मे अधिक आय कमाई जाती है. इसलिए विकास के साथ-साथ लोग कृषि क्षेत्र को छोडकर दूसरे क्षेत्रों मे जाने लगते है. कृषि में जो तक्नोकी उन्नति होती है उससे भी बहुत से व्यक्ति कृषि कार्यो के लिए फालतू हो जाते है इसी प्रकार से भूमि की पूर्ति के बेलोच होने के कारण (जनसख्या वृद्धि के साथ भूमि की मात्रा नही बढ़ती है) भी लोगो को दूसरे क्षेत्रों मे जाना पडता है.

इसके अतिरिक्त जब कृषि के विकास के परिणामस्वरूप कृषि मे अधिक उत्पादन होता है तो कृषि के मूल्य गिर जाते है जबकि उद्योग मे बनी वस्तुओं के मूल्य नही गिरते. इससे कृषि की भुगतान की शर्तें (Terms of Trade) विपक्ष में जाती है. कृषि क्षेत्र के अनुपात मे उद्योग क्षेत्र में अधिक लाभ होने लगते है कृषि के अनिश्चित वातावरण से जहाँ मौसम की अनिश्चितता बनी रहती है तथा जहाँ मौसमी व्यापार चक्रो का प्रभाव पडता है, वहाँ से लोग निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाते है जहाँ लाभ अधिक होते हैं. कृषि का आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति-कर्ता के रूप मे भी महत्व घट जाता है क्योकि आधुनिक युग में कृत्रिम कच्चे माल (Synthetic Products) के कारण भी पैदा होने लगे हैं :

---

1. Egbert de Vries : Quoted from P. 465 of D. B. Singh's op. cit.

कृषि का विकास शुरू करने में महत्व है, विकास के बाद महत्व घट जाता है :

> "Though salvation of a country lies in industrialization raising of agricultural production will be sine qua non of any programme for growth."[1]

IV. Conditions for Agricultural Take-off and Sustained Growth in Under-Developed Countries : कम-विकसित देशों में कृषि के आत्मस्फूर्ति की अवस्था को पहुँचने व स्थायी विकास के लिए आवश्यक तत्व :

कृषि विकास के लिए सर्वोत्तम नीति है "Remove the cause remove the evil" अर्थात अगर हम दोष दूर कर दे तो विकास स्वयं होगा.

Johnston and Mellor ने कृषि के विकास को तीन अवस्थाओं मे बाँटा है प्रथम Pre-condition का दूसरी अवस्था मे कृषि मे श्रम-गहन व पूंजी बचत करने की नीतियाँ अपनाना चाहिये, और तीसरी अवस्था में पूंजी-गहन व श्रम बचत करने वाली तकनीक अपनाना चाहिए

प्रथम अवस्था में :

हमको (i) भूमि-सुधार करना चाहिए, भूमि का अनुकूलतम वितरण करना चाहिए, लगान की स्थिति ठीक करना चाहिए.

(ii) कृषकों को शिक्षित करना चाहिए तथा उनकी पिछड़ी मनोवृत्ति को दूर करना चाहिए.

(iii) विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए

(iv) भूमि की चकबन्दी का कार्य करना चाहिए, परती भूमि को कृषि योग्य करना तथा भू-क्षरण को समाप्त करना चाहिए.

द्वितीय अवस्था में :

हमको (i) कृषि की तकनीक मे उन्नति करना चाहिए

(ii) अच्छे बीज, अच्छी सिचाई व खाद की सुविधाएँ प्रदान करना चाहिए.

(iii) कृषि साख व सहकारिता की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए.

(iv) यातायात में सुधार होना चाहिए.

---

1. J. R. Hicks . Essays in World Economics, Oxford 1959 p 194-5

(v) कृषि मे अनुसन्धान.

(vi) सरकारी सहायता व व्यवस्था परिपक्व हो जाना चाहिए

तृतीय अवस्था में :

हमको कृषि का यन्त्रीकरण करना चाहिए.

Johnston and Mellor की इन अवस्थाओं के अनुसार ही कृषि के लिए आवश्यक नीतियो का अध्ययन करेगे इनमे थोडा-सा सुधार कर दिया गया है परन्तु तर्कों मे अन्य अर्थशास्त्रियो के मत का समावेश किया गया है.

IV-I. Land Reforms and Agricultural development भूमि-सुधार तथा कृषि मे उन्नति :

कृषि विकास के लिए शायद सर्वप्रथम भूमि-सुधार आवश्यक होगा. जो बडे-बडे जमीदार बडी-बडी जमीने रखे रहते है उन्हे लेकर कृषिहीन किसानो को उनका मालिक बनाना चाहिए बडे जमीदारो को कभी भी ऐसी जमीन को रखने की इजाजत नही देना चाहिए जिस पर वे स्वय कृषि न कर सके. इससे कृषक-मजदूरो की रोजगार स्थिति मे चाहे परिवर्तन न हो परन्तु इससे उनकी आय बढेगी तथा उनका सामाजिक स्तर तथा उनकी सुरक्षा मे वृद्धि होती है.

भूमि-सुधारो का लक्ष्य देश की भूमि का ऐसा वितरण होना चाहिए जिससे कि भूमि के टुकडे अनुकूलतम आकार के हो जाएँ. भूमि-सुधार का कार्य तब तक अधूरा रहेगा जब तक कि साथ ही साथ छोटे किसानो को अलग-अलग सहकारी सगठन मे बाँधकर वित्तीय सहायता भी नही प्रदान किया जाता पूँजी की आवश्यक पूर्ति के साथ विपणन, सग्रह आदि की सुविधाएँ भी प्रदान करना चाहिए. भू सुधार का काय भूमि की मालकियत में परिवर्तन ही नही हो जाता है. भू-सुधार तो एक निरन्तर चलती रहने वाली क्रिया है. नये मालिको को शिक्षित करना भी अत्यन्त आवश्यक है.

G. U. Papi के अनुसार

> "The history of land reforms is full of examples of sorry failure, which go to show that the

B. F. Johnston and J W Mellor, "*The Role of Agriculture in Economic Development*," American Economic Review, Sept. 1961, pp 566-593.

problems of agriculture do not respond to isolated measures"

भूमि-सुधार से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है. कृषकों में अपने निजी लाभ बढ़ाने का प्रोत्साहन होता है, और धीरे-धीरे उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके उपभोग स्तर में वृद्धि हो जाती है.

प्रो० दान्तवाला तथा के० ई० बोल्डिंग ने यह भी बताया है कि भूमि-सुधार को कृषि में क्रान्ति लाने का निश्चित कदम नहीं मान लेना चाहिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से भूमि-सुधार निश्चित ही आवश्यक है, परन्तु अगर कृषि के बड़े मालिकों से जमीन लेकर गरीब कृषकों को देने से तकनीकी स्तर तथा विनियोजन की मात्रा गिर जाती है तो भूमि के अनार्थिक टुकड़ों में बट जाने से कृषि उपज गिर सकती है इसलिए कृषि उन्नति के लिए पूंजी व्यवस्था तथा सहकारी कृषि आवश्यक हो जाती है.

लगान में कमी[1]

कम-विकसित देशों में 70% आय खाने पर खर्च की जाती है और खाने की लागत में अनुमानतः 33-34 प्रतिशत भाग लगान का होता है. इस प्रकार से आय का 1/4 भाग लगान में चला जाता है. इसके विपरीत उन्नत देशों में केवल 12% आय खाने पर खर्च होती है जिसका 20% भाग ही लगान के रूप में जाता है इस प्रकार से लगान का भाग राष्ट्रीय आय का केवल 2 5% होता है लगान की अधिकता को कायम रखने के लिए Vested interest (मतलबी दलों) का उदय होता है और वे भूमि सुधार नहीं करने देते.

क्या लगान को कम करना चाहिए ? इसका उत्तर आसान नहीं है लगान कम करने से राज्य की आय कम होती है तथा उसमें कृषि उन्नति कार्य करने की क्षमता घटती है या इसी प्रकार से जमीदारों की पूंजी घटती है. जापान में तो लगान वृद्धि के कारण ही वहां के किसान अधिक पैदा करते थे ताकि वे लगान चुकाकर अपने लिए बचा सकें

इस सबंध में हम यह कह सकते हैं कि लगान पद्धति को प्रगतिशील बनाकर लगान ले सकते हैं. जो किसान अधिक या अधिक मूल्य की फसलें उगाते है उनसे

1. See also : Bayer and Yamey . op cit. ch. xiv.
   See D B Singh : op cit. p 475.
   Schultz Economic Organisation of Agriculture . Mc Graw Hill N York 1953 p 125-7.

अधिक लगान लिया जा सकता है और कम आय पाने वाले किसानों से कम या शून्य लगान लिया जा सकता है.

IV. II भूमि की चकवन्दी, भू-क्षरण को रोकना तथा पडती भूमि को पाटना

कम-विकसित देशो में भूमि-सुधार के बाद सर्वप्रथम भूमि के बिखरे टुकडो को चकवन्दी करके आर्थिक जोतो में परिवर्तित करना चाहिए भू-सुधार का लक्ष्य भूमि के बडे टुकडो को तोडना ही नही होता हे वरन् उनको अनुकूलतम जोता मे परिवर्तन करना चाहिए. बडे पैमाने की कृषि के लाभो को पूर्ण रूप से समाप्त नही करना है इसलिए भूमि की चकवन्दी के बाद सहकारिता के माध्यम से बडे पैमाने पर कृषि हो सकती है प्रत्येक कम-विकसित देश मे आर्थिक जोतो का निर्माण होना चाहिए जो एक कृषक परिवार को एक निश्चित आय प्रदान कर सके आर्थिक जोत की मात्रा किसी देश मे न्यूनतम अपेक्षित आय' भूमि की उर्वरता, सिंचाई सुविधाएँ, कृषि करने का तरीका, फसलो का स्वरूप, मूल्य स्तर आदि पर निर्भर करेगा.

भूमि की चकवन्दी करने के पश्चात यह भी आवश्यक है कि आगे पुनः भूमि का अपखडन न हो इसके लिए आवश्यक नियम बनने चाहिए. जहाँ तक हो सके चकवन्दी को ऐच्छिक रूप से कराना चाहिए अन्यथा अनिवार्य रूप मे भी चकवन्दी की जा सकती है.

चकवन्दी के साथ-साथ कृषि भूमि की उच्चतम सीमा भी निर्धारित करना चाहिए. भारत मे ही, उदाहरणतया, कृषि क्षेत्र के 34·4% भाग पर 4·5% व्यक्ति कृषि करते है, जबकि 15 5% भाग पर 66 9% व्यक्ति कृषि करते है और लगभग 19% कृषि मे रत व्यक्ति भूमि विहीन है. 45% व्यक्तियो के पास 5 एकड से भी कम भूमि है. इसलिए भूमि की सीमा बाँध कर भूमि-विहीन श्रमिको मे भूमि बाँट देना चाहिए. बडे-बडे बागानो या कच्चा माल उगाने वाली इकाईयो को नही तोडना चाहिए. सीमा निर्धारण से धन की असमानताएँ दूर होती है, रोजगार मे वृद्धि होती है तथा कृषि मे उत्पादन भी बढ जाता है. बहुधा बडे जमीदार भूमि को सट्टे के लिए काम में लाते है.

पडती भूमि को पाटना चाहिए :

कम-विकसित देशो में आज भी लाखो एकड भूमि दल-दल, अनावश्यक जंगलो, समुद्र के किनारे, अर्धरेगिस्तान, कृषि योग्य पहाडी भूमि तथा अन्य स्थानो पर

कृषि के प्रयोग में नही आ रही हैं इनको अगर पुन स्थापन करदें तो वास्तव में भूमि की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है

भारत में मोटे तौर से कृषि के प्रयोग की यह स्थिति है

कुल क्षेत्रफल 32 68 करोड हैक्टर
वर्गित क्षेत्रफल 30 56 ,, ,,

इस 30 56 करोड हैक्टर में से भूमि का प्रयोग इस प्रकार है

उचित प्रयोग	1 कृषि की जाने वाली भूमि	45 4%
	2 जगल	19.0%
	3 शहरी भूमि, सडकें आदि	4 8%
	4 चारा भूमि	4 7%
	5 फल-कुज, आदि	1 9%
		75 8%
उचित प्रयोग न होने वाली भूमि		
	1 कृषि योग्य भूमि जिसका प्रयोग नही है	5.8%
	2 परती भूमि-चालू व अन्य	7 1%
	3 कृषि के अयोग्य भूमि	11 3%
		24 2%
	कुल दोनों का जोड—	100 0%

अगर प्रयत्न किए जाएँ तो Terrace cultivation (सीढी के रूप में खेतो में खेती) पहाडी इलाको मे की जा सकती हैं. जहाँ तक वनो का सबध है वे आवश्यक अवश्य हैं पर हम यह कर सकते है कि अर्धरगिस्तानी इलाको मे जगलो का विस्तार करें तथा जहाँ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि निकल सकती है वहाँ जगल काटे जा सकते है कृषि के अयोग्य भूमि को भी बहुत ही अधिक मात्रा में विनि-योजन करके तथा उन्नत विज्ञान की तकनीक को अपनाकर कुछ न कुछ उपज लायक बनाया जा सकता है

कम-विकसित देशो मे विकसित देशो के अनुपात मे कृषि योग्य भूमि या तो कम है या जनसख्या की अधिकता से प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम है. आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक अर्थात् 3 04 हैक्टर है. इसके बाद कनाडा म 2 26 हैक्टर, रूस म 1 15 हैक्टर व अमेरिका में 1 04 है. भारत में यह मात्रा केवल 0 37 हैक्टर, वर्मा में 0 63 हैक्टर व जापान में मात्र 0 07 है

ऐसी स्थिति म Bayer तथा Yamey का मत है

'जहाँ भूमि कम तथा जनसख्या अधिक हो वहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन बढाने के स्थान पर प्रति एकड उपज बढाना चाहिए" (पृ० 382)

सहकारी कृषि

कम विकसित देशो मे जहाँ सभव हो सहकारी कृषि की जानी चाहिए इससे भूमि का राष्ट्रीयकरण किए वगर ही वड पैमाने पर कृषि की जा सकती है इस प्रकार की कृषि से व्यक्तिगत कृषि एव सामूहिक कृषि दोनो के लाभ प्राप्त हो सकत हैं जैसा कि हम जानते है सहकारी कृषि व्यवस्था से उन्नत तक्नीक अपनाई जा सकती है सिचाई की उत्तम व्यवस्था सभव होगी साख व विपणन का उत्तम प्रबन्ध हो सकेगा यह भी सभव है कि इस प्रकार की कृषि से विपणन योग्य अधिक से अधिक पैदा हो तथा इससे कृषि के आग विकास के लिए अधिक पूजी निर्माण सभव होगा इस प्रकार की सस्था को बैको से भी विनियोजन के लिए धन मिल जाता है उत्तम उपज कम मूल्य म पैदा होती है तथा मूल्यो के उच्चावचनो से सामूहिक सुरक्षा हो सकती है

अगर जमीन की मालकियत अलग रखना है तो जैसा कि फ्रास, नार्वे, नीदरलैंड इगलैंड या मेक्सिको में है यह सहकारिता मशीनो, पानी व साख पशुओ की सुविधाओ के लाभ उठाने के लिए अपनायी जा सकती है पूर्वी योरोप के देशो में इस प्रकार की सस्थाएँ सफलता पूर्वक कृषि के विकास म सहयोग देती है U N O के अनुसार

> 'It is clear that if small farms are to gain the benefity of new development co-operative farms, can fulfil a useful indeed an essential, function"

IV-III Capital formation and credit facilities in Growth कृषि विकास के लिए पूजी निर्माण व साख व्यवस्था

कृषि विकास के हर कार्य के लिए पूजी की आवश्यकता होती है भूमि-सुधार के बाद यह पूजी जमीदारो से नही मिल सकती और कृषको को पेशेवर उधार देने

"Land Reforms' p 80

वालो के चगल मे छुडाने के लिए भी यह कार्य राज्य, बैंक तथा सहकारिता के आधार पर ही करना पडेगा कम-विकसित देशो में कृपको की अल्पकालिक, मध्य-कालीन तथा दीर्घकालीन समस्त आवश्यकताओ को पूरा करना पडेगा. आज की स्थिति मे "Money lender cannot be ended, he can be mended only." अर्थात् महाजन को समाप्त नही किया जा सकता वरन् उसकी कार्यप्रणाली मे सुधार किया जाना चाहिए. इसके लिए राज्य को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिए ताकि लायसेंस शुदा पेशेवर उधार देने वाले उचित रूप से उधार दे सकें राज्य को लम्बे काल से चले आ रहे ऋणो को अनिवार्य रूप से कम कर देना चाहिए शिक्षा के विकास के साथ कृपको का अनुत्पादक ऋण के कम होने की आशा है परन्तु उत्पादक कार्यो के लिए उसकी मांग बढेगी इसके लिए देश मे सहकारी साख सर्वोत्तम व सबसे सस्ती होगी. देश के केन्द्रीय बैंक को तथा अन्य बैंको को इस प्रणाली मे मदद देना चाहिए. बैंक तो अल्प-कालिक आवश्यकताओ के लिए ही ऋण दे सकते है. इन बैंको को चाहिए कि इन देशो मे भूमि बन्धक बैंको के ऋण पत्रो व बिलो मे धन लगाकर उनकी साख व्यवस्था मजबूत करें और बहुत बडी मात्रा में पूजी की आवश्यकता के लिए बडे निगमो की स्थापना की जानी चाहिए ये निगम व सस्थाएँ बहुत बडी दीर्घकालीन योजनाएँ जैसे सिंचाई योजनाएँ, भू-रक्षण व पुनरुद्धार योजनाओ के लिए सहकारी सस्थाओ को ऋण दे सकती है।

अल्पकालिक तथा गाँवो व किसानो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहकारी सस्थाएँ ही आवश्यक होगी इनसे कम ब्याज दर पर धन प्राप्त होगा तथा लाभ से भी सदस्यगण ही लाभान्वित होते है कम-विकसित देशो में सहकारिता के आन्दोलन को अपेक्षित प्रगति नही कर पाई क्योकि कृपक अशिक्षित है, महाजनो ने इनकी सफलता मे रोडे अटकाए तथा इनमे भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा. फिर भी जैसा कि कहा जाता है

> "Co operation has failed, co-operation must succeed"

IV-IV. Extension of irrigation facilities, provision of better seeds and fertilizers and transportation.

सिंचाई :

कम-विकसित देशो मे सिंचाई की सुविधाओ का विस्तार परम आवश्यक होगा. इसके लिए बडे-बडे बाँध आवश्यक होगे जो कुछ समय बाद सस्ता पानी तथा

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सस्ती बिजली प्रदान करेंगे परन्तु हाल की समस्याओं के निराकरण के लिए कम धन की मध्यम व छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में जल निकासी संबंधी सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए सिंचाई सुविधाओं के समुचित प्रयोग के लिए खेतों में नालियाँ पृथक-पृथक बनाया जाना चाहिए कुओं, तालाबों तथा नलकूप योजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इन्हें बनाने के साथ-साथ अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए. सिंचाई के साथ-साथ भूमि में अधिक खाद देना चाहिए. जलवायु वेदन और नमक फूलने के दोषों के निवारण हेतु पानी की अधिकता वाली भूमि में से पम्पों द्वारा पानी बाहर निकालना चाहिए. नहरों के तल कंक्रीट से बनाना चाहिए, जल निकासी के मार्गों को साफ रखना चाहिए, कुओं से सिंचाई को प्रोत्साहन देना चाहिए, कृषकों पर जल के मितव्ययितापूर्ण प्रयोग के लिए जोर देना चाहिए और नहरों से समय के अनुसार पानी मिलना चाहिए

बड़ी सिंचाई योजनाओं से रोजगार में वृद्धि होती है, बाढ़ों में सुरक्षा तथा भूमि कटाव का नियन्त्रण होता है, कृषि उपज की मात्रा व किस्म बढ़ती है, एक से अधिक फसलों की प्राप्ति की जा सकती है, यातायात की सुविधाएँ बढ़ती हैं और *विद्युतीकरण से छोटे बड़े सभी उद्योग बढ़ते हैं.*

खाद :

खाद की सुविधाएँ भी बढ़ाना जरूरी हैं. इन्हीं पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि इन देशों में बहुत कम खाद दी जाती है. कम-विकसित देशों में महँगे खाद के होते हुए भी आजकल विदेशों से खाद नहीं मँगायी जाती और न ही विदेशी कम्पनियों को इसका उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है भारत तो अपने एक ही वर्ष के खाद आयात से नया कारखाना लगवा सकता है.

Uex Kuall के अनुसार

> "इन्डोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा तथा भारत में यू० एस० ए० द्वारा उत्पादित खाद के मूल्य से 2 गुना व 3 गुना मूल्य देशी खाद का होता है और ये खाद का उत्पादन न बढ़ाते हैं और न विदेशी कम्पनियों को कारखाने लगाने देते हैं."[1]

H R. Von Uex Kuall : Obstacles to using Fertilizer for Rice in S. E. Asia, World Crops, March 1964.

See also Free Press Journal, London News letter, May 10, 1969.

1. "It becomes extremely difficult to generate a yield take off,

बीज :

भारत तथा अन्य कम-विकसित देशो में कुछ किस्म के उन्नत बीजो के प्रयोग से उत्पादन कई गुना बढ जाता है. इन बीजो के बहुगुणन तथा वितरण की आवश्यकता भी सर्वोपरि हैं.

पौध संरक्षण व जानवरो से बचाव :

कुछ अनुमानो के अनुसार कम-विकसित देशो में लगभग 1/4 फसल टिड्डियो, चूहो, पक्षियो, कीडो व जानवरो द्वारा खा ली जाती है इनसे सुरक्षा किए बगैर सारी Capital inputs (पूँजीगत लागतें) बेकार चली जाएँगी इनको नाश करना मानव जाति के लिए स्वय जीवन मरण का प्रश्न है

यन्त्रीकरण

कालान्तर में कृषि का यन्त्रीकरण आवश्यक होगा परन्तु जब तक कि देश में छद्म-वेशी बेरोजगारी बनी है तब तक ऐसा करना उपयुक्त नही होगा मनुष्य के सहायता के लिए मशीन ठीक है. अभी उसको हटाने के लिए मशीन नही लगाना है.

यातायात :

यातायात के सुगम व सस्ते साधन भी कृषि की उन्नति के लिए अत्यन्त आवश्यक है.

IV-V. Market orientation and Commercialization : कृषि का व्यापारीकरण करना तथा बाजार व्यवस्था उन्नत करना

कम-विकसित देशों में जो कृषि उपज होती है उसके विपणन को उचित व आधुनिक पद्धति से करना चाहिए और दूसरे इन देशो में विपणन योग्य आधिक्य की मात्रा में वृद्धि होना चाहिए. कम-विकसित देशो मे कृषि उपज का केवल 1/4 से 1/2 भाग विपणन को आता है. जब तक कि विपणन योग्य भाग मे वृद्धि नही होती तब तक बचत और पूजी निर्माण कम रहेगा. पूँजी निर्माण से ही उपज

---

without an adequate development of non-agricultural supporting cast, modern agriculture cannot develop in a vacuum Increased application of fertilizers and optimum utilization of water are the two most important requisite for accelerating farm productivity in developing economics "

Dr. D. L. Narayana : op. cit P. A. 49.

बढाने वाली Capital inputs बढाई जा सकती है जिससे उत्पादकता तथा विपणन योग्य आधिक्य बढता है

कम-विकसित देशो मे सर्वप्रथम नियन्त्रित मडियो की स्थापना होना चाहिए जहाँ नियमपूर्वक विपणन हो, जहाँ तौल, भावो व चुकाने की पद्धतियो मे एकरूपता हो, जहाँ कृषक अपनी उपज को स्वतन्त्र रूप मे बेच सके तथा जहाँ बीच के बिचौलिए शोषण न कर सकें. इन मडियो मे उचित श्रेणी विभाजन व प्रमाणीकरण पद्धतियाँ होना चाहिए इस सुविधा से न केवल आन्तरिक व्यापार में वृद्धि होती है वरन् निर्माता भी प्रोत्साहित होते हैं.

देश में गोदामो की सुविधाएँ भी विकसित करना चाहिए इससे उपज नष्ट होने से बचती है तथा कृषि मूल्यो मे गिरावट बच जाती है कृषि के विपणन सुधारने में विपणन अनुसंधान एव सर्वेक्षण, कर्मचारियो का प्रशिक्षण, यातायात सुविधाओ का सुधार, तथा मूल्य आदि की तत्काल जानकारी आवश्यक होगी.

इस संबध मे कम-विकसित देशो में सहकारी विपणन की सम्भावनाओ को जाँचना चाहिए. सहकारी कृषि, सहकारी वित्त-व्यवस्था तथा सहकारी विपणन साथ हो तो और सफलता होगी, अन्यथा सहकारी विपणन सस्था को छोटे-छोटे क्षेत्रो से या छोटे-छोटे कृपको से विपणन योग्य वस्तु खरीदने मे अधिक समय व व्यय लगेगा. Monoculture Countries (मुख्य रूप से एक ही फसल उत्पन्न करने वाले देश) इस प्रकार की विपणन पद्धति से मूल्यो के उच्चावचन से भी सुरक्षा कर सकते हैं बिचौलियो के हटने से अधिक मूल्य मिल जाते हैं तथा प्रतिव्यक्ति व प्रति एकड उत्पादकता, जैसा कि योरोप के देशो में हुआ, बढ़ जाती है.

IV-VI. Agricultural research, sine qua non, for *agricultural development* : कृषि विकास व कृषि अनुसंधान :

कृषि की उन्नति के लिए अनुसंधान का महत्व कम नही है कई कम-विकसित देश विकसित देश की तकनीक को आँख मीच कर नकल नही कर सकता. Herdt तथा Mellor ने यह सिद्ध किया है कि जहाँ U S A. मे प्रति एकड 120 पौंड नाइट्रोजन खाद दी जा सकती है वहाँ भारत मे 50 पौंड से ऊपर हानि होने लगती है इसलिये परिस्थितियो के अनुसार कार्य होना चाहिए. [1]

1. R. W. Herdt and J. W. Mellor "Contrasting Response of Rice to Nitrogen, India and U. S., p. 155. From "Agricultural Take off in Under-developed Countries" Dr. D. L. Narayana, Commerce Annual Nov. 1965.

अनुसधान तो कृषि विकास की कुजी है. Dr. Mc. Meekan के अनुसार.[1] कम-विकसित देशो मे कृषि अनुसधान के पूर्ण सफल होने में दो मुख्य बाधाएँ है :

(i) प्रथम तो इन देशो में सैद्धान्तिक समस्याओ पर अधिक कार्य होता है और स्थानीय महत्व के व्यावहारिक पहलुओ पर विशेष ध्यान नही दिया जाता.

(ii) दूसरे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ स्थानीय समस्याओ को नही समझते तथा इन देशो के विशेषज्ञ विदेशो की बातें वगैर उन्हे देश की परिस्थितियो को ध्यान मे रखे लागू करना चाहते है. इनका कथन है कि अनुसधानो के कार्यो को लाभदायक होना चाहिए इनकी सफलता में राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रशासको का सहयोग होना चाहिए

Johnston and Mellor[2] का विचार है कि यह समस्त अनुसधान का कार्य राज्य या अन्य किसी बडी सस्था को हाथो में लेना होगा "भारत के 6,00,000 गाँव वगैर राज्य के पथ प्रदर्शन के स्वय सगठित होकर उन्नति नही कर सकते." उनका कथन है कि नई उत्पादन पद्धतियाँ, नये बीज व उचित खाद व्यवस्था, नई विपणन, साख व सगठन प्रणालियो के लिए अनुसधान बाहर से करना होगा.

IV-VII. High level of literacy : शिक्षा का विकास व कृषि :

शिक्षा के वगैर कृषि अनुसधान की जानकारी को कृषको मे नही फैलाया जा सकता. अनुसधानशालाओ के सफल प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही तो फैलाए जा सकते है, अभी तक का अनुभव यह साबित कर देता है कि जब तक अशिक्षा बनी रहेगी तब तक उत्पादकता मे वृद्धि नही हो सकती. अशिक्षा ही अज्ञान है. सामाजिक पिछडेपन से नव प्रवर्तन नही होते, निराशा का वातावरण फैलता है और नई मान्यताओ में विश्वास पैदा नही होता.[3]

1. Mc. Meekan : Finance and Development—The Fund and Bank Review vol II No 2, June 1965 p. 78 Washington D. C
2. Johnston &Mellor op cit.
3. उत्तर प्रदेश के माताटीला बाँध का पानी जब सिंचाई के लिये नहरो में छोडा गया था तो नहरी क्षेत्र के अशिक्षित कृषको ने उसे प्रयोग नही किया क्योकि उन्हें यह विश्वास था कि उस पानी से बिजली निकाल लेने पर उसमें सिंचाई के तत्व नही रहे.

श्री लेस्टर आर-ब्राउन (Lester R. Brown)[1] के अनुसार शिक्षा व उत्पादकता म गहरा सम्बन्ध है, उन्होंने मुख्य चावल, गेहूँ व मक्का उगाने वाले देशा का अध्ययन किया. 1935-1962 के बीच इनमे से 24 देशों में साक्षरता का प्रतिशत 50 से कम था, तो इनम उत्पादकता वृद्धि दर 0 17 थी, परन्तु जिन 13 देशो में साक्षरता प्रतिशत 50-80 के बीच थी वहाँ उत्पादकता वृद्धि 1 02 प्रतिशत रही अन्य 23 देशो म जहाँ साक्षरता का अनुपात 80 प्रतिशत से ऊपर था वहाँ उत्पादकता वृद्धि 1 43 प्रतिशत थी.

कम-विकसित देशो में तो दुर्भाग्यवश यह साक्षरता अनुपात 25 से भी कम है.

शिक्षा का विस्तार अवश्य एक आवश्यक शर्त है परन्तु इसके प्रसार मात्र से ही कृषि आत्मस्फूर्ति अवस्था मे नही पहुँच जाती शिक्षा के विस्तार से विकास की राह के अवरोध दूर करने में मदद मिलती है

IV-VIII Price-Support and Price Incentives कृषि विकास तथा मूल्य नीति

कृषि विकास के लिए राज्य को मूल्य सम्बन्धी प्रेरणा या सहायता देना चाहिए अथवा नही इस सम्बन्ध मे अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद है. अधिकाश अर्थशास्त्री यह चाहते है कि राज्य कृषको को मूल्य सम्बन्धी सहायता दे. वैसे यह माना जाता है कि कृषक अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन के अनुसार उपज की मात्रा व किस्म मे परिवर्तन नही करते. बहुत से कृषक मूल्य गिरने पर भी कृषि करते रहते है और बहुधा बढने पर भी शीघ्र उपज नही बढाते फिर भी यह आवश्यक है कि कृषको को मूल्य सम्बन्धी प्रेरणा दी जाए कि वे आधुनिक ढग से कृषि करें और उत्पादकता बढाएँ इसलिए साख उपलब्ध कराने के साथ-साथ कृषक को उचित मूल्य प्राप्त होना चाहिए अर्थात् ऐसे मूल्य हों जिनसे उसे प्रेरणा मिले कि वह अपनी कृषि को उद्योग की भाँति सचालित करें, अगर उन्हे उन्नत तकनीक सीखने या अपनाने मे खर्च होता है तो राज्य को उन्हें अनुदान आदि देना चाहिए अन्यथा वह नव-प्रवर्तनो को कृषि मे नही अपनाएगा.

कृषि मे बहुधा मूल्य गिरने की प्रवृत्ति सामने आ सकती है कृषि पदार्थों का उत्पादन अगर अधिक हो जाता है तो मूल्य गिर जाने है मदी के दिनों में भी कृषि उपज कम नही की जाती जब कि औद्योगिक उत्पादन कम कर दिया जाता

---

1. World Population and Food supplies 1980, A S A Special Publication, No. 6 PP 12-13.

है कृषि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है जब कि औद्योगिक वस्तुओं का बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार होता है. इसलिए कृषि वस्तुओं की "व्यापार की शर्तें" गिर जाती है (अर्थात् औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों से कृषि वस्तुओं के मूल्य अधिक गिर जाते है) जहाँ औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक बेरोजगारी से पीडित रहते है कृषि क्षेत्र के व्यक्ति कम आय से पीडित हो जाते है, इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री कृषकों को Price support देने की सिफारिश करते है

K E Boulding तथा A. G. Hart इस नीति के विरुद्ध है इनका कथन है कि कृषकों के हित को ध्यान मे रखने के लिए जो बाजार मूल्यों से अधिक मूल्य रखे जाते है उनसे लाभ के स्थान पर हानि ही सुनिश्चित है : (This method is wasteful and self-defeating) बोल्डिंग का कथन है कि इस नीति से बडे किसानो को ही लाभ होगा क्योंकि छोटे कृषको के पास विपणन योग्य आधिक्य बहुत कम होता है. उनके शब्दो मे .

> "In case of a completely self-subsistent homestead which sells nothing off the farm the level of income is completely unaffected by prices, for nothing multiplied by anything is still nothing
>
> So a policy of raising farm prices through some artificial means helps the rich farmers who constitute the backbone of agriculture organisation and pressure groups much more that it helps the poor farmers".

A.G. Hart इस नीति को "Charity racket" कहते है अर्थात् "दान का राज्य" यह अनुदान व सहायता दो रूप से दे सकता है प्रथम जैसे वह मूल्य 1 रु० किलो रखना चाहता और बाजार मे वह 0 75 रु० में बिकती है तो राज्य उसे स्वय 1 रु० मे ले या फिर कृषक को 0 25 रु० सहायता रूप मे दे दे

विकसित देश तो इस नीति को और भी नही अपना सकते. उनके सामने जब अधिक उत्पादन के कारण मूल्य गिरने की समस्या आती है तो उनके सामने चार विकल्प हो सकते है

K. E. Boulding : op. cit. 315-322

(i) वे कुछ फसल को नष्ट कर दें, जैसे यू एस ए करता था या ब्राजील काफी को नष्ट कर देता था आज के इस वातावरण म जबकि कम-विकसित देशो मे इतनी भूख है यह निन्दनीय कार्य होगा (Patently wicked)

(ii) वे कम-विकसित को सहायता या कम मूल्य पर दे सकते है.

(iii) या वे उत्पादन गिरा सकते है

उचित यह होगा कि वे सस्ते दर पर गरीबो को दें दे कृषको को मूल्य सहायता अनुचित होगा.

सतुलित मत यह है कि आवश्यकता पडने पर कृषको को Price Support देना अनुचित नही होगा [1]

IV-IX Provision of Agricultural Service and Agricultural Leadership कृषि विकास के लिए यह उचित नेतृत्व व सेवाओ का प्रावधान

कम-विकसित देशो मे कृषक कृषि को बडे उदासीन रूप में करता है (The subsistence farmer is a routine cultivator) इन देशो मे ऐसे व्यक्तियो, सस्थाओ व राज्य प्रशासन की आवश्यकता है जो इन अशिक्षित, भाग्यवादी, निरुत्साही, पुराने विचारो वाले किसानो को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जाये कि वे उत्साह के साथ कृषि को आधुनिक ढग से करें. इन देशो में National Extension Service को शुरू करना चाहिए जिससे उन्हे उन्नत खेती के तरीको को सिखाया जाए Demonstration farms की स्थापना से ही कृषक अच्छी खेती के तरीके सीखेंगे व अपनाएँगे कृषको को सिचाई करने भूक्षरण रोकने, खाद देने, बीज चुनने आदि के सबध म विशेषज्ञो की सलाह मिलना चाहिए Mobile vans (चलती फिरती गाडियो) मे यह सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है. कृषि विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि स्थानीय, राज्य स्तर तथा केन्द्रीय स्तर के कार्य-क्रमो मे समन्वय हो.

●

1. देखिए मूल्य नीति का अध्याय

अध्याय : 3

आर्थिक विकास तथा श्रम को योगदान व मज़दूरी नीति और विकास

Role of Labour Force and Wage Policy for Economic Development

I. Role of Labour force in Growth.
   - A "Work force" या श्रम शक्ति का अर्थ,
   - B. श्रम-शक्ति व विकास.
   - C. श्रम-शक्ति को उन्नत करने के लिए आवश्यक कदम.
   - D. श्रम संघों का विकास में योगदान.

II. Wage policy for economic development.
   1. न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित व कार्यान्वित करना चाहिए.
   2. मजदूरी का प्रमाणीकरण चाहिए.
   3. वास्तविक मजदूरी को गिराकर पूँजी निर्माण सर्वथा अनुचित होगा.
   4. मजदूरी को मुद्रा स्फीति का 'एंजिन' नहीं बनने देना चाहिए.
   5. मजदूरी को उत्पादकता वृद्धि का जरिया होना चाहिए. प्रेरणादायक मजदूरी देना आवश्यक.
   6. देश में सामूहिक सौदागिरी प्रथा (collective bargaining) को कार्यशील होने देना चाहिए. विकेन्द्रित मजदूरी नीति की आवश्यकता.
   7. सामाजिक सुरक्षा का धीरे-धीरे विकास.
   8. मजदूरी नीति को रोजगार व उत्पादकता वृद्धि योजनाओं से समन्वित

यह अध्याय लेखक की पुस्तक ' Economics of Wages, Productivity and Employment" के अध्याय 11 व 12 पर आधारित है.

See also :

(i) charles D. Stewart : Role of labour force in Growth ch. IV of williamson & Buthick's op. cit.

(ii) Tokyo conference on Economic Growth, papers of Dobb & Ashok Mehta.

(iii) Meier & Baldwin : op. cit.

(iv) B. Higgins : op. cit.

अध्याय : 3

आर्थिक विकास तथा श्रम को योगदान व मज़दूरी नीति और विकास

Role of Labour Force and Wage Policy for Economic Development

I Role of Labour force in Growth.

A. "work force" का अर्थ व्यापक रूप से लिया जा सकता है. इसके अन्तर्गत साहसी, मैनेजर, तकनीकी विशेषज्ञ व वैज्ञानिक भी आ जाते हैं. परन्तु हम "work force" का अर्थ सकुचित रूप में लेते हैं और हमारा आशय यहाँ श्रमिक से है. वैसे तो कम-विकसित देशों में विकास के प्रमुख घटकों के रूप में पूँजी व साहसियों को ही माना जाता है, फिर भी श्रम शक्ति ही विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले "हाथ" हैं व साहसी मस्तिष्क हैं. Lewis तथा Nurkse तो केवल श्रम-शक्ति के प्रमुख घटक के आधार पर ही विकास करने की सम्भावनाएँ देखते हैं.

B. श्री चार्ल्स डी० स्टेवर्ट के शब्दों में :

> "Economic development is conditioned by the character of the work force and by the response of workers to innovations, large and small, which lead to more efficient production and increase real income."

जहाँ तक श्रम-शक्ति व विकास का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध मे मुख्य कार्य श्रम-शक्ति को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र मे लाना तथा उसे प्रशिक्षित करना है. उनकी मनोवृत्ति तथा आचरण में उचित परिवर्तन लाना है उनमें नई तकनीक अपनाने की इच्छा व क्षमता का विकास करना होगा.

जैसा कि हम "कम-विकसित देशों की विशेषताओं" के अध्याय मे पढ़ चुके हैं, इन देशों मे जन-शक्ति गरीब, अशिक्षित, या कमशिक्षित, कमजोर, अप्रशिक्षित,

---

इस सम्बन्ध में हम Lewis तथा Nurkse मॉडल अध्ययन कर चुके है.

कम उत्पादक, रूढ़िवादी, परम्परागत मान्यता वाली है. इससे विकास में बाधा पड़ती है, उनकी यह स्थिति स्वय विकास की कमी से है

Stewart के शब्दो मे

> "The work force is not something, independent or separate from the society of which it is a part Deficiency in the work force-illiteracy, lack of training and skill, infavourable attitudes towards the work of suspicion of change-limit the rate of industrial progress, they are at the same time consequences of the entire social milieu associated with the existing stage of economic development."

कम विकसित देशो में श्रम राज्य की अवज्ञा का शिकार रहा है समाज ने उसे उचित दर्जा नही दिया. उसे उसकी मेहनत का उचित पुरस्कार नही मिला. पूजीपतियो ने उसका शोषण किया ह सदियो से श्रम गुलाम रहा है. परन्तु सोवियत क्रान्ति ने श्रम को उसका महत्व सामने ला दिया है जबकि साम्राज्यवादी देशो में उन देशो के श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक कल्याण को सुविधाएँ प्रदान की जाने लगी थी. कम-विकसित देशो मे इन्ही देशो ने छोटी से छोटी सुविधा देने से वचित रखा [1]

C. कम-विकसित देशो में श्रम शक्ति का विकास में भरपूर योगदान सभव हो इसके लिए निम्नलिखित कदम अत्यन्त आवश्यक होगे

(i) श्रमिको को शिक्षित व प्रशिक्षित करना होगा. इसका व्यय मुख्यत. राज्य को उठाना होगा. किसी देश का सबसे अधिक बहुमूल्य साधन सोना चाँदी नही वरन् वहाँ की जनशक्ति होती है

(ii) कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी दूर कर वहाँ की अतिरेक जनसख्या के लिये शहरो में रोजगार व्यवस्था करना चाहिए.

(iii) श्रमिको की मनोवृति इस प्रकार करनी होगी कि वे तकनीकी परिवर्तनो के खिलाफ न हो अगर उनके रोजगार के हित सुरक्षित रखे तो इसमें कठिनाई नही होगी.

---

1. See : Peter C. Speers : "Colonial policy of the British Labour Party" Social Research, Sept. 49, p. 307-8 G.F. Ibid.

(iv) उनको उचित मजदूरी तथा अतिरिक्त आय मिलना चाहिए अर्थात् उन्हें उत्पादकता वृद्धि से पर्याप्त हिस्सा मिलना चाहिए
(इस पर इसी अध्याय व अगले अध्याय मे विस्तार से लिखा है)

Stewart के शब्दो मे

> "Broader distribution of the fruits of economic progress appears to be a necessary condition for maximum growth of per-capita income in industrialized society, in terms both creating an expanding domestic market and providing incentives to workers to respond favourably to changes in traditional patterns of work. High productivity and low wages favour luxury expenditure on personal servants and foreign imports at the expense of possible growth of domestic "Industries based on mass consumption"

(v) देश मे श्रम सघो का पर्याप्त विकास हो तथा देश में सामूहिक सौदागिरी प्रणाली हो श्रम सघ देश मे श्रमिकों को उचित वेतन व लाभ का उचित भाग दिलाते है वे श्रम की उत्पादकता वृद्धि मे सहायक हो सकते है वे उत्पादनकर्त्ताओ को उत्पादन पद्धति के सुधार में सहायता दे सकते है जहाँ आवश्यक हो उनके सहयोग से Wage Restraint तथा Rationalization की नीतियों को कार्यान्वित करा सकते है

श्रमिक जब गाँवो से शहरों में आते है तो बहुत सी आर्थिक सामाजिक समस्यायें सामने आती है इनके समाधान के बगैर श्रम शक्ति का विकास में अपेक्षित योगदान नही हो सकेगा. ये समस्यायें है, गन्दी बस्तियाँ, पारिवारिक विघटन, वेश्यावृत्ति, बाल-अपराध, जुआखोरी, शराबबाजी आदि. श्रमसघ इन समस्याओ के निराकरण में सहायता दे सकते है.

श्रम सघ श्रमिकों के हित के लिए आवश्यक नियम बनवा सकते है जो श्रमिको के कार्य, रहने व वेतन सबधी सुविधाओ को बढाएँ. श्रम सघों को कुछ राजनैतिक कर्तव्य अवश्य निभाने पडते है परन्तु सरकार बनाना, सरकार का विरोध

करना या राजनैतिक समस्याओं पर प्रचार या आन्दोलन करने से उन्हें अवश्य नहीं रखना चाहिए

D कम-विकसित देशों में श्रमसंघों का संगठन कार्य-प्रणाली अभी ऐसी नहीं है कि वे विकास में सहायक हो. बहुधा वे विकास में बाधा ही उत्पन्न कर देते हैं. इन देशों में श्रम संघों की वित्तीय व्यवस्था शोचनीय होती है. सदस्यों की संख्या कम तथा अस्थिर रहती है, उनके वित्तीय प्रबन्ध असंतोषजनक होता है, उनके नेताओं में अनुभव, लगन व परिपक्वता की कमी होती है उनके नेता श्रमसंघों के माध्यम से अपने राजनैतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं. ये नेता बाहर के आन्दोलन से प्रभावित रहते हैं. इन देशों में श्रम संघों व नेताओं की आवश्यकता से अधिक संख्या होती है ये सब श्रम-कल्याण के कार्यों में उतनी रुचि नहीं लेते हैं

इन देशों में इन सब बुराइयों की जड श्रमिकों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता तथा जनसंख्या की वृद्धि हैं दुर्भाग्य से इन देशों में राज्य का आचरण व व्यवहार भी निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ताओं से अच्छा नहीं होता राज्य के उद्योगों में भी श्रमिकों का असंतोष बना रहता है इन उद्योगों के प्रशासक तो श्रम संबंधों में लचीलापन और समाप्त कर देते हैं.

Webb का मत है कि श्रम-संघ तीन मान्यताओं से प्रभावित होते हैं

(i) The doctrine of vested interest (अपने स्वार्थ की भावना) इसके अन्तर्गत वे राज्य का संरक्षण माँगते हैं, नई तकनीक अपनाने में बाधा डालते हैं, भिन्न-भिन्न श्रम-संघों में अन्तर बनाए रखते हैं आदि.

(ii) The doctrine of supply and demand (माँग व पूर्ति का नियम) इसके अन्तर्गत वे सामूहिक सौदागिरी, मजदूरी संरचना, हड़ताल, तालाबन्दी उत्पादन को जानबूझ कर कम रखना या फिर उत्पादन बढ़ाने में सहायक होना आदि की ओर अधिक ध्यान देते हैं

(iii) The doctrine of improvement. (सुधार के नियम) इसके अन्तर्गत श्रम संघ श्रमिकों की कार्य करने, रहने की अवस्थाओं में सुधार के लिये प्रयत्न करते हैं. मजदूरी को बढ़वाते हैं तथा श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि कराने की ओर ध्यान देते हैं.

See also : ch 6 C P. Kindleberger : op. cit. on labour Bayer & Yamey · op cit : chs. V, VI & VII.

Webb का कथन है कि श्रम सघो को प्रथम नीति छोड़ देना चाहिए, द्वितीय को सशोधित रूप में अपनाये तथा तृतीय कार्यों को बढावा दे.

श्री वी० के० आर० वी० राव के शब्दो में हमको एक बात ध्यान में रखना चाहिए. "श्रम उत्पादन का साधन ही नही है वरन् साध्य भी है आर्थिक विकाससवर्धन के चाव व उतावलेपन मे हम श्रम को साधन के रूप मे ही देखने है " मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नही रहता हमको मनुष्य को मशीन *नही बनाना है वरन् विकास का लक्ष्य श्रम का जीवन स्तर ऊँचा करना है .*

> 'We cannot let our desire for economic growth make a machine of a man, even though we should within the limits set by human and spiritual values, strive to adopt and use the human factor for getting out of the rut of economic stagnation on to the road of economic growth."

II. मजदूरी नीति व विकास

1. न्यूनतम मजदूरी को निर्धारण व कार्यान्वित करना चाहिए

अर्थ : कम-विकसित देशो में उचित मजदूरी नीति के बगैर विकास की कोई सम्भावना नही है. इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम इन देशो मे 'न्यूनतम' मजदूरी की स्थापना होना चाहिए.

"न्यूनतम" मजदूरी से हमारा आशय मजदूरी की उस कानूनी न्यूनतम सीमा से जिससे कम कोई उत्पादन कर्त्ता नही दे सकता. हर क्षेत्र के लिए तथा हर उद्योग के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग होती है.

निर्धारित करने वाले तत्व : कम-विकसित देशो मे 'न्यूनतम' मजदूरी को निर्धारित करते समय बहुत सी बातों को ध्यान मे रखना चाहिये सर्वप्रथम उद्योग की मजदूरी देने की क्षमता ध्यान में रखना चाहिए बहुत ऊँची मजदूरी निर्धारित करने से कम कुशल उत्पादनकर्ता व्यापार मे नही रह सकेंगे और बहुत नीचे न्यून-

---

See also : (1) Ishrat Hussain : op. cit. ch. VI on The Labour Force & Population.
(2) V. K R V. Rao : op. cit. ch. 7. The Human Factor in Economic Growth.

तम मजदूरी से श्रम का कोई लाभ नही होगा. किसी "प्रतिनिधि फर्म" की मजदूरी देने की क्षमता को ध्यान मे रख कर यह मजदूरी निर्धारित की जा सकती हैं. दूसरे, 'न्यूनतम' मजदूरी निर्धारित करते समय अन्य उद्योगो की न्यूनतम का भी निर्धारण करना चाहिए.

तीसरे, 'न्यूनतम' मजदूरी को living wage या अच्छे जीवनयापन के लिए पर्याप्त मजदूरी के बराबर होना चाहिए. यह जीवन स्तर इतना होना चाहिए कि मजदूर इज्जत से जीवन यापन कर सके. यह इतनी मजदूरी हैं जो श्रमिक को अच्छा खाना, रहने, पहनने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ट्रेनिंग की सामान्य सुविधाएँ प्राप्त करा सके इसका अर्थ बहुत उच्च स्तर से नही है.

न्यूनतम मजदूरी व उत्पादकता, रोजगार, मूल्य लाभ व विकास पर प्रभाव : कुछ अर्थशास्त्रियो का विचार हैं कि कम विकसित देशो मे न्यूनतम मजदूरी सबधी नियमो को कार्यान्वित करने से उत्पादन-कर्ताओ के लाभ कम होगे और इससे उत्पादन व रोजगार कम होगा. इसलिए विकास के लिए मजदूरी दरो में किसी प्रकार की वृद्धि नही करना चाहिए

यह विचारधारा सर्वथा भ्रमात्मक हैं न्यूनतम मजदूरी नियमो के अनुसार मजदूरी देने से श्रमिको की कार्य करने की शक्ति व इच्छा बढती है, उत्पादनकर्ता भी मेहनत से काम कर सकते हैं अगर न्यूनतम मजदूरी के देने से श्रमिको की कार्यक्षमता बढती है तो मूल्यो का बढना भी आवश्यक नही है. न्यूनतम मजदूरी देने से देश में माँग की वृद्धि होती हैं और इससे उत्पादनकर्ताओ को और अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है.

न्यूनतम मजदूरी देने मे अगर उत्पादकता मे वृद्धि नही होती तो उत्पादनकर्ताओ के लाभ घट जाएँगे और अगर उत्पादकता मे वृद्धि होती हैं तो लाभ पूर्ववत रह सकते हैं और लाभ बढ भी सकते है. अगर कुछ उत्पादनकर्ताओ को हानि भी होती है तो उनके हटने से कोई बुराई न होगी उनका उत्पादन दूसरे उत्पादनकर्ता अपने हाथ मे ले सकते है.

वस्तुस्थिति : आज कम विकसित देशो में वस्तुस्थिति यह है कि न्यूनतम मज-दूरी नियम तो लगभग सब देशो में बना दिए गए है परन्तु उनका पालन बहुत कम होता है. भारत में ही 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का लक्ष्य 1950 तक समस्त उद्योगो के लिए नियम बनाने का था, परन्तु 1961 तक यह कार्य पूरा न हो सका और अन्त में समय सीमा ही हटा दी गई. कम-विक-सित देशो में मजदूरो की अशिक्षा व अज्ञानता के कारण मजदूर अपनी बेरोजगारी

की मजदूरी के कारण कम ले लेते हैं. निरीक्षकों का कार्य अत्यन्त असंतोषजनक रहता है.

देश में मजदूर को विकास मे योगदान योग्य बनाने के लिए सर्वप्रथम देश मे न्यूनतम मजदूरी को स्थापित करना होगा

2. मज़दूरी स्तर का Standardization या स्तरोन्नयन या प्रमाणीकरण होना चाहिए.

मजदूरी की एक दर नही होती वरन् दरें होती हैं उचित मजदूरी प्रणाली का प्रमुख गुण यह होना चाहिए कि मजदूरी की भिन्न-भिन्न दरो में जो अन्तर वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से न्यायोचित हो. कम विकसित देशो मे यह अंतर बहुत अधिक है एक ही शहर एक ही उद्योग की इकाइयो मे मजदूरी कम व अधिक हो सकती है

इसलिए आवश्यक यह है कि इन दरो को न्यायोचित किया जाए. सारे कार्यो व सारे उद्योगो या उनकी इकाइयो के विभिन्न विभागो की मजदूरी की दरे कम व अधिक अवश्य रहेंगी अन्यथा कुशल व अकुशल में अन्तर नही रहेगा. परतु बहुधा यह अन्तर कुशलता व योग्यता पर आधारित होने के स्थान पर किसी अन्य कारण (जैसे श्रमसघो के कार्य) से स्थापित हो सकती हैं. इनको घटा देना चाहिए. समान योग्यता के व्यक्तियो को समान आय व असमान योग्यता के व्यक्ति को असमान आय मिलना चाहिए. पूर्ण समानता सम्भव नही होती. रूस में भी पूर्ण समानता नही है. मजदूरी मे समानता ही देश में विकास का लक्ष्य नही होना चाहिए. उससे अधिक तो महत्वपूर्ण रोजगार मे वृद्धि व उनकी कुशलता में वृद्धि करना अधिक महत्वपूर्ण होगा आज के युग में centripetal (समानता की

References on Minimum wages :

(i) I. L. O. "Problems of Wage Policy in Asian Countries" p 92-7.
(ii) Dr. R. Singh : Movement of Industrial Wages In India, ch. II, III
(iii) Indian Journal of labour Economics Jan. 1959.
(iv) G. Anderson, Fixation of Wages p. 187.
(v) R A. Lester . Economics of Labour & Industrial and Labour relations.

माँग) तथा centrifugal (असमानता की माँग) दोनो प्रवृत्तियाँ साथ चलती हैं. कही पर श्रमिक समानता चाहते है कही असमानताएँ बढवाना चाहते हैं.

मजदूरी के स्तरोन्ययन के लिए कार्य करने से कम-विकसित देशो में प्रयत्न आवश्यक हैं इसका अर्थ यह नही है कि हर मजदूर एक Standard wage ही कमायेगा. केवल standard rate ही निर्धारित किया जाता है. इस कार्य से कार्य क्षमता बढती है, मजदूरी स्तर में न्याय का समावेश होता है, औद्योगिक शान्ति की स्थापना होती है, उन्नत तकनीक अपनाई जासकती है पहले क्षेत्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण होना चाहिए बाद मे देश मे इसे करना चाहिए.

3 विकास के नाम पर वास्तविक मजदूरो नहीं गिराना चाहिए : ★

बहुधा यह सलाह दी जाती है कि विकास के लिए मूल्यो को बढने देना चाहिए और मजदूरी स्तर को वही रहना चाहिए इससे उत्पादनकर्ता लाभ कमाएँगे और, और अधिक पूंजी निर्माण करेंगे.

परन्तु पूँजीनिर्माण के नाम पर तथा मुद्रा स्फीति को नियन्त्रण में रखने के लिए हमको मजदूरी को भुखमरी के स्तर पर नही बांध देना चाहिए. अन्यथा यह गरीब लोग अपने खाने पीने की आवश्यकताओ को भी पूरा नही कर पाएँगे

References :

1. J T. Dunlop "The Test of contemporary Wage Theory" in the Theory of Wage Determination Ed by the same author.
2. A. M. Ross "External Wage structure" in New concepts of Wage determination.
3. F. R Fairchild, Furniss, Buck, Economics p. 407–8.
4. Dr. R. Singh · op. cit. p. 63.
5. J. R Hicks, Economic Foundations of Wage Policy, Economic Journal, Sept 1955.
6. A. D. Gupta, "Skill differentials and Wage Policy." Indian Journal of Labour Economics,
7. E. R. Livernash. "Internal Wage Structure" in New concept of wage Determination.
8. I. L. O. wages General Report v.
9. Dobb. Wages.
10. Rothschild : Theory of Wages.

★ इस सम्बन्ध में पूँजी निर्माण का अध्याय देखिए तत्सम्बन्धित सकेत (references) भी वहाँ देखिए

भारत में 1964 तक मज़दूरों की वास्तविक मजदूरी 1939 के स्तर पर ही रही कम विकसित देशों में विकास का मूल्य गरीबों को ही क्यों चुकाने को कहा जाए ? आज के युग में सामाजिक व राजनैतिक जागरूकता इतनी अधिक है कि समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा रूस में ऐसा किया जा सका था परन्तु वहाँ तो राज्य का अंकुश था आज के युग मे ब्याज व लाभ कमाने वालो की आय वैसे ही अधिक है और फिर मज़दूरी और कम कर दें तो अन्याय के सिवाय और क्या होगा ? अगर इन गैर-मज़दूरी आय को कम न किया जाएगा तो मज-दूरी को कम करना बहुत गलत होगा

कम-विकसित देशों में अधिक मजदूरी से ही मुद्रा स्फीति नहीं फैलती मुद्रा स्फीति के बहुत से कारण है जैसे फिज़ूल खर्ची राजकोषीय नीति, कर लगाने की शर्मीली नीति, कर लगाने व इकट्ठा करने वाला भ्रष्ट प्रशासन, एकाधिकारी उत्पादनकर्ता मूल्य बढ़ा देते है. देश म मूल्य वृद्धि के अन्य कारण है : अधिक लाभ लेना, साख प्रसार, सट्टो में वृद्धि, काला बाजारी, जमाखोरी, अकुशल उत्पादनकर्ता, प्राकृतिक कारणो से कच्चे माल की कमी मूल्यो में वृद्धि कर देते है

इस प्रकार से मजदूरी का मुद्रा स्फीति में योगदान इतना नहीं होता भारत में ही औद्योगिक श्रम राष्ट्रीय श्रम का केवल 2% ही होता है, फैक्ट्री मज़दूरी राष्ट्रीय आय का 2 से 3% भाग ही होती है तथा मजदूरी कुल लागत का 3% से 20% तक ही भाग होती है

दीर्घकाल में मज़दूर संघ इस नीति को स्वीकार नहीं करेंगे. *कम-विकसित देशों मे* बहुत से क्षेत्रो मे उत्पादनकर्ता अत्यधिक लाभ कमाते रहते है अगर मजदूरी बढाने के लिए इन लाभो को कम कर दिया जाए तो रोजगार कम भी नहीं होगा. निम्न-लिखित परिस्थितियो मे मज़दूरी वृद्धि से रोजगार कम नहीं होगा

(i) अगर मजदूरी वृद्धि मूल्य वृद्धि के बाद हुई है तो इससे बेरोज़गारी नही बढेगी

(ii) अगर पूँजी को गतिशीलता नहीं है अर्थात् दूसरे स्थान को नहीं ले जाई जा सकती, तो मजदूरी बढ़ने से बेरोज़गारी नहीं बढेगी

(iii) अगर देश में माँग वृद्धि के कारण और उद्योगो का विकास हो रहा हो तो मज़दूरी वृद्धि से बेरोजगारी नहीं फैलेगी

(iv) मजदूरी वृद्धि से अगर मजदूरो की शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग मे सुधार होता है तो उनकी उत्पादकता वृद्धि से लागत कम होगी और बेरोज़गारी नही फैलेगी क्योकि कम मूल्य के कारण माँग मे वृद्धि होगी.

(v) अगर वस्तु की माँग बेलोचदार है तो मजदूरी बढ़ने से भी माँग में कमी नही आएगी और बेरोज़गारी नही फैलेगी.

(vi) जब मजदूरी कुल लागत का बहुत कम भाग होती है तो मजदूरी बढ़ने से लागत पर प्रभाव नगण्य होगा और बेरोजगारी नही फैलेगी.

(vii) अगर श्रम आन्दोलन देश व्यापी है तो उत्पादनकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने उत्पादनकार्य को नही ले जा सकते हैं और इसमे स्थानीय बेरोजगारी नही फैल सकती.

इन सब विश्लेषण का अर्थ यह नही है कि मजदूरी को उत्पादकता से अधिक बढ़ने दिया जाए. आवश्यकता इस बात की है कि मजदूरी तो बढ़े परन्तु श्रमिक उत्पादकता बढ़ाएँ.

4 मज़दूरी को मुद्रा स्फीति का एंजिन नहीं बनने देना चाहिए.

कम-विकसित देशो मे जहाँ मजदूरो को न्याय देना है तथा जहाँ उनका राष्ट्रीय आय मे हिस्सा वृद्धि करना है वहाँ यह भी आवश्यक है कि यह हिस्सा बढी हुई राष्ट्रीय आय मे से ही आना चाहिए. श्रम नेताओ को यह देखना चाहिए कि उनकी "सामूहिक सौदा" नीति Collective bargaining policy विवेकपूर्ण व जिम्मेदार नीति है आज के युग मे श्रम व उत्पादनकर्ताओ को एक दूसरे का दृष्टिकोण समझकर कार्य करना चाहिए सामूहिक सौदागिरी करने वालो को यह देखना है कि देश मे उत्पादन, उत्पादकता, मालिको के लाभ को बढ़ते रहना चाहिए. उनका हिस्सा भी इसी अधिक आय में से आएगा, अन्यथा ऐसी मुद्रा स्फीति फैल सकती है जो विकास की राह मे रोडा बनकर रह जाएगी. आज के युग में तालाबन्दी व हड़ताल विलासिता है और इस विलासिता को अपनाना विकास के लिए सबसे अधिक घातक होगा

इस सम्बन्ध मे मजदूरी नीति को Anti-inflationary policies मुद्रा-स्फीति विरोधी नीति का सहायक होना चाहिए, जैसा अगर मुद्रा स्फीति फैलने का डर हो तो मजदूरो को अपनी मजदूरी का कुछ भाग deferred payments या देर से भुगतान (जैसे प्रावीडेन्ट फड) के रूप मे ले लेना चाहिए.

5. प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली अपनाना चाहिए.

कम-विकसित देशो मे मजदूरी को प्रेरणादायक रूप मे देना चाहिए (Incentive wages should be established) कार्यानुसार मजदूरी पद्धति से श्रमिक की उत्पादकता भी बढती है और उसकी आय भी अधिक हो जाती है. इस प्रकार से देश की राष्ट्रीय आय मे वृद्धि होती है यह कार्यानुसार मजदूरी भी किसी प्रेरणा-

दायक योजना पर आधारित होना चाहिए, अर्थात् जैसे-जैसे श्रमिक का कार्य व उत्पादकता अधिक हो वैसे-वैसे उन्हें अधिक दर से मजदूरी दी जाए सोवियत यूनियन में Stakhanovist स्ताखनोविस्त आन्दोलन ने वहाँ उत्पादकता वृद्धि के नये से नये कीर्तिमान स्थापित किये है. भारत मे भी श्रमवीर की उपाधि उसीसे मिलती जुलती नीति है परन्तु उसकी व्यापकता कम है तथा अभी इस आन्दोलन को क्रान्तिकारी ढग से नही लिया जाता है

लाभ मे से श्रमिकों को हिस्सा देने से भी (Bonus or profit sharing) श्रमिको की उत्पादकता बढेगी श्रमिको को फिर नैतिक और कानूनी अधिकार भी है इन सब व्ययो को हमे लागत के रूप मे ही नही देखना है वरन् यह तो 'मानव-साधन' में विनियोजन है, क्योंकि अधिक उत्पादकता ही विकास की कुजी है.

6 देश में सामूहिक सौदेबाजी (Collective bargaining) प्रथा को बढ़ावा देना चाहिए और जहाँ तक हो सके विकेन्द्रित मजदूरी नीति होना चाहिए.

कम-विकसित देशों में सदियो से मजदूरी निर्धारण उत्पादनकर्ताओं के हाथ में रहा है कम-विकसित देशो मे इस प्रकार मजदूरी बहुत ही निम्न स्तर पर निर्धारित होती रही, मजदूर केवल दया की भीख माँगने के अलावा कुछ नही कर सकते थे. कालान्तर में राज्य ने हस्तक्षेप करना शुरू किया. उधर श्रम आन्दोलन के विकास के साथ-साथ सामूहिक सौदेबाजी भी विकसित होने लगी. कम-विकसित देशो मे अगर आर्थिक स्वतन्त्रता कायम रखना है तो सामूहिक सौदेबाजी को विकसित करना आवश्यक है. बहुधा सामूहिक सौदेबाजी असफल हो जाती है तो राज्य मजदूरी निर्धारण Tripartite Boards द्वारा निर्धारित कराता है. भारत के वर्तमान (लिखने का समय 17–5–1969) कार्य वाहक राष्ट्रपति श्री व्ही० व्ही० गिरी, जो स्वय प्रसिद्ध श्रमनेता रहे है, इस प्रकार की मूल्य निर्धारण पद्धति को उचित नही मानते. उनके शब्दों मे

> "मजदूरी बोर्ड सगठित उद्योगो में बेकार होते है और वे श्रम व मालिकों के अच्छे संबधों मे बाधा ही बनते हैं. इन बोर्डों के निर्णय को मानना कानूनी बाध्यता होती है और इसीलिए ये दोनो पार्टियो को पसन्द नही आते इन बोर्डों से श्रम एकता को धक्का लगता है, श्रम-सघो मे विश्वास घटता है क्योंकि उनके मामलों में तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप होता है"

इसलिए यह आवश्यक है कि कम-विकसित देशों मे सामूहिक सौदेबाजी को विकसित किया जाए. कम-विकसित देशो मे श्रम-संघो को "कम्युनिस्ट एजेन्ट" ही

नही मानना चाहिए. श्रम-संघों को राजनीति के बजाय श्रमिको के हित के मामलो मे ही ध्यान रखना चाहिए.

सामूहिक सौदेबाजी शक्ति सबद्ध होती है. एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करता है. दोनों पक्ष असहमत होने पर समझौता कर सकते हैं फिर वे तालाबन्दी व हड़ताल से एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश करते हैं. वे देखते हैं कि दूसरे पक्ष की शर्तें मानना सस्ता है अथवा हड़ताल या तालाबन्दी की स्थिति का सामना करना सस्ता है. सामूहिक सौदेबाजी मे धोखा तथा सद्भावना दोनों प्रयोग में आते हैं तथा आर्थिक तत्वो के साथ सामाजिक, राजनैतिक मनोवैज्ञानिक तथा एतिहासिक तत्वो का भी समावेश होना चाहिए.

अगर सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित किया जाता है तो मालिको व मजदूरो मे परस्पर एक दूसरो के दृष्टिकोण को समझेंगे मजदूर लोग महंगाई बढने पर, मालिको के लाभ बढने पर, अन्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा अधिक मजदूरी देने पर, तथा मजदूरो की उत्पादकता बढने पर प्रकाश डालते हैं जबकि मालिक इस बात पर जोर देते हैं कि इससे लागत बढ जाएगी. अगर देश में सामूहिक सौदेबाजी

References :

1. Barbara Wootton · Social foundations of wage Policy.
2. A. M. Ross : Trade Union & wage Policy.
3. S. A Palekar : Problems of wage policy for Economic development.
4. Chamberlin : Labour.
5. J. T. Dunlop : Wage Determination under Trade unions
6. Bowen . wage price issue.
7. Chamberlin : Trade Unions-Economic Analysis of Labour Union-Powers.
8. P. Ford : Economics of collective Bargaining.
9. Giri : Labour Problems in Indian Industries, P. 505.
10, W. H. Hutt : The Theory of Collective Bargaining.
11-12. Marshall : Principles of Economics, Book VI, ch. III-V. Economics of Industry, Book VI, ch. IV.
13. Lindblom : Unions and capitalism. p. 35.
14. S. H. Slichter : The Challenge of Industrial Relations.
15. A. M. Ross : The Trade Unions as wage-Fixing Institutions; The Dynamics of wage Determination under Collective. Bargaining; Union Policies and Industrial Management.

को प्रथा को उन्नत किया जाए तो श्रम-सघो के सहयोग से उत्पादकता बढ सकती है जहाँ जहाँ श्रम-सघ सक्रिय रहे है वहाँ मालिको को अच्छी मशीनें लगानी पडी है, अच्छा कच्चा माल प्रयोग करना पडा तथा उत्पादकता बढानी पडी. इसीसे विकास होता है.

7. देश में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होना चाहिए :

कम-विकसित देशो मे सामाजिक सुरक्षा सुविधाओ के दौर लगने पर मुआवजा, मृत्यु होने पर मुआवजा, बीमारी का इलाज, प्राविडेन्ट फड व पेंशन, मातृत्व के समय छुट्टी व इलाज आदि की आवश्यकता तो विकसित देशो से भी अधिक है. कम-विकसित देशो मे बहुत से मजदूरो का जीवन स्तर अत्यन्त हीन होता है और वे थोडी सी असुरक्षा सहन नही कर सकते परन्तु आज की स्थिति हम कम-विकसित देशो मे विकसित देशो की भाँति सामाजिक सुरक्षा प्रदान नही कर सकते. 1958 मे जर्मनी में प्रति व्यक्ति 191 U S. डालर के बराबर, यू. एस. ए. मे 175 डालर के बराबर, तथा आस्ट्रेलिया मे 131 U. S. डालर के बराबर सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान की गई. इतनी तो बहुत से कम-विकसित देशो की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी नही होती

साधनो की कमी से इतनी सुविधाएँ प्रदान न की जा सके तो भी इन सुविधाओ का शुभारम्भ आवश्यक होगा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, भूमि सुधार, मूल्य नियमन, अधिक रोजगार, शिक्षा का प्रसार यह सर्वोत्तम सामाजिक सुरक्षा होगी.

Wage guarantees कम-विकसित देशो मे थोडी बहुत मात्रा में "मजदूरी की जमानतदारी" भी दी जानी चाहिए, अर्थात् अगर मजदूर का कोई दोष हुए वगैर किसी कारण वश उसे हटाना पड़े या कुछ समय के लिए कार्य बन्द करना पडे तो उत्पादनकर्ताओ को मजदूरी का भाग मिलते रहना चाहिए. इससे श्रमिकों के जीवन स्तर की सुरक्षा रहेगी और उनकी उत्पादकता पर अच्छा प्रभाव पडेगा मालिक भी उत्पादन मे पडे अवरोधो को शीघ्रातिशीघ्र हटाने की कोशिश करेगे इस प्रकार की व्यवस्था से देश मे औद्योगिक शान्ति भी रहेगी तथा मजदूरो की आय नही गिरेगी व असमानताएँ नही बढेगी इससे देश मे उपभोक्ता माँग भी स्थिर रहती है तथा विनियोजन मे भी स्थिरता आती है.

कम-विकसित देशो मे धीरे-धीरे उन सुविधाओ के विस्तार से उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि अवश्य होगी और यह बात विकास में सहायक होगी.

कम-विकसित देशो मे दो प्रकार की मजदूरी नीति अपनाई जा सकती है. एक Centralized wage policy केन्द्रीय नियन्त्रित मजदूरी नीति तथा दूसरी,

decentralized wage policy अर्थात् विकेन्द्रित मजदूरी नीति. कम-विकसित देशों मे श्रम आन्दोलन इतना विकसित या सगठित नही पाया जाता कि केन्द्रीय नियन्त्रित मजदूरी नीति अपनाई जासके. इसके अतिरिक्त अगर कम-विकसित देश Capitalist or mixed economy पूंजीवादी या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाता है तो पूर्ण रूप से केन्द्रीय सचालित श्रम नीति स्वतन्त्रता व लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है हर देश मे क्षेत्रीय अन्तर होते हैं और एक सी नीति सम्भव नहीं हो सकती. इसी प्रकार से हर उद्योग व उद्योग की इकाइयो की स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती हैं. स्वय श्रम सघ इस नीति को पसन्द नहीं करते क्योंकि इससे उनकी स्वतन्त्रता का हनन होता है और श्रम आन्दोलन तानाशाही के अन्तर्गत आ जाता है.

कम-विकसित देशों में कुछ मौलिक सिद्धान्त बना लेना चाहिए (Some contours of basic principles) और फिर परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए. राज्य को तो सिर्फ सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित करके मजबूत करना चाहिए और देश में औद्योगिक झगडों को निपटाने वाली एकसी व्यवस्था होना चाहिए.

8. मजदूरी नीति को रोजगार व उत्पादकता वृद्धि योजनाओं से समन्वित होना चाहिए :

कोई भी मजदूरी नीति हर देश के लिए उपयुक्त नही होती और न एक ही देश के लिए हर समय के लिए उपयुक्त होती है. मजदूरी नीति ऐसी होना चाहिए जो :

(i) पूजी निर्माण में बाधक न बनें.
(ii) उत्पादकता बढाने में सहायक हो, तथा
(iii) विनियोजन व रोजगार वृद्धि में सहायक हो.

मजदूरी नीति स्वयं में विकास उत्पन्न नहीं कर सकती इसके लिए मौद्रिक, राजकोषीय, मूल्य तथा अन्य नीतियाँ भी सहायक होना चाहिए. मजदूरी नीति को उनसे समन्वित होना चाहिए

कालान्तर में हर चीज की सीमा होती है. इसी प्रकार से किसी भी देश में परिस्थितियों के अनुसार optimum wage या अनुकूलतम मजदूरी स्तर होता है. हमको इसे लाँघना नही चाहिए.

अध्याय 4

उत्पादकता तथा विकास

Productivity and Economic Growth

I उत्पादकता का अर्थ

II उत्पादकता माप

III उत्पादकता वृद्धि का महत्व उत्पादकता व विकास

IV कम-विकसित देशो मे उत्पादकता

V उत्पादकता वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व

यह अध्याय मुख्यत लेखक की पुस्तक Economics of Wages Productivity and Employment के अध्याय 2, 8, 9 व 10 पर आधारित है अन्य references दिए हुए है

अध्याय : 4

उत्पादकता तथा विकास

Productivity and Economic Growth

I उत्पादकता का अर्थ

अधिक उत्पादकता का अर्थ होता है कि उतनी ही मात्रा के साधनो से अधिक या और अच्छा उत्पादन होता है या उतनी ही मात्रा का उत्पादन कम साधनों से उत्पन्न होता है अधिक उत्पादकता का अर्थ होता है कि अधिकाधिक उत्पादन को पैदा करने के लिए पूजी, कच्चा माल मेहनत या कार्य क घटे अपेक्षाकृत कम लगते है उत्पादकता वृद्धि के वातावरण मे साधारण घटनाक्रम तोड दिया जाता है (routine is broken), नई उत्पादन मनोवृत्ति का जन्म होता है और अर्थ-व्यवस्था म प्रवैगिक गतिशीलता का सचार हो जाता है उत्पादकता का अर्थ होता है कि उत्पादन मे कार्य क्षमता बढी है और उत्पादन में मितव्ययिता हुई है उत्पादकता को हम प्रति मशीन की इकाई को भौतिक उत्पादकता प्रति व्यक्ति उत्पादन, या प्रति अश्वशक्ति उत्पादन के रूप में व्यक्त करते है

> "Productivity can be expressed as the physical output per unit of horse power raised, per unit of Capital equipment operated, per unit of materials consumed, or per unit of labour employed it is expressed as ratio of output to resources expended, as overall effectiveness of a productive unit, as ratio of output to the corresponding input of labour or production per man-hour"

II. उत्पादकता नापने की विधियाँ

उत्पादकता को नापना सरल कार्य नही है उत्पादन बहुत सी लागतो (inputs) तथा उत्पादन के अगो का सामूहिक परिणाम होता है और किस अग या लागत

के कारण कितना उत्पादन हुआ यह बताना सरल नही होता. सामान्यत उत्पादकता श्रम की उत्पादकता के रूप मे व्यक्त की जाती है

श्रम के रूप में उत्पादकता नापना :

परम्परानुसार उत्पादकता श्रम की इकाईयो की उत्पादकता के रूप में नापी जाती है. शायद इसका मुख्य कारण यह है कि अन्य inputs लागतो की अपेक्षा श्रम का समय आसानी से नापा जाता है और श्रम घटे तो हर उत्पादित वस्तु में निहित होते हैं कुल उत्पादन को कुल कार्य घटो से भाग देने पर प्रति श्रम घटा उत्पादन निकल आता है श्रम की उत्पादकता इस प्रकार से नाप सकते है

$$R = \frac{O}{LH}$$

R=Ratio . O=output in volume,

H=No of hours LH=Total available labour Hours

श्रम उत्पादकता को हम "प्रति व्यक्ति उत्पादकता" या "प्रति श्रम घटा उत्पादकता" के रूप मे नापते है मुख्यत हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के लिए "प्रति श्रम घटा" उत्पादकता ही नापते हैं

यद्यपि उत्पादकता "प्रति श्रम घटा" ही अधिक नापी जाती है परन्तु यह प्रणाली दोष रहित नही है उत्पादकता श्रम के अतिरिक्त पूँजी, सगठनकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञो सभी के सहयोग से बढती है और केवल श्रम-घटे के रूप में ही हम उसे नही नाप सकते. इसी प्रकार से अगर खराब कच्चे माल, अथवा किसी भी तकनीकी अवरोध के कारण उत्पादकता गिरती है तो इसका अर्थ यह तो नही होगा कि श्रम की कार्य क्षमता घट गई है

Select references

1. M M Mehta, Measurement of Industrial Productivity.
2 M B Shah, M P. Chronicle, May 30, 1960
3 K. V. Ramana, Indian Journal of Economics July 1953, Vol, XXXIV, No. 132. P. 87.
4 R A Lester, Industrial & Labour Relations p 78
5. P. Mazumdar, Indian Journal of labour Economics, vol III. No. 61, Jan 61.
6. Vehar Sangha . Productivity

इसके अतिरिक्त कई व्यक्ति जैसे कानूनी सलाहकार, क्लर्क, तेल देने वाला व्यक्ति आदि की उत्पादकता नापी नही जा सकती.

मशीन की उत्पादकता के रूप में उत्पादकता नापना :

जिन उद्योगों या उत्पादन कार्यो मे मशीनीकरण अधिक हो उनकी उत्पादकता, स्वभावत मशीन की इकाई की उत्पादकता के रूप में नापी जाना चाहिए, तब उत्पादकता इस प्रकार से नापी जाएगी.

$$R = \frac{O}{MH}$$

R = ratio, O = output in Volume, MH = Machine hour

यह प्रणाली भी दोषपूर्ण है क्योकि समस्त उत्पादन वृद्धि या कमी मशीनो के कारण नही होती. बहुधा उन्ही मशीनों पर कार्य करते रहने पर उत्पादकता बढती घटती रहती है

द्रव्य से उत्पादकता नापना :

> Measurement in terms of monetary value of the output or the corrected monetary Value of the output.

उत्पादकता नापने का सर्वोत्तम तरीका उसे राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में नापना चाहिए हम समस्त लागतो के द्राव्यिक मूल्य के आधार पर उत्पादकता नाप सकते है इस प्रकार से उत्पादकता को हम 'उत्पादन-लागत अनुपात" के रूप में व्यक्त कर सकते है या तो इसे हम Cost per unit प्रति वस्तु लागत से नाप सकते हैं या लागत मूल्य के प्रतिशत के रूप में नाप सकते है

एक और तरीका Conected monetary Value of output के रूप मे उत्पादकता नापने का होता है इसके अनुसार उत्पादकता भौतिक रूप में नही नापी जाती वरन् मूल्यों के परिवर्तनो के अनुसार उत्पादकता को आका जाता है.

सही उत्पादकता नाप के लिए हमको एक से अधिक तरीके से नापकर उत्पादकता माप के परिणामो को अध्ययन करना चाहिए

III. उत्पादकता व विकास : उत्पादकता का महत्व :

उत्पादकता से केवल अर्थशास्त्रियो का ही सबध नही होता है वरन् इससे देश के मजदूर, उत्पादनकर्ता, आयोजनकर्ता तथा राज्य सभी का सम्बन्ध रहता है. हर

ऐसे देश में जहाँ खाद्यान्न की कमी हो, जहाँ साधनों की कमी हो तथा जहाँ विनियोजन व रोजगार में वृद्धि करना हो वहाँ उत्पादकता वृद्धि सर्व प्रथम आवश्यक होती है. जीवन स्तर को उसी स्तर पर कायम रखने तथा वृद्धि करने के लिए उत्पादकता वृद्धि आवश्यक है उत्पादकता वृद्धि के आकड़ों से ही हमें विभिन्न क्षेत्रों में विनियोजन करने का मार्ग दर्शन मिलता है.

विनियोजन तथा उत्पादन सम्बन्धी समस्या आयोजन उत्पादकता वृद्धि की मान्यताओं व सम्भावनाओं पर आधारित होती है उत्पादकता वृद्धि का अर्थ लागत में कमी होती है इसलिए इससे लाभ की मात्रा, माग तथा प्रति व्यक्ति आय प्रभावित होती है.

उत्पादकता के अनुमान तथा आकड़े अर्थ व्यवस्था के Temporal Changes (दो समयों के बीच के परिवर्तन या व्यापार चक्रीय परिवर्तनों), Spatial (अर्थात् दो स्थानों के बीच परिवर्तनों) तथा Cross-Sectional Changes (दो उद्योगों के बीच परिवर्तनों) का मूल्यांकन करने में सहायता देते हैं उत्पादकता के अनुमान के आधार पर ही भिन्न-भिन्न उद्योगों का चयन, उनके स्थानीय करण करने का प्रश्न, उनके विकास का आयोजन, तथा उनका सचालन का प्रकार निश्चित किया जाता है

उत्पादकता समको का भविष्य में मांग परिवर्तनों के अध्ययन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इन आँकड़ों को हम उन्नत तकनीक का रोजगार पर परिवर्तन का प्रभाव अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते है. और फिर देश के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन कर सकते हैं इन्ही आँकड़ो के अध्ययन से हम विनियोजन, उत्पादन, रोजगार व राष्ट्रीय आय पर मौद्रिक व राजकोषीय नीति आदि का प्रभाव अध्ययन कर सकते है उत्पादकता आँकड़ों से हम rationalisation (या तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन का विवेकीकरण करना) के प्रभाव अध्ययन कर सकते हैं.

जैसे क्रिकेट खेल मे कहावत है "A run saved is a run made" उसी तरह उत्पादन क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उत्पादकता वृद्धि से जो साधनों की बचत होती है वह आय कमाने के बराबर ही होती है. उदाहरणतया अगर किसी देश में 15000 करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय है और आयोजन के कारण 5% उत्पादकता बढ़ती है तो 750 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन होता है. राज्य की योजना कार्यान्वित करने मे अगर उत्पादकता वृद्धि होती है तो या तो उसको

कम कर लेने से काम चल जाएगा या फिर वह उतनी मात्रा मे अधिक कार्य कर सकता है.

अधिक उत्पादकता के लिए हमको साधनो का अनुकूलतम प्रयोग करना पडेगा और इसी से देश में राष्ट्रीय आय व कल्याण बढ़ सकता है अधिक उत्पादकता से अधिक लाभ होता है, अधिक बचत हो सकती है, अधिक मात्रा मे विनियोजन योग्य पूंजी का निर्माण होता है और इस प्रकार से अधिक उत्पादकता विकास की कुंजी है.

अधिक उत्पादकता की आवश्यकता कई कारणो से उत्पन्न होती है. औद्योगीकरण की योजना के कारण देश में भारी उद्योगो में अधिक विनियोजन है और इससे उपभोग वस्तुओं की कमी पड जाती है इस कारण आय तो बढ जाती है परन्तु उसी मात्रा मे वस्तुओं के न बढने से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है मूल्यो के बढने से कच्चे माल तथा अन्य लागतो पर खर्च बढने से और मूल्य वृद्धि होती है और हो सकता है कि इससे पूंजी निर्माण हतोत्साहित हो क्योंकि बचतें कम हो जाती है इसलिए सतुलित, स्थाई व निरन्तर विकास के लिए उत्पादकता वृद्धि अत्यन्त आवश्यक होती है. M Bertrand de Fourenel des Ursin (यह एक ही व्यक्ति है) ने मन व्यक्त किया है कि कम-विकसित देश उत्पादन वृद्धि को अधिक मानें अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए पूंजी गहन तकनीक अपनाई जाती है और इससे बेरोजगारी फैलती है इसलिए पहला महत्व उत्पादन वृद्धि पर होना चाहिए और फिर उत्पादकता वृद्धि पर होना चाहिए.

IV कम-विकसित देश व उत्पादकता :

कम-विकसित देशो मे उत्पादकता कम है, इसमे तो कोई सशय नही है परन्तु तुलना के लिए विश्वास योग्य आँकडे उपलब्ध नही हैं इन देशो मे उत्पादकता बहुत कम है और इन देशो के मजदूर विकसित देशों के मजदूरो की तुलना मे बहुत अधिक समय उतनी ही मात्रा मे वस्तु पैदा करने के लिए लेते हैं निम्नलिखित तालिका से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं

See also : (1) "Wages and Productivity in Indian Industry." P. Y. Chinchankar, Commerce Annual Number 1968

(2) "Prosperity through Higher Productivity-certain basic issues and Practical difficulties." Naval H Tata, Commerce Annual Number 1965

देश	हर टन पैदा करने के लिए श्रम घंटे		हर शिफ्ट मे उत्पादित टनो मे
	शक्कर	सीमेन्ट	कोयला
फिलीपाइन्स	16 83	...	...
हवाई	4 64	...	...
लाउइशियाना	7 87	...	...
प्यूरटिरिको	5 10	...	...
भारत	83 04	10 18	0 51
फ्रान्स	...	1·60	...
जर्मनी	.	2·20	2·00
वेल्जियम		1 51	...
यू० के		1·82	1 84
यू० एम० ए०		1 50	15·00
जापान		1·75	...

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय मजदूर हवाई के मजदूर के मुकाबले में एक टन शक्कर बनाने मे 16 गुना अधिक समय लेता है, तथा सीमेन्ट बनाने मे यू० एस० ए० के मजदूर से 10 गुना अधिक समय लेता है, या कोयले के उत्पादन मे भारतीय मजदूर की उत्पादकता केवल $\frac{1}{30}$ है यह जरूर है कि उन देशो में उन्नत तकनीक, मशीनों तथा अन्य कारणों से उत्पादकता अधिक है फिर भी मजदूर की भी कम उत्पादकता मे बहुत जिम्मेदारी है.

भारत[1] में 1946 से 1952 के बीच समस्त उद्योगो की उत्पादकता निर्देशांक 100 से गिरकर 92 आ गया अर्थात् उत्पादकता 1·56 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से घट गई तत्पश्चात् उत्पादकता बढी और 1964 में यह निर्देशांक 157 था. अर्थात् 1946-1964 के 19 वर्षों में उत्पादकता 57% बढी यानी प्रतिवर्ष $\frac{57}{19}$ = 3 00 प्रतिशत के हिसाब से बढी

Eastern Economist के अनुसार[2] 1939-1959 साल में संगठित उद्योगो मे उत्पादकता केवल 1% प्रतिवर्ष से बढी.

G. F. : Ch 13. J. Pajestka : अध्याय के अन्तिम पृष्ठ पर reference है.
Ref : Nawal H. Tata : op. cit.

1. Cf : P. Y. Chinchankar : op. cit.
2. Eastern Economist Annual Number 1961.

यह उत्पादकता वृद्धि अधिक नही थी क्योंकि विकास को शुरू के काल में उत्पादकता वृद्धि की अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं

U S S. R में शुरू के काल में वही अधिक उत्पादकता वृद्धि हुई थी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका मे स्पष्ट है

वर्ष	उत्पादकता वृद्धि
1900-1913	3·1% प्रतिवर्ष
1928-1955	7·5% ,,
1950 1958	7·2% ,,

कम-विकसित देशो में उत्पादकता कम होने के कारण पता लगाना कठिन नही है :

1. सर्वप्रथम इन देशो मे मशीनें पुरानी व पिछडे किस्म की होनी हैं बहुधा उन्नत देशो द्वारा हटाई गई पुरानी मशीनें खरीद ली जाती है.
2. इन देशो मे श्रमिक शारीरिक रूप से कमजोर तथा अप्रशिक्षित व तकनीक ज्ञान मे पिछडे होते हैं निम्नजीवनस्तर के कारण वे बीमार रहते हैं, जिससे उनकी गैरहाजरियाँ अधिक रहती हैं. वे जल्दी थक जाते हैं और उनमें अधिक कार्य करने की शक्ति, रुचि व योग्यता का अभाव रहता है.
3 इन देशो में सचालित छोटे बडे उद्योग अनुकूलतम आकार के नही होते. कुछ उद्योग इतने छोटे पैमाने पर चलाए जाते हैं कि उनमें बडे पैमाने के उद्योगों को उपलब्ध आन्तरिक व वाह्य मितव्ययिताएँ प्राप्त नही होती अथवा कुछ बडे उद्योग बहुत Unwieldy भारी या स्थूल होते हैं.
4 इन देशो में कुशल व उत्साही साहसियो की कमी है. बहुत से प्रशासक भी कर्मण्य व दक्ष नही होते. ये अपने हर काम पुराने ढग व ढर्रे से चलाते रहते हैं.
5. पूँजी की कमी मे (जो स्वय कम उत्पादकता, कम राष्ट्रीय आय, कम प्रति व्यक्ति आय व कम बचतो के कारण होती है) देश मे पूँजीगत विनियोजन कम होता है जिसके कारण उत्पादन के तौर तरीके पुराने होते हैं और उत्पादकता कम होती है
6 इन देशो मे नव प्रवर्तनो की कमी रहती है और विदेशी को तकनीक की नक्ल करते हैं चाहे वैसी स्थितियाँ इन देशों में उपलब्ध हों या नहीं.
7 इन देशो में वाजार विस्तृत नही होते. यातायात साधनो का पिछडापन, गरीवी तथा अज्ञानता व पिछडेपन के कारण माँग की व्यापकता कम होती है.

इस कारण उत्पादकता भी कम रहती है इन देशो में बगैर बिके सामान तथा अतृप्त आवश्यकताओं की विरोधाभासी स्थिति मौजूद रहती है

8. इन देशो मे मजदूरी कम होने से श्रमिको का जीवनस्तर कम रहता है और इस कारण उनकी योग्यता व शक्ति तथा कार्य करने की इच्छा कम रहती है

9. कम-विकसित देशो मे श्रमसघ भी उत्पादकता वृद्धि मे सहायक नही होते भारत की National Productivity Council के भूतपूर्व अध्यक्ष डा पी० एस० लोकनाथन के अनुसार भारत के प्रमुख श्रम सघ 'Indian National Trade Union Congress" ने 1966 मे उत्पादकता वर्ष" के कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने में सहयोग नही दिया

10. इन देशो मे जो बेरोजगारी की अधिकता है उससे भी उत्पादकता कम रहती है रोजगार वृद्धि से सामाजिक उत्पादकता बढती है देश की आय बढती है तथा परिवारो की आय बढती है इसके फलस्वरूप आम जनता के शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर ऊँचे उठते है और पूर्ति बढाने की क्षमता बढ जाती है दूसरी ओर सामाजिक आय बढने से देश में प्रभावशील माँग बढती है और उत्पत्ति की मात्रा मे वृद्धि से बडे पैमाने के उत्पादन के लाभ प्राप्त होते है जिन देशो मे पूर्ण रोजगार व्यवस्था होती है, वहाँ पर श्रमिक मशीनीकरण के विरोधी भी नही होते और फिर तकनीकी उन्नति होती है जिससे उत्पादकता म वृद्धि होती है

11 मजदूरी स्तर के नीचे होने, प्रेरणादायक मजदूरी प्रणाली के न होने, लाभ में भागीदारी की उचित व्यवस्था न होने तथा श्रम को सस्ती वस्तु के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्तियाँ इन देशो मे उत्पादकता को नीचे स्तर पर ले जाती है

12 इन देशो मे उत्पादकता कम होने के अन्य कारण इस प्रकार है

(i) उत्पादकता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय आन्दोलनो की सर्वथा कमी है.

(ii) इन देशो में उत्पादकता वृद्धि सबधी अनुसधानो की सर्वथा कमी है

(iii) उत्पादकता वृद्धि के लिए समन्वित योजना, जिसके अन्तर्गत यातायात सबधी प्राथमिकताएँ तक निर्धारित की जाती है, का सर्वथा अभाव रहता है

(iv) मूल्यों के उच्चावचन भी उत्पादकता सबधी दीर्घकालीन आयोजन को सभव नही बनाते.

V. उत्पादकता वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व :

कम-विकसित देशों में उत्पादकता वृद्धि के लिए मजदूर, उत्पादनकर्ता, संगठनकर्ता, वैज्ञानिक, राज्य तथा अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से ही सम्भव होगा लेखक के दृष्टिकोण से इसके लिए सबसे मुख्य बातें देश में :

(1) पूँजी निर्माण बढाना.
(11) मजदूरों की मजदूरी को प्रेरणादायक बनाना.
(111) देश म पूर्ण रोजगार की नीति अपनाना चाहिए.
(1V) तकनीकी उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए.
(V) उद्योगो का आकार अनुकूलतम रखना चाहिए.
(V1) सगठन आधुनिक रूप में करना चाहिए, आदि.

हम इनको विस्तृत रूप में अध्ययन करें

1 मजदूरी को प्रेरणादायक बनाया जाए :

आज के युग मे कम विकसित देशों में कम मजदूरी, कम उत्पादकता, तथा कम-उत्पादकता और कम मजदूरी का दुष्चक्र है. प्रश्न यह है कि मजदूरी पहले बढाई जाए अथवा पहले उत्पादकता बढे और तदुपरान्त मजदूरी बढाई जाए. लेखक का मत है कि पहले मजदूरी स्तर में उन्नति करना चाहिए. योरोप व अमेरिका में उत्पादकता वृद्धि का कारण वहाँ श्रमिक को प्रेरणादायक मजदूरी देना रहा है. एशिया मे श्रम सस्ता है इसलिए यहाँ पर उद्योगीकरण अधिक नही हुआ. स्वय यू एस.ए मे दक्षिण में सस्ते नीग्रो श्रमिकों की उपलब्धि के कारण वहाँ पर मशीनीकरण कम है और उत्पादकता भी कम है

अधिक मजदूरी देने से

(1) श्रमिक के खाने पीने के स्तर से उसकी शक्ति बढती है, भावी श्रम पीढिया स्वस्थ होती हैं
(11) उचित शिक्षा व ट्रेनिंग पा सकते है
(111) श्रमिक की फिर रूढीवादिता, भाग्यवादिता, आलस्य समाप्त होता है
(1V) उसकी गतिशीलता बढती है वह दूसरे कार्य कर सकता है.
(V) शिक्षित श्रमिकों के होने से मजबूत तथा अच्छे श्रम-सघो का विकास होता है.
(V1) उन्नत तकनीक को अपनाकर कार्य कर सकते है तथा बाजार के विस्तार से भी उत्पादकता वृद्धि होती है

इस पर पूरा अगला अध्याय लिखा गया है

परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि मजदूरी को प्रेरणादायक बनाया जाए तथा कार्यानुसार दिया जाए मजदूरी के अन्तर भी तर्कयुक्त होना चाहिए

J. P. Davison, P. Sargant Florence, Barbara Gray and N. S. Ross के अनुसार

> "प्रेरणादायक मजदूरी देने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रति वस्तु लागत घटती है, सिरोपरि लागतों का प्रति वस्तु भार कम होजाता है. कम ओवरटाइम की आवश्यकता रहती है, कार्य सन्तुष्टि बढ़ती है."

Stansfield ने तो न्यूटन के मॉडल पर Socio-Psychological Motion का नियम बनाया है कि

> "Every person continues in his state of rest, or of uniform work in a straight line, unless he is compelled by impressed incentives to. change his state."

इसलिए मजदूरी व्यवस्था के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए.

2. पूर्ण रोजगार की नीति अपनायी जाए :

कम-विकसित देशो में रोजगार के प्रति पूर्ण ध्यान नही दिया जाता है. भारत में प्रथम योजना के अन्त मे 53 लाख व्यक्ति बेरोजगार, चतुर्थ योजना के अन्त तक इनकी सख्या बढकर 160 लाख से ऊपर हो जाने की सम्भावना है. इस कारण कोई भी व्यक्ति यह नही चाहता कि *rationalization* नीतियों के कारण वह नौकरी से निकले. इसलिए श्रमिक उत्पादकता वृद्धि नीतियो के विपक्ष में हो जाते है. कम-विकसित देशो मे पूर्ण रोजगार प्रदान करने के बारे मे असमर्थता व्यक्त की जाती है परन्तु राज्य सब व्यक्तियो को नौकरी नही दे सकता पर रोजगार के अवसर तो प्रदान कर सकता है.

3 तकनीकी उन्नति :

तकनीकी उन्नति का अर्थ यह नही है कि कम विकसित देश एकदम उन्नत देशों की तकनीक अपना सकते है. इसका अर्थ है कि अपनी विशेष परिस्थितियो के अनुसार वे तकनीक अपनाएँ और उसमें यथोचित परिवर्तन करते रहें.

4. श्रम संघो को सहायता देना चाहिए

श्रम सघ औद्योगिक शान्ति बनाये रखने, उत्पादकता बढ़ाने की प्रेरणा देने व जिम्मेदारी सिखाने, तकनीकी व्यवस्था को अपनाने में सहायता देने आदि कार्यों से उत्पादकता वृद्धि में सहायता कर सकते है.

5. संगठन :

उत्तम संगठन, उत्पादन इकाई का अनुकूलतम आकार, कार्य करने व रहने की उत्तम व्यवस्था, अच्छे कच्चे माल का प्रयोग, मशीनों को अच्छी तरह से चलाना व रखना, उचित बजट कन्ट्रोल, better layout उद्योग का उचित स्थापन, उचित खरीद व बेच नीति तथा उत्तम प्रशासन उत्पादकता वृद्धि के लिए परम आवश्यक हैं.

6. राज्य की अन्य नीतियाँ :

उत्पादकता वृद्धि के लिए सस्ती साख व्यवस्था तथा उचित कर व्यवस्था जिसमें विनियोजन को प्रोत्साहन मिले आवश्यक होगी.

●

Other references —

Angus Maddison .

1. Facts and Observations on labour Productivity in Western Europe, North America & Japan
2. Walter Galenson & John R Erikson Industrial Labour Productivity in North Western Countries.
3. J Pajestka . Stages of Industrialization & Labour Productivity.
4. Strigeto Tsuru . Technology and Productivity.
5. W. E G Salter Productivity Growth and Accumulation as historical processes.
6. Reynolds . Wages and Productivity.
7. S Carlson Contribution of management to productivity.
8. H A Turner . The Contribution of workers to productivity.
9. John T. Dunlop : Evaluation of factors affecting Productivity
10. Participants . Internation Economic Association
    Cf: Problems in Economic Development, Ed. E. A. G Robinson, Melvin Redder, V. K. R V. Rao, Gyorgy Cukor, E. I. Kapustin, Giovanni Lasorsa, D J Delivanis, Edvard Mirz, Elliort Berg Subbiah Kannappan, Gosta Rehn, J H Davis, J P. Carter, John Kendrik, Pierre Gonad, Felix Trappaniers, Carl Knoltinger, Kjell Eide, R. Ulavic, Huber Sainmount, G A. Prudensky, Zofia Morecka, Adolf Sturumthal, K. F. Walker etc.

अध्याय : 5

विकास व मौद्रिक नीति

Growth And Monetary Policy

भाग 1

I. मौद्रिक नीति का अर्थ .

II विकसित देशो मे स्थिरता व विकास के लिए नीति :

(a) आन्तरिक मूल्य में स्थिरता का लक्ष्य.

(b) विनिमय दर स्थिरता का लक्ष्य.

(c) तटस्थ मुद्रा नीति.

(d) विकास के लिए मौद्रिक नीति.

III. विकसित देशो मे मौद्रिक नीति की सीमाएँ ·

IV. मौद्रिक व राजकोषीय नीति.

भाग 2

I विकास के लिए मौद्रिक नीति के आवश्यक तत्व :

(i) मौद्रिक नीति से संस्थागत बचतें बढ़ना चाहिए.

(ii) मौद्रिक नीति को पूँजी निर्माण में सहायक होना चाहिए, मुद्रा स्फीति व पूँजी निर्माण.

(iii) देश में साख का सामाजीकरण व प्रजातान्त्रीयकरण होना चाहिए.

(iv) केन्द्रीय बैंकिंग की कला का विकास आवश्यक.

(v) विदेशी विनिमय पद्धति में स्थायित्व.

(vi) दीर्घकालीन विनियोजन को प्रोत्साहन.

(vii) मौद्रिक नीति को सतुलित होना चाहिए.

II मौद्रिक नीति की सीमाएँ

अध्याय : 5

विकास व मौद्रिक नीति

Growth And Monetary Policy

भाग 1

I मौद्रिक नीति का अर्थ

मौद्रिक नीति [1] के अन्तर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जो राज्य या केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा चलन या साख, मुद्रा चलन (Close Money Substitute or Near Monies) प्रभावित करने के लिए करता है मौद्रिक नीति के अन्तर्गत, बैंक दर में परिवर्तन करना खुले बाजार की नीति के अन्तर्गत प्रतिभूतियों को खरीदना व बेंचना, व्यापारिक बैंकों की न्यूनतम नगद विधि को बदलना, अथवा साख नियन्त्रण करना आदि सब कार्य आते हैं

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मुद्रा व साख का नियमन व नियन्त्रण किया जाता है K. E Boulding 'मौद्रिक नीति" के स्थान पर "वित्तीय नीति" कहना पसन्द करते हैं उनका विचार है कि "मौद्रिक नीति" के अन्तर्गत बैंक ऋणों का जिन्हें हम साख नहीं कह सकते उनका नियन्त्रण आता है जबकि "वित्तीय नीति" के अन्तर्गत बैंकों व बीमा कम्पनियों के नियन्त्रण का कार्य आता है केन्द्रीय बैंक के संचालन का कार्य तथा मुद्रा बाजार का नियन्त्रण भी इसी नीति के अन्तर्गत आते हैं

परन्तु आज समस्त अर्थशास्त्री "मौद्रिक नीति" शब्द ही प्रयोग में लाते हैं और उनका आशय इस नीति से वही होता है जो कि बोल्डिंग "वित्तीय नीति" से मानते हैं

पुराने अर्थशास्त्रियों का मौद्रिक नीति की अस्थिरता दूर करने के लिए अपनाए जाने में अत्यधिक विश्वास था वे मानते थे कि जब कभी भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है मौद्रिक नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके स्थिति

1. Allen, Buchanan and Colberg · "Prices, Income & Public Policy," p. 221.

पर नियन्त्रण किया जा सकता है. परन्तु स्वर्णमान के टूटने और 1930 की महान् मंदी के बाद मुद्रा नीति से राजस्व नीति का महत्त्व अधिक बढ़ गया लेकिन हाल के वर्षों में अर्थशास्त्रियों ने मौद्रिक नीति के महत्व को पुन स्वीकार करना शुरू कर दिया है

II मौद्रिक नीति और विकसित देश . स्थायित्व या विकास ?

विकसित देशों के सम्बन्ध म मौद्रिक नीति के चार मुख्य उद्देश्य बताये जाते है कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि विकसित देशों मे मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य देश मे आन्तरिक मूल्यो मे स्थिरता लाना है[1] कुछ अन्य अर्थशास्त्री विदेशी विनिमय स्थायित्व को मौद्रिक नीति का मुख्य अग मानते है[2] कुछ अन्य अर्थशास्त्री "तटस्थ मौद्रिक नीति" की सिफारिश करते हैं, जबकि बहुत से अन्य अर्थशास्त्री यह चाहते हैं कि विकसित देशो में भी मौद्रिक नीति का लक्ष्य देश मे विकास बढाना है. हम इन नीतियो के औचित्य को जाचेंगे

(a) क्या मौद्रिक नीति का लक्ष्य आन्तरिक मूल्य स्तर में स्थायित्व लाना है ?

1930 के वर्षो की महान् मदी के बाद केन्स ने मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य नियन्त्रण पर बहुत जोर दिया Crowther (क्राउथर) तथा Gustav Cassel (गुस्टव कैसेल) भी इसी मत के थे. इन अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उन्नत देश चक्रीय मूल्य परिवर्तनो से पीडित रहते हैं "मंदी के काल" म उत्पादनकर्ता व व्यापारी हानि उठाते है इन दिनो में बेरोजगारी फैलती है, राष्ट्रीय आय गिरती है विनियोजन कम होते है, बैंक फेल होते है तथा मजदूरी दर गिरती है तेजी के काल मे, इसके विपरीत निश्चित आय व मजदूरी पाने वालो को मूल्य वृद्धि के कारण वास्तविक आय में कमी उठानी पडती है इन दिनो मे विनियोजन महँगा पड जाता है ऐसे काल म आर्थिक जगत मे जो तेजी, आशावाद और जोश आता है वह अल्पकालिक व कृत्रिम होता है मुद्रा स्फीति में स्वय ही बरबादी के बीज बोये रहते है

इसके लिए यह आवश्यक है कि चक्र विरोधी मौद्रिक नीति अपनायी जाए.

1. K E. Boulding : Principles of Economic Policy, Asia Publishing House 1962 p 210-11
2. A G. Hart, Monetary Policy for Income Stabilization for a developing democracy. Ed. Max F. Millikan Yale 1953. p. 304.

मदी के काल मे बैंक दर घटा दी जानी चाहिए ताकि बैंक अधिकाधिक साख निर्माण कर सकें राज्य को चाहिए (या केन्द्रीय बैंक को चाहिए) कि वह खुले बाजार मे प्रतिभूतियाँ खरीदे ताकि जनता या बैंको के कोष बढ सकें और वे और अधिक साख निर्माण कर सकें इन दिनो मे प्रवृत्य गुणात्मक साख नियत्रण (Selective Credit Control) या चयनात्मक साख नियत्रण या तो ढीला कर देना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए

मुद्रा स्फीति काल में इनके विपरीत मौद्रिक नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए अर्थात् इन दिनो मे बैंक दर बढा दी जानी चाहिए, चयनात्मक नियत्रण शुरू करना चाहिए, व्यापारिक बैंको द्वारा जमा किए जाने वाली राशि परिवर्तनशील न्यूनतम निधि अनुपात बढा दी जानी चाहिए और राज्य को खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचना चाहिए जिससे कि देश से फालतू मुद्रा चलन में से निकाली जा सके

आन्तरिक मूल्य स्तर को स्थिर रखने की इस मौद्रिक नीति का U S A. मे प्रेसीडेन्ट एफ डी रूज़वेल्ट की ' न्यू डील नीति" मे भी समर्थन मिला था

आलोचना :

इस प्रकार की नीति को बहुत से अन्य अर्थशास्त्रियो से समर्थन प्राप्त नही है इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि मूल्य नियत्रण नीति से साहसियो व उत्पादनकर्ताओ को लाभ नही होंगे जिससे पूँजी निर्माण रुकेगा इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि वास्तव मे "वस्तुओं" के मूल्यो को स्थिर करने के स्थान पर ' उत्पादन के अगो" के मूल्य स्थिर करना चाहिए. आन्तरिक मूल्य स्थिर करने के सम्बन्ध मे सबसे मुख्य परेशानी तो यह रहती है कि किन वस्तुओ के मूल्य स्थिर रखे जाएँ देश में उत्पादित समस्त वस्तुओ के मूल्य तो स्थिर नही किए जा सकते है इसके अतिरिक्त लागत सम्बन्धी इतनी कठिनाइयाँ रहती है कि यह प्रश्न उठता है कि मूल्यो को किस स्तर पर स्थिर किया जाए इस सम्बन्ध मे इसीलिए 1932 मे Prof. Hayek ने कहा है

> "हमको यह नही भूलना चाहिए कि पिछले छै या आठ वर्षों से मौद्रिक नीति को हमने समस्त विश्व में स्थिरता लाने के समर्थको की सलाह पर ढाला है. अब वक्त आ गया है कि हम इनके प्रभाव को, जिससे पर्याप्त हानि हो चुकी है, उत्तार फेंका जाए "

---

cf. F. A Von. Hayek "Monetary Theory & Trade Cycles" p. 18-22

(b) क्या मौद्रिक नीति का लक्ष्य विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाना होना चाहिए ?

कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य विदेशी विनिमय में स्थिरता लाना होना चाहिए. यह नीति मुख्य रूप से उन देशों को अपनाना चाहिए, जो अपनी राष्ट्रीय आय का मुख्य भाग विदेशी व्यापार से प्राप्त करते है यह नीति उन देशो के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनमें बहुत सी विदेशी पूजी लगी हो. इन अर्थशास्त्रियो का मत है कि विदेशी विनिमय मे अस्थिरता से विदेशी मुद्रा बाजार मे विदेशी मुद्रा का सट्टा होने लगता है अगर देश मे विदेशी विनिमय दरो में स्थिरता नही रहेगी तो विदेशी पूजी का आना जाना इस प्रकार से लगा रहेगा कि देश को लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है, विदेशी विनिमय की अस्थिरता के कारण जनता की तरलता पसदगी बढ जाती है और वे स्वर्ण सचय करने लगते है, जिसे वे बाद में "सुरक्षित मुद्रा" (Safe currency) में बदल लेते है

इस नीति के समर्थक यह चाहते हैं कि जब विदेशो में मूल्यो में परिवर्तन हो तो अपने देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दर मे परिवर्तन करने के स्थान पर देश के आन्तरिक मूल्यो मे परिवर्तन कर देना चाहिए

हमने देखा था कि प्रथम नीति के प्रवर्तक (आन्तरिक मूल्यो मे स्थिरता के समर्थक) आन्तरिक मूल्य मे स्थिरता और तदनुसार विदेशी विनिमय दरो मे परिवर्तन चाहते थे, जबकि इस नीति के प्रवर्तक विदेशी विनिमय दरो मे स्थिरता और तदनुसार आन्तरिक मूल्यो मे परिवर्तन के समर्थक हैं

आज इस नीति के अधिकाश अर्थशास्त्री समर्थक नही हैं फिर I.M F या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद यह कार्य अब मौद्रिक नीति का मुख्य अग नही रह गया है

(c) क्या तटस्थ मौद्रिक नीति उपयुक्त होगी ?

विकसटीड (Wicksteed) जे सी. कूपमॉन्स (J. C. Koopmans), हाएक (Hayek) तथा डी. एच. राबर्टसन चाहते हैं कि विकसित देश तटस्थ मौद्रिक नीति अपनाएँ तो सर्वोत्तम होगा. इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि मौद्रिक नीति इस प्रकार की हो कि देश में आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो, जिसमे मुद्रा के माध्यम से विनिमय ऐसा हो, जो वास्तव मे "अदला बदली" हो (The aim of the monetary policy should be to establish an economic system in which exchange may essentially be barter with the help of money I)

तटस्थ मौद्रिक नीति का मुख्य ध्येय यह कि देश में मौद्रिक नीति का प्रयोग न तो मुद्रा स्फीति को उत्पन्न करना होना चाहिए और न ही मुद्रा विस्फीति उत्पन्न होने देना चाहिए.

यह सिद्धान्त वास्तव में "मुद्रा परिमाण" सिद्धान्त पर आधारित है और उस नीति की भाँति ही त्रुटिपूर्ण है इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों का ख्याल है कि अगर मुद्रा की मात्रा निश्चित रखी जाए तो मूल्य स्तर भी उच्चावचन रहित रहेंगे. वास्तव में मूल्य परिवर्तन तो मुद्रा की स्थायी मात्रा पर भी होंगे दीर्घकाल में तटस्थ मुद्रा नीति आर्थिक मंदी का कारण बन जाती है आज के युग में गतिशील या प्रवैगिक अर्थव्यवस्था में तटस्थ मौद्रिक नीति अनुपयुक्त रहेगी

(d) विकसित देश और विकास प्रोत्साहित करने वाली मौद्रिक नीति :

Crowther क्राउथर के अनुसार, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य पूर्ण रोजगार अवस्था पर बचत व विनियोजन में समन्वय व साम्य स्थापित करना पड़ता है.

विकास के लिए तो वास्तव में वर्तमान बचतों से वर्तमान विनियोजन ज्यादा होना चाहिए. यह कार्य या तो साख या बैंकनिवेश या मुद्रा की चलन गति में वृद्धि करके किया जा सकता है. जमा की हुई (Hoarded) मुद्रा को निकालने का भी यही प्रभाव होता है जब पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाए तो बचत व विनियोजन बराबर हो जाना चाहिए इस स्थिति में अगर विनियोजन, बचतों से अधिक रहा तो देश की वास्तविक आय में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, केवल मुद्रा स्फीति फैलेगी और अगर विनियोजन कम रहा तो देश में बेरोजगारी और मंदी फैलेगी.

मौद्रिक नीति अगर देश में पूर्ण रोजगार के स्तर पर मूल्य स्थिरता रखने में सफल होती है तो इससे विकास होगा. जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा की मात्रा में आवश्यकतानुसार वृद्धि से देश में मुद्रा-स्फीति भी नहीं होगी और देश में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के आयोजन में कोई अवरोध भी पैदा नहीं होगा

III. विकसित देशों में विकास के लिए मौद्रिक नीति की सीमाएँ :

(a) मौद्रिक नीति ही विकसित देशों में न तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रख पाती है और न ही मुद्रा विस्फीति को दूर कर पाती है :

Alvin H. Hansen एल्विन हन्सन का मत है कि मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने में मौद्रिक नीति अपर्याप्त रहती है आज जबकि मुद्रा परिमाण

See : Alvin H. Hansen : Ch. II. Monetary Theory & Fiscal Policy p. 159-163.

सिद्धान्त को "ताक पर रख दिया गया है" फिर भी कभी-कभी यह देखने में आता है कि कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि मूल्यों पर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव पडता है. यह बात अर्ध-सत्य और वास्तविकता का सरलीकरण है

हन्सन का मत है कि राजकोषीय नीति का प्रयोग इस सबध मे मौद्रिक नीति के प्रयोग से अधिक प्रभावशील और कम खतरनाक है मौद्रिक नीति से प्रभावशील माँग कम करना अत्यन्त कठिन होगा या तब ही हो सकता है जबकि 'ब्रेक" (Brakes) इतनी तेजी से लगाए जाएँ कि अर्थव्यवस्था झटके से स्थिर होकर गिर जाए. इसके लिए ब्याज की दर को बहुत बढाना होगा

हन्सन ने सुन्दर शब्दो मे कहा

> "वे लोग, जो मौद्रिक नीति से मुद्रा स्फीति को नियत्रण करने की बडा मुँह फैलाकर बात करते हैं यह भूल जाते हैं कि केवल मौद्रिक नीति से काम नही बन सकता और अगर वे उसे प्रभावशील बनाने के लिए सख्त कदम उठाते है तो अर्थव्यवस्था लडखडाकर गिर जाएगी (The economy will turn into tail spin)"

वे और कहते हैं

> "किसी भी मोटे व्यक्ति का मोटापा दूर करने का सबसे सरल उपाय उसका गला घोटना ही है इतना सख्त कदम उठाने पर अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और इससे कम कदम उठाने पर यह नीति प्रभावहीन रहेगी" (It would be an easy matter to stop a man from becoming excessively corpulent simply by strangling him to death A sufficiently sharp curtailment of money supply could indeed quickly end an inflation. No one denies that. But a programme to stop an inflationary development merely by reducing the quantity of money is a dangerous device Moderately used, it courts the failure of ineffectiveness, pushed to the needed fanatical extremes, it courts disaster."

हन्सन की इस सम्बन्ध मे अन्य आपत्तियाँ ये है

1. मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए साख नियत्रण से छोटे विनियोजको को हानि

होगी. बड़े विनियोजकों के पास तो अपने स्वय का धन होता है. इससे सामाजिक अहित होगा.

2 देश में बैंक ही तो साख नही प्रदान करते. बैंकिंग कम्पनियाँ, निजी उधार देने वाली सस्थाएं, तथा वित्तीय सस्थाएँ भी तो धन देती है इस सबध मे Radcliffe Committee का मत है कि मौद्रिक नीति प्रभावशील तभी हो सकती है जबकि इससे सम्पूर्ण देश की तरलता प्रभावित होती हो.

3. हन्सन ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पर उनका कथन है कि मुद्रा स्फीति के नियत्रण म मजदूरी नियत्रण व राज्यकोषीय नीतियाँ अधिक प्रभावशील होती हैं .

(b) मौद्रिक नीति से मदी भी दूर नही होती.

Pro. Bach : प्रो. बाख का कथन है कि मौद्रिक नीति मदी दूर करने मे प्रभावहीन रहती है. मौद्रिक नीति से अगर जो कुछ भी मुद्रा स्फीति नियत्रण होता है उससे भी कम उसका प्रभाव मदी को दूर करने मे होता है. किसी भी देश मे केन्द्रीय बैंक बाजार से मुद्रा की बाढ़ ला सकता है परन्तु उसमे यह शक्ति नही होती कि वह बैंको को उधार देने और विनियोजकों को उधार लेने पर मजबूर कर सके. उनके शब्दो मे

> "मौद्रिक नीति से मदी दूर करना उतना ही कठिन है जितना कि गैस निकले फुकने को डोर ढीला करके ऊपर चढाना होता है"

मौद्रिक नीति के अन्तर्गत मदी दूर करने के लिए ब्याज की दर घटाते है. परन्तु (जैसा कि केन्स के मॉडल में देख चुके है) ब्याज की दर के घटाने से मदी दूर नही होती.

(c) मौद्रिक नीति के प्रभावशील होने में देर लगती है :

Milton Friedman मिल्टन फ्राइडमेन के अनुसार मौद्रिक नीति का प्रभाव देर से प्रकट होता है उन्होंने अनुमान लगाया है कि मौद्रिक परिवर्तन होने के कारण आर्थिक स्थिति मे परिवर्तन होने मे 16 से 20 महीने तक का समय लग जाता है

(d) मौद्रिक परिवर्तनो का मदी व तेजी के काल में पूरा प्रभाव इसलिए नही रहता कि मदी के काल में अगर M का सकुचन रोक भी दिया जाय तो V का

---

1. George Leland Bach . Economics : ch 14 : Monetary Policy p 256-9
2. Milton Friedman quoted from D B Singh op. cit p 265.

संकुचन नही रुक पाता और उसी प्रकार से तेजी काल में M को तो कम किया जा सकता है परन्तु V को कम नही किया जा सकता

(e) मौद्रिक नीतियाँ विकासवर्धन के लिए अपर्याप्त है :

आज के युग में मौद्रिक नीति की विकासवर्धन क्षमता अधिक नही मानी जाती इस सबध में निम्नलिखित उद्धरण महत्वपूर्ण है, जो यह सम्मति जाहिर करते हैं कि मौद्रिक नीति विकास में महत्वपूर्ण नहीं है

Haberler : हेबरलर का कथन है

> "भिन-भिन राष्ट्रो के दीर्घकालीन भविष्य, उन देशो के व्यक्तियो के जीवन स्तर और देश की राष्ट्रीय आय की विकास दरे, मुख्य गैर-मौद्रिक कारणो से प्रभावित होती है ये तत्व है—अनुकूल भूमि-श्रम सबध, अच्छे प्राकृतिक साधन, देश की जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य स्तर, राजनैतिक व सामाजिक स्थिरता बचत की क्षमता, तथा उत्पादकता मौद्रिक नीतियाँ-विकास में बाधक के रूप मे अधिक प्रभाव बता सकती है, पर विकासवर्धन क्षमता उनकी सीमित है उचित मौद्रिक नीति विकास में सहारा दे सकती है पर स्वय विकास-कारक नही हो सकती"

K E Boulding *के ई. बोल्डिगका मत भी हेबरलर जैसा है. उनके अनुसार*

> "विकास के महत्वपूर्ण घटक परस्पर तथा देश की संस्कृति व मनोवृत्ति से इतने अधिक सह-सबधित है कि उनको अलग करना कठिन है इसी कारण हम यह कहने म असमर्थ रहते है कि विकास के लिए नियंत्रित बैंकिंग पद्धति उत्तम है या बिल्कुल स्वतन्त्र पद्धति उपयुक्त है. या देश मे आयोजित अर्थ-व्यवस्था उत्तम है या निर्बाधवादी अर्थव्यवस्था उत्तम है
>
> वित्तीय व्यवस्था का कभी कार्य केवल साहसियो की सहायता देना है तो कभी उन्हे स्वय साहसी बनना पडता है इसलिए हम यह निर्धारित नही कर सकते कि विकास के लिए निष्क्रिय परम्परागत बैंकिंग पद्धति होना चाहिए या चपल साहसपूर्ण पद्धति होना चाहिए

1. Haberler : Monetary factors affecting economic stability, in International American Association's "Stability & progress in the world's economy" Ed. by D. C Hague pp 151-207.
2. *Boulding . op cit : p* 222

(Whether a conservative banking system is preferable to an active entrepreneurially minded banking system)."

Back बाख के शब्दों मे

"आर्थिक विकास बहुत सी बातो पर निर्भर होता है और मुख्यतः वह विनियोजन की दर पर निर्भर है. अगर मौद्रिक नीति से विनीयोजन प्रोत्साहित होता है तो विकास होगा और अगर विनियोजन हतोत्साहित होता है तो विकास रुकेगा कम ब्याज की दर से विकास मे सहायता मिलती है क्योंकि इससे विनियोजन और रोजगार में वृद्धि होती है अगर किसी देश मे बेरोजगारी के वृद्धि की प्रवृत्ति हो तो कम ब्याज की दर निश्चित ही समृद्धि तथा विकास में सहायक होते हैं. अगर देश मे पहले ही पूर्ण रोजगार है तो ब्याज की दर को गिराने से केवल मुद्रा स्फीति फैलती है मँहगाई फिर विकास का मूल्य (दड) बन जाती है और अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति मे ब्याज की दर अधिक रखी जाए तो विकास रुक जाता है ... There is the danger of too much or too little in monetary policy "

IV विकास और मौद्रिक व राजकोषीय नीति

वैसे तो मौद्रिक व राजकोषीय नीतियाँ एक दूसरे की पूरक है, परन्तु विकास वर्धक नीति के रूप में राजकोषीय नीति का मौद्रिक नीति के मुकाबले मे अधिक प्रभाव पडता है मुद्रा स्फीति के दिनों मे हम या तो कर बढा सकते है (जिससे व्यय कम हो) या हम ब्याज की दर को बढा सकते है व्यवहार मे कर बढाने के प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण पाए गए है मदी के काल मे भी ब्याज की दर के घटाने से सार्वजनिक व्यय बढाने व कर घटाने की नीतियाँ अधिक महत्वपूर्ण पाई गई है. फिर भी वास्तव मे दोनो नीतियो को एक साथ कार्यान्वित करने के अधिक प्रभाव होते है.

मीयर तथा बाल्डविन, बेन्जामिन हिगिन्स, एलन, बुखानन, कोलबर्ज, बोल्डिंग, हेबरलर सब ही यह मानते है कि जब तक कि राजकोषीय नीति और मजदूरी नीति का मौद्रिक नीति से समन्वय नही होता तब तक मौद्रिक नीति प्रभावशील नही हो सकती मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण है परन्तु एलन, बुखानन तथा कोलबर्ज का कथन है :

"सफल मौद्रिक नीति कुछ नियमो पर आधारित है, एक आधुनिक मौद्रिक नीति को बनाने मे कठिनाई यह है कि उसके नियमो पर सहमति नही है और मौद्रिक नीति को कार्यान्वित करने मे कठिनाई यह है कि लोग तत्सम्बन्धित नियमो का पालन नही करते है."

इन सबका अर्थ यह नही है कि मौद्रिक नीति बिल्कुल महत्वहीन है

प्रो. बेन्जामिन हिगिन्स के अनुसार

"जहाँ राजनैतिक कारणो से उचित राजस्व नीति नही अपनाई जा सकती, वहाँ मौद्रिक नीति सफल हो सकती है"

Hansen का भी कथन है :

"In conjunction with fiscal and other policies, monetary policy can play a significant role in helping to bring the economy through more stable conditions"

भाग 2

I. कम-विकसित देशो के विकास के लिए मौद्रिक नीति की विशेषताएँ

कम-विकसित देश व्यापार चक्रो से पीडित नही होते वरन् वे तो चिरकालीन पिछडेपन से पीडित रहते है. इसलिए इन देशो मे मौद्रिक नीति का लक्ष्य केवल आर्थिक स्थायित्व करना ही नही होता वरन् विकास को प्रोत्साहन देना होता है. इसलिए कम-विकसित देशों मे मौद्रिक नीति को निम्नलिखित लक्ष्यो की पूर्ति करना चाहिए.

1. देश में बचतों को प्रोत्साहन : बचतो को सस्थागत किया जाना चाहिए :

कम-विकसित देशो मे बचतें तो कम है ही, साथ ही इन बचतो का अधिकाश भाग लोग अपने ही पास रखते है या फिर सोने, चाँदी एव जमीन खरीदने मे लगा देते है एक दृष्टिकोण से इस प्रकार से बचत करना व्यक्तिगत हित के लिए ठीक है इस प्रकार उनकी बचतों का वास्तविक मूल्य मुद्रा स्फीति के काल में भी नही गिरता, बल्कि बढता है. पर इस प्रकार की बचतो से समाज को लाभ नही होता, इन्ही बचतो को जब बैंको, बीमा कम्पनियो व राज्य के ऋण पत्रो मे

Hansen : op. cit. p 162.

लगाया जाए तो देश मे इन बचतो को पूंजी निर्माण के काम में लाया जा सकता है. इसलिए कम-विकसित देशो में इन सस्थाओ का विकास किया जाना चाहिए

दूसरी आवश्यक बात यह है कि जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ व छूट देकर इन बचतो का सस्थायीकरण कराना चाहिए इसके लिए यह देखना आवश्यक होगा कि जनता का धन सुरक्षित रहता है, केन्द्रीय बैंक को यह देखना चाहिए कि देश की मौद्रिक सस्थाएँ फेल तो नही होती. भारत मे जो जमा बीमा योजना (इसके अन्तर्गत बैंक, बीमा किस्त चुकाते है और अगर बैंक 'फेल' हो जाए तो जो जमा करनेवालो को धन बीमा कम्पनी देती है.) है वैसी हर कम-विकसित देश मे होना चाहिए

2. मौद्रिक नीति को पूंजी निर्माण में सहायक होना चाहिए. क्या इसके लिए मुद्रा स्फीति की नीति आवश्यक है ?

जैसा कि हम सब जानते है कि कम-विकसित देशों मे जनता राज्य से हर कार्य की अपेक्षा करती है वह अच्छी सडकें, स्कूल, कालेज, अस्पताल आदि चाहती है परन्तु उतनी मात्रा म साधन राज्य के हाथों मे, करों व ऋणो के माध्यम से, नही देती. परिणाम यह होता है कि राज्य को केन्द्रीय बैंक से उधार लेकर मुद्रा स्फीति के द्वारा पूंजी निर्माण करता व कराना पडता है

हनसेन, काल्डार तथा हेमिल्टन आदि अर्थशास्त्री इस प्रकार की मौद्रिक नीति चाहते है जिससे हीनार्थप्रबन्धन करके देश मे थोडी मुद्रा स्फीति फैलाकर, उत्पादनकर्ताओ को लाभ पहुँचाकर, पूजी निर्माण किया जाए, इनका कथन है कि बाद में जब उत्पादन बढने लगेगा तो मूल्य फिर गिर जायेंगे, पर पूंजी निर्माण से देश उन्नति की राह पर चल निकलेगा वे पूंजी निर्माण के लिए Mild inflation (थोडी मुद्रा स्फीति) चाहते है और उनका विचार है कि इस प्रकार की स्फीति Self-Liquidating (स्वय समाप्त होने वाली) होगी

इस प्रकार की नीति की बहुत आलोचना की जाती है मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार है

(i) इससे देश की गरीबी पर बहुत भार पडेगा और आर्थिक उन्नति से उन्हें लाभ के स्थान पर हानि होगी

(ii) भिन्न-भिन्न देशो ने जो यह नीति अपनाई थी, उनके अलग-अलग कारण थे, जैसे इगलैंड अपने अधीनस्थ देशो से सस्ता कच्चा माल व

---

1 आप पूंजी निर्माण सबधी अध्याय मे इस सबध मे पढ ही चुके है

खाद्य-सामग्री प्राप्त कर लेता था रूस में सरकारी अकुश था तथा अमेरिका मे उस समय विदेशी पूजी काफी मात्रा मे प्राप्त थी

(iii) मुद्रा स्फीति से, एरिक लिण्डहाल Eric Lindhall के अनुसार, एक ओर तो ऋण लेने वाले अधिक ऋण लेते है क्योंकि उन्हे बाद मे जब ऋण वापस करना पडता है तो उसका वास्तविक मूल्य कम होता है और दूसरी ओर देशवासी अपने धन को सोना चादी व जमीन के खरीदने मे लगाकर और मुद्रा स्फीति बढा देते है

(iv) इसके अतिरिक्त प्राचार्य पी सी. मलहोत्रा के शब्दो में, "Mild inflation is like small pregnancy" अर्थात् थोडी मुद्रा स्फीति "थोडे मे गर्भाधान" की भांति है—अर्थात् वह तो पूर्ण रूप से विकसित होगी ही.

(v) मुद्रा स्फीति से निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होगे, जिससे भुगतान की स्थिति और बिगडेगी.

(vi) मुद्रा स्फीति मे राज्य के भी व्यय बढ जाते है और राज्य को अधिक कर लगाने पडेगे या और मुद्रा स्फीति बढेगी

David Felix डेविड फेलिक्स ने भी इसी प्रकार कहा है

> "स्पेन मे पिछले 200 वर्षों मे मूल्य वृद्धि के काल में लाभ वृद्धि बहुत कम रही है. फ्रान्स में लाभ वृद्धि मूल्य वृद्धि के बगैर होती रही इगलैड मे कम लाभ स्फीति के साथ-साथ ही आर्थिक उन्नति हुई है. इस प्रकार से मुद्रा के कारण लाभ स्फीति होना और आर्थिक उन्नति होना आवश्यक नही है"

मोयर तथा बाल्डविन भी इस नीति के विपक्ष मे है उनका कथन है

> "साख वृद्धि पर आधारित मुद्रा स्फीति से बचतें या तो बढती ही नही है या फिर बहुत कम बढती है और अगर हम मुद्रा स्फीति के दुष्प्रभावो को ध्यान मे रखें तो हम कह सकते है कि यह रीति सर्वथा

अन्य आंकडों के लिए पूजी निर्माण सबधी अध्याय देखिए .

Principal P. C. Malhotra : A remark in seminar on "Price Mechanism and Development" at Bhopal, in May 1967.

David Felix, Price Inflation & Industrial Growth, the Historic Record & Contemporary Analogies. The Quarterly Journal of Economics, August, 1956, P 444.

गल्त व अवाछनीय है. बहुत से देशो के अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि केवल साख वृद्धि से ही विनियोजन नही बढ जाता है. शायद मुद्रा स्फीति के न होने से ज्यादा विनियोजन हो सकता है."

Haberler हेबरलर भी इसी प्रकार से कहते है :

"दीर्घकाल में मुद्रा स्फीति से विकास रुक जाती है हमारे युग में मुद्रा स्फीति से पूंजी निर्माण का बहुत ही अधिक दुरुपयोग हुआ है और यह दुरुपयोग विशेषतया कम-विकसित देशो में अधिक हुआ है."

जी. एम बर्नस्टीन तथा **आई. जी. पटेल** ने इसीलिए यह विचार व्यक्त किया है कि मुद्रा स्फीति के दुष्परिणाम अधिक होते हैं. उन्होने कहा है :

"गहन विश्लेषण के बाद हम कह सकते है कि निरन्तर मूल्य वृद्धि का उत्तरदायित्व गलत मौद्रिक नीति पर डाल सकते है. मुद्रा स्फीति मौद्रिक घटना है (Phenomenon) और मौद्रिक नियत्रण से ही दूर की जा सकती है"

उपरोक्त कथन के सबध मे अर्थशास्त्रियो मे मतभेद है. कुछ अर्थशास्त्री कहते है कि मूल्य वृद्धि के कुछ 'वास्तविक कारण" होते है (जैसे वस्तुओ की कमी) (Inflation is a real 'Phenomenon'. Such economists are known as structuralists.) इन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन व पूर्ति का बेलोचदार होना है. मौद्रिक व राजस्व नीतियाँ तो मूल्य वृद्धि में केवल सहायक हो सकती है.

मूल्य वृद्धि का कारण कुछ भी हो, मूल्य वृद्धि व विकास में कोई निश्चित् सबध नही होता. जैसे

(i) भारत व लका मे काफी समय से मूल्य स्थिरता रही पर उन दिनो मे आर्थिक उन्नति कम ही रही. जबकि,
(ii) बर्मा मे मूल्यो की स्थिरता के साथ आर्थिक उन्नति हुई.
(iii) मेक्सिको, ब्राजील व टर्की में मूल्य वृद्धि के होते हुए भी आर्थिक उन्नति हुई. तथा,

---

1. Meier & Baldwin : Economic Development. Asia 1962 p 401
2. Haberler : op cit. (as in this chapter).
3. G. M Bernstien & G. M Patel : Inflation in Relation to Economic Development' International monetary fund staff Papers, Vol II No. 3 Nov. 1952 p. 363-98.

(iv) चिली, इन्डोनेशिया, बोलिविया व अर्जेन्टाइना में मूल्य वृद्धि के साथ आर्थिक उन्नति नहीं हुई.

निष्कर्ष :

इस संबंध मे हम इतना ही कह सकते है कि मौद्रिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि इसके प्रयोग से मुद्रा स्फीति के बगैर ही पूँजी निर्माण होना चाहिए. मुद्रा स्फीति के साथ न तो विकास सुनिश्चित है और न ही असभव है. केन्द्रीय मौद्रिक संस्थाओ का मुख्य कर्तव्य यह है कि वे देश मे व्यक्तियो या संस्थाओ का सम्पर्क स्थापित करें. मियर व बाल्डविन का कथन है :

> 'देश मे मुद्रा पूर्ति उस अनुपात मे होना चाहिए जिस अनुपात मे देश मे जनसख्या मे वृद्धि हो रही हो तथा जिस अनुपात मे अमुद्रा क्षेत्र से (From non-monetized sector मुद्रा क्षेत्र मे (monetized) साधनों का हस्तान्तरण किया जाता है."

Kindleberger ने इसीलिए कहा है·

> "हमें यह नही सोचना चाहिए कि मौद्रिक नीति के माध्यम से हम विकास की शाही सडक पर पहुँच सकते है. विवेक से कार्य करने पर सहायता अवश्य मिलती है."

3. देश में साख का "सामाजीकरण व प्रजातान्त्रीयकरण" करना चाहिए :

इन देशो मे यह आवश्यक है कि बैंको द्वारा साख निर्माण का लाभ छोटे व्यापारी, किसान, उद्योगपति व उपभोक्ताओ को भी पहुँचना चाहिए जैसा कि **प्रो. बोल्डिंग** का मत है . कम-विकसित देशो में किसान व छोटे व्यापारी "ऋण की गुलामी" (Debt slavery) से पीडित हैं और यह अन्यायपूर्ण है. अगर साख का लाभ सबको प्राप्त हो सके तो इससे साख का "सामाजीकरण व प्रजातान्त्रीय-करण" होगा (The Government through democratization of credit can bring about deproletarianization of the masses, through its monetary policy.)

पर इस नीति मे एक बुराई भी उत्पन्न हो सकती है. अगर साख का "प्रजातान्त्रीयकरण" बहुत अधिक हो जाए तो ऐसे लोग भी उधार ले सकते है जो बाद मे ऋण चुकाने योग्य न हो, इसलिए साख निर्माण का कार्य कम धनी व्यक्तियो के लिए सुलभ होने के साथ साथ सुरक्षित भी होना चाहिए

Kindleberger : op. cit, p. 229-240.

4. केन्द्रीय "बैंकिंग कला" का पूर्ण विकास होना चाहिए :

कम-विकसित देशो में केन्द्रीय बैंको की स्थापना भी काफी देर मे हुई हैं. पर अभी भी बहुत से देशो मे केन्द्रीय बैंक की तक्नीक पूर्ण-विकसित नही हो पाई हैं. Henry wallich के अनुसार

> "आज की परिस्थितियो मे कम-विकसित देशो मे केन्द्रीय बैंक मुद्रा नियन्त्रण के स्थान पर साख निर्माण व मुद्रा स्फीति का कारण बनकर रह जाते है."

केन्द्रीय बैंको को चाहिए कि देश के अमौद्रिक क्षेत्र को समाप्त करें जब मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हो तो बैंक दर बढ़ा कर, खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ बेचकर, अथवा चयनात्मक साख नियत्रण से रोकें. अगर देश में मदी है तो केन्द्रीय बैंक, बैंक दर घटाए, खुले बाजार मे प्रतिभूतियाँ खरीदें और साख नियत्रण के प्रतिबध हटालें.

5 मौद्रिक नीति को विदेशी विनिमय दर में स्थायित्व लाने में सहायता देना चाहिए :

हम सबको विदित है कि कम विकसित देशो मे निर्यात से आयात अधिक रहते हैं. इन देशो मे पूँजी या मशीन के आयात अत्यन्त आवश्यक होते है और इससे विदेशी विनिमय की स्थिति और गम्भीर हो जाती है विदेशी मुद्रा की माँग की अधिकता से विनिमय दर विपक्ष मे जाती है, जिससे देश की हानि होती है, तथा मुद्रा व्यापार में सट्टा होता है.

उचित मौद्रिक नीति का तकाजा यह है कि जब कभी भी निर्यात अधिक हो तो विदेशी मुद्रा को संचित करें. आयात पर कडा नियत्रण हो यह भी उचित होगा कि राज्य विदेशी विनिमय व्यापार अपने हाथ मे ले ले. लेकिन निर्यात बढाने के लिए देश में मुद्रा अपस्फीति की नीति नही अपनाना चाहिए. इस सबध में उचित मुद्रा नीति के साथ-साथ उचित राजस्व नीति भी आवश्यक है.

6. मौद्रिक नीति को दीर्घकालीन विनियोजन में सहायता देना चाहिए :

विकास विनियोजन का ही प्रतिफल होता है साख के बगैर विनियोजन सम्भव नही होता देश मे मौद्रिक सस्थाओं को स्थापित होना चाहिए जो अल्प व दीर्घ, कम व अधिक, तथा विभिन्न क्षेत्रो को उचित ब्याज दर पर उधार दे सकें. इसके

Boulding : op. cit.

Henry wallich : Monetary Problems of an Export Economy Harvard University Press, Cambridge 1950 p. 284.

लिए केन्द्रीय बैंक से पुनर्भुनाने की सुविधा (Rediscounting facilities) व्यापारिक बैको को प्रदान करना चाहिए

7. मौद्रिक नीति "सतुलित" होना चाहिए :

कम विकसित देशो मे ब्याज की दर न तो कम और न बहुत अधिक होना चाहिए थोडी ऊँची ब्याज की दर बचतो को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक होगी, परन्तु बहुत अधिक ऊँची होने से विनियोजन हतोत्साहित होगा उधर कम ब्याज दर से राज्य का ऋण भार तो कम रहेगा परन्तु इससे बचते कम रहेगी.

कम विकसित देशो में सफल आयोजन व आर्थिक उन्नति के लिए देश मे सचालित पत्र मुद्रा का मान होना चाहिए और मुद्रा की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि देश मे न तो मुद्रा स्फीति रहे और न मुद्रा विस्फीति

कम-विकसित देशो मे मौद्रिक नीति क्या होना चाहिए यह तो हर देश विशेष की परिस्थितियो पर भी निर्भर करता है. हम इस सबध में, निष्कर्ष में, बेन्जामिन हिगिन्स को उद्धृत कर सकते है

> "Under developed Countries may need monetary measures of a sort tailor made for their own institutional framework, but that such measures can be an effective insurance of economic stabilization"
>
> (अर्थात् "कम विकसित देशो को अपनी परिस्थितियो व सस्थाओ के अनुसार नीति बनानी होगी (Tailor made) अर्थात सिले सिलाए कपडो की भाँति "रेडी मेड" नही वरन् नाप देकर बनाए हुए कपडे की भाँति)

II. कम-विकसित देशो मे मौद्रिक नीति की सीमाएँ

जब हम यह देख चुके है कि मौद्रिक नीति विकसित देशो मे भी पूर्ण रूप से प्रभावशील नही होती, तो कम-विकसित देशो मे उसके पूर्ण रूप से प्रभावशील होने का प्रश्न ही नही उठता. कम विकसित देशो में मौद्रिक नीति के पूर्ण रूप से प्रभावशील न होने के कई कारण है, जिनमे से मुख्य कारणो का उल्लेख नीचे किया गया है

1 सर्वप्रथम सीमा तो यह होती है कि इन देशो मे मुद्रा बाजार कम-विकसित होते है. "भारत में ही अनुमानतया 35% राष्ट्रीय आय मौद्रिक सौदा के

क्षेत्र से बाहर है. मौद्रिक क्षेत्र मे भी लगभग 50% उधार पूँजी सगठित मुद्रा बाजार से प्राप्त होती है और शेप 50% गैर बैंकिग सस्थाओ से प्राप्त होती है"

2. दूसरे इन देशो मे साख मुद्रा से अधिक 'चलन' मुद्रा महत्वपूर्ण होती है इस कारण साख नियत्रण के उपायो से मुख्य मुद्रा चलन पर प्रभाव नही पडता.
3. इन देशो मे बैंक दर बढाने से भी साख सकुचन नही हो पाता, क्योकि विदेशी बैंक इन देशो के केन्द्रीय बैंको से उधार लेने के स्थान पर अपने विदेशी मुख्यालय से धन मँगा लेते है. इधर देश के व्यापारिक बैंक भी केन्द्रीय बैंक के ऊपर आश्रित नही होते क्योकि ब्याज की दर बढने से बैको के पास जमा राशि बढ जाती है. इस कारण वे अपनी साख का निर्माण का कार्य पूर्ववत् रख सकते है
4. इसी प्रकार से खुले बाजार की नीति भी साख निर्माण बढाने या सकुचन करने मे अधिक सफल नही होती इसका कारण यह होता है कि इन देशो मे राज्य की प्रतिभूतियो का बाजार अधिक विकसित नही होता. राज्य की प्रतिभूतिया पर औसतन 4 या 5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है जबकि व्यापारिक सस्थानो की प्रतिभूतियो पर ब्याज की दर 8 से 12 प्रतिशत तक होती है. इससे व्यापारिक बैंक इन प्रतिभूतियो में व्यापार करते है और केन्द्रीय बैंक की खुले बाजार नीतियो का प्रभाव कम पडता है.
5. इसी प्रकार से केन्द्रीय बैंक के द्वारा 'न्यूनतम कोप सीमा' बढाने से भी साख संकुचन नही होता. कम-विकसित दशो में बैंकिग के बहुत से सौदे नगद होते है इस कारण बैंक इस न्यूनतम सीमा से कही अधिक नगद कोप रखते है और अगर केन्द्रीय बैंक यह जमा सीमा बढाता है तो उसके लिए साख सकुचन नही करना पडता
6. श्री एच० वी० आर० आएग्यार H V. R Iengar ने जो भारत के रिजर्व बैंक के भूतपूर्व डायरेक्टर रहे है, कम-विकसित देशो मे विकास बढाने मे मौद्रिक नीति की सीमाओ का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है. उनके विचारो को नीचे व्यक्त किया जा रहा है .

> "इसमे कोई शक नही है कि मौद्रिक नीति प्रशासको का विकास मे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, फिर भी उनके महत्व को बढा चढाकर

See : H. V. R. Iengar Monetary Policy & Economic Growth p 46 & p 136.

प्रस्तुत नही करना चाहिए. किसी भी प्रकार की मौद्रिक नीति खाद्यान्न उत्पादन नही बढा सकती. इसी प्रकार से मौद्रिक नीति का उन समाजद्रोही तत्वो, जो कि काला बाजार, व सट्टा व जमाखोरी करते है उन पर कोई प्रभाव नही पडता. मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति को इतना रखें कि न्यून पूर्ति वस्तुओ पर माँग का दबाव कम बना रहे. साख नियत्रण ऐसे कठोर नही होना चाहिए कि इससे उत्पादन मे रुकावट हो या बाजार के व्यापक होने मे बाधाएँ आएँ.

माँग पर मौद्रिक भार पडने से बचने के लिए केन्द्रीय बैंक चयनात्मक व सामान्य साख नियत्रण पद्धति अपना सकता है. परन्तु मौद्रिक नीति पूर्ति की कमी को दूर नही कर सकती परन्तु सटोरियो और जमा-खोरो को साख सुविधा बन्द कराकर केन्द्रीय बैंक उचित कार्य कर सकता है. यहाँ पर कठिनाई यह है कि यह व्यक्ति गैर-बैंकिग सस्थाओं से उधार लेते हैं यह आवश्यक है कि और गैर-बैंकिग सस्थाएँ केन्द्रीय बैंकिग के नियत्रण में आयें "

अध्याय : 6

विकास व राजकोषीय नीति

Role of Fiscal Policy for Economic Development

or

Fiscal Policy and Economic Development

I प्रस्तावना

विकसित देशों के लिए राजकोषीय नीति

Functional Finance (क्रियात्मक वित्त) Counter or anti-cyclical finance (चक्रविरोधी नीति) या compensatory finance (क्षति-पूर्ति नीति)

1. मंदीकाल · घाटे का बजट व उसकी तीन रीतियाँ
2. तेजीकाल :

   चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रीतियाँ.

   Built-in flexibility, formula flexibility, discretionary action.

II कम विकसित देशो के लिए राजकोषीय नीति

II : A. आय नीति :

II A (a) कर नीति के उद्देश्य अर्थशास्त्रियो के दृष्टिकोण से ·

1. पूँजी निर्माण का उद्देश्य
2 उपभोग कम, बचतें, विनियोजन तथा उत्पादन के लिए प्रेरणा
3 विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन, विदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहन.
4. मुद्रा स्फीति नियन्त्रण
5. समानता लाने का लक्ष्य.
6 देश में, कर व्यवस्था में समन्वय तथा अन्य नीतियों से समन्वय
7. भ्रष्टाचार रोकना व प्रशासनिक सुधार

मीयर तथा बाल्डविन, किन्डलबरजर, आर०एन० भार्गव व आर०एन० त्रिपाठी के विचार [1]

II : A (b) कम-विकसित देशो मे भिन्न-भिन्न करो का स्वभाव व सापेक्षिक सरचना कैसी हो

कृषि पर कर, आय कर व कम्पनी कर, सम्पत्ति कर, उत्तराधिकार कर, पूंजी लाभ कर, उपहार कर, उत्पादन कर, बिक्री कर, आयात व निर्यात कर, लाभ पर कर, विदेशी विनियोजको पर कर आदि की विकास के लिए क्या संरचना हो.

II : A. (c) करो की अधिकता विकास के लिए घातक

II : B कम-विकसित देशो के लिए सार्वजनिक व्यय नीति व विकास

II : C. कम-विकसित देशो मे ऋण व्यवस्था सबधी नीति व विकास

1. अन्य अर्थशास्त्रियो के विचारो की समालोचना नही की गई क्योकि इन्ही विचारो को दूसरे शब्दो में व्यक्त करना पडता.

अध्याय : 6

विकास व राजकोषीय नीति

Role of Fiscal Policy for Economic Development

or

Fiscal Policy and Economic Development

I. प्रस्तावना

राजकोषीय नीति के अन्तर्गत बजट की वे समस्त क्रियायें आती हैं, जिनके अन्तर्गत राज्य के द्वारा धन इकट्ठा करना, खर्च करना, ऋण लेना और चुकाना, तथा वित्तीय प्रबन्धन करना शामिल है पहले इस नीति को Public finance policy राजस्व नीति कहते थे परन्तु इसका आधुनिक नाम Fiscal policy राजकोषीय नीति है

इसी प्रकार से वित्तीय नीति (financial policy) तथा राजकोषीय नीति के उद्देश्यों मे अन्तर होता है वित्तीय नीति के अन्तर्गत हम राज्य का आय इकट्ठा करने एव खर्च करना अध्ययन करते हैं राजकोषीय नीति के अन्तर्गत राज्य का आय संचित करना व व्यय करना भी किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है उदाहरणत सडक निर्माण कार्य इसलिए किया जाता है कि एक सडक की आवश्यकता है (यह वित्तीय नीति के अन्तर्गत कार्य हुआ) परन्तु जब सडक का निर्माण इसलिए भी किया जाता है कि इससे देश मे रोजगार व आय मे भी वृद्धि हो, तो यह राजकोषीय नीति का उद्देश्य हुआ [1]

विकसित देशो के लिए राजकोषीय नीति :

विकसित देशो मे राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य मदी को रोकना है. राजकोषीय नीति का प्रयोग तेज़ी व मदी के चक्रा के दुष्प्रभावो को रोकना है. पुराने अर्थशास्त्री आर्थिक मदीको दूर करने के लिए मौद्रिक नीति का प्रयोग करने के पत्त में थे.

1. Allen, Buchanan & Colberg : Prices, Income & Public Policy : ch. 191.

Hawtrey हाट्रे का तो यहाँ तक विश्वास था कि केवल अल्पकालीन ब्याज की दरो मे परिवर्तन कर के ही मदी एव तेजीकाल पर नियन्त्रण पाया जा सकता है. परन्तु 1930 की महान मदी ने मौद्रिक नीति द्वारा मदी व बेरोजगारी को दूर करने मे प्रभावहीनता साबित कर दी. महान मदी के बाद केन्स (Keynes) हनसेन (Hansen) तथा लेरनर (Lerner) जैसे प्रभावशील अर्थशास्त्रियो ने राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण बताया. तब से आजतक राजकोषीय नीति विकसित देशो मे चक्रविरोधी नीति के रूप मे प्रयोग होती है.

• Functional finance (क्रियात्मक वित्त) Counter or Anti-cyclical finance (चक्रविरोधी नीति) या Compensatory finance (क्षति-पूर्ति वित्तीय नीति) :

1. मंदीकाल :

मदीकाल मे, जैसा कि सर्वविदित है, मूल्य गिरते है जिससे उत्पादनकर्ताओ को हानि होती है, उत्पादन कम होता, मजदूरो की छटनी होती है, रोजगार वृद्धि के अवसर कम होते है, मजदूरी की दरें गिरती है, विनियोजन कम होता है, राज्य की आय गिरती है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय गिरती है जो व्यक्ति रोजगार मे लगे रहते है उनकी वास्तविक आय तो बढ जाती है परन्तु पारिवारिक आय, बेरोजगारी के कारण, गिर जाती है विकसित देशो में यह मदी मुख्यत प्रभावशील माँग की कमी, अर्थात् उपभोग में सापेक्षिक कमी तथा बचतो मे सापेक्षिक वृद्धि हो जाती है मदी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक रूप से, बचतो को घटाना व उपभोग बढाना लक्ष्य रहता है, तथा देश मे घाटे का बजट बनाकर देश मे अतिरिक्त मुद्रा पहुँचा कर मूल्यो मे वृद्धि करना होता है

घाटे का बजट तीन रूप से प्रस्तुत हो सकता है :

पहली रीति है कि खर्च बढा दिए जाएँ एव आय उतनी ही रखी जाए और अतिरिक्त व्यय को नये नोट छापकर पूरा किया जाए **दूसरी रीति** है कि खर्च उतना ही रखा जाए परन्तु करो को घटा दिया जाए और यह घाटा भी नये नोट छापकर पूरा कर लिया जाए **तीसरी रीति** है कि सतुलित बजट के गुणक प्रभाव द्वारा मदी का सामना किया जाए

पहली रीति :

यह रीति यह है कि राज्य अपने विनियोजन एवं राहत कार्यो पर व्यय बढाए. बेरोजगारी का मुआवजा दे, उपभोक्ताओ को बोनस दे, किसानो को गिरते मूल्यो की क्षति पूर्ति करे या मुआवजा दे. (to give price support) परन्तु

अपनी आय को उसी स्तर पर रखे इस नीति के कई लाभ है, जैसे मदी के दिनो में चीजे सस्ती होने के कारण राज्य को विनियोजन करना भी सस्ता पड़ता है (real cost of public expenditure is pess), दूसरे जनता को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य उत्पादन वृद्धि के कार्य मे आगे आकर वास्तव में मदी को दूर करने के लिए कटिबद्ध है परन्तु इस नीति को अगर बहुत अधिक कार्यान्वित किया गया तो निजी क्षेत्र के विनियोजको को यह भय भी हो सकता है कि राज्य उनसे प्रतियोगिता करने लगा है और इस कारण वे हतोत्साहित हो सकते है

दूसरी रीति :

राज्य यह भी कर सकता है कि करो को कम कर दे तथा कर सबधी ऐसी छूटें दे जिससे उत्पादन बढे. अगर राज्य ऐसी वस्तुओ के कर मे कमी करे जिनकी माँग लोचदार है तो इससे देश म प्रभावशील माँग बढेगी स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था मे ऐसी नीति को प्रथम नीति से अधिक पसद किया जाता है दूसरे यह खर्च बढाने के कार्य से अधिक सरल है और शीघ्र किया जा सकता है

इस नीति की प्रमुख बुराई यह है कि इससे धन की असमानताएँ बढती है.

उचित नीति तो यह होगी कि कुछ मात्रा मे तो कर कम किए जाएँ तथा कुछ मात्रा मे व्यय बढाए जाएँ वास्तव मे दोनो नीतियो का उचित समिश्रण उचित होगा

तीसरी रीति :

यह एक दिलचस्प विचार है कुछ अर्थशास्त्रियो का कथन है कि सतुलित बजट से भी गुणक प्रभावो द्वारा मदी दूर होने मे सहायता मिलती है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते है

माना कि एक देशवासी औसतन अपनी आय का 4/5 भाग उपभोग करते है अर्थात् 1/5 बचत करते है तब इस देश मे गुणक 5 होगा, (Multiplier will be 5) अर्थात् राज्य जो 100 रुपये खर्च करेगा उसके बाद 400 रुपए और खर्च होकर कुल 500 खर्च होगे राज्य के 100 रु० खर्च करने से कुल 500 रु० के बराबर प्रभावशील माँग बढती है

राज्य 100 रु० व्यय करने के लिए 100 रु० के कर लगाएगा कर लगाने से लोग 80 रु० तो उपभोग कम करके देंगे (उपभोगक्षमता 4/5 है) और 20 रु० बचतो मे से देंगे. कुल उपभोग $80 \times 5 = 400$ रु० का कम होगा इस प्रकार से समाज मे फिर भी समाज को 100 रु० की मुद्रा के बराबर प्रभावशील माँग बढ जाएगी

देश मे उपभोग क्षमता अधिक होने से Balanced budget multiplier अधिक होगा

इस नीति या विचार मे यह कमी है कि 100 रु० की आय खर्च करने को 100 रु० से अधिक के कर लगते हैं करो के इकट्ठा खर्च व सार्वजनिक व्यय करने मे भी तो व्यय होगा

घाटा किस प्रकार से पूरा किया जाए ?

राज्य घाटे को या तो नए नोट छाप कर पूरा कर सकता है, या व्यापारिक वैको से उधार लेकर पूरा कर सकता ह या फिर जनता से उधार लेकर पूरा कर सकता है

(1) राज्य अगर नए नोट छाप कर घाटे को पूरा करता है (अर्थात् केन्द्रीय वैंक से उधार लेकर) तो इससे देश मे मुद्रा प्रसार बढेगा. मुद्रा की मात्रा बढने से ब्याज की दर घटेगी और निजी विनियोजन प्रोत्साहित होगा

(ii) अगर यह घाटा साधारण वैको से उधार लेकर परा किया जाएगा तो राज्य द्वारा उधारी की माँग से ब्याज की दर बढेगी और निजी विनियोजन प्रोत्साहित नही होगा

(iii) जनता से उधार लेकर घाटा पूरा करना इसी प्रकार से उचित नही होगा क्योंकि जनता राज्य को ऋण देने के लिए वैको से ऋण लेगी और इससे वैंको के कोष कम होंगे और साख निर्माण कम होगा यह नीति आजकल प्रचलित रीतियो की मान्यताओ से भिन्न है **आजकल राज्य मन्दी के दिनो में ऋण लौटाती है, लेती नही है.**

2 तेजी दूर करने को

मुद्रास्फीतिकाल मे मदीकाल का उल्टा होना चाहिए, अर्थात् इसमे अधिक का बजट बनता है (Surplus budget) अधिक का बजट या तो करो की मात्रा व्यय से अधिक करके या करो के वर्तमान स्तर से उससे व्यय की मात्रा घटाकर बनाया जा सकता है राज्य को ऐसे करो को बढाना चाहिए जिनसे उपभोग कम हो, अर्थात् लोचदार माँग वाली विलासिताओ पर कर लगाना चाहिए.

See :

1. Boulding . Principles of Economic Policy. p. 147 Fg
2. Taylor : Public finance chs. 4, 5, 6.
3. Ganguly : Public finance p 80-90.

and other standard works on Public Finance.

तेजीकाल में राज्य को ऋण लेना चाहिए. इस काल में अनिवार्य बचत योजनाएँ चलाई जा सकती हैं. आय कमाने के बाद तात्कालिक कर काटा जा सकता है. Tax deduction at source

चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की रीतियां :

चक्रविरोधी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की तीन रीतियां हैं. ये तीन रीतियाँ हैं.

(i) Built-in Flexibility स्वय उत्पन्न होती रहने वाली लोचकता :

यह वह व्यवस्था है जिसमे बगैर कर की या व्यय की दरो मे परिवर्तन किए या बगैर कोई सवैधानिक कदम उठाये स्वय ही स्वय चक्र विरोधी वित्तीय व्यवस्था हो जाती है अर्थात् जब देश मे मुद्रा फैलती है तो करो से आय स्वय बढ जाती है, और व्यय स्वय कम हो जाते हैं, यह उस समय होता है जबकि देश की कर व्यवस्था अत्यन्त प्रगतिशील हो जब मूल्य वृद्धि होती है तो लोग स्वय ही ऊँचे आय स्तर पर पहुँच जाते हैं, अधिक विलासिताओं का प्रयोग करते हैं तथा स्वय ही अधिक कर चुकाते हैं उधर किसानो को Price support subsidies (मूल्य गिरने की क्षतिपूर्ति) या बेरोजगारो को मुआवजा जैसे व्यय कम हो जाते हैं. जब मदी आती है तो व्यय बढ जाता है और लोगो की आय कम होने से आय भी कम हो जाती है

(ii) Formula Flexibility · सूत्रीय लोचकता :

किसी भी देश में कर व्यवस्था इतनी पूर्ण रूपेण लचीली नही होती कि स्वय वित्तीय व्यवस्था में मुद्रा स्फीति या विस्फीति को ठीक करने की क्षमता हो इसके लिए राज्य किसी निश्चित योजना व आधार पर करो व व्ययो की दरो मे परिवर्तन करता है. तेजी काल में दरों को बढा दिया जाता है और मदी काल मे घटा दी जाती है

(iii) Discretionary Action · इच्छानुसार परिवर्तन :

इस नीति के अन्तर्गत समय एव परिस्थितियों के अनुसार ही वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, परिवर्तन के प्रकार एव परिवर्तनो की मात्रा परिस्थिति के अनुसार ही निश्चित की जाती है.

सारांश :

"राजकोषीय नीति के दो पहलू होते हैं : सख्यात्मक व गुणात्मक सख्यात्मक पहलू के अन्तर्गत हम यह सोचते हैं कि कितनी मात्रा में

खर्च करें एवं कर लव इस बात पर ही देश की आर्थिक उन्नति निर्भर करती है दूसरा पहलू है कि कितना व्यय किन पर करे व किनसे कितना कर लें इस बात पर स्थिरता न्याय व स्वतन्त्रता निर्भर रहती है आर्थिक उन्नति व स्थिरता, न्याय व स्वतन्त्रता यही चार वित्तीय नीति के लक्ष्य हैं ' (बोल्डिंग)

II कम विकसित एवं विकासशील देशों के लिए राजकोषीय नीति

विकासशील देशो के लिए चक्रविरोधी या क्षति पूर्ति राजकोषीय नीति का उतना महत्व नही है क्योकि यहा पर उन्नत देशो की भांति व्यापार चक्र नही आते तथा इन देशो में तेजी या मन्दी आन्तरिक मूल्य स्तर म परिवर्तन से उतनी नहीं आती

References —

1 Meier & Baldwin op cit p 390-398
2 B Higgins op cit chs 20 21, 22 23, and 24
3 Raja Chelliah Fiscal policy in under developed countries
4 R N Tripathi Fiscal Policy and Economic Development in India
5 Nurkse op cit 140-150
6 U N Report on Methods of Financing Economic Development in under developed countries '
7 Lewis op cit p 396-408
8 U N Taxation and Fiscal policy in under developed countries
9 Kurihara The keynesian Theory of Economic Development op cit ch ix
10 D S Nag Problems of Under developed Economy p 219-232
11 Taxation Enquiry Commission Govt of India 1953 54
12 H C Wallich & J H Adler Public Finance in Developing country
13 C P kindleberger op cit p 240 247
14 W A Lewis The Theory of Economic Growth ch vii
15 R N Bhargava Federal Finance & Tax Policy and Economic Development Eastern Economist Feb 23, 1968
16 N kaldor The Role of Taxation in Economic Development ch 8 Williamson & Buttrick op cit
17 B R Shenoy Tax Structure and its Effects on Savings & Growth Eastern Economist March 8 1968

जितनी की आयातीत एव निर्यातीत वस्तुओं के मूल्यों मे परिवर्तन के कारण आती हैं

जैसा कि हम जानते हैं कि राजकोषीय नीति के अन्तर्गत (i) राजकीय आय (ii) राजकीय व्यय (iii) ऋण व्यवस्था तथा हीनार्थप्रबन्धन तथा (iv) बजट प्रशासन आता है. हम अब यह देखेंगे कि कम विकसित देशों के विकास के लिए तत्सम्बन्धी नीतियाँ क्या होनी चाहिए.

II A कम-विकसित देशों के विकास के लिए सार्वजनिक आय (विशेषरूप से कर) नीतिया

कम-विकसित देशों मे विकास की मुख्य समस्या बचतों, पूँजी निर्माण, विनियोजन रोजगार, राष्ट्रीय आय (उत्पादन व उत्पादकता) प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करना है. इस सम्बन्ध मे कर नीति का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है.

Ragner Nurkse. रैगनर नर्क्स ने इस सम्बन्ध में कहा है कि :

> 'कर वास्तव मे राज्य द्वारा जनता की ओर से, की गई सामूहिक बचतें हैं"

उनका कथन है कि

> "पूंजी निर्माण के दो तत्व होते हैं—बचत एव विनियोजन ये दोनों मितव्ययिता और साहस पर निर्भर करते हैं. कोई कारण नहीं कि निजी साहस' के साथ (With private enterprise system) जनता से करो द्वारा यह 'सामूहिक बचतें' कराई जाएँ कि राज्य जितना व्यय बढाये उतनी ही मात्रा मे कर ले ले. इस रीति से, फिर भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी."

II A (a) Economists on Fiscal Policy for Development Meier and Baldwin :

मीयर व बाल्डविन के अनुसार कम-विकसित देशों मे राजकोषीय नीति का व्यापक व प्रभावशाली प्रयोग विकास के लिए अत्यावश्यक है. राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा उसके लिए आय इकट्ठा करने के कार्य से विकास दर पर चार महत्वपूर्ण प्रभाव पड सकते हैं

(i) इससे साधनो का वितरण (allocation) प्रभावित होता है

(ii) इससे धन के वितरण मे परिवर्तन होता है.

Meier & Baldwin : op cit.

(iii) इससे पूँजी निर्माण मे वृद्धि होती है, तथा

(iv) मुद्रा स्फीति नियंत्रित की जा सकती है.

1. राज्य अपने सार्वजनिक व्यय द्वारा (Subsidies included) जहाँ वह चाहता है उद्योगो को स्थापना करा सकता है तथा अधिक व विभेद पूर्ण करो द्वारा उद्योगों को (जिनकी Social corts अधिक हो) हतोत्साहित कर सकता है. इस प्रकार देश मे विनियोजन को इस प्रकार से करा सकता है कि देश मे सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप विनियोजन हो
2. राज्य के प्रगतिशील करो तथा प्रगतिशील सार्वजनिक व्ययो (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरो को प्रदान करके) देश में धन व सम्पत्ति की असमानताएँ दूर कर सकता है इससे विकास के लाभो का न्यायोचित वितरण हो जाता है.
3. राजकोषीय नीति मे पूँजी निर्माण प्रभावित करना अधिक महत्वपूर्ण होता है. पूँजी निर्माण के लिए बचते या तो (i) निजी बचतों से, (ii) साख निर्माण मे, (iii) विदेश से या (iv) राज्य द्वारा आय व ऋण से प्राप्त हो सकती हैं. अल्पकाल मे प्रथम तीन साधनो से बचतें अपेक्षित मात्रा में नही बढाई जा सकती इसलिए राज्य के लिये राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण होती है.

इसलिए राज्य या तो कर बढाता है या फिर हीनार्थप्रबन्धन करता है. **मीयर तथा बाल्डविन** हीनार्थप्रबन्धन से पूँजी निर्माण के पक्ष मे नही हैं. उनका कथन है कि यहाँ के बाजारो की अपूर्णता, कृषि उपज का बेलोच होना, उपभोग क्षमता का अधिक होने से हीनार्थप्रबन्धन से पूँजी निर्माण के लाभदायक परिणाम नही होगे. इसलिए राज्य को करो में वृद्धि कर के सामूहिक बचतो द्वारा पूँजी निर्माण करना चाहिए. इससे उपभोग कम होगे तथा उनके स्थान पर राज्य द्वारा पूँजी निर्माण होगा. या राज्य इस धन को बैंको मे पहुँचा सकता है (अपने ऋण चुका कर) जिससे वे साख निर्माण कर सकते हैं और निजी पूँजी निर्माण में सहायता दे सकते हैं. मीयर तथा बाल्डविन के शब्दो मे :

> "The over-all concern of the Government's fiscal policy should be directed towards maximising savings, mobilizing them for productive investment, and *canalizing them into* directions that will best serve the objectives of a balanced development programme."

करो के सम्बन्ध मे ये अर्थशास्त्री चाहते है कि

(i) कम-विकसित देशो मे करदेय क्षमता व आधार का विस्तार किया जाए.

(ii) कर प्रशासन योग्य व अच्छा बनाया जाए.

(iii) राज्य प्रतिभूतियो के बाजार को विस्तृत किया जाए.

(iv) देश मे विभिन्न प्रकार के करो का चयन व उनकी सरचना ऐसी होना चाहिये कि देश की कर व्यवस्था मे न्याय, समानता, सरलता व उत्पादन बढाने के गुण बने रहें

(v) देश मे, आय मे वृद्धि तथा प्रेरणा को बनाए रखने के लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए.

(vi) मदी के काल मे घाटे व तेजी या मुद्रा स्फीति के काल में अधिक का बजट बनाना चाहिए.

देश मे कर व्यवस्था में राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यो को प्राप्त करने की क्षमता होना चाहिए

राज्य की राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य इन देशो मे मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित रखना भी है, जैसा कि विकसित देशो में मदी को दूर करना होता है.

C. P. Kindleberger ·

किन्डलबरजर भी कम विकसित देशो मे राज्य की आय व्यवस्था को पूँजी निर्माण का महत्वपूर्ण साधन बनाने की सलाह देते है. निजी बचतो के कम होने, विदेशो से पूँजी न मिलने, पूँजी बाजार के विकसित न होने, तथा सार्वजनिक व्यय को कम न रख सकने की अवस्था मे पूंजी निर्माण केवल राज्य द्वारा करो की मात्रा को बढाने से ही सभव होगा

विकसित देशो मे हमारा ध्यान Ability to pay पर जाता है जबकि कम विकसित देशो मे मुख्य प्रश्न यह है कि क्या राज्य मे Ability to tax है ? इन देशो मे करो को जहाँ उपभोग, विलासिता उपभोग तथा गैर जरूरी व अनुत्पादक विनियोजन रोकना चाहिए. वहाँ कर व्यवस्था को पूजी निर्माण करने, लाभ कमाने तथा उनको पुन विनियोजित करने में सहायक होना चाहिए. इसलिए

> "These considerations imply a tax programme heavily weighted on the side of consumption and against imposts on income."

1. op cit : p. 392. Ragner Nurkse का भी यही मत है .
   "The two components of capital formation, saving and investment, depend on thrift and enterprise; there is nothing to prevent collective thrift from being combined with individual enterprise" . op cit. p. 151.

C. P. Kindleberger : op. cit : p 240-6 : मुद्रास्फीति पर Kindleberger के विचार "मौद्रिक नीति" अध्याय में भी दिए गए है.

किन्डलबरजर चाहते है कि कम विकसित देश भूमि व उस पर बढ़ती आय पर पर्याप्त मात्रा में कर लगाएँ. विदेशी विनियोजकों पर भी पर्याप्त मात्रा में कर लगाना चाहिए परन्तु इतना नही कि वे पुनर्विनियोजन ही न करे.

हीनार्थ-प्रबन्धन, मुद्रा स्फीति व राजकोषीय नीति :

किन्डलबरजर यह मानते हैं कि कम विकसित देशों को पूंजी निर्माण करने तथा आवश्यक बाह्यमितव्ययिताओं का सृजन करने के लिए हीनार्थप्रबन्धन करना ही पड़ेगा पर इसको यथासम्भव नियन्त्रित रखना चाहिए. कम-विकसित देशों में राजकोषीय नीति का मुद्रा स्फीति नियन्त्रण करने मे प्रभावशीलता कम रहती है मुद्रा स्फीति कम करने के लिए या तो व्यय को कम करें या भारी मात्रा में कर लगाए परन्तु कम विकसित देशों मे राजनैतिक तथा प्रशासनिक कारणों से सभव नहीं हो पाता. Kindleberger के शब्दो में

> "In this circumstance inflation, like the working girl who has slipped, is more to be pitied than scorned .... . An under-developed country with luck or virtue can avoid inflation; but it needs more of either or both than a developed country."

Dr. R. N. Bhargava .

डा० भार्गव, जो भारत में राजकोषीय समस्याओं पर विशेषज्ञ हैं, के अनुसार विकास के लिए कर नीति में निम्नलिखित मुख्य तत्व होना चाहिए.

श्री शेनाय भी चाहते हैं कि कम-विकसित देश मुद्रा-स्फीति को राजकोषीय नीति का अंग न बनाएँ. उनके शब्दों में :

> "Inflation eats into savings through shifting incomes from the masses and wage earners into the pockets of residual income groups when the level of living is already low, consumption being largely limited to necessaries of life, these income shifts cannot be met by cuts in Consumption on the part of the victims of inflation cuts in Consumption would be resisted, or savings will decline Inflation in a back ground of poverty would, thus, be a net debit on national savings. op cit.

Dr. R. N. Bhargava : op. cit.

1. राज्य को, कर नीति को साधनों के जुटाने व विकास क्रियाओं को कार्यान्वित करने हेतु धन प्राप्त करने का मुख्य अंग बनाना चाहिए. अगर करों से पर्याप्त आय न हुई तो हीनार्थप्रबन्धन करना पड़ेगा जिससे मुद्रा स्फीति फैलेगी, जिससे बचतें कम होगी, उनका मूल्य कम होगा तथा राज्य की करों द्वारा इकट्ठी आय का वास्तविक मूल्य कम होगा. इसलिए Non inflationary measures से या मुद्रा स्फीति न फैलाने वाली रीति से आय प्राप्त करना चाहिए

2. Incentive Taxation कम-विकसित देशों में कर नीति का लक्ष्य समानता लाना होता है और यह लक्ष्य भी होता कि देश में बचतें तथा विनियोजन न केवल हतोत्साहित हो वरन् प्रोत्साहित हो. ये दोनों लक्ष्य आपस में विरोधाभासी हैं. इनको प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी पड़ेंगी. समानता के पीछे हमको विनियोजकों को हतोत्साहित नही करना चाहिए. निर्यातवर्धन, पुनर्विनियोजन तथा विदेशी पूँजी या तकनीकी जानकारी लाने के लिए कर सम्बन्धी छूटें देना चाहिए

3. Co-ordination कम विकसित देशो मे केन्द्रीय व राज्य सरकारों की कर नीतियो मे समन्वय होना चाहिए समन्वय का यह अर्थ नही है कि राज्यों की सरकारें केन्द्र के एकदम अधीन हो

   यह आवश्यक है कि कर, मूल्य, आय व तटकर नीतियो म पूर्ण समन्वय हो कर नीति से समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों मे समानता आती है, परन्तु हीनार्थप्रबन्धन से मूल्यों का स्तर विकृत हो जाता है हीनार्थप्रबन्धन के फलस्वरूप जो मुद्रा स्फीति होती है उससे सामाजिक अन्याय होता है कम आय पानेवाले तथा निश्चित आय पानेवाले हानि उठाते है कमजोर मूल्य नीति से विवेकपूर्ण कर नीति विकृत हो जाती है (Thus a weak price policy distorts a sensible tax policy)

4. Administration कम-विकसित देशो मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो का *प्रशासन बहुधा अकर्मण्य व भ्रष्ट होते है इससे कर वचन बहुत होता है* बहुत हद तक बहुत ऊँची प्रत्यक्ष कर की दरें इसके लिए उत्तरदायी है एक सीमा के बाद भारत म ही प्रत्यक्ष कर शत-प्रतिशत से भी अधिक हैं. इतने अधिक कर इसीलिए बर्दाश्त किये जाते है कि इनसे वचन हो सकता है. इससे देश में अन्य लोग भी भ्रष्ट रीतियाँ अपनाने को उत्सुक होते है.

किन्ही किन्ही कम-विकसित देशों मे करो की सरचना इतनी जटिल है कि कर विशेषज्ञो को भी परेशानी हो जाती है, कर विशेषज्ञ N Kaldor ने भारतीय कम्पनी कर व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था

> "The company taxation provisions of India... are apt to strike a detached observer as a perfect maze of un-necessary complications, the accretion of years of futile endeavour to reconcile fundamentally contradictory objectives."

कम विकसित देशों मे कर सरचना न केवल जटिल रहती है वरन् बार-बार बदलती रहती है हर वित्तमन्त्री अपनी इच्छा के अनुसार (कुछ नाम कमाने की इच्छा से) हर वर्ष अनावश्यक परिवर्तन करता रहता है. यह इन देशों मे विनियोजन *आयोजन के लिए अत्यन्त दुविधाजनक स्थिति पैदा करती है. श्री भार्गव के अनुसार ·*

> "It is necessary that a tax policy to be successful must be stable, consistent and certain, this will help investment and enterprise so vital in a developing economy."

Dr. R. N. Tripathy

कम-विकसित देशों को अपने विकास आयोजन को सफल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा मे धन चाहिये इसको हम आन्तरिक व बाह्य दोनो साधनो से प्राप्त करते है. अन्तरिक साधनो में यह धन हम

(i) करो मे वृद्धि व नए कर लगाकर.
(ii) मुद्रा स्फीति विहीन ऋण-व्यवस्था से तथा-
(iii) हीनार्थप्रबन्धन से प्राप्त करते है.

डॉ० त्रिपाठी का कथन है कि .

> "कम विकसित देश उपभोग कम करके ही बचत कर सकेंगे, भले ही इन देशो मे उपभोग के स्तर पहले से ही नीचे क्यो न हो. इसलिए अनावश्यक विनियोजन व उपभोग पर अधिक कर लगाना ही पड़ेगा."

See also : ch. 8 : The Role of Taxation in Economic Development
N. Kaldor : I. E. A. op cit.
R. N. Tripathy : op cit.

कर नीति के दो पहलू होते हैं पहला Static स्थैगिक पहलू तथा दूसरा Dynamic या प्रवैगिक पहलू. कम विकसित देशो मे कर नीति का पहला पहलू तो यह है कि वे उपभोग को न बढने दे और दूसरा पहलू यह है कि जब विकास से उत्पादन बढे तो बढे हुए उत्पादन मे से अधिकाधिक भाग विनियोजन के लिए प्राप्त करें.

श्री त्रिपाठी यह नही चाहते कि यह बढी हुई आय निजी विनियोजकों के पास ही पुनर्विनियोजन के लिए छोड दें. उनका कथन है कि वास्तव मे विकास के लिए कम विकसित देशो मे पहले सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करनी पडेगी और इसलिए करो मे वृद्धि आवश्यक होगी ही. उनके शब्दो मे

> "Tax policy in a developing country as an instrument of development finance for the public sector has to be geared effectively to the taxation of non-entrepreneurial incomes, providing at the same time adequate incentive to the private sector undertaking useful production and essential investment."

अपनी ऋण लेने की नीति को सफल बनाने के लिए राज्य को वित्तीय बाजार का संगठन करना होगा. ग्रामीण क्षेत्रों मे अच्छी ब्याज की दर पर बाँट लेना पडेगा. कम-विकसित देशो मे हीनार्थप्रबन्धन को पूर्ण रूप से लागू नही किया जा सकता है. हीनार्थप्रबन्धन की मुद्रा स्फीति कारक नीति से बचने के लिए जल्दी उत्पादन करने वाली योजनाओ को, जिनमे श्रम गहन तकनीक के प्रयोग की अधिकता हो, कार्यान्वित करना चाहिए. परन्तु हीनार्थप्रबन्धन को मुद्रा स्फीति नही फैलाने देना चाहिए अन्यथा गरीबों पर भार पडेगा, मजदूरी स्तर बढने से लागत व पुन मूल्य बढेगे, विदेशी विनिमय सबधी कठिनाइयाँ बढेंगी, सट्टेबाजी बढेगी व ठोस विनियोजन हतोत्साहित होगे, बचतें व उनका मूल्य कम होगा और विकास पर बुरा प्रभाव पडेगा.

विकासशील देश मे केन्द्र व राज्य की नीतियो मे समन्वय होना चाहिए.

II A(b) कम-विकसित देशो मे भिन्न-भिन्न करो का स्वभाव व सापेक्षिक सरचना कैसी हो

कृषि पर कर :

कम-विकसित देशो मे अधिकाश राष्ट्रीय आय कृषि क्षेत्र से आती है और इसमें

देश की अधिकाश जनता कार्यरत होती है. प्रति व्यक्ति आय के कम होने के कारण इस क्षेत्र पर कर का भार शहरी क्षेत्र से कम होगा. कृषि क्षेत्र के व्यक्ति, लगान, कृषि आय कर के रूप मे प्रत्यक्ष कर देते हैं और अपने द्वारा उपभोग की जाने वाले वस्तुओ पर अप्रत्यक्ष कर देते हैं

अधिकाश कम-विकसित देशो में भू-राजस्व या लगान खेतो को आकार के अनुसार लिया जाता हैं इसलिए यह काफी बेलोचदार होता है क्योकि मूल्य व उत्पादकता वृद्धि के अनुसार यह नही बढता. कृषको की अशिक्षा तथा सदियो से उनका जमीदारो के "दास" के रूप मे रहने से वे कठोरता व भ्रष्टाचार के शिकार रहे है.

कम-विकसित देशो मे विभिन्न क्षेत्रो या राज्यो में भू-राजस्व की दरो मे व आधारो मे समानता लाई जानी चाहिए. तथा लगान को उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओ, मूल्य परिवर्तन आदि के अनुसार करके उसे लोचदार बनाना चाहिए.

कालान्तर मे लगान को कृषि कर के रूप में बदल देना चाहिए. आधुनिक युग में राज्य सरकारो कृषि को उन्नत करने के लिए बहुत विनियोजन किया है और इससे कृषि मे उन्नति होती है. मूल्यो के सबध में क्षतिपूर्ति सहायता दी गई है. (Price support) इसलिए कृषको पर भी कर लगाना चाहिए. उदाहरणत 1967-68 में ही भारत मे कृषको को 1000 करोड रुपयो की अतिरिक्त आय हुई. परन्तु करो के उतने ही रहने से उन पर कर का भार घट गया आज भारत के 75% लोग गाँवो मे रहते है, परन्तु वे कुल करो का 15% भाग देते है, और 25% जनता जो शहरो में रहती है वह 85% कर देती है. देश की राष्ट्रीय आय का 48% भाग कृषि से आता है पर कुल उपज का 1% ही कृषि से कर के रूप मे आता है. 1951 स कृषि करो की आय राष्ट्रीय आय के 4% से बढकर 5% हुई पर अकृषि करो का भाग राष्ट्रीय आय का 9% से बढ़कर 14% हो गया

1. कृषि कर व्यवस्था में कृषको को बाढ, सूखा, कीडो आदि से हानि के दिनो में कर सबधी छूटें दी जाना चाहिए.
2. कृषि भूमि के सट्टात्मक व्यापार को रोकने के लिए कडे कर लगाना चाहिए Capital gains tax अर्थात् पूँजीगत मूल्य बढने पर कर.
3. जिन खेतो पर खेती न की जाती हो. (जिसको केवल समय आने पर बेचने के उद्देश्य से रख छोड़ा हो) उन पर भी कर लगाना चाहिए.

देखिए : O. S. Shrivastava द्वारा लिखित अध्याय 22, "मुद्रा बैंकिंग... ...राजस्व" कैलाश पुस्तक सदन, 1969.

4. कृषि क्षेत्र में लगे करो को जहाँ वहाँ कि बचतों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए वहाँ यह भी देखना है कि इससे विनियोजन करना कठिन तो नहीं हो जाता है.

> "जापान ने कृषि करो को उन्नत कृषि के लाभ से राज्य ने भी अच्छा हिस्सा लिया, तथा वहाँ के कृषको ने करो को चुकाने के लिए और अधिक मेहनत की."

आय कर तथा कम्पनी कर :

कम-विकसित देशो में गरीबी है तथा धन की असमानताएँ है. इसलिए आय करो को इस प्रकार का होना चाहिए कि ये असमानताएँ कम तो हो परन्तु साहसियों को उत्पादन वृद्धि मे बाधा न आये. कम-विकसित देशो में बहुधा कर की दरो को बढा कर आय बढाने की प्रवृत्ति होती है इससे अधिक आवश्यकता कर का आधार (Tax base) या कर देने वालो को सख्या बढाना है. कम-विकसित देशों में अधिकाश जनता द्वारा हिसाब किताब न रखने, बैंको का प्रयोग कम करने, अशिक्षा व भ्रष्टाचार के कारण जनता कर का दायित्व ईमानदारी से नही चुकाती.

भारत के भूतपूर्व वित्तमत्री श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने एक बार कहा था

> "अगर भारत में वे सब व्यक्ति जिन्हे कर चुकाना चाहिए. कर चुका दें, तो करो की मात्रा आधी की जा सकती है."

इसलिए विकास के लिए करो की दरो में वृद्धि के बजाय कर प्रशासन को सुधारना तथा कर का आधार बढाना अधिक महत्वपूर्ण होगा. देश में मौद्रिक क्षेत्र में वृद्धि से भी इस सम्बन्ध में आय बढेगी.

कम विकसित देशो मे उत्पादन व विनियोजन वृद्धि की प्रेरणा बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत व कम्पनी कर इतने अधिक नही होना चाहिए कि बचत व पूँजी निर्माण ही रुक जाए नये उद्योगो को शुरू के कुछ वर्षो के लिए कर से छूट देना चाहिए, तथा उद्योगों मे उन्नति व नवीनीकरण में पर्याप्त मात्रा मे घिसावट का प्राविधान करने की अनुमति होना चाहिए

गैर कमाई आय पर अधिक कर : सम्पत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, तथा पूंजी-लाभ कर, उपहार कर :

कम-विकसित देशो मे गैर कमाई आय पर करो की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इस प्रकार की आय बहुधा विलासिताओ के दिखावटी उपभोग, सट्टे, पूँजी को

W. W. Lockeword : Economic Development of Japan.

इधर-उधर भेजते रहने, जमाखोरी के काम मे लाया जाता है इसमे देश मे मुद्रा स्फीति ही अधिक फैलती है Harvey Leibenstein इसी प्रकार के कार्यो को जैसा कि हम पढ चुके है, Zero-sum enterprises कहते है.

इस प्रकार से ब्याज पर रुपया उधार देकर सूदखोरी करने वाले, जमाखोर व पूँजीगत वस्तुओं के सट्टे करने वालो पर अधिक कर लगाना चाहिए.

कम-विकसित देशो मे मृत्यु कर (उत्तराधिकारी कर) को प्रगतिशील रूप में लगाना चाहिए अन्यथा भावी पीढियाँ स्वय उत्पादक कार्य करने के स्थान पर बैठे-बैठे खाने की क्षमता रखेंगे यह बात देश मे अकर्मण्यता को जन्म देती हैं,[1] कम-विकसित देशो मे बहुधा real estates या सम्पत्ति मे बहुत धन लगा दिया जाता है. जब देश मे इस प्रवृत्ति को रोकना हो तो सम्पत्ति करों को बढा देना चाहिए. अगर सम्पत्ति कल-कारखानों के रूप मे बढाई जा रही है, जहाँ कि उत्पादन होगा तो इनको कर विमुक्त कर सकते है या कम कर लगा सकते है. सम्पत्ति कर आय को असमानताओं को दूर करने का अच्छा साधन भी है

Capital Gains tax : कम-विकसित पेशेवर सम्पत्ति में व्यापार करने वालो (जमीन, मशीन, शेयर, प्रतिभूतियाँ, मकान व अन्य सम्पत्तियो मे व्यापार करने-वाले) पर भी अच्छी तरह कर लगा सकते है. Capital appreciation का अर्थ होता है सम्पत्ति का मूल्य बढ जाना. जैसे कोई 1,00,000 रु० की सम्पत्ति का मूल्य समय के अन्तर से बढकर 3,00,000 हो जाए तो इस प्रकार के काम पर अधिक कर लगाया जा सकता है.

Gift tax कम-विकसित देशो मे आय को बढाने, असमानताओ को कम करने व मृत्युकर से बचन रोकने के लिए देश मे उपहार करों को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए.

कम-विकसित देशो में अप्रत्यक्ष कर : उत्पादन कर, सेल्स टैक्स, आयात निर्यात कर :

कम-विकसित देशो मे अप्रत्यक्ष करो का कुल आय मे महत्व बढता जा रहा है. यू० एस० ए० में आय कर से 78% राज्य की आय प्राप्त होती है, और यू० के तथा जापान मे यह प्रतिशत 57 व 50 है. भारत मे 99% व्यक्ति आयकर नही देने तथा 93% आय पर आयकर नही पड़ता है. भारत में प्रत्यक्ष करो का कुल

---

1. 'साप्ताहिक-हिन्दुस्तान' मे एकबार एक सुन्दर कविता आई थी जो इस प्रकार है .

बडे बाप के बेटे है,
जब से पैदा हुए लेटे है

आय में जहाँ 1950-51 मे योगदान 36% था वहाँ 1968-69 मे वह घट कर 24% हो गया अर्थात् अप्रत्यक्ष करो का योगदान इस काल में 64% से बढकर 76% हो गया

विकास के साथ-साथ प्रत्यक्ष करो का योगदान बढना चाहिए. भारत में ऐसा न होने का मुख्य कारण देश मे कर बचन का होना, तथा लोगो का हिसाव न रखना ही है. इस स्थिति को दूर करना चाहिए.

अप्रत्यक्ष करो मे Excise duties उत्पादन कर, सेल्सटेक्स, आदि कर आते है यह आवश्यक है कि कम-विकसित देश इन करो को लोचदार बनाएँ ताकि आय के साथ इन करो से आय बढ़ती रहे इन करो का मुख्य लक्ष्य देश मे अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग व उत्पादन का कम रखना है ताकि देश मे बचतें हो और उनका प्रयोग ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से हो कि देश मे विकास की नीव पड़े तथा अधिकतम लोगो की अधिकतम आवश्यकताएँ पहले सतुष्ट हो [1] अप्रत्यक्ष करो को प्रगतिशील होना चाहिए, अन्यथा इससे न केवल असमानताएँ बढेंगी वरन् विनियोजन का allocation (वितरण) भी त्रूटि पूर्ण होगा, जो देश के लिए ठीक न होगा

अप्रत्यक्ष करो का लाभ यह है कि इनसे सब वर्गों से आय प्राप्त हो जाती है, परन्तु बहुत ऊँचे अप्रत्यक्ष कर इन देशो मे कठिनाई पैदा कर सकते है. अगर वे अप्रगतिशील है तो उनसे देश मे गरीब वर्गो को कठिनाई होगी और उनका उपभोग कम करने के स्थान पर बचतो को ही कम करेंगे अन्य वस्तुओं पर अधिक मात्रा मे अप्रत्यक्ष करो से देश मे माँग कम होने से उत्पादन हतोत्साहित हो सकता है, इसलिए 'बहुत अधिक' अप्रत्यक्ष कर भी नही होना चाहिए

कम विकसित देशो मे प्रत्यक्ष करो की आय की लोच कम है इस लोच को इकाई तक लाना ही चाहिए ताकि कम-विकसित देशो मे अप्रत्यक्ष करो को इतना अधिक लगाने की मजबूरी न रहे कम-विकसित देशो मे जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढती है उसी अनुपात मे प्रत्यक्ष करो से आय नही बढती श्री जी० एस सहोता के अनुसार भारत मे प्रत्यक्ष करो की लोच 0 674 ही है इसीलिए अप्रत्यक्ष करो को इतना बढाना पड रहा है

अप्रत्यक्ष करो की वृद्धि फिर भी हीनार्थप्रवन्धन के कारण मूल्य वृद्धि से ठीक है.

---

1. George Bernard Shaw ने एक बार कहा था .
   "वह राष्ट्र जो बच्चो के दूध का इन्तजाम करने से पहले शराब उत्पादित करता है वह बेवकूफ राष्ट्र है."

जहाँ तक आयात व निर्यात करो का प्रश्न है, कम विकसित देशो को इन्हे अपने हित के अनुसार रखना चाहिए अधिकाश कम विकसित देश भुगतान असतुलन से पीडित रहते है इसकारण यह आवश्यक होगा कि अनावश्यक तथा विलासिताओ की वस्तुओ पर या तो पूर्ण नियत्रण हो या उन पर अधिक मात्रा मे आयात कर लगाए जाएँ साथ ही इनको चोरी छिपे लाने को रोकने के लिये कठोर प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए. इन देशो मे Demonstration effect imports (विदेशो की विलासिताओ की नकल के लिए आयात)

कम विकसित देशो को आयातीत मशीनो तथा आवश्यक कच्चा माल पर कम आयात कर लगाना चाहिए ताकि औद्योगीकरण मे आसानी हो. आयातीत कच्चे माल से बने सामान को निर्यात करना हो तो आवश्यकतानुसार (अगर वस्तु की विदेश में माँग लोचदार हो) आयात ड्यूटी वापस भी की जा सकती है

निर्यात करो को भी आवश्यकतानुसार निर्धारित करना चाहिए अगर निर्यातीत वस्तुओ की विदेशो में बेलोचदार माग है तो निर्यात कर अधिक रखना चाहिए बहुधा विदेशी आयातकर्ता खरीदारो का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं (Monopsonistic or oligopsonistic combines) और कम-विकसित देशो को कम मूल्य देते हैं कम विकसित देश भी इसी प्रकार के Monopolistic combines एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं लोचदार माँग की वस्तुओ पर निर्यात शुल्क कम रखना चाहिए

लाभ पर कर विदेशी विनियोजको पर कर

लाभ पर कर तथा विदेशी विनियोजको के लाभ के प्रति भी Pragmatic approach या यथासगत नीति अपनाना चाहिए. कम विकसित देशो में पूर्ति की बेलोचपन से मूल्य बढ जाते हैं ऐसे समय मे उत्पादनकर्ता व व्यापारी अधिक लाभ कमा लेते हैं कम विकसित देशो इस प्रकार के 'Excess' profits पर (या 'अतिरिक्त' लाभ पर) अधिक कर लगना चाहिए परन्तु अगर इस अतिरिक्त लाभ को पुन वास्तविक विनियोजन वृद्धि म लगाया जाता है तो फिर उस पर कर सबधी छूट मिलना चाहिए अन्यथा देश मे बचतो व पूँजी निर्माण रुकेगा. भारत म Super profit tax, (अत्यधिक लाभ पर कर) 1 अप्रैल 1963 को बची हुई आय पर (कारपोरेशन कर देने के बाद बची आय पर) 50% दर से लगाया, बशर्ते कि यह आय Paid up जमा पूँजी तथा reserves या जमाकोष से 6% भाग से अधिक हो इसकी दर को इस प्रकार लगाया गया अगर बची हुई आय जमा पूजी व जमाकोष के 10% से अधिक हो तो 60% कर

के रूप मे देना था. वित्तमंत्री ने उस समय आशा व्यक्त की थी कि इससे अत्यधिक लाभ कमाने और मूल्य बढाने की प्रवृत्ति रुकेगी. परन्तु वित्तमत्री ने अपनी भूल अगले ही वर्ष स्वीकार की और यह देखा गया कि इससे औद्योगिक विकास अवरुद्ध हुआ बाद मे इस कर के स्थान पर Surtax on profits of joint stock companies लगाया गया इससे देश में पूँजी आधार मे वृद्धि हुई (Capital base was widened) और कर अधिक न्यायपूर्ण हुआ और कर की दर को भी कम कर दिया गया

प्रो० ल्युस ने भी इसी प्रकार कहा है

> "High taxes on profits will destroy development if the proceeds of the taxes are spent by the state on Current purposes, instead of being saved and invested productively, and if the managerial classes are not rewarded both financially and socially"

इसलिए 'बहुत अधिक' लाभो पर कर लगना चाहिए परन्तु लाभ ही पूँजीनिर्माण का स्त्रोत होते हैं इसलिए लाभ व लाभ कमाने की इच्छा को ही समाप्त कर देना चाहिए

विदेशी कम्पनियों का जहाँ तक प्रश्न है वहाँ हमको यह देखना चाहिए कि उनपर इतना कर न लगे वे अपनी पूँजी वापस ले जाने का सोचे या और पूँजी न लाएँ, परन्तु उन्हे शोषण नही करने देना चाहिए शोषण क्या है, यह तो परिस्थितियो के अनुसार ही जाँचा जा सकता है विदेशी विनियोजक पूँजी लाते हैं, तकनीकी जानकारी लाते है, अपने विश्वव्यापी सम्पर्क से सामान को निर्यात करके विदेशी मुद्रा लाते हैं, इसलिए इन्हें विकास मे सहायता के अवसर देना चाहिए

II A (c) करो की अधिकता-विकास के लिए घातक .

श्री बी. आर. शेनाय करो की अधिकता को विकास के लिए घातक मानते है. श्री शेनाय का कथन हैं कि करो की अधिकता से बचतें घटती हैं और सामाजिक पूंजी निर्माण भी कम हो जाता है राज्य जो धन करो के रूप मे लेता है उसका अधिकाश भाग तो सार्वजनिक उपयोग में व्यर्थ चला जाता है. श्री शेनाय का कथन है कि भारत में ही 1960 61 से अभी तक (1968) सार्वजनिक उद्योगों में पूंजी

1. Dr R N Bhargava : op cit : Eastern Economist, Feb. 23, 1968 W A Lewis : op. cit · p 243.

निर्माण के रूप में सार्वजनिक आय का केवल 3 8% ही प्रयोग में आया. अगर इसी धन को जनता के हाथों में रहने दिया जाता तो कम से कम 25% भाग अवश्य ही पूंजी निर्माण के कार्यों में ले लिया जाता.

इस आधार पर, श्री शेनाय का कथन है, हर 100 करोड रु० के कर लगाने से निजी क्षेत्र की 25% बचतें कम हो जाती है जबकि राज्य मे केवल 3·8 करोड रुपयों का पूंजी निर्माण हो पाता है. इस प्रकार से राज्य के द्वारा 100 करोड रु. की सार्वजनिक आय वृद्धि से 21 करोड रुपयों की बचत की हानि होती है. या अन्य शब्दों में, अगर देश में 100 करोड रु० के कर कम कर दिए जाएँ तो 21 करोड रु० की बचतें समाज में बढ जायेंगी

श्री शेनाय ने हिसाब लगाया कि अगर भारत मे कर 1959 60 के स्तर पर रहते जो निजी क्षेत्र की आय, कर देने के बाद, 9800 करोड रुपयों से अधिक होते और 1966 67 तक हर वर्ष 412 करोड रुपयों का पूंजी निर्माण अधिक होता

> **"अगर किसी भी देश में विकास करना लक्ष्य है तो वह देश समाजवादी कर प्रणाली नहीं अपना सकता."**

भारत मे, श्री शेनाय ने बताया, स्वय 1961, 13 मार्च को भारत के वित्तमंत्री ने राज्य सभा में स्वीकार किया था कि भारत मे "15 या 20% व्यक्ति अपनी आय का 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) करो मे दे रहे है" यह शोषणात्मक कर प्रणाली भारत के विकास के लिए घातक है. एक कम-विकसित देश स्वय स्फूर्ति की अवस्था मे इस प्रकार के करो से कभी नही पहुँच सकती

भारत में उच्चतम कर की सीमान्त दरें नार्वे, स्वीडन व यू० के० भी ज्यादा है और जर्मनी तथा यू एस. ए से तो कही ज्यादा है.

पश्चिमी जर्मनी[1] मे जो आर्थिक क्रान्ति आई है उसका मुख्य कारण करो की कमी रही है उसके मुख्य कारण 'राज्य द्वारा व्ययों में कमी", '50% से करो का अधिक न होना" तथा "करो में भिन्न-भिन्न प्रकार की छूटें देना है" प्रो. शेनाय का कथन है कि अगर कम-विकसित देशो मे विकास के लिए विनियोजन को प्रोत्साहन देना है तो व्यक्तिश कर व कम्पनी करो को बहुत कम रखना चाहिए

---

1. Palkhiwala : *op. cit.* इसी कारण को "Most Taxed Nation in the world" कहते हैं.
2. B. R. Shenoy : op cit.

प्रो. एफ ए. हायेक भी बहुत प्रगतिशील करो को विकास मे बाधक मानते हैं. श्री शेनाय का कथन है कि प्रगतिशील करो से उत्पादन हतोत्साहित होता है तथा बचतें व पूंजी निर्माण कम होते है, साहसियों और व्यापारियो की प्रेरणा कम होती है, उनकी आगे की उन्नति रुक जाती हैं प्रगतिशील कर कर्मण्यता, कार्यक्षमता, मेहनत, लगान तथा समृद्धि पर कर हैं श्री शेनाय के शब्दो मे

> "Progressive taxation is a tax on initiative, talent and efficiency. It penalises successful entrepreneurs It violates the basic doctrine of equality of all before the law. It amounts to paying progressively less for more work by men of the highest productivity .... It checks capital formation. deprives the society of the full production progressive taxation stifles dynamism of vertical mobility."

श्री शेनाय तथा अन्य अर्थशास्त्री एक सीमा के बाद समानुपातिक कर चाहते हैं तथा वे चाहते है कि राज्य सुरक्षा, न्याय, व्यवस्था, मुद्रा चलन, आधारभूत यातायात, सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन तथा कृषि सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त हर क्षेत्र से धीरे धीरे निकल जाए.

II. B : कम-विकसित देशों के लिए सार्वजनिक व्यय करने की नीति व विकास

आज के युग मे सार्वजनिक व्ययो की मात्रा व क्षेत्र दोनो में वृद्धि हो रही है. आज समस्त राज्यो में, चाहे वहाँ केन्द्रीय सत्ता प्रणाली हो या विकेन्द्रीय सत्ता प्रणाली हो, चाहे वह छोटा राज्य हो या बडा, चाहे वहाँ शान्तिप्रिय सरकार हो या युद्ध-

1 देखिये

(i) Ludwing Erhard "Prosperity through competition" London 1960 p. 19-24.

(ii) Lawrence Festing "One Exports Almost Ruined Germany" In 'Freeman', August, 1961.

(iii) अन्य वे अर्थशास्त्री जो प्रगतिशील करो के खिलाफ है J. S. Mill (Jr.). Blum, Kalven, Milton Friedman, F. A. Hayek. H. L. Lutz, Lord Lionel Robbins and David Mc Cord Wright.

प्रिय, बढते हुए सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति निश्चित रूप से मौजूद रहती है. दुर्भाग्य से आज कम विकसित देशो में सुरक्षा व्ययो के बढने की प्रगति बढ रही है. आज के युग मे कम-विकसित देशो मे प्राकृतिक साधनो के सर्वेक्षण तथा अधिकाधिक प्रयोग, उत्पादन क्षमता बढाने पर (जैसे कारखाने स्थापित करना, *जगल लगवाना, भूरक्षण बजर जमीन पाटना, बाढ नियन्त्रण, सामाजिक व आर्थिक* सिरोपरी सुविधाओ के विस्तार (यातायात व सचार के साधनो में विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास) तथा आधारभूत उद्योगो तथा Public utilities सुविधाओ मे व्यय करना पडता है. राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों म नियंत्रण कार्य भी वढ गए है.

कम विकसित देशो मे इन्ही व्ययो की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण ही अधिकाधिक कर लगाये जाते है. विकास मे सार्वजनिक व्ययो का प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण है. सार्वजनिक व्ययों से निजी उत्पादनकर्ताओं व विनियोजको को जो सामाजिक व आर्थिक सिरोपरी सुविधाएँ प्राप्त होती है उनसे न केवल निजी क्षेत्र का विनियोजन बढता है वरन् वे स्वय बचतें बढाकर पूँजी निर्माण करते है. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पेन्शन आदि पर व्यय से देश की उत्पादन शक्ति का विकास होता है. सार्वजनिक व्यय से पूँजी निर्माण बढता है और इसके बढने से जो निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, उससे देश में कुल विनियोजन वृद्धि से देश मे रोज़गार बढता है. सार्वजनिक व्यय से वास्तव में देश की कार्य करने व बचत करने की योग्यता में वृद्धि होती है. राज्य के सार्वजनिक से बचत व विनियोजन मे समन्वय आता है. पिछड़े वर्गों व पिछडे क्षेत्रो को अनुदान देकर देश मे विकास का असतुलन दूर होता है और सतुलित विकास होता है

राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण, सिचाई सुविधाओ की वृद्धि, सुरक्षा, प्राकृतिक साधनो का विकास, अनुसधान, तथा सचार के साधनों के विकास से समाज में उत्पादन व उत्पादकता, विनियोजन तथा रोजगार, राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि होती है. **सार्वजनिक व्यय का महत्व हम इस बात से तब अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब कि हम यह विचार करें कि अगर राज्य यह सब व्यय न करता तो क्या स्थिति होती.**

सार्वजनिक व्यय से हम व्यापार चक्रो की हानियों से बचते है तथा इससे समाज में वितरण की समानता आती है और हम समाजवाद के निकट आते है. सार्व-

Dalton : Public Finance ch. XVIII.

जनिक व्यय से हम नियोजित तथा नियन्त्रित पूँजीवाद लाते है और देश में गरीबो के लाभ के लिए नियन्त्रण लाकर सामाजिक कल्याण बढाते है.

कभी-कभी राज्य के सार्वजनिक व्यय के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. अनियमित व्यय से मुद्रा स्फीति हो सकती है, फिर कर का भार बढता है. देश में बहुधा लाभ में न चलने वाले उद्योगों की स्थापना हो जाती है. भ्रष्टाचार के कारण राज्य का बहुत धन गबन होने लगता है और जैसे पानी मे मछली को पानी पीने से नही रोक पाते. वैसे ही यह भ्रष्टाचार नही रुक पाता. सामाजिक सुरक्षा का व्यय जहाँ अच्छा है वहाँ कार्य करने और बचत की इच्छा को कम भी कर सकता है. राज्य के व्यय का क्या प्रभाव पडेगा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा, निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा की प्रतियोगी वस्तु या पूरक वस्तु है. अगर राज्य की वस्तु प्रतियोगी वस्तु है तो निजी क्षेत्र मे उत्पादन कम होगा और अगर वह पूरक है तो उत्पादन कार्य बढेगा. कभी-कभी तो एक व्यय किसी का पूरक व किसी का प्रतियोगी व्यय हो जाता है. उदाहरणतः राज्य द्वारा पुलिस के कार्यों पर किये जाने वाले व्यय से तालो के उत्पादनकर्ताओ को हानी होती है पर इससे निजी सम्पत्ति सचित करना लाभदायक सिद्ध हो जाता है. उसी प्रकार से अच्छी सडको से जहाँ कार खरीदकर रखना कम खर्चीला हो जाता है वहाँ टायर के उत्पादनकर्ताओ को हानि होती है.

प्रो. यूगो पापी ने इसलिए कहा है

> "अधिक सार्वजनिक व्यय के लिए अधिक कर लगाने पडते है इससे देश में बचत व पूँजी निर्माण पर बुरा प्रभाव पडता है अत्यधिक सार्वजनिक व्यय से उन वस्तुओ की माँग उत्पन्न हो जाती है, जो पैदा ही नही हुई है"

See also :

1. Musgrave · op cit : p. 251-56.
2. Taylor : op. cit : p. 68-71.
3. Keynes : op. cit.
4. U. Hicks : Public Finance ch. II.
5. Lutz : Public Finance p. 164-7.
6. Brownlee & Allen : Economics of Public Finance pt. III. ch. 10.
7. G. Ugo Papi, "Internal Faction Causing and Propagating Inflation from I. E. A. "Inflation."
8. प्रो० एस० श्रीवास्तव : "मुद्रा .....सांख्यिकी" अध्याय 5, 6, 7.

सार्वजनिक व्यय संबन्धी नीति :

सार्वजनिक व्यय सबधी नीति ऐसी होनी चाहिए जो प्रगतिशील हो, अर्थात् गरीब लोगों को अधिक लाभकारी हो, इसे आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने तथा जनशक्ति की किस्म सुधारने मे व्यय करना चाहिए राज्य को उन्ही क्षेत्रो मे व्यय करना चाहिए जहाँ निजी क्षेत्र वाले व्यक्ति व्यय नही करते. आधुनिक युग में जनसख्या नियत्रण या परिवार नियोजन इसका अच्छा उदाहरण है व्यय को दूरदर्शिता, वृद्धिमत्ता, चतुराई, विचार तथा विवेक पूर्णरूप से खर्च करना चाहिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी, रोजगार व ट्रेनिंग वृद्धि, असमानताओं को दूर करने सबन्धी व्यय विकासवर्द्धक होंगे

सबसे मुख्य बात यह होना चाहिए कि राज्य के सार्वजनिक उद्योग लाभ पर चलें, अन्यथा ऐसे उद्योगों की स्थापना ही न की जाए

II C कम-विकसित देशो मे ऋण व्यवस्था सबधी नीति

कम विकसित देशो मे भी, विकसित देशों की भाँति सार्वजनिक ऋण व्यवस्था राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण अग होते हैं और विकास प्रयासो मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं सार्वजनिक ऋण भी आय के साधन है. कम विकसित देशो की सरकारें आधुनिक युग में Pay-as-you go finance (चालू व्ययो) तथा emergency expenditure (सकटकाल के) अतिरिक्त बहुत अधिक मात्रा में उत्पादक कार्यो (direct productive works) तथा सामाजिक व आर्थिक सिरोपरी (Economic and social overheads or external economies) प्रदान करने के लिए ऋण लेती हैं.

इन कार्यों के लिए जब ऋण लिया जाता है तो करो का भार कम रखा जा सकता है. कर देने से करदाताओ की आय कम होती है परन्तु ऋण देने से वे जो बचत करते हैं उसमें स्वेच्छा होती है तथा विकास प्रक्रिया मे जो जनता के सहयोग की आवश्यकता पडती है वह प्राप्त होता है तथा उनसे विरोध नही मिलता

आज कम विकसित देशो मे सामाजिक सुधार कार्यों के लिये भी ऋण लिया जाता है. आज "उत्पादक" शब्द का अर्थ व्यापक है. Musgrave के शब्दों मे

पुराने अर्थशास्त्री सामाजिक सुधार कार्यों के लिए ऋण लेने के खिलाफ थे. बेस्टाविल का कथन था :

> "राष्ट्रीय सस्कृति, शिक्षा तथा सामाजिक उन्नति को बढावा देना आवश्यक है परन्तु इतना आवश्यक नहीं है कि राज्य ऋण लेकर इन्हे बढाए."

"We do not have the cement and steel concept of development" यह अत्यन्त विरोधाभास की बात होगी कि हम शराब के कारखाने से शराब के उत्पादन के कारण इसे 'उत्पादक' समझे तथा शिक्षा प्रसार को उत्पादक न कहे. आज कम-विकसित देश Capital budget पूँजी बचत तथा चालू बजट दोनो के लिए ऋण लेते हैं आज इस विचार को नही माना जाता कि राज्य के ऋण व सम्पत्ति बराबर होना चाहिए, क्योंकि राज्य की "सम्पत्ति" मिल और कारखाना की वृद्धि से ही नही बढती वह तो देश की जनता के उन्नत होने से भी बढती है.

Musgrave ने इसीलिए कहा है

> "While the net-worth approach (assets being equal to debts) might serve to sell businessmen on the idea of unbalanced budgets, this is a point in fiscal politics rather than fiscal economics."

कम-विकसित देशो मे आज ऋणो को उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करने, पूंजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार व सामाजिक व आर्थिक सिरोपरी उत्पन्न करने के लिए लिया जाता है जो कि उचित है विदेशी ऋणो से देश में मशीनें, आवश्यक कच्चा माल, तकनीकी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञो को आयात कर सकते हैं जिससे देश मे उद्योग-विशेष रूप से निर्यात वर्धक तथा आयात प्रतिस्थापक स्थापित किए जा सकते है और देश की बाद मे विदेशी आय बढ सकती है.

इसलिए कम-विकसित देशो में विकास के शुरू के काल में जो अधिक विनियोजन की आवश्यकता पडती है उसका एक भाग ऋण के द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए और दस या पन्द्रह वर्षो के चक्र से सतुलित बजट बनाएँ.

ऋण को वापस करने तथा भार को कम रखने संबधी नीतियां :

कम-विकसित देश ऋण वापस करने की जानी मानी तरीको के यथोचित समिश्रण द्वारा ऋणो को वापस कर सकते हैं अनुत्पादक ऋणो को यथा शीघ्र वापस करना चाहिए और उत्पादक ऋणो को सम्पत्ति के कार्य-काल मे ही वापस कर देना चाहिए. इस सबध मे यह बात ध्यान रखने योग्य है कि ऋण वापस करने

Musgrave . Theory of Public Finance : ch. 23 and 24
Pigon : Fublic Finance ch. VI
Taylor : op cit.

की बहुत जल्दी से अधिकाधिक धन को ऋण परिशोध कोष मे रखा (और रखा रहने दिया) तो इससे मंदी व बेरोजगारी फैलेगी और विकास कार्य आगे नहीं बढ़ सकेगा इसको ऋण कम करने की चिंता से अधिक बेरोजगारी दूर करने व विकास करने की चिन्ता होनी चाहिए

आवश्यकतानुसार राज्य ऋणो को नये ऋणो मे भी परिवर्तित कर सकती है अगर कम-विकसित देशो में आयोजन व विकास के शुरू काल में मुद्रा स्फीति फैलने से व्यापारी वर्ग ने बहुत कमाया हो तथा राज्य उनके लाभा पर पर्याप्त मात्रा मे कर न लगा सका हो तो राज्य यथा समय पूजी कर" लगाकर (Capital levy) भी ऋण चुका सकता है इसमें कर वचन करनेवालो, सट्टो व चोरी से सम्पत्ति बनानेवालो पर यथोचित कर लग जाएगा मूल्य गिरने के काल मे इन ऋणदाताओ को लाभ होता है और राज्य (वास्तव मे कर दाताओं) को हानि होती है मुद्रा स्फीति के बाद इस प्रकार से ऋण चुकाये जाना चाहिए. परन्तु इस सबध में यह ध्यान रखना चाहिए कि सही व्यक्तियो पर ही यह कर लगे. इससे देश के मुद्रा बाजार मे भय एव आतक का वातावरण न फैले, पूंजी निर्माण, मितव्ययिता व उत्पादन कम न हो और न विदेशो मे पूंजी जाए अन्यथा यह उस प्रकार होगा जैसे कि "कोई अपना भोजन बनाने के लिए अपने ही घर को जलाए " (It would be like burning your own house to roast your pig).

ऋण के भार को कम रखने सम्बन्धी नीति :

(A) सार्वजनिक ऋणो के भार को कम रखने के लिए सर्वप्रथम तो हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना चाहिए राष्ट्रीय आय मे वृद्धि स्वय ऋण भार कम करती है. यह प्रत्यक्ष रीति या तरीका व परिणाम होता है Evsev domar ने इसी लिए कहा है

> ' वे समस्त व्यक्ति जो राष्ट्र के ऋणी होने के कारण भाषण देते हैं, लेख लिखते है, फिक्र करते है तथा रात बगैर सोये बेचैनी से गुजारते हैं, अगर वे उससे आधा समय ही राष्ट्रीय आय बढाने में लगाएँ तो वे ऋण समस्या के हल करने में सहायक होंगे "

E D. Domar, The Burden of the Debt and the National Income, American Economic Review, Dec 1944, p 423

Quoted from "The Economics of Public Finance by P E. Taylor p 240

ऋण का भार कम रखने के दो प्रमुख उपाय और हैं

(i) सर्वप्रथम ऋणो की व्यवस्था ऐसी हो कि ऋण गरीब से अधिकाधिक प्राप्त हो (जैसे अल्प बचत योजनाओं से) इससे गरीब वर्ग ब्याज प्राप्तकर्ता के रूप में आयेगा यह बहुत अधिक सम्भव नहीं होता क्योंकि गरीबों से अधिक ऋण देने की क्षमता अमीरो की होती हैं

(ii) दूसरे करो की व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि देश में धनी व्यक्ति अधिक कर दें इससे ऋण व्यवस्था देश में राजकोषीय नीति के समानता लाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगी.

इसकी उल्टी व्यवस्था नहीं होना चाहिए अगर ऋण दायक तथा कर देनेवाले अर्थात् ब्याज प्राप्तकर्ता और करदाता एक ही वर्ग के व्यक्ति हैं तो ऐसी ऋण व्यवस्था से न तो लाभ होगा और न भार ही पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में ऋण का भार मानसिक भार होगा क्योंकि ऋणदाता जिस लाभ की आशा करते थे वह उन्हें प्राप्त नहीं होती हैं

(B) कम-विकसित देशों को ऋण व्यवस्था मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखने के लिए प्रयोग मे लाना चाहिए इसका अर्थ होता है कि मुद्रा स्फीति काल में राज्य को अतिरेक क्रयशक्ति को खीचने के लिए ऋण लेना चाहिए. इस सबध मे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जहाँ ऋण लेने से मुद्रा स्फीति कम होती है वही ऋणो के बने रहने से मुद्रा स्फीति फैलती है यह इसलिए होता है कि राज्य के ऋणदाता जो प्रतिभूतियाँ अपने पास रखते हैं उन्हे वे आवश्यकता पड़ने पर भुना कर बैंको से और उधार ले सकते है ये प्रतिभूतियाँ Money sitting कहलाती हैं इस प्रकार से दीर्घकाल मे पुन मुद्रा स्फीति फैल सकती है

(C) ऋणो का भार कम रखने लिए[1] जिन कार्यों में ऋण का प्रयोग किया जाता है उनका Gestation period या फल दायक काल के आने का काल कम होना चाहिए

जहाँ तक विदेशी ऋणो का प्रश्न है इस सबध मे यह नीति होना चाहिए कि इन ऋणो का सदुपयोग देश में आयात हतोत्साहित व निर्यात प्रोत्साहित करनेवाले उत्पादक कार्य स्थापित हों

---

1. ओ० एस० श्रीवास्तव द्वारा लिखित अध्याय 15-18 "मुद्रा साख्यिकी" कैलाश पुस्तक सदन, ग्वालियर : 1969.

अनिवार्य बचतें ?

कम विकसित देशो में बहुधा अल्प बचतो, तथा राज्य के ऋणो से पर्याप्त मात्रा में धन नही आए तो राज्य को अनिवार्य रूप से ऋण लेने की बात सोचनी चाहिए. Nurkse के अनुसार

> "अनिवार्य बचतें करो का उत्तम विकल्प है, इनसे आय भी होती है और इनका दुष्प्रभाव कार्य करने की इच्छा व शक्ति पर नही पड़ता."

भारत में भी "अनिवार्य बचत योजना" शुरू की गई थी जो अब केवल बडी आय वालो तक (Annuity Deposit Scheme) सीमित है. अनिवार्य रूप से बढे हुए महँगाई भत्ते का हिस्सा प्रावीडेन्ट फंड मे लगाना भी इसी प्रकार की नीति है

ग्रामीण क्षेत्र :

कम-विकसित देशो मे, जैसा कि हम देख चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र राज्य की आय में कम योगदान करता है आज बहुत से कम-विकसित देश ग्रामीण जनता पर प्रशासनिक कठिनाइयो व राजनैतिक कारणों (वहाँ के वोटो को खोने के डर) से कर पर्याप्त मात्रा में नही लगाते. इसलिए इस क्षेत्र से कम से कम बचतें इकट्ठी अवश्य की जानी चाहिए

यहाँ से बचतो का लेना केवल बैंकिंग कार्य ही नहीं है इसको राजकोषीय नीति का अग भी बनाया जा सकता है

•

Nurkse : op. cit. p 170

अध्याय : 7

विकास के लिए मूल्य नीति

Price Policy for Economic Growth

(A) Market mechanism vrs. Controlled prices

(B) Stable price level vrs. rising price level.

(A)

Market mechanism vrs. Controlled prices.

I. प्रस्तावना :
मूल्य का आर्थिक कार्य.

II. कृषिक्षेत्र मे स्वतन्त्र मूल्य पद्धति या नियन्त्रित मूल्य पद्धति :

(a) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति के पक्ष में तर्क या नियमित नीति के विपक्ष में तर्क.

(b) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति के विपक्ष में या नियन्त्रित या नियमित मूल्य नीति के पक्ष में तर्क

(c) नियमित मूल्य या नियत्रित मूल्य.

(d) मूल्य नियमित होना चाहिए

(e) न्यूनतम व अधिकतम मूल्य का प्रश्न

(f) मूल्य नीति positive (प्रत्यक्षात्मक) होना चाहिए.

III. उद्योग क्षेत्र के लिए मूल्य नीति :

(a) स्वतन्त्र नीति के पक्ष में तर्क : हेरी जी० जानसन व डा० खटखटे.

(b) स्वतन्त्र मूल्य नीति के विपक्ष में : रोजन्सटीन रोदान.

(B)

Stable price level vrs. rising price level.

अध्याय : 7

विकास के लिए मूल्य नीति

Price Policy for Economic Growth

(A)

Market mechanism vrs. Controlled prices.

I. प्रस्तावना :

The Role of Prices .

अर्थशास्त्रियो ने हमेशा Theory of price पर ध्यान दिया है, अर्थशास्त्रियो का सम्बन्ध मूल्य स्तर से इतना अधिक रहा है कि हम Oscar Wilde (ओसकर वाइल्ड) के परोडी को दुहरा सकते है कि अर्थशास्त्री वह है जो "who knows the price of everything and the value of nothing." मूल्य व विकास को अधिकाश अर्थशास्त्रियो ने "मुद्रा स्फीति व विकास" के रूप मे ही अधिकत अध्ययन किया है परन्तु अधिक उपयुक्त अध्ययन यह होगा कि क्या स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली विकास के लिए आवश्यक है अथवा नियंत्रित मूल्य प्रणाली आवश्यक है.

जैसा कि हम सब जानते है 'मूल्य' अर्थव्यवस्था के Signals है (अर्थात् जैसे रेल के हरे-लाल सिगनल चलने व रुकने के सकेत देते हैं वैसे ही गिरते व बढते मूल्य सकेत देते है) 'मूल्य' का मुख्य कार्य माँग व पूर्ति मे सतुलन लाना है. अगर कभी किसी वस्तु की माँग अधिक या पूर्ति कम होने के कारण मूल्य बढते है तो उत्पादनकर्ता स्वय ही या तो पूर्ति बढा देते है या माँग कम हो जाती है. इसके विपरीत मूल्यो का गिरना इस बात का द्योतक है कि उस वस्तु विशेष की पूर्ति अधिक है और माँग कम है. मूल्य गिरने से उत्पादनकर्ता पूर्ति कम कर देते है और माँगकर्ता माँग बढा देते है

मूल्यो मे वृद्धि इस प्रकार से और वृद्धि होने को रोकती है और मूल्यो मे गिरावट और अधिक गिरावट को रोकती है

मूल्यो के इन्ही उच्चावचनो के कारण उपभोगकर्ता अपने भिन्न-भिन्न वस्तुओ के उपभोग की मात्रा निर्धारित करते है मूल्यो से ही फिर भिन्न-भिन्न वस्तुओ की

कुल व सापेक्षिक मात्रा निर्धारित होती है. मूल्य ही भिन्न-भिन्न क्षेत्रो व भिन्न-भिन्न उद्योगो मे विनियोजन की मात्रा निर्धारित करते है. (They halp in allocating scarce resources among various investment filds in optimum manner).

II. Market mechanism or price mechanism and development of agricultural sector. स्वतत्र बाजार प्रणाली या स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली तथा कृषि क्षेत्र का विकास :

(a) पक्ष में तर्क :

बहुत से अर्थशास्त्रियो का विचार है कि कृषि क्षेत्र का विकास करना हो तो स्वतत्र मूल्य प्रणाली से ही ऐसा हो सकता है इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि अगर इन देशो मे कृषि वस्तुओं के मूल्यो को स्वतन्त्र बाजार पद्धति के अनुसार निर्धारित होने की स्वतन्त्रता हो तो मूल्य बढेंगे. किसी भी कम विकसित देश में विकास के युग के शुरू मे आधारभूत उद्योगो के स्थापित करने तथा अन्य विकास कार्यों पर व्यय करने से देश मे एकदम मुद्रा प्रसार होता है इस मुद्रा प्रसार से मूल्य स्तर बढता है और कृषि वस्तुओं के मूल्य भी बढते हैं. कम-विकसित देशो में कृषि वस्तुओ की विकास के शुरू के काल में income elasticity of demand अधिक होती है. अर्थात् जैसे-जैसे लोगो की आय बढती है तो वे अच्छा व अधिक खाने का सामान माँगते है विकास के 'बहुत बाद के काल' में तो फिर वे आय बढ़ने पर मोटरें, रेफ्रीजेटर्स आदि माँगते है और फिर कृषि पदार्थो की income elasticity of demand कम हो जाती हैं. इस कारण भी विकास के काल मे कृषि वस्तुआ के मूल्य बढते है.

स्वतन्त्र बाजार या मूल्य पद्धति के समर्थको का कथन है कि यह स्थिति कृषि विकास के लिए अत्यन्त लाभदायक होगी

(1) इससे कृषको को अधिक आय मिलेगी और सदियो से सोती हुई कृषि व्यवस्था में बढते हुए मूल्यो की प्रेरणा से कृषक लोगो की आय वृद्धि होगी

इस अध्याय का अधिकाश भाग उस अग्रेंजी लेख पर आधारित है जो कि लेखक ने 1966 मे Vikram University Economist's seminar में पढा था यह फिर एक पुस्तक "Economics of wages, Productivity and Employment" में भी शामिल किया गया था.

(ii) उनकी इस आय वृद्धि से वे कृषि मे उन्नति कर सकते है. कृषक अपने ऋण चुकाकर अपनी बचतें व पूँजी निर्माण बढा सकते हैं, और कृषि की आवश्यक inputs या लागतें ले सकते है.

(iii) अप्रत्यक्ष रूप से यह ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण उन्नत करता है. जब कृषक स्वय अच्छा खाएगे, पहनेगे, अच्छी शिक्षा लेगे व अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करेंगे तो समस्त ग्रामीण जनता की उत्पादकता बढेगी

(iv) इस मूल्य वृद्धि से न केवल अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी वरन् इससे कृषक एक से अधिक फसले उगाएँगे तथा तदनुसार सिंचाई आदि की सुविधाएँ बढा लेगे. इसी प्रकार से वे खाद्य तथा व्यापारिक फसलो में सतुलन लायेंगे

(v) स्वतन्त्र मूल्य या बाजार प्रणाली इसलिए भी आवश्यक होगी कि अगर ऐसा न किया गया तो विकास के दिनो में जहाँ द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के व्यक्तियो (Secondary and Tertiary sector) की वास्तविक आय बढ जाएगी, कृषि क्षेत्र के लोगो की वास्तविक आय नही बढ पाएगी. इसलिए कृषिक्षेत्र की वस्तुओ के मूल्य नियन्त्रित नही होना चाहिए

(b) कृषिक्षेत्र में स्वतन्त्र मूल्य व बाजार के विपक्ष में तर्क :

कम-विकसित देशो मे उपरोक्त नीति से गम्भीर दुष्परिणाम भी हो सकते है

(i) इन देशो मे 80-90% व्यक्ति अपनी आय का 60–70% भाग खाद्यान्न पर व्यय करते है स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य बढने से इन पर तो मृतभार पड जाएगा

(ii) कृषि वस्तुओ का जो मूल्य बढेगा यह आवश्यक नही कि उस वृद्धि से कृषक पूँजी निर्माण ही करें अगर उन्होने उसको अपव्यय कर दिया या अगर बढे हुए लाभ को बीच के बिचोलियो ने रख लिया तो उत्पादन वृद्धि नही हो पाएगी और मूल्य बढते ही चले जाएंगे

(iii) कृषि वस्तुओं के मूल्य बढने से उद्योगो को कच्चा माल महँगा प्राप्त होगा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत बढेगी

(iv) कृषि वस्तुओ, विशेषरूप से खाद्यान्नो के मूल्य बढने से मजदूर लोग अधिक मजदूरी मागेगे और अगर उनकी उत्पादकता मे वृद्धि नही हुई तो cost-push inflation या लागत-वृद्धि से मुद्रास्फीति फैलेगी

(v) कृषि पदार्थों के बढते मूल्यों से सट्टे की प्रवृत्ति फैलेगी
"Profits will flow to speculators in towns and villages, whereas the farmers, specially the smaller ones, will feel acutely all the negative effects of the entire economy which are induced by a violent price increase of agricultural produce"[1]

(vi) कृषि मे बढते हुए मूल्य की समस्या उस देश के लिए गम्भीर नही होगी जिसदेश को किसी प्रकार का विदेशी विनिमय का संकट न हो. ऐसा देश विदेशों से वस्तुएं मंगा सकता है और मूल्य वृद्धि से निपट सकता है परन्तु अधिकांश कम-विकसित देश तो विदेशी विनिमय के संकट में रहते हैं उनका यह संकट और बढ जाएगा. मूल्य वृद्धि से उनके निर्यात कम होंगे या कालान्तर मे उन्हें अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना होगा कम-विकसित देशों को यह समस्या और भी गम्भीर रूप से सामने आएगी अगर उनकी वस्तुओं की विदेश में मांग लोचदार है अथवा विदेशी खरीदार एकाधिकारी स्थितिमें है (When the purchasing countries are in monopsonistic or oligo-psonistic position).

(vii) कम विकसित देशों में बढते हुए मूल्य बहुधा कृषकों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा देने में भी सफल नही होते मूल्य वृद्धि से कृषक अपनी भिन्न-भिन्न उपजों की मात्रा को एकदम घटाते व बढाते भी नहीं हैं और बहुधा यातायात, तथा अन्य सहायक चीजों के उपलब्ध न होने से कृषि उत्पादन मे वृद्धि नही हो पाती

(viii) कम-विकसित देशों मे बाह्य मितव्ययिताओं के सृजन मे (यातायात शक्ति की सुविधाओं का विकास) विनियोजन की बहुत आवश्यकता होती है श्री एल. के झा (L.K Jha)[2] का मत है कि इस प्रकार की स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से सामाजिक सिरोपरि व्यय नही किए

1. Dr. O S Shrivastava "Economics of wages, Productivity & Employment" p 49
2. L. K Jha's lecture at New Delhi—Ram Memorial lecture : Governor Reserve Bank, 20th April 1968.

जाएँगे 'Given the continuing shortage of capital it would be unrealistic is expect in foreseeable future that through the free play of the price mechanism and by allowing capital to be deployed with higher profits as the prime objective one would secure reasonable investment in sectors important from the point of view of over all growth or social benefit.'

(ix) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति को तो हम उस देश मे अपना सकते हैं जहाँ कि हमको आय व सम्पत्ति के वितरण को ठीक करने के बारे में कुछ नही करना है वहाँ मूल्यो के अनुसार उत्पादन होता है और मूल्यो के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओ को पूरा कर लेते हैं कम-विकसित देश यह पद्धति अपनाएँ तो बढे हुए मूल्यो पर धनी लोग ही सम्पूर्ण पूर्ति खरीद सकते है और गरीब तो खरीद ही नही पाएगे : इन देशों में बेरोजगारी पहले ही मौजूद है और अगर मूल्य भी बढने दिए गए तो गरीब तो पिस जाएगे इसलिए नियन्त्रित मूल्य प्रणाली उचित होगी.

(c) Regulated prices vrs controlled prices. **नियमित मूल्य पद्धति उचित होगी, परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण नियन्त्रण जरूरी नही**

हम यह देखते हैं कि कम-विकसित देशो मे स्वतन्त्र मूल्य पद्धति मे लाभ मे अधिक हानियाँ होने की सम्भावनाएँ हैं इसलिए हमको यह पद्धति नही अपनाना चाहिए.

स्वतन्त्र मूल्य पद्धति का उल्टा नियन्त्रित मूल्य प्रणाली है इसका अर्थ है कि देश मे Control 'कन्ट्रोल' होना चाहिए परन्तु सारी वस्तुओ के मूल्यों पर तो नियन्त्रण नही किया जा सकता

कन्ट्रोल की बुराइयाँ व समस्यायें .

कन्ट्रोल व नियन्त्रित मूल्य पद्धति स्वय कुछ समस्यायें उत्पन्न कर देती है कन्ट्रोल करने के बाद तो वास्तव मे मूल्य घटते नही है वरन् बढ जाते है. कन्ट्रोल के दिनो मे व्यापारी जमाखोरी करने लगते है और मूल्य बढ जाते है राज्य भी मूल्य नियन्त्रित रखने के लिए buffer stock या स्टाक बनाता है और वह स्वय जमा करने लगता है, और "यहाँ वह मसल हो जाती है कि पुलिस भी चोर बन

जाती है"[1] ऐसे समय मे राजनीतिज्ञ व 'लीडर' लोग भी कमियो व भावी कमियो को लेकर जोर शोर से भाषण करने लगते है जो आग मे घी का काम करते है इससे सट्टेबाजो को और फायदा होता है

कन्ट्रोल या नियन्त्रित मूल्य कभी कभी देश में बहुत ही हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते है भारत मे ही Agriculture Price Commission ने, बढते हुए मूल्यो की समस्या के निवारण हेतु, खाद्य क्षेत्र (food zones) बनाने की सिफारिश की और नियन्त्रित मूल्यो की पद्धति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया उसकी यह सिफारिश इस विश्वास पर आधारित रही कि अगर मूल्य स्वतन्त्र बाजार पद्धति पर आधारित रहे तो metropolitan centres या बडे-बडे शहरो मे, जहाँ धन अधिक है, अधिकाश पूर्ति खिच जाएगी, और छोटे शहरो व गरीब क्षेत्रो में पूर्ति कम हो जाएगी

भारत में जो कुछ हुआ उसने दिखा दिया कि इससे भिन्न-भिन्न राज्यो में ही मूल्यो में बहुत अन्तर नही पनपे वरन् एक ही राज्य के अलग-अलग जिलो मे अन्तर रहे. ये अन्तर उत्पादन लागतो के अन्तर या यातायात लागत के अन्तरो पर आधारित नही थे वरन् कन्ट्रोल व नियन्त्रण के कारण उत्पन्न थे. इस प्रकार के नियन्त्रित मूल्यो व नियन्त्रित वितरण के कारण भ्रष्टाचार, जमाखोरी, काला बाजारी व चोरी छिपे इधर उधर ले जाना पनपा. राशनिंग, कन्ट्रोल व नियन्त्रित मूल्यो से उन लोगो को लाभ होता है जो नौकरशाही के निकट सम्पर्क में रहते है उन्हे अतिरिक्त 'कोटा' मिल जाता है और इन दिनो में जाली परमिटो की सख्या बढ जाती है.

जब खाद्यान्न के मूल्यो को नियन्त्रित किया जाता है तो कृषक व्यापारिक फसलो की खेती करने लगते है अगर किसी एक अनाज के मूल्य नियन्त्रित करके उसे बेचा जाता है तो उसकी माग मे अनावश्यक वृद्धि हो जाती है.[2]

---

1. Dr O S Shrivastava · op cit. p 50.
2. भारत में जब कट्रोल से गेहूँ मिलते थे, तो उनका भाव ज्वार, मक्का के खुले बाजार के भाव से कम था. नतीजा यह हुआ कि मक्का और ज्वार खाने वाले भी गेहूँ माँगने लगे और गेहूँ की पूर्ति विषमता और बढ गई

   See also : Commerce Annual Number Dec. 1966, "Wanted . A Rational price policy" H T. Parekh General manager I C I. C I.

(d) Prices should be regulated, they should not be controlled .

राज्य को मूल्यो को regulate या नियमित करना चाहिए. उन्ह control या नियन्त्रित नही करना चाहिए यह कार्य राज्य स्वय भी एक प्रतिकर्ता के रूप मे कर सकता है जहाँ निजी क्षेत्र के व्यक्ति कृषि वस्तुग्रो का क्रय विक्रय करें वहाँ राज्य भी monopoly procurement या एकाधिकारी खरीदारी करके ग्रावश्यकता पडने पर ग्रर्थात मूल्य ग्रधिक बढने पर स्वय बेचना शुरू कर कर सकते है परन्तु ऐसा देखा गया है कि राज्य के पास साधन ग्रधिक होने पर भी निजी क्षेत्र वालो को कृषक लोग फसल बेचना पसन्द करते है बर्मा राज्य मे जब राज्य ने सस्ते मूल्यो पर ग्रावश्यक वस्तुग्रो को बेचना शुरू किया तो निजी क्षेत्र के एजेन्ट लाइन म लगकर (क्यू म लगकर) सामान खरीदकर ग्रपनी दुकानो मे बेचते थे बर्मा की सरकार ने फिर इन्हे पूर्ण तरह से समाप्त ही कर दिया.

परन्तु कम-विकसित देशो में यह कार्य राज्य, सहकारी सस्थाएँ ग्रौर निजी क्षेत्र सब मिलकर कर सकते है निजी क्षेत्र के व्यापारियों को एकदम समाप्त करना उचित नही होगा एक तो राज्य की इतनी क्षमता नही होगी कि वह समस्त व्यापारिक कार्यों का सचालन कर सके ग्रौर फिर यह उसे बहुत महगा पडेगा जिसका व्यय वह करो से ही पूरा करेगा सहकारी सस्थाग्रो को भी नियमित रूप से कार्य करना चाहिए श्री पाई, जो भारत के फुड कारपोरेशन के भूतपूर्व चेयरमैन रहे है, के शब्दो मे भारत म सहकारी सस्थाग्रो ने बहुधा उससे ग्रधिक मुनाफा कमाया है जितना कि निजी क्षेत्र के लोग कभी नही कमाते देश मे इस प्रकार से ऐसी बिक्री व्यवस्था होनी चाहिए जिसम कृषकों ग्रौर उपभोक्ताग्रो के बीच कम से कम व्यक्ति हो तथा वे पूर्ण प्रतियोगिता के ग्राधार पर कम से कम लाभ लें

(e) Minimum or support prices or floor prices /Standard prices/and Maximum prices

कृषि के उचित व शीघ्र विकास के लिए न्यूनतम मूल्य व ग्रधिकतम मूल्यों को निर्धारित करना पडेगा ग्रगर कृषि वस्तु मूल्य कम रहेंगे तो इससे

(i) उपभोग बढेगा.

(ii) Inventory stock piling बढेगा ग्रर्थात् लोग जमा करेंगे.

(iii) कृषक भी स्वय का उपभोग बढा लेंगे. तथा

(iv) वे उत्पादन कम कर देंगे. इस तरह से एक न्यूनतम सीमा से मूल्य गिरने नही देना चाहिए.

राज्य को यह न्यूनतम मूल्य (Floor prices) फसल से पहले ही घोषित कर देना चाहिए. इनको पिछले चार वर्षों या तीन वर्षों के औसत से कुछ अधिक होना चाहिए इनको इतना होना चाहिए कि वे लागत व यातायात व्यय को पूरा कर सके यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि कम-विकसित देशो में input तथा output या लागत व उपज के सही आंकड़े उपलब्ध नही होते

> "Not much is known about the input data, eg. it is very difficult to reckon in monetary terms such fixed costs & maintaining a peasant's family"

अगर न्यूनतम मूल्य इतने रखे गए कि पिछड़े से पिछड़े किसान के लागत व्यय पूरा हो जाए, तो यह मूल्य बहुत अधिक रहेंगे इसलिए इनको इतने होना चाहिए कि Sub-marginal cultivators या अनुसीमान्त कृषक अपने उत्पादन में उन्नति करें

अगर मूल्य गिरने लगें तो राज्य को स्वयं खरीद करके न्यूनतम मूल्यों के स्तर से मूल्य गिरने नही देना चाहिए.

राज्य को इसी प्रकार से उपभोक्ताओं और उद्योगो के हित को ध्यान में रखकर "अधिकतम मूल्यों" को भी निर्धारित करना चाहिए अगर मूल्य इससे ऊपर जाएँ तो राज्य को अपने buffer stocks को बेचकर मूल्यो को नीचे लाना चाहिए.

(f) Positive policy

लेखक के मत से सर्वोत्तम मूल्य नीति वह होगी जिसमे सब पक्षो के हित को ध्यान में रखा जाएँ बहुत नीचे मूल्य कृषको को हानिकारक है तो बहुत अधिक मूल्यों से उपभोगकर्ताओं, कच्चे माल के प्रयोगकर्ताओ तथा निर्यात व्यापार में हानि होगी नियन्त्रित मूल्य अल्पकाल के लिए जरूरी हो सकते है दीर्घकालीन लक्ष्य तो उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमे स्वतन्त्र मूल्य पद्धति कार्यान्वित हो सके.

दुर्भाग्य से अभी तक बहुत से कम-विकसित देशो ने buffer stock mechanism, साख नियन्त्रण, वितरण नियन्त्रण, तथा अन्य राजकोषीय व वित्तीय

See also ·

"Rationale of Procurement Prices" S Venue Eastern Economist February 2, 1968

2. O. S Shrivastava · op. cit 49.

नीति का सहारा लेकर कृषि क्षेत्र की वस्तुओं की मूल्य नीति को तय किया है. **उचित नीति तो यह होगी कि वे देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार बढाएं और उत्पादकता बढाएं जिससे मूल्य नीति पर नियन्त्रण आवश्यक ही नहीं होगा**

देश मे आन्तरिक मूल्य नीति विकसित देशा की तटकर नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति पर भी निर्भर होती है

श्री एल० के० झा के भी इसी प्रकार के विचार हैं उनके अनुसार

> "A successful price policy has to be conceived in a long term perspective, While we may not wish to leave our economy at the mercy of market forces, we should not hesitate to harness market forces to subserve our objectives A well-concived price policy sould in the short run prevent the exploitation of the consumer in conditions of scarcity and in the longrun provide adequate inducement to the producer to step up his output"

III Price policy for industrial sector and for the economy in general औद्योगिक क्षेत्र तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य नीति

जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र के लिए क्या मूल्य नीति होना चाहिए इसके बारे में मतभेद हैं उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए मूल्य नीति के बारे में भी मतभेद है कम विकसित देशों के सबंध मे अधिकाश अर्थशास्त्री नियमित मूल्य नीति चाहते है.

(a) स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के पक्ष में · Harry G Johnson

हैरो जानसन चाहते हैं कि कम-विकसित देशो को चाहिए कि वे स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली में विश्वास रखें और देश में मूल्यों की माँग और पूर्ति म समन्वय लाने

L K Jha : op cit

Harry G. Johnson . "The Market Mechanism as an Instrument of Development" From Money, Trade and Economic Growth George Allen & Unwin, London 1962 p 152-63 q. f. G. Meier : op. cit.

दें. उनका विश्वास है कि एडम स्मिथ की यह मान्यता कि नियन्त्रित मूल्य भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता को उत्पन्न करते हैं आज भी ठीक है.

जानसन यह मानते हैं कि नियन्त्रित मूल्य प्रणाली देश में धन की असमानताएँ नहीं बढने देती वरन् वह तो गरीबों के हित को ध्यान में रखती है. जानसन का कथन है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से विकास पनपता है जबकि नियन्त्रित मूल्य प्रणाली से धन का वितरण ठीक होता है, जानसन का विचार है कि कम-विकसित देशों को मुख्यत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए. उनका कथन है कि

> "We should not worry too much about the distribution of income."

श्री जानसन का कथन है कि स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था का गुण है कि उससे देश के साधनों का उपयोग व उत्पादन तथा उत्पादन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उचित वितरण (Allocation) होता है. जिस चीज का मूल्य बढ़ता है उसकी पूर्ति भी बढ जाती है इस प्रकार से अगर किसी वस्तु की पूर्ति कम हो तो वह बढ जाएगी, अगर कुशल श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है तो अकुशल श्रमिक ट्रेनिंग लेकर पूर्ति बढ़ाएँगे भिन्न भिन्न स्थानों व उद्योगों के बीच पूजी वहाँ लगायी जाएगी जहाँ लाभ अधिक होंगे और इस प्रकार म देश में न्यून पूँजी का अच्छा उपयोग होगा. स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के आधार पर पूजी उन उद्योगों में लगाई जाती है जिनमें लाभ अधिक होता है. इससे पूजीपति और पूंजी निर्माण करते हैं उनका कथन है

> "अगर स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली ठीक तरह से क्रियान्वित है तो इससे देश में अर्थव्यवस्था में कार्य क्षमता व कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी तथा विकास भी होगा. इस सबध में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस प्रकार से विकास करने से देश में न तो केन्द्रीय सचालन सस्था की आवश्यकता होती है, न किसी जटिल कानूनी या प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है."

श्री जानसन यह मानते हैं कि मूल्य प्रणाली या बाजार व्यवस्था का पूर्ण रूप से स्वतन्त्र न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं होने, तो इसमें स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली को नहीं हटाना चाहिए वरन् उन दोषों व कमियों को दूर करना चाहिए.

इसी प्रकार से कम-विकसित देशों में बाजार पूर्ण रूप से न तो सगठित रहते हैं और न ही उनमें पूर्ण गतिशीलता व पूर्ण प्रतियोगिता होती है. इस कारण ही राज्य को नियन्त्रित मूल्य नीति नहीं अपनाना चाहिए वरन् राज्य को इन देशों में

बाज़ार व्यवस्था को ठीक करना चाहिए. अगर बाज़ार सबंधी सभी जानकारी सब लोगों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो तो स्वतन्त्र बाज़ार की क्रियाओं से कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नही हो सकते. और वे फिर कहते है कि विकास के शुरू के काल में ही सामाजिक न्याय प्राप्त नही हो सकता. सामाजिक न्याय की बात तो काफी विकास के बाद करना चाहिए :

> "एक विकसित देश सामाजिक न्याय के खातिर थोड़े बहुत मात्रा मे विकास का त्याग कर सकता है. किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय आय के स्तर नीचे है तो इस काल समानता की बात महँगी पड़ेगी. हम सब जानते हैं कि विकास के लिए आकस्मिक लाभों की आकांक्षा अधिकता से होती है और यह आकस्मिक लाभ तभी अधिक हो सकता है जबकि इन देशों मे बाजार प्रणाली स्वतन्त्र हो."

श्री जानसन यह नही कहते कि मूल्य के सम्बन्ध में एकदम निर्बाधवादी नीति अपना ली जाए वे तो यह चाहते है कि बाजार व मूल्य प्रणाली पर नियंत्रण के अकुश नही होना चाहिए वरन् आयोजन का मुख्य कार्य ही स्वतन्त्र मूल्य व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए

Dr. Khatkhate

डा० खटखटे ने भारत के पिछले अनुभव के आधार पर यह कहा कि निर्यात मूल्य प्रणाली से बहुत ही निराशाजनक परिणाम हासिल हुए हैं वे भ्रष्टाचार को फैलाते है. उन्होंने कहा था

> "At some stage of growth you have to jettison all price controls and allow the capitalism function to help growth."
>
> अर्थात् "विकास के किसी अवस्था में यह आवश्यक हो ही जाएगा कि समस्त मूल्य नियंत्रणों को त्याग दिया जाए (Jettison का अर्थ होता है कि अगर कोई जहाज समुद्र मे फँस जाए और फिर उसको चलाने के लिए उसे हल्का करने को सामान फेंक दिया जाए) और स्वतन्त्र पूँजीवादी व्यवस्था को विकास में सहायक होने दें"

Dr. Khatkhate भारत के रिजर्व बैंक मे उच्च पद पर है. उनकी यह सम्मति उनकी निजी सम्मति है और बैंक की नीति की द्योतक नही है उन्होंने यह विचार उपरोक्त पृष्ठों में उद्धृत भोपाल में अर्थशास्त्रियों की सेमीनार में व्यक्त किए थे.

डॉ० खटखटे चाहते है कि देश मे दुहरी मूल्य व्यवस्था रह सकती है. कुछ वस्तुएँ जो गरीबो के उपभोग कि है उन्हें नियमित कर सकते है. अगर हम मूल्य नियन्त्रि करें तो एक मात्रा मे basic efficiency भी निर्धारित करना होगा.

(b) In favour of regulated prices · **नियमित मूल्य पद्धति के पक्ष में :** नियन्त्रित मूल्य पद्धति के पक्ष मे भी अर्थशास्त्री है, जिनमें Rosenstein Rodan के विचार यहां दिए जा रहे है.

Rosenstein Rodan ·

श्री रोदान, जो सतुलित विकास पद्धति के प्रबल समर्थक है, स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली के प्रभावशाली होने में विश्वास नही रखते उनका विचार है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से कम-विकसित देशो मे विकास नही हो सकता क्योकि इन देशो में पूँजी बाजार बहुत ही अपूर्ण रूप से विकसित हुए है उनका मुख्य तर्क यह है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से सामाजिक हित का विनियोजन नही होता. स्वतन्त्र बाजार व मूल्य प्रणाली देश में निजी क्षेत्र वालो को लाभ देती है उससे जो वे कमाते है उसे वे सामाजिक सिरोपरी व्यय मे नही लगाते अर्थात् Social overheads मे नही लगाते, क्योकि इनमे अधिक मात्रा मे व्यय होता है और इनमें धन लगाने मे उन्हे लाभ नही होता

> "Price mechanism works under the assumption of small changes, and where there is indivisibility or lumpiness of capital, price mechanism does not work. Price mechanism cannot equate private and social net marginal product"

"श्री रोदान" का विचार है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से उपभोग वस्तुओ का अच्छा वितरण हो सकता है परन्तु वह विनियोजन ठीक नही करती और न ही मौद्रिक सतुलन लाती है

> "Price mechanism cannot equate aggregate supply and aggregate demand and then prices

"The flaw in the Mechanism of Market forces" Paul N Rosenstein Rodan, in Programming in Theory and in Italian Practice in Massachusetts Institute of Technology, Centre for International Studies, Investment Criteria and Economic Growth, Asia : 1961 p 19 22 See also quoted From G. Meier : op. cit.

cease to be reliable parameters of choice and the price mechanism breaks down......it does not function in the fields of investment and monetary equilibrium"

पुस्तक के वर्तमान लेखक का भी मत है कि पूर्णरूप से स्वतन्त्र मूल्य उचित नही है आज के युग मे मूल्य नीति स्वय उस देश की राजनीति से प्रभावित होती है. अगर देश में निजी क्षेत्र को विकास में अधिक योगदान का मौका दिया गया है तो मूल्य मुख्यत अनियन्त्रित होना चाहिए. फिर भी आज के युग मे पूर्णरूप से अनियंत्रित मूल्य नही रखे जा सकते. राज्य को यह शक्ति होना चाहिए कि वह आवश्यकता पडने पर अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सके. अगर ऐसा न किया गया गया तो निजीक्षेत्र के उत्पादनकर्ता बहुत अधिक मूल्य ले लेगे.

उदाहरणतया

"भारत में हम दवा उद्योग का उदाहरण सामने रखें तो हम पाते हैं है कि भारत में Sulpha thalazole को 800 रु पौंड बेचा जाता है जबकि हेफकीन इन्सटीट्यूट मे यह केवल 20 रु. पौंड बनाया जा सकता था. इसी प्रकार से भारत में Tetracyctine केपस्युल 20 रु. की 16 बेची जाती है जबकि उसकी लागत केवल 2 रु. प्रति 16 केपस्युल है. भारत मे बहुत सी जीवन रक्षक दवाएँ अपनी लागत व्यय से 17 से 20 गुने अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं बहुत सी कम्पनियो के लाभ उनके लागत व्यय, अनुसधान व्यय, विज्ञापन, तथा सेल्स व्यय सबको मिला देने के पश्चात् भी उनसे अधिक थे.[1]

देश में मूल्य नीति हमेशा के लिए एक सी नही रह सकती. समय-समय पर उसमे परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है कभी कडे नियन्त्रण की आवश्यकता हो सकती है, कभी नियमन से काम चल सकता है तथा कभी स्वतन्त्र मूल्य ठीक होगे मूल्य नीति जो भी हो, यह आवश्यक है कि नीति ऐसी होना चाहिए कि उत्पादन में कमी नही हो.

दीर्घकाल में जहाँ तक हो सके पूर्ति मे वृद्धि करके मूल्यो को स्वतन्त्र ही रखा जाना चाहिए. आज के युग में समाजवादी देश भी Price mechanism के महत्व को मानने लगे हैं

1. An article in Economic Weekly, Dec. 18, 1965 written by the Director of the Institute S Hazra.
quoted From O. S. Shrivastava's op. cit. p. 52.

(B)

Price Stability vrs Rising Prices for Growth[1]

विकास के लिए स्थिर मूल्य या बढ़ते मूल्य

पिछले अध्यायो मे[2] हम यह देख ही चुके हैं कि विकास के लिए न तो स्थिर मूल्य स्तर उपयुक्त और न ही मुद्रा स्फीति ही लाभदायक है वरन् धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य स्तर उपयुक्त है

Dr V. K. R V. Rao के अनुसार

> "A rigid stable general level of prices may be as much of a deadweight on economic growth as a rapidly rising price level."

जब मूल्य बढ़ते है तो निश्चित आय पाने वालो का अहित होता है और वे अधिक आय या मजदूरी माँगते हैं और इससे लागत बढ़ती हैं और फिर मुद्रा स्फीति फैलती हैं और पुन लागते बढ़ती है और मूल्य वृद्धि होती जाती है. अगर मूल्य नीति के साथ-साथ अन्य नीतियाँ इस प्रकार से क्रियाशील हो रही हो कि देश में उत्पादन भी बढ़ जाए (और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उत्पादकता बढ़ जाए) तो मूल्य वृद्धि Self perpetuting (स्वय बढ़ने वाली) वरन् self-liquidating (स्वय नष्ट होने वाली) होगी. मूल्य नीति को रोजगार, उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि मे सहायक होना चाहिए

वास्तव में कम-विकसित देशों मे धीरे-धीरे बढ़ने वाला मूल्य स्तर चाहिए. मूल्य नीति का प्रमुख अग गरीब जनता के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओ के मूल्यो को नियन्त्रित रखना हैं. अगर देश मे मूल्य वृद्धि ऐसी विनियोजन के कारण है जिसका फलदायक काल लम्बा समय बाद शुरु होता है तो देश मे उतनी मात्रा में cash holdings बनना चाहिए.

कम-विकसित देशों में मूल्य वृद्धि की एक प्रवृत्ति ही होती है और यह जब तक चलती रहती हैं जब तक कि देश take-off stage को छोड़कर देश self-sustaining व self-accelerating (निरन्तर विकास) की अवस्था मे नही पहुँच जाता.

1. पाठको ने इस सम्बन्ध मे (i) पूँजी निर्माण, (ii) मौद्रिक नीति तथा (iii) राजकोषीय नीति के अन्तर्गत इस विषय पर पढा है इसको हम Inflation and Growth के रूप में भी अध्ययन कर सकते है.
2. Dr. V. K. R. V. Rao . Price Policy and Economic Development in Essays in Economic Development

अध्याय : 8

राज्य का विकास में योगदान : राज्य प्रवर्तित विकास

The Role of Government in Growth Sponsored Growth

I. प्रस्तावना

II. राज्य के विकास मे प्रत्यक्ष व सक्रिय योगदान की आवश्यकता :

(i) निर्बाधवादी नीति के दोषो को दूर करना.

(ii) विकास की नींव रखना.

(iii) सामाजिक कल्याण के लिए.

III. राज्य द्वारा किए जाने वाले आवश्यक कार्य :

(i) न्याय व व्यवस्था.

(ii) पूंजी निर्माण करना

(iii) कृषि में क्रान्ति लाना
(iv) साधनो का अनुकूलतम प्रयोग
(v) जनसख्या सरचना सुधार
(vi) श्रम बाजार सगठन तथा साधनों में समन्वय
(vii) आवश्यक मात्रा में विनियोजन
(viii) उचित मौद्रिक, राजकोषीय व मूल्य नीति
(ix) विदेशी व्यापार व विनियोजन को प्रोत्साहन
(x) पिछडे वर्गों व इलाको की समस्या
(xi) महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन

IV राज्य के योगदान की सीमाएँ

Select references

1 The role of Government Herman Finer, Ch X Willia mson & Bultrick op cit
2 Tokyo Conference on Growth A Paper on 'Sponsored Growth A challenge to democracy
3 D B Singh op cit ch XVI
4 A H Hansen Public Enterprise and Economic Development
5 Bayer and Yamey ch XI General Appraisal of the Role of Govt in influencing Economic Development and ch XII on function of Government op cit
6 A Lewis op cit ch VII Govt
7 Kindleberger op cit 125-132
8. Meier & Baldwin op cit p 366-372

अध्याय : 8

राज्य का विकास में योगदान : राज्य प्रवर्तित विकास

The Role of Government in Growth Sponsored Growth.

I. प्रस्तावना

"समझदार व्यक्ति इस वाद-विवाद मे नही पडते कि आर्थिक विकास राज्य के कार्यो से होता है अथवा निजी क्षेत्र की रुचि व उत्साह से होता है. वे जानते है कि आर्थिक विकास दोनो के सहयोग से होता है, वे तो केवल उसके समिश्रण की मात्रा के बारे मे ही विचार करते है राज्य अगर सही मात्रा मे सही कार्य करता है तो विकास होता है अगर राज्य गलत कार्य करता है या सही कार्यो को ही बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा मे करता है तो विकास रुकता है"

—आर्थर ल्युस, (पृ० 377-408)

राज्य का योगदान कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए. इस सम्बन्ध मे अर्थशास्त्रियो मे बहुत मतभेद है कुछ अर्थशास्त्री जो साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव म है, राज्य को विकास की पूरी जिम्मेदारी सौपना चाहते है उनका विश्वास है कि आज के युग म किसी भी कम विकसित देशो मे आर्थिक विकास व आर्थिक कल्याण राज्य के द्वारा (सार्वजनिक उद्योगो के द्वारा ही) हो सकता है इसी मत के, कम उग्रवादी अर्थशास्त्री राज्य को मुख्य व निजी क्षेत्र को गौण स्थान देना चाहते है.

दूसरे मत के अर्थशास्त्री चाहते है कि राज्य कम-विकसित देशो मे Pioneering (नीव डालने का) कार्य करें तथा देश मे विकास की आधार शिला रखकर विकास क्षेत्र से निकल जाएँ. अन्य अर्थशास्त्रियो का मत है कि राज्य को निजी क्षेत्र को ही विकास कार्य सौंपना चाहिए. राज्य को उसे सहायता देना चाहिए या आवश्यकता पडने पर उसका नियमन करना चाहिए.

आज अर्थशास्त्री Gerschenkron के इस मत से सहमत हैं :

> 'विकास कार्यों को शुरू करते समय जो देश जितना अधिक पिछड़ा होता है, उसे उतना ही राज्य के कार्यों की आवश्यकता होती है."

Kindleberger का भी कथन इस संबंध में बहुत उपयुक्त है कि राज्य के या निजी क्षेत्र द्वारा विकास में महत्व का प्रश्न सद्धान्तिक नहीं है वरन् यह तो व्यावहारिक प्रश्न है. उनका कथन है

> 'जब जनता का या स्वयं निजी क्षेत्र का हित, निजी क्षेत्र के विकास से सिद्ध होता है, तो निजी क्षेत्र को ही कार्य करने देना चाहिए, उन क्षेत्रों में जिनमें निजी क्षेत्र, जन हित के कार्य को नही कर सकता जहाँ निजी क्षेत्र बाह्य मितव्ययिताओं का सृजन नही कर सकता वहाँ राज्य को कार्य कर खाई पाटना चाहिए"

वे इसे The Vacuum Theory of Government कहते हैं

II. राज्य के कार्यों की विकास मे आवश्यकता

औद्योगिक क्रान्ति के बाद विकास की असीमित सम्भावनाएँ सामने आयी. राष्ट्रीय आय कई गुनी बढने लगी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था ने सर्व-साधारण को भी राजाओं के समान धनी होने के अवसर दिए परन्तु यह सब होते हुए भी अप्रत्याशित समृद्धि के बीच अप्रत्याशित गरीबी उत्पन्न हुई. छोटे पैमाने के उद्योग तथा उससे सम्बन्ध आर्थिक स्वतन्त्रता समाप्त हो गई. एक ओर बहुत बडे पैमाने पर कारखाने तथा धन और सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण हुआ दूसरी ओर सारे आर्थिक कष्ट केन्द्रित हो गए. गन्दी बस्तियाँ, मन्दे, गरीब व अशिक्षित लोग तथा शोषित मजदूरों व छोटे किसान व नौकर पेशा लोगों की संख्या बढती गई.

कालान्तर में यह पाया गया कि स्वच्छन्द पूँजीवाद अधिक उत्पादन दे सकता है, तथा अधिक विकास की दर दे सकता है परन्तु इसमे सामाजिक व निजी हितों की एकरूपता नही रहती. राज्य के हस्तक्षेप के बगैर विकास में स्थिरता नही रहती, तथा साथ ही साथ बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी व गरीबी बनी रहती है.

समाजवादी अर्थशास्त्रियों के प्रहार, मार्क्स का दर्शन तथा समाजवादी देशों में विकास का अपना अलग ढंग यह सिद्ध कर चुका था कि राज्य के हस्तक्षेप बगैर या तो स्थिर व स्थायी विकास होगा ही नही या फिर इस विकास से सर्वांगीण कल्याण कदापि नहीं होगा.

1930 के वर्षों की महान् मंदी तथा केन्स की विचारधारा ने राज्य के हस्तक्षेप व प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता को औद्योगिक क्रान्ति के बाद योरोपीय देशों ने कम-विकसित देशों में उपनिवेश कायम किये और जब वे आजाद हुए तो वे विकसित देशों के मुकाबले में काफी पीछे रह गए थे इन देशों म साहसियो तथा विकास के लिए आवश्यक पूंजी, सगठन व प्रशिक्षित श्रम शक्ति सब का अभाव था इन देशों मे स्वतन्त्रता जिन नेताओं ने दिलाई, स्वाभाविक था कि जनता विकास का उत्तर-दायित्व, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर, उन्हे ही सौंपे ये ही नेता सरकार चलाने लगे और विकास मे राज्य के अधिकाधिक योगदान की स्थिति सामने आई कम-विकसित देशों में आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने, कृषि को सदियों पुराने पिछड़ेपन से निकालने, देश में बचत, पूंजी निर्माण व विनियोजन मे वृद्धि करने, देश को आर्थिक, राजनैतिक व सामरिक दृष्टिकोण से बलशाली बनाने, देश मे जन शक्ति व प्राकृतिक साधनो का पूर्ण प्रयोग करने, देश म वाह्य मितव्ययिताओं का सृजन करने, देश में विदेशी विनियोजकों व तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग लेने, देश में सतुलित विकास को उत्पन्न कर बढ़ावा देने, तथा देश में सर्वांगीण विकास व कल्याण करने के लिए कोई भी साहसी या साहसियों का समूह योग्य न पाया गया और यह सब कार्य राज्य की ही जिम्मेदारी बने

Dr. Bright Singh के शब्दो मे

> "The need to telescope a hundred years progress into a decade, call for the state inter vention in the maller of economic development"

आज के युग म राज्य अगर प्रत्यक्ष रूप मे योगदान न भी दे तो भी राज्य के नियमन व नियन्त्रण के कार्य ही इतने व्यापक हैं जितने कि कुछ सदियो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थ

आज के युग मे राज्य के कार्य पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए नहीं, वरन् पूंजीवाद को कायम रखने के लिए ही जरूरी हैं

III. राज्य से अपेक्षित कार्य जो विकासवर्धक है

विकास के लिए राज्य द्वारा अपेक्षित कार्य क्या है ? इसके उत्तर म सही मायनों का पूरा "विकास का अर्थशास्त्र" लिखा जा सकता है लेखक ने अपनी एक पूर्व पुस्तक मे लिखा था

> "The responsibility of the government cannot

be easily defined. Infact, it is not possible to delimit its functions."

फिर भी इस पुस्तक मे राज्य द्वारा अपेक्षित कार्य, जो विकास प्रक्रिया शुरू करने, उसे बनाए रखने तथा उसको सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से वाछनीय बनाने के लिए आवश्यक है, सूची व विश्लेषण नीचे दिए जा रहे है (इनमे से कुछ कार्यो पर पूरे अध्याय इसी पुस्तक मे है)

(i) न्याय व व्यवस्था, जिसमें आवश्यक उत्पादन कार्य सम्पादित हो सके :

अगर राज्य को देश मे विकास सम्भव बनाना है तो उसे देश में व्यवस्था, न्याय तथा ऐसे नियम बनाने होंगे जो सब नागरिकों को उत्पादन करने, अपनी मेहनत से कमाई गई पूंजी को बचाने, विनियोजित करने व सम्पत्ति बनाने में सहायक हो. इन्ही आवश्यक कार्यो में मुद्रा व्यवस्था तथा नाप-तौल व्यवस्था भी शामिल है. आधुनिक युग म दुर्भाग्य से आज इसकी सर्वथा कमी है समाजवादी विचारधारा तथा राजनैतिक मतभेद व गन्दी पदलोलुपता के कारण इन देशो मे आए दिन सैनिक व असैनिक क्रान्तियाँ होती रहती है तथा ताला बन्दी, हडताल व हिंसात्मक कार्यवाही चलती रहती है इससे न केवल निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता हतोत्साहित होते है वरन् स्वय राज्य के क्षेत्र को गम्भीर हानि होती है (जैसे भारत में हर झगडे पर रेल सम्पत्ति को हानि पहुँचायी जाती है) अगर निजी क्षेत्र को कायम रखना है तो उसे लाभ कमाने का अवसर देना होगा

(ii) पूंजी निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कार्य

जहाँ विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का 15% से 25-30% तक बचत कर लेते है वहाँ कम-विकसित देशो मे यह प्रतिशत 5 से 10 तक ही रहती है. इन देशो को कम से कम 15-20% बचत कर के पूँजी निर्माण करना ही होगा. राज्य को इस सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप मे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. प्रत्यक्ष रूप मे राज्य को देश मे

(i) मुद्रा प्रसार को रोकना होगा.

(ii) स्वय अपने अनावश्यक व अधिक व्यय को कम रखना होगा.

---

1. O.S. Shrivastava, op cit, p 47
2. See also : U N Measures for Economic Development in under developed countries
3. Vikrant : Reforms of Administration, planning and its implementation · Commerce Annual No 1966.

(iii) देश के सार्वजनिक उद्योगों को लाभ या कम से कम बगैर हानि के चलाना होगा, अन्यथा वे पूँजी उपभोग के साधन बन जायेंगे

(iv) देश म पर्याप्त मात्रा म कर लगा कर (सट्टो के लाभ, अनावश्यक व विलासिता उपभोग) स्वय पूँजी निर्माण करना होगा

(v) देश म बचतो को प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सस्थाओ को शुरू करना होगा तथा अपनी मौद्रिक व राजकोषीय नीतियो द्वारा बचत व पूँजी निर्माण को सम्भव बनाना होगा

श्री आर्थर ल्युस ने राज्य के विकास मे वृद्धि करने के लिए नौ कार्य बताया है, तथा उन्होने वे भी नौ कार्य बताए है जिनसे विकास रुकता है. वे कार्य निम्न है

(i) देश में सार्वजनिक सेवाओ को प्रदान करना
(ii) देश मे विकास की मनोवृत्ति का पनपाना.
(iii) आर्थिक सस्थाओ को विकास वर्धक बनाना
(iv) साधनो का प्रयोग बढाना
(v) धन के वितरण को विकास मे सहायक करना
(vi) मुद्रा का नियत्रण करना
(vii) आर्थिक उच्चावचनो को नियन्त्रित करना
(viii) पूर्ण रोजगार की स्थिति लाना, तथा
(ix) विनियोजन का स्तर बढाना

विकास म अवरोध डालनेवाले नौ कार्य निम्न है

(i) देश में न्याय, सुरक्षा व व्यवस्था को कायम न रख सकना
(ii) देश म जनता को लूटना या कर व्यवस्था का दोषपूर्ण होना व प्रशासन का भ्रष्ट होना
(iii) देश में एक वर्ग को दूसरे वर्ग का शोषण करने देना
(iv) देश म विदेशी विनियोजकों की सहायता न लेना या उन्ह कार्य न करने देना
(v) देश मे विनियोजन को अलाभप्रद ढग से करना
(vi) देश में बहुत अधिक निर्बाधवादी नीति अपनाना
(vii) देश में बहुत अधिक नियत्रण की नीति अपनाना
(viii) देश मे सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत अधिक व्यय करना तथा
(ix) देश में सार्वजनिक व्यय का फिजूल खर्ची होना

अप्रत्यक्ष रूप से निजी उत्पादनकर्ताओ के पूंजी निर्माण में सहायता देना चाहिए. इसके लिए

(i) पूंजी बाज़ार को मजबूत करना होगा.
(ii) साख निर्माण को सुलभ बनाना होगा.
(iii) कर सबधो विभिन्न छूटो से साहसियो को बचत व पूजी निर्माण में सहायता पहुँचाना होगा

(iii) देश में कृषि को आधुनिक ढग पर लाना पडेगा :

कम-विकसित देशो को सर्वप्रथम कृषि को विकसित करना होगा इसके विकास से ही औद्योगिक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र विकसित होगा, देश में राष्ट्रीय आय बढेगी. रोजगार वृद्धि होगी व स्थाई विकास की नीव पडगी. राज्य की सहायता के द्वारा ही कृषि विकास सभव ह राज्य को कृषि विकास के लिए

(i) भूमि सुधार करना होगा खेतो की मालकियत खेतीहर लोगो को देना होगा
(ii) देश की बहुत सी कृषि योग्य भूमि को पाटने का काम हाथ में लेना होगा
(iii) भूमि की चकबन्दी करना व करवाना पडेगा
(iv) भू-क्षरण रोकना होगा.
(v) कृषि के विकास के लिए साख व्यवस्था मजबूत करके कृषको को महाजनो के चगुल से छुडाना होगा.
(vi) उत्तम बीज, खाद कीटनाशक दवाइयाँ व यातायात सुविधाएँ प्रदान करना होगा.
(vii) कृषि विपणन सुधारने के लिए मण्डियो की स्थापना करनी होगी और गोदामो की सुविधाएँ प्रदान करनी होगी.
(viii) कृषि की उन्नत तकनीक कृषकों को Demonstration farms के द्वारा समझाना होगा.
(ix) भूमि प्रयोग की उपयुक्तता तथा अन्य मामलों के बारे में अनुसंधान करने होगे, तथा
(xi) कृषि मूल्यो को स्थिर रखने व आवश्यकतानुसार Price support देना होगा.

संक्षेप में राज्य को शायद स्वय कृषि करने को छोड कृषि के सबध में सब कुछ करना होगा.

विस्तृत वर्णन के लिए पूंजी निर्माण सबन्धी तथा कृषि अध्याय देखिए.

(iv) साधनो के (प्राकृतिक व मानवीय) अनुकूलतम व अधिकतम प्रयोग कराने में मदद देनी होगी :

हम देख चुके है कि किसी देश के विकास मे जितना महत्व प्राकृतिक साधनो के होने का नही है उससे अधिक उनके उचित व अनुकूलतम प्रयोग का है. राज्य का कर्तव्य होता है कि राज्य देश के प्राकृतिक साधनो की मात्रा व किस्म का आर्थिक तकनोकी सर्वेक्षण करे तथा उनके प्रयोग के लिए पर्याप्त पूजी व उचित तकनीक का प्रबन्ध करे. इन साधनो का बहुउद्देशीय प्रयोग कराने मे सहायता करे तथा देश में बाजार स्थिति के सर्वेक्षण मे सहायता करे साधनो का परिरक्षण Conservation का कार्य केवल राज्य ही कर सकता है राज्य का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि Vested interests अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम न्यूनता बनाए अर्थात प्राकृतिक साधनो का पूर्ण प्रयोग करे. देश मे इनके प्रयोग सम्बन्धी अनुसधानो को भी राज्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए इनके गलत प्रयोग पर राज्य को अधिक कर लेना चाहिए.

जैसा कि हम देख चुके है मानवीय साधन तो प्राकृतिक साधनो से भी अधिक महत्वपूर्ण है राज्य का कर्तव्य है कि वह देश मे पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करे. यह एक बहुत कठिन काम है कि कम-विकसित देश, जहाँ प्रायः जनसख्या भी तेजी से बढती है, पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकें. फिर भी श्रम गहन तकनीक अपना कर रोजगार के अवसर व रोजगार से आय बढाई जा सकती है. परन्तु दीर्घकाल मे (मेरे विचार में ३० वर्षो में) पूर्ण रोजगार की स्थिति पर पहुँच जाना चाहिए इस काल मे

(i) जनसख्या वृद्धि मे नियत्रण व

(ii) पूँजी निर्माण करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जाना चाहिए.

अधिक जनसंख्या वाले देश कुछ अधिक, व कम जनसख्या वाले देश इससे कम काल मे यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते है अगर सरकार यह न कर सकी तो बेरोजगार लोग सरकार बदल देंगे

(v) जनसंख्या संरचना सुधार '

विकास जनसाधारण के द्वारा, जनसाधारण के कल्याण के लिए किया जाता है विकास के लिए जनसख्या सरचना सबधी सुधारो मे राज्य का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा जिन कम-विकसित देशो मे जनसख्या का दबाव व वृद्धि की मात्रा कम है उन्हे इतनी गम्भीर समस्या का सामना नही करना पडता जितना कि उन देशो

इस सम्बन्ध मे प्राकृतिक साधनो व जनसंख्या सबधी अध्याय में विस्तृत वर्णन देखिए

की सरकार को करना पड़ता है जहाँ जनसंख्या वृद्धि भी अधिक है और जनसंख्या का दबाव भी अधिक है

स्वाभाविक रूप से इन देशो मे परिवार नियोजन सबधी प्रचार व उस सबधी सामग्री उपलब्ध कराना शायद राज्य का सबसे मुख्य कर्तव्य होगा Prof. S Enke ने अनुमान लगाया है कि कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन पर व्यय, अन्य किसी भी विनियोजन से, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने मे 100 गुना अधिक प्रभावशील है उदाहरणतया अगर जन्मदर को 40 प्रति हज़ार से घटाकर 35 प्रति हज़ार ले आया जाये तो इससे राष्ट्रीय आय मे ½ प्रतिशत वृद्धि होगी जिसके लिए बहुत अधिक विनियोजन आवश्यक होता राज्य का कर्तव्य इस दिशा मे यह होगा कि वह

(i) जनसख्या की जन्म दर मे, विशेष रूप से गरीब वर्ग की, भारी कमी लाएँ

(ii) देश मे स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रशिक्षण सबधी सुधार करें देश मे घनत्व सतुलन लाये

(vi) श्रम बाजार सगठित करें व उत्पादन के साधनो में समन्वय लाएँ :

श्रम ही उत्पत्ति का सबसे सक्रिय साधन है उसकी कुशलता वृद्धि से ही श्रम व पूँजी की उत्पादकता की वृद्धि होती है. राज्य को श्रम बाजार को सगठित करने मे सहायता देनी होगी. मजदूरी के चुकाने, कार्य के घटे व वातावरण नियमित करने, श्रमिको को कार्य पर लेने व निकालने, उनको मुआवजा देने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, देश मे रोजगार दिलाने वाले दफ्तर खोलने के कार्य को सम्पादन करना होगा देश मे औद्योगिक सघर्षो को निपटाने के लिए उचित सस्थाओ की स्थापना व उन्हे निपटाने के नियम बनाने होगे. इस सम्बन्ध में सबसे प्रमुख बात देश मे हड़ताल व तालाबन्दी को कम से कम रखना है. यह कम विकसित देशों के लिए विलासिता होगी. अधिक उत्पादन से ही श्रम को अधिक भाग मिल सकता है. दुर्भाग्य से, कम-विकसित देशो ने पहले ही समानता के लिए सघर्ष होने लगता है. हमको समृद्धि में समानता लाना चाहिए न कि गरीबी में समानता.

कम-विकसित देशो मे राज्य को उत्पादन के भिन्न-भिन्न अगो मे समन्वय भी लाना होगा. इन देशों मे Co-operant factors की कमी रहती है. अर्थात्

इस सबध मे आप 'कम-विकसित देशो की विशेषताओ' के अध्याय मे पढ ही चुके हैं.

Cf S. Enke . National Productivity Council, Annual Number, Economic Journal, march 1966

साहसियो, कुशल प्रशासको तथा कुशल मजदूरों की कमी रहती है इसकी पूर्ति
वृद्धि के लिए राज्य को सहायता करना चाहिए.

(VII) राज्य को देश में आवश्यक मात्रा में विनियोजन कराना चाहिए :

कम विकसित देशों मे बचत व विनियोजन मे समन्वय अपने आप नही होगा और
शायद पर्याप्त मात्रा मे भी न हो पाए. कम-विकसित देशो मे राज्य को कम से कम
7-10% वार्षिक विकास की दर को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाकर निजी व
सार्वजनिक क्षेत्रो को उसको प्राप्त करने की निश्चित जिम्मेदारियाँ बाँटना चाहिए.
राज्य को चाहिए कि वह दोनो क्षेत्रो को एक दूसरे के पूरक के रूप मे चलाएँ :
राज्य स्वय इन देशो मे Infra-structures मे या external economies
में (यातायात, संचार सुविधाएँ, शिक्षा व स्वास्थ्य विकास, शक्ति व सिचाई सुवि-
धाएँ आदि) विनियोजन करे. राज्य को ही देश मे आधार भूत (इस्पात, भारी
इन्जीनियरिंग, रासायनिक खाद आदि) उद्योगो की स्थापना करनी होगी कृषि व
प्राकृतिक साधनो के अधिकतम परीक्षण व प्रयोग मे भी राज्य को सहायता करनी
होगी.

निजी क्षेत्र को कर सबन्धी छूटें देकर तथा उन्हे अन्य सुविधाएँ देकर निर्यात वर्धक
व आयात प्रतिस्थापन्न उद्योगो मे विनियोजन करने को प्रोत्साहित करे राज्य को
चाहिए कि कुल विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय की 20% तक पहुँचा दे. राज्य
को अपने उद्योगो का सचालन लाभ या "न लाभ न हानि" के आधार पर करना
चाहिए. राज्य को, Herman Finer के शब्दो मे

> "Government may claim all mineral, power and water resources and the land for the Government and proceed by direct management "licensing to private firms or co-operatives" ...."No private economic corporation has ever been close to attaining such power to animate, direct, stimulate or narcoticize economic development. In addition to financing, Government can acquire funds by the sale of goods it produces, through power, transportation, communications, fuel and so on, specially in nationalized industries."

(VIII) राज्य उचित मौद्रिक, राजकोषीय व मूल्य नीति अपनाएँ :

कम-विकसित देशों में विकास बहुत मात्रा में राज्य की इन तीन नीतियों पर निर्भर रहता है. जैसा कि हम देख चुके हैं राज्य का मुख्य कार्य देश में संस्थागत बचतों में वृद्धि कराना, मुद्रा स्फीति व विस्फीति को नियंत्रित रखना, देश में साख का विस्तार तथा नियत्रण करना और साख की सुविधाओं को छोटे बड़े समस्त उत्पादनकर्ताओं को उपलब्ध कराना विदेशी विनिमय दर के उच्चावचन रोकना चाहिए, तथा देश में अमौद्रिक क्षेत्र को कम करके, मौद्रिक सस्थाओं को केन्द्रीय बैंक के अन्तर्गत लाना चाहिए

राजकोषीय नीति ऐसी होना चाहिए जो देश में बचतों, पूँजीनिर्माण व विनियोजन को प्रोत्साहन दे, विदेशी विनियोजन व निर्यात प्रोत्साहित करें, समानता लाने के साथ साथ देश में पूँजी सचय की प्रेरणा बनाए रखे तथा देश में विभिन्न प्रकार के करों की सरचना ऐसी रखे जो न्याय व उत्पादकता के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके. कर इतने अधिक भी न हों कि विनियोजनकर्ताओं को कार्य करना ही कठिन पड़ जाए. राज्य को ऐसी राजकोषीय नीतियाँ अपनाना चाहिए जिससे ऋण का भार कम रहे तथा सार्वजनिक व्यय विकास की नीव डाले, न कि मुद्रा स्फीतिका साधन बन जाए राज्य को प्रेरणादायक स्वतन्त्र मूल्य नीति को कार्यरूप होने की सुविधा देना चाहिए परन्तु आवश्यकता पड़ने पर मूल्य नियमन व नियत्रण भी करना चाहिए

(IX) विदेशी व्यापार व विदेशी विनियोजकों को प्रोत्साहन देना चाहिए :

कम-विकसित देश विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों में फँसे रहते हैं. राज्य एकदम तो इन देशों में विदेशी विनिमय का संतुलन पक्ष में नहीं कर सकता. इस सबध में राज्य को निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे :

(i) आवश्यक आयातों को होने देना तथा विलासिताओं के आयात को रोकना चाहिए

(ii) निर्यात वर्धक व आयात प्रतिस्थापन्न उद्योगों की स्थापना करे. कर सम्बन्धी छूटों, विदेशों में प्रदर्शनियों, सम्पर्कों, राजनैतिक व्यापार समझौतों से निर्यात में वृद्धि करें.

(iii) विदेशी मुद्रा के सट्टों पर कड़ा नियत्रण रखे.

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों से कम-विकसित देशों को अपनी निर्यातीत वस्तुओं में उच्चावचन रोकना चाहिए. निर्यात की मात्रा के साथ-साथ विविध वस्तुओं का निर्यात प्रोत्साहित करना चाहिए

पिछले तीन अध्यायों में विस्तार से अध्ययन हो ही चुका है

कम विकसित देशों के राज्यों को विदेशों व विदेशी संस्थाओं से ऋण व तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इस संबध में राज्य को विदेशी विनियोजकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए उन्हें समान अवसर देना चाहिए. देश में इनकी सम्पत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए. हाल के वर्षों मे भुगतान में समय की पाबन्दी का न होना, मुद्रा अस्थिरता, विनिमय नियन्त्रण, जब्त करने की धमकियों, भेद-भाव पूर्ण कर नीतियों व श्रम नियमों, राज्य की प्रतियोगिता आदि के कारण कम-विकसित देशों मे विदेशी विनियोजक हतोत्साहित हो रहे हैं राज्यों को इस सबंध में विदेशी विनियोजकों के विश्वास को बनाए रखना चाहिए.

(x) धन का न्यायोचित वितरण, पिछड़े वर्ग व इलाकों का विशेष ध्यान, श्रापत-कालीन सहायता :

राज्य देश मे धन व आय का वितरण कैसा रखे यह एक गम्भीर समस्या है. राज्य का कर्तव्य है कि वह समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के साथ-साथ आर्थिक प्रेरणा को बनाए रखे सही नीति यह होगी कि राज्य "समान व्यक्तियों में असमानता तथा असमान व्यक्तियों मे समानता न आने दे" राज्य को गैर कमाई आय को कम करना चाहिए परन्तु मेहनत से कमाई आय तथा साहसियों की आय को अधिक नहीं घटाना चाहिए साहसियों के लाभ पर कम व जमीदारों के लाभ पर अधिक कर लिया जाना चाहिए. नये उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए.

Lewis के शब्दों में

> "The less developed countries have awakened into a century where every body wishes to ride two horses simultaneously, the horse of economic equality and the horse of economic development. The U S. S R. has found that these two horses will not go in the same direction, and has, therefore, abandoned one of them. Other less developed countries will have to make their own compromises."[2]

हर कम-विकसित देश में कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के अनुपात में ज्यादा पिछड़े होते हैं अगर राज्य इनके विकास में दिलचस्पी न ले तो निजी क्षेत्र वाले इन क्षेत्रों मे

अगले अध्याय में इस सबध मे विस्तृत रूप से लिखा है

2. Lewis : op cit . p. 379-80.

आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी सुविधाओं की कमी से कभी विकास नहीं करेंगे कम विकसित देशों के राज्यों को इन देशों मे उद्योग खोलकर "Jobs to the men" नौकरियाँ ले जाना चाहिए

इन देशों की जनता लगभग जीवन यापन स्तर पर रहती है किसी भी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने की क्षमता उनम नही होती ऐसी अवस्था म वे केवल गरीब ही नही रहते वरन् भूखो मर जाते है राज्य का यह कर्तव्य है कि अगर देश की उत्पादन क्षमता का वृहद पैमाने पर नुक्सान हो तो उसकी वह क्षति पूर्ति करे

(xi) सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं में सुधार किए जाएँ, जिससे वे विकास में सहायक हो ·

विकास मनुष्यो के बदलते हुए आचरण व मान्यताओं के कारण भी होता है. कम-विकसित देशों की जनता का बड़ा भाग पिछड़ा हुआ है और वह विकास करने का न तो इच्छुक दीखता है न प्रयत्न करता है और न क्षमता रखता है. राज्य को देश में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का विकास करना चाहिए. शिक्षा के विकास से रूढ़िवादिता व परम्परावादिता कम होती है विकास की इच्छा बढ़ती है, न्याय व शान्तिप्रियता की ओर रुझान होता है, इमानदारी, कर्तव्यपरायणता, नियमितता, कार्यक्षमता व उत्पादकता बढ़ती है

इन देशों मे धर्मान्धता (धार्मिकता नही) कम करना चाहिए आधुनिकता को अपनाना राज्य के प्रसार व प्रचार से ही सभव होगा 'सक्षेप मे' राज्य के महत्व को हम निम्नलिखित शब्दो में व्यक्त कर सकते है

> "Like the population's physical health, its literacy and knowledge and its mores of honesty and alertness, Governments enterprize, improved and uncorrupt administration is an "Intangible capital " Government should be objective, Requirements of economic development require that personal,religious, 'partisan' ' ideological prejudices be ignored, or indeed suppressed "
>
> (Herman Finer).

इस पर प्रथम अध्याय भी देखिए.

Finer आगे लिखते हैं :

"राज्य के द्वारा आर्थिक विकास राज्य द्वारा सही सगठन व निर्णयो पर निर्भर है. राज्य को भी अपने कार्यो मे विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, उसके प्रशासन मे उचित कार्य-व्यवस्था होना चाहिए Proper departmentalization देश मे महत्वपूर्ण बातें केन्द्रीय स्तर पर निर्णित होना चाहिए जबकि उनको कार्यान्वित करने मे विकेन्द्रित कार्यकलाप की भी सुविधा होनी चाहिए."

IV. राज्य के योगदान की सीमाएँ

राज्य का विकास प्रक्रिया में कहाँ तक योगदान होना चाहिए ? क्या उसको आवश्यक कार्य करके हट जाना चाहिए ? राज्य वास्तव मे विकास प्रक्रिया से पूरी रूप से नही हट सकता. अगर वह पहले विकास की आधार शिला रखेगा तो बाद मे उसे देश मे आर्थिक स्थायित्व के लिए कार्य करना पडेगा :

राज्य का प्रशासन अगर भृष्ट व अकर्मण्य है तो देश की अर्थव्यवस्था मे निजी क्षेत्र व राज्य दोनो शोषण करेंगे Tokyo conference मे इस सबध मे निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया था

"राज्य के विकास मे योगदान के बडे खतरे भी हैं उसकी अकुशलता व भ्रष्टाचार से निजीक्षेत्र का गला घुट सकता है वास्तविक खतरा तो यह है कि अगर राज्य की नीतियाँ कारगर नही होती तो वह अपनी नीतियो को मनवाने में तानाशाही का कार्य करेगा.

उदाहरणतया .

बहुत अधिक कर लगाएगा, सामूहिक कृषि थोपेगा, श्रम सघो को भी निष्क्रिय कर देगा और देश मे पूर्णरूप से स्वतन्त्रता नष्ट कर देगा."

अध्याय : 9

पूँजी-निर्माण व विकास

Capital-Formation & Growth

I प्रस्तावना .

पूंजी-निर्माण का अर्थ.

II. पूंजी-निर्माण को नापने की रीतियां :

(a) Commodity flow approach
(b) The expenditure approach.
(c) Aggregate savings approach.
(d) Changes in physical stock.

पूंजी-निर्माण नापने की कठिनाइयाँ व संतुलित मूल्याकन.

III. विकसित व कम-विकसित देशो मे पूजी निर्माण : कम-विकसित देशों मे पूजी-निर्माण कम होने के कारण ·

IV. पूंजी-निर्माण रीतियां

(a) बचत व पूंजी निर्माण विकसित व कम-विकसित देशो में बचतो की मात्रा व सरचना, बचतो को बढाने के उपाय, बचतों का विनियोजन.
(b) अतिरेक जनशक्ति का प्रयोग व पूंजी-निर्माण.
(c) मुद्रा स्फीति व पूंजी-निर्माण
(d) पूंजी-निर्माण व राजकोषीय नीति.
(e) पूंजी-निर्माण व उपभोग में कमी.
(f) साधनों का पूर्ण प्रयोग.

V. पूंजी-निर्माण व विकास . सीमाएँ, महत्व तथा "झिरन" Leakages :

अध्याय : 9

पूँजी-निर्माण व विकास

Capital Formation & Growth

I प्रस्तावना

Meaning of Capital-Formation पूजी-निर्माण का अर्थ

जैसा कि सर्वविदित है, धन का वह भाग जो और अधिक आय या धन उत्पन्न
करने के कार्य आता है वह पूजी है पूंजी म वृद्धि ही पूंजी-निर्माण होता है पूजी-
निर्माण के लिए बचतो मे वृद्धि की आवश्यकता है और इन बचतो का विनियोजन
आवश्यक होता है सामान्यत (सकुचित अर्थ मे) पूँजी-निर्माण का अर्थ मशीनो
गृहो, कारखानो मे वृद्धि तथा Inventories accumulation से होता है.
Inventories का अर्थ कच्चा माल, बने सामान तथा उत्पादन के अन्य
साधनो की मात्रा में वृद्धि से होता है. उत्पादन के कार्य मे आने वाली सम्पत्ति मे
वृद्धि ही पूंजी-निर्माण समझी जाती है, उपभोग के कार्य मे आने वाली सम्पत्ति
में वृद्धि पूंजी-निर्माण नही होती.

पूंजी-निर्माण का यह सकुचित रूप हुआ. वास्तव मे देश मे शिक्षा, स्वास्थ्य,
ट्रेनिग आदि की सुविधाओ के विस्तार से भी देश मे उत्पादन क्षमता मे वृद्धि
होती है अत यह भी पूंजी-निर्माण कार्य है पूंजी-निर्माण का अर्थ भौतिक साधनो
में विनियोजन से ही नही लिया जाता, वरन् मानव साधनो मे भी विनियोजन से
होता है.

पंजी-निर्माण का विश्लेषण हम दो रूप से करते है . Gross capital for-
mation या कुल पूंजी-निर्माण तथा Net capital formation या शुद्ध
पूंजी-निर्माण कुल पूंजी-निर्माण का अनुपात हम कुल राष्ट्रीय आय मे से पूंजी-
निर्माण के रूप में आकते है जबकि विशुद्ध पूंजी-निर्माण को आकने के लिए हमको
पूंजी की घिसावट निकालनी पडती है वास्तव में शुद्ध पूजी-निर्माण मे वृद्धि अधिक
महत्वपूर्ण होती है, परन्तु इसको आकना अधिक कठिन होता है सक्षेप में

"Domestic capital formation consists of such

domestic output and imports which are neither exported nor consumed by household and by general government but result in the additions to the total stock of capital goods in the country"

II Methods of Measurement or Estimation:
पूंजी-निर्माण की मात्रा को नापने की विधियाँ ·

सामान्यतया पूँजी-निर्माण मे वृद्धि की मात्रा 4 रूप से आकी जाती है ये चार रीतियाँ है

(a) Commodity flow approach वस्तु उत्पादन रीति.
(b) Expenditure approach व्यय गणना रीति.
(c) Changes in the physical stock of capital goods approach पूँजी की भौतिक मात्रा मे परिवर्तन गणना रीति तथा
(d) Aggregate savings approach कुल बचतो की गणना रीति

(a) Commodity flow approach : **वस्तु उत्पादन रीति :**

इस रीति मे पूँजी निर्माण नापने के लिए देश में समस्त वस्तुओ के उत्पादन तथा आयात का जोड़ लगा लेते हैं और उसमे से उपभोग व निर्यात घटा लेते हैं तथा बचा हुआ भाग उस देश का पूंजी-निर्माण माना जाता है.

इस प्रकार से पूँजी निर्माण की मात्रा आँकने के लिए उपभोग की मात्रा आँकने मे काफी कठिनाई होती है, इतनी कठिनाई निर्यात व आयात की मात्रा आँकने मे नही होती

(b) The Expenditure Approach : व्यय गणना रीति :

इस रीति के अन्तर्गत मशीन, भवनों तथा अन्य उत्पादक सम्पत्तियों (Productive construction and equipment) पर व्यय को आँकते है. इसमे हम अन्य सम्बन्धित व्ययो (यातायात, तथा अन्य व्यय) भी शामिल कर लेते हैं. इन आँकड़ो को हम औद्योगिक संस्थानो या व्यापारिक संस्थानो की लेखा-तलपट (Balance sheets) से पता लगा लेते हैं. भिन्न-भिन्न औद्योगिक संस्थानो की लेखा रीतियाँ जहाँ भिन्न होती हैं वहाँ पूँजी आँकने में अन्तर पड जाते हैं और इस प्रकार से पूजी-निर्माण की मात्रा मे अन्तर आ जाता है.

(c) Changes in the physical stock of capital goods

पूँजी की भौतिक मात्रा में परिवर्तन गणना रीति :

इस रीति के अन्तर्गत देश में वर्ष के शुरू व अन्त मे पूंजी की मात्रा आँकी जाती है और अगर साल के अन्त में पूँजी की मात्रा बढी हुई रहती है तो उतनी मात्रा मे पूँजी निर्माण माना जाता है. परन्तु पहले इसमें से घिसावट, पुरानेपन की हानि व मूल्य परिवर्तनो के अन्तर घटा दिए जाते है तब शुद्ध पूँजी-निर्माण का पता चलता है. (मूल्यो के परिवर्तन का आशय यह है कि माना साल के शुरू मे एक मशीन 1 लाख की थी और साल के अन्त मे उसका मूल्य बढकर 1,20,000 रु० हो गया तो वास्तविक पूजी तो वही रही केवल मौद्रिक रूप से बढ गई इसको हम पूंजी-निर्माण नही मानते) फिर कम-विकसित देशों में पूँजी-बाजार के समुचित रूप से उन्नत न होने के कारण इस प्रकार का अनुमान लगाना ठीक नहीं है.

(d) Aggregate savings approach - **कुल बचतों की गणना रीति :**

इस रीति में देश मे एक वर्ष में होने वाली कुल बचतों का अनुमान लगाया जाता है और यह मान लिया जाता है कि पूजी-निर्माण भी इतनी ही मात्रा मे हुआ है. यह बात इस मान्यता पर आधारित है कि बचतें व विनियोजन बराबर हो जाएंगे. कम-विकसित देशो मे न तो ये अनुमान ठीक रूप से लगाए जा पाते है और न इस रीति की मान्यताएँ सही होती है.

कम-विकसित देशो में पूंजी निर्माण नापने में सामान्य कठिनाइयां :

(1) कम-विकसित देशो मे पूँजी-निर्माण की मात्रा का सही अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन होता है. आयात व निर्यात सम्बन्धी अनुमान तो ठीक से या लगभग ठीक से लगाए जा सकते है परन्तु देश में उत्पादन के अनुमान लगाने मे बहुत कठिनाइयां सामने आती है. कम-विकसित देशों में बड़े पैमाने के उद्योगो के उत्पादन का अनुमान तो लग जाता है परन्तु असंख्य छोटे पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं का अनुमान नही लग पाता. इससे Commodity flow approach को ठीक

See 1. U N Concepts and Measurements of Capital Formation 1953.

2. S.G. Tiwari "Concept and Measurement of Capital Formation," Unpublished Paper of Vikram University Conference on Capital Formation at Bhopal in 1966.

3. D. B. Singh : op. cit

से नही अपना पाते, क्योंकि फिर यह भी ठीक-ठीक पता नही होता कि इस उत्पादन में से कितना भाग निर्माण कार्य मे लगा है.

(ii) कम-विकसित देशो मे पूँजीगत निर्माण कार्यो में मजदूरी आदि के अनुमान भी ठीक से नही लग पाते, क्योंकि बहुत से स्थानो में मजदूरी नगद के स्थान पर वस्तुओ के रूप मे दी जाती है.

(iii) ग्रामीण क्षेत्रो में बहुत सा निर्माण कार्य अवैतनिक आधार पर किया जाता है, अर्थात बहुत सा निर्माण कार्य परिवार के लोग मिलकर ही कर लेते हैं इस प्रकार के निर्माण कार्यो का अनुमान ही लगाया जा सकता है

iv) सबमे बडी कठिनाई तो Inventories के पता लगाने मे आती है. अर्थात कच्चे, अर्ध बने व बने हुए माल के स्टाक का अनुमान लगाना कठिन होता है (Inventories मे वृद्धि भी पूजी-निर्माण होता है) Inventories का सही मूल्याकन तो विकसित देशो में भी कठिन होता है कम-विकसित देशो में तो यह बहुत ही अधिक कठिन होता है.

(v) पूंजी-निर्माण को नापने के लिए Capital goods पूँजी गत वस्तुओ, Parts of capital goods (पूंजी गत वस्तुओ के भाग) का अनुमान तो किसी प्रकार से लगा भी लिया जाये तो partly capital goods अर्थात ऐसी वस्तुएँ जिनका उपभोग भी हो सकता है तथा जिनको उत्पादन कार्य मे भी ले लिया जा सकता है, का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है

(vi) कम-विकसित देशो वचतो का बडा भाग घरेलु बचतो से प्राप्त होता है और इनका अनुमान नही लग पाता क्योकि बहुत सी बचतें सस्थागत नही होती

पूजी-निर्माण को सही-सही रुप से आकने के सम्बन्ध में बहुत सी सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ भी है (Concepteral problems), जो इस प्रकार से है :

(i) कम-विकसित देशो मे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे जब assets या सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता है तो इसके पूर्ण अनुमान मौजूद नही रहते.

(ii) भूमि, जगल आदि प्रकृतिदत्त मुफ्त के अनुदान है इनको पूंजी नही माना जाता परन्तु इनम उनति करने को पूँजी-निर्माण कार्य मानते है. व्यक्तिगत रूप से भूमि को खरीदना पडता है और पूंजी मानी जाती है परन्तु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उसे पूंजी नही माना जाता है.

(iii) किसी भी पूँजीगत वस्तु में सुधार कार्य (Repairs) को पूँजी निर्माण नहीं माना जाता क्योंकि इसमें केवल पूँजी की कार्यक्षमता बनी रहती है. उसमें उन्नति नहीं होती. परन्तु बहुधा ऐसे सुधार भी हो जाते हैं जिनसे पूँजी की कार्यक्षमता या कार्यकाल में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार के अन्तरों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाता और इससे पूँजी-निर्माण को सही-सही रूप से नहीं जाँच पाते कम-विकसित देशों में तो Repairs की मात्रा का ही पता नहीं रहता

पूँजी निर्माण का सन्तुलित मूल्यांकन :

कम-विकसित देशों में पूँजी-निर्माण का कोई एक ही तरीका संतोषजनक नहीं हो सकता, फिर भी सबसे पहले Commodity flow approach का अपनाना उचित रहता है तत्पश्चात विकास-कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए देश में समस्त उत्पादक कार्य हेतु निर्माण कार्य (मकान, कारखाने, मशीनें, भूमि विकास, भूमि को पाटना, मेड़ें बाधना, कुएँ खोदना, सिंचाई सुविधाएँ बढ़ाना, बागान लगाना, जंगलों का विस्तार, सड़कें डालना, रेलें तथा अन्य यातायात साधनों में वृद्धि, संचार साधनों में वृद्धि तथा शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि) को आंकना पड़ता है संक्षेप में यह इस प्रकार से आंक सकते हैं :

1. निम्नलिखित में अचल पूँजी-निर्माण	2. निम्नलिखित में स्टाक वृद्धि
(i) कृषि, जंगल, मछली पालन.	(i) कृषि, जंगल व मछली पालन
(ii) खानों	(ii) खानों.
(iii) उद्योगों में	(iii) उत्पादन कार्य में लगे पशु
(iv) निर्माण कार्यों में,	(iv) उद्योगों, निर्माण कार्यों.
(v) बिजली, गैस तथा पानी वितरण	(v) थोक व फुटकर व्यापार
(vi) यातायात, संचार तथा storage	(vi) अन्य उत्पादन कार्यों में
(vii) थोक तथा फुटकर व्यापार.	
(viii) बैंक, बीमा तथा real estates	
(ix) सार्वजनिक प्रशासन.	
(x) आवश्यक सेवाएँ.	

III Low Levels of capital formation in under developed countries कम-विकसित देशो मे पूँजी निर्माण की कमी .

कम विकसित देशो में पँजी निर्माए की मात्रा विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है यह बात निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो सकती है यह तालिका 1959-61 मे पूँजी निर्माण की Range दर्शाता है

Gross capital formation as a percent of gross domestic product.	Countries
35—45%	जापान (44), यूगोस्लाविया (37).
30—35%	ब्रिटिश गुयाना (33), नार्वे व फिनलैंड.
25—30%	बारबेडॉस, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, प०जर्मनी, ट्रिनीडाड, इजराइल, ग्रीस तथा अलजीरिया
20—25%	प्यूर्टियोरिको, इटली, आइसलैंड, स्वीडेन, आस्ट्रेलिया, स्वीटजरलैंड, फारमोसा, डेन्मार्क पुर्तगाल, कोलबिया, कनाडा
15—20%	फ्रास, जमाइका, लग्जेम्बर्ग, रोडेसिया घाना, पीरू, ब्राजील, सूडान, थाईलैंड, स्पेन, वेनेज्येला, वेल्जियम, यू० एस० ए०, यू० के०, पनामा, आइरलैंड, बर्मा, केन्या.
10—15%	टगानियाका, इक्वेडार, लका, नाइजीरिया, होन्डुरास, ग्वाटेमाला, युगान्डा, आइरलैंड, मलाया.
5—10%	भारत, चिली, फिलीपीन्स, परागुए

U. N. Statistical Year Book 1963.

Quoted from Kindleberger : op. cit : p. 96.

कम पूंजी-निर्माण के कारण :

कम पूंजी निर्माण के कारणों के विश्लेषण के लिए किसी महत्वपूर्ण खोज की आवश्यकता नही है. ये कारण तो सर्वविदित हैं

1 सर्वप्रथम कम पूंजी निर्माण इन देशो मे राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय व बचत के निम्न स्तर के कारण है इन देशो मे विश्व की 63% जनसख्या रहती है और विश्व की केवल 12% आय प्राप्त करती है एक तो यहाँ बचतें ही कम है और दूसरे जो बचतें है वे जमाखोरी (Hoarding) के रूप मे अधिक होती है और पूंजी निर्माण कम होते हैं जैसा कि हम देख चुके हैं. इन देशो मे कम बचतों व कम पूजी निर्माण का दुष्चक्र चलता है पूर्ति की ओर से कम पूंजी से कम विनियोजन होता है, इससे कम उत्पादकता होती है, कम रोजगार होता है, इससे उत्पादन स्तर व राष्ट्रीय आय कम रहती है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है. कम-विकसित देशो मे उपभोग क्षमता अधिक होने से बचते कम रहती है और कम पूंजी-निर्माण होता है.

2 माँग की ओर से कम माँग के कारण (प्रभावशील माँग की मात्रा का कम होना व उपभोग क्षमता का अधिक होना साथ-साथ चलता है) विनियोजन भी कम होता है और पूंजी की माँग भी कम होता है.

3. कम-विकसित देशों मे ब्याज की दर अधिक होती है इसका मुख्य कारण इन देशों में बचतो की कमी तथा उपभोग के लिए उधारी की माँग की अधिकता होती है परन्तु इससे विनियोजन हतोत्साहित होता है और पूंजी निर्माण कम होता है

4 कम-विकसित देशो मे निम्न आय के कारण शिक्षा के स्तर तथा जीवन स्तर नीचा रहता है. इस कारण बाजार सकुचित रहते हैं और इस कारण भी पूजी-निर्माण कम रहता है.

5 कम-विकसित देशो मे बचतें न केवल कम होती हैं वरन् उनमे से अधिक भाग सस्थागत नही होता. बचतो को सोना, भूमि, और सट्टो मे लगा दिया जाता है इस कारण भी पूँजी-निर्माण कम रहता है

6. कम-विकसित देशो मे बढती हुई आय के परिणाम स्वरूप उपभोग क्षमता की अधिकता के कारण, बहुत अधिक भाग व्यय कर दिया जाता है इन देशो मे demonstration effect expenditure (अच्छी व विलासिताओ

References cited in previous chapters.

की वस्तुओं पर नकल व्यय) बहुत व्यय हो जाता है सामाजिक रीतिरिवाजों पर भी बहुत अनावश्यक व्यय कर दिया जाता है.

7 कम-विकसित देशो म साहसियों की नितान्त कमी रहती है. अगर साहसी कुशल, सूझ-बूझ वाले तथा प्रतिस्पर्द्धा रखनेवाले होते हैं तो वे स्वय पूँजी खीच लेते है.

IV. Methods of Capital Formation : पूजी-निर्माण रीतियाँ

पूँजी-निर्माण बचतो का परिणाम होता है बचतो की वृद्धि की रीतियाँ ही पूँजी-निर्माण रीतियाँ है, बशर्ते कि इन बचतो को उत्पादक कार्य में लगाया जा सके कम-विकसित देशों से हम बचतों के बारे म अध्ययन करेंगे तथा फिर पूँजी-निर्माण की रीतियों का अध्ययन करेंगे. पूंजी-निर्माण की मुख्य रीतियाँ यह हैं :

(i) बचतों की सस्थागत करना

(ii) अतिरेक जनशक्ति के प्रयोग से पूँजी-निर्माण (नवर्स व ल्युस का थीसिस)

(iii) मुद्रा स्फीति फैलाकर या वास्तविक मजदूरी गिराकर पूँजी-निर्माण (मौद्रिक व राजकोषीय नीति का सहारा लेकर)

(iv) राजकोषीय नीति का प्रयोग व पूँजी-निर्माण अर्थात् राज्य द्वारा सामूहिक बचतो का करना.

(v) उपभोग में कमी करके पूँजी-निर्माण

(vi) साधनो का पूर्ण प्रयोग करके पूँजी-निर्माण

(A) Savings, Capital Formation and Growth : बचत, पूंजी निर्माण तथा विकास.

1. विकसित व कम-विकसित देशो में बचतें :

कम-विकसित देशो में विकसित देशों के मुकाबले मे बचतें न केवल कम रहती हैं बल्कि उनमे स्थिरता भी नही रहती निम्नलिखित तालिका से विकसित व कम-विकसित देशो की सापेक्षिक स्थिति की तुलना की जा सकती है.

Leveles of Gross and Net Domestic Saving 1950–59
(percent of gross domestic product)

High Income Countries

देश	Domestic Savings	
	Gross	Net
जापान	28·7	21·1
नार्वे	27·1	17·2
फिनलैंड	26·7	21·7
प जर्मनी	26·3	17·2
आस्ट्रेलिया	26·1	20·2
नीदरलैंड	25·7	15·9
कनाडा	22·5	11·4
न्यूजीलैंड	22·5	15·9
आस्ट्रिया	20·4	13·3
इटली	19 5	10·6
यू एस ए	18 6	9·9
डेनमार्क	18·5	12·4
फ्रान्स	18·4	9·1
बेल्जियम	17 6	8·0
यू. के.	15·2	7·2

Low Income Countries

देश	Domestic Savi	
	Gross	Net
रोडेसिया व न्यासालैंड	20	14
वेनेज्येला	24	16
कांगो	24	16
जमाइका	12	5
प्यूरटोरिको	2	4
अरजेन्टिना	18	8
बर्मा	20	14
स्पेन	15	8
कोलम्बिया	18	9
ग्रीस	9	4
ब्राजील	15	10
इराक	17	13
टर्की	12	8
लंका	11	9
चिली	8	1
फिलीपीन्स	7	2
इन्डोनेशिया	5	2
भारत	—	7

References :

All references cited before with particular reference to Dr. D. Bright Singh's · op. cit : ch. vi and Dr. (Miss) Ishrat Z. Husain's op. cit : ch. ix.

World Economic Survey 1960; I

समीक्षा :

अधिकांश कम-विकसित देशों में बचते 10% से भी कम है जबकि अधिकांश विकसित देशो म बचतें 20% तक रहती है कुछ देशो में बचते कम अवश्य हैं परन्तु राज्य व अन्य सस्थागत बचतो में वृद्धि हुई. उधर कुछ कम विकसित देशो में जो अधिक बचते है वह विशेषरूप से विदेशी विनियोजको की बचतो की अधिकता के कारण रहा है

विकसित देशो म बचतो का प्रतिशत कम विकसित देशो के अनुपात मे अधिक अवश्य है परन्तु इन देशा में आय वृद्धि के साथ साथ बचतो में वृद्धि नही हुई है Simon kuznets Modigliani, W A Lewis, Dusenberry आदि ने इस बात के कारणो का अध्ययन किया और कई कारण बताए. (सामान्यतया आय बढने के साथ-साथ बचतें बढना चाहिए) इन्होने जो कारण बताए वे इस प्रकार है

(i) इन देशो म शहरीकरण के साथ साथ माँग बढती जाती है

(ii) इन देशो में नई-नई वस्तुएँ या उनके नए नए मॉडल निकलते हैं और Demonstration effect के कारण (नकल करने की भावना) उपभोग में कमी नही आती

(iii) इन देशा मे real profits वास्तविक लाभ कम हो रहे है और वास्तविक मजदूरी बढ रही है

(iv) इन देशो में औसत आयु बढने से वृद्धो की सख्या मे वृद्धि होती है और ये व्यक्ति dissavers या बचतो को खर्च करने वाले होते है.

विकसित देशो में बचते व विनियोजन अलग-अलग व्यक्तियो द्वारा की जाती है इसलिए वे शायद ही कभी बराबर हो पाते है स्वतन्त्र मूल्य व्यवस्था उन्हे एक स्तर पर नही ला पाती इसलिए जब कभी बचतें अधिक व विनियोजन कम रहता है तो मुद्रा विस्फीति व बरोजगार फैलता है तथा भुगतान सन्तुलन सुधरता है और अगर विनियोजन अधिक होता है तो मुद्रा स्फीति फैलती है और भुगतान सतुलन सबधी सुधार हो सकता है (दीर्घकाल में यह नही होगा).

कम विकसित देश :

कम विकसित देशो मे जहाँ अधिक बचतो की आवश्यकता है वहाँ बचतें कम हैं. समस्त कम विकसित देश 1950 मे अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 5% भाग

बचत करते पाये गए लेटिन अमेरीकी कुछ देशों मे बचत 10 व 12% तक हो जाती है परन्तु एशिया व अफ्रीका के कई देश तो 5% मे भी कम बचत कर पाते हैं. एशिया में औसतन प्रति व्यक्ति बचत $2 डालर प्रति वर्ष रहती है जबकि न्यूजीलैंड मे यह बचत $125 से भी ऊपर रही. 1950 में न्यूजीलैंड में एशिया के अनुपात में केवल 1/600 भाग जनसंख्या थी, परन्तु बचतो मे उसकी बचतें एशिया की बचतों का 1/10 भाग ही थी.

कम विकसित देशो की बचत सम्बन्धी आधुनिकतम जानकारी का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बहुत से कम-विकसित देशो में बचतो की प्रतिशत घट रही हैं. अधिकाश कम-विकसित देशों मे सार्वजनिक व्यय के बढने तथा करो सम्बन्धी आय उतनी न बढने के कारण राज्य की बचते कम हो रही हैं निजी क्षेत्र में छोटे व्यापारी या कम आय पाने वाले व्यक्तियों की बचतें भी मुद्रा स्फीति के भार से कम हो जाती है. लागतो मे वृद्धि, मजदूरी दरों मे वृद्धि, करो में वृद्धि आदि से Corporate क्षेत्र (कम्पनी क्षेत्र) मे भी बचतें अपेक्षित दर से नहीं बढी.

(अगले पृष्ठ 448 पर टेबिल देखिए).

गलत प्रयोग :

बचतो का गलत प्रयोग भी बहुत होता है. सामाजिक रीति-रिवाजों, सोना, चाँदी के संचित करने, भूमि के सट्टो मे भी बचतो को लगा देते है राज्य भी आवश्यकता से अधिक बडी इमारतो या सडको पर व्यय करने लगती है. उदाहरणतया इंडोनेशिया में जहाँ राष्ट्रपति सुकर्ण के शासन के अन्तिम वर्षो मे बेरोजगारी व मँहगाई चरम सीमा पर थी, वहाँ उनका शासन विश्व की सबसे बडी मसजिद तथा खेल के स्टेडियम आदि बनाने में व्यस्त था.

एशिया में, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, लका, नेपाल आदि मे जेवरो में बहुत धन लगा देते है. भारत में अनुमानत विश्व का 7% सोना तथा 26% चाँदी संचित है. भारत में आजकल अनुमानत [1] हर वर्ष 50 से 100 करोड रु० का सोना चोरी छिपे लाया जा रहा है और आज भारत में 3000-4000 करोड रु० का सोना होने का अनुमान है.

1. देखिए 'धर्मयुग' में Anti-Smuggling operations के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मिरान्डा का लेख : 1969 जून के दूसरे हफ्ते का धर्मयुग.

Increase or decrease (–) in the level of Savings in Under developed Countries 1950-52 to 1957-59, as Percentage of Gross domestic products.

देश	कुल शुद्ध बचतें	विदेशी बचतें	घरेलु बचतें	सरकारी बचतें	निजी बचतें		
					कुल	कारपोरेट	घरेलु
जमाइका	10	2	8	2	6	2	4
बर्मा	7	10	–3	–3	—	—	—
भारत	5	3	2	—	2	—	—
पनामा	4	2	2	—	2	3	–1
ग्रीस	4	2	3	—	3	—	—
इक्वेडोर	4	2	2	4	–2	–1	–1
चिली	4	2	2	1	1	—	—
रोडेशिया न्यासालैंड	3	7	–4	—	–4	–5	1
फिलीपीन्स	2	1	1	1	—	1	–1
प्यूरटोरिको	1	8	–7	—	—	1	—
कोरिया (दक्षिण)	1	2	–2	—	–2	—	—
ट्रिनीडाड टोबैगो	—	—	—	2	–1	—	–1
ब्राजील	—	–1	—	—	1	1	—
कोलम्बिया	–1	–1	—	1	–1	1	–2
पुर्तगाल	–1	2	–3	1	–3	—	—
वेनेज्यूएला	–1	4	–5	1	–6	1	–7
लंका	–2	5	–7	–3	–4	–2	–2
होन्डुरास	–2	2	–3	–2	–2	1	–2
द० अफ्रिका	–4	–3	—	—	—	1	–1
कांगो	–10	9	–19	–5	–14	–14	—
मोरक्को	–14	–9	–5	–2	–3	1	–2

World Economic Survey 1960, U. N p 75 Table 2-13.

बचनों व बचतो से पूंजी निर्माण बढाने के उपाय :

बचतो व पूजी निर्माण बढाने के लिए मुख्यतया तीन कदम उठाने पडते हैं

(i) बचतो को बढाना.

(ii) बचतो को सस्थागत करना तथा

(iii) बचतो को विनियोजित करना

बचतों को बढाना :

बचतो की, किसी भी देश में, न्यूनतम व अधिकतम सीमाएँ होती हैं. हर देश को एक न्यूनतम मात्रा मे बचत करनी ही पडेगी अन्यथा जनसख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय गिर जाएगी. इसी प्रकार से बचतो की अधिकतम सीमा भी होती है. यह सीमा देश के साधनों, उनके प्रयोग, रोजगार स्तर, श्रम व तकनीकी स्थिति, साहसियो के कार्य तथा करो की मात्रा पर निर्भर करती है.

सर्वप्रथम कम विकसित देशो को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र मे प्रतिवर्ष प्रति-इकाई उत्पादन बढाने के लिए पूँजी की मात्रा नापने की आवश्यकता पडेगी. इसको हम Capital-output ratio या Capital co efficient आँकना कहते हैं. Capital-output ratios निकाले जाते हैं, परन्तु सामान्यतया Average capital-output ratios निकाले जाते हैं, परन्तु पूँजी की आवश्यकता नापने के लिए Incremental capital-output ratio निकालनी पडती है.

इन आँकडो के आधार पर हम अपेक्षित बचतो के अनुमान निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम उत्पादन को 20 रुपयो के बराबर बढाना चाहते हैं, और हमारा Incremental capital output अनुपात 4 1 है तो जाहिर है कि हमे $20 \times 4 = 80$ रुपयो की पूँजी की आवश्यकता पड जाएगी.

हम इन्ही आधारो पर विकास की सम्भावित दरो का पता लगा सकते हैं. जैसे माना कि राष्ट्रीय आय 1000 रु० है, और इनमें से 60 रु० बचाए जाते हैं तो बचत अनुपात ·06 हुआ अब अगर उस देश में ICOR, चार हो उपज मे 15 रु० के बराबर वृद्धि होगी (60 – 4) और इस प्रकार से विकास दर 1·5% हुई. अगर उत्पादन का Gestation period (फल देने शुरु होने के काल) लबा हुआ तो विकास की दर कम होगी और इसका वही प्रभाव होगा जो बचतो के अनुपात घटने या ICOR के बढने का होता है.

Ecafe : Estimates of Capital Requirements : Programming Technique of the first Group of Experts on Programming–The Role of Capital of G. Meler., op. cit :

हम इन्ही आधारो पर बचत का वांछनीय अनुपात भी निकाल सकते है. जैसे माना कि किसी देश मे जनसंख्या 1·5% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढती है, और बचत अनुपात 6% है तथा ICOR 4 है. यह क्रम देश के जीवन स्तर को ऊँचा नही उठा सकता है अब अगर हम प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को 2% से बढाना चाहे तो राष्ट्रीय आय को 1 5 + 2% = 3 5% से बढना होगा. अगर ICOR वही 4 रहे तो बचत अनुपात 06 से बढकर 14 होना होगा, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना होगा

बचतो की वृद्धि रीतियां :

कम-विकसित देशो में बचतो की मात्रा बढानी होगी तथा उन्हे संस्थागत बनाना जरूरी है. बैंको, पोस्ट आफिसो, इन्स्योरेन्स कम्पनियो, तथा सहकारी सस्थाओ व राज्य को इन देशो मे बचतो को बढाने का अभियान अत्यन्त वृहद मात्रा में करना होगा. आज कम-विकसित देशो मे ये अभियान "अल्प बचत योजनाओ" बीमा योजना आदि के रूप म चल रहे है इनमे कभी शिथिलता नही आना चाहिए.

इन देशो म राज्यो को ऋणपत्र निर्गम करके बचतो को इक्ट्ठा करना चाहिए. इनको प्राप्त करने के लिए कम से कम कार्यवाही करना आवश्यक होना चाहिए विशेष क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली, विशेष योजनाओ के लिए, उन्ही विशेष क्षेत्रो में राज्य को ऋणपत्र निर्गम करना चाहिए. सबसे बडी आवश्यकता तो इन ऋणपत्रो की Real value या वास्तविक मूल्य को कायम रखना है. मुद्रा स्फीति से ऋणदाताओ को हानि होती है, राज्य को कोई मुआवजे की योजना बनाना चाहिए, अर्थात् अगर मूल्य बढ जाएँ तो ऋणपत्रो के चुकाने मे उतनी ही प्रतिशत धन अधिक दिया जाए.

सहकारी सस्थाएँ भी कम-विकसित देशो मे बचतो को इक्ट्ठा करने मे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. बीमा योजना का विस्तार भी ग्रामीण क्षेत्रो में बढाना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रो मे संयुक्त परिवार प्रणाली या निम्न जीवन यापन स्तर के कारण, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति असुरक्षा को उतनी गम्भीर समस्या नही समझते विकास से जैसे-जैसे उनका जीवन स्तर बढेगा वे निम्नजीवन स्तर पर जाने की असुरक्षा की गम्भीरता समझने लगेगे और राज्य को इन क्षेत्रो में कम से कम औपचारिकता मे बीमा पालिसियाँ देना चाहिए.

राज्य को बचत करने के लिए कुछ कर सबधी छूटे भी देना चाहिए राज्य को साहसियो को विकास कार्य व उत्पादन कार्य करने की सुविधाएँ देना चाहिए अगर

साहसियो को उचित कार्य वातावरण मिला तो स्वय ही बचतो को खीच लेंगे.
राज्य लाटरियो को शुरू करके भी बहुत-सी बचतें खीच सकते हैं.

C C Liang ने कम-विकसित देशो में बचतो को बढाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताई हैं :

(a) सुरक्षा (Security) • देश में बचत करनेवालो को बैको के फेल होने के सबध म सुरक्षा होना चाहिए

(b) आय (Yield) बचत योजनाएँ इस तरह की होना चाहिए कि बचत करनेवालो को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके परन्तु बहुत ऊँची ब्याज की दर से देश म विनियोजन हतोत्साहित होगा

(c) तरलता Liquidity देश म बचतो को इकट्ठा करने की रीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जमा कराने वाले व्यक्ति अपनी बचतो को अपनी आवश्यकतानुसार यथाशीघ्र निकाल सके

(d) आसान पहुँच Accessibility कम विकसित देशो मे ग्रामीण क्षेत्रो में अधिक से अधिक बैको व पोस्ट आफिसो को खोलना चाहिए Mobile या गाँव-गाँव जाने वाली गाडियो से भी बीमा, जमा व लाटरी के लिए बचतें इकट्ठी की जानी चाहिए

(e) Divisibility भिन्न-भिन्न बचत योजनाओ को इस प्रकार बनाना चाहिए कि सब स्तरो की आय वालो को भिन्न-भिन्न बचत योजनाओ में धन लगा सकने की सुविधा हो

(f) Simplicity privacy and personal relations बचत योजनाओ मे धन जमा करने व निकालने की कार्यविधि सरल होना चाहिए तथा बचत करने वालो की बचतो की मात्रा को अन्य व्यक्तियो से गुप्त रखना चाहिए तथा बचत करन वालो को व्यक्तिगत सेवा मिलना चाहिए

See

1 C C Liang • Mobilization of Rural Savings with Reference of the Far East" Mobilization of Domestic capital Report and Documents of the First working party of Experts, U N 1952 p 152-53

2 C Wolf and S C Sufrin Capital Formation and Foreign Investment in Under developed Countries, 1958

3 S Howard Ellis • The Financing of Economic Development in under-developed Areas Indian Economic Journal, 1956 p 266 cf D B Singh • op cit

बचतों का विनियोजन[1] :

बचतो को इकट्ठा करना ही पर्याप्त नही होता, और न बचतो के बढने से पूजी निर्माण हो जाता है या उत्पादन व विकास वृद्धि होने लगती है. देश में विनियोजन प्रोत्साहन के लिए भी बैक तथा अन्य सस्थाएँ स्थापित करना चाहिए.

शीघ्र फलदायक योजनाओ म अधिकाधिक विनियोजन आवश्यक है. इससे देश में मुद्रा स्फीति नही फैलेगी और बचत करने वालो की बचतो के मूल्य में ह्रास से उन्हे हानि नही होगी

बचतो को विनियोजन मे लाभदायक रूप से लगाया जा सके इसके लिए साहसियो को कार्य करने की सुविधा होना चाहिए तथा राज्य द्वारा सचालित उद्योगो को भी लाभ अर्जन करना चाहिए, अन्यथा देश मे बचतो का उचित लाभ नही उठाया जा सकेगा

(b) Capital formation through surplus manpower-Nurkse-Lewis Thesis or Disguised unemployment as a potential source of capital formation

जैसा कि हम देख चुके है[2] ल्युस तथा नर्क्स श्रम शक्ति के प्रयोग से ही पूजी निर्माण की सम्भावनाएँ देखते है इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि कम-विकसित देशो में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में, बहुत से व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगे रहते है जहाँ उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है जैसे एक खेत पर जहाँ चार व्यक्ति ठीक से खेती कर सकते है वहाँ पर व्यक्ति कार्य करते है क्योकि अन्य दो व्यक्तियो के पास कुछ और करने को नही होता है इस प्रकार से ये व्यक्ति कृषि आवश्यकताओ के लिए अतिरेक होते है क्योकि इनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है.

इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि अगर इन व्यक्तियो से पूजी निर्माण कार्य कराया जाये (जैसे बाध बनवाना, भूमि सुधार कराना, जगल लगवाना, सडकें बनवाना तथा खान व कारखानो के निर्माण कार्य कराना) तथा उन्हे वेतन न दिया जाये तो पूजी-निर्माण "लागत-हीन" (free or self financing) हो जाएगा

1. अगला अध्याय Investment Criteria पर विस्तृत अध्ययन के लिए देखिए.
2. इस सम्बन्ध में आप Lewis तथा Nurkse के मॉडल में पढ चुके है. सदर्भ भी वही है.

इनका कथन है कि इनका जो कुछ दिया जाये वह उन्हीं परिवारों से वे लिया जाए जहाँ ये व्यक्ति पहले रह रहे थे और खाते पीते थे. इस प्रकार वे बगैर वेतन के कार्य कर सकेंगे, अर्थात् उनके वेतन के बराबर धन उनके परिवारों से Mobilize करना चाहिए अर्थात करों या अन्य रीतियों द्वारा प्राप्त करना चाहिए. इस प्रकार से इन अतिरेक व्यक्तियों के पूर्ण प्रयोग से बचत व पूंजी-निर्माण की सम्भावनाएं है.

ल्युस के अनुसार :

> "विकास सिद्धान्त की मुख्य समस्या यह है कि वह उस प्रक्रिया को समझे जिससे एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जो अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 4 से 5 प्रतिशत तक बचाती है वह अपनी राष्ट्रीय आय का 12 से 15% भाग बचत करके विनियोजित करे."

ल्युस के अनुसार कम-विकसित देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या के दुष्प्रभावों को निरस्त करने व उचित विकास स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 4% राष्ट्रीय आय में वृद्धि आवश्यक होगी. इस विकास दर को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय का $\frac{1}{4}$ भाग या 25% भाग को उपभोग नहीं करने दिया जाना चाहिए और इतनी पूंजी-निर्माण करना चाहिए. इस 25% भाग का वितरण इस प्रकार से करना चाहिए .

(i) राष्ट्रीय आय का 13% भाग पूंजी निर्माण में.

(ii) „ „ „ 12% भाग व्यक्तिगत सेवाओं के प्रदान करने में

12% का बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए

- 3% शिक्षा पर.
- 2% सार्वजनिक स्वास्थ्य पर.
- 3% प्रचार, कृषि व भूगर्भ संबंधी खोजों पर.
- 4% सामान्य प्रशासन व कल्याण पर

ल्युस का कथन है कि आज कम-विकसित देश लगभग 85 प्रतिशत राष्ट्रीय आय उपभोग करते हैं और केवल 15% बचाते हैं जो पूंजी निर्माण व व्यक्तिगत

See also :

1. W. A. Lewis · Some reflection on Economic Development : Economic Digest, Institute of Economic Development, Karachi, Pakistan, vol No. 3, No. 4, winter 1960 p. 3-5, G. Meier : op cit : 95-98

सेवाओं दोनो के काम लेते हैं. यह मात्रा कम है. इसी 15% में से जमीन व जेवरो म भी विनियोजन हो जाता है. इस कारण वास्तविक पूँजी-निर्माण बहुत कम हो पाता है.

ल्युस चाहते है कि राज्य कम से कम राष्ट्रीय आय का 20% भाग करों के रूप में ले ले जिसमे से 12% राज्य कार्यो पर व्यय करे और 8% का पूँजी-निर्माण करे 5% पूँजी-निर्माण निजी क्षत्र से आना चाहिए और इस प्रकार से 13% वास्तविक पूँजीनिर्माण राज्य आसानी से शुरु कर सकता है

नर्क्स व ल्युस की अतिरेक जनसख्या के पूर्ण प्रयोग से पूँजी निर्माण की रीति में कई कमियाँ है, जिनका उल्लेख हम पिछले अध्यायो में कर चुके हैं. सक्षेप में ये इस प्रकार है

(i) उन परिवारो से, जहाँ अतिरेक' रह रहे थे खाद्य सामग्री लेना कठिन होगा परिवार के बाकी सदस्य अपने उपभोग स्तर को ऊँचा कर लेंगे, क्योंकि उनम स कई परिवार जीवन यापन स्तर के बराबर ही उपभोग कर रहे होते है

(ii) इस प्रकार से साधनो को इकट्ठा करने मे बहुत सी प्रशासनिक व यातायात सबधी कठिनाइयाँ आएँगी

(iii) कम विकसित देशो में श्रमिक गतिशील नही होते और उन्हे अन्य स्थानो पर पूँजी निर्माण के लिए ले जाना अत्यन्त कठिन होगा शायद इसके कडे कदम शासन को उठाना पड सकते है.

(iv) कृषि से निकले अतिरेक व्यक्तियो को ट्रेनिंग दिए वगैर पूँजी-निर्माण कार्यों में नही लगाया जा सकता. इस प्रकार से पूँजी-निर्माण Self financing नही हो सकता.

लेकिन इस रीति को हम महत्वहीन नही कह सकते भारत मे 'श्रमदान' पद्धति वास्तव मे अतिरेक जनशक्ति के प्रयोग से पूँजी निर्माण का ही तरीका है थोडी बहुत मात्रा में इस रीति से पूँजी निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हो इस प्रकार से पूजी निर्माण हो सकता है. चीन में अतिरेक जनसख्या से Communes पद्धति के अन्तर्गत बहुत से पूँजी निर्माण कार्य सेना की अनुशासन पद्धति से कराये गए, जो कि काफी हद तक जबरन कराए गए.

कालान्तर में इस रीति से बहुत अधिक पूँजी-निर्माण नही हो सकेगा.

(c) Capital Formation through Inflation :

मुद्रा प्रसार[1] से या हीनार्थप्रबन्धन से पूंजी निर्माण करने के पक्ष मे बहुत से अर्थशास्त्रियो ने अपने मत व्यक्त किए है. वास्तव मे शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने अपने आर्थिक विकास के लिए कभी न कभी इस रीति को न अपनाया हो हम देख ही चुके है कि इस रीति को न अपनाने की सलाह देते है हम यह देखेगे कि किन परिस्थितियो मे मुद्रा स्फीति या हीनार्थप्रबन्धन से पूंजी निर्माण होता है या नही होता है

1 आपने मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति के अध्यायो मे भी इस सम्बन्ध मे पढा है.

References :

1 K. K. Kurihara . The Keynesian Theory of Economic Development.
2. Keynes : Treatise on Money II; 1934, p. 149–177.
3. E. J Hamilton : Profit Inflation and Industrial Revolution, Quarterly Journal of Economics, 1942, p 263.
4. C. P. Kindleberger : Economic Development, 1958. p. 189-90.
5. P H Douglas : Real wages in U. S 1890, 1926, 1930, p. 219, 46, 540
6 A. L Bowley Wages and Income in the U. K since 1860, p 30, 34, 99.
7. P Brown . The course of wage rates in five countries 1860–1939, Oxford Economic Papers.
8 U. N O .: Conditions of Economic Progress, 1958.
9. P A. V Philips : Public Finance in under developed countries.
10 Bayer & Yamey : op cit.
11. Palekar : The Problems of wage Policy for Economic Development
12 Felipe Pazos : Economic Development and Financial Stability, IMF staff Papers 1952, p. 377.
13 U N Ecafe : "Inflation and Capital formation in under developed countries of Asia" Economic Bulletin of Asia and the far East." Vol II, No 3, 1951, pp. 22–5.
14. Gardner Patterson : Impact of Deficit financing in underdeveloped countries : Some Neglected aspects, Journal of finance. Vol. XII, No. 2, May 1957, pp. 179–89.

कम-विकसित देश पूजी निर्माण या तो

(i) अधिक घटो तक (उतनी ही आय पर) काम करके पूँजी निर्माण कर सक्त है या

(ii) अधिक कर लकर सामूहिक पूजी निर्माण कर सकन है या

(iii) अधिक बचत बढाकर (विशपरुप से अनिवाय बचता को) तथा

(iv) मुद्रा स्फीति फलाकर

---

15 H W Singer Deficit financing of Public Capital formation, Social and Economic studies sept 1958 Special Number pp 91-6

16 Gertrude Lovasy Inflation and Exports in Primary Producing countries I M F Staff Papers 1962 March p 38-40

17 Graeme S Dorrance The Effect of Inflation on Economic Development I M F Staff Papers March 1963, p 1-31

18 H J Bruton Inflation in a Growing Economy Annual Lectures by Visiting Professor of Monetary Economics 1960-61, University of Bombay

19 Arthur I Bloomfield Monetary Policy in under developed countries in Public Policy Vol VII Edited by C J Friedrich and S E Harris Harward University Press 1956, p 244-72

20 U Tun Wai The Relation Between Inflation and Economic Development A Statistical Inductive study, staff Papers Vol VII 1959 60 p 302-17

21 O S Shrivastava op cit p 39 44 on Inflation Vrs Capital Formation

22 W W Lockwood Economic Development of Japan p 300 01

23 Kuczinsky, Jurgen, A short History of Labour conditions under Industrial Capitalism Germany 1800 to the Present Day, 1945 Vol III, pt I

24 Harry Schwartz Russia s Soviet Economy p 840-42 1950

25 A Baykov The Development of Soviet Economic sysem

26 P. A Baran The Political Economy of Growth 1958 p 40

27 J A Schumpeter The Theory of Economic Development p 154

28 Dr V K R V Rao Deficit Formation and capital Formation in op cit

29 Cf G Meier op cit IV Part complete

प्रथम तीनो रीतियो को अपनाने की अपनी अपनी सीमाएँ है. कम विकसित देशो में जितनी पूंजी-निर्माण की आवश्यकता पडती है उतनी मात्रा में करो से आय प्राप्त नही हो सकती. भारत मे जहाँ राष्ट्रीय आय का केवल 10% भाग करो के रूप में प्राप्त होता है वहाँ यू० के० में राष्ट्रीय आय की 33% भाग करो में ले लिया जाता है. राज्या को इतनी अधिक मात्रा में कर लगाने की राजनैतिक हिम्मत भी नही होती.

मुद्रा स्फीति फैलाकर पूंजी-निर्माण करने के समर्थक अर्थशास्त्रियो का कथन है कि राज्य को चाहिए कि वह हीनार्थप्रबन्धन करके मुद्रा स्फीति फैलाएँ राज्य को चाहिए कि वह मूल्य तो बढने दें परन्तु मजदूरी को उसी अनुपात मे न बढने दें मजदूरी को अगर न बढने दिया गया तो उत्पादनकर्ताओ के लाभ बढेंगे तथा वे बचत करके पूजी-निर्माण कर सकेंगे मुद्रा स्फीति से अनावश्यक वस्तुओ का उपयोग भी कम होगा और बचतो मे वृद्धि होगी मुद्रा स्फीति से जो उत्पादनकर्ताओ को लाभ होता है उसमें से वे अधिकाधिक भाग से पूजी निर्माण कर लेते है क्योकि उनकी उपभोग क्षमता कम होती है उत्पादनकर्ता यह लाभ दो रूप से उठा सकते है :

(1) मूल्य वृद्धि से उन्ह लाभ उठाने दे तथा उनकी मजदूरी व कच्चे माल सबंधी लागतो को न बढने दिया जाए, तथा

(11) जब उत्पादकता बढ रही हो तब उनको मूल्य घटाने को न कहा जाए

इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि इस प्रकार से पूजी-निर्माण करने मे अल्पकालिक कठिनाई ही हो सकती है. जो मुद्रा स्फीति होगी वह Self-Liquidating होगी, अर्थात् स्वय समाप्त हो जाएगी मुद्रा स्फीति से पूजी-निर्माण होगा, और इस पूजी से उत्पादन बढेगा जिससे मूल्य स्वय गिर जाएगे उधर राज्य को भी अधिक उत्पादन व आय से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करो से आय बढ जाएँगी, और राज्य को हीनार्थप्रबन्धन की आवश्यकता नही रहगी

प्रत्येक देश ने, इन अर्थशास्त्रियो के अनुसार अपने विकास के शुरू के काल मे इस नीति को अपनाया है

U S A. मे, युद्ध काल मे मूल्यो मे 50% वृद्धि हुई और अगर इतनी वृद्धि नही होती तो पूजी-निर्माण सभव न होता जापान ने भी (विशेष रूप से 1929-39 में) मुद्रा स्फीति फैलाकर ही पूजी-निर्माण किया. जर्मनी में भी 1919-1923 की मुद्रा स्फीति ने पूजी-निर्माण में सहायता की जर्मनी में 1801-1914 के

बीच उत्पादन 50 गुना बढा परन्तु वास्तविक मजदूरी को केवल 16 प्रतिशत ही बढने दिया गया और इस प्रकार पूजी-निर्माण किया गया

स्वय रूस मे 1929-39 के बीच मूल्य 700% बढ गए और 1928 से 1952 तक वास्तविक मजदूरी बराबर गिरती रही 1948 मे तो वास्तविक मजदूरी 1928 के अनुपात मे केवल 45% रह गई थी इस प्रकार से रूस मे मूल्य वृद्धि करके, तथा वास्तविक मजदूरी कम रखकर पूंजी-निर्माण किया गया

सक्षेप मे यह कहा जाता है कि कालान्तर मे मुद्रा स्फीति की निशानी स्वरूप केवल बाँध, सड़कें व कारखाने रहेंगे जो आर्थिक विकास के ठोस प्रमाण होंगे.

Arguments against विपक्ष में तर्क :

1. आज के युग मे मुद्रा स्फीति से पूजी निर्माण के विपक्ष मे अधिकाधिक अर्थशास्त्री होते जा रहे है मुद्रा स्फीति मे पूँजी-निर्माण करने को Ostrich Mentality "शुतुरमुर्ग मनोवृत्ति" कहा जाता है, अर्थात् तथ्यो के सामने आँखे बन्द करना है.[1] जिन देशो ने पुराने जमाने मे इस नीति को अपनाया था उसकी विशेष परिस्थितियाँ थी जापान मे हर व्यक्ति एक उत्साही साहसी था, रूस मे राज्य का अकुश था, इग्लैड मे आवश्यक कच्चा माल व खाद्य सामग्री सस्ते मूल्यो पर बाहर से आ जाती थी आज ये परिस्थितियाँ बहुत से कम-विकसित देशो मे नही हैं.

U. Tun Wai .

2. (जिनके सन्दर्भ का उल्लेख किया जा चुका है) के अनुसार मुद्रा स्फीति व पूँजी-निर्माण व विकास मे सह सम्बन्ध नही है युद्धोत्तर काल के विकसित देशो के सन्दर्भ मे उन्होने बताया कि स्थिर मूल्यो पर जहाँ 4% विकास दर प्राप्त हुई वहाँ कम मात्रा मे मुद्रा स्फीति से इससे आधी ही विकास दर प्राप्त हुई और अधिक मुद्रा स्फीति से तो और कम हो गई. निम्न तालिका इसी बात को दर्शाती है :

---

1. रेगिस्तान मे जब तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग चोच व आँखें रेत मे धँसा लेता है और जब तक तूफान बन्द नही होता देखता ही नही है

हाल के वर्षों में मुद्रा स्फीति व आर्थिक विकास मे सम्बन्ध.

	प्रति व्यक्ति विकास दर का वार्षिक प्रतिशत		
	स्थिर स्थिति	कम-मुद्रा स्फीति	अधिक मुद्रा स्फीति
यू० एन० ओ० के अनुमान	2	2	2
U. Tun Wai के (i) Unadgusted अनुमान	6	2	3
(ii) भुगतान की शर्तों के अनुसार सशोधित	4	1	1
Per capita Social Productivity	4	3	—

3. मुद्रा स्फीति से अगर पूँजी-निर्माण बढता है तो विनियोजन की लागत भी तो बढ जाती है वास्तविक आय के अनुपात में मौद्रिक आय अधिक बढ जाती है. कृषि क्षेत्र मे पूर्ति की बेलोचपन के कारण उत्पादन शीघ्र नही बढता और अनुपात से कम बढता है, इससे और मूल्य बढने लगते हैं. राज्य की करो द्वारा प्राप्त की गई आय का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और उसे और अधिक मात्रा में मुद्रा स्फीति हीनार्थ प्रवन्धन से करनी पडती है. मुद्रा स्फीति फिर बढती ही जाती है

4. मुद्रा स्फीति के कारण ब्याज, लगान व मजदूरी प्राप्त कर्ताओं को हानि होती है. कृषकों द्वारा वेची जाने वाली वस्तुओं के मुकावले में उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक बढ जाता है जिससे वे भी उतनी मात्रा में लाभान्वित नही होते.

मुद्रा स्फीति के कारण वे ही वर्ग नुकसान उठाते हैं जो सबसे कम बोल सकने वाले व कमजोर होते हैं. विकास गरीबों की भलाई के लिए किया जाता है जब कि मुद्रा स्फीति से इनका ही अहित होता है. इससे वर्गसंघर्ष बढ़ता है और आज के युग में समाज इसे सहन नहीं करेगा.

5. मुद्रा स्फीति से जो बचतें पनपती हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे पूँजी-निर्माण के कार्य में ही लाई जाएँ. बहुधा वे सट्टा (वितरण मे लाभ) सम्पत्ति व Inventory accumulation (सामान इकट्ठा करने) मे लगा देते हैं. बचतों को सोना, चाँदी आदि मे भी लगा दिया जाता है.
6. मुद्रा स्फीति से फिजूल खर्ची, अयोग्यता व लागत बढ़ती हैं. ऐसे उद्योगों का निर्माण हो जाता है और ऐसी वस्तुएँ बिकने लगती हैं जो कि केवल मुद्रा स्फीति के बने रहने पर ही बिक सकती हैं. विनियोजन गलत मदों में हो जाता है और बहुधा Excess Capacity (आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता) का निर्माण हो जाता है U. S. A. मे 1952 के तेजी के काल में भी केवल 52% उत्पादन क्षमता का प्रयोग हो सका था.
7. मुद्रा स्फीति से निर्यात हतोत्साहित होते हैं और आयात या चोरी छिपे माल लाना प्रोत्साहित होता है और इसमे विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं. विदेशी विनियोजक भी स्थिर मुद्रा के देशों में विनियोजन पसंद करते हैं.
8. I. M. F. के Staff Papers की गवेषणा के अनुसार दीर्घ काल मे मुद्रा स्फीति पूँजी-निर्माण के स्थान पर पूँजी-ह्रास का कारण बन जाती है. Chile (चिली) मे जहाँ 1944 मे राष्ट्रीय आय का लगभग 7% भाग का पूँजी-निर्माण हुआ वहाँ 1951 मे वह मुद्रा स्फीति के कारण 4·7% ही रह गया. कोलम्बिया मे मुद्रा स्थिरता के कारण इसी काल मे पूँजी-निर्माण का प्रतिशत 12 1% रहा इन्डोनेशिया में प्रेसीडेन्ट सुकर्ण के शासनकाल के अन्तिम कुछ वर्षों में ही मूल्य 10000% बढ़ गए परन्तु पूँजी-निर्माण भारत के मुकाबले में जहाँ इस काल मे केवल 100% वृद्धि हुई पूँजी-निर्माण घट गया.
9. दीर्घकाल तक बने रहने वाली मुद्रा स्फीति से सामाजिक कल्याण घटता है और मुद्रा स्फीति "self-liquidating" होने के स्थान पर self-limiting तथा "self-frustating" हो जाती है. गरीब लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय घटाना पड़ता है. इससे मशीनों व भौतिक पूँजी चाहे बढ़ जाए परन्तु मानवीय पूँजी का तो ह्रास होता है. कम-विकसित देशों में कम

कुशल व्यक्तियो को ही काम नही देना होता है, बल्कि कुशल व्यक्तियो की कमी के कारण इन्हें भी रोजगार नही दे पाते.

10. मुद्रा स्फीति के काल में हर वर्ग अपनी वास्तविक आय बनाए रखने का प्रयत्न करता है. मजदूर अपनी मजदूरी बढवाते है, राज्य को सस्ते दर पर आवश्यक सामान उपलब्ध कराना पडता है, मूल्य नियन्त्रण करने पडते है. जब यह सब करना पडे तो उत्पादनकर्ताओ को लाभ भी न होगे और फिजूल मे प्रशासनिक समस्याएँ खडी हो जाती है

इसलिए इस नीति को अल्पकाल मे, शीघ्र उत्पादन कार्यो (with short gestation period) के लिए अपनाना चाहिए उत्पादकता वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए अन्य राजकोषीय तरीको से करो से पर्याप्त आय लेना चाहिए तथा निजी बचतो को प्रोत्साहित करना चाहिए मेरे विचार मे :

> "Inblationary finance as a means of capital formation should be resorted to as a last resort and within sober limits and should not be made a permanent policy"

(d) Fiscal Measures for Promoting Capital Formation :

पूंजी-निर्माण व राज्य की राजकोषीय नीतियाँ :

(इस सबध मे अगया 'राजकोषीय नीति' सबधी अध्याय मे आप पुन पढिए)

(e) Capital Formation by Reducing Consumption :

पूंजी-निर्माण उपभोग कम करके :

यह अन्य रीतियो को दूसरे रूप मे व्यक्त करना है Lewis रीति में भी उपभोग कम करके पूजी-निर्माण करने की सलाह दी थी. राजकोषीय नीति का भी एक उद्देश्य करो से उपभोग कम रखने की सलाह दी जाती है. मुद्रा स्फीति फैलाकर भी उपभोग को नियत्रण रखने का लक्ष्य रखता है.

परन्तु कम-विकसित देशो म उपभोग को कम करने की तो सम्भावनाएँ कम ही है पर इस बात की सम्भावनाएँ भी कम हैं कि उपभोग को बढने से रोका जाए. पिछले जमाने मे भिन्न-भिन्न देशो मे उपभोग कम रखने के जो भी कारण रहे हो आज कम-विकसित देशो में समाज इस बात को गवारा नही करेगा कि अधिकाश जनता का उपभोग कम रखा जाए. जनता को भी विकास मे लाभान्वित

O. S. Shrivastava : op. cit : p 44.

होना चाहिए दूसरे जितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में उपभोग कम भी तो नही हो सकता. उतनी मात्रा में उपभोग को पुन प्राप्त करने में कई साल लग जायेंगे केवल 1.5 या 2% राष्ट्रीय बढाने के लिए लगभग 15% उपभोग कम करना पडेगा इतना उपभोग हर वर्ष कैसे कम हो सकता है ?

वास्तव मे कमी तो अनावश्यक व विलासिताओ के उपभोग मे (जिसे James S Duesenberry, "Demonstration effect expenditure" कहते हैं) कमी लाना चाहिए. अनावश्यक आयातो पर भी इसी तरह नियन्त्रण होना चाहिए.

(f) Better Utilisation of Resources : साधनो के पूर्ण प्रयोग से पूंजी-निर्माण :

कम-विकसित देशो मे पूंजी की कमी होते हुए भी पूंजी का पूर्ण उपयोग नही हो पाता है. बहुत कुछ इसका कारण देश मे Complementary resources या पूरक साधनो (विशेष रूप से कुशल प्रशासक व तकनीकी व्यक्ति) का न होना रहता है. नई मशीने लगाने से पूर्व, पुरानी मशीनो का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए यह कार्य पालियाँ (Shifts) बढाकर किया जा सकता है. कभी कच्चे माल के समय से न मिलने, शक्ति की कमी या यातायात की सुविधाओ के समय पर न मिलने से पूंजी का पूर्ण प्रयोग नही हो पाता और एक कम-विकसित अपने सबसे दुर्लभ साधन का दुरुपयोग नही कर पाता अगर देश मे पूंजी का पूर्ण प्रयोग हो तो Capital-output ratio पूंजी-निपज अनुपात घट जाता है और देश के विकास मे सहायता मिलती है. जैसे युद्ध के काल मे पूंजी का पूर्ण प्रयोग होता है वैसे ही अगर शान्ति काल मे हो तो विकास के लिए नई पूंजी की आवश्यकता कम रहेगी.

विकास के लिए केवल पूंजी ही महत्वपूर्ण नही होती पूंजी से अधिक महत्वपूर्ण "तकनीकी उन्नति" होती है. आज अगर कम देशो में अमेरिका के बराबर प्रति व्यक्ति पूंजी उपलब्ध हो भी जाए तो उत्पादन व उत्पादकता के अमरीकी स्तर पर नही पहुँच सकते, क्योकि इन देशो को श्रम शक्ति उन तकनीको को अपनाने की योग्यता नही रखती. जरूरत तो इस बात की है कि कम-विकसित देश ऐसी तकनीक अपनाएँ और ऐसी तकनीकी उन्नति करते रहे जिसमें उनकी श्रमशक्ति का भी पूर्ण प्रयोग हो, जो सस्ती हो तथा जो शीघ्रता से सीखी जाएँ. पूंजी वृद्धि के साथ साथ तकनीकी उन्नति भी पूंजी निर्माण का अग मानना चाहिए.

See . O S Shrivastava, op. cit p. 45

श्रम-शक्ति :

श्रम-शक्ति का पूर्ण प्रयोग भी पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक है इस संबंध मे एक दुष्चक्र है जिसे तोडना है यह कहा जा सकता है कि जब तक पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तब तक श्रम-शक्ति का पूर्ण प्रयोग नही हो सकता परन्तु यह भी तो सही है कि जब तक साधनो (श्रम व प्राकृतिक) का पूर्ण प्रयोग नही होगा तब तक देश मे उत्पादन वृद्धि नही होगी और तब तक पूंजी निर्माण नही होगा. कम-विकसित देशो में प्राय आर्थिक उत्पादकता वृद्धि पर जोर दिया जाता है (कम लागत पर अधिक उत्पादन) पर सामाजिक उत्पादकता वृद्धि (अधिक रोजगार) पर उतना ध्यान नही दिया जाता अगर उपर्युक्त आर्थिक नीतियों को अपनाकर साधनो का पूर्ण प्रयोग किया जा सके तो इससे स्वय बचतो में वृद्धि होगी और पूंजी-निर्माण बढ़ेगा

श्रम ही उन्नत तकनीक को जन्म देता है या उन्नत तकनीक को कार्यान्वित करता है, तथा श्रमद्वारा उत्पादित धन मे से ही पूंजी-निर्माण होता है (Capital is stored up labour). Solomon Fabricant के अनुमानो के अनुसार, U. S. A. मे 1869–73 मे 1949–53 के बीच प्रति-व्यक्ति उत्पादन 19% के हिसाब से बढा. इसमे से केवल 1/10 भाग पूंजी की वृद्धि से हुआ तथा बाकी का 9/10 भाग श्रम की कार्यक्षमता, लगन व उत्पादकता वृद्धि के कारण हुआ [1]

इसलिए कम-विकसित देश अगर बेरोजगारी की समस्या का. निराकरण न कर सके और बेरोजगारी को बढने देते रहे तो पूंजी-निर्माण करने मे ही विफल नही होगे वरन् उस पूंजी-निर्माण के लाभ भी कम होगे U. N. O के Experts के अनुसार अगर कम-विकसित देश अपनी अर्धरोजगार कथित जनता या शहरी मजदूरो को उनके खाली समय मे कुएँ, तालाब, नहरे, बाँध, स्कूल, अस्पताल, सडको के निर्माण, जगल लगवाने आदि पर लगा सके तो पूंजी-निर्माण बढेगा.

V. Capital Formation and Economic Growth :
पूंजी-निर्माण व आर्थिक विकास-महत्व.

पूंजी-निर्माण व आर्थिक विकास में क्या संबध है इस सबंध में अर्थशास्त्रियो में बहुत मतभेद है. परन्तु मुख्यतया आज इस बात पर सहमति है कि पूंजी का

1. Shultz, Theodore W. : "The Role of the Government in Promoting Economic Growth " State of the Social Sciences. (Ed). White Lcoraw. D Chicago, 1956, p. 372.
quoted from D B. Singh : op. cit. 176.

विकास में बहुत अधिक महत्व नहीं होता. Alec cairncross पूंजी को विकास कारक घटक के रूप में कम महत्व देते हैं. उनका कथन है :

> "अतिरिक्त पूँजी, चाहे वह विदेशों से उधार ली गई हो या देश में अतिरेक जनशक्ति के पूर्ण प्रयोग से संचित की गई हो, स्वयं में, देश में औद्योगिकरण का चक्र शुरू करने में पर्याप्त नहीं होती पूँजी-निर्माण के साथ साथ, कुशल संगठन, प्रशासकों व मजदूरों की उचित ट्रेनिंग तथा उचित वातावरण बनाना भी महत्वपूर्ण है. सबसे महत्वपूर्ण देश में नवप्रवर्तन करने व विकास करने की मनोवृत्ति का निर्माण करना होगा."

"श्री क्रेनक्रास" के अनुसार पूंजी विकास कारक नहीं होती वरन् विकास के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होती है. (Capital formation is not a causal factor of growth but a concomittant phenomenon) उन्होंने बताया कि

> "18वीं सदी में पूर्ति की ओर से नयें-नये अविष्कारों तथा नवप्रवर्त्तनों के कारण विकास हुआ और माँग की ओर से बढ़ते हुए बाजारों से विकास हुआ"

इन कारणों से जो लाभ हुए उनमें पूँजी-निर्माण संभव हो सका. वास्तव में पूँजी के साथ-साथ अन्य सहयोगी व पूरक घटक (Co-operant factors) भी महत्वपूर्ण होते हैं

कभी-कभी पूँजी की बहुतायत होते हुए भी कुशल साहसियों, संगठनकर्ताओं और श्रमिकों की कमी के कारण, विकास नहीं हो पाता इसी प्रकार से कभी-कभी साहसियों को पूँजी के अभाव में (जब पूँजी-निर्माण कम हो तथा जब पूँजी को भूमि व सोने के रूप में संचित कर रखा हो) विकास कार्य हाथ में लेना संभव नहीं होता

See

1 J H. Adler & K S. Krishnaswamy · "The supply of capital and the supply of other factors" in Economic Development for Latin America, Proceedings of a conference held by International Economic Association, (Ed) by H. S Ellis, St Martin's Press N. Y. 1961, p 126–30

2 Alec cairncross : "The place of Capital in Economic Progress (Ed), Dupriez Economic Progress, Papers and Proceedings, I. E A 1955 p 248

Bayer and yamey, ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि

> "पूंजी विकास के लिए आवश्यक अंग अवश्य हो सकती है, परन्तु उसका होना ही पर्याप्त नहीं है. अगर हम एक कम-विकसित देश को विकसित देश की भाँति पूंजी या मशीनें प्रदान भी कर दें तो उससे विकास सुनिश्चित नहीं होता"

सच्चाई की बात तो यह है कि विकास की प्रक्रिया पूंजी-निर्माण को जन्म देती है न कि विकास पूंजी-निर्माण का परिणाम है.

इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास को जन्म देने और बनाये रखने में बहुत से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तत्त्व महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इनमें सह-सम्बंध पूर्णरूप से नहीं निकाल सकते. ज्यादा से ज्यादा, हम यह कह सकते हैं कि, अन्य बातों के साथ साहसियों की मनोवृत्ति, पूंजी की मात्रा, तकनीक, श्रम की कुशलता इन सबसे विकास होता है, इनका अलग-अलग योगदान निकालना कठिन है. Simon Kuznets ने भी कहा है :

> "The majar Capital stock of an industrilly advanced country is not its physical equipment; It is the body of knowledge amassed from tested findings and the capicity and training of the population to use this knowledge effectively."

Dr. (Miss) Ishrat Z Husain ने भी पूंजी व विकास में सह-सबंध को नापा है और उनके निष्कर्षों का सार हम नीचे दे रहे हैं उनके अनुसार समस्त देशों की जानकारी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुल आन्तरिक पूंजी-निर्माण (Gross domestic capital formation) तथा देश के कुल आन्तरिक उत्पादन दर (The rate of growth of gross domestic product) में धनात्मक सह-सबंध तो है परन्तु वह बहुत कम है. उनके

See .
Bayer & yamey : op, cit ch X : Capital p. 127 ff.
Simon Kuznets quoted in United Nations, Process and Problems of Industrialization in under-developed countries New york 1955, P. 5.

अनुसार यह सबंध (Correlation) + 0·44 है, हालाकि यह सबंध विकसित देशो के लिए अधिक है

निम्नलिखित तालिका में इसका विवरण है :

Co-efficient of Correlation Between The Rate of G.D.C Formation Proportion and the Annual Rate of Growth of Real G D P	
1. Value of r (Correlation) for 34 countries	+ 0·44
2. „ „ „ for 11 industrialized „	+ 0 50
3. „ „ „ „ 10 (Excluding Germany)	+ 0·71
4. „ „ „ „ 8 Semi-industrialzed „	+ 0·88
5. „ „ „ „ 15 Under-developed „	+ 0·51

महत्व :

उपरोक्त विश्लेषण का अर्थ यह सिद्ध करना नही है कि पूजी का विकास में बहुत कम महत्व है. वास्तव मे लक्ष्य यह था कि यह बताया जाए कि पूंजी "सबसे अधिक महत्वपूर्ण" नही है. पूंजी-निर्माण किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे महत्वपूर्ण योगदान करता है पूंजी का महत्व इसलिए अधिक है कि जहाँ भूमि की मात्रा को बढाया नही जा सकता तथा श्रम की पूर्ति को भी बहुत से मनोवैज्ञानिक अवरोधो के कारण शीघ्रता से नही बढाया जा सकता. पूंजी की पूर्ति की गतिशीलता अधिक होने के कारण तथा उसकी किस्म में सुधार को जल्दी कर देने की सम्भावना के कारण, पूँजी का महत्व बढ जाता है. अन्तत. पूंजी की मात्रा में वृद्धि से ही विनियोजन में वृद्धि हो सकती है तथा श्रम व भूमि की किस्म सुधारी जा सकती है. पूँजी के प्रयोग से ही हम उन्नत तकनीक या उत्पादन के जटिल Round about methods of production को अपना सकते हैं पूजी के होने से ही हम (Capital deepening) गहन-पूजी विनियोजन (अर्थात् उद्योगो में अधिक पूजी लगाना) तथा बहुत से क्षेत्रो मे विनियोजन (Capital widening) कर सकते है. अन्य शब्दो में हम पूजी से बडे पैमाने के उत्पादन से आन्तरिक मितव्ययिताएँ प्राप्त कर सकते है (By capital deepening)

For a detaled and excellent discussion See her "Economic Factors in Economic Growth", p. 155-173.

"Capital-output Ratio तथा भारत में पूँजी-निर्माण व पूजी-निपज अनुपात पर आगे अलग अध्याय देखिए

तथा capital widening से हम देश में सतुलित विकास को या वाह्य मितव्ययिताओं को प्राप्त कर सकते है

Shri P. C. Malhotra के शब्दों में :

"One cannot take more out of the pot than one has put into it"

इसलिए पूंजी-निर्माण के उपर विकास बहुत अधिक निर्भर है. देश में पूंजी-निर्माण से देश लाभान्वित हो इसके लिए पूंजी-निर्माण में से Leakages या "भिरन" नही होना चाहिए

Leakages and capital formation

पूंजी-निर्माण में से कम से कम Leakages या "भिरन" होना चाहिए श्री मल्होत्रा के अनुसार यह Leakages निम्नलिखित हो सकती है

1 उपभोग तथा आयात पूंजी-निर्माण में से Leakages होती है. समस्त उपभोग व आयात तो कम नही हो सकते है इसलिए अनावश्यक आयात व उपभोग कम करना चाहिए.
2. "भिरन" मुद्रा स्फीति से होती है और इसे नियंत्रित रखना चाहिए.
3. भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक अकर्मण्यता व फैलाव (Parkinson's Law) भी पूंजी-निर्माण का "भिरन" करते है और इसे भी रोकना होगा.
4. बडे-बडे "इज्जत बढानेवाले कार्य" Prestige projects तथा अनावश्यक सार्वजनिक व्यय से सबसे अधिक बरबादी होती है. मार्च के अन्त में जो राज्य के डिपार्टमेन्ट या विभाग फिजूल खर्ची करते है (Racing of March hares) वह पूंजी की बर्बादी करते हैं
5 साधनों का अपूर्ण प्रयोग भी महत्वपूर्ण भिरन होती है. अंत में

"The most important of all leakages is that resulting from self-complacency, self exoneration, perfunctory insistence on the forms of democratic management and control of public under-takings and the creation of a climate in which initiative is sapped ... "

(Retd) Principal P C Malhotra's, paper "Fundamentals of capital Formation for development" at Bhopal Seminar in 1966. He was the Director of the seminar "Leakages & capital Formation" This discussion is based on his paper.

अध्याय : 10

विनियोजन मानदण्ड

Investment Criteria

I. प्रस्तावना ·

II. विनियोजन के मानदण्ड

(a) श्रम गहन तकनीक : कम-पूंजी-उत्पादन अनुपात या अधिकतम रोजगार का मानदण्ड : Factor Endowment criteria/Labour Intensive technique/Low capital output ratio.

(b) पूंजी गहन तकनीक : अधिक दर से आर्थिक विकास के लिए अधिक पुन-विनियोजन Capital Intensive Investment/Criteria to accelerate growth/The reinvestment quatient.

(c) सामाजिक उत्पादकता वृद्धि का मानदण्ड
Social Marginal productivity.

(d) विशिष्ट समस्या के निवारण हेतु विनियोजन.
Investment to solve specific problem

(e) समयानुसार आयोजन का मानदण्ड.
The time factor criteria.

III. निष्कर्ष तथा व्यावहारिक मानदण्ड

IV. विनियोजन व स्वतत्र मूल्य प्रणाली व राज्य द्वारा सचालन.

अध्याय : 10

विनियोजन मानदण्ड

Investment Criteria

I. प्रस्तावना :

कम-विकसित देशो के विकास के लिए पूंजी-निर्माण के पश्चात पूजी को उचित रूप से विनियोजित करना बहुत महत्वपूर्ण है.

Everelt E Hagan के शब्दो मे :

"विकास के लिए आयोजन कार्यक्रम निर्धारित करते समय अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे विनियोजन करने की समस्या मुख्यरूप से सामने आती है. पूजी को भिन्न-भिन्न उद्योगो, भिन्न-भिन्न उत्पादन रीतियो, भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रो तथा भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रो मे विनियोजित करने का प्रश्न सामने आता है, जिसको पूर्ण समन्वय पूर्ण रीति से करना चाहिए"

कम-विकसित देशो मे विनियोजन के मानदण्ड चुनने का प्रश्न इसलिए भी महत्व-पूर्ण है कि इन देशो म पहले ही बचत व पूजी कम रहती है इसलिए ये देश पूजी की बरबादी को बर्दाश्त नही कर सकते यहाँ पर पूंजी का

(i) कृषि उद्योग व तृतीयक क्षेत्र के बीच
(ii) सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच
(iii) पूजी गत व उपभोग उद्योगो के बीच, तथा
(iv) भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रो के बीच

किस प्रकार वितरण हो, एक महत्वपूर्ण समस्या व कार्य होता है.

References :

1 Everelt E Hagan "The Allocation of Investment in under-developed countries", observations based on the experience of Burma

2 Jan Tinbergen . 'Investment criteria and Economic Growth'. Oct. 1954 Conference on Investment criteria and Economic growth in Cambridge, Asia Publishing house 1961, Reprinted 1964

विनियोजन के मानदण्ड केवल आर्थिक कारणों पर ही आधारित नही होते वरन् सामाजिक व राजनैतिक मानदडो के आधार पर भी निर्धारित होते हैं कम-विकसित देशो मे कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रो के मुकाबले में अधिक पिछड़े होते हैं. इन क्षेत्रो में साख, यातायात, व सचार की सुविधाएँ कम होती हैं और इन क्षेत्रो में कुशल श्रमिक सगठनकर्ता व साहसियो की भी कमी रहती हैं बाजार भी इन क्षेत्रो में सकुचित रहता है इन कारणो से, केवल आर्थिक मानदण्ड के आधार पर, इन क्षेत्रो मे विनियोजन कम रखा जा सकता है. परन्तु आजकल सामाजिक व राजनैतिक कारणो से इन क्षेत्रो मे भी विनियोजन करना पडता है.

Gerald Meier के अनुसार

विनियोजन के कई मानदण्ड हैं परन्तु हमको मुख्यतया निम्नलिखित मानदण्डो पर ध्यान देना चाहिए

(i) Maximum employment absorption अधिक रोजगार वृद्धि

(ii) Maximum Social marginal productivity of capital पूँजी की अधिकतम सामाजिक उत्पादकता

(iii) Minimum Capital output Ratio न्यूनतम पूँजी-निपज अनुपात

(iv) Maximum Reinvestment quotient अधिकतम पुनर्विनियोजन अनुपात.

Meier के अनुसार ये सब मानदण्ड आपस मे एक दूसरे के परक नही हैं वरन् आपस मे एक दूसरे के विरोधाभासी हैं. उदाहरणतया यह सर्वथा उचित है कि कम-विकसित देश को अपने पूंजी-निपज अनुपात को कम रखने के लिए श्रम गहन तकनीक अपनाना चाहिए, परन्तु अधिकतम पुनर्विनियोजन के लिए पूँजी-गहन तकनीक ही आवश्यक होगी क्योंकि इसी क्षेत्र मे अधिकतम लाभ होगे,

वस्तुत इस अध्याय मे मुख्य रूप से "श्रमगहन तकनीक" व "पूँजीगहन तकनीक" के सम्बन्ध मे अध्ययन महत्वपूर्ण है.

Gerald Meier : Ch. V . Introductory Note . Leading Issues of Development Economics

D. B. Singh : op. cit · ch VII.

II. Various Investment Criteria · विभिन्न विनियोजन मानदण्ड :

(a) Factor Endowment Criteria / Labour Intensive Technique / Nurkse – Lewis – Heckscher – Ohlin – Hayek Thesis / Low Capital – Output Ratio : श्रमगहन तकनीक : अधिकतम रोजगार मानदण्ड : कम पूंजी-निपज अनुपात.

पक्ष :

उपरोक्त अर्थशास्त्रियो का कथन है कि कम-विकसित देशो को ऐसी विनियोजन नीति अपनाना चाहिए जिससे वे अपने उन साधनो का प्रयोग कर सकें जो उनके पास सबसे अधिक मात्रा में है, अर्थात् वे अपने श्रम का पूर्ण प्रयोग कर सके. कम-विकसित देशो मे पूँजी की कमी तथा श्रम की अधिकता रहती है, इसलिए कम-विकसित देशो को चाहिए कि वे श्रम-गहन तकनीक अपनाएँ और कम से कम पूँजी से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके.

इन अर्थशास्त्रियो का विचार है कि जैसे कम-विकसित देशो को उपभोग के क्षेत्र मे "नकल से प्रभावित उपभोग" नही करना चाहिए उसी प्रकार से कम-विकसित देशो को विकसित देशो की नकल कर के पूँजी-गहन तकनीक पूरी-पूरी तरह से नही अपनाना चाहिए. (This will be demonstration effect in production).

श्री हाएक का कथन है "एक ऐसा देश जिसके पास U. S A के बराबर पूँजी नही है उसको U. S A की तकनीक नही अपनाना चाहिए." कम-विकसित देश अगर पूँजी-गहन तकनीक अपनाएँगे तो इससे कुछ ही क्षेत्र मे पूजी केन्द्रित रह जाएगी (Capital deepening in a limited sector) परन्तु अगर वे श्रम-गहन तकनीक अपनायेंगे तो पूंजी एक बडे क्षेत्र मे बट जाएगी (Capital widening over a large field)

इन अर्थशास्त्रियो के अनुसार यह Hekscher ohlin के तुलनात्मक सिद्धात के अनुरूप है. श्रम लागत के कम होने के कारण उसे प्रयोग मे लाना चाहिए. इन देशो मे पूजी-गहन तकनीक अपनाने से पूजी का पूर्ण प्रयोग नही होता क्योकि

See : Nurkse : op. cit.
Lewis : op. cit.
Hayek : op. cit } आप पुन. इनके मॉडल देखे.

वह कुछ ही क्षेत्रों को लाभान्वित करती है अगर एक बुलडोजर (Bulldozer) \$ 5000 म आता हो और जितनी मिट्टी वह हटा सकता है उतनी ही मिट्टी 1500 व्यक्ति हटा पाते हो जिन्हे \$ 2 5 का फावडा प्रत्येक को देना पडे तो इससे केवल \$ 3750 की पूजी लगेगी और बेरोजगारी भी दूर होगी

कम-विकसित देशो में कृषि की जोतो का आकार भी इतना छोटा होता है कि पूजी गहन तकनीक अपनाने से पहले महत्वपूर्ण भू-सुधार आदि करने होगे.

विपक्ष आलोचनाएँ :

उपरोक्त विचार कि, जैसा कि अर्थशास्त्र में होता है, कई अन्य अर्थशास्त्रियो ने आलोचना की है. इन अर्थशास्त्रियो मे Maurice Dobb, Kuznets, Bruton, Gerschenkron A O Hirschman तथा J. J. Polak Leibenstein मुख्य है उनकी मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार है

(i) श्रम-गहन तकनीक अपनाने से हम वर्तमान अवस्था को बनाए रखेंगे. अगर कम-विकसित देश पिछडी तकनीक ही अपनाए रहे तो उत्पादकता भी कम बनी रहेगी आज का युग प्रवैगित अवस्था का युग है और श्रम गहन तकनीक मे ही विनियोजन करते रहना स्थैगिक अवस्था में बने रहने के बराबर है कम-विकसित देश अगर इस नीति को अपनाते रहे तो विकास नही होगा. (Dobb)

(ii) कम-विकसित देश श्रम गहन तकनीक को पूजी की कमी के कारण अपनाते है, परन्तु इससे तो पूजी निर्माण और कम बना रहेगा क्योकि देश में पूजी का आधार ही व्यापक नही हो पाता

(iii) J J Polak का कथन है कि यह सर्वथा गलत बात होगी कि एक Project को केवल इसलिए छोड दिया जाए कि उसमें Capital-output ratio अधिक है (अर्थात् उत्पादन वृद्धि के लिए अधिक पूजी लगानी पडती है) यह हो सकता है कि इस प्रकार के project (योजना या कार्य) से अन्य उद्योगो में Capital-output अनुपात कम होता हो, अर्थात् यह Project अन्य Projects का पूरक हो.

(iv) इसी प्रकार से उनका कथन है कि श्रम-गहन तकनीक अल्प-काल में तो कम खर्चीली होती है परन्तु दीर्घकाल मे यह महगी पडती है. बहुत से उद्योगो मे वर्तमान कम पूंजी-निपज अनुपात देखने मे ही कम

होते है, जैसे कृषि मे श्रम-गहन तकनीक अपनाने से अधिक खाद या उर्वरक देने पड सकते हैं.

(v) दीर्घकाल मे कम पूजी-गहन तकनीक अपनाने पर, श्रमिक संघ इन्ही तकनीको को बनाए रखने के लिए जोर देते रहते है और वे मशीनीकरण के खिलाफ हो जात है, और देश को हमेशा पिछडी अवस्था में बनाए रहते हैं.

(vi) यह धारणा भी सही नही है कि श्रम-गहन तकनीक से रोजगार के अवसरो मे वृद्धि होती है. पूजी-गहन तकनीक से तीनो क्षेत्रो में रोजगार के अवसर (primary, secondary and tertiary) बढते हैं और दीर्घकाल में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं.

(vii) इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे होते है कि जहाँ श्रम-गहन तकनीक अपनाई ही नही जा सकती जैसे इस्पात, पेट्रोल, जल या यातायात योजनाएँ आदि.

(ix) Gerschenkron का कथन है : 'जितना जो देश तकनीकी नवप्रवर्तनो में पिछडा हो उतना ही उसे औद्योगीकरण की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए. जैसा कि Veblen ने सही रूप से बताया है, उन्नत देशो की तकनीक की नकल करके ही पिछडा देश औद्योगीकरण कर सकता है.''

(x) Leibenstein ने भी इस विनियोजन मानदण्ड को उचित नही बताया है. उन्होने कहा "There is no evidence to lead us to belive that

---

(v) J J Polak . Balance of Payments Problems of Countries Reconstructing with the help of foreign loans, Quarterly Journal of Economics, Feb, 1943, 208-40 cf G Meier : op cit.

(vi) U. N. Ecafe : Criteria for allocating investment Resources among Various fields of Development in under-developed Countries : Economic Bulletin for Asia and the Far East, 1961 p. 30-33 · cf G Meier : op. cit.

(vii) A O. Hirschman : Economics & Investment Planning : Reflections based on experience in Colombic : cf Asia op. cit.

the particular technique suggested by Nurkse is the best way of obtaining the forced savings or that the amount so saved is optimum amount"

(b) पूजी-गहन तक्नीक अधिक विकास के लिए अधिक पुनर्विनियोजन : Capital Intensive Investment/or Criteria to Accelerate Growth/or The Reinvestment Quotient Rostow—Galenson—Leibenstein—Hirschman

ये अर्थशास्त्री प्रथम वर्ग के अर्थशास्त्रियो के विपरीत मत के हैं इनका मत है कि किसी देश का विकास इसलिए रुका रहता है कि उस देश मे पूजी-गहन तक्नीक नही अपनाई गई है और विकास के लिए पूजी-गहन तक्नीक के अपनाने से विकास होने लगेगा आधुनिक तकनीक का साहसियो पर प्रवैगिक असर होता है इस प्रकार की तकनीक अपनाने से अधिक लाभ होते हैं और फिर उनसे और अधिक बचतें होती है पूजी-गहन तक्नीक अपनाने से सामाजिक अवरोध दूर होंगे

A O Hirschman का कथन है कि कम-विकसित देशा को पूजी-गहन तकनीक अपनाना चाहिए जिसके अन्तगत वे Project planning करें अर्थात् कुछ कार्य विशेष करें और इस प्रकार से असतुलित विकास पद्धति अपनाएँ, वे सतुलित विकास पद्धति[1] के बारे म कहते है

"Integrated development planning is a myth."

उनका कहना है कि आजकल सरकारो, विदेशी विनियोजको, अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजक सघो तथा आर्थिक सलाहकारो की 'प्राकृतिक प्रवृत्ति' यह है कि वे ऐसे

See also	Kindleberger	op cit
	B Higgins	,,
	Meier & Baldwin	,,
	Leibenstein	,,
	Gerschenkron	,,
	Singer	,,

1. पाठक इस सबध में "Balanced Vrs Unbalanced Growth" के अध्याय को भी पुन देखे वास्तव मे श्रमगहन तक्नीक वाले विचार "सतुलित विकास पद्धति" तथा पूंजी-गहन तक्नीक के विचार "असतुलित विकास पद्धति" से मिलते है

projects या योजनाओं को कार्यान्वित करने की सलाह देते हैं जो देश का नक्शा बदलती हैं न कि देश के व्यक्तियों की स्थितियाँ बदलनी हैं वे कहते हैं

"All Governments... .. show a preference for projects that can be inaugurated"

उनका कथन है

"यह बात कोई गलत नही है, क्योंकि इस प्रकार की विशिष्ट योजनाएँ (specific projects) सोए हुए समाज को जगा देते हैं, वे जागरूकता बढ़ाने के लिए उदाहरण तो बन जाते हैं. उनका कथन है कि निजी क्षेत्र के व्यक्ति स्वयं ही अपनी-अपनी योजनाओं के लिए Infra-structure तैय्यार कर लेंगे (अर्थात् पानी, बिजली, कुशल श्रमिकों की व्यवस्था कर लेंगे"

वे मानते हैं कि इस प्रकार की तकनीक अपनाना उल्टा कार्य होगा. (It is no doubt inverted development) परन्तु कालान्तर में इससे मजबूत आधार शिला पर सर्वाङ्गीण विकास हो सकेगा उदाहरणतया अगर हम पहले शराब बनाने या रबड़ के टायर बनाने के कारखाने स्थापित करें और कच्चा माल बाहर से मगाएं तो कालान्तर में वे देश ये कच्चे माल को स्वयं उत्पादन करने लगेंगे और फिर Secondary sector द्वितीयक क्षेत्र की उन्नति से Primary sector या कृषिक्षेत्र भी उन्नत हो जाएगा

इस सबंध में हिर्शमैन कुछ अन्य बातों की ओर भी ध्यान खींचना चाहते हैं, जो इस प्रकार हैं

(i) बड़ी-बड़ी विशिष्ट योजनाओं के साथ-साथ शिक्षा, छोटे उद्योग तथा सहयोगी उद्योगों पर भी ध्यान देते रहना चाहिए.

(ii) विशेष रूप से ऐसे उद्योग स्थापित करना चाहिए जिसमें सुधार कार्य maintenance बहुत कम हो या फिर सुधार कार्य इतने महत्वपूर्ण हों कि उन्हें टाला नहीं जा सकता है. हिर्शमैन उदाहरण देते हैं . सड़कों का सुधारकार्य टाला जा सकता है परन्तु हवाई उड़ान संबंधी किसी भी सुधारकार्य को टाला नहीं जा सकता. इसलिए अगर विशिष्ट कार्य हाथ में लिए गए तो वे हमेशा अच्छी हालत में रखे जाएँगे, और specific projects से ही कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है [1]

---

1. He says:
"Under-developed countries are characterized not only by a low rate of investment, but also by the low efficiency of

(iii) विनियोजन करने से पहले कई मुद्दों पर विचार कर लेना चाहिए जैसे (a) क्या विनियोजन आयात प्रतिस्थापन्न करे या निर्यात वर्धन में सहायक हो, (b) क्या विनियोजन से उत्पादकता बढ सकती है और क्या (c) उद्योग व कृषि में समन्वय आवश्यक है.

The Reinvestment quotient

Galenson तथा Leibenstein ने एक "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" में विनियोजन की कल्पना की है. अगर विकास करना है तो इसके लिए इस "अत्यावश्यक न्यूनतम मात्रा" से कम विनियोजन से कोई लाभ न होगा. अगर इस मात्रा से कम-विनियोजन किया गया तो अर्थव्यवस्था पिछडी अवस्था में ही बनी रहेगी. विनियोजन की यह न्यूनतम मात्रा इतनी होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों का मुकाबला करते हुए भी विकास सभव हो सके. विनियोजन इतना और इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे लाभ हो और जिससे बचतो व पूजी-निर्माण में वृद्धि हो सके. इसके लिए मजदूरी दरो को कम रखना भी आवश्यक होगा. इनका विश्वास है कि पूंजी-गहन तकनीक से ही और अधिक विनियोजन के लिए पूंजी मिलेगी तथा दीर्घकाल में अधिक रोज़गार का सृजन होगा

विनियोजन को "Highest marginal per-capita reinevestment quotient." देना चाहिए, अर्थात् अधिकतम पुनर्विनियोजन योग्य धन उपलब्ध कराना चाहिए. Reinvestment quotient को हम "प्रति व्यक्ति उत्पादकता में से प्रति व्यक्ति उपभोग घटाकर अनुपात निकाल कर पता लगाते है."

विपक्ष : आलोचनाएँ :

Hollis B Chenery, Henry villard तथा O. Eckstein ने पूजी-गहन तकनीक की आलोचना की है. उनका कथन है कि इस नीति से :

---

much of the investment that is actually undertaken. This is due in part to the many false starts that will necessarily be made before a country's economy is really launched on a secure course, and in part of the lack of qualified engineers, agronomists, economists etc, who can produce really useful and well thought, though specific, investment projects"..... thus the most important-task for the economist is to make a contribution to the elaboration of sensible sector programmes and specific investment projects." op. cit p. 42-43.

(i) कम-विकसित देशों को पूंजी जुटाने के लिए बहुत अधिक कर लगाना पड़ेंगे, उपभोग (जो पहले से ही कम है) कम करना पड़ेगा, या फिर विदेशों से बहुत अधिक ऋण लेना पड़ेंगे.

(ii) मजदूरी कम रखने से मजदूरों का जीवन स्तर गिरा रहेगा उनकी कार्य-क्षमता शिक्षा व ट्रेनिंग कम रहेगी तथा सामाजिक असन्तोष बढ़ेगा.

(iii) बेरोजगारी को बनाए रखना देश के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से न केवल घातक होगा वरन् इसके गम्भीर राजनैतिक व सामाजिक दुष्परिणाम होंगे.

(iv) इस पद्धति में वर्तमान उपभोग को कम करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में उपभोग स्तर ऊँचे हो सकें परन्तु जनसाधारण इस सम्भावित वृद्धि के प्रति उदासीन हो जाते हैं

"After all investment choice is to be so made as to maximize the present value of the future consumption stream......endless growth for its own sake does not make to much sense. There may be circumstances in which the current consumption may be a more immediate concern"

(c) The Concept of Social Marginal Productivity **सामाजिक उत्पादकता वृद्धि का मानदण्ड** : A. E kahn, H B. chenery, Everelt. E Hagan,

यह मानदण्ड सर्वप्रथम काहन् Kahn ने 1951 में प्रतिपादित किया. यह सिद्धात अर्थशास्त्र के जाने माने "सीमान्त उपयोगिता या उत्पादकता सिद्धान्त" का ही प्रतिरूप है. यह सिद्धात इन शब्दों में व्यक्त किया गया

(i) W. Galenson and H Leibenstein, "Investment Criteria, Productivity and Economic Development", Quarterly Journal of Economics August 1955 p. 343-70

(ii) आप Leibenstein Model का अध्याय भी देखें

Eckstein : Investment criteria for Economic development and the Theory of Inter-temporal welfare Economics, Quarterly Journal of Economics Feb. 1957. p. 56 85.

"The correct criteria for obtaining the maximum return from limited resources is the social marginal productivity, taking into account the total met contribution of the marginal unit to national product and not merely that portion of the contribution (or its costs) which may accrue to the private investor"

अर्थात कम-विकसित देशों में दुर्लभ साधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए "सीमान्त सामाजिक उत्पादकता" सिद्धान्त अपनाना चाहिए अर्थात् विनियोजन से होनेवाले निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को ध्यान में रखना चाहिए.

अन्य शब्दों में कम विकसित देशों में भिन्न-भिन्न योजनाओं में विनियोजन इस प्रकार से किया जाए कि समस्त उद्योगों की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता बराबर या लगभग बराबर हो. अगर कहीं विनियोजन की सीमान्त सामाजिक उत्पादकता कम हो तो वहाँ से साधनों का हस्तान्तरण वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ विनियोजन की सीमान्त उत्पादकता अधिक हो

Hagan के शब्दों में

"In a sense there is only one relevant economic criterion. In its usual statement it is that

---

A K Khan : Investment-criteria in Development Programmes, Quarterly Journal of Economics, Feb 1951. p 38 61

H. B. Chenery The application of Investment criteria, Quarterly Journal of Economics, Feb 1953, p. 76-96.

E V. Hagan : op. cit

See : Meier's : op cit & Asia Publishing House's op. cit.

See also :

I L O, "Social Productivity and Factor intensity criteria some aspects of the investment Policy in under-developed countries International Labour Review Vol Lxx VII, No. 5 May 1958 p p 289-90, 393-7, 400-4, 411-15,

Hagan : op-cit : Cf G Meier op-cit p. 58.

projects which comprise an investment programme should be so selected among alternative sectors, projects, methods and geographical locations that no included use of capital yields a lower social marginal product than any excluded use and by marginal product is meant total met value added, and not merely return to Capital"

"वास्तव में, एक मायने में, विनियोजन का एक ही मानदण्ड है और वह यह है कि भिन्न-भिन्न योजनाओं, कार्यों, क्षेत्रों व कार्य प्रणालियों में विनियोजन इस प्रकार से किया जाए कि जिसमे विनियोजन किया गया है उसमे सीमान्त सामाजिक उत्पादकता उससे कम न हो जिसे छोड़ दिया गया है"

इन अर्थशास्त्रियों का कथन है कि अगर इस मानदण्ड के आधार पर विनियोजन किया गया तो "Accounting Prices" या "Shadow prices" का सहारा लेना होगा Shadow prices "वे काल्पनिक मूल्य है जो अगर बाजार में हो तो अपेक्षित साम्य स्थापित किया जा सकता है' यह विचार J Tinbergen, Chenerv तथा K S Kretschmer ने प्रस्तुत किया Accounting or shadow prices की यह परिभाषा प्रस्तुत की

"Shadow prices are the values of the marginal productivity of factors when a selection of technique has been made which produces the maximum possible volume of output, given the availability of resources, the pattern of final demand and the technological possibilities of production"

(अर्थात् ये वे मूल्य है जो अगर स्थापित कर दिए जाए तो अधिकतम उत्पादन करने मे सहायक होगे)

See also :

R. S. Eckaus Technical change in the less Developed Areas, in the Development of the Emerging countries, Making an optimal choice of Technology.

इन अर्थशास्त्रियो का कथन है कि राज्य का कर्तव्य यह है कि वह उत्पादन के अगो व क्षेत्रो की सीमान्त उत्पादकता को आंके तथा अर्थव्यवस्था को, करो व सहायता द्वारा, इस प्रकार से सचालित करें कि समस्त पूर्ति के अगो की सीमान्त उत्पादकता बराबर हो इस मानदण्ड के अनुसार विनियोजन करने के लिए केवल यह ही आवश्यक नही है कि अलग-अलग क्षेत्रो की सीमान्त उत्पादकता का पता लगा लिया जाए मुख्य समस्या तो उत्पादनकर्ताओ की करो व सहायताओ से सबधित प्रतिक्रिया को अध्ययन करना है

आलोचना :

S M P Criteria या सीमान्त उत्पादकता के मानदण्ड की सबसे मुख्य आलोचना तो यह है कि (1) सीमान्त उत्पादकता का निकालना कठिन है. कम-विकसित देशो मे मूल्य निर्धारण पद्धति आधुनिक नही होती और न ही सारी अर्थ-व्यवस्था मौद्रिक मान पर सचालित होनी है. इन देशो मे श्रम की बेरोजगारी व मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति के कारण मूल्य स्तर 'वास्तविक" नही होता वास्तव में इन देशो मे मूल्यो मे कितने ही परिवर्तन करें, देश मे सामाजिक सीमान्त उत्पादकता बराबर नही की जा सकती.

Otto Eckstein, Galenson तथा Leibenstein इस मानदण्ड की आलोचना करते है. इस मानदण्ड मे (2) जनसख्या की वृद्धि का विनियोजन पर क्या प्रभाव पडना चाहिए. यह अध्ययन नही किया जाता इनका विचार यह भी है कि सीमान्त उत्पादकता के स्थान पर "औसत उत्पादकता" वृद्धि का विचार

"The more extensively one adjusts market prices upwards or downwards to allow for social factors is the more one uses shadow or accounting prices in calculating social marginal productivity, the farther one gets from the realm of objective facts and the more heavily one relies on subjective value judgements It is arguable that by the time one has finished making all the adjustments to private marginal productivity that would be needed to convert it into social marginal productivity one will be left with a concept so tenuously related to anything. That is objectively measurable that one might as will sever the connection altogether and admit that marginal analysis can provide no practical guidance to governments in taking investment decisions "

I. L. O. op. cit.

अधिक महत्वपूर्ण है. इस मानदण्ड के आधार पर ऐसी योजनाएँ भी हाथ मे ली जा सकती है जो शून्य लाभ देती हो और इस मानदण्ड के अनुसार विनियोजन करने से बहुत अधिक कर लगाने पड़ेंगे (क्योंकि सामाजिक आर्थिक सिरोपरी का सृजन करना होगा).

(d) Investment to control specific problem विशिष्ट समस्याओं के निवारण हेतु विनियोजन.

भुगतान संतुलन हेतु :

कम-विकसित देश विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयों मे फसे रहते हैं उनका भुगतान सतुलन बहुधा विपक्ष में रहता है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था "drain economy" बनी रहती है कम विकसित देशों में आयात प्रतिस्थापक उद्योग तथा निर्यात-वर्धक उद्योगों की स्थापना के लिए विनियोजन किया जा सकता है वास्तव में यह बात उतनी सरल नहीं है, क्योंकि इन उद्योगो की स्थापना हेतु और अधिक विदेशी मुद्रा चाहिए होती है. इसलिए इस प्रकार का विनियोजन विदेशी सहायता के बगैर सम्भव नहीं रहता. दूसरी कठिनाई इस सम्बन्ध में यह आती है कि इस प्रकार के विनियोजन से जो मुद्रा स्फीति फैलती है उससे निर्यात हतोत्साहित व आयात प्रोत्साहित होते हैं इसलिए मुद्रा स्फीति को उत्पन्न न होने देना चाहिए अथवा नियन्त्रित रखना चाहिए

निर्यात-वर्धक या आयात प्रतिस्थापक विनियोजन स्वय मे विकास नहीं लाता. कम विकसित देशो मे विदेशी विनियोजकों ने इन देशो के कच्चे सामान के निर्यात-वर्धक उद्योग व बागान चलाए परन्तु फिर भी इन देशो मे आर्थिक विकास नहीं हुआ.

मुद्रा स्फीति नियंत्रण :

कम-विकसित देशो मे मुद्रा स्फीति की स्थितियाँ हमेशा मौजूद रहती है. विकास न होने पर वस्तुओं की कमी के कारण अथवा विकास के शुरू के दिनों मे विनियोजन के कारण मौद्रिक प्रसार वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति फैल जाती है. ऐसे दिनों मे विनियोजन रीति में परिवर्तन करके मुद्रा स्फीति पर नियत्रण किया जा सकता है. पूजी गहन उद्योगों मे विनियोजन के स्थान पर श्रम-गहन उद्योगो मे, शीघ्र उत्पादन करने वाले उद्योगो में, तथा मुख्य रूप से उपभोग उद्योगों मे विनियोजन बढाकर मुद्रा स्फीति नियन्त्रित की जा सकती है.

इस नीति मे विकास के लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान न देकर स्थायित्व की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है.

(e) The time factor Criteria **समयानुसार आयोजन का मानदण्ड :** अगर किसी देश मे आयोजन के फल अल्पकाल मे ही सामने लाना है तो श्रम-गहन तक्नीका म विनियोजन करना होगा और अगर ऐसी कोई जल्दी न हो तो पूँजी-गहन तकनीक मे विनियोजन किया जा सकता है. समाजवादी देशो मे दीर्घकालीन आयोजन इसलिए भी आसानी से कर लिया जाता है कि इन देशो में जनता अल्पकालिक फल के लिए उतावली नही होती क्योकि राज्य का कडा नियत्रण रहता है

III Conclusion & Practical Considerations निष्कर्ष तथा विनियोजन मानदण्ड का व्यावहारिक पक्ष

उपरोक्त विनियोजन मानदण्ड मे से कौन सा अच्छा है यह निश्चितरूप से नही कहा जा सकता.

D. Bright Singh के शब्दो में

> "विभिन्न अर्थशास्त्रियो द्वारा प्रतिपादित विनियोजन के मानदण्ड त्रुटिपूर्ण है. विनियोजन मानदण्ड की समस्या इतनी जटिल है कि एक ही सही मानदण्ड का चयन असभव है विकास के लक्ष्यो में ही समन्वय व एकरूपता नही होती, तो विनियोजन के मानदण्डो में भी समन्वय नही हो सकता."

Gerald Meier का भी कथन है

> "No criteria is good for all times and under all conditions No single criteria can be selected Then there is still the problem of practical application" op. cit

Rosenstein Rodan के अनुसार ·

> "विनियोजन के मानदण्ड को निर्धारित करने का अर्थ, प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओ में विनियोजन करना है. हमको

1 D B Singh op cit p. 253

2 Douglas Dosser Practical conditions facing Investment choice—General Investment criteria for less developed countries A post mortem Scottish Journal of Pol Econ Vol-IX No 2 June 1962, cf G Meier. p. 247–50

इस संबंध में यह निश्चित करना पड़ता है कि क्या यह योजना या कार्य आवश्यक है, क्या वह सही स्थान पर है, क्या उसका संचालन ठीक है, आदि''

परन्तु व्यवहार में शायद ही कोई कार्य या योजना इतनी अधिक मात्रा में पूर्व अनुमानों पर आधारित होती है. अगर सही मायने में समस्त मानदण्डों के आधार पर विनियोजन किया जाए तो शायद कुछ ही योजनाओं पर ही कार्य शुरू किया जा सकेगा यू. एस ए. जैसे देशों में आधे से ज्यादा कार्य शुरू ही नहीं किए जा सकेंगे

निष्कर्ष :

विनियोजन का एक मानदण्ड नहीं है फिर भी इन बातों को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए.

1. कुछ उद्योग पूँजी-गहन हो तो छोटे पैमाने के (श्रम-गहन) उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए.
2. विनियोजन को रोजगार में वृद्धि लाना चाहिए.
3. देश में विकास की दर में वृद्धि होना चाहिए, उत्पादकता वृद्धि का लक्ष्य भी प्राप्त होना चाहिए.
4. वर्तमान व भविष्य की पूँजी व उपयोग आवश्यकताओं में समन्वय होना चाहिए.
5. निर्यात-वर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए.
6. किसी भी देश की तकनीक की अन्धाधुंध नकल नहीं करना चाहिए.
7. विनियोजन नीतियों को सामाजिक व राजनैतिक स्थिति के अनुसार भी बनाना चाहिए विनियोजन नीतियों से अधिक से अधिक लोगों को सन्तुष्टि प्राप्त होना चाहिए. देश की सामाजिक रुकावटों को भी दूर करना चाहिए.
8. विनियोजन कार्यक्रम कुशल कार्यकर्ता, मैनेजर आदि के कारण असफल हो जाता है इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग सुविधाओं में भी विनियोजन करना चाहिए

See ·

General characteristics of the Problem and comments on the conference on Investment criteria, in Asia's op. cit. by William vellner. p. 122-155

IV. Should Investment be controlled by market mechanism or should it be controlled by Government : क्या विनियोजन मूल्य प्रणाली से संचालित हो या राज्य द्वारा निर्धारित हो ?

पुराने अर्थशास्त्री यह विश्वास करते थे कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से देश में अधिकतम व अनुकूलतम विनियोजन होगा और इससे अधिकतम उत्पादन व विकासदर प्राप्त होगी परन्तु बहुत से कारण ऐसे हैं जिससे यह लक्ष्य स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली से प्राप्त नहीं होंगे ये कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं

(i) निजीक्षेत्र के उत्पादनकर्ता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही विनियोजन करते हैं इनके विनियोजन से बाह्य मितव्ययिताओं का सृजन नहीं होता.

(ii) निजीक्षेत्र के किसी भी उत्पादनकर्ता या विनियोजक का दृष्टिकोण व्यापक नहीं होता और उसमें इतनी दूरदर्शिता नहीं होती कि वह समस्त अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप विनियोजन करे.

(iii) स्वतन्त्र मूल्य पद्धति से Lump Investment बड़े पैमाने का विनियोजन संचालित नहीं होता

Paul N. Rosenstein-Rodan का कथन है

> "स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली उपभोग को तो नियन्त्रित कर सकती है परन्तु विनियोजन को नियन्त्रित नहीं कर सकती इसके लिए विवेकपूर्ण, विचार पूर्ण, एकरूपता लिए हुए व समन्वित नीति आवश्यक होगी. राज्य का लक्ष्य रोजगार व उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए."

इनका विचार है कि मूलभूत निर्णयों को[1] (कितना व किन क्षेत्रों में) राज्य करे तथा प्रशासनीय व व्यवस्था संबंधी निर्णयों को विकेन्द्रित रूप से किया जाना चाहिए जबतक कि इन बड़े-बड़े निर्णयों को राज्य नहीं लेगा तब तक देश में संतुलित विकास नहीं होगा क्योंकि देश में आर्थिक व सामाजिक सिरोपरी सुविधाओं का सृजन नहीं होगा.

See :
Programming in the Theory in the Italian Practice Paul N Rosenstein-Rodan. Asia's op cit.
मूल्य नीति संबंधी अध्याय भी पुन देखिए.

1 "Decision as to how much to invest cannot be taken on dispessal basis The collective choice may be philosophically indefensible but it is practically irrefutable."

अध्याय : 11

जनसंख्या व विकास

Population and Economic Growth

भाग 1

I. प्रस्तावना : सह-संबंध का स्वभाव :

(a) जनसंख्या व पूंजी-निर्माण,
(b) जनसंख्या व तकनीक का चयन.
(c) जनसंख्या व राष्ट्रीय आय.
(d) जनसंख्या व रोजगार.

भाग 2

जनसंख्या नीति

I. "जनसंख्या नीति" का अर्थ व क्षेत्र :

(a) परिवार नियोजन : जन्म दर में कमी लाने की आवश्यकता : अर्थ : महत्व : रुकावटें व विरोध : आपत्तियों की निर्मूलता : क्या किया जा रहा है भारत में परिवार नियोजन . कम-विकसित देशों में परिवार नियोजन को सफल बनाने के उपाय.
(b) खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि व संतुलित आहार.
(c) जनसंख्या का देश व विदेशों में विवेकशील वितरण.
(d) शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन.
(e) अनुकूलतम जनसंख्या.

निष्कर्षरूपीय नोट.

अध्याय : 11

जनसंख्या व विकास

Population and Economic Growth

भाग 1

I. प्रस्तावना . सह-संबंध का स्वभाव

जनसंख्या और विकास मे महत्वपूर्ण सह-संबंध होता है विकास से जनसंख्या की जन्म व मृत्यु दरा मे, जीवन काल या आयु मे, जनसंख्या की सरचना पर, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण, घनत्व आदि सब पर प्रभाव पड़ता है.

उसी तरह से जनसंख्या के शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर, उन्नत तक्नीक के प्रति मनोवृत्ति, परिवार नियोजन के प्रति मनोवृत्ति, जन्म व मृत्यु दर आदि का पूंजी-निर्माण, विनियोजन, तकनीक आदि अर्थात् राष्ट्रीय आय या विकास पर महत्वपूर्ण असर होता है

परन्तु यह समझना भूल होगी कि यह सह-संबंध पूर्णतया धनात्मक है. यह स्थिति भी है कि विकास की दर के अधिक होने पर भी जन्मदर मे परिवर्तन नही आता या कई ऐसे भी विकसित देश है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कम-विकासत देशो से कम न होते हुए भी (यू० एस० ए०, आस्ट्रेलिया, कनाडा व न्यूजीलैंड[1]) विकास दर कही अधिक है आज विश्व मे कम व अधिक घनत्व दोनो प्रकार के कम-विकसित देश हैं तात्पर्य यह है कि जनसंख्या विकास का एक घटक है और यह विकास मे बाधक व सहायक दोनों हो सकती है.

हम सब जानते है कि एशिया मे जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मूल रूप से विकास मे बाधा के रूप म सामने आता है, जबकि योरोप और अमेरिका मे वह सहायक है जनसंख्या वृद्धि मुख्यतया चार प्रकार से विकास म बाधक होती है ·

(1) इसमे भूमि व प्राकृतिक साधनो पर दबाव डालती है.

---

1 Villard op cit
See ·ch 6. The Population obstacle to economic Betterment : Spengler & Duncan.

(ii) इससे प्राकृतिक साधनों का ह्रास होता है और उत्पादन लागत बढती है.

(iii) इससे बचतें व पूँजी निर्माण कम होती है और

(iv) बहुत सा विनियोजन देश को यथा-स्थिति मे रखने मे ही निकल जाता है. देश म 2% विकास दर तो इसी वृद्धि के कारण आवश्यक हो जाती है.

कम-विकसित देशो में जनसख्या वृद्धि से गम्भीर समस्याएँ पैदा होती है एक जोडा ही (स्त्री व पुरुष) 1% प्रतिवर्ष जनसख्या वृद्धि दर से दसहजार सालो मे :

1340,000,000,000,000,000,000, (1340×10^{18})

तक जनसख्या ले जाती है.

किसी भी देश मे "अनुकूलतम जनसख्या" से ऊपर जनसख्या निकलने पर आर्थिक विकास रुकता है. आज विश्व की वही जनसख्या जिसमें वृद्धि रुक गई है या बहुत कम है (50 वर्षो मे 50 %) वही समृद्ध है. विश्व की 40% जनसख्या में वृद्धि दर अधिक है और यहाँ सबसे बडी आवश्यकता सस्ते परिवार नियोजन के साधन की है.

इस अध्याय में हम निम्नलिखित बातो पर विचार करेगे

(a) जनसख्या व पूंजी-निर्माण

(b) जनसख्या व विनियोजन तथा तकनीक चयन.

(c) जनसख्या व प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय

(d) जनसख्या बढे, स्थिर रहे या घटे.

(a) Population and Capital Formation जनसंख्या व पूंजी-निर्माण :

पूँजी-निर्माण के अध्याय में हम पूँजी-निर्माण का महत्व पढ चुके है जिस देश मे जितना अधिक पूँजी-निर्माण होगा उस देश मे उतनी ही अधिक जनसख्या को उच्च स्तर दे सकते है. अधिक पूँजी-निर्माण से जो विकास होता है वह स्वय ही जन्मदर घटा देता है और जनसख्या वृद्धि ही कम हो जाती है

यहाँ पर हमको जनसख्या का पूँजी-निर्माण पर प्रभाव अध्ययन करना है. जनसख्या का पूँजी-निर्माण पर क्या असर पडेगा अथवा कितनी मात्रा में पूँजी-निर्माण को

A. B Wolfe · op cit · (See at the end of the chapter)

आवश्यकता होगी. यह जन्म व मृत्यु दर की अवस्थाओं पर निर्भर करेगा यह अवस्थाएँ इस प्रकार हो सकती है.

ऊँची जन्मदर व ऊँची मृत्युदर :

अधिकाश पिछडे कम-विकसित देशों मे जन्म व मृत्यु दरे ऊँची होती है. कम आय व निम्न जीवन स्तर, पिछडी व कम मात्रा मे स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं के कारण आयु कम होती है बच्चे भी अधिक पैदा होते है. ऐसे देशो मे जनसख्या वृद्धि या तो होती नही है या बहुत कम होती है. इस स्थिति से पूँजी-निर्माण कम होता है अधिक जनसख्या से प्रति व्यक्ति आय व बचतें कम होती है. पिछड़ेपन के कारण बहुत सी बचते "अनार्थिक रूप" मे रहती है या फिजूल खर्ची म उपभोग कर ली जाती है. दूसरी ओर इस अल्पपूँजी-निर्माण का भी पूर्ण प्रयोग नही हो पाता. बहुत से बच्चे जवान होने से पूर्व ही मर जाते है और वे केवल उपभोगकर्ता के रूप मे जीवित रह कर, अर्थात् वगैर उत्पादनकर्ता बने, ससार से चले जाते है यह समस्त विनियोजन बेकार जाता है, इस प्रकार की जनसख्या में इस प्रकार से कम पूँजी-निर्माण होता है और पूँजी की बर्बादी भी होती है

ऐसी अवस्था से निकलने के लिए पूँजी-निर्माण अधिक होना चाहिए और जन्म व मृत्यु दरो को नीचे आना चाहिए

ऊँची जन्मदर व कम मृत्युदर ·

जब कम-विकसित देशो म जन्म व मृत्यु दरा को घटाने के प्रयास किए जाते है तो पहले मृत्युदर घट जाती है स्वास्थ्य की सुविधाओं मे सुधार से मृत्यु दर शीघ्र गिर जाती है परन्तु जन्मदर के गिरने में समय लग जाता है. यह "सक्रामक काल" होता है इस काल मे बहुत अधिक मात्रा मे पूँजी-निर्माण की जरूरत होती है. इस अल्पकाल मे बहुत त्याग की आवश्यकता होती है, इस काल मे ही हर तरह से (मौद्रिक, राजकोषीय व अन्य नीतियों से) पूँजी-निर्माण की आवश्यकता होगी.

नीची जन्मदर व मृत्युदर :

इस अवस्था को देश काफी उन्नति के बाद प्राप्त करता है. इस अवस्था में स्वय ही अधिक पूजी-निर्माण, विनियोजन व उपभोग सम्भव होता है यह अवस्था उन्नत देशो मे रहती है.

नीची जन्मदर व ऊँची मृत्युदर · या नीची मृत्युदर व उससे भी नीची जन्मदर :

ऐसे समाज में पूँजी-निर्माण की समस्या पैदा नही होती. इस समाज की मुख्य समस्या तो अपनी जाति या जनसख्या को समाप्त होने से बचाना रहती है

अधिक घनत्व व पूँजी-निर्माण .

जिन देशों में जनसख्या का घनत्व अधिक होता है उनमे खाद्य सामग्री पैदा करने, जमीन की उत्पादकता बढाने, नई जमीन पाटने व उसम उन्नति करने, कृषि को उन्नत करने, देश मे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएँ बढाने, सामाजिक व आर्थिक सिरो-परि सुविधाएं प्रदान करने, तथा आवास व उद्योग की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अधिकाधिक पूँजी की आवश्यकता होती है.

जैसा कि हम देख चुके हैं कम-विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 5-7% भाग बचाते हैं जब कि विकसित देशो मे यह भाग 25-30% तक होता है. अगर कम विकसित देशों में जनसख्या मे 1 25% वार्षिक वृद्धि हो और अगर Capital-output ratio हो तो 5% पूँजी तो जनसख्या वृद्धि के कारण स्थिति को यथावत् रखने म हो निकल जाएगी

Hobbs का कथन है

> "जब जनसख्या बढती है तो व्यक्तियो के Time horizons (समय क्षितिज) बहुधा छोटे हो जाते हैं (अर्थात् वे दूर भविष्य की बात नही सोचते) वे वर्तमान की आवश्यकताओ को सतुष्ट करने मे ही अधिक धन खर्च कर देते हैं उनको भविष्य के बजाय वर्तमान की आवश्यकताओ की सतुष्टि पर ज्यादा ध्यान देना पडता है, इससे पूजी-निर्माण कम हो जाता है परन्तु अगर परिवार के सदस्य विवेक-शील है तो यह Time horizon लम्बा हो जाता है. ऐसे लोगों की बचत क्षमता उतनी ही रहते हुए वे बचतो को बढाने के लिए प्रेरित रहते हैं."

सक्षेप मे जनसख्या और पूजी-निर्माण म सह सम्बन्ध है. अधिक पूँजी-निर्माण से जो विकास होता है उससे अधिक ऊँचा जीवन स्तर होता है अधिक जनसख्या पूँजी-निर्माण मे बाधक है परन्तु अधिक जनसख्या के लिए अधिक पूँजी आवश्यक होती है

(b) Population Growth and Technology जनसंख्या व तकनीक

जनसख्या का तकनीक स्तर पर भी गहरा प्रभाव पडता है अगर देश की जनसख्या शिक्षित है तथा उन्नति की आकाक्षी है तो वे नई तकनीक को खोजते हैं या अपना लेते हैं अशिक्षित व उदासीन जनसख्या पिछडी तकनीक ही अपनाए रहती है इसीलिए शहरी जनसख्या पहले उन्नत तकनीक को अपना लेती है

जनसख्या की मात्रा तथा उसकी वृद्धि दर भी तकनीक या विनियोजन मानदण्ड

को अपनाने पर प्रभाव डालती है. जैसा कि हम देख चुके हैं,[1] अगर किसी देश में जनसख्या अधिक है तो ऐसे देश मे श्रम-गहन तकनीक को अपनाना पड जाता है अगर ऐसा देश पूँजी-गहन तकनीक अपनाता है तो यह महगा भी पडता है और देश मे बेरोजगारी की समस्या का निराकरण भी नही हो पाता अल्पकाल में ऐसे देश को श्रम गहन तकनीक के कार्यों को अधिक मात्रा में हाथ मे लेना चाहिए परन्तु एक अधिक जनसख्या वाला देश पूर्ण रूप से पूजी-गहन तकनीक के उद्योगो को नही त्याग सकता.

अगर किसी कम-विकसित देश मे जनसख्या का घनत्व कम है अथवा जनसख्या वृद्धि की दर कम है तो ऐसे देश में पूजी-गहन तकनीक को अपनाना सरल होगा ऐसे देश मे तकनीकी उन्नति भी शीघ्र हो सकेगी. इन देशो मे पूजी-गहन तकनीक अपनाने पर श्रम आन्दोलन भी नही होगे.

जहाँ तक विकास का प्रश्न है वह तो किसी भी तकनीक के अपनाने से हो सकता है वास्तव मे कोई भी देश पूर्ण रूप से श्रम-गहन तकनीक के उद्योग या पूजी-गहन तकनीक के उद्योग नही अपना सकता उसको दोनो तकनीको के उद्योग रखने पडते है. प्रश्न केवल अधिक या कम मात्रा का रहता है.

(c) Population And Per-Capita Income & Economic Conditions : जनसख्या तथा प्रति-व्यक्ति आय व आर्थिक स्थितियाँ :

जनसख्या मे परिवर्तन से प्रति-व्यक्ति आय व आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पडता है इस पर निश्चितता से कुछ नही कहा जा सकता इनमे सह-सबध जटिल है. जनसख्या वास्तव मे परिवर्तन से दूसरे घटक पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्तन होते है और इससे भी पुन जनसख्या पर प्रभाव पडता है. जनसख्या परिवर्तनो का वास्तविक आय या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कई बातो पर निर्भर करती है

अगर जनसख्या का अनुपात अन्य उत्पादन अगो के मुकाबले मे बढता है, तो अन्य बाते समान रहे, तो प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन व आय घट जाएगी इसका मूल कारण यह है कि श्रम, भूमि, पूजी तथा सगठन का पूर्ण प्रतिस्थापक नही है कम-विकसित देशो मे पूंजी की मात्रा उतनी ही रहने के कारण, जनसख्या बढने से हर व्यक्ति के पास पहले से कम पूजी रह जाती है (Increase in population or labour force means that it becomes less equipped than before with capital remaining the same) जनसख्या बढने का प्रति व्यक्ति उत्पादन पर प्रभाव उस समय अधिक होता है

1 पिछला अध्याय देखिए

जबकि उत्पादन मुख्यतया भूमि या बढाए न जा सकने वाले प्राकृतिक साधनो पर निर्भर रहता है जहां भूमि व प्राकृतिक साधनो का योगदान कम रहता है, वहाँ जनसख्या वृद्धि का उत्पादन पर कम प्रभाव पडता है अगर कोई अर्थव्यवस्था, विदेशी विनिमय प्राप्त करके अथवा किसी अन्य युक्ति से उत्पादन मे भूमि व प्राकृतिक साधनो के योगदान के अनुपात मे पूजी का योगदान बढा दे (अर्थात् पूजी बढा दे) तो जनसख्या बढने के दुष्प्रभाव कम हो जाएगे.

अगर किसी देश में जनसख्या कम हो रही हो तो वह देश घटिया भूमि या घटिया प्राकृतिक साधनो का प्रयोग छोडकर, उत्तम तकनीक अपनाकर उत्पादन बढा सकता है.

(d) Should there be Increasing, Declining or Stationary Population for full employment ? **क्या देश में पूर्ण रोजगार के लिए बढती, घटती या स्थिर जनसंख्या आवश्यक है ?**

विकसित देशों में पूर्ण रोजगार के लिए बढती हुई जनसंख्या ?

A. H. Hansen's Thesis

A H Hansen's ने यह विचार प्रतिपादित किया है कि विकसित देशो मे पूर्ण रोजगार कायम रखने के लिए बढती हुई जनसख्या आवश्यक है. उनकी यह विचारधारा केन्स के "सामान्य सिद्धान्त" पर आधारित है केन्स के अनुसार घटती हुई जनसख्या से प्रभावशील माँग कम होती है और विनियोजन के कम होने से रोजगार कम होगा D. H. Handerson ने भी यही डर व्यक्त किया है कि घटती हुई जनसख्या विकसित देशो का विकास रोक सकती है

बहुत से पश्चिमी देशो मे इस बात से बहुत चिंता उत्पन्न हो रही है कि बच्चे पैदा करने वाली स्त्रियाँ अपना पुन स्थापन ही नही कर रही है.

"आस्ट्रिया मे यह कमी ·36, फ्रान्स मे ·14, स्वीडेन मे 30, जर्मनी ·11, इग्लैण्ड व वेल्स मे ·24 तथा यू० एस० ए० मे 06 है"
(Population Index 1939)

Myrdal भी घटती जनसख्या की प्रवृत्ति से भयभीत हुए है उनके अनुसार .

"विकासशील पूँजीवादी प्रणाली मे प्रगतिशील जनसंख्या विकास की प्रथम आवश्यकता है घटती हुई जनसख्या से चारो ओर विनियोजन जोखिम बढ जाता है."
(Population, A problem for democracy p. 164.)

See : Reference at the end of the chapter .

A H. Hansen ने विकसित देशो मे पूर्ण रोजगार कायम रखने के लिए बढती हुई जनसख्या की आवश्यकता पर बल दिया है. उन्होने माल्थस की कडी आलोचना की कि उन्हाने जनसख्या की वृद्धि में रुकावट को अच्छा माना था हन्सेन का कथन है

> 'माल्थस कि तुलना में एडम स्मिथ के विचार बहुत अधिक सतुलित थे बढती हुई जनसख्या से श्रम-विभाजन जटिल होता है और अधिक उत्पादन व उत्पादकता की वृद्धि होती है इससे पूँजी-निर्माण बढता है और स्वय श्रम की माग बढती है हन्सेन का कथन है कि वास्तव मे आज भी एडम स्मिथ का यह विचार ठीक है कि बढती हुई जनसख्या से आर्थिक उन्नति होती है. आज पुन एडम स्मिथ के प्रवैगिक विश्लेषण को अपनाने की आवश्यकता है "

बढती हुई जनसख्या से देश मे प्रभावशील माँग कायम रह सकती है. बढती हुई जनसख्या से आवास सुविधाओं को बढाने के लिए पूँजी को विस्तृत क्षेत्र में विनियोजित करना पडता है हन्सेन के शब्दो मे

> "It is my growing conviction that the combined effect of the dicline in population growth, together with the failure of any really important innovations of a magnitude sufficient to absorb large capital outlays, weighs very heavily as an explanation for the failure to recent recovery to reach full-employment.........Developed countries may face the problem of declining investment opportunities as a result of cessation of population growth and disappearing of new territories for settlement and expansion......"

(अर्थात् यह मेरा बढता हुआ पक्का विश्वास है कि जनसख्या के घटने

Ch. 5 of Spengler & Duncan's "Population Theory and policy" The Free Press of Glencoe 1963 —"Populations movements Employment & Income " p 252 & 272, ch 9. p 448

Hansen's paper : Economic progress & Declining population Growth.

का (साथ साथ महत्वपूर्ण नवप्रवर्तन के न होने से) कुल मिलाकर यह प्रभाव पडता है कि मदी की स्थिति पूर्ण तरह से समाप्त होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति तक नही पहुँच पाती है......आज विकसित देशो मे घटती हुई विनियोजन की सम्भावनाओ का मुख्य कारण घटती हुई जनसख्या व नए इलाको को पता लगाने की सम्भावनाओ की समाप्ति है)

हन्सेन इस कारण बढती हुई जनसंख्या चाहते है.

आलोचना :

उपरोक्त विचारधारा की काफी आलोचना की गई है.

Dr. Ellis ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा है

> "क्या हम यह कहना चाहते है कि बेरोजगारी का इलाज और बच्चे पैदा करना है."

B. M. Anderson भी इस विचारधारा को सर्वथा गलत मानते है. और कहते है

> "घटती हुई जनसख्या से बेरोजगारी होना आवश्यक नही है. इससे माँग कम नही होती, वरन् माग का स्वभाव बदल जाता है. घटती हुई जनसख्या से "पालनो" की माँग कम होगी तो "पहिएदार कुर्सियो" की माँग बढेगी.

Fellner-Terborgh के अनुसार जनसख्या घटने से उपभोग उसी मात्रा में नही घट सकता. इस कारण जनसख्या के घटने मे बेरोजगारी का फैलने का भय निर्मूल है उन्होने कहा

> "High population need not give rising population consumption function for the aggregate population tends toward linearity with minor oscillations that seem to be unrelated to changes in population growth"

Melvin D Brockie ने अपने लेख 'Population growth and the rate of investment" में हन्सेन की विचारधारा की बहुत आलोचना की है. उन्होने लिखा .

> "स्थिर जनसख्या मे कम पूँजी की आवश्यकता पडेगी, कम मकानो की आवश्यकता पडेगी और हर व्यक्ति पर बच्चो का भार कम रहेगा.

स्थिर जनसख्या से कम मात्रा में पूजीगत वस्तुएँ अवश्य उत्पादित की जाएगी परन्तु उपभोग वस्तुएँ तो अधिक मात्रा में उत्पादित की जा सकती है. "व्यक्तिगत सेवाओ" का अधिक सृजन किया जा सकता है. जनसख्या कम होने से माँग मे कमी हो, तो कम लोगों को रोजगार भी तो देना पडता है जनसख्या के कम होने से मदी नही आती है वरन् मदी काल में जनसख्या कम हो जाती है क्योकि लोग देर से शादी करते है तथा अधिक परिवार नियोजन अपनाने लगते है 1"

निष्कर्ष :

विकसित देशो मे भी बढती हुई जनसख्या आवश्यक नही है आज के युग में स्थिर जनसख्या ही उचित है कम विकसित देशो में भी इसलिए जनसख्या वृद्धि रुकना आवश्यक है.

Spengler के शब्दो में

"आज की साधनों की स्थिति तथा समस्त तक्नीक सबधी उन्नति को ध्यान मे रखकर भी यह कहा जा सकता है कि विश्वव्यापी गरीबी को दूर करने के लिए जनसख्या वृद्धि को शीघ्र ही रोकना होगा. उन्नति व विकास के किसी भी आयोजन मे जिसमें इस बात का ध्यान नही रखा जाएगा, वह असफल हो जाएगा"

1. "One might thus aver that although population growth historically has provided broad investment opportunities for Saving, a stationary population need not be the prelude to secular stagnation Alternative investment outlets exist today and have existed for generations, population growth of the past simply created opportunites which were more lucrative at a particuler time. Savings could just as easily gravitated toward qualitative improvements and a feutherence of the standrad of living of already existing numbers.
—Parenthetically, there appears to be little validity to the ar gument which concerns itself with increasing numbers as adevice for keeping the mature population employed. The tribulations of over population are perhaps more serious than the trials of under-population."

भाग 2

जनसंख्या नीति

Population Policy

I What is a "Population Policy"

जनसख्या नीति का अर्थ

"जनसख्या नीति" का विस्तृत व सकुचित दोनों अर्थ लिए जाते है Myrdal (मिरदाल) के अनुसार

'जनसख्या नीति वास्तव मे मोटे रूप से सम्पूर्ण समाज नीति ही होती है अगर हम समाज नीति के व्यावहारिक पहलुओ को ध्यान नही देगे तो जनसख्या नीति का क्षेत्र अनावश्यक रूप से सकुचित हो जाएगा जनसख्या नीति को अन्य सामाजिक नीतियो पर प्रभाव डालना चाहिए और अन्य नीतियो से प्रभावित होना चाहिए'

इस प्रकार से अगर हम परिभाषा ल तो वास्तव में समस्त आर्थिक नीतियाँ ही "जनसख्या नीति" के अ तर्गत आ जाएगी विदेशी आयात निर्यात नीति से भी जीवन स्तर ऊँचा होता है, विनियोजन वृद्धि से जनसख्या को अधिक रोजगार मिलता है इसी तरह यातायात सुविधाओ की वृद्धि से भी जनसख्या लाभान्वित होती है इन सब कार्यो को हम जनसख्या नीति के अन्तर्गत नही ले सकते अन्यथा समस्त अर्थशास्त्र ही जनसख्या शास्त्र हो जाएगा ऐसा करना उचित नही होगा और हमको जनसख्या नीति की सीमित रूप मे अध्ययन करना चाहिए

A Population Policy can be nothing less than a social policy at large If practical social science is not on the watch, there is a Palpable danger that Population Policy will be irrationally narrowed down and forced into remedial quackery A population programme must work itself into the whole fabric of social life and inter-penetrate and be interpenetrated by all other measures of social change The population crisis must, if we are to react rationally, make us rethink all social objectives and programmes

Myrdal, A Nation & Family, 1941, p 101.

हम जनसख्या नीति के अन्तर्गत

(i) जन्मदर,
(ii) मृत्युदर,
(iii) जनसख्या वृद्धि दर
(iv) जनसख्या नियन्त्रण,
(v) जनसख्या की सरचना सुधार आदि को अध्ययन करते है

Dr Terao के शब्दो मे :

> "जनसख्या की समस्या निवारण हेतु कदमो को ही जनसख्या नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है. इस नीति में मुख्यतया वृद्धि करना या सीमित करना आता है." जब अर्थ व्यवस्था के अनुरूप जनसख्या को करना होता है तो वह जनसख्या नीति मे आएगा और जब जनसख्या के अनुरूप अर्थ व्यवस्था को करना होगा तो वह आर्थिक नीतियो के अन्तर्गत आएगा श्री तेराव के अनुसार मन्दी के कारण बेरोजगारी की समस्या "जनसख्या की नीति" की समस्या नही है बल्कि आर्थिक समस्या है, परन्तु कम-विकसित देशो मे अतिरेक जनशक्ति की बेरोजगारी की समस्या जनसख्या की समस्या है"

जनसख्या नीति के मुख्यतया दो पहलू है

(i) सख्या सम्बन्धी तथा
(ii) किस्म सम्बन्धी। कम-विकसित देशो में जन्म व मृत्यु दरे दोनो अधिक रहती है और विकास के फलस्वरुप मृत्युदर पहले गिरती है जिससे जनसख्या विस्फोट हो जाता है और जन्मदर गिराने की समस्या मुख्य हो जाती है

जहाँ तक किस्म सुधारने का प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सतुलित आहार प्रदान करना, शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध करना, विवेकपूर्ण वितरण करना आदि मुख्य है.

हम इस अध्याय में जनसख्या नीति के लिए निम्नलिखित प्रश्नो पर विचार करेंगे :

1. जन्मदर कम करना या परिवार नियोजन का प्रसार
2 देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा सतुलित आहार का प्रदान करना.

Tokuma Terao, The Meaning of Population Policy in the Report of the Fifth International Planned Parenthood Conference 1955. p 16.

3 Emigration outside and inside the country · जनसख्या का देश मे उपयुक्त वितरण
4 शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नति
5 किन्ही महत्वपूर्ण सामाजिक सस्थाओं मे सुधार
6 आर्थिक विकास व अनुकूलतम जनसख्या

उपरोक्त प्रश्नो को ही जनसख्या नीति का अग माना गया है

(a) Reduction in birth rate and family planning जन्मदर में कमी व परिवार नियोजन

1 अर्थ, 2 आवश्यकता, 3 कुछ समस्यायें, आचरण व विरोध, 4 क्या किया जा रहा है, 5 क्या और किया जाना चाहिए.

1. Meaning अर्थ

"Birth control" शब्द का अर्थ आज सबको मालूम है परन्तु यह शब्द सही मायनो मे गलत है. सही शब्द "Conception control" या 'गर्भधारण नियत्रण' होना चाहिए सही मायने मे हम गर्भधारण न हो सके यह चाहते है. गर्भधारण हो जाए तो 'जन्म नियत्रित' नही कर सकते फिर भी आज "Birth control" शब्द चल निकला है और जब कभी भी "Birth control" शब्द प्रयोग मे आए तो इसका आशय हमको "conception control" मे ही लेना है

गर्भधारण के नियत्रण के प्राकृतिक व कृत्रिम दोनो तरीके इस शब्द के अन्तर्गत लिये जाते है.

2 Need, objectives, Necessity, Importance and Phoilosophy of Family Planning परिवार नियोजन की आवश्यकता व महत्व ·

कम विकसित देशो मे, विशेषरूप मे एशिया के कम-विकसित देशो में, परिवार नियोजन की आवश्यकता को Crying need of the hour या समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता कह सकते है आज जन्म दर मे कमी की इसलिए भी बहुत आवश्यकता है कि इन देशो में मृत्युदर में कमी आ गई है और चूँकि मृत्युदर को बढाया नही जा सकता या बढी हुई नही रहने दिया जा सकता, इसलिए केवल जन्मदर को कम करके ही जनसख्या वृद्धि को रोका जा सकता है जन्मदर

References . Appended at the end of the chapter

नियन्त्रित करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शारीरिक सभी कारण महत्वपूर्ण है

आर्थिक :

पिछले पृष्ठो के अध्ययन के पश्चात, जनसख्या नियन्त्रण की आवश्यकता के सबध मे किसी को मतभेद की गुजाइश नही रहती कम-विकसित देशो मे भूमि की कमी, बचत की कमी, बेरोजगारी व निम्न प्रति व्यक्ति आय के कारण जन्मदर को यथावत रखना न केवल विकास की राह मे बडा रोडा बनाए रखना है वरन् स्वयं अन्धकार की अवनति की राह मे फस जाना होगा.

भारत का ही उदाहरण ले तो हमको महत्वपूर्ण आकडे परिवार नियोजन की आवश्यकता समझाते है

भारत में पिछले 5000 वर्षो के बाद 1968 तक जनसंख्या 52.6 करोड हुई. परन्तु अगले सन् 2000 तक अर्थात् केवल 32 वर्षो मे यह सख्या दुगुनी हो जाएगी भारत मे हर डेढ सेकिन्ड मे एक बच्चा पैदा होता है और एक वर्ष में 2 करोड 10 लाख बच्चे पैदा हो जाते है भारत मे हर वर्ष आस्ट्रेलिया के बराबर जनसख्या जुड जाती है. भारत में हर दशक में जनगणना होती है 1881-91 तथा 1911-21 के बीच तो जनसख्या बढने के स्थान पर घट गई थी, और अन्य दशको मे औसत रूप से 2 से 3 करोड प्रति दशक बढती थी. परन्तु 1961-71 के बीच यह जनसंख्या 12·5 करोड से बढ जाएगी, अर्थात् एक ही दशक में आधी सदी के बराबर जनसख्या बढ जाएगी

भारत में 87% परिवार केवल जीवन निर्वाह के बराबर आय पाते है. 1960 में 25·5% परिवारो की औसत आय प्रतिदिन केवल 75 पैसे थी, 38·3% परिवारो की प्रतिदिन की औसत आय 39 पैसे थी और 23·2% परिवारो की प्रति दिन की औसत आय मात्र 14 पैसे ही थी. समस्त 87% परिवारो की औसत आय प्रतिदिन केवल 35 पैसे ही थी यह आकडे स्वयं अपने में समस्या की गंभीरता बतलाते है

आज भारत में 1 5 करोड व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार है और लगभग 1 करोड व्यक्ति अर्ध बेरोजगार हैं. रहन सहन के स्तर अत्यन्त शोचनीय है भारत में 1968 में दिल्ली मे 63%, कलकत्ते में 72%, बम्बई में 72·3%, मद्रास में 67·5%, अहमदाबाद में 65 3%, हैदराबाद में 46% तथा कानपुर में 62% व्यक्ति केवल एक कमरे के मकान मे रहते थे.

1968 में आज भारत में 9 5 करोड़ जोड़े (पति-पत्नी) 15 से 45 वर्ष की आयु के हैं अर्थात बच्चे पैदा करने वाली आयु के हैं. और इनमे से केवल 8% परिवार नियोजन का पालन कर रहे हैं शेष 92% अभी भी अनियन्त्रित रूप से बच्चे पैदा करने मे लगे हैं भारत में 6 करोड़ पति-पत्नियो के होन से अधिक बच्चे हो चुके है. सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि भारत मे स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के कारण बच्चो की मृत्यदर कम हो गई है और आज 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जनसख्या के 40% है कुछ वर्षो मे इनके भी बच्चे पैदा होने लगेगे और फिर Population explosion या "जनसख्या का विस्फोट" और भयानक हो जायेगा स्त्रियो की अधिकाश आयु बच्चे पैदा करने में ही निकल जाती है और बच्चे पैदा करने की आयु मे 2/3 स्त्रियो की मृत्युएँ बच्चे पैदा करने में ही हो जाती है.

अगर कम-विकसित देशो में प्रति व्यक्ति आय बढाना हो और समानता तथा इज्जत की जिन्दगी देना हो तो परिवार नियोजन सर्वप्रथम आवश्यक होगा. विश्व में जो 18 सदियो में जनसख्या एक मिलियन बढती थी अब केवल 15 वर्षो में बढ जाती है

भारत की चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह मान्यता है कि जनसख्या के नियत्रण के बगैर आर्थिक उन्नति असम्भव है भारत में बढती हुई जनसख्या के कारण ही नई भूमि खेती योग्य बनाई गई और उत्पादन में भी वृद्धि की गई परन्तु उसके लाभ प्राप्त नही हुए और बढती हुई जनसख्या से समस्त लाभ Neutralize निरस्त हो गए. अगर यह क्रम चलता रहा तो हमको योरोप के वर्तमान स्तर को पहुँचने के लिए 200 वर्ष लग जाएँगे, परन्तु अगर हम परिवार नियोजन के कार्य को व्यापक करके जनसख्या वृद्धि को 1% प्रतिवर्ष ला दें तो राष्ट्रीय आय मे 5% वृद्धि करके हम यह स्तर 70 80 वर्षों में ही पहुँचा सकते हैं

सामाजिक :

परिवार नियोजन से महत्वपूर्ण सामाजिक उन्नति होगी. विशेष रूप से स्त्रियाँ बच्चे पैदा करने की मशीन मात्र बनकर नही रह जाएँगी वे फिर सामाजिक कार्यो मे अधिक हिस्सा ले सकती है. परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो लडकियो की शिक्षा में भी वृद्धि होती है. गरीब परिवारो में लडकियो की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है. परिवारो का रहन-सहन का स्तर बढता है, पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन तथा गृहस्थ जीवन का अच्छी तरह से आनन्द ले सकते है और

इस कारण सुखी परिवार बनते है. पारिवारिक कलह, तनाव, चिन्ताओ और परेशानियो को दूर करने का एक मात्र उपाय है

Aldous Huxley के शब्दो मे

> "A rational control of human density depends on the existence of a stable world population with low death ratio. It does not make sense to talk about Human Dignity and the four freedoms in relation to souce far Eastern countries where, say almost half of the inhabitants die befor they are 30, and where, none the less, the total population rises by tens of millions every decade. The giant misery of the world cannot be mitigated by inspirational twaddle, but only by an intelligent attach upon the cause of that misery, viz, by controlling the future progeny."

Sir Julian Huxley ने बहुत सुन्दर शब्दो में परिवार नियोजन की आवश्यकता को समझाया है

> "People do not exist just to provide bomb-fodder for rival churches, or cannon-fodder for rival parasites, or labour-fodder for rival economic system, or ideology fodder for rival economic systems, or even consumer fodder for profit making systems. It cannot be their destiny to exist in ever larger megapopolitan sprawls, cut off from contact with nature and from the sense of human community and condemned to increasing frustrations noise, mechanical routine, traffic congestion and enless commuting, nor to live out their under nourished lives in some squalid Asian or African village .
> If man is not to become the planets cancer instead of its partner and guide, the threatening plethora of the unborn must be for ever banished from the scence."
>
> —Sir Julian Huxley, F R. S. in Population review, July 1962

राजनैतिक :

पहले कुछ देशो व उनके नेताओ (विशेष रूप से धार्मिक आधार पर स्थापित राज्यो मे) का विचार था कि जब तक कि देश में जनसख्या अधिक न होगी वह देश अपनी सामरिक सुरक्षा नही कर पाएगा परन्तु आज युद्ध केवल जनसख्या की (या सिपाहियो की) अधिकता पर निर्भर नही करता वरन नवीनतम् सामग्री, सामरिक व्यूहरचना तथा तथा मनुष्यों की शक्ति व भावना पर निर्भर करता है युद्ध जीतने या देश को शक्तिशाली रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र मे शक्तिशाली होना चाहिए और आज इसके लिए परिवारो का सीमित होना आवश्यक है सीमित परिवारो के कारण देश में बेरोजगारी नही रहती है और प्रति व्यक्ति आय अधिक रहती है और देश मे राजनैतिक असतोष नही रहता. शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है शिक्षित व्यक्तियो से देश में ही, सही प्रजातन्त्र स्थापित होता है.

अगर मनुष्य को इस पृथ्वी का कैंसर के रूप मे बनकर नही रहना है तो अप्रत्याशित रूप से बच्चे पैदा होते रहने की स्थिति बदलना चाहिए.

शारीरिक : Physical and Eugenic .

परिवार नियोजन से न केवल कम बच्चे पैदा किए जाएँगे वरन् इससे बच्चो के बीच अन्तर भी रखा जा सकता है. इस कारण माँ-बाप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते है तथा सतान का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है. बच्चो को बचपन में अच्छा स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की जा सकती है. इससे परिवार के सदस्यो या सही मायनो में देश की जनता की किस्म सुधरती है

Eugenic practices को पालन लिया जा सकता है Eugenic practice का अर्थ यह है कि अयोग्य व्यक्तियों को बच्चे पैदा न करने दिए जाएँ, ये अयोग्य व्यक्ति वे है जो कोढ़, तपेदिक, पागलपन, सिफलिस या गिनोरिया (यौनिक बीमारियाँ) आदि बीमारियों से पीडित रहते है. ऐसे व्यक्ति भी सभोग करते हुए बच्चे पैदा करने से तो बचे रह सकते है.

परिवार नियोजन के भिन्न-भिन्न सर्वेक्षणो के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है .

(i) जैसे-जैसे बच्चों की सख्या अधिक होती है तथा

(ii) उनके बीच अन्तर कम रहता है, वैसे-वैसे बच्चो की मृत्यु की दर अधिक रहती है

Dr. Woodbury ने "Maternal Mortality" में लिखा है

"अगर दूसरा बच्चा 1 ही साल बाद पैदा हो जाए तो 1000 मे से

147 शायद अपने पहले जन्मदिन को न देख पाएँ, अगर दो साल बाद पैदा हो तो यह मृत्युदर 99/1000 रहेगी और तीन साल बाद पैदा होने पर यह दर घटकर 86 5/1000 हो जाएगी"

इसी प्रकार के एक अन्य अध्ययन मे Drs. Bruine तथा Lange के अनुसार रही

परिवार मे एक ही बच्चा हो तो बच्चो की मृत्युदर	20 1%
,, ,, दो ,, ,, ,, ,, ,, ,,	20 1%
,, ,, तीन ,, ,, ,, ,, ,, ,,	25·1%
,, ,, चार ,, ,, ,, ,, ,, ,,	23·4%
,, ,, पाँच ,, ,, ,, ,, ,, ,,	24·5%

नौ बच्चो के परिवार मे मृत्यु अनुपात (बचपन मे ही मर जाने का) 52 5 तक पाया गया.

3. Some resistances, difficulties & attitudes .

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कुछ रुकावटें · विरोध व आचरणों के प्रश्न :

आपत्तियाँ :

1 आज के युग मे भी परिवार नियोजन के विरोध मे काफी कुछ सुनने को मिलता है. धर्म के रूढ़ीवादी रूप से मानने वाले व्यक्ति इसे अधार्मिक कार्य मानते हैं. वे न केवल बच्चे को गिराने (abortion) को बुरा मानते हैं. वरन् गर्भधारण को रोकने को भी बुरा मानते हैं वे इसे भी अनैतिक, अधर्मी तथा ईश्वर विरोधी कार्य मानते हैं वे इसे भी भ्रूण की हत्या मानते हैं. Roman Catholic Church के सब पोप इसके विरोध म रहे हैं और स्वय इस सदी के पोप ने अपने Encyclical मे परिवार नियोजन को बुरा माना है मुसलमान वर्ग के अनुयायी भी सामन्यतया इसके विरोध में पाए जाते है, जब कि उनकी धर्मपुस्तक "कुरान शरीफ" में आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन को अपनाने की भी सलाह दी गई है. मिश्र के इस्लाम के सबसे बडे स्कूल के बडे मुफ्ती (Mufti) ने भी यह विचार प्रस्तुत किया है कि इस्लाम परिवार नियोजन की इजाजत देता है. किन्ही परिस्थियो मे तो यह Abortion या बच्चे को गर्भ से गिराने को भी मान सकता है.

2 भारत मे कई व्यक्ति परिवार नियोजन के इसलिए विरोध मे हैं कि इससे देश मे हिन्दू व गैर हिन्दुओ मे अनुपात बिगड जाएगा. भारत मे 1891 से 1941 के बीच हिन्दुओ के अनुपात मे मुसलमानो का Child-ratio

अधिक रहा है इसका मुख्य कारण हिन्दुओ का परिवार नियोजन के पक्ष मे होना तथा विधवा विवाह के विपक्ष मे होना है, जबकि मुसलमानो मे इसके विपरीत मनोवृत्ति है. कुछ हिन्दू "नेताओ" का कथन है कि कालान्तर मे इस प्राय द्वीप की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण पुन पाकिस्तान के जन्म के समय जैसी मनोवृत्ति उत्पन्न हो सकती है.

3 कुछ सामाजिक आधारो पर भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है. प्रसिद्ध समाजशास्त्री पितरिम सोरोकिन (Pitrim Sorokin के शब्दो में :

"परिवार नियोजन के प्रसार से हम "लाइसेंसयुक्त" यौनभोग के भूखे लडके लडकियो को बढावा देंगे व उत्पन्न करेंगे. समाज मे अनुशासित व्यक्तियो के स्थान पर अपराधी पनपेंगे हर सार्वजनिक स्थान यौनिक खेलो का स्थान बन जाएगा. स्कूल व कालेज "स्केटिंग ग्राउंड" बन जाएँगे, टूरिस्ट व बालरूम घर बन जाएँगे हमारा युवा समाज पतवार हीन नाव बन जाएगा मानसिक सतुलन बिगड जाएगा. आन्तरिक शान्ति नही मिलेगी और शादी की पवित्रता ही नष्ट हो जाएगी."

बहुत से व्यक्तियो का विचार है कि परिवार नियोजन की सुविधा की उपलब्धी से लडकियाँ अपने शील को कायम नही रख पाएगी. शादी से पहले यौनिक संबंध आम बात हो जाएगी, पुरुषो द्वारा स्त्रियो को फुसलाना या स्त्रियो द्वारा पुरुषो को फुसलाना साधारण बात हो जाएगी. नौकर-पेशा लडकियाँ यौनिक व्यापार भी करने लगेंगी. वैश्यावृत्ति बढेगी तथा यौन सबसे बडा खेल व व्यापार बन जाएगा. विकसित समाज मे यह बात सार्वभौमिक हो गई है कम-विकसित देशो मे भी यह हो जाएगा और फिर नैतिकता लगभग समाप्त हो जाएगी.

4 कुछ बुद्धिजीवियो द्वारा भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है George Bernard Shaw ने तो इसे Suicide of the intellectual race कहा था. इन बुद्धिजीवियो की आपत्ति यह है कि व्यवहार मे परिवार नियोजन पढे लिखे और धनी लोग ही अधिक अपनाते है कृषक, मजदूर व अन्य कम पढे लिखे लोग नही अपनाते एक कुली के चार लडके वर्तमान स्थितियो में कुली ही रह जाएँ परन्तु एक इजीनियर के चार लडके शायद समाज के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर सकते है इसलिए वर्तमान स्थितियो में कुशल व व्यक्तियो की सख्या गिरती जाएगी और अकुशल की बढती जाएगी.

कठिनाइयाँ :

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं विभिन्न वर्गों द्वारा विरोध के अलावा अभी भी बहुत उदासीनता पाई जाती है. शिक्षा की कमी, झूठी शर्म व धन की कमी भी परिवार नियोजन के प्रसार में बाधक रहती हैं. निम्न जीवन स्तर, मनोरंजन के अन्य साधनों की कमी, परिवार नियोजन सामग्री की अनुलब्धता या महँगापन, विवेक व सूझ-बूझ की कमी भी परिवार नियोजन कार्यक्रम को असफल बनाती है सफाई की कमी (यौनिक क्रिया के पहले व बाद में साबुन के प्रयोग से शुक्राणु मरते हैं Soap is spermicidal) भी जन्मदर अधिक रखती है घरो म जगह की कमी के कारण भी यह सब उपकरण प्रयोग म नही ला पाते और सीधे यौनिक सहवास क्रिया मे जुट जाते हैं. हाल के वर्षों तक राज्य व समाज भी इस कार्यक्रम के प्रति उदासीन रहा आज भी आवश्यकतानुसार धन व व्यक्ति, विशेष रूप से डॉक्टर आदि, उपलब्ध नही है.

आपत्तियों की निर्मूलता :

1. बहुत सी आपत्तियाँ वास्तव मे निर्मूल हैं, जहाँ तक वैश्यावृत्ति पनपाने का प्रश्न है शायद उसमे परिवार नियोजन अपनाने से कमी आ सकती है आज बहुत से पुरुष घर मे यौनिक सम्बन्ध स्थापित करने के स्थान पर वेश्याओं के यहाँ इसलिए जाते है कि उन्हे घर म बच्चों की सख्या बढने का डर रहता है परिवार नियोजन के बाद वे कितनी ही बार घर में सहवास कर सकते हैं और इससे पति-पत्नी मे बगैर डर के सुखी वैवाहिक जीवन चल सकता है
2. परिवार नियोजन के कारण तनाव व फिक्र मे कमी होती है. यौनिक सहवास स्त्रियों व पुरुषों के लिए अत्यन्त आवश्यक है इससे (अगर इसकी बहुत अधिकता न की गई तो) शरीर स्वस्थ्य होता है, मानसिक तनाव दूर होता है, यहाँ तक कि आयु में भी वृद्धि होती है स्त्रियों को सहवास (और सतोषजनक) न मिलने की स्थिति में hysteria, neurosis (मानसिक अशाती व असतुलन, चिड़चिड़ापन) तथा अनियमित माहवारी हो जाती हैं. परिवार नियोजन से यह दूर हो जाते है, पति-पत्नी शारीरिक व मानसिक रूप से पास आते हैं, परिवार सुखी रहता है परिवार नियोजन से "यौन" के दोनों कार्य—बच्चे पैदा करना तथा वैवाहिक जीवन का आनन्द लेना—अलग हो जाता है.
3. जहाँ तक कि Suicide of the intellectual race का प्रश्न है यह भी कालान्तर मे नही रहेगा. धीरे-धीरे गरीब वर्ग भी, समझाने-बुझाने से,

परिवार नियोजन अपनाने लगेंगे. सबसे बड़ी आपत्ति इस सम्बन्ध मे यह की जाती है कि यह जरूरी नही है कि "उच्च वर्ग" के व्यक्तियो के बच्चे हमेशा कुशल निकले.

4. आज के युग मे केवल स्वार्थी व्यक्ति (Vested Interests) ही परिवार नियोजन के खिलाफ हो सकते है.

Prof. T. N Carver के शब्द मे

"लोमड़ियाँ चाहती है कि खरगोशो की सख्या बढे, स्वार्थी उत्पादन-कर्ता चाहते है कि श्रमिक वर्गो मे अधिक बच्चे हो जिससे उन्हे सस्ते मज़दूर मिलें, 'धर्म के नेता' अधिक सख्या मे अपने अनुयायी चाहते है, सेना के नेता अपनी बन्दूको के लिए "अधिक पाउडर" चाहते है, राजनीतिज्ञ बडी सख्या मे अधिक अज्ञानी मतदाता चाहते है, ऐसे ही व्यक्ति गरीब वर्ग की जनसख्या अधिक रखने की सलाह दे सकते है."

5. परिवार नियोजन की आलोचना जो अप्राकृतिक कार्य के रूप मे की जाती है वह भी सर्वथा गलत है आज के युग मे प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने का अर्थ जगली जीवन व्यतीत करने की दिशा मे कदम होगा. हम सुबह से शाम तक आधुनिकतम चीजो का प्रयोग खाने, पहनने व रहने मे करते है. अगर परिवार नियोजन की सुविधाओ का दुरुपयोग होता है तो यह तो व्यक्तिगत चरित्रहीनता के कारण. जिनको Adultery (एक से अधिक स्त्री भोग या पुरुष के साथ सहवास) का शौक है वे तो हर हालत मे यह करेंगे.

Dr. C. B. Mamorea के शब्दो मे :

"शादी के बाहर यौनिक सम्बन्ध हमेशा बने रहे है, हर बात का किसी न किसी वर्ग द्वारा दुरुपयोग होता रहता है. लोग ब्लेड से अपना या दूसरे का गला काट लेते या देते है, पर हम इस कारण ब्लेड से दाढी बनाना तो नही छोड सकते, लोग कुओं या तालाबो में गिर जाते है परन्तु हम उन्हे बन्द तो नही कर देते."

4. क्या किया जा रहा है ?

विश्व में परिवार नियोजन बहुत पुरानी रीति है. आदि काल से मनुष्य को बच्चे पैदा न करने की कुछ न कुछ रीति मालूम थी तथा किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन अपनाया जाता रहा है. पुराने जमाने मे भी जड़ी-बूटियो से बच्चे का जन्म रोका जाता था (चित्रक, कलमभा, अर्द्धनंगरंगा, लाल मिट्टी, आदि). बच्चो को गर्भावस्था मे गिराना (Abortion), मार डालना (Infanticide)

ब्रह्मचर्य, सहवास के पश्चात् यौनि से बाहर स्खलित होना, सहवास करना परन्तु स्खलित ही न होना, रुई में तैल या फिटकरी लगाकर यौनि में रखना आदि रीतियाँ पहले से प्रचलित थी.

कन्डम (Condom or prophylactic sheath or F L.) वास्तव में पहले मलमल तथा बाद में जानवरों की झिल्ली से बना और 1564 में इटली के Fallopius ने इसे सुझाया था. Diaphragm का प्रयोग 1880 के बाद और जैली का इस शताब्दी के आरंभ में प्रयोग शुरू हुआ. हाल के वर्षों में नई गोलियों का (खाने और रखने की) प्रयोग शुरू हुआ है आपरेशन को भी सरल, जल्द होने वाला, जल्द जख्म ठीक होने वाला, निरापद तथा जोखिम रहित बनाया गया है.

योरोप व अमेरिका में परिवार नियोजन का अपनाना बहुत आम बात है इन देशों में आय की अधिकता, शिक्षित दम्पतियों की चाह, स्त्रियों की स्वतन्त्र मनोवृत्ति, शहरीकरण, उच्चजीवन स्तर की चाह आदि के कारण परिवार नियोजन 1870 से ही काफी प्रचलित है अमेरिका में तो लगभग 70% शादीशुदा व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन सामग्री प्रयोग में लाते हैं फ्रान्स में तो घटती हुई जनसख्या की समस्या सामने रहती है और 1936 से ही फ्रान्स में अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. रूस मे भी इसी प्रकार से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है. आज वहाँ चौथा बच्चा पैदा करने पर 250 रूबल तथा पाँचवे पर 375 रूबल और नौवें बच्चे पर 775 रूबल इनाम दिया जाता है. अधिक बच्चे पैदा करनेवाली माँ को तमगे दिए जाते हैं.

एशिया मे चीन व जापान में परिवार नियोजन का बहुत रिवाज है. जापान में तो बच्चा गिराना (Abortion) कानूनी रूप से वैध है. चीन सरकार परिवार नियोजन को पूँजीवादी विचारधारा मानती है. वह जनशक्ति को सीमित नही करना चाहती. परन्तु हाल के वर्षों मे खाद्यान्न के सकट के कारण उसने भी परिवार नियोजन के पक्ष में कार्य करना शुरू कर दिया है. उसका कहना यह है कि इससे चीन की माताओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वे देश की उन्नति में अधिक योगदान देंगी.

दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका मे परिवार नियोजन निजी मामला माना जाता है और अभी तक राज्य ने कोई उल्लेखनीय दिलचस्पी नहीं दिखाई है

भारत में परिवार नियोजन :

भारत में परिवार नियोजन संबंधी आन्दोलन बहुत पुराना नहीं है. प्रो० वाताल

(Wattal) ने सर्वप्रथम इस संबंध मे अपना मत व्यक्त किया और प्रो० आर० डी० कार्वे ने 1925 मे बम्बई में, घोर विरोध के बीच, एक क्लीनिक खोला मद्रास में नव माल्थस् लीग की स्थापना हुई और 1930 मे विश्व में प्रथम बार एक सरकारी परिवार नियोजन क्लीनिक मैसूर मे खुला. 1936 मे बम्बई मे प्रथम स्त्री क्लीनिक परिवार नियोजन के लिए खुला. 1939 मे उज्जैन में मात्र सेवा सघ द्वारा तथा उत्तर प्रदेश मे भी कुछ क्लीनिक खुले 1949 मे प्रथम "फैमिली प्लानिंग एसोशिएशन ऑफ इन्डिया' की स्थापना हुई स्वतन्त्रता के बाद श्री जवाहरलाल नेहरु की अध्यक्षता में योजना आयोग ने परिवार नियोजन कार्य-क्रम को योजना का अग बना दिया. भारत इस प्रकार से विश्व मे पहला देश बना जिसमें परिवार नियोजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश की योजना में स्थान दिया पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओ मे परिवार नियोजन को उतना महत्व नही दिया गया था जितना कि तीसरी योजना मे दिया गया. प्रथम योजना मे केवल 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया और द्वितीय योजना मे 4·97 करोड रुपयो का प्रावधान किया गया इन दस वर्षों मे 28 परिवार नियोजन सबधी अध्ययन सचालित किए गए.

तीसरी योजना मे इसे सजीव और उच्चस्तरीय कार्यक्रम के रूप मे अपनाया गया. इस कार्यक्रम को स्पष्ट एव ठोस रूप मिला इस योजना में 27 करोड रुपयो का प्रावधान किया गया जिसमें से लगभग 26 करोड रुपए व्यय किए गए योजना मे यह बात मूल रूप मे मान ली गई कि "योजनाबद्ध विकास का केन्द्र बिन्दु निश्चित अवधि के लिए जनसख्या मे वृद्धि की निर्धारित दर बनाए रखना होना चाहिए. तथा इसे एक ऐसे राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में अपनाने की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य व्यक्ति, परिवार तथा देश के लिए उन्नत जीवन सुलभ करने की प्रवृति को बढावा देना हो.'' तृतीय योजना काल में 23 लाख स्त्रियो ने किसी न किसी रूप में परिवार नियोजन के तरीको को अपनाया.

चतुर्थ पचवर्षीय योजना के प्रारूप मे 145 करोड रु० खर्च करने का प्रावधान है इस राशि को Family planning education committee की सिफा-रिश के अनुसार इस राशि को 240 करोड रु० तक कर दिया जाएगा. चतुर्थ योजना मे किसी भी आर्थिक-सामाजिक नीति को इतना महत्व नही दिया गया है. यद्यपि परिवार नियोजन एक प्रान्तीय विषय है तथापि इसे केन्द्रीय सरकार के

---

cf : Dr. C. B Mamoria : op cit : p. 217-218. 1925-1949 के इतिहास के लिए.

कार्यक्रम के रूप मे चलाया जा रहा है. इसमे कार्यक्रम का सचालन और समन्वय अधिक प्रभावशाली ढग से होगा योजना का लक्ष्य यह है कि जन्म दर को 40 प्रति हजार से कम करके 25 प्रति हजार तक ले आया जाए. इसके लिए यथाशीघ्र समस्त 5000 विकास ब्लाक तथा शहरी क्षेत्रों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा.

योजना के अन्तर्गत, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग से दफ्तर खोले व कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है हर शहर, कस्बे में केन्द्र है तथा निजी सगठनो व डाक्टरो की भी सेवाएं ली गई है लेडी डाक्टरों के अभाव को पूरा करने के हेतु एक Central Family Planning Corps of Doctors बनाया गया है, जिसमें से राज्यो को आवश्यकतानुसार सख्या मे डॉक्टर भेजे जाते है. अधिकाश राज्यो मे पूरे समय के सन्तति-निग्रह अधिकारी नियुक्त किए गए है केन्द्रीय सगठन को सुदृढ बनाने के लिए अगस्त 1965 मे एक परिवार नियोजन कमिश्नर नियुक्त किया गया है छ प्रादेशिक कार्यालय भी स्थापित किए गए है. अब तक लगभग 80,000 व्यक्ति प्रशिक्षित कर दिए गए है विश्वविद्यालयो में तत्सबधी अध्ययन शुरू हो गया है

1967 मे अनुमानतया 20 लाख व्यक्तियो ने आपरेशन कराए और 20 लाख स्त्रियां ने लूप लगवाए इसके अतिरिक्त 20 लाख अन्य स्त्रियो द्वारा किसी अन्य तरीके से, परिवार नियोजन के तरीके अपनाए हुए थी. अब लक्ष्य यह है कि हर वर्ष 60 लाख स्त्रियो को लूप लगाए जाए तथा भारत में 9.5 करोड, बच्चे उत्पादन कर सकने योग्य, पति पत्नियो के परिवार नियोजन करा दिये जाएँ. योजना के अनुसार 1968 69 में प्रत्येक हजार म से 16 तथा 1973-74 मे 33 स्त्रिया लूप धारण किए हुए हो. 1971 के अन्त तक लगभग 35 लाख आपरेशन करने का भी लक्ष्य है कानपुर मे लूप बनाने का कारखाना भी स्थापित हो चुका है जिसमे 30 हजार लूप प्रतिदिन तैयार होते है. आपरेशन करने पर नगद रकम दी जाती है तथा छुट्टिया भी दी जाती है भारत मे अब गर्भ निरोध वस्तुएँ बहुत ही सस्ती कीमतो पर बाजार म उपलब्ध है.

1968 तक (1-11-1968) 53 लाख व्यक्तियो का आपरेशन हो चुका था और कुल 26 लाख लूप लगाए गए शहरो मे परिवार नियोजन केन्द्रो की सख्या 1880 हो गई थी तथा गावों मे भी लगभग 24400 केन्द्र स्थापित हो गए थे. इनके अतिरिक्त 9130 अन्य निजी डिस्पेन्सरियो मे परिवार नियोजन सबधी सुविधाए मौजूद थी आज भारत मे 1,25,000 व्यक्ति परिवार नियोजन के कार्य

मे लगे हुए है. भारत मे 30 अनुसधान केन्द्र, 43 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा 5 ट्रेनिंग सेन्टर है आगे भी भारत मे इस दिशा मे बहुत प्रगति सुनिश्चित है.

5 कम-विकसित देशो में परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए वाछनीय कदम या सुझाव :

कम-विकसित देशो मे परिवार नियोजन को सफल बनाने म कोई शिथिलता नही बरतना चाहिए. यह तो जिन्दगी और मौत का प्रश्न है (It is a question of do or die) तथा इस कार्यक्रम को युद्ध की गम्भीरता से सफल बनाना होगा (on war footing). कम-विकसित देशो मे परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे

1. सर्वप्रथम, इसके लिए हर देश को पर्याप्त मात्रा में धन का आयोजन करना चाहिए हम देख ही चुके है कि बच्चे के जन्म को रोकने का व्यय उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने व रहने के इन्तजाम के व्यय से बही कम पडेगा यही बात सभी देशो के लिए भी लागू होती है विकसित देश भी इसके लिए धन, तकनीकी सहायता तथा आवश्यक उपकरण दे सकते है आज के युग में यह सहायता शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी.
2. दूसरे इसके लिए इन देशो में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओ की आवश्यकता होगी, अर्थात् डाक्टरो नर्सो, हेल्थ विजीटर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओ की आवश्यकता होगी. इन व्यक्तियों मे योग्यता व लगन दोनो होना चाहिए. अगर एकदम डॉक्टरों की सख्या न बढाई जा सके तो अल्पकालिक 'ट्रेनिंग' देकर भी कार्यकर्ताओ को तैयार किया जा सकता है इन कार्यकर्ताओ का कार्य-क्षेत्र विशेष रूप से गांवो मे रहेगा और इसके लिए उन्हे तैयार रहना चाहिए
3. तीसरे, इसके लिए आधुनिक उपकरण व अस्पताल सुविधाओ की भी आवश्यकता रहेगी राज्यों को इसे प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए. गावो में इन सुविधाओ को पहुँचाने के लिए चलती फिरती गाडियाँ (Mobile vans) प्रयोग में लाई जाना चाहिए. हर अस्पताल मे परिवार नियोजन शाखा होना चाहिए.
4. परिवार नियोजन सबधी सामग्री सस्ती दरो पर सुलभ होना चाहिए. जैसाकि सर्वविदित है रबड के कन्डम, झागदार गोलियाँ जैली व पिचकारी, तथा खाने की गोलियाँ तो बाजार मे ही उपलब्ध की जा सकती है परन्तु स्त्रियो के प्रयोग के लिए ' पेसरीज, व डायाफ्राम'' जो गर्भाशय के मुँह पर

जैली डालकर प्रयोग किए जाते हैं, वे केवल अस्पतालो मे ही (योनी के नाप के अनुसार) दिए जाते हैं.

I U C D (Intra uterine contraceptive device) या 'लूप" भी अस्पताल मे ही फिट किए जाते हैं. इन्हे भी कम-विकसित देशो मे अधिकाधिक मात्रा में सुलभ होना चाहिए.

परिवार नियोजन का सबमे अचूक तरीका पुरुषो व स्त्रियो का आपरेशन है और इसके लिए सुविधाएँ व पुरस्कार प्रदान किए जाना चाहिए. आपरेशन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए

5. शायद सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता परिवार नियोजन का प्रचार होगी. कम-विकसित देशो म शिक्षा की कमी के कारण यौन सबधी जानकारी कम रहती है बहुत से वयस्क, यहाँ तक कि शादीशुदा व्यक्ति भी, यौन सबधी समस्त बातो के ज्ञान से अनभिज्ञ रहते है केवल सभोग क्रिया का ज्ञान ही सब नही होता वरन् स्त्रियो व पुरुषो की सरचना व तत्सबन्धित बीमारियो या प्रजनन प्रक्रिया का ज्ञान भी आवश्यक होता है

अधिकाधिक प्रचार से जनता को परिवार नियोजन के लाभ समझाए जाना चाहिए तथा उन्हे परिवार नियोजन के लिए राजी करना चाहिए इसके लिए प्रचार विकेन्द्रित होना चाहिए अर्थात् नगरपालिकाएँ, बोर्ड, पञ्चायतें या विधायक सबको ग्रामवासियो को उन्ही की भाषा मे इन बातो की आवश्यकता समझाना चाहिए पोस्टर, मॉडल, पर्चो, सिनेमा फिल्मो तथा स्लाइड्ज, ड्रामे, कहानियो, कविताओ आदि सभी का सहारा लेकर इसका प्रचार आवश्यक होगा

आवश्यकता इस बात की है कि इतना अधिक प्रचार हो कि किसी भी व्यक्ति को परिवार नियोजन सामग्री का प्रयोग करने या जानकारी हासिल करने में झिझक या झूठी शर्म न बाकी रह जाए परिवार नियोजन की सफलता तो तब होगी जब कि निम्नस्तर के जीवनयापन करनेवाले कृषक व मजदूर लोग तथा विपन्नी समूह भी इस कार्यक्रम को अपनालें.

6 परिवार नियोजन के हर तरीके को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोग अपनी इच्छानुसार इसको अपना सकें. परिवार नियोजन को बच्चे के जन्म को रोकने तथा Spacing या बच्चो के बीच समय के अन्तराल के लिए अपनाया जाता है परन्तु अधिकतर आपरेशन या लूप पर जोर दिया जाना

चाहिए. लूप के बाद स्त्रियो को बहुधा अधिक रक्तस्राव की शिकायत हो जाती है जिसकी नियोजन केन्द्रो को अच्छी देखभाल करना चाहिए. आवश्यकतानुसार देशो मे बच्चे गिराने को भी कानूनी बनाया जा सकता है, ताकि जिस बच्चे की चाह न हो उसे गिराया जा सके.

7. बडे-बडे कारखानो एव डिस्पेन्सरियो मे भी इन सुविधाओ को प्रदान किया जाना चाहिए. इन कारखानो मे श्रमसघो को भी इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सहायता देना चाहिए कारखानो के मजदूरो को भी इसे अपनाने पर भी छुट्टियां आदि की सुविधा देना चाहिए.

8. परिवार नियोजन अपनाने के लिए आर्थिक प्रलोभन भी आवश्यक होगा. प्रत्येक स्त्री या पुरुष जो परिवार नियोजन के लिए आपरेशन कराता है उसे कुछ आर्थिक अनुदान देना चाहिए उसका तत्सबन्धी इलाज मुफ्त होना चाहिए कुछ अन्य किस्म की रुकावटे भी लगाई जाती है, जैसे अगर 3 या 4 से अधिक बच्चो के होने पर शिक्षा मे वजीफे या मातृत्व अवकाश न दिया जाये आदि.

9. कम-विकसित देशो में Eugenic programme अपनाना चाहिए अर्थात् क्षय, कोढ तथा अन्य असाध्य बीमारियों या यौनिक बीमारियों से पीडित व्यक्तियो का अनिवार्यरूप से बन्ध्यीकरण कर देना चाहिए. असख्य भिखारी, या भिखारियो जैसे जीवन व्यतीत करने वालो को अनिवार्य रूप से या समझाकर बच्चे पैदा करने के अयोग्य कर देना चाहिए

10. अन्य आवश्यक कदम जो इस दिशा में उठाये जाना चाहिए उनसे अनुसधान व सामाजिक सहयोग प्राप्त करना मुख्य होगा.

Dr C. B. Mamoria के शब्दो मे

> "Medical men and women, nurses and health visitors, demographers, economists, chemists, nutrition experts, sexologists, psychologists, psychiatrists, pathologists, research workers, clinicians, statisticians and social workers would all have to co-operate in building a satisfactory programme to cover all aspects of the vast field that must be tackled."

देश मे आर्थिक विकास के साथ-साथ परिवार नियोजन को स्वयं ही अधिकाधिक मात्रा में अपनाया जाएगा परन्तु आज के युग मे परिवार नियोजन का सदेश घर-घर पहुँचना चाहिए.

Sir Winston Churchill ने एकबार कहा था

"अगर मुझे समय मिले तो मै हर घर के सामने लिख दूँगा कि बीमा कराइए."

उस स्थान पर मै यह कहना चाहूँगा

"आज हर घर मे यह सन्देश पहुँचना चाहिए कि परिवार नियोजन कराओ."

(b) Increasing Food Supply & better nuitrialwnal diet :
खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि तथा सतुलित आहार :

(कृषि उत्पादन सबधी अध्याय देखिए इसमे आप सक्षेप मे यह अध्ययन कर सकते हैं कि कम-विकसित देशो मे कृषि उत्पादन कैसे बढाया जा सकता है तथा उनका क्या महत्व है).

संतुलित आहार :

कम-विकसित देशो मे कृषि का उत्पादन, उत्पादकता बढानी होगी कृषि उपज के यातायात व सचय की सुविधाओ को सुधारना होगा. कृषि की Inputs (सिंचाई, खाद, बीज आदि) को बढाकर, उन्नत तकनीक अपनाकर, कृषि योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि करके, फसलो की रक्षा करके, एक से अधिक फसलें उगाकर, उन्नत किस्म की फसले उगाकर, कम-विकसित देशो को खाद्यान्न के उत्पादन मे आत्म निर्भर होना होगा आज अमेरिका की अधिकाधिक खाद्यान्न की कमी पूरी करने की क्षमता कम होती जा रही है इससे कम-विकसित देशो को कृषि उपज व राष्ट्रीय आय बढानी होगी.

केवल अधिक मात्रा मे खाने से ही शरीर पुष्ट नही होता. वास्तव में संतुलित आहार अधिक महत्वपूर्ण होता है कम-विकसित देशो में आहार के असंतुलन व आहार में प्रोटीन की कमी के बारे मे हम पढ ही चुके है.[1]

अगर विश्व की जनसख्या वृद्धि दर 1965 की वृद्धि दर की भांति ही रही तो 1985 मे 52% और अधिक केलोरीज की आवश्यकता होगी और अगर परि-

1. See : Characteristles of under developed Countrles Demographic Charcterlstles.

33

वार नियोजन का आन्दोलन प्रभावकारी रहा तो भी 43% अधिक केलोरीज की आवश्यकता होगी यह तो विश्व का औसत है कम-विकसित देशो मे तो केलोरीज की आवश्यकता और भी अधिक रहेगी, जैसे भारत मे 88% से 108% और अधिक केलोरीज प्रदान करनी पडेगी पाकिस्तान मे 118% से 146% अधिक केलोरीज प्रदान करनी पडेगी इसी प्रकार ब्राजील मे 91% से लेकर 105% तक अधिक केलोरीज युक्त भोजन देना पड़ेगा. अगले 20 वर्षों मे (1986 में) इन देशो मे खाद्यान्न की आवश्यकता दुगुनी हो जाएगी. इसलिए कम-विकसित देशो म उत्पादन मे भी वृद्धि करनी होगी और जनसख्या वृद्धि पर भी नियत्रण करना पडेगा, क्योंकि विश्वव्यापी भुखमरी भविष्य की नही बल्कि वर्तमान की ही समस्या है.

असतुलित आहार की कमी दूर करने के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होगी, जिसे हम Single-cell Protein से दे सकते हैं इसे हम Yeast या Bacteria of Carbohydrates, Hydrocarbon या Cellulose से तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से अगर हम प्रोटीन उत्पादित करके वितरित कर सकें तो विश्व के व्यक्तियों का स्वास्थ्य खाद्यान्न पर ही निर्भर नही रहेगा फूलपत्तियो मे तथा ऐल्गी (Algae) से भी प्रोटीन प्राप्त करने के सबध मे महत्वपूर्ण अनुसधान हो चुके हैं Algae के फोक (waste elements) को हम जानवरो को भी खिला सकते हैं हम गोश्त का उत्पादन व मछली का उपभोग भी बढा सकते हैं पेट्रोलियम स भी प्रोटीन प्राप्त करने की दिशा मे महत्वपूर्ण प्रयोग हो रहे है शायद भविष्य मे खाद्य समस्या के निराकरण में समुद्र पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान रहे. यह साधन अभी लगभग असीमित मात्रा मे खाद्य पदार्थ दे सकता है कम-विकसित देशो में बच्चो को प्रोटीनयुक्त खाना दिया जाना चाहिए सोयाबीन, मूगफली, और वपासिए से ' शाकाहारी प्रोटीन'' प्राप्त हो सकता है. मास से प्राप्त होने वाला प्रोटीन उन जानवरो से अधिक प्राप्त करना चाहिए जो अपने भोजन के लिए मानव जाति से प्रतियोगिता न करे

(c) Rational Distribution of Population : Emigration.

जनसख्या का विवेकपूर्ण वितरण :

जनसख्या की समस्या के निवारण हेतु जनसख्या का विवेकपूर्ण वितरण भी आवश्यक होता है. यह जनसख्या का हस्तान्तरण देश मे तथा विदेशो मे किया जा सकता है बहुधा यह सलाह दी जाती है कि विश्व की जनसख्या समस्या के विवेकपूर्ण रूप से हल करने हेतु अधिक जनसख्या वाले देशो से 'अतिरेक' जनसख्या को

कम जनसख्या वाले देशो मे भेजना चाहिए. आज विश्व मे आस्ट्रेलिया, पश्चिमी-उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा तथा दक्षिणी अमेरिका में लाखो एकड भूमि पर उन्नति करके एशिया की जनसख्या को बसाया जा सकता है. इन देशो के ऊष्ण क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, चीन व जापान के व्यक्ति बसाए जा सकते हैं इन देशो के व्यक्ति इन कम जनसख्या वाले देशो में जाकर वहाँ के वनो, कृषि योग्य भूमि व साधनो का पूर्ण रूपेण उपयोग कर सकते है.

परन्तु आज के इस "सकीर्ण राष्ट्रीयता" के युग में यह सभव नही दीखता. आज विश्व बन्धुत्व कोरी कल्पना है आज दूसरे देशो की जनसख्या अपने देश में लेना तो दूर की बात रही, बल्कि कई देश तो आज उन विदेशियो को ही बाहर निकालने लगे जिन्होने उन देशो की आर्थिक उन्नति मे महत्वपूर्ण योगदान दिया था. भारतीय प्रवासियो का ही हम उदाहरण ले सकते हैं हम भारतीय प्रवासियो को लगभग विश्व के समस्त देशो में देख सकते हैं, परन्तु मुख्यरूप से ये बर्मा, लका, द० अफ्रीका, केन्या, मलाया, सिंगापुर, मारीशस, फिजी, ब्रिटेन, कुवैत, अदन, वेस्ट इन्डीज, ब्रिटिश गायना आदि में हैं अन्य देशो में भी (यू. एस ए , कनाडा, आस्ट्रेलिया, थाईलैंड, तनजानियाँ व अन्य देश) भारतीय प्रवासी काफी सख्या में पाए जाते हैं. अनुमानतया आजकल 50 लाख भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व के अन्य देशों में हैं ये व्यक्ति मुख्य रूप से ऊष्ण देशो मे है और मुख्य रूप से सस्ते मजदूरो के रूप में भारत मे ले जाए गए थे और 75% से अधिक वे 'कामनवेल्थ' देशो में है इन प्रवासियों को बागान, खानो, रेलवे-लाइनें बनाने आदि में कार्य करने के लिए ले जाया गया था. बर्मा, लका, केन्या व दक्षिणी अफ्रीका से भारतीयों को निकाला जा रहा है और उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है

इसके अतिरिक्त विश्व के भिन्न-भिन्न देशो के प्रवासी न तो नए देशो के व्यक्तियों से और न अन्य स्थानों से आए हुए प्रवासियो के साथ घुलमिल पाते हैं. भाषा, धर्म, रग व अन्य रीति-रिवाजो के भेदो के कारण बहुधा खून खराबा हो जाता है, जैसे हाल के दिनो मे मलाया में मलाया वासियो (चीनी, भारतीय व मलय) के बीच खून खराबा चल रहा है

Kingsley Davis के अनुसार

> "कम-विकसित देशो से अधिक जनसख्या घनत्व वाले देशो में जो व्यक्ति उन्नत देशो द्वारा लिये जाते है, वे वास्तव में कुशल व्यक्ति होते है—जैसे डाक्टर, प्रोफेसर, इन्जीनियर आदि कम-विकसित देशो में इनकी आवश्यकता अधिक रहती है, परन्तु केवल कुशल व्यक्तियों

के लिए जाने से कम-विकसित देशो की जनसख्या की किस्म खराब होती है और इन देशो मे Brain Drain या कुशलता का निर्यात हो जाता है"

देश के अन्दर :

जहाँ तक किसी देश मे जनसख्या के आन्तरिक दबाव को ठीक करने का प्रश्न है, जनसख्या का एक स्थान से (अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों मे) दूसरे स्थान या क्षेत्र (कम घनत्व वाले) मे ले जाने से अनेक समस्याओं का निराकरण होगा भारत में दक्षिण भारत मे केरल, तथा पूर्व म बगाल से अन्य क्षेत्रो मे जनसख्या का लाना वाँछनीय होगा. इन्डोनेशिया मे जावा द्वीप मे ही 90% जनसख्या रहती है और जनसख्या का घनत्व सम्पूर्ण देश मे बहुत अधिक न होते हुए भी, जावा विश्व के बहुत अधिक घनत्व वाले क्षेत्रो मे एक है.

इस सबध मे सबसे बड़ी समस्या मनुष्यो मे गतिशीलता की कमी की रहती है. भारत मे आज भी 90% जनता अपने जन्म स्थान के जिलो मे ही रहती है और 5% आसपास के जिलो मे रहती है केवल 5% जनता ही उल्लेखनीय रूप से प्रवासी हुई है भाषा की भिन्नता, धन की कमी, यातायात व आवास संबंधी कठिनाइयाँ, परिवार व स्थान प्रेम आदि के कारण गतिशीलता कम रहती है बहुधा ग्रामीण क्षेत्रो मे औद्योगिक क्षेत्रो मे ही जनसख्या प्रवासी होती है, परन्तु

"There is obviously not much scope for relieving over-population by emigration" Spatt O H K, India & Pakistan, p 113.

"Emigration will not check growth in the most important areas of population pressure at the present stage of the demographic situation" Review of Demographic Studies of Selected Areas of Rapid Growth, 1947, p 318

"In our present nationalised world, in which the best lands have been occupied and restrictive measures are in force, migration is no answer to economic and social strain induced by so-called overpopulation" I Bowman, Limits of Land Settlement, 1937, p 1.

"As a sole relief for population pressure, emigration is a palliative rather than a solution To be effective it must not only remove people from the region, but by hastening social change, aid in reducing fertility." Davis, Population of India and Pakistan, 1951., q f. Mamoria, op. cit, p. 97.

दुर्भाग्य से आज भारत मे ही एक क्षेत्र की जनसख्या का दूसरे क्षेत्र मे स्वागत नही होता. प्रान्तीयता बढ़ती जा रही है, इस प्रवृत्ति का मूल कारण देश में बेरोजगारी की समस्या है आज अगर यह समस्या नही रहती है तो पुन भारतीयो में हर क्षेत्र के लोगों के साथ प्रेम से रहने की प्रवृत्ति कायम हो जायेगी.

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसख्या ले जाने से देश के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है देश मे अधिक घनत्व के क्षेत्र से कम घनत्व के क्षेत्र को जनसख्या ले जाने के लिए यातायात, आवास, स्कूल, अस्पतालो मे विनियोजन बढ़ता है इससे देश मे रोजगार भी बढ़ता है उत्पादकता बढ़ती है और साधनो का विवेकपूर्ण वितरण होता है और अनुकूलतम प्रयोग होता है

जनसख्या के विवेकपूर्ण वितरण के लिए आन्तरिक हस्तान्तरण महत्वपूर्ण सभावनाएं रखता है

(d) Extension of educational and medical facilities and suitable institutional changes. शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व सामाजिक सस्थाओ में परिवर्तन :

शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओ के विकास का भी जनसख्या समस्या निराकरण में बहुत महत्व है. शिक्षा के विकास से परिवार नियोजन का विरोध शिथिल होता

References :

Apart from the books mentioned in previous chapters this chapter has been prepared using the matter of under-mentioned books and papers

1. The World Food Problem · A Special Report to President Johnson, May 1967, U S. I S , New Delhi
2. U N World Population Conference Papers, Belgrade, Yugoslavia, 30 August to 10th September 1965,
   Manpower Structure in Relation to Economic Growth by K. S Gnanasekaran.
3. Yojana . Vol XII No 18 Septt 15, 1968–A Special Number on Family Planning, with following articles :
   (i) Jaya Prakash Narain · Graver than an Invasion.
   (ii) Dr. S Chandrasekhar · Towards a People's Programme
   (iii) Dr. Ashish Bose : Life begins at Twenty
   (iv) Dr. S N Agarwal : Demography & Development.

है, रोग निरोधक कदम जल्द उठा लिये जाते है और औसत आयु में वृद्धि होती है. शिक्षा का विकास पर भी महत्व होता है, शिक्षित समाज अधिक पूजी सचित करता है, उन्नत तकनीक से अधिक उत्पादन होता है और इन सबका जन्म दर गिराने पर अच्छा प्रभाव पडता है.

स्वास्थ्य सुविधाओ के विकास से भी आयु बढती है और फिर कम बच्चे पैदा करने की आवश्यकता रहती है.

जहाँ तक सस्थाओ में परिवर्तन का प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण बात इन देशो में शादी की आयु को बढाना होगा. अगर पुरुषो की शादी की आयु 25 व लडकियो की 20 कर दी जाय तो भी आधी समस्या तो हल हो जाए इस सम्बन्ध में कानूनी नियम बनाए जाना चाहिए.

स्त्रियो को उच्च सामाजिक दर्जा देने व उन्हे शिक्षा देने से भी जन्मदर कम होगी. जहाँ स्त्रियाँ शिक्षित, स्वतन्त्र व समाज में ऊँचा दर्जा पाती है वहाँ जन्मदर कम हो जाती है. इसी प्रकार से स्त्रियो द्वारा नौकरियाँ करने से भी जन्मदर मे कमी आती है

(v) Govind Narain : A target-and time-oriented programme.
(vi) Frank Wilder . Telling the Millions.
(vii) G K Mathur . Crossing the Mental Barrier.
(viii) Dr Dipak Bhatia World's biggest drive.
(ix) Dr. J. N Sinha : More people, less food.
(x) Dr. K. C. Sehgal : Small families, better living.
(xi) Dr Raina : Role of Research.
(xii) K. B. Suri : Education & Population Growth.

4 Bowen : Population (contains good information and discuss on world population, various factors that govern population growth, population & food supply, ideas of maximum, minimum population, optimum population and ecological equilibrium and international migration.)
5. Coontz : Population Theories and the Economic Interpretation.
6. Sadler : Biology & Population Growth & Studies In Human Biology.
7. Josue De Castro : Geography of Hunger.
8. Nirmal Sethi : A very mixed attitude to Family Planning.

(e) An optimum population to be conceived : अनुकूलतम जनसंख्या

हर देश के प्राकृतिक साधना, विदेशी आय व सहायता व तक्नीक के आधार पर एक अनुकूलतम जनसंख्या होती है यह जनसंख्या वास्तव में एक सैद्धान्तिक कल्पना है परन्तु फिर भी हर देश को अपनी जनसंख्या इससे ऊपर नही जाने देना चाहिए. Imre Ferenczi के अनुसार

> "All population considerations be fitted into the frame of reference known as optimum population This concept will very likely always be more of a desideratum than a precise formula We may make two approaches in the

9. U N. World Demographic Year Books
10. U N. The Determinants and Consequences of Population Growth
11. C B. Mamoria Population Growth and Economic Development in India
12 C B. Mamoria Population & Family Planning in India.
13. Philip M Hansen & Otis Dudley Duncan · The Study of Population, Yojana July 9, 1967.
14. G C Hallen . A National Population policy to be evolved by a National Population Commission—Some doubts and questions
15 Planning Commission of India ; Draft Fourth Five year Plan.
16 Warren S Thompson Population Problems, Assistant, Evangelyn D. Minnis
17. S. Chandrasekhar Areas of Light & Darkness : Yojana, Vol. XI. No 3. July 9, 1967.
18 ,, ,, Asia's Population Problem
19. ,, ,, . Hungry People & Empty Lands.
20. Jossleyn Hennessy . Food Problems in Developing countries-Eastern Economist, Feb. 23, 1968. & two further members—March 8, 1968
21 George C. Zaidan · Population Growth and Economic Development

search for an optimum population Quantitatively, it implies a set of economic and social conditions which will allow each citizen an opportunity to satisfy his fundamental needs according to certain minimum standards. Qualitatively, it means a population programme which, while guaranteeing the continued maintenance of a people, takes into account the eugenic as well as euthenic improvement of the population Obviously, a fixed optimum is an impossibility"

---

22 J N Shrivastava : Occasional Papers No 2 Family Planning in India, Demographic Research centre, Lucknow University.
23 American Reporter · Aug 16, 1967 A 20 year Graphic Projection of India's Food-Population Problem
24. Also in details in Economic & Political Weekly, July 8, 1967.
25 H W. Singer : op cit : ch. 8.
26. H Vellard · op cit : ch 16,17.
27. William Fielding Ogburn : Population, Resources, Technology & levels of Living
28 Manuel Gottlieb . The Theory of optimum population for a closed Economy.
29 Joseph Spengler : Population & per capita Income.
30 Alan T. Peacock . Theory of Population & Modern Economic Analysis
31. Joseph Spengler Population Movements, Employment and Income.
32 Alvin H. Hansen : Economic Progress & Declining Population Growth.
33 Melvin D. Brockie · Population Growth & the rate of Investment.
34 Clarence L. Barber : Population Growth and the demand for Capital.
35 August Losch : Population cycle as a cause of business cycle

निष्कर्ष :

जनसंख्या नीति में मुख्यतया इन बातों का समावेश होना चाहिए :

(i) बच्चों की जन्मदर नियन्त्रित हो, वे माता-पिता की इच्छानुसार पैदा हों.
(ii) देश में जनसंख्या का समुचित बँटवारा हो.
(iii) देश की जनसंख्या की किस्म सुधरे, अर्थात् उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि हो.
(iv) समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों की आवश्यकतानुसार पूर्ति हो.
(v) अधिक जनसंख्या की समस्या के निराकरण हेतु खाद्यान्न की पूर्ति में भी वृद्धि हो, तथा जन्म दर में भी कमी लाई जाए.

---

36. Joseph Spengler : The Population obstacle to Economic Betterment.
37. A. B. Wolfe : The Population Problem since the World War I.
38 Donald olen Cowgill : The Theory of Population Growth.
39. Kingsley Davis . Population and the Further Spread of Industrial Society.
40 Kingsley Davis : Population Growth & International Relations.
41. Spengler & Duncan : Population Policy.
42. Spengler : Socio-economic Theory and Population Policy.
43. Frank W. Notestein : Problems of Policy in Relation to Areas of Heavy Population Pressure.
News in Indian Express and other Newspapers and many other Journals.

अध्याय 12

आयोजन

Planning

I प्रस्तावना

आयोजन का अर्थ

सकुचित व सही विचारधारा, राबिन्स, ज्वीग, डाब, ल्युस, लवी, नेहरू डिकिन्सन, मिरडाल, लारविन, बूटन, डाल्टन, फ्रिश की परिभाषाएँ, सारयुक्त परिभाषा

II आयोजन के उद्देश्य व विशेषताएँ

आर्थिक राजनैतिक सामाजिक

III आयोजन की मुख्य विशेषताएँ

IV आयोजन के प्रकार

(a) भौतिक व वित्तीय आयोजन

(b) सरचनात्मक व क्रियात्मक

(c) सुधारात्मक व विकास के लिए आयोजन

(d) प्रोत्साहन मूलक व प्रजातन्त्रीय आयोजन

(e) निर्देशन, केन्द्रीय सस्था द्वारा समाजवादी शासकीय या फासिस्ट आयोजन

V आयोजन की सफलता के आवश्यक तत्व

सिगर के विचारो के नोट सहित

VI आयोजन व अनायोजित अर्थव्यवस्था

VII आयोजन की अवस्थाएँ

VIII आयोजन कार्यक्रमो की कमियाँ व कठिनाइयाँ

अध्याय : 12

आयोजन

Planning

I. प्रस्तावना

आयोजन का अर्थ

संकुचित व सही विचारधारा .

आयोजन के अर्थ के सबंध म अर्थशास्त्रियो में बडा मतभेद है. कुछ अर्थशास्त्री, जो पूँजीवाद के कट्टर समर्थक है वे राज्य के निजी सम्पादन व वितरण, थोडे से हस्तक्षेप को "आयोजन" कहने लगते है इनके अनुसार 'आयोजन' व 'सगठनवाद एक ही चीज है अर्थात् थोडे से नियमन व हस्तक्षेप को ये अर्थशास्त्री 'समाजवाद' का आना मानने लगते है यह सकुचित मत है, और जैसा कि प्रो० हाएक ने कहा है -

> "हो सकता है कि बहुत अधिक आयोजन के होते हुए भी, बहुत कम समाजवाद आए और उन्नत समाजवाद में बहुत ही कम आयोजन हो।"

इसके अतिरिक्त कट्टर समाजवादी तब तक आर्थिक व्यवस्था को आयोजित नही मानते जब तक कि सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का अधिकार न हो और वह ही उसे सचालित न करे वे थोडी सी भी आर्थिक स्वतन्त्रता को आयोजन का विरोधाभास मानते है. यह भी सकुचित मत है.

सही मत यह है कि आयोजित व्यवस्था मे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था मे समन्वय होता है चाहे कुछ उद्योगो या सस्थानो की मालकियत निजी क्षेत्र में ही क्यो न हो अधिकतर अर्थशास्त्री इसी मत के है.

आयोजन कोई नई चीज नहीं है :

आयोजन के अनुसार हर व्यक्ति हर समय कार्य करता रहा है हर व्यक्ति, थोडी या अधिक मात्रा मे उपभोग मे, मकान बनाने में, खर्च व बचत करने आदि में आयोजन करते है. हर समाज, हर राष्ट्र और हर राज्य आयोजन करता है एमिल लेडरर (Emil Lederer) के अनुसार कभी भी कोई समाज आयोजन रहित

नही रहा है. समाज के कुछ या सम्पूर्ण भाग का थोडा बहुत आयोजन हमेशा किया गया है प्रो० राबिन्स (Prof. Robbins) ने इसीलिए कहा है कि

"आज के युग मे आयोजन हमारे लिए सर्वरोगघ्न औषधि या त्रैलोक्य चिंतामणि (Grand panacea) है"

आयोजन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं :

राबिन्स :

"आयोजित व्यवस्था मे निजी उत्पादन व विनिमय पद्धति पर राज्य का निर्देशन होता है. देश के निजी उत्पादनकर्ताओ की योजनाओ के लक्ष्यो मे समन्वय लाया जाता है. आयोजन मे हम देश के लक्ष्यो की पूर्ति हेतु साधनो का चयन करते है."

फर्डीनेन्ड ज्वोग (Ferdinand Zweig) के अनुसार .

"आयोजन एक विवेकपूर्ण कार्य है क्योकि आयोजन का लक्ष्य देश के उपलब्ध साधनो से अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है" राज्य द्वारा लगाए गए हस्तक्षेपो से अर्थव्यवस्था आयोजित नही हो जाती है हर राज्य में उपभोग, उत्पादन, मूल्यो, वितरण, व्यापार, विनियोजन पर कुछ न कुछ नियन्त्रण व नियमन रहता है. पर यह आयोजन नही होता. आयोजित अर्थव्यवस्था मे पूर्ण अर्थव्यवस्था का आयोजित होना आवश्यक है. संयुक्तराष्ट्र अमेरिका मे भी थोडा बहुत आयोजन है, पर हम इसे आयोजन नही कह सकते.

आयोजन से शक्तिशाली केन्द्र सरकार की उत्पत्ति होती है और शक्तिशाली केन्द्रीय शासन व्यवस्था से आयोजित व्यवस्था सफल होती है."

मारिस डॉब (Maurice Dobb) के अनुसार

"आयोजन मे हम देश के महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयो को समन्वित रूप मे कार्यान्वित करते है • आयोजित अर्थव्यवस्था में हम समस्त आर्थिक मुद्दो पर (प्रश्नो पर) संगठित निर्णय लेते है. जिससे अर्थव्यवस्था के समस्त अंगो मे अनुरूपता रहे.

जॉन ल्युस (John Lewis) के अनुसार

"किसी देश में केन्द्र द्वारा आयोजित व संचालित अर्थव्यवस्था म राज्य ही देश की कुल विनियोजन की मात्रा, देशवासियो के व्यवसाय या कार्य व उपभोक्ताओ द्वारा किए जानेवाला उपभोग-चयन निर्धारित करता है. आयोजित अर्थव्यवस्था मे निजी सम्पत्ति की संस्था धीरे-धीरे

समाप्त हो जाती है अन्त में ऐसी अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता को प्राप्त कर लेती है."

हारमन लेवी (Harman Levy) के अनुसार

'आर्थिक नियोजन का लक्ष्य देश के अन्दर माँग और पूर्ति में समानता लाना है आयोजन म हम सोच विचार कर, ज्ञान पूर्ण रीति से, उत्पादन या वितरण या दोनो पर नियन्त्रण करते है. आयोजित अर्थव्यवस्था मे हम स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के विपरीत, माँग और पूर्ति म सक्रिय कार्य से समानता लाते हैं."

श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार

"आयोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेने से नही होता और न हीं यह एक राजनैतिक आदर्शवाद है. आयोजन एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व प्राप्त कर सकते है."

एच. डी. डिकिन्सन (H D Dickinson) के अनुसार :

"जब एक केन्द्रीय शक्ति समस्त अर्थव्यवस्था के वृहत सर्वेक्षण के पश्चात् यह निश्चित करती है कि कितना पैदा करना है, क्या पैदा करना है तथा किस प्रकार से वितरण करना है, तो इस कार्य को हम आयोजन कहेंगे"

गुन्नार मिरडाल (Gunnar Myrdal) के अनुसार

"आयोजित अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की सरकार स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था मे इस प्रकार हस्तक्षेप करती है कि अर्थव्यवस्था से अधिकाधिक सामाजिक उन्नति हो"

ल्युस लारविन (Lewis Larwin) के अनुसार

"आयोजित अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का इस प्रकार से गठन किया जाता है कि देश के अलग अलग चलनेवाले उद्योगो या व्यापारिक सस्थानो के विकास मे समन्वय रहे ताकि कम से कम काल में अधिक मे अधिक व्यक्तियो को अधिक से अधिक संतुष्टि मिले."

श्रीमती बारबरा वूटन (Mrs. Barbara Wootton). इनकी परिभाषा डिकिन्सन की परिभाषा की भाँति है अर्थात्

"आयोजित व्यवस्था वह है जिसमें स्वतंत्र बाजार पद्धति में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि वाँछित नतीजे प्राप्त हो सकें."

डाल्टन (Dalton) के अनुसार

"आयोजन में हम अपने पहले से चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था को सचालित करते है."

रेगनर फ्रिश (Ragner Frisch) के अनुसार

"आयोजन हम उस उस वैज्ञानिक नियोजन को कहेंगे, जिसके अन्तर्गत हम आर्थिक समस्याओं और विकास कार्यों का एक व्यापक विश्लेषण करते है तथा विकास कार्यों को अधिकतम् (Optimum) लाभ प्राप्त करने हेतु करते हैं इसके अन्तर्गत हम इस प्रकार से एक साथ कार्य करते है कि हर एक कार्य हर दूसरे कार्य को प्रभावित या निर्धारित करता है"

एक ऐसी परिभाषा जो सबका सार देती है :

आयोजित अर्थव्यवस्था में

(1) देश के व्यक्ति व्यापारिक व औद्योगिक संस्थान व राज्य के कार्यों में समन्वय होता है और वे एक दूसरे के पूरक होते है

(11) आर्थिक आयोजन व्यक्तिगत लाभ के बढाने के स्थान पर समाज के गरीब वर्गों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए किया जाता है

(111) इसका लक्ष्य देश के साधनो का अधिकतम उपयोग (जिसमे कम से कम बर्बादी हो) करके देश की राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय बढाई जाए व जीवन स्तर को ऊँचा किया जाए व रोजगार वृद्धि हो और

(1v) यह सब कार्य एक निश्चित समय में किए जाएँ

II Aims and characteristics of planning · आयोजन के उद्देश्य व विशेषताएँ

किसी भी देश के आयोजन से एडवर्ड हीमॉन (Edwrd Heimann) के अनुसार तीन मुख्य उद्देश्य हो सकते है

(1) देश मे साम्य स्थापित करना,

(11) अर्थ- व्यवस्था को गतिशील बनाना तथा

(111) देश में महत्वपूर्ण सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन लाना 1

1. Planned Society, 1937 Types and Potentialities of Economic Planning

(अ) सर्वप्रथम हम आर्थिक उद्देश्यों का अध्ययन करें :

1 सर्वप्रथम आर्थिक उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनो का अधिकतम उपभोग व अनुकूलतम वितरण लाना होता है इसका अर्थ यह नही है कि आयोजन देश के प्राकृतिक साधनो का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग कर लिया जाए इसका अर्थ यह होता है कि देश के साधनों का प्रयोग देश की बडी जनता के हित के लिए हो, कुछ एकाधिकारियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए नही साथ ही प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग व बरबादी न हो

2 **पूर्ण रोजगार** देश के उत्पादन के अगो में मनुष्य मुख्य साधन है अनायोजित अर्थव्यवस्था मे बेरोजगारी कभी दूर नही होती व्यापार चक्रो के कारण उत्पन्न बेरोजगारी तो बनी ही रहती है ज्वीग के अनुसार "आयोजित अर्थ-व्यवस्था मे पूर्ण रोजगार देना मुख्य लक्ष्य होता है और आयोजित क्रियाओं का मुख्य फल ही पूर्ण रोजगार स्थापित करना है हम एक भी आयोजित अर्थव्यवस्था ऐसी नही बना सकते जिसमे पूर्ण रोजगार अथवा लगभग पूर्ण रोजगार न हो"

रूस व अन्य समाजवादी देशो मे पूर्ण रोजगार है भारत में हमारी आयोजित व्यवस्था पूर्णरूप से आयोजित नही है इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति भी नही है

बेरोजगारी समाप्त करना तो आज हर देश का लक्ष्य बन गया है अमेरिका मे "न्यू डील" का भी यही लक्ष्य था परन्तु हर देश पूर्ण रोजगार की स्थिति पर नही पहुँच पाता है, युद्ध के काल मे रोजगार स्वय बढ जाता है परन्तु शान्तिकाल मे आयोजित व्यवस्था से ही पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है [1]

आयोजित अर्थव्यवस्था म कृषि मे अर्ध-बेरोजगारी को समाप्त करते है, कृषि विकास से जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में फालतू हो जाते है उन्हे औद्योगिक क्षेत्र में आयोजन के अन्तर्गत रोजगार देते है

3 **उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना** आयोजित अर्थव्यवस्था में अधि-कतम उत्पादन व अनुकूलतम उत्पादन का लक्ष्य रहता है इस प्रकार की व्यवस्था मे, जिन क्षेत्रों मे उत्पादन अधिक होता है, उसे या तो घटा दिया है या उसके लिए आन्तरिक मॉग बढाई जाती है व निर्यात किया जाता है.

1. Zweig : op. cit., p 70.

अत्युत्पत्ति को देश पर सकट नही लाने दिया जाता है, जिन क्षेत्रो में उत्पादन कम होता है, उनमें बढा दिया जाता है. अनायोजित व्यवस्था मे मूल्य गिरने से अत्युत्पत्ति समाप्त होती है और वृद्धि से कम उत्पादन की स्थिति इन दोनो प्रकार की स्थिति से व्यापार चक्र आते है और देश को मूल्य गिरने या महँगाई बढने के कष्ट उठाने पडते है. सफल आयोजन मे यह नही होता उत्पादन बढाने से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादकता बढाना होता है. उत्पादकता का अर्थ उत्पादन बढने की दर मे वृद्धि से होता है अर्थात् कम लागत मे अधिक सामान पैदा होता है यह विकास की कुजी है अधिक उत्पादकता से लाभ व मजदूरी अधिक होती है व अधिक पूँजी प्राप्त होती है. आयोजन का लक्ष्य उत्पादन व उत्पादकता मे वृद्धि लाना है

4. **संतुलित विकास व पिछडे इलाको व वर्गों की उन्नति .** अनायोजित अर्थ व्यवस्था में उन्ही इलाको में उन्नति होती जाती है जहाँ सामाजिक व आर्थिक सुविधाएँ मौजूद रहती है (जैसे भारत मे बम्बई क्षेत्र मे) अन्य क्षेत्र पिछडे रह जाते है. वहाँ बेरोजगारी, पिछडापन व कम आय के स्तर बने रहते है आयोजित अर्थव्यवस्था मे इन्ही पिछले इलाको व वर्गों (जैसे आदिवासी या हरिजनो) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसके देश का विकास सतुलित रहता है

   पिछडे वर्ग व पिछडे इलाको के कारण दीर्घकाल मे उन्नत क्षेत्रो का विकास भी रुक जाता है क्योकि इन क्षेत्रो में बिक्री कम हो जाती है. यहाँ जन्म दर अधिक बढती है, उत्पादन कम बढता है. आयोजित व्यवस्था का उद्देश्य इस प्रकार के असतुलन को दूर करना होता है

5. **देश में समानता लाना** वैसे तो अधिक उत्पादन बढाने व देश में पूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने से स्वयं ही असमानताएँ दूर होनी है परन्तु आयोजित व्यवस्था से व्यय, सम्पत्ति व आय की इन असमानताओ को वित्तीय व राजकोषीय नीति से भी दूर किया जाता है.

   आयोजित अर्थव्यवस्था में उद्देश्य यह होता है कि "समृद्धि मे समानता" लाई जाए न कि "गरीबी की समानता" अर्थात् अधिक उत्पादन व समान वितरण से समानता लाई जाना चाहिए. बगैर उत्पादन बढाए समान वितरण अधिक उपयोगी न होगा. पहले समानता करने से पूँजी-निर्माण व उत्पादन रुक जाता है. पूर्णरूप से आयोजित व्यवस्था (जैसे रूस में) मे भी पूर्णरूप से न तो समानता लाई जा सकी है और न ही लाई जा सकेगी. बुद्धि व योग्यता,

उत्पादकता व उद्योगो के स्वभाव के अन्तरो के कारण अधिक अन्तर बने ही रहते हैं. कृषि व उद्योग क्षेत्र मे भी अन्तर रहेंगे.

परन्तु आयोजित अर्थव्यवस्था में "जन्म के लाभ" (धनी व्यक्ति के पुत्र होने) नही मिलते. योग्यता के अनुसार अवसर मिलते है और एक सीमा के ऊपर आय न रहने देने का उद्देश्य होता है.

> 'आयोजित व्यवस्था मे जनसख्या के बडे भाग की आवश्यक आवश्यकताओ को धनी व्यक्तियो की मामूली आवश्यकताओ के सन्तुष्ट होने से पहले सन्तुष्ट किया जाता है न्याय व व्यावहारिक औचित्य की यही माँग होती है. जिस समाज मे अन्यायपूर्ण असमानताएँ मौजूद रहती हैं उसमे बुराइयाँ व पतन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है देश मे 'राजनैतिक प्रजातन्त्र' मे अधिक सामाजिक प्रजातन्त्र आवश्यक होता है. समाज में दु ख व सुख का समान वितरण होना चाहिए देश मे निरपेक्ष समानता को नही वरन् उचित समानता की आवश्यकता होती है."[1]

6 **सामाजिक सुरक्षा** · आयोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य देश में सामाजिक सुरक्षा उत्पन्न करना है. यह सामाजिक सुरक्षा शिक्षा व रोजगार के समान अवसर के प्राप्त होने तथा बेरोजगारी को समाप्त करने से उत्पन्न होती है "सामाजिक सुरक्षा पूर्ण रोजगार, उचित मजदूरी, उचित लाभ, उचित मूल्य, लगान, ब्याज व विनिमय की दरो के स्थापित करने से उत्पन्न होती है"

7. देश में **एकाधिकारियों पर नियन्त्रण** करना तथा शोषण को समाप्त करना भी आयोजित अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य हो गए.

सक्षेप में आयोजन के आर्थिक उद्देश्य ये हैं

(i) प्राकृतिक साधनो का अधिकतम व अनुकूलतम उपयोग.
(ii) पूर्ण उत्पादन करना
(iii) अधिक उत्पादकता वृद्धि लाना.
(iv) पूर्ण रोजगार बढाना
(v) देश मे शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए.
(vi) राष्ट्रीय आय व प्रतिव्यक्ति आय मे वृद्धि लाना
(vii) देश में जन साधारण का जीवन स्तर ऊँचा करना
(viii) देश में माँग व पूर्ति में सतुलित लाना.

---

1. See : op cit. · p. 90-96

4

(ix) धन, आय व सम्पत्ति की असमानताओं को दूर करना.

(x) अधिकतम आर्थिक व सामाजिक उन्नति को एक निश्चित काल मे प्राप्त करना

(xi) देश मे औद्योगीकरण का आधार रखकर सतुलित विकास लाना

(xii) पिछड़े वर्ग व इलाको को उन्नत करना.

(xiii) मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप मे राष्ट्रीय आय का न्यायोचित वितरण करना

(xiv) एकाधिकारो को तोडना व शोषण समाप्त करना.

(xv) कृषि को उन्नत उद्योग बनाना

(xvi) देश मे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा देश का सर्वांगीण विकास करना

(xvii) देश को आत्मनिर्भर व बलशाली बनाना.

(xviii) देश मे सामाजिक व सास्कृतिक स्तर को आधुनिक व ऊँचा करना.

(b) राजनैतिक व सामाजिक उद्देश्य '

समस्त साम्यवादी देशो में आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना होता है. हिटलर ने देश मे आर्थिक आयोजन तो अन्य देशो को आधिपत्य मे लाने के लिए किया चीन भी आधुनिक समय मे अपने पडोसी देशो को आधिपत्य में लाने या प्रभाव में लाने के लिए आर्थिक आयोजन कर रहा है. इटली में भी फासिस्ट आयोजन का उद्देश्य रोमन साम्राज्य की स्थापना करना था. इस प्रकार का आयोजन वास्तव मे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शस्त्रो की होड को जन्म देता है और फिर आर्थिक क्षेत्र में कम साधन प्राप्त होते है तथा करो की बहुत अधिकता रहती है

आयोजित व्यवस्था का उद्देश्य देश में अधिकाधिक राज्य संचालित उद्योगो की स्थापना करना होता है

सामाजिक क्षेत्र मे आयोजन का लक्ष्य देश में जाति, धर्म, रग के भेदो को मिटाना है एक सघर्ष विहीन देश ही आयोजित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है देश में उन्नत जीवन स्तर की स्थापना होती है. यह जीवन स्तर आर्थिक दृष्टिकोण से ही उन्नत नही होता वरन् सास्कृतिक दृष्टिकोण से भी उन्नत होता है.

यह सब कार्य एक निश्चितकाल में किए जाते है. कम से कम काल में अधिकाधिक अच्छे आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यो का प्राप्त करना ही आयोजन का उद्देश्य होता है.

"आर्थिक आयोजन का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अधिकाधिक बढाना ही नही है वरन् स्वयं सामाजिक व्यवस्था को भी अनुकूल बनाना है. आयोजित व्यवस्था में कार्य प्राप्त करने का हक, उचित आय कमाने का हक, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त करने का हक, बीमारी, बुढापा व बेरोजगारी से सुरक्षा पाने का हक देने का उद्देश्य सर्वोपरि रहता है."

Social Planning : **सामाजिक आयोजन :**

आर्थिक नियोजन मे सामाजिक उन्नति का लक्ष्य होता है. U. N. O. ने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक तत्वों को आर्थिक विकास के कार्य-क्रम में शामिल करने पर महत्व दिया है. रिपोर्ट के अनुसार

"देश मे आर्थिक विकास तब तक नही होगा जब तक कि उस देश के व्यक्ति उसे नही चाहेंगे उनमे जब आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक ढाँचे को बदलने की इच्छा बलवती होगी, तब ही आर्थिक विकास होगा. जिस समाज मे कार्य के समान अवसर न हो, जिस समाज में अशिक्षित, अज्ञानी, रूढिवादी, निरुत्साही, जाति-पाँति के बंधनो मे जकडे हुए तथा रीति रिवाजो के गुलाम व्यक्ति रहते हो वहाँ आर्थिक उन्नति सभव नही होती"

विकास पुरानी मान्यताओ को समाप्त करता है. समाज को इसके लिए तैय्यार रहना पडेगा. सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति साथ-साथ लाना होगा इसके लिए समाज की स्वीकृति लेकर चलना होगा

सामाजिक आयोजन में आयोजन का लक्ष्य समाज का अधिकतम कल्याण बढाना होना है इस प्रकार के आयोजन का लक्ष्य केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना ही नही है वरन् उसके उचित व न्यायपूर्ण वितरण का भी लक्ष्य होता है. Proudhon (प्रोधो), Gray (ग्रे), Owen (ओवेन) तथा Marx (मार्क्स) ने इसीलिए **सामाजिक आयोजन को आर्थिक आयोजन का अंग नहीं माना वरन् आर्थिक आयोजन को सामाजिक आयोजन का अंग माना गया है.** समाज के लिए आर्थिक नियोजन होता है न कि आर्थिक आयोजन के लिए समाज है

सामाजिक आयोजन का लक्ष्य अधिकतम लोगो की अधिकतम आवश्यकताओं को

See : U. N. O., Measures for Economic Development in Underdeveloped Countries.

पूरा करना होता है कुछ लोगों की विलासिताओं को पूरा करने से पहले अधिक-तम लोगों को अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा

Pepalasis (पेपालासिस) ने इसी प्रकार के आयोजन के बारे में लिखा है

> "The process of economic development is not restricted to economic change but is essentially a transformation of the human agent and his social environment."

Shri Wadia के अनुसार

> "आर्थिक आयोजन उचित सामाजिक वातावरण में ही सम्भव है. (Economic planning is not done in a social vacuum) केवल आर्थिक साधनों के खर्च करने से ही आयोजन नहीं हो जाता है. भौतिक तत्वों से मानव तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं आयोजन का मुख्य लक्ष्य मानव साधनों का पूर्ण प्रयोग करना होता है."

सामाजिक आयोजन का लक्ष्य देश में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार में वृद्धि लाना है. धन की असमानताओं को दूर करना चाहिए. सामाजिक आयोजन "शान्ति के युद्ध" पर विजय पाना होता है (अर्थात् गरीबी व शोषण पर विजय पाना होता है).

III Main Features of Planning : आयोजन की मुख्य विशेषताएँ .

किसी भी देश में आयोजन की निम्नलिखित विशेषताएँ होती है

एक निश्चित लक्ष्य

हर देश में आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य हो सकता है. यह लक्ष्य अलग-अलग देशों में अलग हो सकते है. बहुत उन्नत देशों में यह लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता रखना या बेरोजगारी को रोकना हो सकता है. कम-विकसित देशों में मुख्य लक्ष्य

(i) देश में उत्पादन बढ़ाना

Pepalasis . op. cit.

S S. Wadia : Techniques cf Planning.

(ii) देश के प्राकृतिक साधनो का उपयोग.

(iii) देश मे उत्पादकता बढाना

(iv) देश की अतिरेक (Surplus) जनशक्ति का प्रयोग करना.

(v) आय म समानता लाना आदि हो सकता है

कभी-कभी आयोजन के एक से अधिक लक्ष्य हो सकते है. फिर कोई एक लक्ष्य मुख्य होता है समस्त कार्य फिर इन्ही लक्ष्यो के आधार पर किए जाते है.

एक केन्द्रीय शक्ति

किसी भी देश मे एक केन्द्रीय शक्ति के बगैर आयोजन सभव नही होता. अगर केन्द्रीय शक्ति न हो तो अर्थव्यवस्था की इकाइयो (जैसे अलग अलग राज्यो या उद्योगो द्वारा बनाई योजनाओ) मे समन्वय नही रहेगा. परस्पर विरोधी योजनाएँ भी तैय्यार हो सकती है. केन्द्रीय शक्ति ही साधनो के अनुसार अधिकतम लाभ देने वाली योजना बना सकती है.

यह योजना केन्द्रीय सरकार (सत्तारूढ राजनैतिक पार्टी) द्वारा बनाई जा सकती है या सब राजनैतिक पार्टियो के सहयोग से बनाई जा सकती है. तकनीकी विशेषज्ञो की हमेशा सहायता ली जाती है

निजी क्षेत्र भी आयोजन क्षेत्र में

आयोजन का लक्ष्य केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो को ही आयोजनानुसार चलाना नहीं होता. निजी क्षेत्र के उद्योगो को भी उत्पादन लक्ष्य दे दिए जाते है और उनसे उन्हे पूरा करने को कहा जाता है दोनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं. (Complementary and Supplementary) भिन्न भिन्न उद्योगो को इस प्रकार से बढने दिया जाता है कि एक की वृद्धि दूसरे को भी लाभदायक हो. वे एक दूसरे की आवश्यकताओ को पूरा करते है.

प्राथमिक लक्ष्यों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है :

कम-विकसित देशो मे साधन तो कम रहते है और आवश्यकताएँ अधिक रहती हैं. सही प्राथमिकताओ के निर्धारण से साधनो के प्रयोग में मितव्ययिताएँ होती है प्राथमिकताओ के निर्धारण मे निम्नलिखित तत्वों को ध्यान मे रखा जाना है

(1) कृषि व उद्योगो मे समन्वय, कृषि मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सर्व-प्रथम लक्ष्य होना चाहिए. इससे उद्योगो को सस्ता व अधिक कच्चा माल मिलता है, देश मे मूल्य वृद्धि नही हो पाती व समस्त विकास की नीव ठोस पड जाती है

(ii) कम-विकसित देशों में विदेशी मुद्रा की अत्यन्त कमी रहती है. इसके लिए *आयात-वर्धक व निर्यात कम करने वाले उद्योगों को पनपाना* चाहिए. हो सकता है कि आयात-वर्धक उद्योगों के विकास के लिए पहले बहुत सी मशीनें मँगाने से आयात बढ़ें. परन्तु हर देश को उन उद्योगों को प्राथमिकता देना चाहिए जिनमें भुगतान सतुलन सुधरे.

(iii) भौतिक उत्पादन वृद्धि के साधनों (जैसे उद्योग, यातायात, कृषि आदि) तथा अभौतिक वृद्धि के साधनों मे समुचित प्राथमिकता दी जाती है इस देश मे शिक्षा, स्वास्थ्य व कुशलता वृद्धि को भी ध्यान में रखते हैं.

(iv) समस्त उद्योगों में कुछ न कुछ आयोजन का प्रभाव अवश्य होना चाहिए. किसी एक उद्योग में ही समस्त साधनों का विनियोजन नहीं किया जाता है. उपभोग उद्योग व भारी उत्पादन उद्योगों को इस प्रकार प्राथमिकताएँ दी जाती है कि विकास भी आगे बढ़े तथा जनता की माँगें भी यथासभव पूरी हो सकें

आर्थिक उत्पादकता के साथ-साथ सामाजिक उत्पादकता वृद्धि—दोनों पर ध्यान रखा जाता है :

अनायोजित अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक इकाइयाँ अपने यहाँ वस्तुगत उत्पादकता या आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं. कभी-कभी तो यह भी सभव नहीं हो पाता. क्योंकि किसी भी उद्योग मे उत्पादन वृद्धि बहुत से अन्य क्षेत्रों मे उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि पर निर्भर रहती है. आयोजन मे इस प्रकार से समन्वित विकास किया जाता है कि हर क्षेत्र मे उत्पादकता बढ़े इसके अतिरिक्त सामाजिक उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है. सामाजिक उत्पादकता देश मे शिक्षा, ट्रेनिंग व स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास व पूर्ण रोजगार बढ़ाने से बढ़ती है

देश की अल्प व दीर्घकालिक योजनाएँ व आवश्यकताएँ :

आयोजन में 'समय' आयोजन का मुख्य अग होता है हर देश एक दीर्घकालीन योजना बनाता है. यह योजना दस या बीस वर्ष की हो सकती है फिर इसको चार-साला या पाँच-साला योजनाओं में बाँट दिया जाता है. फिर हर इस प्रकार की योजना को वार्षिक योजनाओं में बाँट देते है. हर बड़ी योजना के छोटे टुकड़े इसलिए कर दिए जाते है कि अगर ऐसा न किया जाये तो योजना के शुरू में काम धीमी गति से होगे और बाद के वर्षों में बहुत काम इकट्ठा हो जाएगा इसलिए

आयोजन की यह विशेषता होती है कि इस प्रकार की योजनाओं में देशवासियो को अल्प व दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान मे रखा जाता है.

साधनों का विवेकपूर्ण वितरण :

हर देश मे कुछ न कुछ साधन सबधी कमियाँ रहती है कही प्राकृतिक साधन कम होते है तो कही पूँजी की कमी रहती है और कही दोनो की कमी रहती है आयोजित अर्थव्यवस्था मे इनका बँटवारा इस प्रकार से किया जाता है कि अधिकतम क्षेत्रो को कम से कम खर्च से अधिकतम लाभ प्राप्त हो.

IV. Types of Planning . आयोजन के प्रकार :

(a) Physical and Financial Planning

Physical Planning भौतिक आयोजन :

आयोजन का लक्ष्य भौतिक वस्तुओ के रूप मे व्यक्त किया जाता है, जबकि Financial Planning वित्तीय आयोजन म लक्ष्य वित्तीय व्यय को प्राप्त करना होता है, उदाहरण के रूप मे प्रथम प्रकार के आयोजन मे राज्य यह निश्चय करता है कि 200 कॉलिज, 2000 मील लम्बी सडकें, 8 बाँध, 20 अस्पताल आदि का निर्माण करना है. राज्य तदानुसार आय जुटाता है और व्यय करता है. द्वितीय प्रकार के आयोजन मे राज्य के लक्ष्य इस प्रकार से व्यक्त किये जायेंगे. शिक्षा पर 80 लाख रुपया, सडक निर्माण पर 20 लाख रुपया, सिंचाई पर 100 लाख रुपया व स्वास्थ्य पर 80 लाख रुपया इनके अनुसार खर्च होगा

प्रथम प्रकार के आयोजन म लक्ष्यो को "वास्तविक रूप मे" (inreal te rms) में व्यक्त किया जाता है और यह विकास मे वृद्धि करता है, द्वितीय व्यवस्था में एक त्रुटि है, अगर मूल्य दुगने बढ जायें तो वही 80 लाख रुपये मे 200 कॉलिजो के स्थान पर केवल 100 कॉलिज ही स्थापित हो सकेगे

Physical Planning मे लागत व लाभ का ध्यान रखा जाता है.

Financial Planning : *वित्तीय आयोजन :* इसमे एक निश्चित मात्रा मे व्यय करने का लक्ष्य होता है. इस प्रकार के आयोजन का महत्व मुद्रा विस्फीति या मदी काल में होता है जबकि बाजार मे एक निश्चित मात्रा मे खर्च करने की आवश्यक्ता होती है.

पर दोनो प्रकार के आयोजन एक दूसरे पर निर्भर रहते है. साधनो की कमी से कभी-कभी भौतिक लक्ष्यो को घटाया या बढाया जा सकता है. या कभी कभी

कुछ भौतिक लक्ष्यों का प्राप्त करना इतना आवश्यक हो सकता है कि उसके अनुसार साधनों की व्यवस्था करनी पड सकती है. दोनो प्रकार का आयोजन एक दूसरे का पूरक है, विरोधाभासी नही, कम-विकसित देशों में सांख्यकीय पद्धति व प्रशासन के पूर्ण रूप से उन्नत न होने के कारण बहुधा दोनों प्रकार के लक्ष्यों में समन्वय नही आ पाता इस कारण आयोजन में बाधायें आती हैं व असफलतायें हाथ लगती हैं

भारत ने तो लक्ष्यो को Global आधार पर (सम्पूर्ण क्षेत्रो मे) इस प्रकार निर्धारित किया कि बाद मे उनकी लागतें बढती गईं और उनके वित्तीय लक्ष्य अवसर बढते गये और मुद्रा स्फीति पैदा हुई.

(b) Structural Planning and Functional Planning :

Revolutionary Planning and Evolutionary Planning.

Structural Planning संरचनात्मक आयोजन :

समाज का आर्थिक व सामाजिक ढाँचा ही बदल दिया जाता है और नए आर्थिक व सामाजिक ढाचे का निर्माण होता है इस प्रकार के आयोजन मे थोडे बहुत सुधारात्मक कार्य ही नही किए जाते हैं, वरन् सम्पूर्ण नया समाज उत्पन्न कर दिया जाता है इस प्रकार के आयोजन मे रचनात्मक कार्य के साथ साथ पुरानी पद्धतियो, पुरानी व्यवस्थाओ को समाप्त कर दिया जाता है. समाजवादी देशो मे इसी प्रकार का आयोजन होता है. इस कारण हम इस प्रकार के आयोजन को क्रान्तिकारी आयोजन या Revolutionary Planning भी कहते है

Functional Planning क्रियात्मक आयोजन :

वर्तमान आर्थिक ढाचे व सामाजिक व्यवस्था को कायम रखा जाता है और जो कुछ कमियाँ होती है उन्ही मे सुधार कर दिया जाता है. यह Evolutionary Planning हुआ.

इस संबंध में एक बात ध्यान मे रखने योग्य यह है कि कालान्तर से Structural Planning, Functional Planning में परिणत हो जाती है. जैसे रूस या चीन मे जब आयोजन शुरू हुआ तो वहां के आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक ढाँचे को उखाड फेंका गया और फिर उसमें आयोजन किया गया पर एक बार जब समाजवाद स्थापित हो गया तो फिर कोई क्रान्तिकारी परिवर्तनो की गुंजाइश या सम्भावनाएँ ही नही रही और आयोजन Functional हो गया.

See · F. Zweig. The Planning for Free Societies p 101-2.

दूसरी ओर Functional Planning मे धीरे-धीरे आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन हो जाता है और धीरे-धीरे सुधार से नयी आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है. साराश मे पहले प्रकार के आयोजन मे नए समाज को शीघ्रातिशीघ्र लाया जाता है, तो दूसरे प्रकार के आयोजन में केवल सुधार किए जाते है पर धीरे-धीरे यही सुधार समाज बदल देता है. आज के कम-विकसित देशो मे समाज व आर्थिक व्यवस्था को बहुत बदलने की आवश्यकता है अगर यह क्रान्तिकारी तरीको से नही बदला जा सकता है तो कम से कम काल मे यह परिवर्तन लाने होगे भारत की प्रथम योजना मे वर्तमान व्यवस्था को एकदम बदलने की बात नही की गई है वरन् धीरे-धीरे परिवर्तन की बात कही गई है.

(c) Corrective and Development Planning : सुधारात्मक व विकास के लिए आयोजन :

Corrective Planning or Emergency Planning, or Preventive Planning or Restorative Planning

विकसित देशो में, विशेष रूप मे पूँजीवादी देशों मे, सुधारात्मक आयोजन ही किया जाता है. जब ऐसा देश विकास के रास्ते से हट जाता है या मदी का शिकार हो जाता है तो मदी लाने वाले तत्वो को 'सुधारात्मक आयोजन' से दूर कर दिया जाता है. 1930 की महान विश्व मदी के बाद आज पूरी अर्थव्यवस्था को काफी मात्रा मे निर्देशन दिया जाता है आज बाजार मूल्यों तथा मजदूरी की दरो को नियमित व नियत्रित किया जाने लगा है. आज समस्त विकसित देशो मे 'बेरोजगारी' को दूर करना आयोजन का लक्ष्य बन गया है आज ऐसे विकसित देशो मे भी जो अनियोजित व्यवस्था के उदाहरण रहे. उपरोक्त प्रकार का सुधारात्मक आयोजन अर्थव्यवस्था का अग बन गए है.

परन्तु सुधारात्मक आयोजन मे राज्य अर्थव्यवस्था मे बहुत अधिक हस्तक्षेप नही करता. इस प्रकार के आयोजन म राज्य निजी उत्पादकों व विनियोजकों को सहायता देता है, निर्देशन देता है और आवश्यकता पडने पर नियत्रण करता है इसका मुख्य लक्ष्य देश म 'आर्थिक अस्थिरता' दूर करना है.

मुद्रा स्फीति (महँगाई) के काल म राज्य बचत के बजट बनाती है (खर्च कम, आमदनी ज्यादा) जिससे बाजार का अधिक पैसा खिंच आये व मूल्य गिरे. इस काल मे ब्याज की दरो, मूल्यो, मजदूरी की दरो व सट्टे को नियत्रित किया जाता है साथ ही साथ अधिक उत्पादन व उत्पादकता बढाने की सुविधाएँ दी जाती है

मन्दी काल मे घाटे का बजट प्रस्तुत करके (खर्च अधिक आमदनी कम) नए नोट छाप कर बाज़ार मे मुद्रा की मात्रा बढाई जाती है इस अतिरिक्त मुद्रा से राज्य राहत व विकास कार्य हाथ में लेता है. इसी काल मे राज्य सामाजिक सुरक्षा के लाभो को बढाता है. करो मे कमी करता है तथा बैंको द्वारा दी जाने वाली साख बढाने की सुविधायें देता है

इस प्रकार के आयोजन में जैसे ही अस्थिरता का भय दूर होता है. आयोजन बन्द हो जाता है, इस प्रकार का आयोजन एक राजनैतिकवाद पर निर्धारित नही होता यह चक्र विरोधी नीति का अग होता है.

Development planning : विकास के लिए आयोजन :

कम-विकसित देशो मे आयोजन का लक्ष्य केवल आर्थिक व्यवस्था मे थोडे बहुत सुधार करना नही होता, वरन् समस्त आर्थिक व्यवस्था का जीर्णोद्धार करना पडता है. इस कारण "विकास के लिए किए जाना वाला आयोजन सुधारात्मक आयोजन से अधिक जटिल, कठिन व महत्त्वपूर्ण होता है. इस प्रकार के आयोजन मे आर्थिक ढाँचे के साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनीय और कानूनी ढाँचो को भी बदलना पडता है. इस प्रकार के आयोजन में सुधारात्मक आयोजन से कई लक्ष्य भिन्न होते है, उदाहरणतया जबकि सुधारात्मक आयोजन मे आय की असमानताओ को कम करने पर ज़ोर दिया जाता है. "विकास के लिए" आयोजन मे असमानताओ को दूर करने से पूँजीपतियो द्वारा किए जाने वाला पूँजी-निर्माण रुक जाएगा और देश मे उत्पादन व रोजगार स्तर गिर जाएँगे "विकास के लिए आयोजन" में "समृद्धि मे समानता" लाना चाहते है न कि "गरीबी मे समानता" लाना चाहते है.

"विकास के आयोजन" मे मुख्य रूप से निम्नलिखित पाँच कदम उठाए जाते है :

(1) सर्वप्रथम हमे देश के प्राकृतिक साधनो का सर्वेक्षण करना पडेगा और फिर उनके प्रयोग करने के लिए लागत का अनुमान लगाना पडता है.

(ii) इसके बाद यह निश्चित करना पडता है कि कौन से प्राकृतिक साधनो का प्रयोग पहले हो और कौन से साधनो का प्रयोग बाद मे हो.

(iii) इसके पश्चात पूरे देश की एक वृहत् और दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है फिर देश के भागों की छोटी-छोटी व अल्पकालीन योजनाओ को बनाया जाता है

(iv) इसके बाद इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है.

(v) कार्यान्वित करने मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना जिसमे योजना लचीली रहे

'विकास के आयोजन' मे कृषि, उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश के व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सबका विकास किया जाता है. देश मे रोजगार, आय, प्रति व्यक्ति आय आदि के स्तर को उन्नत किया जाता है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रो में विनियोजन मे वृद्धि की जाती है. देश मे बचत व पूँजी-निर्माण बढाया जाता है. देश के प्राकृतिक साधनो का अधिकतम प्रयोग करके उत्पादन व उत्पादकता बढाई जाती है तथा माँग और पूर्ति मे समन्वय लाया जाता है.

(d) Planning by Inducement and Planning by Direction· आर्थिक प्रोत्साहन देकर आयोजन तथा निर्देशन देकर आयोजन

Planning by Inducement or Democratic Planning : प्रोत्साहन मूलक या प्रजातन्त्रीय नियोजन :

पहले तो यह माना जाता था कि अगर आयोजन है तो प्रजातन्त्र नही रहता, पर अब ऐसा नही माना जाता इस प्रकार के आयोजन मे निजी सम्पत्ति को समाप्त नही किया जाता है. सरकारी व निजी क्षेत्र के कारखाने व व्यापारिक संस्थान साथ-साथ चलते है देश की योजना किसी एक राजनैतिक दल द्वारा नही बनाई जाती है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियो द्वारा तकनीकी व्यक्तियो की सलाह से बनाई जाती है किसी प्रकार के 'दबाव' के स्थान पर 'समझाने' की पद्धति से कार्य लिया जाता है.

निजी क्षेत्र के उद्योगो को पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है परन्तु किन्ही विशेष परिस्थिति में कुछ उद्योगो को अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित किया जा सकता है राज्य देश की विनियोजन की मात्रा व क्षेत्रो को अपनी मौद्रिक व राजकोषीय नीति से प्रभावित करता है अर्थात् जिस क्षेत्र में राज्य विनियोजन की मात्रा बढवाना चाहता है उसे अधिक धन उधार दिला सकता है या कर सम्बन्धी छूट दे देता है

ल्युस (Lewis) ने इस प्रकार के आयोजन का उदाहरण दिया है. जैसे अगर राज्य चाहता है कि देश के बच्चे रोज एक निश्चित मात्रा मे दूध का प्रयोग करें. राज्य इसके लिए या तो दूध के उत्पादनकर्ताओ को कर से मुक्त कर सकता है या दूध को सस्ते दामो पर बिकवा सकता है और दूध के उत्पादनकर्ताओ को कुछ धन अपने पास से दे सकता है.

Lewis इस प्रकार के आयोजन को निर्देशन के द्वारा सचालित आयोजन मे

अधिक महत्वपूर्ण मानते है. वे चाहते है कि यथा सम्भव स्वतन्त्र बाजार प्रणाली को अपनाये रहकर भी आयोजन होना चाहिए.

कम-विकसित देशो मे उत्पादन कम होता है जिससे मूल्य अधिक रहते है. देश में उत्पादन के क्रम गतिशील कम होते हैं. बहुधा सरकार ऐसे समय मे राशनिग या कन्ट्रोल करती है और मूल्य नियत्रण करती हैं, पर अच्छा यह हो कि राज्य की उत्पादकता बढाने पर विशेष जोर दिया जाए. Lewis का कथन है

> "आयोजन की सफलता उत्तम राशनिंग पद्धति और कठोर मूल्य नियत्रण से नही आकी जाती, बल्कि इस बात से आकी जाती है कि कितने शीघ्र इस न्यूनता को समाप्त करके राशनिंग व मूल्य नियत्रण को अनावश्यक कर दिया जाए."

हम सबको विदित है कि लिंकन ने प्रजातन्त्र की परिभाषा यह दी थी

> 'प्रजातन्त्र में राज्य सरकार जनता द्वारा स्थापित, जनता के लाभ के लिए जनता के द्वारा गठित होता है" उसी प्रकार से इस प्रकार का आयोजन भी "Planning by the people, for the people and of the people" कह सकते हैं. इस प्रकार के आयोजन में राज्य जनता पर हावी नही होता. जनता राज्य के आयोजन की आलोचना कर सकती है आयोजन मे जनता सहयोग भी करती है इस प्रकार के आयोजन को इसीलिए Planning from the bottom अर्थात आधार से या नीचे से आयोजन कहते है.''

परन्तु इस प्रकार का आयोजन वहाँ सफल होता है जहाँ के देशवासी शिक्षित, समझदार व अनुशासित होते हैं फ्रांस मे इस प्रकार का आयोजन इसी कारण सफल रहा. इस प्रकार के आयोजन की सफलता एक तो इस बात पर निर्भर करती है कि निजी क्षेत्र के उद्योग सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखकर समाज का अपने स्वार्थ के लिए शोषण न करे और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सुचारु रूप से कार्य करें अर्थात घाटे में न चलें

प्रजातान्त्रिक आयोजन की सबसे बडी समस्या समन्वय की होती है आयोजन में भिन्न-भिन्न योजनाएँ इस प्रकार से चलाई जाना चाहिए कि वे एक दूसरे की प्रतियोगी होने के स्थान पर पूरक हो. (They should supplement each other, not supplant each other).

बहुधा प्रजातन्त्र व स्वतन्त्रता के नाम पर इस प्रकार के आयोजन के सफल होने की राह में रुकावटें डाल दी जाती है.

(e) Planning by Direction : निर्देशन से आयोजन or Planning by Central Authority : केन्द्रीय सस्था के द्वारा आयोजन or Socialist Planning समाजवादी आयोजन or Authoritarian Planning शासकीय आयोजन or Fascist Planning फासिस्ट आयोजन :

इस प्रकार के आयोजन मे उत्पादन के समस्त अगो का राष्ट्रीयकरण हो जाता है निजी क्षेत्र के पास सम्पत्ति नही छोडी जाती या बहुत थोडी मात्रा में छोडी जाती है वस्तुओ व सेवाओ के उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण राज्य के द्वारा नियन्त्रित होते हैं, इस प्रकार का आयोजन कठोर होता है. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जैसी कि प्रजातन्त्र देशों मे होती है या तो समाप्त हो जाती है या नाम मात्र रह जाती है, आलोचना करने से दड के भागी हो सकते है. एक केन्द्रीय आयोजन समिति योजना के लक्ष्य निर्धारित करती है जिनको एक निश्चित काल म पूरा करना होता है. देश के इस प्रकार मे औद्योगीकरण करने पर बल दिया जाता है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए सकुचित राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है

देश में बचत की मात्रा कितनी होना चाहिए यह राज्य निर्धारित करता है यह बचतें या तो अनिवार्य रूप से वेतन में से काट ली जाती है या फिर उत्पादन करो के रूप में ले ली जाती है. कभी-कभी तो इससे जनता को महान् कष्ट हो जाता है

इस प्रकार के आयोजन में देश की राजनीति व सामाजिक व्यवस्था ही कठोर होती है, जनता उपभोग कम करके या जो बचत करते है वे उज्ज्वल भविष्य की आशा मे ऐसा करते है. बहुधा उनके सामने कोई और विकल्प भी नही होता. इस प्रकार के आयोजन म निजी लाभ, व्यापारिक व्याज व लगान समाप्त हो जाते है. देश के आर्थिक कार्यों से जो लाभ होते है वे राज्य को प्राप्त होते है और इनमें मे प्रशासनिक व्ययो को निकाल कर जो बचता है उससे पूँजी निर्माण होता है और इसके लाभ जनता को ही बाँट दिए जाते है.

Dickenson डिक्सिन व Pigou पीगू इस प्रकार के Authoritative आयोजन को उत्तम आयोजन पद्धति मानते है. क्योकि इसमे समस्त साधनों पर पूर्ण अधिकार होता है, लक्ष्य सुनिश्चित होते है तथा कार्यान्वित करने में समन्वय की कमी नही रहती

Durbin भी इस प्रकार के आयोजन को उत्तम मानते है.

पर इस प्रकार के आयोजन म हर चीज राज्य की आज्ञा से होती है. हम त्युस

के दूध वाले उदाहरण को यहाँ भी ले सकते हैं इस प्रकार के आयोजन मे अगर राज्य बच्चो को एक निश्चित मात्रा मे दूध का सेवन कराना ही चाहता है तो वह अनिवार्य रूप से ऐसा निम्नलिखित किसी भी युक्ति द्वारा कर सकता है .

(i) राज्य स्कूलों मे अनिवार्य रूप से दूध बटवाए
(ii) अन्य बच्चो के वार्ड बना दिए जाएँ और उन्हे रोज दूध लेना पड़े.
(iii) स्वय दूध की उत्पादन वृद्धि अपने हाथ में ले और उस दिशा मे कार्य करे.

ल्युस ने इस प्रकार के आयोजन मे बहुत सी बुराइयाँ बताई है जो इस प्रकार है .

(i) इस प्रकार के आयोजन मे रोजगार चयन राज्य करता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने पेशे को चुनने की उन्मुक्त स्वतन्त्रता नही होती पर यह आलोचना निर्मूल है सही अर्थ मे तो पूजीवाद मे यह स्वतन्त्रता नही होती. वहाँ इतनी बेरोजगारी होती है कि जिसको जो कार्य मिल गया उसको वही करते रहना पड़ता है. समाजवाद में हर व्यक्ति को रोजगार, मौलिक अधिकार के रूप मे, प्राप्त होता है. राज्य अपनी आवश्यकतानुसार लोगो को शिक्षा व ट्रेनिंग देती है.
(ii) यह आयोजन प्रणाली कठोर होती व लोचदार नही होती है इसमे लक्ष्यो मे शीघ्र परिवर्तन नही होता.
(iii) आयोजन के कार्यान्वित करने मे अवसर समस्यायें खडी हो जाती हैं उदाहरण के तौर पर आयोजित हर उद्योग को कोयले का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है. परन्तु अगर मौसम की खराबी, हड़ताल अथवा किसी भी कारण से कोयले का उत्पादन कम हुआ तो भिन्न भिन्न कारखानो के लक्ष्य पूरे नही हो सकते. इनको पेट्रोल भी नही दिया जा सकता क्योंकि पेट्रोल का भी तो पूर्ण वितरण (allocation) पहले से हो चुका होता है पूँजीवादी आयोजन में कमी के कारण मूल्य बढ जाते हैं और बढे हुए मूल्यो पर माग मे कमी आती है और माग व पूर्ति का नया साम्य उत्पन्न हो जाता है, पर इन दोषो को भी बढाचढाकर बताया गया है. असाधारण परिस्थिति मे लक्ष्य भी दुहरा लिए जाते हैं और सचित स्टाक मे कमियाँ पूरी की जाती हैं
(iv) ल्युस के अनुसार ऐसे आयोजन वाले देशो में अर्थशास्त्रियो की भरमार हो जाती है. रूस मे 10 लाख से अधिक इस प्रकार के अर्थशास्त्री है.

V. Conditions for Successful Planning . आयोजन की सफलता के आवश्यक तत्व

1 किसी भी देश मे आयोजन शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आवश्यकता आयोजन के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न आर्थिक क्षेत्रों के "सही और विस्तृत आँकडे प्राप्त करना" होता है जैसे जनसख्या के स्तर तथा बढने सम्बन्धी आँकडे व देश में बचत, पूँजी निर्माण, उत्पादन, उत्पादकता विनियोग, रोजगार, बेरोजगार, लागत और उत्पत्ति आदि के आँकडे जाने बिना योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारित होना असम्भव है इसलिए सही और व्यापक सर्वेक्षण करना व साख्यकीय विभाग खोलना आवश्यक हो जाता है

2 देश मे "आयोजन के चार पद" होते है
   (i) योजना बनाना.
   (ii) योजना स्वीकार करना
   (iii) योजना कार्यान्वित करना.
   (iv) योजना का मूल्याकन करना

जुईग (Zweig) के अनुसार योजना को विकेन्द्रित रूप से तैयार करना चाहिए पर उसकी स्वीकृति केन्द्र से होना चाहिए उसको कार्यान्वित करना और मूल्याकन करना विकेन्द्रित रूप से होना चाहिए. योजना को बनाने का कार्य और मूल्याकन का कार्य मुख्य रूप मे विशेषज्ञो को करना चाहिए. उसकी स्वीकृति का काम पार्लियामेन्ट अर्थात् राजनैतिक स्तर पर करना चाहिए और उसका सचालन प्रशासनीय अफसरो द्वारा करना चाहिए. एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नही होना चाहिए

3. सफल आयोजन के लिये लक्ष्यो का सही चयन होना चाहिए अर्थात् विचार-पूर्ण आयोजन होना चाहिए यह लक्ष्य देश को युद्ध में ताकतवर या रोजगार में वृद्धि करना या दीर्घकालीन उन्नति की ओर ले जाना आदि कुछ भी हो सकता है

4 अगर लक्ष्य बहुत है और साथ रूप है, जैसा कि अधिकतर देशो में होता है तो उनकी प्राथमिकता निश्चित करना चाहिए, अगर बहुत से लक्ष्य एक साथ चुन लिए गये तो इससे देश के आर्थिक साधनो पर बहुत अधिक प्रभाव पडेगा और जनता म असतोष बढेगा. उदाहरण के लिए भारत ने अपने लक्ष्यो को बहुत ऊँचा रखा और परिणाम स्वरूप जनता के सामने लक्ष्य पूर्ण न होने का दृश्य सामने आया जबकि पाकिस्तान ने अपने लक्ष्यो को नीचा रखकर उनसे

अधिक कार्य किया और उससे जनता के सामने सफल आयोजन का दृश्य प्रस्तुत किया आयोजन को कभी भी अत्यधिक आशावादी नही होना चाहिए

5 **"देश मे मजबूत, कुशल, उत्साही तथा ईमानदार राजनीतिज्ञ तथा सरकार होना चाहिए "** युद्ध काल मे जुईग के अनुसार प्रजातन्त्र मे आयोजन सफल होता है जिसका मुख्य कारण उस समय सरकार का शक्तिशाली होना होता है लेकिन जुईग का यह भी कथन है कि सरकार की यह शक्ति भौतिकरूप मे नही की जानी चाहिए बल्कि नैतिक रूप मे सरकार को शक्तिशाली होना चाहिए अर्थात् सरकार को कुशल व ईमानदार होना चाहिए जिससे जनता का विश्वास हो रूस मे आयोजन के सफल होने का कारण वहाँ राज्य का शक्तिशाली होना था व फ्रास म Blum-experiment व अमेरिका मे New Deal के असफल होने का कारण सरकार का कमजोर होना था

6 सफल आयोजन के लिए "प्रलोभन" अत्यन्त आवश्यक है यह प्रलोभन आर्थिक और अनार्थिक दोनो हो सकते है आर्थिक प्रलोभन का अर्थ होता है कि देश में ऐसी व्यवस्था हो कि कुशल उत्पादनकर्ता को उचित पारितोषिक मिले और अकुशल को उचित दण्ड अनार्थिक प्रलोभन का अर्थ होता है कि ऐसे प्रलोभन जैसे यश या इज्जत, मेडल अथवा पदवी प्रदान की जाय. जैसे, रूस में Stakhanovist आन्दोलन अथवा भारत मे कृषि पण्डित व श्रमवीर आदि

7. *जनता का सहयोग* देश के *आयोजन* के लिए *प्रचार व्यवस्था कुशल* व व्यापक होना चाहिए जनता का सहयोग आयोजन रूपी मशीन चलाने के लिए तेल व पेट्रोल दोनो का काम करता है. भारत में आयोजन शुरू होने के काल मे जनता का काफी सहयोग था परन्तु बाद में राजनीतिज्ञो और प्रशासनीय भ्रष्टाचार के कारण वह उत्साह अब नही दिखता है आयोजन कितना भी वैज्ञानिक क्यो न हो, जब तक देश के नेताओ में सम्पूर्ण देश को जाग्रत करने और कार्य का उत्साह भरने की शक्ति नही होगी आयोजन सफल नही होगा.

8. जनता के सहयोग के लिए यह जरूरी होता है कि आयोजन मे "उचित समानता" पाई जाय अन्यथा गरीब लोगो मे कोई उत्साह नही रहेगा । परन्तु बहुत अधिक समानता से पूंजी-निर्माण रुक जायगा Oscar Lange के अनुसार आयोजन म निजी क्षेत्र की शोषण शक्ति समाप्त होनी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो को कुशलता व लाभ सहित कार्य करना चाहिए.

9. *आयोजन की एक खास बात यह होनी चाहिए कि* Richard S. Euckas के अनुसार "आयोजन की एक योजना नही होना चाहिए" बल्कि उन्ही लक्ष्यो को प्राप्ति के लिए एक से अधिक योजनायें होना चाहिए. जैसे भोजन करने के लिये एक से अधिक भोज्य-पदार्थ होते है दुर्भाग्य से कम-विकसित देशो में एक ही योजना बनाई जाती है और उसमे सुधार और सशोधन भी बहुत कम होते हैं इकास का कथन है कि कोई भी देश हमेशा समस्त आर्थिक घटको के बारे में पूर्व अनुमान नही लगा सकता और कही न कही गलती अवश्य होगी इसलिए आयोजन मे लोच होना चाहिए.
10 जहाँ तक सभव हो छोटा "आयोजन क्षेत्र" होना चाहिये अर्थात् बहुत विस्तार मे नही होना चाहिए जितना अधिक आयोजन का विस्तार होगा उतना ही उसकी सफलता की कम आशा है।
11 समस्त आयोजन मे "समय का महत्व" है और इसलिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों को अलग अलग रखना चाहिये

H. W. Singer on conditions for successful planning :

हेन्स सिंगर ने सफल आयोजन के कुछ अलग ही अच्छे सिद्धान्त बताए है जिनका सार नीचे दिया जा रहा है

1. **बचतों में वृद्धि कर पूँजी-निर्माण करना :**
   विकास की किसी भी योजना को बनाने व कार्यान्वित करने से पहले उतनी मात्रा में पूँजी आवश्यकता को आँकना पडेगा देश मे किस तकनीक को अपनाया जाएगा तथा देश मे ICOR (Incremental capital output ratio) क्या है ? इसके आधार पर पूँजी की आवश्यकता आँकी जा सकती है. तदनुसार बचतो को बढाकर तथा अन्य रीतियो से[1] पूँजी-निर्माण किया जाना चाहिए
2 The principle of cumulation : सचयिता का सिद्धान्त :
   इसके बाद योजनाओ (projects) का चयन करना चाहिए जिनसे एक से

आयोजन की सफलता के लिए प्रमुख आर्थिक नीतियाँ अच्छी होना चाहिए, अर्थात् देश म (i) उचित कृषि नीति, (ii) प्राकृतिक साधनो के उपयोग नीति (iii) पूँजी निर्माण नीति . जिनका उल्लेख इस पुस्तक मे किया जा चुका है, होना चाहिए.

भिन्न-भिन्न प्रमुख नीतियो का सक्षिप्त साराश लिखा जाना चाहिए.

1. पूँजी निर्माण सम्बन्धी अध्याय देखिए.

अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो, जैसे सर्वप्रथम Multipurpose river valley projects बहुउद्देश्यीय नदीघाटी योजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं. इन योजनाओं के हर पहलुओं को पहले से योजनाबद्ध कर लेना चाहिए तथा उनको समन्वित रूप से कार्यान्वित करना चाहिए.

3. *Co-ordination between public and private projects:* **निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में समन्वय :**

   कम-विकसित देशों में निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में पर्याप्त समन्वय नहीं होता. बहुधा दोनों में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है. हर क्षेत्र को उन कार्यों को हाथ में लेना चाहिये जिसके लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त हो. देश में आर्थिक सामाजिक सिरोपरि सुविधाओं की योजनाएँ राज्य ही को हाथ में लेना चाहिए देश में आय सृजन करनेवाले (जैसे बिजली उत्पादन) तथा आय को उपयोग करनेवाले (जैसे अस्पतालों) क्षेत्रों में समन्वय होना चाहिए

4. *Research and importance of timing* **अनुसधान तथा समय का महत्व :**

   देश में हर चीज पर्याप्त व व्यापक अनुसधान के बाद होनी चाहिए जैसे कृषि के विकास के आयोजन को करने से पहले भिन्न-भिन्न किस्म की भूमियों की मिट्टी का सर्वेक्षण व सिंचाई व कीटनाशक दवाइयों की जरूरत का अन्दाज लगा लेना चाहिए उसी प्रकार से खाद, बीज आदि का प्रावधान भी कर लेना चाहिए अनुसधान के बगैर गल्तियाँ हो जाती हैं श्री सिंगर के शब्दों में

   > "Probably one of the most common sources of mistakes in economic development programming has been to wait too long without having a programme at all and then, having drawn up a programme, to rush it through without sufficient research Great mistakes are made and large sums of money wasted by not allowing a year or two for research after the

---

See : Chapter 9 Lecture on Development Planning International Development : Growth & Change : Mcgraw Hill Inc. 1964. P. 92-120.

> outline of the plan has been prepared. The important thing is to be patient at the right time and impatient at the right time."

हर योजना की लाभ-लागतो का अनुमान लगा लेना चाहिए और जहाँ तक सभव हो हर योजना को साधनो का सृजन करना चाहिए.

5 Dispersal vrs. Centralisation विकेन्द्रित आयोजन या केन्द्रित आयोजन[1] .

सिंगर के अनुसार विकास के लिए आयोजन "असतुलित विकास पद्धति" के आधार पर होना चाहिए उनका कथन है कि यह बात सही है कि विकास की आवश्यकता उन्ही क्षेत्रो मे अधिक होती है जो पिछडे हुए होते हैं. परन्तु इन क्षेत्रो मे आर्थिक सामाजिक सिरोपरि सुविधाओ के न होने से इस प्रकार से विकास महँगा पडेगा पहले उन्नत क्षेत्रो मे विकास करके साधनो का सृजन करना चाहिए और फिर पिछडे क्षेत्रो मे नियोजन करना चाहिए

6 Allocation of resources साधनो का आवटन :

Singer के अनुसार

> "Resources are horses and projects are carts, and it does not make sense to put the cart before the horse."

नियोजन के शुरू में साधनो के अनुसार योजना बनाना चाहिए एक साथ कई योजनाओ को हाथ में नही लेना चाहिए आयोजन आवश्यकताओ के आधार के स्थान पर साधनों के आधार पर बनाना चाहिए. साधनो को अधिकतम लाभ के आधार पर आवटित करना चाहिए.

7. Inflation to be avoided मुद्रास्फीति नहीं होना चाहिए :

विकास की वही योजना अच्छी होगी जिसमे मुद्रा स्फीति बिल्कुल न फैले. सिंगर का कथन है कि मुद्रा स्फीति से तो कभी भी विकास आयोजन को नही चलाना चाहिए. केवल मौद्रिक पूर्ति बढा देने से तकनीक व शिक्षा का विकास तो नही हो सकता उनका कथन है

> "In under-developed countries the trouble is not insufficiency of monetary demand In un-

---

op. cit : p. 95.

1. आप Balanced vrs. unbalanced growth के अध्याय म पढ चुके है.

der-developed countries, production is limited by technical factors, by absence of capital, by absence of skills, by the absence of raw materials, by the absence of public servants and by the absence of the machinery and you cannot cure these physical deficiencies by monetary devices "[1] (p. 99)

आगे उन्होने एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी है

"Finance can never make possible what is physically impossible."

8. Every project to be self-liquidating or atleast not yielding losses

हर आयोजन कार्य को अपनी लागत अपने लाभ से निकाल लेना चाहिए. अगर ऐसा न हो सके तो कम से कम हानि तो नही होना चाहिए. परन्तु समस्त उद्योग लाभ पर नही चल सकते बिजली उद्योग को लाभ पर चलाने के लिए अगर बिजली की दर अधिक रखी गई तो अन्य उद्योगो की लागत बढ जाएगी. इसलिए यह भी देखा जा सकता है कि एक उद्योग के हानि से चलने से क्या बहुत से अन्य उद्योग लाभ पर चल सकते है.

9. Flexibility **लोचकता :**

आयोजन हमेशा लोचदार होना चाहिए. हमको लक्ष्यो का गुलाम होकर ही नही रह जाना चाहिए आवश्यकतानुसार लक्ष्यो को अथवा योजना को कार्यान्वित करने की रीति को बदला या सुधारा जाना चाहिए

VI Planned Vrs. Unplanned Growth : आयोजित व अनायोजित अर्थव्यवस्था :

अनायोजित अर्थव्यवस्था :

Prof. Hayek (Road to Serfdom) :

प्रो. हायेक आयोजन के पूर्ण विरोधी है उनके अनुसार आयोजित अर्थव्यवस्था 'गुलामी की सडक' पर ले जाती है. उनका विश्वास है कि जैसे जैसे आयोजित व्यवस्था समाज मे बढेगी वैसे वैसे देश मे 'जुल्म के राज्य' की स्थापना होगी.

---

1. हम उनके इस मत से असहमत हो सकते है. अल्पकाल मे व उचित मात्रा मे मुद्रा स्फीति से लाभान्वित हो सकते है.

उनका कथन है कि अगर आर्थिक क्षेत्र मे स्वतन्त्रता नही है तो राजनैतिक स्वतन्त्रता भी नही होगी प्रत्येक व्यक्ति को जब अपना व्यवसाय चुनने व सम्पत्ति बनाने की स्वतन्त्रता होगी तब ही आर्थिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता होती है और आयोजित व्यवस्था में यह स्वतन्त्रता नही होती

परन्तु प्रो हाएक पूर्ण अहस्तक्षेप नीति के समर्थक नही है वे राज्य द्वारा एकाधिकार पर नियन्त्रण को बुरा नही समझते. वे यह भी नही कहते कि राज्य अपने देश मे आर्थिक रूप से ताकतवर लोगो द्वारा कमजोरो का शोषण होने दे.

वे तो planning by direction के खिलाफ है उनका विश्वास था कि इस प्रकार के आयोजन में तानाशाही का जन्म होगा. योजना एक केन्द्रीय शासन द्वारा बनाई जाएगी इस प्रकार की योजना कभी सभी वर्गो को सतुष्ट नही कर सकेगी ऐसी व्यवस्था मे प्रजातान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हो जायेगी पार्लियामेंट, ऐसी व्यवस्था मे, केवल "बतियाने वाले घर" रह जायेंगे

ऐसी व्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नष्ट हो जाएगी. जनता को वह उपभोग *करना पडेगा जो राज्य पैदा करता है. उपभोक्ताओ की माग व रुचि को* देखकर उत्पादन करने की पद्धति समाप्त हो जायेगी. इसी प्रकार से व्यक्तियो को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता भी नही रहेगी.

प्रजातन्त्र के प्रक्रियावादियों के रूप मे बुरे से बुरे लोग शक्ति हथिया लेते है ऐसी व्यवस्था मे राज्य जनता को दबाने के लिए Concentration camps (जहाँ हिटलर यहूदियो को बन्द कर यातनाएँ देता था) तथा Torture chambers (जहाँ कैदियो को यातनाएँ दी जाती थी) की स्थापना करता है देश मे हिंसा की अग्नि भडक उठती है और ऐसे समाज मे अन्त मे हिंसा का सहारा लेकर ही *सब कार्य कराए जाते है जनता को दबाव व धोखे से कुछ मान्यताओ का गुलाम* बना दिया जाता है और उनके स्वतन्त्र चिन्तन कार्य करने की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया जाता है.

अन्त मे देश मे नैतिकता का नाम नही रहता निजी स्वतन्त्रता समाप्त होने के बाद राज्य की बागडोर gangsters (गुडो) व Sadists (विकृत प्रवृत्ति) के हाथो में चली जाती है

हाएक ने कहा :

> "यह सर्वथा वाछनीय है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त करें, पर समाज पर विजय पाने से हमारी सभ्यता का नाश होगा सामाजिक उन्नति रुकेगी और तानाशाही को जन्म मिलेगा "

Walter Lipmann आयोजित व्यवस्था के खिलाफ है उनका कथन है कि :

"इसमे देश की विभिन्नता नष्ट होती है स्वतन्त्र समाज मे हम शासक वर्ग की आलोचना कर सकते है और स्वय विरोध करना सवैधानिक कार्य है, जबकि आयोजित व्यवस्था में यह देशद्रोह समझा जाता है. आयोजित व्यवस्था मे लोगो को इच्छानुसार योजना को नही बनाया जाता, बल्कि योजना के अनुसार लोगो की विचारधारा को बनाया जाता है"

John Jewkes का कथन है

"आयोजित अर्थव्यवस्था मे पूरे समाज पर आतक छा जाता है. जनता की स्वतन्त्रता असुरक्षित हो जाती है और विकृत मनोवृत्ति की यातनाएं दी जाती है कला दुर्बल होती है, मानवता कम होती है तथा दयाभाव समाप्त हो जाता है"

Von Mises आयोजित पद्धति के विरोधी है. उनका कथन है कि .

"आयोजित प्रणाली में स्वेच्छाचारी रूप मे बजट बनता है. स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था में मूल्यो के द्वारा ही माग व पूर्ति में साम्य होता है वे अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले Lever (दण्ड) है. (अगर किसी देश मे किसी वस्तु की पूर्ति कम है तो मूल्य बढ जाते है इसके परिणाम स्वरूप एक ओर तो माग कम होती है और दूसरी ओर पूर्ति बढा दी जाती है, और सतुलन पैदा हो जाता है) आयोजित अर्थ व्यवस्था में जब मूल्यो की स्वतन्त्र पद्धति छोड दी जाती है तो फिर आयोजक स्वेच्छाचारी निर्णय लेते जो बहुधा गलत होते है और फिर बार बार ठीक करना पडता है और इससे केवल गडबड ही फैलती है"

Waber का कथन है :

"आयोजित अर्थव्यवस्था मे जो साम्य होता है वह अस्वाभाविक व कृत्रिम होता है इसलिए अनुचित होता है."

Robbins का कथन है :

"जब एक देश मे आयोजित व्यवस्था स्थापित होती है तो वह देश यह चाहता है कि अन्य देश भी आयोजित व्यवस्था अपनाएँ. फिर आर्थिक सम्बन्धो को राजनैतिक पुट दे दिया जाता है. रूस में जब आयोजित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई तो उसने अन्य "आधिपत्य" के देशो में भी यही व्यवस्था फैलायी और यह भी एक नए प्रकार का "साम्राज्यवाद" है."

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर अनियोजित अर्थव्यवस्था के पक्ष में, तथा आयोजित व्यवस्था के विपक्ष में मुख्य तर्क :

1. आयोजित व्यवस्था मे स्वतन्त्रता नही रहती. पहले आर्थिक स्वतन्त्रता नष्ट होती है क्योकि अपने व्यवसाय चुनने व सम्पत्ति बनाने की स्वतन्त्रता नही होती, मन चाही वस्तुओं का उपभोग सम्भव नही हो पाता. धीरे-धीरे सामाजिक व राजनैतिक स्वतन्त्रता भी नष्ट हो जाती है आलोचना का अधिकार नही रहता. योजना ऊपर से लाद दी जाती है. एक बार समाजवादी आयोजन पद्धति आ गई तो इसको बदलना ही सम्भव नही होता है.
2. इस प्रकार की व्यवस्था म तानाशाही, लालफीताशाही व भ्रष्टाचार बढता है. पूँजीपतियो का स्थान बडे ओहदे वाले, पार्टी के व्यक्ति व बडे अफसर लेते है जो भ्रष्ट होते है. शासन मे शिथिलता रहती है मन लगाकर काम नही होता इस कारण जोर जबरदस्ती से कार्य कराया जाता है
3. अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार द्वारा सचालित नही हो तो "परमिट-कन्ट्रोल" राज्य स्थापित हो जाता है अर्धनियन्त्रित व अर्ध-आयोजित अर्थ-व्यवस्था मे बडे व्यापारी व सरकारी कर्मचारी रिश्वतें देते-लेते है
4 उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नष्ट हो जाती है
5 आयोजित व्यवस्था में राज्य ही यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा लेना चाहिए तथा किस प्रकार की नौकरी करना चाहिए
6 जब कभी भी देश में आयोजित अर्थव्यवस्था शुरू की गई तो एकदम बहुत गडबडी सामने आयी एकाएक उत्पादन रुक जाता है राज्य के आलोचक व आयोजन के विरोधी रुकावटे डालते है राज्य इनको बुरी तरह से दबाता है, कभी-कभी तो लाखो व्यक्तियो को मरवा दिया जाता है. बाद में फिर राज्य खूब कर लगाता है क्योकि उसको पूँजी की आवश्यकता होती है रूस मे तो आयोजन के प्रथम 30 वर्षो मे मजदूरो की वास्तविक मजदूरी घट गई. मूल्य 800 प्रतिशत बढा दिए गए और मजदूरो को बहुत कष्ट हुआ.

आयोजित व्यवस्था के पक्ष में तथा अनायोजित व्यवस्था के विपक्ष में तर्क :

प्रो० डुरबिन ने "हाएक की तीव्र आलोचना" की है उनका कथन है :

1. हाएक के विचारो में "मानसिक व राजनैतिक" हठधर्मी है तथा उनके विचार भ्रान्तिपूर्ण है
2. यह कहना बिल्कुल गलत है कि आयोजित अर्थव्यवस्था मे मूल्य व लागत का निर्धारण ठीक से नही हो पाता

3 जहाँ तक उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का प्रश्न है वह तो केवल पुस्तको मे लिखने के लिए है एक व्यक्ति के पास जब धन ही नही है तो उपभोग की स्वतन्त्रता कोई मायने नही रखती.

4 आज के युग मे अनायोजित अर्थव्यवस्था "पूर्ण प्रतियोगिता" की व्यवस्था नही होती, जिसके हाएक गुण गाते है, वरन् एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता की व्यवस्था होती है जिसमे जनता का भला नही होता वरन् शोषण होता है (Social good is damnified instead of being served)

5. अनायोजित अर्थव्यवस्था मे बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा और अज्ञानता बनी रहती है हाएक का यह कथन तो उल्टा ही है कि आर्थिक स्वतन्त्रता के न होने से राजनैतिक स्वतन्त्रता नही होती. वास्तव मे अनायोजित अर्थव्यवस्था मे राजनैतिक स्वतन्त्रता बेकार है क्योकि गरीबी, बेरोजगारी व असुरक्षा के कारण यह सब निर्मूल होती है.

Durbin · डर्बिन कहते है[1] :

> "Planning is likely to be a more efficient method of reaching any set of ends because reason is superior to instinct and knowledge to ignorance" .... "Political liberty without economic liberty is a plain case of post hoc propter hoc.

Lewis के अनुसार

> ' नियोजन व स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था व अराजकता के बीच का झगडा नही है नियोजन तो आज हर जगह मौजूद है प्रश्न यह है कि कितना नियोजन अदृश्य रूप से हो (स्वतन्त्र बाजार प्रणाली से) तथा कितना प्रत्यक्ष रूप मे हो बाजार व्यवस्था या अनियोजित अर्थव्यवस्था से भी सामाजिक कल्याण हो सकता है नियोजित अर्थव्यवस्था से यह कल्याण और अधिक हो सकता है और नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार व्यवस्था को भी सहायता मिलती है. थोडा बहुत आयोजन हमेशा रहा है और यह आवश्यक नही है कि नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही

1 Durbin : op cit , p 103-4

हो, "The dispute about planning cuts right across left and right, and has nothing to do with the dispute about socialism"

आयोजन के पक्ष में :

1 आयोजित व्यवस्था मे हम सब कार्य सुचारु रूप से करते है. वास्तव मे "We all are planners today" आज हम सब आयोजक है. योजनाबद्ध कार्य तो जीव जन्तु भी करते है.

2. अनायोजित अर्थव्यवस्था मे सब कुछ 'अहस्तक्षेप की नीति' के कारण पूंजीपतियो के हाथ मे छोड दिया जाता है. जिसके कारण प्राकृतिक साधनो का अधिक से अधिक ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते है. अधिकतम उत्पादनतो होता है परन्तु अधिकतम सामाजिक लाभ नही होता आयोजित व्यवस्था इन दोषो को दूर करती है

3 अनायोजित अर्थव्यवस्था मे उत्पादन मे समन्वय नही होता. बहुत से उत्पादनकर्ता पूर्णरूप से एक दूसरे के पूरक नही होते. कभी-कभी आवश्यकता से अधिक पैदा कर लेते है जिसमे मदी व बेरोज़गारी बढती है या कम वस्तुएँ पैदा करते है जिससे महँगी वस्तुएँ हो जाती है और गरीबो को कठिनाइयाँ होती है

4. अनायोजित अर्थव्यवस्था मे वितरण न्यायपूर्ण नही होता एक तरफ तो अमीरो की विलासिताओ व सब शौक के अनुसार ही, वस्तुए उत्पादित होती है और दूसरी तरफ गरीबो को आवश्यक वस्तुए उपलब्ध हो जाती है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे मे जार्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है

> "ऐसा राष्ट्र जो गरीब बच्चो के लिए दूध का इन्तज़ाम करने से पहले शराब का उत्पादन करता है, वह पागलो का राष्ट्र है."

आयोजित अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार से सुनियोजित उत्पादन व वितरण होता है. इस व्यवस्था मे एक सीमा के बाद अमीर लोगो को आय नही लेने दिया जाता अथवा उन्हे समाप्त ही कर दिया जाता है.

5 आयोजित अर्थव्यवस्था में मजदूरों का शोषण नही हो सकता. अनायोजित व्यवस्था मे या तो श्रम सघो की कमजोरियो के कारण उन्हें पर्याप्त मजदूरी नही मिलती या फिर बेरोजगारी बनी रहती है

6 आयोजित अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार में सतुलन बढाया जा सकता है. अनायोजित अर्थव्यवस्था मे गरीब देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे बहुत हानि

होती है ऐसे देशो मे अमीरो के उपभोग के लिए बाहर से विलासिताओं की वस्तुएँ आती हैं व देश से बाहर जाने वाली चीजो को अमीर देश सस्ता खरीद लेते हैं. आयोजित अर्थव्यवस्था मे देश के औद्योगीकरण के लिए मशीनें मँगाने के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है.

7 अनियोजित व्यवस्था मे अस्थिरता का दोष हैं. नियोजित अर्थव्यवस्था में यह दोष नही होता. अनियोजित अर्थव्यवस्था मे आये दिन व्यापार चक्र आते रहते है तेजी व मंदी के चक्र मे कई उद्योग बरबाद हो जाते है कई लाख व्यक्ति बेरोजगारी व गरीबी के चक्र में फस जाते है

8. अनियोजित अर्थव्यवस्था मे राज्य कुल उत्पादन का बहुत थोडा भाग पैदा करता है. इस कारण वह अपने कार्यो के परिणाम से अनभिज्ञ रहता है. आयोजित अर्थव्यवस्था मे राज्य परिस्थिति और कार्यो के प्रभाव का अच्छी तरह से मूल्याकन कर सकता है आयोजित अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक साधनो का विवेकपूर्ण प्रयोग होता है आयोजित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य देश मे संतुलित विकास उत्पन्न करना होता है.

9. अनियोजित व्यवस्था से भी विकास होता है पर आयोजित व्यवस्था से विकास भी होता है और सामाजिक कल्याण भी बढता है.

Lewis का कथन है .

> "अनियोजित अर्थव्यवस्था मे अराजकता है. आयोजित अर्थव्यवस्था मे सुव्यवस्था है"

Durbin ने इसीलिए कहा है .

> "आज के युग मे केवल पागल व्यक्ति ही अनायोजित व्यवस्था की बात कर सकते है."

VII. Stages of Planning : आयोजन की अवस्थाएँ :

किसी भी देश मे आयोजन की मुख्यत पाच अवस्थाएँ होती है, जो इस प्रकार है .

(i) सर्वप्रथम राज्य को भिन्न-भिन्न आकडो का अनुमान लगाना पड़ेगा, जैसे राज्य की राष्ट्रीय आय, रोजगार स्तर, उपभोग स्तर, बचतो व विनियोजन के अनुमान लगाने होगे. भिन्न-भिन्न वस्तुओ की कमियो या अधिकता का अनुमान लगाना होगा. राज्य को केवल वित्तीय बजट ही नही बनाना चाहिए वरन् हर क्षेत्र का बजट बनाना चाहिए, जैसे वस्तुओं का बजट, विदेशी व्यापार बजट आदि.

"From these data . a budget for each industry which seems likely to be in serious disequilibrium, a budget for each raw material that will be in short supply, setting demands against availabilities, a manpower budget, and a *foreign trade budget* *will have to be* prepared."

(ii) जब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रो की पूर्ति सबन्धी कमियो का अनुमान लगा लिया जाता है तो राज्य को मुख्यतया दो कार्य करने होते है. सर्वप्रथम तो यह करना होता है कि राज्य प्राथमिकताओ के आधार पर इन क्षेत्रो में पूर्ति बढाए, यही बात नियोजन की औचित्यता की द्योतक होती है दूसरा कार्य यह करना पडता है कि मूल्य नीति या 'कोटा प्रणाली' से माँग को सीमित करे. इस प्रकार से पूर्ति बढा कर माँग कम करके माँग और पूर्ति मे समन्वय लाना आयोजन की द्वितीय अवस्था होती है

(iii) आयोजन की तृतीय अवस्था मे लक्ष्यो को निर्धारित करना पडता है. "लक्ष्य" वह आँकडा है जिसे अपेक्षित कार्य द्वारा प्राप्त करना पडता है इन लक्ष्यो को काल्पनिक नही होना चाहिए वरन् उन्हें वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए अगर लक्ष्य "हवाई लक्ष्य" हुए तो सम्पूर्ण योजना ही अवास्तविक हो जाएगी इससे साधनो का त्रुटिपूर्ण आवटन हो जाएगा. उसी तरह लक्ष्यो को बहुत नीचा रखने की प्रवृति, जिससे बाद मे लक्ष्यो से अधिक कार्य करना सिद्ध हो सके, भी गलत प्रवृति है

"Overfulfilment is just as much a sign of bad planning as is underfulfilment."

योजना को लोचपूर्ण होना चाहिए. अगर योजना पचवर्षीय योजना है तो भी हर वर्ष योजना की प्रगति का मूल्याकन होना चाहिए

(iv) इस अवस्था मे सम्पूर्ण योजना देश के ससद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ससद मे इसकी आलोचना व सुधारो के अनुसार यथासभव सुधार किए जाना चाहिए यही बात योजना के जनतन्त्रीय होने का

Cf. : Ch. ix : Lewis : op cit. : p 107-114. How to Plan.

द्योतक होती है. ससद का अनुमोदन का अर्थ यह नही होता कि हर व्यक्ति की आलोचना को दूर किया जाए. अगर ऐसा किया गया तो योजना को कभी पूरा नही किया जा सकेगा. फिर भी यथासभव सशोधनो को अपनाने के लिए तैय्यार रहना चाहिए.

(v) पाँचवी अवस्था, योजना को कार्यान्वित करने की अवस्था होती है. इस कार्य को पूरी लगन से करना होगा. भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता व व अयोग्यता को कोई स्थान नही मिलना चाहिए यह नही होगा तो फिर आयोजन सफल नही हो सकता, नेताओ को केवल भाषाबाजी नही करना वरना योजना को कार्यान्वित करने के कार्य पर उचित मार्गदर्शन व नियत्रण रखना चाहिए

"Governments frequently take action to reduce demand but are not good at taking action to increase supply. The leaders try to plan by exhortations, making speeches urging people to produce more but in fact have no plans, whether of inducement or of direction, to shift resources into the right places. They are then surprised and hurt at the end of the year, when their plans have not been fulfilled, and they make still more speeches. Planning by exhortation is not planning."

VIII. Defects, Limitations and Difficulties in Planning Programmes of Under-developed Countries कम-विकसित देशो मे नियोजन कार्यक्रमो मे कमियाँ, सीमाए तथा कठिनाइयाँ :

आज हर देश मे नियोजन किया जाता है. समाजवादी देश तो पूरी तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था मे रहते है परन्तु स्वय Stalin (स्टालिन), जो रूस के प्रधानमत्री रहे थे, लिखा है

"नियोजन के महत्व व योगदान को कम बताना गलत होगा, परन्तु उसको आवश्यकता मे अधिक महत्व देना भी गलत होगा हम ऐसी अवस्था को कभी नही पहुँच सकते जबकि हम हर चीज को नियन्त्रित

या नियोजित कर सकें. हमको यह नही भूलना चाहिए कि अगर कुछ क्षेत्रो में नियोजन हो सकता है तो कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ नियोजन सभव नही है"

U N O ने भी कम-विकसित देशो मे आयोजन की कठिनाइयो व कमियो पर विचार किया है

आँकडो व आवश्यक सूचनाओ की कमी :

कम-विकसित देशो मे अभी भी साख्यकीय विभाग विकसित नही हुए है, आँकडे या तो पर्याप्त मात्रा मे इकट्ठे नही किये जाते या फिर कुछ ही क्षेत्रो या घटको से इस सबध मे इकट्ठे किए जाते हैं. कुछ देशो में तो बहुत आवश्यक क्षेत्रो (जैसे जनसख्या, बचतों व पूंजी उपज अनुपातो) के आकडे भी ठीक मात्रा मे व सही किस्म के नही होते हैं. इस प्रकार से बगैर पर्याप्त अनुसधान, अध्ययन, मूल्याकन के आयोजन भी सफल नही होते.

पूंजी-निर्माण की कमी :

हम पढ ही चुके हैं कि कम-विकसित देशो मे बहुत स कारणो से बचतो की कमी रहती है और बचतों के दुरुपयोग से पूंजी-निर्माण कम रहता है जो पूंजी होती है उससे स्थिर व चक्र पूंजी दोनो की आवश्यकता पूरी नही होती. इन देशो मे मशीनो का रख रखाव (Maintenance) भी उचित नही होता

इधर सार्वजनिक वित्त प्रबन्धन भी ठीक नही रहता करो से आय कम प्राप्त होती है करो का वचन अधिक होता है कही-कही राज्य को करनीतियाँ निजी क्षेत्र के विकास में भी बाधक हो जाते है.

उन्नत तकनीक की कमी :

कम-विकसित देशो मे जनसख्या की अधिकता, पूजी की कमी, शिक्षा के निम्नस्तर तथा कुशल व्यक्तियों की कमी के कारण नियोजन की सारी योजनाएँ सफलता-पूर्वक कार्यान्वित नही हो पाती है. नियोजन की लागत बढ जाती है

प्राथमिकताओं का उचित न होना : विनियोजन का त्रुटिपूर्ण आबंटन :

कम-विकसित देशो म बहुधा सार्वजनिक कार्यो को आवश्यकता से अधिक महत्व मिल जाता है और कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि को उतना महत्व नही मिल पाता. सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोजन से कभी निजी क्षेत्र के विनियोजन को

Stalin : Leninism, p 11.

U N, Seminar on Formulation & Execution of Development Programmes held in Puerto Rico in 1950.

सहायता देने के स्थान पर बाधा उत्पन्न हो जाती है सार्वजनिक उद्योग पूँजी-निर्माण के साधन के स्थान पर पूजी-उपभोग के कारण बन कर रह जाते हैं. और फिर मुद्रा स्फीति या अधिकाधिक कर लगाने के कारण बन जाते हैं.

दोषपूर्ण शासन व्यवस्था :

आज कम-विकसित देशो के शासन अत्यन्त दोषपूर्ण हैं बहुत से कम-विकसित देशों ने साम्राज्यवादियो के शासन से स्वतन्त्रता तो प्राप्त कर ली परन्तु सक्षम, भ्रष्टाचार रहित व उत्साही प्रशासन देने मे असफल रहे. बहुत से कम विकसित देशों में बहुधा "तख्ते पलट" किए जाते हैं भारत मे भी उदाहरणतया राज्य सरकारो मे पार्टी परिवर्तनो के कारण राज्य शासनो मे अस्थिरता बनी रहती हैं विधानसभा के सदस्य राजनीति म ही उलझे रहते है. आर्थिक नीतियो के निर्धारित करने व उन्हे कार्यान्वित करने की फुरसत ही नही रहती. आज कम विकसित देशो मे सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजनीतिज्ञो द्वारा ही पनपाया जाता है नियोजन के लिए जो धन इकट्ठा होता है उसका बहुत बडा भाग भ्रष्ट राजनीतिज्ञो, प्रशासको व ठेकेदारो के पास चला जाता हैं. जनता का कल्याण कम हो पाता है.

राज्य के आयोजन के कार्य कागजों पर अधिक होते रहते हैं. नियोजन की सफलता के लिए उत्साही जनता व ईमानदार शासक चाहिए. जापान मे यही था इसी कारण वहाँ नियोजन सफल हो सका है

जन सहयोग की कमी :

कम विकसित देशो मे जनसहयोग की कमी से भी आयोजन असफल हो जाता है हर देश मे आयोजन के शुरू मे जनता का सहयोग रहा है. भारत मे भी 'श्रम दान" द्वारा बहुत कुछ कार्य हुए. कालान्तर मे जब आम जनता उम्मीद के अनु-

---

Select Bibliography·

Apart from the books mentioned in previous chapters, following books and articles were consulted

Books·

1. E F M Durbin · *Problems of Economic Planning*
2. Maurice Dobb An Essay on Economic Growth and Planning.
3 Herman Finer · Road to Reaction.
4. Ragner Frisch : *Planning for India : Selected Exploration in Methodology*
5. S. E Harris · Economic Planning.
6 P von Hayek . The Collectivist Economic Planning

सार लाभान्वित नही होती और अन्य लोगों को भ्रष्टाचार से लाभान्वित होते देखती है तो वह सहयोग के स्थान पर असहयोग करने लगती है. अगर आयोजन मे बेरोज्गारी, निम्न आय की समस्या को 15 20 वर्षो के आयोजन से कम न किया गया तो निश्चित ही जनता असहयोग करती है आज भारत मे भी इतनी बेरोजगारी व गरीबी है कि हर छोटी से छोटी समस्या के कारण फालतू व्यक्ति लूटपाट, आगजनी आदि करने के लिए मिल जाते है.

बहुत लम्बी अवधि का आयोजन तथा अल्पकालिक समस्याओ की अवहेलना :
आज कम-विकसित देशो के नियोजक, परम्परागत अर्थशास्त्रियो की भांति "दीर्घ-काल मे सब ठीक हो जायेगा" की बात करते है. कुछ वर्षो तक जनसाधारण इस उम्मीद मे रहता है कि नियोजन से उसे लाभ होगा. परन्तु अगर बहुत दीर्घ-कालिक नियोजन हुआ तो वह सफल नही होता राज्य का जीवन असीमित है

7. Indian Planning Commission . Various Five year Plans.
8. Oskar Lange : Essays on Economic Planning.
9. W. A Lewis . *The Principles of Economic Planning.*
10 Ludwig von Mises : Planning for Freedom
11 Lionel Robbins : Economic Planning & International Order.
12. Ferdynand Zweig : The Planning of Free Societies.
13. W. Birmingham & A G Ford . Planning and Growth in Rich *and Poor Countries.*
14. Charles Bettelheim : Studies in the Theory of Planning.
15. S. S. Wadia : Techniques on Planning.
16. Zinkin : Growth, Change and Planning.
17. Maurice Dobb : Economic Growth and Planning.

Papers :

18. Edward S Mason Some Aspects of the Strategy of Development Planning : Centralization vrs Decentralization.
19. Gernard Colm and Theodore Geiger : Public Planning and Private Decision-making in Economic and Social Development.
20. *Max F. Millikan : Criteria for Decision-making in Economic* Planning—The Planning Process.
21 Howard S. Ellis : National Development Planning and Regional Economic Integration.
22. Harvey S. Perloff and Raul Saer : National Planning and *Multinational Planning under the Alliance for Progress.*

परन्तु जनता का Time Horizon (समय सीमा) सीमित होती है. नियोजन को इस काल मे ही परिणाम प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा नियोजन सफल नही हो सकता.

आवश्यकता से अधिक नियंत्रण :

Planning fails because of the too little or too much action कम-विकसित देशो मे कही-कही राज्यो का हर क्षेत्र मे बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है. बहुत अधिक हस्तक्षेप से भी आयोजन असफल होता है. माग और पूर्ति के नियम तो नियोजित अर्थव्यवस्था मे भी लागू होते हैं इसलिए पूर्ण रूप से मूल्य नियंत्रण भी उचित नही होगे. नियोजन मे भी बाजार व्यवस्था का ध्यान रखना होगा. पर इसका अर्थ यह नही है कि मुद्रा स्फीति फैलने दी जाए. बहुधा मुद्रा स्फीति ही नियोजन की असफलता का मुख्य कारण बन जाती है.

---

23 P. N Rosenstein-Rodan Determining the need for and Planning the use of External Resources.

24 Hollis B Chenery : A Model of Development Alternatives.

25. Gustav F Papanek and Moeen A Qureshi . The use of Accounting Prices in Planning

26 Kenneth R Hansen : Planning as a Continuing Process.

27. Stephen K Bailey : The Place and Functioning of a Planning Agency within the Government Organization of Developing Countries

All United States papers prepared for the United Nations Conference on the Application of Science and Technology for the benefit of the less developed areas.

28. Richard S Eckaus : Appendix on Development Planning in Kindleberger's op cit

Books :

29. Edward Heimann : Types and Potentialities of Economic Planning

30. A. B. Bhattacharya : Theory and Practice of Planning.

31. B. G. Gupta : Economics of Planning.

अध्याय 13

विदेशी सहायता व आर्थिक विकास

Foreign Aid and Economic Development

I प्रस्तावना

विदेशी सहायता का अर्थ

II कम-विकसित देशो को विकसित दशो से मिलने वाली सहायता का आकार व प्रकार भिन्न भिन्न सस्थाओ व देशो का योगदान

III भारत का विकास व विदेशी सहायता

विश्व बैंक व सहायक सस्थाएं, U S A , U S S R का योगदान :

IV. कम-विकसित देशो के लिए आवश्यक सहायता के अनुमान

V. कम विकसित देशो के लिए विदेशी सहायता सबधी नीति के आवश्यक तत्व

(a) अधिकाधिक अनुदान आवश्यक

(b) Soft loans या कम विकसित देशो की मुद्रा में चुकाए जानेवाल ऋण अधिक हो

(c) तक्नीकी सहायता मिलना चाहिए

(d) Hard loans की शर्तें आसान हो

(e) Special or project loans तथा General loans का समन्वय

(f) अन्य प्रमुख बातें

आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का महत्व व सीमाएँ : विदेशी सहायता व तीन क्षमताऐं

अध्याय : 13

विदेशी सहायता तथा आर्थिक विकास

Foreign Aid and Economic Development

I. प्रस्तावना .

विदेशी 'सहायता" का अर्थ :

समान्यतया "सहायता" से हमारा आशय अनुदान से होता है. इस प्रकार से विदेशों से मिलनेवाला अनुदान (grant) ही वास्तव मे "सहायता" हुई, परन्तु व्यवहार मे विदेशो से मिलने वाले अनुदान, नरम ऋण (soft loans), व्यापारिक ऋण, विदेशी पूँजी आदि सब को "सहायता" के अन्तर्गत शामिल कर लेते हैं.

सर राय हरोड (Sir Rov Harrod) के अनुसार :

> "अगर विदेशी ऋण-दाता अपने द्वारा दिए जानेवाले ऋण पर सामान्य लाभ कमाता है तो हम इसे "सहायता" नही कह सकते. "सहायता" के अन्तर्गत तो हम केवल अनुदान (grants) तथा "नरम ऋण" (soft loans)[1] को ही शामिल कर सकते है.
>
> इसलिये विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण भी "सहायता" नही कहे जा सकते, क्योंकि विश्व बैंक उतनी ही दर से ब्याज लेता है जितना कि उसे अपनी सरकार को ऋण देने पर ब्याज मिलता है. यह दर भले ही उस ब्याज की दर से कम हो जो कि बाजार मे प्रचलित है पर इतनी कम नही कि इसके ऋणों को 'सहायता' कहा जा सके. *'सहायता' का अर्थ है कि देनेवाले व्यक्ति ने कुछ त्याग किया है.* इस प्रकार के ऋणो मे किसने त्याग किया है"

1. Soft Loans वे है जिनकी अदायगी कम विकसित देश अपनी ही मुद्रा में करते हैं.

Cf : Sir Roy Harrod : "Aid to the Less-developed Countries" Commerce, Annual Number, Dec. 1965.

लेखक सर राय हरोड की परिभाषा से सहमत है, परन्तु विकास व "सहायता" के सह-सबंध को अध्ययन करने के लिए अनुदान, नरम ऋण, विदेशी मुद्रा ऋण, तकनीकी सहायता व वस्तुगत सहायता सब को 'सहायता'' मान लिया है

II कम-विकसित देशों को विकसित देशों से मिलने वाली सहायता का आकार व प्रकार

विकसित देश कम-विकसित देशों को आज पहले से बहुत अधिक सहायता दे रहे है. जहाँ 1950's के काल (mid-50's) मे कम-विकसित देश 2.5 billion dollars की सहायता प्राप्त करते थे. मध्य 1960 मे यह सहायता 5 5 billion dollars हो गई. आज भी सहायता की मात्रा बढ़ती ही जा रही है. विदेशी विनिमय का यह सबसे सुनिश्चित साधन है. जहाँ 1954 में विदेशी सहायता निर्यात का 3% थी वहाँ अब निर्यात का 20% हो गई है जहाँ विदेशी सहायता पहले कम-विकसित देशो की केवल 1% राष्ट्रीय आय के बराबर योगदान करती थी वहाँ वह अब लगभग 3% से अधिक है. आजकल विदेशी सहायता की मात्रा मे हर वर्ष लगभग 15% वृद्धि हो रही है.[1]

जहाँ ये आँकडे बढती हुई सहायता की बात बतलाते है वहाँ यह सहायता बहुत ही अपर्याप्त है. U.N.O. की E/3131 रिपोर्ट जो 1958 मे 26 वे सम्मेलन मे प्रस्तुत की गई, उसम निम्नलिखित आकडे दिये गये है.

(a) 1956 57 मे वे 20 देश जिनमे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $ 100 से कम थी उनको कुल $ 1004 million की सहायता मिली थी यह वितरण इस प्रकार था

$ 336	Million	द० कोरिया
$ 246	,,	द० वियतनाम
$ 41	,,	कम्बोडिया
$ 49	,,	लाओस
$ 34	,,	लीबिया

1. For estimates

See : 1. H.W. Singer : op. cit , p 32-33

2 Frederick Benham
3 Gatt . estimates
4. U N O. estimates
5. I.B R D , I M.F. Bulletins

(2–5: all references at the end of the chapter)

6. मुद्रा, बैंकिंग .. सांख्यकीय मेहता, श्रीवास्तव, गुप्ता.

अन्य 15 देशो मे बाकी का 400 million डालर दिया गया. इन 15 देशो मे 67 करोड जनसख्या का निवास था और इस प्रकार प्रति व्यक्ति केवल 60 सेंट सहायता प्राप्त हुई. भारत को तो यह सहायता केवल 10 सेंट प्रति व्यक्ति ही थी.

(b) अन्य 18 देश जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 100 तथा 200 डालर के बीच थी, को कुल 464 billion dollars सहायता के रूप मे दिए गये जिसका वितरण यह था.

ताइवान (फारमोसा)	\$ 111	million.
बोलिविया	\$ 24	,,
गोटेमाला	\$ 26	,,
मोरक्को	\$ 79	,,
ट्यूनिशिया	\$ 50	,,
अन्य 13	\$ 174	,,

इन अन्य 13 देशो मे प्रति व्यक्ति 1 डालर मिला (इनकी जनसख्या 175 m थी)

(c) प्रति व्यक्ति सहायता की मात्रा बहुत कम है सब मिलाकर अभी भी सब देशो को 1 डालर प्रति व्यक्ति से भी कम प्राप्त होता है. कुछ देश जो सामरिक दृष्टि से पश्चिमी देशों के गुट में हैं, उन्हें अवश्य अधिक सहायता मिलती है. निम्नलिखित तालिकाएँ इस स्थिति पर प्रकाश डालती है. यह सहायता 1954-56 के काल की है

तालिका I

Group A	100 डालर प्रति-व्यक्ति प्रति-वर्ष GNP (Gross National Product) से कम वाले देश		
	देश	प्रति-व्यक्ति सहायता	
1	बर्मा	·9	डालर
2.	भारत	·6	,,
3.	इन्डोनेशिया	·5	,,
4.	पाकिस्तान	3 8	,,
5.	थाइलैंड	2·0	,,
6.	द० कोरिया	31·4	,,

तालिका II

Group B : $ 100–200 डालर प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष GNP वाले देश	
देश	प्रति-व्यक्ति सहायता
1. लका	2·1 डालर
2 मिस्र	2 1 ,,
3. लीबिया	54·8 ,,
4. परागुए	3 8 ,,

तालिका III

Group C : $ 200–300 डालर प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष GNP वाले देश	
देश	प्रति व्यक्ति सहायता
1 एल सेलवाडोर	4·0 डालर
2. मेक्सिको	2·7 ,,
3. फिलीपीन्स	2 0 ,,
4. इजराइल	83·0 ,,

उपरोक्त तालिकाओं में इजराइल, लीबिया व द. कोरिया को अधिक सहायता प्राप्त करते हुये दिखाया गया है. ये देश पश्चिमी देशों के अधिक निकट होने के कारण सहायता प्राप्त करते हैं

इतने अध्ययन के बाद हम देख सकते हैं कि कम-विकसित देशो को अभी पर्याप्त मात्रा मे सहायता नही मिल रही है. U. N. O. के वर्तमान महासचिव श्री ऊ थाँ (U Thant) ने समस्त विकसित राष्ट्रो से अपील की है कि वे अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 1% कम-विकसित देशो को सहायता के रूप मे दें. परन्तु यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नही किया गया है. वास्तव मे इस प्रतिशत तक पहुँचने के बजाय और दूर हो रहे है. 1961 मे विकसित देशो ने अपनी राष्ट्रीय आय का केवल ·8% सहायता के रूप में दिया और 1965 में यह प्रतिशत गिर कर केवल ·6% रह गया. इसके अतिरिक्त जितनी सहायता का वायदा किया जाता है उसका केवल 60–65% ही दिया जाता है.[1]

1. See : Patriot : Sept. 27, 1966.

एक बात ध्यान देने योग्य है कि विकसित देशो की राष्ट्रीय आय बढ रही है इस लिए अगर सहायता का प्रतिशत उतना ही रहे तो भी निर्पेक्ष रूप मे सहायता की मात्रा तो अधिक हो जाती है. परन्तु इस लाभ के विपरीत कम-विकसित देशो की मूल्य वृद्धि के कारण इस सहायता का वास्तविक मूल्य भी कम हो जाता है. यह मात्रा निश्चित ही बढाया जाना चाहिए. विकसित देश जितना युद्ध की तैयारी व हथियारो की होड मे खर्च कर देते है यह तो उसका केवल 5% ही है, और अभी भी सहायता की शर्तें बहुधा उतनी उदार नही रहती जितनी होना चाहिए.

विश्व बैंक तथा सहायक संस्थाओ द्वारा सहायता[1]

विश्व बैंक की स्थापना वैसे तो युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुन निर्माण के लिए हुई थी परन्तु कालान्तर से यह कम-विकसित देशो को दीर्घकालीन पूँजी की सहायता देने लगा या दिलवाने लगा यह अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन को भी प्रोत्साहित कराता है, निजी विदेशी विनियोजको को "गारन्टी प्रदान" कर या उसमे हिस्सा बटाकर भी सहायता करता है. यह बैंक उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण देता है और कम-विकसित देशो को उनके साधनो के विकास मे सहायता देकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और भुगतान सतुलन की स्थापना मे सहायता करता है. बहुधा यह बैंक 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देता है. बैंक खर्चे पर नियत्रण रखता है तथा आवश्यकता अनुसार ऋण की अदायगी करता है. बैंक कम-विकसित देशो को आयोजन व वित्तीय साधन जुटाने मे भी सलाह देकर सहायता करता है तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराता है तथा प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करता है. कुछ देशो को सहायता के लिए विशेष "सहायता क्लब" जैसे Aid India club व Aid Pakistan club बनाए है. साधनो के सर्वेक्षण मे भी मदद करता है. इससे लिए गए ऋणो व ब्याज का भुगतान विदेशी मुद्रा मे ही किया जाता है.

शुरू मे विश्व बैंक बहुत कम ऋण देता था परन्तु अब वह प्रति वर्ष $ 600 से $ 700 Million तक ऋण उधार देता है. 1965 में बैंक के द्वारा दिए गए बकाया ऋणो की मात्रा $ 6 Billion थी 1967 के मार्च के अन्त तक बैंक व उनकी सहायक सस्थाओ ने 40 मुद्राओ में 8 Billion डालर के 500 से अधिक ऋण प्रदान किए थे

1. विश्व बैंक पर श्री आर. पी. गुप्ता द्वारा लिखित अध्याय 7 व 8, "बैंकिंग मुद्रा ··· ·· 'साख्यकीय", लेखक मेहता, श्रीवास्तव व गुप्ता : कैलाश पुस्तक सदन.

निम्नलिखित तालिका 30 जून 1965 तक दिए गए ऋणों का विवरण देती है :

क्षेत्र	राशि की मात्रा करोड डालर मे	कुल का प्रतिशत
1. एशिया तथा मध्यपूर्व	309·2	34
2 दक्षिणी और मध्य अमेरिका	220·8	25
3. यूरोप	199 1	23
4 अफ्रीका	110 4	13
5 आस्ट्रेलिया	45 7	5
	877·2	100%

विश्व वैक ने सन् 1966 म ~90 1 करोड डालर के ऋण प्रदान किए है और सन् 1967 के प्रथम तीन माह म 14 47 करोड डालर के ऋण प्रदान किए है.

I. F C व I. D A.

International Development Agency. (I. D. A.) तथा International Finance Corporation (I. F. C.) दोनो विश्व वैक की सहायक सस्था के रूप मे स्थापित की गई I. F. C की स्थापना जुलाई 1950 में हुई और I D A की अक्टोबर 1959 मे हुई. I F. C. निजी क्षेत्रो की औद्योगिक योजनाओ को "इक्विटी पूँजी" तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है. विश्व वैक की भाँति यह सस्था भी तब ऋण प्रदान करती है. जब अन्य क्षेत्रो से ऋण मिलने की सम्भावना नही रहती है तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है व प्रदान कराता है. प्राय 5 से 15 वर्ष तक के लिए निगम सहायता करता है. I. F C ने 1967 तक 20 करोड डालर से अधिक ऋण, मुख्यतया लेटिन अमरीकी देशो को प्रदान किए, परन्तु हाल में ही यह एशिया व अफ्रीका में भी दिलचस्पी लेने लगा है. यह निगम कम-विकसित देशो मे वित्त निगमो को स्थापित करने मे सहायता देता है और ये वित्त निगम फिर इन देशो मे निजी क्षेत्र के विकास मे सहायक होते है और इन देशों में पूँजी बाज़ार का विकास होता है अब 1966 के बाद विश्व वैक ने इसे और 40 करोड डालर दिए है जिससे इसकी

See also · Kindleberger, op cit, p 337.
Norman G. Jones : "Disbursing Bank Loans", Finance and Development, March 1967. p. 55.
David Grenler, I F.C , An Expanded Role for Venture Capital, Finance and Development, June 1967, p. 139.

क्रियाओ मे और विकास हुआ है. इसके द्वारा सहायता किए गए उद्योग लगभग औसतन् 12·15% लाभ प्रतिवर्ष कमा रहे है वित्त निगम के द्वारा 21 देशो मे 25 वित्त कम्पनियो को अब तक 56 करोड डालर का ऋण प्रदान कर उनके विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है

I D. A. मुख्यतया सामाजिक-आर्थिक सिरोपरि व्यय के विनियोजन (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का विकास) करता है I.D.A. की ब्याज की दरें भी नीची होती है तथा ऋण भी काफी दीर्घकाल के लिए होते है. विकास सघ द्वारा अब तक प्रदत्त ऋणो के चुकाने की अवधि 50 वर्ष है और ऋण आसान किश्तो मे चुकाए जाते है एव प्रथम किश्त ऋण प्राप्त करने के 10 वर्ष पश्चात् शुरू होती है. विश्व बैंक के ऋणो की भाँति I.D A. भी बहुत जाँच पडताल के बाद ऋण प्रदान करती है विकास सघ द्वारा कार्य 8 नवम्बर 1961 को शुरू किया गया अपने कार्य-काल के प्रथम चार वर्षों में विकास सघ द्वारा 70 योजनाओ के लिए 100 करोड डालर से भी अधिक ऋण प्रदान किया है. सन् 1966 के वर्ष में 47·55 करोड डालर के ऋण और प्रदान किए गये. विकास सघ ने रेलवे, सिंचाई, बन्दरगाहो के विकासार्थ, कृषि विकास आदि कार्यों के लिए ऋण प्रदान किए है. विकास सघ ने अप्रैल 1966 से मार्च 1967 के बीच निम्नलिखित ऋण दिए .

भारत	रेलो के लिए	6 8	करोड	डालर
भारत	औद्योगिक आयात	6 5	,,	,,
भारत	विद्युत	2 5	,,	,,
पाकिस्तान	औद्योगिक आयात	2·5	,,	,,
पाकिस्तान	शिक्षा	1·3	,,	,,
केमरून	कृषि	1 1	,,	,,
पेरेग्वे	पशुपालन	0 75	,,	,,
ट्यूनिशिया	कृषि	0 6	,,	,,
अन्य		3·1	,,	,,
		24·95	,,	,,

U.N O की आमसभा ने U.N.O. के अन्तर्गत एक विशेष कोष Special U.N Fund for Economic Development (SUNFED) बनाया जिसके लिए भिन्न-भिन्न देशो से उनकी योग्यतानुसार धन इकट्ठा करके कम-विकसित देशो मे उनकी गरीबी के अनुसार, अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की.

U. S. A. इस SUNFED को सबसे प्रमुख अनुदान देनेवाला बनता परन्तु उसने इसका घोर विरोध किया. फिर केवल 100 m. डालर से एक U. N Special Fund की ही स्थापना हो सकी इससे विशेष तकनीकी सहायता व सर्वेक्षण के लिए ऋण दिया जाता है.

III. भारत का विकास व विदेशी सहायता :

ऋण :

भारत को मार्च 1, 1969 के दिन 1877·42 करोड रु० (P. L. 480 के ऋणो को छोडकर) की सहायता आ रही थी. (Was in the pipeline) 28, February 1969 तक भिन्न-भिन्न देशो से (जिनमे विश्वबैंक व उसकी सहायक सस्थाओ के ऋण शामिल हैं) 7788·18 करोड रुपयो की सहायता के समझौते हो चुके थे. इसमे से 6484 35 करोड रुपयो के ऋण विदेशी मुद्रा मे चुकाए जाएँगे तथा 1303 83 करोड के ऋण U. S. S. R. व अन्य साम्यवादी देशो के हैं जिन्हे सामान्यतया निर्यात से चुकाया जाएगा

P L 480 के ऋण, जो अबतक 1423 87 करोड रुपयो के हो चुके हैं, तथा अन्य रुपयो के ऋणो को, जो 509 करोड रुपयो के हैं, मिलाकर 28 फरवरी 1969 तक 9721 38 करोड के विदेशी ऋण हो गए हैं

इन 7788 18 करोड रुपयो के ऋणो के लिए 6484·43 करोड के सामान मगाने के लिए आर्डर जा चुके हैं अभी तक 5910·76 करोड का पूर्ण प्रयोग हो चुका है और केवल 1877 42 करोड का प्रयोग और होना है.

Rupee loan या रुपयो मे विदेशी ऋण (1933 20 करोड) मे से 1715 ·69 करोड रुपयो के ऋणो का पूर्ण प्रयोग हो चुका है और केवल 217·51 करोड रुपयो के ऋण का प्रयोग बाकी है. इस प्रकार विदेशी ऋणो मे से अभी 2094 93 करोड का प्रयोग बाकी है. (1877·42+217·51)

See :

1. Free Press Journal : 18th July 1969.
2. The Financial Express ; 28th July 1969.
3. India's Fourth Five Year Plan, 1969-74:. p. 91-95. draft.
4. Foreign Aid & India's Economic Development. VKRV Rao and Dharam Narain.
5. Free Press Journal : 14th Feb. 1969, for America's Economic Aid to India.

28 फरवरी 1969 तक विदेशी मुद्रा ऋण में से 1060 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में तथा 630 करोड़ व्याज के रूप में चुकाए जा चुके हैं और अब 4850 करोड़ रुपये के ऋण विदेशी मुद्रा में और 1225 करोड़ के ऋण रुपयों में वापस करना है.

सहायता अनुदान :

भारत को 1969 फरवरी तक 1108 करोड़ रुपये दान के रूप में प्राप्त हुए जिसमें से 1028 करोड़ रुपया का प्रयोग कर लिया गया है और 80 करोड़ रुपये के बराबर का अनुदान और प्रयोग करना है.

चतुर्थ योजना :

भारत की चतुर्थ पच-वर्षीय योजना (1969-74) के लिए 10050 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी जिसको निर्यात-आय व विदेशी सहायता से प्राप्त किया जाएगा इसके अतिरिक्त 2280 करोड़ रुपये के विदेशी ऋणों के मूलधन व ब्याज का व्यय होगा इसमें से 1750 करोड़ रुपये ही (ऋण भुगतान के अतिरिक्त) विदेशी सहायता के रूप में आवश्यक होंगे. भारत की तृतीय योजना में 3500 करोड़ रु० की विदेशी सहायता प्राप्त हुई. और तीन वार्षिक योजनाओं के काल में भी (1966-1969) इसी योजना काल के औसत के अनुसार सहायता प्राप्त हुई चतुर्थ पच-वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में अधिक मात्रा में व सुनिश्चित रूप से सहायता की आवश्यकता होगी इस 1750 करोड़ की सहायता के सबध में चतुर्थ योजना में लिखा है

> 'This will be available only if the gross aid utilisation in the economy is of the order of Rs 4030 crores comprising PL 480 food aid of Rs. 380 crores and the project and non project aid of Rs 3650 crores."

विश्वबैंक व सहायक सस्थाओं द्वारा ऋण व सहायता :

भारत को विश्व बैंक से तीनों योजनाओं के काल में 462 81 करोड़ रुपयों के ऋण प्राप्त हुए और 379 97 करोड़ के ऋण प्रयोग कर लिए गए थे. उस समय इस प्रकार से 82·84 करोड़ रुपयों के ऋण बकाया थे. विश्व बैंक के 34 ऋणों

See . Ch. 21 on Public Finance written by Dr. O. S. Shrivastava in "मुद्रा . साख्यिकीय" मेहता, श्रीवास्तव, गुप्ता. Eastern Economist, Annual No., 1968.

मे से 13 यातायात, 12 उद्योग, 7 शक्ति विकास, 1 कृषि, 1 बहुमुखी योजना के लिए दिया गया. Aid India club से भारत को तृतीय योजना काल में 540 करोड रु० से ऊपर सहायता प्राप्त हुई I F. C. से भारत को पिछले तीन वर्षों मे 70 लाख डालर ऋण प्राप्त हुए. I. D. A. से जो ऋण प्राप्त हुए है वे इस प्रकार रहे है

स्वीकृति का दिनाक माह सन्	ऋण का उद्देश्य योजनाएं	ऋण की मात्रा लाख डालरो में
जून 1961	सडक निर्माण तथा सुधार	600
सितम्बर 1961	ट्यूबवेल का निर्माण	60
मार्च 1962	बाढ नियन्त्रण	100
जून 1962	सोन नदी सिंचाई	150
जुलाई 1962	पूरना नदी घाटी	130
अगस्त 1962	कोयला विद्युत शक्ति	171
सितम्बर 1962	सवाद वहन	420
सितम्बर 1962	बम्बई बन्दरगाह सुधार हेतु	180
मार्च 1963	भारतीय रेलो का विस्तार	675
मई 1963	काठगोदाम विकास विद्युत शक्ति	200
जून 1964	व्यावसायिक वाहन, औद्योगिक मशीन तथा निर्माण उपकरण	900
अक्टूबर 1964	सवाद वहन का विस्तार	330
दिसम्बर 1964	भारतीय रेलो का विकास	620
मई 1966	भारतीय रेलें	680
जून 1966	विद्युत शक्ति	230
फरवरी 1967	औद्योगिक आयात	550

I. D A. ने भारत को सर्वाधिक ऋण दिए है

See Also :

John Mc Diarmid : "International Action for Economic and Social Progress" Indian Finance, 11 November 1967.

U S A द्वारा भारत को सहायता

भारत को सबसे अधिक आर्थिक सहायता U S A से प्राप्त हुई है परन्तु भारत उसका उतना आभार मानता नजर नही आता जितना कि वह सोवियत यूनियन का भारत को U S A न सवप्रथम 1951 म आर्थिव सहायता दी उसके बाद जनवरी 1969 तक उसने 8994 1 million dollars (6745 58 करोड रुपये) की सहायता दी है निम्नलिखित तालिका इसको दर्शाती है

		करोड रु० म
1	USAID Mission Technical Cooperation Programme	
	(a) अनुदान	310 58
	(b) ऋण रुपयो या डालर म वापस करन वाल	115 58
2	USAID development loans (विकास ऋण)	
	(a) डालर में जिनका भुगतान होना ह	1770 90
	(b) रुपयों म जिनका भुगतान करना है	396 53
3	P L 480–Title I (अनुदान व रुपया म चुकाए जान वाल ऋण)	2365 40
4	P L 480–Title II अनुदान	370 65
5	बाढ व दुर्भिक्ष दान	4 13
6	U S Export Import Bank loans (डालर म वापस करना ह)	343 70
7	1951 का गहूँ ऋण (डालर म ऋण)	142 28
		6745 58

U S A न जो कुछ दिया उसका

19 5% अनुदान है

45 3% रुपयो म वापस करना है

33 4% डालर म वापस करना है

1 8% डालर या रुपयों म (U S A की मर्जी पर) वापस करना है

100 00%

See Free Press Journal Feb 14 1969

U. S. A. की सहायता तीन सस्थाओ द्वारा प्राप्त होती है ये तीन सस्थाएँ है

(i) United States Agency for International Development (USAID)
(ii) P L. 480 (शान्ति के लिए खाद्य) तथा
(iii) U S. Export--Import Bank.

U. S A ने भारत को अभीतक 2715 विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई है *कृषि, उद्योग, यातायात, सचार, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रो मे महत्वपूर्ण* योगदान रहा है यह डालर ऋण 40 वर्ष की अवधि के है और प्रथम दस वर्षों मे कुछ भी वापस नही करना पड़ता है तथा ब्याज 2% लिया जाता है तत्पश्चात् ब्याज की दर 3% होती है. P. L 480 के अन्तर्गत खाद्य सहायता देकर अमेरिका ने न केवल देश को भुखमरी से बचाया है वरन् विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर किया और वह धन जो हम खाद्यान्न के आयात मे व्यय करते उसे विकास के कार्य मे ले सके (अब तक 57 m tons से ऊपर खाद्यान्न मिल चुके है) इस सहायता से भारत मे मुद्रा स्फीति व भुखमरी के सकट को टाला जा सका है या बहुत कम रखा जा सका है

U. S A की आर्थिक सहायता (केवल 1969 जनवरी तक) के महत्व को तो हम इस ही बात से समझ सकते हैं कि यह पूरी सहायता सम्पूर्ण द्वितीय योजना की धनराशी के बराबर है. इससे ही हम समझ सकते है कि अमेरिका का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है मोटे-मोटे रूप से U. S. A की सहायता का प्रयोग इस प्रकार हुआ है

46%	खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे माल के लिए
33%	उद्योग व शक्ति के लिए
13%	यातायात जिसमें 12% रेलो के विकास को
10%	कृषि, सिंचाई व सामुदायिक योजनाएँ, मत्स्य व जगल.
100%	

U S S. R की आर्थिक सहायता व कम विकसित देशो, विशेष रूप से भारत का विकास :

U. S. S. R. ने हाल मे कम-विकसित देशो के *आर्थिक विकास मे सहायता देना* शुरू किया है. इसकी सहायता अमरीका के अनुपात म तो बहुत कम है परन्तु फिर भी इसका योगदान महत्वपूर्ण है. U S. S. R. का दावा है कि जहाँ पश्चिमी देशो का सहायता देने का लक्ष्य कम-विकसित देशो को अपने अधीन या प्रभाव में

रखना है, वहाँ U. S. S. R. का लक्ष्य कम-विकसित देशों को कम से कम समय में आत्मनिर्भर करना है. लेनिन ने रूस की क्रान्ति से पहले ही कहा था

> "हम पिछड़े व दलित देशों की जनता को नि स्वार्थ सहायता देंगे. हम उन्हें मशीनों का प्रयोग, श्रम के भार को कम करना तथा समाजवादी प्रजातन्त्र सिखाएँगे "
>
> (Lenin : Collected Works, Vol 23., p. 67)

सोवियत यूनियन ने 1930's के काल मे टर्की को आर्थिक सहायता दी और वहाँ तथा अफगानिस्तान मे कपडा मिलों की स्थापना की. द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत यूनियन की सहायता बढ़ गयी. 1955 म सोवियत यूनियन के सहायता सम्बन्धी समझौते केवल दो देशो से थे—और ये देश थे भारत व अफगानिस्तान, परन्तु सोवियत यूनियन की क्रान्ति की 50 वी वर्षगाँठ के अवसर पर उसके अफ्रीका, एशिया व लेटिन अमरीका के 37 देशों से समझौते थे ये देश थे, भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, इन्डोनेशिया, इराक, इरान, यमन, कम्बोडिया, कुवैत, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान, सिगापुर, सीरिया, टर्की, लका, अलजीरिया, धाना, ग्याना, कमारून, केन्या, कान्गो, माली, मिश्र, सेनेगाल, सोमालिया, सूडान, तनज़ानिया, ट्यूनीशिया, युगान्डा, इथोयोपिया, मोरक्को, चिली व ब्राजील.

1967 के अन्त तक सोवियत यूनियन ने कम-विकसित देशों को 4000 million रूबल की सहायता दी थी. इससे 600 औद्योगिक सस्थान शुरू किए गये हैं. इनमे से 220 projects तो पूरे हो ही गए है 1956-66 के दस वर्षों मे सोवियत यूनियन का कम विकसित देशों से व्यापार छैः गुना बढ गया है. सोवियत यूनियन साथ में तकनीकी व सर्वेक्षण की सहायता भी देता है, तथा उसके द्वारा स्थापित उद्योगों को सचालित करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है

इस अध्याय में सोवियत यूनियन द्वारा अन्य साम्यवादी देशों को सहायता इसमे शामिल नही है.

See particularly :

1. Bolshakov : Soviet-Indian Economic Cooperation, Soviet Land Books, 1968.
2. Arts & Letters, Daryaganj, Delhi-6, "Indo-Soviet Economic Collaboration " 1955-1965 and other issues of 'News & Views from Soviet Union.'
3. M. Sundar Rajan : Soviet aid and Indo-Soviet Trade - Yojna, June 12, 1966 & many other news items

सोवियत यूनियन द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज कम लिया जाता है और उसकी अदायगी वह आयात के रूप में ले लेता है इससे कम-विकसित देशो को ऋणों को वापिस करने मे आसानी रहती है वह कम-विकसित देशो में इन उद्योगो के लाभ में से भी कोई हिस्सा नही लेता. जो सहायता दी जाती है उसका मुख्य भाग उद्योग स्थापित करने मे काम लिया जाता है.

भारत व सोवियत यूनियन :

भारत व सोवियत यूनियन के बीच सर्वप्रथम सहायता सम्बन्धी समझौता 1955 में हुआ, जिसके अन्तर्गत भिलाई स्पात कारखाना स्थापित करने का समझौता हुआ तत्पश्चात् आज 41 projects या योजनाओं में सोवियत यूनियन का योगदान प्राप्त हो रहा है. सोवियत यूनियन से भारत को 1227 million रूबल की सहायता मिली जो कि 1022 करोड़ रुपयों के बराबर है.

41 औद्योगिक projects में से 22 अभीतक पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य करने लगे है. इनमें प्रमुख भिलाई स्पात कारखाना, राँची का भारी इन्जीनियरी के सामान का कारखाना, दुर्गापुर का कोयले की मशीन का कारखाना, हरिद्वार का बिजली का कारखाना, बरौनी व कोयाली मे तेलशोधक कारखाना, नेवेली में थरमल पावर स्टेशन, दाहिने किनारे का भाखरा का बिजली स्टेशन तथा अन्य बहुत से कार्य हैं अब 66 projects मे तक्नीकी सहायता मिल रही है और 1300 से अधिक विशेषज्ञ कार्य कर रहे है.

सोवियत सहायता से 1968 के शुरू तक भारत मे 10 मि० टन स्पात, 50000 टन भारी मशीन, 80 लाख टन तैल, 9000 m. kwh. बिजली तथा 90 लाख टन तेल शोध बनाया गया.

IV. कम-विकसित देशो के लिए आवश्यक सहायता के अनुमान :

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियो तथा "कमेटियो" ने कम-विकसित देशो के लिए उस सहायता के अनुमान लगाए है जिसको पाकर वे विकास के पथ पर सुनिश्चित रूप से अग्रसर हो सकते है Dr Rao ने इन अनुमानो की तुलना की है.

Chicago Study ने यह अनुमान लगाया था (Chicago university study for the senate committee on foreign aid) कि कम-विकसित देशो को प्रति वर्ष $ 3 billion को आवश्यकता रहेगी, जिसमें से $ 1 billion निजी क्षेत्र से प्राप्त हो सकेंगे. 10 या 15 वर्षों मे यह मात्रा $ 5 billion तक हो जाना चाहिए. यह अनुमान केवल गैर-कम्यूनिस्ट कम-विकसित

देशो के लिए है. Chicago Study ने यह अनुमान इस मान्यता पर लगाए है कि कम-विकसित देशो में बचत प्रतिशत 9-10% होगी, जनसख्या वृद्धि केवल 1·5% प्रति वर्ष होगी विनियोजन की दर 14-16% होगी और राष्ट्रीय आय मे 3-4% वृद्धि होगी.

Miltikan and Rostow ने, इस आधार पर कि कम-विकसित देशो के साधनो मे 30% वृद्धि विदेशी सहायता से कर दी जाए, यह अनुमान लगाया है कि इन्हे $ 3·5 billion की आवश्यकता रहेगी.

Dr. Rao का कथन है कि यह दोनो अनुमान कम है. Tinbergen ने अनुमान लगाया था कि कम-विकसित देशो को प्रति वर्ष $ 15·2 billion की सहायता आवश्यक होगी. उन्होने इस मात्रा का अनुमान इन देशो में 5-7% बचत दर तथा 4% विकास दर की मान्यता पर आधारित किया है. यह अनुमान, डा. राव के मत में, अधिक है क्योकि इसमें बचत की मात्रा कम आँकी गई है.

U. N. O. के विशेषज्ञो ने 1951 मे Measures for the Economic Development of Under-developed Countries मे कम-विकसित देशो के लिए 13 9 billion डालर की सहायता आवश्यक समझी (इसमे चीन के लिए सहायता भी शामिल थी).

Dr. Rao के स्वय के अनुमान के अनुसार समस्त कम विकसित देशो को 7 billion डालर की आवश्यकता रहेगी, जिसमे से $ 4·5 billion गैर कम्यूनिस्ट देशो के लिए होगी.

जहाँ तक अधिकतम सहायता के अनुमान का प्रश्न है Frederic Benham ने इसका अनुमान इस प्रकार लगाया है

> "समस्त कम-विकसित देशो में (1961 मे) 1200 Million जनसख्या रहती है जिसकी औसत आमदनी $ 130 प्रति व्यक्ति है. अगर

See :

Dr V. K. R. V Rao : Essays in Economic Development.
Dr O S Shrivastava op. cit : p 55-58
Frederic Benham. } as appended in the end of the chapter.
U. N. O. }
M. F Miltikan & W. W. Rostow : A Proposal-Key to an Effective Foreign Policy, Harper, N. Y. 1957. p. 56 ff.

> इसे हम $ 200 प्रति व्यक्ति पहुँचाना चाहे तो $ 85 billion की आवश्यकता पड़ेगी. इतनी मात्रा मे सहायता असम्भव है."

श्री बेन्हम का मत है कि कम से कम हर वर्ष $ 10 billion सहायता अवश्य दी जाना चाहिए यह सहायता सुनिश्चित तथा सस्ती दर पर दीर्घकाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए

V कम-विकसित देशों के लिए विदेशी सहायता सबंधी नीति के आवश्यक तत्व :

(a) अधिकाधिक सहायता व अनुदान आवश्यक :

जैसा कि हम ऊपर देख चुके है सयुक्तराष्ट्र महासचिव का कथन है कि हर विकसित देश को अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत अवश्य उधार या दान के रूप मे कम-विकसित देशो को देना चाहिए. इसी बात को Dr. Sjafruddin (डा० सफरुद्दीन) जो 1954 मे Bank of Indonesia के गवर्नर रहे है I M.F. व I.B.R.D. की बैठक मे बड़े मार्मिक शब्दो में कहा था ·

> "कम-विकसित देश कोई सुविधा विशेष नही माँगते वरन् वे तो न्यायपूर्ण बर्ताव या हक माँगते है.. जो सहायता प्राप्त कर सकते है उन्हें सहायता अच्छी है. जो देश व्यापार मे मोल-भाव करने की सुदृढ स्थिति में है. उन्हे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हितकर होता है. कम-विकसित देश तो न्यायोचित बर्ताव चाहते है. वे विश्व की आय में से न्यायपूर्ण भाग चाहते है हम चाहते है कि हमारी आवश्यकताओ को केवल व्यापार की दृष्टि से ही न समझा जाए वरन् मानवता के दृष्टिकोण से समझा जाए. यह बात भले ही हमारे I. M. F. व I. B. R. D. के जन्मदाताओ के सोचविचार से परे हो परन्तु यह उस जन्मदाता के विचारो के अनुरूप अवश्य होगी जिसने हम सबको जन्म दिया है."

कम-विकसित देशो को अधिकाधिक अनुदान मिलना चाहिए, अन्यथा विकसित व कम-विकसित देशो की आय व विकास के अन्तर कम होने के स्थान पर बढते जाएँगें.

डा० राव के शब्दों में .

> "अगर यह मान भी लिया जाए कि कम-विकसित देश हर वर्ष 15% विकास दर को प्राप्त कर लेते है तो भी वे 1974 में U S. A.

Dr. Sjafarudin : quoted from Benjamin Higgin's : op. cit., p. 596.

व कनाडा के 1956 के स्तर के 1/10 को, फ्रांस व U.K. के 1/4 स्तर को और यूरोप व सोवियत यूनियन के 1/3 स्तर को ही पहुँच पायेंगें इस काल मे उन्नत देश और उन्नत हो जाएँगें.

यह तो स्थिति उस समय होगी जब कि ये कम-विकसित देश 15% विकास दर को प्राप्त करे. वास्तव मे वे तो 3 से 6% विकास दर पर ही चल रहे हैं

अब तो यह भी आवश्यक है कि विकसित देश कुछ वर्षो के लिए अपने देश के विकास को बन्द रख कर कम-विकसित देशों को सहायता व सहयोग देकर उन्हे अपनी बराबरी पर लाएँ."

वास्तव मे स्थिति यह है कि U S A. की 2% आय वृद्धि से उनके यहाँ 40–45 डालर की वृद्धि हो जाती है जब कि कम-विकसित देशो मे केवल 2–3 डालर की ही वृद्धि होती है.

जहाँ तक हो सके कम विकसित देशों को Grants या अनुदान ही अधिक मिलना चाहिए. अगर कम-विकसित देशो में भुगतान सबधी कठिनाइयाँ है अर्थात् उनके निर्यात कम है व बढने भी नही है तथा आयात अधिक है और घटते भी नही है, तो ऐसे देशो को अधिकाधिक अनुदान की ही आवश्यकता होगी [1]

(b) Soft Loans या कम-विकसित देशों की मुद्रा में ही वापस करने वाले ऋण :

अनुदान के रूप में समस्त आवश्यकता की पूर्ति नही हो सकती. इसके लिए यह आवश्यक है कि जो ऋण हो उनमे से अधिकाधिक Soft Loans या कम-विकसित देशो की मुद्रा मे ही वापिस करने वाले ऋण होना चाहिए. इससे कम-विकसित देश अपनी वस्तुओ को बेचकर ऋण चुका सकेंगे और उन्हे वापिस करने की समस्या नही आएगी. ऋण देने वाले देश इन्ही ऋणो से फिर अपने दूतावास का

---

1 "If the economy lacks capacity to transform because of the zero elasticity in expenditure and in import competing industries or if demand abroad has price elasticity of unity or less, which prevents expansion in exports, or if imports are of great importance to the economy—either necessities, such as food materials and fuel, or capital equipment already slated for investment projects—a grant may be needed for overhead projects or a disequilibrium system on the international front cannot be avoided "

Kindleberger : op. cit., p. 338.

व्यय निकाल सकते हैं. अनुदान लेने में देश की इज्ज़त कम होती है परन्तु Soft Loans या नरम ऋणों के सम्बन्ध मे यह नही कहा जा सकता

(c) तकनीकी सहायता अधिक मिलना चाहिए :

कम-विकसित देशों को केवल विदेशी सहायता ही पर्याप्त नही है. बहुधा उनके प्रयोग के लिए तकनीकी जानकारी भी आवश्यक होती है. इन दोनो प्रकार की सहायता देने मे समन्वय होना चाहिए विशेषज्ञों के बगैर तो सहायता भी प्रयोग में नहीं ला पाते इसीलिए विदेशी निजी विनियोजन से यह लाभ होते हैं कि वह अपने विशेषज्ञ स्वय ले आते हैं. इसके लिए यह भी आवश्यक है कि विदेशी विशेषज्ञ देश के व्यक्तियो को भी प्रशिक्षित कर दें ताकि वे भविष्य मे उनका स्थान ले सकें.

आज कोई भी देश अपनी स्वय की तकनीक पूर्णरूप से उन्नत नही कर सकता. "विकास के 50 वर्षो के बाद भी सोवियत यूनियन आज कनाडा, फ्रान्स व अन्य यूरोपीय देशो से पूरे-पूरे plants (या कारखानों) के साथ-साथ तकनीक भी मँगाते हैं"

(d) Hard loans या विदेशी मुद्रा में वापस करनेवाले ऋणों की चुकाने की शर्तें आसान होना चाहिए.

जो ऋण विदेशी मुद्रा मे ही चुकाए जाएँ उनको चुकाने की शर्तें सुलभ होना चाहिए, अर्थात् .

(i) उन पर ब्याज की दर कम होनी चाहिए.

(ii) ऋण को दीर्घकालीन होना चाहिए अर्थात् 40-50 वर्ष तक की अवधि होना चाहिए.

(iii) ऋण के शुरु के 10 वर्षों मे चुकाने के दायित्व से मुक्त होना चाहिए तथा ब्याज या तो बिल्कुल न लिया जाये या बहुत कम होना चाहिए.

(iv) अगर आवश्यक्ता हो अर्थात् कम-विकसित देशों को ऋण चुकाने में कठिनाई हो तो उन्हें कुछ और मुहलत दी जानी चाहिए.

(v) ऋण के साथ राजनैतिक शर्तें नही होनी चाहिए

(e) Specific or project loans (कुछ कार्य विशेषो के लिए ही ऋण) तथा general loans (किसी भी कार्य के लिए ऋण) का उचित सम्मिश्रण होना चाहिए.

बहुत से विकसित देश कम-विकसित देशों को Specific or project loans

See : Manubhai Shah : Foreign Know How : Pros & Cons : Commerce, Sept. 14. 1968.

अर्थात् कुछ कार्य विशेषो या बडी योजनाओं के लिए ही ऋण देते हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि ये बडी योजनाएँ विकसित देशो का Show piece या दिखावट का नमूना बन जाते हैं सहायता प्राप्त करने वाले देश की जनता दूसरे देश के योगदान को समझ तो सकती है साथ ही साथ यह योजनाएँ विकास के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनमे जो लाभ होते हैं उनसे पूँजी निर्माण होता है परन्तु ये वे योजनाएँ होनी चाहिए जिन्हे कम-विकसित देश चाहते हैं न कि वे योजनाएँ जो कि विकसित देश स्थापित करना चाहते है.

आवश्यकतानुसार विकसित देशों को इस बात की भी स्वीकृति देना चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार उस सहायता को किसी भी कार्य मे प्रयोग कर सकते हैं. अगर वे चाहे तो उस राशि से उन्हे अन्य देशो से भी खरीदने की सुविधा होनी चाहिए.

विकसित देशो को Cultural aid भी देना चाहिए अर्थात् कम-विकसित देशो मे शिक्षा, स्वास्थ्य व ट्रेनिंग मे सुधार करने मे सहायता देना चाहिए तथा पुरानी रूढियो व मान्यताओ को तोडने मे सहायता देना चाहिए

अन्य महत्वपूर्ण बातें :

(i) विदेशी सहायता म समन्वय होना चाहिए अर्थात् अलग-अलग विकसित देशो को एक ही प्रकार की सहायता नही देना चाहिए. भिन्न-भिन्न देशो की कम-विकसित देशो की भिन्न-भिन्न आवश्यकताएँ मिल कर पूरी करना चाहिए

(ii) विकसित देशो को काफी पहले से सहायता का वायदा कर देना चाहिए तथा कम विकसित देशो के प्रति अपने वायदो को पूरी तरह निभाना चाहिए

(iii) सबसे प्रमुख बात यह भी है कि कम विकसित देशो को सहायता का दुरुपयोग नही करना चाहिए बहुधा कम-विकसित देशो की सरकारें फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी सहायता का सदुपयोग नही करते और इससे देश म उत्पादन क्षमता मे विकास नही हो पाता और विदेशी ऋण देश की जनता पर भार बन कर रह जाते हैं.

(iv) देश की सरकार को अपने साधन जुटाने व उचित विकास नीति अपनाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए

आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का महत्व व सीमाएँ :

आज कोई भी कम-विकसित देश बगैर विदेशी सहायता के विकास नही कर सकता

ह स्वय सशक्त राष्ट्र अमरिका तथा सोवियत यनियन विदेशी सहायता के बगर विकास नही कर सक्त थ

परन्तु जसा कि Mikesell तथा Allen न कहा ह

> 'There is no mechanical relationship between the volume of economic assistance and the rate of economic growth of developed countries Foreign aid is basically a means of helping countries to help themselves"
>
> (अर्थात आर्थिक विकास व विदेशी सहायता म कोई सुनिश्चित सह सबध नही ह विदेशी सहायता तो उनकी सहायक होती ह जो अपनी सहायता अपन आप कर त ह)

इसी प्रकार से Frederic Benham का कथन ह

> आर्थिक विकास केवल विनियोजन की मात्रा पर ही निभर नही रहता (चाहे यह न्यनतम आवश्यकता या वाछनीय मात्रा म ही क्यो न हो) और न ही विदेशी सहायता से ही देश स्वय स्फूर्ति की अवस्था म पहुच जाता ह इसके साथ देश के प्रयत्न भी महत्वपरण होत हैं

आर्थिक सहायता से देश के विकास म क्या मदद मिली यह केवल उन विशिष्ट योजनाओ के योगदान से ही नही नापा जा सकता वरन न योजनाओ से भी और याजनाए आग बढती ह विदशी सहायता से उसी क्षत्र का ही विकास नही होता जिसके लिए सहायता दी गई हो वरन उन क्षत्रो का भी विकास होता ह जो विदेशी सहायता के क्षत्रो की सहायता से विकसित होत ह

Dr V K R V Rao के शब्दो म

> 'The net contribution of aid to productive capacity depends in the last analysis on the overall policies pursued by the recipient countries regarding their total disposable resources rather than on merely the form or the specific use of aid resources'

ऋण का विकास म योगदान अन्तत तीन क्षमताओं पर निभर ह य हैं

(1) विकसित देशो की सहायता देन की क्षमता

Dr Rao and Dharam Naran op cit

(ii) कम विकसित देशों की सहायता को प्रयोग कर सकने की क्षमता तथा
(iii) ऋणों को वापस करने की क्षमता

जहाँ तक प्रथम क्षमता का प्रश्न है वह तो विकसित देशों की इच्छा पर निर्भर करती है और हम देख चुके हैं कि विकसित देशों को और सहायता करना चाहिए दूसरी क्षमता कम विकसित देशों में तकनीकी स्तर व राज्य की नीतियों पर निर्भर रहती है और इसके लिए यह आवश्यक है कि कम विकसित देश सहायता का सदुपयोग करें

Select Bibliography

Apart from the standard works mentioned in earlier chapters, the following references were consulted particularly

1 Sir Roy Harrod Aid to Less Developed Countries, Commerce Annual Number, 1965
2 Brahmanand Prasad Foreign Aid and Economic Development Commerce, Pamphlet-7 Com June 8 1968
3 John Mc Diarmid International Action for Economic and Social Progress Indian Finance, 11 November, 1967
4 Woods (President World Bank) The Philosophy of Economic Aid Indian Finance His Lecture in Stockholm on 27th Oct
5 Thorkil Kristensen Aid to Under-developed Countries Commerce, Annual Number 1965
6 Singer, H W Ch III op cit
7 Gaston Ludec International Aid and Growth I E A paper
8 Frederic Benham Economic Aid to Under developed Countries Oxford University Press 1961, 37-42 112-18 cf G Meier op cit
9 U N O Deptt of Economic and Social Affairs The Capital Development Needs of Less Developed Countries N Y 1962, cf G Meier op cit
10 R F Mikesell & R L Allen (U S Congress Joint Economic Committee) Economic Policies toward Less developed Countries-Studies Types and conditions of foreign aid , U S Govt , G Meier op cit
11 GATT External Financing of the Third Five Year Plan of India G Meier op cit

तीसरी क्षमता देश की उत्पादकता वृद्धि से बढती है इस सबध म Evsey Domar ने कहा है

> ' व समस्त व्यक्ति जो राष्ट के विदेशा के ऋणी होने के कारण फिक्र करत है लख लिखते है भाषण करते है तथा रात बगैर नीद लिए बेचैनी से बितात है व अगर उससे आधा समय ही राष्ट्रीय उत्पाद क्षता व आय बढान म लगावें तो समाज का कल्याण भी करेंग और ऋण समस्या के हल करने म भी सहायक होग जब राष्ट्रीय आय बढती है तो राज्य की आय करो द्वारा स्वय ही बढ जाती है जिससे ऋण का भार कम हो जाता है.

●

---

12 U N O ' On making foreign aid more effective' I E A Paper G Meier op cit
13 Benjamin Higgins Ch 26 op cit
14 Kindleberger Ch 17
15 Meier & Baldwin Ch 19 op cit
16 Y Bolshakov Soviet Indian Economic Cooperation Soviet Land Books 1968
17 Arts & Letters 57, Daryaganj, Delhi-6 Indo Soviet Economic Collaboration 1955-1965
18 K S Bhatia Soviet Land Booklets 1968 Soviet-Indian Cooperation in Agriculture
19 Free Press Journal Feb 14, 1969 ' U S Economic Assistance to India till Jan 1969
20 Manubhai Shah Foreign Know-How Pros & Cons Commerce, Sept 14 1968.
21 G L Mehta Development and Foreign Collaboration
22 O S Shrivastava op cit p 55 60
23 V K R V Rao Essays in Economic Development
24 V K R V Rao & Dharam Narain Foreign Aid and India s Economic Development, Asia 1963
25 Patriot Sept 27, 1966

अध्याय : 14

विदेशी पूँजी व आर्थिक विकास

Role of Foreign Capital in Economic Development

I प्रस्तावना :

विदेशी पूँजी का योगदान व महत्व.

II. कम-विकसित देशो मे विदेशी पूँजी के लाने मे कठिनाइयाँ.

III. विदेशी पूँजी को कम-विकसित देशों मे लाने के लिए आवश्यक बातें.

IV कम-विकसित देशो के विकास मे विदेशी पूँजी के योगदान की सम्भावित हानियाँ और सीमाएँ.

भारत का विकास व विदेशी पूँजी

I. मात्रा.

II. देश जहाँ से पूँजी प्राप्त हुई है.

III. भारत की नीति व प्रयत्न.

IV. समयावधि.

V. रायल्टी व लाभांश.

अध्याय : 14

विदेशी पूँजी व आर्थिक विकास

Role of Foreign Capital in Economic Development

I. प्रस्तावना :

योगदान व महत्व :

जैस कि हम जानते हैं, कम-विकसित देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशो से पूँजीगत व उपभोग वस्तुओं की आवश्यकता रहती है. अगर यह न मिलें तो उपभोग कम रहेगा अथवा बचत व पूँजी कम रहेगी और ऐसे कार्य शुरू नही किए जा सकते, जो देश के विकास में सहायक हो.

हम देखते है कि कम-विकसित देशो को जो विदेशी-मुद्रा की आवश्यकता होती है. वह मुख्यतया निर्यात, अनुदान व ऋण से प्राप्त होती है. इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी भी महत्वपूर्ण साधन रहती है.

आजकल लगभग $ 2 billion की वार्षिक विदेशी पूँजी कम-विकसित देशों मे लगाई जाती है. विश्व के आज जो विकसित देश है वे भी कभी विदेशी पूँजी की सहायता से विकसित हुए थे. सोवियत यूनियन, सयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि सभी देशों के विकास मे विदेशी पूँजी सहायक रही है. ब्रिटेन ने 17वी व 18वी सदी में हालैंड से बहुत पूँजी प्राप्त की थी. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी 19वी सदी में योरोप से पूँजी प्राप्त की थी. कनाडा ने 1900-1930 के बीच यू० के० व संयुक्तराष्ट्र अमेरिका से पूंजी प्राप्त की थी और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा. आज भी कनाडा, जो विश्व में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार, कुवैत व सयुक्तराष्ट्र अमेरिका के बाद स्थान रखता है, विदेशी पूँजी का शुद्ध आयातकर्ता है.

See : References quoted in the previous chapters

U. N. "Process and Problems of Industrialisation of Under-developed Conutries." 1951.

D. B Singh : ch. XII, "External Capital : The Problem of Utilization."

लाभ व आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन में विदेशी पूजी के योगदान या महत्व को हम निम्नलिखित सूत्रों में बाँध सकते हैं :

1. विदेशी विनियोजन से देश की वास्तविक आय में वृद्धि होती है देश का पूँजी निर्माण बढता है. अगर विदेशी पूँजी न आये तो कम-विकसित देशों के देश-वासियों को अपने उपभोग को कम करके पूजी निर्माण करना पडता है. हम "पूजी-निर्माण" के अध्याय मे देख चुके है कि आज के युग में उपभोग को कम करके पूँजी-निर्माण करना बहुत से आर्थिक सामाजिक कारणों से सभव नही होगा.
2. विदेशी पूजी के विनियोजन से Healthy precedent अर्थात अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है और फिर और अधिक विदेशी पूंजी आने लगती है. प्रथम बार विदेशी विनियोजक हिचकते हैं और जब पूँजी आने लगती है तथा उसके द्वारा सचालित उद्योगो को पर्याप्त सुविधा मिलती रहती है तो विदेशी विनियोजन से काफी विकास की सभावना बढ जाती है. विदेशी पूँजी के आगमन का Demonstration effect भी होता है.
3. विदेशी पूँजी के विनियोजक कम-विकसित देशो मे लाभ अर्जित करते है (जब कि ऋणो पर ब्याज दिया जाता है) और इसके लिए बहुधा वे अपने मैनेजर तथा तकनीकी विशेषज्ञ साथ लाते है. वे जो उन्नत तकनीक लाते है उससे देश मे तकनीकी उन्नति होती है तथा वे देश मे श्रमिको व प्रशासको को भी प्रशिक्षित करते है
4. विदेशी विनियोजक से देश के विनियोजको को भी विनियोजन बढाने की प्रेरणा मिलती है. बहुधा विदेशी पूंजी के विनियोजन से देश मे कुछ वस्तुएँ ऐसी पैदा होने लगती है जो अन्य उद्योगो के लिए कच्चा माल बन जाती है और इससे देश के उद्योगो मे विनियोजन बढ जाता है. कुछ आवश्यक कच्चे-माल या मशीनो को अगर यह विदेशी विनियोजक देश में ही उत्पादन करने लगते है तो बगैर विदेशी मुद्रा व्यय किए या कम व्यय मे ही, ये देश मे औद्योगीकरण को सभव कर देते हैं.
5. विदेशी पूँजी वैसे तो तब देश मे आती है जब कि देश में पहले से ही "बाह्य मितव्ययिताएँ" मौजूद हो परन्तु कभी-कभी विदेशी पूँजी भी देश मे Infra-structure or external economies "बाह्य मितव्ययिताओ" का सृजन करती है.
6. विदेशी पूँजी से देश मे मुद्रा स्फीति विहीन विकास सम्भव होता है अगर विदेशी पूँजी देश मे न आती हो तो हम पाते है कि बचत से ज्यादा विनि-

योजन करने से (हीनार्थ प्रबन्धन करके) देश में मुद्रा स्फीति फैलती है विदेशी पूँजी के आने से यह सम्भावना समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है परन्तु इसके लिए यह भी आवश्यक है कि

(1) विदेशी पूँजी से जो उत्पादन हो वह शीघ्र हो. तथा
(11) अगर उत्पादित सामान विदेशों में भेज दिया जाय तो देश के उपभोग के लिए आयात भी हो

7. विदेशी पूँजी के विनियोजक देश में बहुधा कुछ विशिष्ट कार्य या योजनाओ (Specific projects) मे धन लगाते है. ये Specific projects देश में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ावा देते हैं.

8. विदेशी पूँजी के आने से देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति भी सुधरती है भुगतान सतुलन को विपक्ष में जाने से रोकती है या पक्ष में लाती है. इससे कम-विकसित देशो की "भुगतान की शर्तें" सुधरती है कम-विकसित देश बहुधा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए जल्दी से निर्यात कर देते हैं परन्तु अगर वह बहुमूल्य मुद्रा विदेशी पूँजी से प्राप्त हो जाती है तो ये कम-विकसित देश कुछ ठहर जाते है और मूल्य स्थिति सुधरने पर ही बेचते है और इस प्रकार से उनकी "भुगतान की शर्तें" सुधरती है. विदेशी पूँजी के आने से कम-विकसित देशों की मोल-भाव करने की शक्ति सुधरती है

9. विदेशी पूँजी से राज्य को विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त "लाभ पर कर" भी प्राप्त होता है जनता को सस्ते मूल्य पर वे वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती है जो उन्हे या तो नहीं मिल पाती या फिर मँहगी मिलती है.

10 सक्षेप में विदेशी पूँजी के आने से देश में उपभोग, बचत, पूँजी-निर्माण, उत्पादन, लाभ, रोजगार व आय बढ़ती है

D B Singh के शब्दो मे

"Foreign capital helps in promoting economic development in the usual multiplier way"

See also : (1) G Meiers's Note on "The Contribution of Private Foreign Investment", op cit ch. III
(2) B Higgins . op cit
(3) Meier & Baldwin : op cit.
(4) H W. Singer : op cit.
(5) O S Shrivastava : op cit

II. कम-विकसित देशो मे विदेशी पूंजी लाने मे कठिनाइयाँ :

आज बहुत से कम-विकसित देश चाहते हैं कि विदेशी पूंजी उनके देश में आए परन्तु इसकी राह मे कई रुकावटें है उनमें मुख्य ये है

1 बहुत से कम-विकसित देश मे राजनैतिक अस्थिरता बनी रहती है. वियतनाम, कोरिया तथा नाइजीरिया मे तो युद्ध ही चलता रहा है स्वतन्त्रता के बाद कांगो मे भी विघटन को क्रियाएँ चलती रही. पाकिस्तान में भी प्रेसीडेण्ट अयूब के लम्बे शासनकाल से पहले 8—प्रधान मन्त्री बदले, जब कि भारत में श्री नेहरू ही प्रधान मन्त्री बने रहे. बर्मा, इरान, इराक, सीरिया आदि देशो मे सैनिक क्रान्तियाँ हुई. द० अमेरिका मे तो तख्तापलट साधारण बात है. ऐसी स्थिति में विदेशी विनियोजक हिचकिचाते है क्योंकि उन्हें यह भरोसा नही रहता कि वे लाभ कमा सकेंगे या नही तथा लाभ को अपने देश भेज सकेंगे कि नही. राष्ट्रीयकरण का भी डर बना रहता है.

2. कम-विकसित देशों मे मुद्रा स्फीति बहुत रहती है. इससे देश की मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है. गिरते हुए मूल्यों के स्थान पर विकसित देशो के विनियोजक स्थिर मूल्य स्तर या मुद्रामूल्य वाले देशो को पसन्द करते है.

3 कम-विकसित देश बहुधा विदेशी विनियोजको पर कुछ समय बाद भेदभाव पूर्ण कर लगाने लगते है और उन्हे अपने लाभो को भी पूर्णरूप से अपने देश से नही ले जाने देते. कम-विकसित देश, अपनी विदेशी मुद्रा सबधी कठिनाई के कारण, विदेशी विनिमय पर नियत्रण करते है और इस कारण विदेशी विनियोजको को कठिनाई होने लगती है.

4. बहुधा कम-विकसित देशो के प्रशासन को लाली फीताशाही का भी विदेशी विनियोजक शिकार हो जाते है

5. बहुधा कम-विकसित देश विदेशी विनियोजको को आवश्यक कच्चा माल विदेशो से नही मँगाने देते है.

6. आज के युग म कम-विकसित देशो मे श्रम सगठित है और बहुधा विदेशी विनियोजको को राज्य श्रम सकट सुलझाने मे सहायता नही करते.

"*In recent years payment defaults,* currency instability, exchange control, expropriation risks, restrictive labour laws, discriminatory taxation, government competition with private enterprise, joint participation, *regulation* etc. have all acted as deterrents to private and government foreign investment." (O. S. Shrivastava : op. cit. : p. 58.)

7. विदेशी विनियोजकों के लिए साधनों, बाजार व अन्य आर्थिक घटकों के संबंध में जानकारी (based on surveys and research) प्राप्त नहीं होती.
8. "विदेशी विनियोजकों का कम-विकसित देशों में अधिकाधिक विनियोजन करना केवल अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी की पूर्ति का ही प्रश्न नहीं है, वरन् माँग पक्ष भी महत्वपूर्ण है. बहुत से कम-विकसित देश, जो हाल में ही साम्राज्यवादियों की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, विदेशी पूँजी के प्रति शंकित रहते हैं कुछ देशों में यह भावना जम गई है कि "विदेशी-एकाधिकारी-पूँजीपति-साम्राज्यवादियों को इन देशों के "सम्पन्न साधनों" का लाभ न लूटने दिया जाए[1]
9. कम-विकसित देश बाद में अनुचित रूप से विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण कर लेते हैं और या तो मुआवजा देते नहीं हैं या कम देते हैं या देर से देते हैं. इन्डोनेशिया व केन्या के उदाहरण सामने हैं. आज केन्या से कई भारतीयों को निकाला जा रहा है, वर्मा ने भी भारतीयों को बगैर पर्याप्त मुआवज़ा दिए निकाल दिया और यही बात लंका ने भी की है
10. बेन्जामिन हिगिन्स के शब्दों में, एक और डर इन देशों में Creeping expropriation का है (अर्थात् धीरे धीरे सम्पत्ति जब्त करने का डर) यह मुख्यतया भेदभावपूर्ण नीति के कारण होता है जिससे कि विदेशी विनियोजक पर्याप्त लाभ नहीं कमा पाते या हानि उठाने लगते हैं[2]
भारत के सम्बन्ध में हिगिन्स ने लिखा है कि

> "भारत में हर प्रशासनिक निर्णय देर में लिया जाता है. आयात, निर्यात व विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रहता है. जनता तथा बहुत सी राजनैतिक पार्टियाँ रोज ही विदेशी विनियोजकों को "शोषक" के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं. भारत के व्यापारियों की व्यापार पद्धतियाँ उनकी समझ से परे रहती हैं. भारत ने अभी भी बहुत से देशों से दुहरे कर न लगने के समझौते नहीं किए हैं तथा यहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिक व सामाजिक आर्थिक सिरोपरि व्ययों की कमी है."

III. विदेशी पूँजी को कम-विकसित देशों में लाने के लिए आवश्यक बातें

जैसाकि साधारणतया कहा जाता है "Remove the cause, remove the evil" अर्थात् कारण को समाप्त कर दो, बुराई स्वयं ही समाप्त हो जाएगी.

---

1. B Higgins : op cit. p. 593-4
2. ,, op cit p 582-3.

इसी प्रकार से कम-विकसित देशों में अगर विदेशी पूँजी को अधिकाधिक लाना है तो जिन अवरोधों के कारण पूँजी कम आती है उन्हें दूर करना होगा.

कम-विकसित देशों में अगर विदेशी पूँजी अधिकाधिक आए तो इसके लिए यह जरूरी है कि कम-विकसित देश उन्हें सुविधाएँ दे और विदेशी विनियोजक कम-विकसित देशों की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर कार्य करें

ECAFE (Economic Commission for Asia and Far East) ने विदेशी विनियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर बल दिया है

1 देश में राजनैतिक स्थिरता हो
2 देश में जन-जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था हो
3 देश में लाभ कमाने के अवसर मौजूद हो
4 जब तक कि विदेशी विनियोजक अपनी पूँजी वसूल न कर ले तब तक उनकी पूँजी का राष्ट्रीयकरण नही होना चाहिए और जब राष्ट्रीयकरण हो तो उचित मुआवजा चुकाया जाना चाहिए
5 लाभ को अपने देश भेजने पर रुकावट नही होना चाहिए.
6. विदेशी विनियोजको को अपने प्रशासक व तकनीकी व्यक्ति रखने की अनुमति होना चाहिए तथा तकनीक अपनाने की सुविधा होना चाहिए.
7 कार्य के शुरू के वर्षों मे कर कम होना चाहिए तथा कभी भी विभेदपूर्ण कर नही लिए जाना चाहिए
8 दुहरे कर (दोनो देशो की सरकारो द्वारा) नही लगना चाहिए
9. राज्य को अनुचित नियन्त्रण लगाना व प्रतियोगिता नही करना चाहिए
10 सक्षेप मे, राज्य को विदेशी विनियोजको के प्रति दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए

U.N.O. की आर्थिक काउन्सिल ने यह सिफारिश की है कि कम-विकसित देशो की सरकारो को "व्यापारिक जोखिमो" के अतिरिक्त और समस्त जोखिमो के प्रति "बीमा" प्रदान करना चाहिए. कर में छूट देने से ही काम नही चलता भेदभाव पूर्ण नीति का छोड़ना तथा लाभ कमाने देना बहुत महत्वपूर्ण है

See : U. N. "Economic Commission for Asia and Far East Committee on Industry and Trade, Second Session, Foreign Investment, Laws and Regulation in Ecafe Region" Bangkok, March 1950. p 4-5.

> "The attraction of private foreign investment now depends less on fiscal action, upon which most countries have concentrated and more on other conditions and measures that guarantee protection of investment and provide wider opportunities for the foreign investment If private investment is to be encouraged, it is necessary to allay the investor's concern over the possibilities of discriminatory legislation, exchange control, threats of expropriation Investment guarantees may be utilized more effectively to lessen the investor's apprehension of non-business risks"

साथ ही विकसित देशो के विनियोजको को चाहिए कि उनका विनियोजन विकास योजना के अनुरूप हो न कि कम-विकसित देशो की विकास योजना उनकी विनियोजन योजना के अनुरूप हो.

अगर अन्तर्राष्ट्रीय विनियोजन भी U N.O की भाँति किसी अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के माध्यम से समन्वित रूप से हो तो यह और भी उपयुक्त होगा

आज विश्व मे सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, यू० के०, फ्रास, जर्मनी तथा अन्य पश्चिम योरोपीय देश विश्व के कम-विकसित देशो को पूँजी निर्यात करते है आज जो भी पूँजी विदेशो मे लगाई जाती है, उसमे एशिया का हिस्सा, जनसख्या के अनुपात मे बहुत कम रहता है. सयुक्तराष्ट्र अमेरिका के विनियोजको ने जो विनियोजन विदेशो मे किए है उसका 40% कनाडा में, 30% द० अमेरिका मे, 15% योरोप तथा उनके अधीनस्थ देशो मे तथा बाकी का 15% अन्य क्षेत्रो मे (जिनमें एशिया व अफ्रीका शामिल है) लगाया सयुक्तराष्ट्र अमेरिका का अधिकाश विनियोजन पेट्रोल उद्योग मे है, फ्रान्स ने लगभग सभी विनियोजन अफ्रीका मे किया है. इसलिए यह आवश्यक है कि पूँजी को विस्तृत क्षेत्रो मे लगाया जाए.

बहुधा यह कहा जाता है कि कम-विकसित देशो मे, सामाजिक आर्थिक सिरोपरि

U. N. Economic and Social Council, The Promotion of the International Flow of Private Capital. Further report by the Secretary General, Doc E/3492, *Geneva*, 1961, ch. III.

सुविधाओं की कमी के कारण विनियोजन के अवसरों व लाभ कमाने के अवसरों की कमी है परन्तु National Industrial Conference Board of American Businesses ने 1951 में बताया कि विश्व में 54% विदेशी विनियोजन करनेवाली 107 में से 89 फर्में यह मानती थी कि विदेशी विनियोजन में अच्छी आय कमाई जा सकती है 1950 में सयुक्तराष्ट्र अमेरिका के Department of Commerce ने यह जानकारी दी कि U. S A ने भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया, फिलीपाइन्स में 227 million dollars के शुद्ध विनियोजन पर कर देने से पहले 133 million dollars कमाए थे, जो कि शुद्ध विनियोजन के 58% के बराबर था.

IV. कम-विकसित देशों के विकास में विदेशी पूंजी के योगदान की सम्भावित हानियाँ और सीमाएँ ·

विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कम विकसित देशों को कुछ कीमत भी चुकानी पडती है बहुधा विदेशी विनियोजकों को सस्ती दरों पर पानी, जमीन या बिजली की सुविधाएँ देनी पडती हैं कर सबधी छूटें भी देनी पडती हैं. यह सब प्रत्यक्ष लागतें है

कभी कभी विदेशी विनियोजक कम-विकसित देशों में उद्योगों को नही पनपने देते. उनसे अनुचित प्रतियोगिता करते हैं. देश के विनियोजकों के लाभ कम कर देते हैं. इससे देश में बचत व पूंजी-निर्माण के स्तर गिर जाते हैं और देश और अधिक विदेशी विनियोजन का आश्रित हो जाता है

विदेशी विनियोजक कभी-कभी राज्य को अपने प्रभाव में ले लेते हैं (रोडेशिया में खान के मालिकों का प्रभाव रहा, कटागा में विदेशी विनियोजकों का ही एक प्रकार से राज्य था) देश में श्रमिकों का व देश के साधनों का शोषण करते हैं और जो

---

cf : 1 Study of Factors Limiting American Private Investment–Summary of Preliminary Findings and Recommendations, Deptt of Commerce, July 1953, p 5 quoted from Capital Formation and Foreign Investment in Under-developed Areas : Wolf and Sufrin, 1958, p. 53.

2 S. A. Paleker op cit : 119-138.

3. O. S. Shrivastava : op. cit. p. 57-58.

See : H. W. Singer : The Distribution of Gains Between Investing and Borrowing Countries, American Economic Review—I. E. A. Papers and Proceedings. May 1950

लाभ कमाते हैं उन्हें अपने देश मे ले जाते हैं और कम-विकसित देशो में ही विनियोजन करके उनके विकास में सहायता नही करते

विदेशी विनियोजकों द्वारा जब पूँजी या लाभ बाहर ले जाया जाता तो देश पर बहुत भार पड जाता है और व्यापार की शर्ते विपक्ष में जाती हैं

भारत का विकास व विदेशी पूँजी

I. मात्रा

अन्य देशो के विकास मे योगदान की भाँति, विदेशी पूजी का भारत के विकास मे भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है 1965 के अन्त तक भारत मे 936 करोड रु० की विदेशी पूँजी लगी थी. 1948-61 के बीच भारत में विदेशी पूँजी का विनियोजन 157% से बढ गया था और 1961 मे यहाँ 680 करोड की विदेशी पूंजी लगी थी. भारत की तीन योजनाओ के काल मे 625 करोड रु० की पूँजी विदेशो मे आई अर्थात् योजना काल मे जितना विनियोजन निजी क्षेत्र ने किया उसका 25% भाग विदेश मे आया था

II. देश ·

भारत मे जो विदेशी पूजी लगी है उसका अधिकाश भाग यू० के० से आया है. भारत मे 1967-68 के अन्त तक 2200 विदेशी सहयोग के समझौते हुए उनमे

Select references : For latest views and data

(1) Reserve Bank of India Report on "Foreign Collaboration in Indian Industry" This gives data upto 1967-68. It is the most comprehensive and latest study For this analysis see Ch VI particularly—Published in late 1968
(2) T. V Sethuraman 'Foreign Investment In India" Yojana, June 23, 1968,
(3) G L Mehta "Development & Foreign Collaboration" Indian Econ Conference Paper, Dec. 1968–Golden Jubilee Session-Madras
(4) D. T. Lakdawala : "Foreign capiteal & Development." as above
(5) M. V. Arunachalam . Development and Foreign Collaboration. as above and all reference mentioned earlier.

से 1051 प्रभावशील हो गए थे. इन 1051 Collaboration या सहयोग योजनाओं में से अलग-अलग देशो का योगदान Subsidiary Companies (विदेशी कम्पनियो की शाखा के रूप मे), Minority participation of foreign Capital (भारतीय कम्पनियो मे 50% शेयर से कम की हिस्सेदारी) तथा Technical Collaboration (या तकनीकी सहयोग) के रूप में रहा है. पेट्रोल, यातायात सामान, बिजली का सामान, रसायन, दवाएँ आदि के उद्योगो में प्रथम दो प्रकार का सहयोग है जब कि मशीन, मशीन टूल्स, धातु तथा कपडा उद्योग मे तकनीकी सहयोग रहा है

निम्नलिखित तालिका मे भिन्न-भिन्न देशो के योगदान के आँकडे दिए हैं .

The Countrywise Classification of Agreements.

Country	Subsidiaries	Minority Participation	Tech Collaboration	Total
1 U K.	81	181	158	420
2 U S A	24	86	84	194
3. West Germany	7	74	68	149
4. Switzerland	9	25	32	66
5 Japan	1	17	33	51
6 France	3	16	16	35
7. Netherland	3	13	8	24
8 Sweden	7	6	5	18
9. East European Countries	—	—	25	25
10. Others	9	27	33	69
	144	445	462	1051

R. B. I. Study, 1968 : op. cit.

उपरोक्त 1051 समझौतो मे से 1006 औद्योगिक उत्पादन के लिए, 11 बागान, खान व पेट्रोल के तथा 34 अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में थे, 1006 औद्योगिक उत्पादन समझौतो का विवरण इस प्रकार है :

1.	मशीन व मशीनी औजार	250.
2	रसायन	177
3	बिजली का सामान	162
4.	यातायात सामान	115
5.	धातु व धातु का सामान	107
6	बुनाई मिल (सूती व अन्य)	59.
7.	खाद्य व पेय	12.
8	अन्य	124.
		1006.

(Ibid)

III भारत की नीति :

आजादी के तुरन्त बाद भारत मे विदेशी विनियोजन को बुरा तो नही माना जाता था परन्तु उसको प्राप्त करने के लिए भारत ने पहल नही की है. प्रथम योजना मे यही नीति रही द्वितीय योजना काल मे 1956-57 मे ही प्रथम योजना काल के बराबर विदेशी विनिमय का प्रयोग किया गया और इस काल मे विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया गया. तृतीय योजना मे तो बडे उत्साह से इसका स्वागत किया गया

Dr. D T. Lakdawala के शब्दो में

"The Indian attitude to foreign capital, as it came to be slowly formed, was ambivalent. The instinctive hostility to foreign capital was greatly tempered by a recognition at least in the modern sector of the important role it plays and the lacunae its absence would create."

तृतीय योजना मे ही भारत सकट मे पड गया इस काल में दो विदेशी आक्रमण हुए, दो प्रधानमन्त्री स्वर्गवासी हुए और दो सूखे के वर्ष पडे भारत में विदेशी पूंजी के आने की मात्रा कम होने लगी जिसके और कम होने का डर होने लगा. कुछ तो विश्व मे ही पूंजी की कमी थी[1] और कुछ भारत की परिस्थितियां भी

1. Arunachalam's (op cit) observation :
"Currently in the context of world shortage of capital, it is almost puerile to imagine that there awaits a flood of foreign capital to inundate and enliven our moribund Capital market."

प्रतिकूल थी. भारत मे पूंजी आने की सम्भावनाओ के कम होने के निम्नलिखित कारण है

1. भारत मे हाल के वर्षो में राजनैतिक अस्थिरता है. लगभग हर प्रान्त मे आगजनी, विध्वंस व अराजकता यदाकदा छा जाती है.
2. भारत में बैंको के राष्ट्रीयकरण से भी विदेशी विनियोजक भयभीत हो सकते है.
3. भारत मे पिछले वर्षो मे मुद्रास्फीति के कारण भी भारतीय मुद्रा का मूल्य गिरा है. इससे विदेशी विनियोजक उत्साहित नही होते क्योकि उनकी लागतें बढ जाती है
4. आजकल भारत का पूंजी बाजार भी तेजी में नही है
5. बहुत से विदेशी विनियोजक भारत मे "Minority Participation" को पसन्द नही करते वे 50% से अधिक के शेयर के मालिक बनना चाहते है

भारत ने विदेशी पूंजी को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए है यह कदम मुख्य रूप से 1957 के बाद उठाए गए है. विदेशी पूंजी को आय कर, सम्पत्ति कर, सुपर टैक्स, वेतन पर कर पर कुछ विशेष रियायते दी गई है. उनकी रायल्टी पर 'कारपोरेशन टैक्स' भी घटा दिया गया है. बहुत से देशो से दोहरे कर न लगने के समझौते भी किए गए है. भारत में विदेशी विनियोजको के विनियोजन प्रश्नो पर गौर किया जाता है और 1964 के बाद मे इसकी पद्धति भी सरल कर दी गई है और इसी कारण जैसा कि डा० लकडावाला का कथन है

> "हम इन वर्षो में जो कठिनाई व इम्तहान के दौर मे गुजरे है उसमें हमारा साथ विदेशी विनियोजको ने छोडा नही है."

इतना अवश्य है कि विदेशी विनियोजको ने कुछ शर्तें बहुत अनुचित लगा रखी है, जैसे कि कुछ देशो से आयात नही कर सकते अथवा कुछ देशो को निर्यात नही कर सकते

IV. Duration या समयावधि

भारत में 30 समझौते तो अनिश्चित काल के लिए है तथा 13% समझौते दस वर्ष की अवधि के ऊपर के है. अन्य समझौते 10 वर्ष या इससे कम के लिए किए गए है.

V Royalty and dividend payment रायल्टी व लाभाश-भुगतान

जिन उद्योगा में विदेशी विनियोजक मालकियत रखत हैं उनमे उन्हें dividend या लाभाश प्राप्त होता है और जिनमें तकनीकी सलाह देते हैं या पेटेन्ट को प्रयोग में लाने की अनुमति देते हैं तो उन्हें रायल्टी मिलती है निम्नलिखित तालिकाएँ इससे सबधित जानकारी प्रदान करती हैं

Distribution of royalty agreements linked to value of sales/production

%Rate of royalty	No of agreements
0—2	78
2—3	153
3—4	72
4—5	199
5 and above	67
	569

Table showing dividend remittances and royalty Crores of rupees

Year	Dividend	Royalty
1960—61	11 38	1 51
61—62	14 14	1 92
62—63	18 35	2 32
63—64	16 11	3 35
64—65	20 58	4 95
65—66	19 58	6 40
66—67	21 50	7 97
	122 01	28 42

Countrywise royalty
Between 1960-61 to 1966-67 (Crores of rupees)

U. K	11·19
U. S. A.	9·26
West Germany	4·28
Others	3 69
	28·42

R Bank of India के 1966 की एक रिपोर्ट के अनुसार U K. व U. S.A. ने 1958-62 के बीच अपने विनियोजनों पर क्रमश 9 व 12% कमाया. विदेशी विनियोजक भारत में औसतरूप से 6% लाभ या रायल्टी कमाते है.

अध्याय : 15

पूँजी-निपज अनुपात

Capital-Output Ratios

I पूजी-निपज अनुपात व उसके प्रकार.

II. पूजी-निपज अनुपात की विशेषताएँ.

III. पूजी-निपज अनुपात के अध्ययन व प्रयोग का महत्व.

IV. पूजी-निपज अनुपात के प्रयोग की सीमाएँ.

V विकसित व कम-विकसित देशो मे पूजी-निपज अनुपात.

अध्याय : 15

पूँजी-निपज अनुपात

Capital-Output Ratios

I. Meaning of Capital-Output Ratios and Types : पूजी-निपज अनुपात व उसके प्रकार

George Rosen के अनुसार

"पूजी-निपज अनुपात (Capital-output ratio or Capital Co-efficient) किसी वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था या उद्योग में होने वाले विनियोजन व उसी वर्ष में होनेवाली उपज में सह सम्बन्ध बतलाता है"

Capital-output ratio कई प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य है

(i) Average capital-output ratio या औसत पूजी-निपज अनुपात
(ii) Incremental capital-output ratio (ICOR) या वृद्धि पूंजी निपज अनुपात
(iii) Marginal capital-output ratio या सीमान्त पूँजी-निपज अनुपात
(iv) Gross capital output ratio या कुल पूंजी-निपज अनुपात
(v) Net capital-output ratio या शुद्ध पूजी-निपज अनुपात
(vi) Sectoral capital-output ratio या क्षेत्रीय पूजी-निपज अनुपात तथा
(vii) Capital-output ratio of the economy या सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पूंजी-निपज अनुपात.

इनके अर्थ यह है

Average C-O Ratio

यह अनुपात वह है जो किसी समय में पूंजी व उत्पत्ति में सह-सम्बन्ध दर्शाता है.

All references appended at the end of the chapter

इसको निकालने के लिए हमको एक वर्ष की कुल पूंजी मे कुल आय से भाग देना पडता है

Average capital-output ratio is the value of the total stock of capital ÷ by total income.

Incremental capital-output ratio

यह अनुपात विकास आयोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है यह अनुपात किसी वर्ष में होने वाले पूंजी-निर्माण तथा उस पूंजी-निर्माण से अगले समय में उत्पादित शुद्ध उत्पादन के सम्बन्ध को बतलाता है वैसे तो किसी भी पूंजी विनियोजन से प्रतिफल कुछ समय बाद मिलता है परन्तु सुविधा के लिए हम इस सम्बन्ध म उसी काल के उत्पादन से सम्बन्ध निकाल लेते हैं.

Incremental capital output ratio is the value of the addition to the stock of capital (Net investment) ÷ by addition to income or net national income

अर्थात् वृद्धि पूंजी-निपज अनुपात निकालने के लिए किसी समय के शुद्ध अतिरिक्त पूजी निर्माण मे उस समय की शुद्ध आय वृद्धि से भाग करते हैं.

Gross Capital-Output Ratio and Net Capital-Output Ratio

"कुल पूंजी-निपज अनुपात" देश की कुल अचल पूंजी व कुल उत्पादन का सम्बन्ध है तथा शुद्ध पूजी-निपज अनुपात देश की कुल अचल पूंजी तथा शुद्ध उत्पादन (अर्थात् कुल उत्पादन मे से कच्चे माल, ईंधन व घिसावट आदि निकालने के पश्चात्) के बीच अनुपात बतलाता है

Overall Capital-output Ratio or For the Economy as a Whole

सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का पूंजी-निपज अनुपात भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के C O. Ratios का औसत होता है जिसको हम भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उपज वृद्धि से weight देते हैं. इस प्रकार से सम्पूर्ण अनुपात भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार या weight पर निर्भर रहता है. यह भार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की पूंजी-गहनता के अनुपात में दिया जाता है

W. B. Reddaway ने क्षेत्रीय पूजी-निपज अनुपात निकालने के लिए निम्न-लिखित Summary या साराश रूपी विवरण प्रस्तुत किया है

किसी भी देश मे कुल पूंजी की आवश्यकता नापने के लिए सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के पूँजी-निपज अनुपात को जानना बहुत आवश्यक होता है परन्तु जैसा कि हम देख चुके है यह अनुपात हम तब तक नही जान सकते जब तक कि हमका भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के पूँजी-निपज अनुपात मालूम न हो

C.P. Kindleberger ने C.O. Ratio तथा Marginal Efficiency of Capital (M E.C.) मे अन्तर बतलाया है. जहा C.O Ratio सम्पूर्ण पूंजी या पूजी वृद्धि व सम्पूर्ण उत्पादन या उत्पादन वृद्धि में (जिसमें कि अन्य स्थिर या परिवर्तनशील उत्पादन अगो को ध्यान मे नही रखा जाता) सम्बन्ध बतलाता है. M. E. C मे केवल विनियोजन वृद्धि से उत्पादन वृद्धि (जब कि अन्य अंगो की मात्रा स्थिर हो) का सम्बन्ध नापते है.

एक क्षेत्र की दो समयो के बीच की उत्पत्ति को इस प्रकार से बाँटना चाहिए

(i) वह उत्पत्ति वृद्धि जिसमें अधिक पूजी लगाए बगैर, अर्थात् उन्नत रीति प्रयोग करके उत्पादन बढे (इसे हम P for Progress से दर्शाएँ)
(ii) वह उत्पत्ति वृद्धि जो किसी कारखाने की मशीनो का, माँग बढने के कारण, पूर्ण प्रयोग करने से होती है. (D for Higher production due to demand).
(iii) दो शिफ्ट या पालियो मे कार्य करने से उत्पादन वृद्धि (S).
(iv) अच्छे व अनुकूल मौसम से उत्पादन वृद्धि (W)
(v) क्षेत्र विशेष मे उचित तकनीकी अनुपात रहे जैसे श्रम की कमी न हो आदि अगर हम क्षेत्र की पूजीगत लागत (x) माने व पूजी-उत्पादन अनुपात को (r) माने तो वार्षिक उत्पादन वृद्धि $= \frac{x}{r}$

Investment किसी समय विशेष मे विनियोजन की मात्रा (x) बराबर होगी, जिसमे हमे नवीनीकरण का व्यय (M) Modernization expenditure जोडना होगा तथा जिसमे $\pm$ Time Lag या पूजीगत व्यय को शुरू कर के समाप्त करने के अन्तर को adjust करना होगा.

तब Marginal capital-output ratio for a sector $=$

$$\frac{X+M+L}{\frac{x}{r}+P+D+S+W.}$$

(W. B. Reddaway, The Development of the Indian Economy, Homewood, 1962, p. 207-8.)

II. Main Characteristics and Features of C-Os. पूंजी-निपज अनुपात की विशेषताएँ :

पूजी-निपज अनुपात कभी स्थिर नही रहते भिन्न-भिन्न देशो मे पूजी-निपज अनुपात अलग-अलग रहते है कही वे अधिक होते है तो कही पर कम होते है—फिर एक ही देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रो में पूजी-निपज अनुपात अलग-अलग रहते है, इसके अतिरिक्त एक ही क्षेत्र, उद्योग व देश मे समयान्तर से यह अनुपात गिर जाते है या बढ जाते है

निम्नलिखित पृष्ठो मे उन तत्वो का वर्णन है जिनसे पूजी निपज अनुपात बढते या घटते है

पूंजी-निपज अनुपात किन परिस्थितियों में अधिक रहेगे :

निम्नलिखित परिस्थितियो मे पूजी-निपज अनुपात अधिक रहेगे पूजी-निपज अनुपात तब अधिक होता है जब पूजी अधिक लगती हो व उत्पादन कम होता हो

1 अगर देश मे भारी उद्योगो की स्थापना हो रही हो अथवा देश मे भारी Infra-Structure या वाह्य मितव्ययिताओ पर या आर्थिक-सामाजिक सिरो परि व्यय हो रहा हो (This is called lumpy investment also) तो पूंजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा.

2. अगर देश में विकास के लिए या किसी कारण (जैसे युद्धोपरात या बाढ व भूकम्प की बरबादी के बाद) मकानो, सार्वजनिक निर्माण व public utilities मे (सार्वजनिक सेवा उद्योग) मे विनियोजन हो रहा हो तो पूजी-निपज अनुपात अधिक रहेगे.

3 अगर देश मे कृषि के मुकाबले मे उद्योगो को तथा छोटे उद्योगो के मुकाबले मे बडे उद्योगो को अधिक महत्व दिया जा रहा होगा तो पूजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा

4. अगर किसी देश मे उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नही कर रहे है अर्थात् देश मे Excess capacity मौजूद है तो देश मे पूजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा इसीलिए मन्दी काल म पूँजी-निपज अनुपात अधिक रहता है.

5. अगर उद्योगो का फलदायक काल देर से शुरू होता है अर्थात् gestation period अधिक है तो भी पूजी-निपज अनुपात अधिक रहेगा.

6. अगर देश मे कर वृद्धि से, या मजदूरी वृद्धि से अथवा कच्चे माल की लागत

वृद्धि से पूजीगत वस्तुओं (मशीनो) की लागत व कीमत बढ जाती है तो पूजी-निपज अनुपात बढ जाएगा

7. अगर उत्पत्ति मे ह्रास नियम लागू हो रहा हो तो उपज कम होने से पूजी-निपज अनुपात बढ जाता है

8. औद्योगीकरण की शुरू की अवस्था मे पूजी-निपज अनुपात अधिक रहता है क्योंकि भारी उद्योगो मे धन लगाया जाता है परन्तु अगर विकास के साथ साथ पूजीगहन तकनीकें भी अपनाई जाती रही तो पूजी-निपज अनुपात घटेगा नही वरन् बढता ही जाएगा, जैसे U S A मे हुआ है U S A मे पूजी-निपज अनुपात इस प्रकार रहा है

1879	2.98 1
1884	3 01 : 1
1889	3 21 1
1894	3 59 1
1899	3 85 1
1950-59	5 3 1

8. अगर देश मे श्रम व सगठनकर्ता अकुशल* या कम कुशल है तो उत्पादकता कम होने से भी पूजी-निपज अनुपात बढ जाते है.

पूजी निपज अनुपात कब कम होते हैं ॰

पूजी-निपज अनुपात उस समय कम होते है जबकि पूजी कम लगे और उत्पादन अधिक हो इस प्रकार से जो परिस्थितिया ऊपर व्यक्त की गई है उनके विपरीत स्थितियों मे पूँजी-निपज अनुपात कम होता है सक्षेप म यह स्थितिया इस प्रकार है

1. अगर देश मे श्रम गहन तकनीक अपनाई गई हो.
2. अगर देश म सस्ती तकनीक अपनाई गई हो
3. अगर देश में उद्योग अपनी पूर्ण क्षमतानुसार उत्पादन कर रहे हो
4. अगर देश में श्रम उत्पादकता अधिक हो.
5. अगर उत्पादन मे उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा हो.
6. अगर उद्योगो का फलदायक काल शीघ्र शुरु हो रहा हो.

---

* विकास के साथ पूजी-निपज अनुपात बढेगा अथवा घटेगा, इस सबध मे पाठक Leibenstein के मॉडल मे पढ ही चुके है

7. अगर देश म नए साधनो का पता लग रहा हो.
8 अगर देश मे आन्तरिक व बाह्य मितव्ययिताए उपलब्ध हो
9 अगर देश में कृषि व छोटे उद्योगो में अधिक विनियोजन हो रहा हो तो देश मे पूंजी-निपज अनुपात कम रहेंगे.

III Importance of the Study And Use of Capital-output Ratios पूजी-निपज अनुपात के अध्ययन व प्रयोग का महत्व

पूंजी-निपज अनुपात का प्रयोग हम देश मे पूंजी निर्माण की मात्रा निर्धारित करने के लिए करते है. इनके निकालने में कठिनाइया अवश्य है परन्तु फिर भी इनके प्रयोग से हम अनुमानित विनियोजन से सम्भावित उत्पादन निकाल लेते है अल्पकाल में पूजी-निपज अनुपात बहुत अस्थिर रहते हैं परन्तु दीर्घकालिक आयोजन में हम इनका अच्छा प्रयोग कर सकते है.

सर्वप्रथम तो यह अनुपात हमको देश में आवश्यक विनियोजन की मात्रा आकने में मदद करता है. अगर किसी देश मे प्रति व्यक्ति आय $ 50 हो, जनसख्या वृद्धि 1.33 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो, बचतो की मात्रा राष्ट्रीय आय का 4% हो और पूंजी-निपज अनुपात 4 1 हो तो न्यूनतम विनियोजन की मात्रा जो कि अर्थव्यवस्था को उसी स्तर पर रखेगी 5.33% होगी

इसी मान्यता के आधार पर हम कह सकते है कि 2% विकास के लिए 20% तथा 5% विकास के लिए 40% विनियोजन आवश्यक होगा.

पूजी-निपज अनुपात मुख्यत पूंजी की सामाजिक उत्पादकता दर्शाते है. भिन्न भिन्न क्षेत्रों व उद्योगो के पूजी-निपज अनुपात के सम्भावित आकडो से हम भिन्न भिन्न उद्योगो या क्षेत्रो की पूंजी गहनता का अनुमान लगाते है. इससे हमको विनियोजन की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने में सहायता मिलती है

पूजी निपज अनुपातो के दीर्घकालीन अध्ययन से हमको भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता की प्रवृत्ति का पता चलता है (We can have an insight into efficacy of factor combination also). इस अध्ययन से हम यह भी जान सकते है कि उत्पादन के किन अगो की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए अथवा किनमें कमी की जानी चाहिए.

---

1 पूजी निर्माण के अध्याय मे भी आप C O. ratios के अध्ययन का महत्व पढ़ ही चुके है

ICOR (Incremental capital-output ratios) या वृद्धि पूंजी-निपज अनुपात का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनाना चाहिए बेन्जामिन हिगिन्स ने यह सावधानियां अपनाने को कहा है :

1 ICOR को निकालने के काफी समय के आंकड़े (कम से कम 5 साल के) मौजूद होना चाहिए अगर सभव हो तो एक सम्पूर्ण व्यापार-चक्र को इकाई मानकर ICOR निकालना चाहिए.
2. जिस काल के ICOR निकाले जा रहे हो वह "सामान्य काल" होना चाहिए अर्थात् न तो वह अधिक उत्पादकता या कम उत्पादकता या अधिक या कम लागत का काल होना चाहिए
3 यह ध्यान मे रखना चाहिए कि ICOR के आधार पर आयोजन के विनियोजन की मात्राएँ निर्धारित होती है तो स्वय आयोजन से ICOR भी परिवर्तित हो जाता है
4 ICOR का प्रयोग केवल पूजी की मात्रा को आकने के लिए करना चाहिए. इससे प्राथमिकताएँ निर्धारित नही करना चाहिए अर्थात् अधिक ICOR के कारण किसी विनियोजन योजना को नीची प्राथमिकता नही दी जानी चाहिए.
5. जहाँ तक सभव हो ICOR को बहुत सही निकालना चाहिए

सक्षेप में पूंजी-निपज अनुपात को हम किसी विनियोजन की लागत-लाभ अनुपात जानने के लिए पता लगाते है

IV. Limitations of the concept पूंजी-निपज अनुपात के प्रयोग की सीमाएँ

पूँजी-निपज अनुपात के महत्व पर लिखने वाले समस्त लेखक यह मानते है कि पूँजी-निपज अनुपात को सही रूप मे निकालना कठिन है और फिर इसके प्रयोग से बहुत अधिक महत्व के निष्कर्ष भी नही निकाले जा सकते.

U. N. O. की रिपोर्ट के अनुसार

> "यह अनुपात हमको यह नही बतला सकता है कि किसी एक विनियोजन से पूँजी-निपज के अनुपात के अनुसार ही उत्पादन होगा. यह अनुपात सह-सबध की प्रवृति ही बतलाता है कोई निष्कर्षात्मक सिद्धान्त नही देता." (The ratio does not imply a causal theory it indicates only a statistical association between investment and output.)

Dr D. Bright Singh का भी कथन है :

> "विनियोजन व उत्पादन में कोई निश्चित सरलात्मक सम्बन्ध नही है अगर पूँजी-निपज अनुपात से यह अर्थ निकाला जाए तो यह भ्रमात्मक है सही-सही पूजी-निपज अनुपात तो एक उद्योग के लिए निकालना ही कठिन होता है, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तो निकाल सकने का प्रश्न ही नही होता किसी देश मे इस प्रकार के अनुमानित पूँजी-निपज अनुपात से न तो पूजी की आवश्यक मात्रा और न ही उससे प्राप्त होनेवाली विकास-दर आँकी जा सकती है" (यह सम्पूर्ण विचार Nebulous नीहारिका समान है और अमाप्य है)

पूँजी निपज अनुपात को ठीक से न नाप सकने मे निम्नलिखित कठिनाइयाँ सामने आती है

1. सर्वप्रथम तो यह कठिनाई ही सामने आती है कि पूँजी की क्या परिभाषा ली जाए—वह व्यापक हो अथवा सकुचित हो बगैर इसको तय किए पूँजी की मात्रा ही नही निकाल सकते.
2. इसी प्रकार उत्पादन का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है बिजली के कार-खाने में लगी पूँजी से बिजली का ही उत्पादन नही होता वरन् उससे अप्र-त्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रो में भी उत्पादन बढता है, फिर उससे अन्य क्षेत्रो के उत्पादन और फिर अन्य क्षेत्रो का उत्पादन प्रभावित होता है, इससे किस विनियोजन का क्या उत्पादन रहा यह बताना कठिन हो जाता है.
3. 'समय' की समस्या भी महत्वपूर्ण है. सामान्यतया जो विनियोजन होता उसके प्रतिफलस्वरूप उत्पादन कुछ समय बाद होता है हर विनियोजन के फलदायक काल शुरू होने मे समय लगता है विनियोजन व उत्पादन के तीन रूप हो सकते है
   - (i) एक बार विनियोजन करें और उत्पादन निरन्तर होता रहे (Investment at a point of time with continuous production)
   - (ii) एक बार विनियोजन हो और एक बार उत्पादन हो. (Point input and point output).
   - (iii) निरन्तर विनियोजन हो व निरन्तर उत्पादन होता रहे. (Continuous investment and continuous production).

U. N O , "Economic Bulletin for Asia and the Far East", Nov. 1955, p. 26.

इस कारण यह समस्या होती है किस काल के विनियोजक का कौन सा उत्पादन माना जाए, सामान्यतया हम एक ही काल के विनियोजन व उत्पादन से पूँजी-निपज अनुपात निकालते है परन्तु ऐसा करें तो बहुत भ्रमात्मक परिणाम निकल सकते हैं जैसे जगल लगवाने पर पूँजी 1960-1961-1962 मे खर्च की जाए और उससे लाभ 1970-71 से मिलना शुरू हो तो वास्तव मे 1970-71 में समस्त उत्पादन के लिए उस वर्ष मे विनियोजन तो शून्य ही था और अगर उपरोक्त आधार पर पूँजी-निपज अनुपात निकालें तो परिणाम, जैसा कि जाहिर है, अति भ्रमात्मक होगा.

Kindleberger का कथन है

"When an economy undertakes all three types of investments ie. point input and point output investment, continuous input and continuous output and point input and continuous output, the capital-output ratio that relates this year's output to this years investment is evidently wide off the mark"

4 इसके अतिरिक्त पूँजी-निपज अनुपात ऐसे कारणो से भी परिवर्तित हो सकता है जिनका सबन्ध पूँजी से हो ही नही जैसे अच्छे मौसम के कारण भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना मे उम्मीद से अधिक उत्पादन हुआ और उस कारण योजना में तो पूँजी निपज अनुपात 3 1 सोचा गया था पर वास्तव में वह 2·1 ही रह गया.

इन्ही सब कारणो से पूँजी-निपज अनुपात के महत्व की सीमा है और इसी बात को हम George Rosen, Benjamin Higgins तथा Gerald Meier के शब्दो को उद्धृत कर व्यक्त कर सकते है.

C. P. Kindleberger · op cit p 103

He also says : "Capital output ratio is not useful for fine work. It's drawbacks include ambiguity over whether to take output net or gross, the problem of associating given outputs with given investment, whether by sectors or in time and disassociating simple growth based on capital investment from changes in output produced by changing technology, discovery of land etc"

George Rosen :

"कम पूंजी-निपज अनुपात स्वय मे कोई आकर्षक बात नही है जो विनियोजन के निर्णयों को प्रभावित करे कम पूंजी-निपज अनुपात को प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीक छोडकर पिछडी तकनीक नही अपनाई जा सकती."

Benjamin Higgins .

"इस पूंजी-निपज अनुपात का बगैर सोचे समझे प्रयोग नही करना चाहिए इसके आँकने मे भी बहुत सी कठिनाइयाँ है."

"The use of ICOR is beset by pitfalls which must be carefully avoided if serious errors are to be prevented"

Gerald Meier भी कहते है

"पूंजी व उत्पादन मे कारण व परिणाम रूपक सह सबध नही है हम यह भी नही कह सकते कि समस्त उत्पादन पूंजी से ही होता है. There are many conceptual difficulties and statistical pitfalls which surround the deviation and use of capital-output ratios."

V. Capital-Output Ratios in Developed and Under-developed Countries : विकसित व कम-विकसित देशो मे पूजी-निपज अनुपात .

पूंजी-निपज अनुपात विकसित व कम-विकसित देशो म कम रहते है या अधिक इस सबध में कुछ नही कहा जा सकता. कही पर यह अनुपात विकसित देशो में अधिक होता है (मुख्यतया पूंजी-गहन तकनीक अपनाने के कारण) तथा कही कम रहता है (मुख्यतया अधिक उत्पादकता के कारण) कही कम-विकसित देशो में उत्पादकता की कमी के कारण (कम पूँजी गहन तकनीक के होते हुए भी) पूंजी-अनुपात अधिक रहता है.

George Rosen : "Industrial Change in India" Asia, 1951, p 38.
B. Higgins - op. cit. p 652.
G. Meier : op. cit. p 101

निम्नलिखित तालिकाओ म इससे सम्बन्धित जानकारी देखी जा मकती हैं

1950–1959 के बीच कुछ देशो में ICOR

प्रथम श्रेणी के देश ($ 500 प्रतिव्यक्ति से ऊपर आय वाले)			
नार्वे	8 9	कनाडा	6 0
न्यूजीलैंड	7 8	बल्जियम	6 0
फिनलैंड	7 0	नीदरलैंड	5 3
डनमार्क	6 7	यू एस ए	5 3
ग्रास्ट्रेलिया	6 5	प जर्मनी	3 1
यू के	6 1		

द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के देश ($ 350 to 499 and $ 200 to 349 per-capita income)			
अर्जेन्टाइना	17 0	यूगोस्लाविया	3 2
पुर्तगाल	4 0	चिली	3 1
प्यूरटारिको	3 7	जापान	3 0
इटली	3 6	इजराइल	2 2
ग्रीस	3 3		

चतुर्थ श्रेणी के देश ($ 200 प्रतिव्यक्ति आय से कम)			
भारत	5 5	बर्मा	3 7
यू ए आर	4 8	इक्वडोर	3 0
रोडेशिया	4 2	द कोरिया/टर्की/फारमोसा	2 5
कोलम्बिया	4 2	ब्राज़ील	2 3
लका	4 0	इन्डोनेशिया/फिलीपीन्स/चीन	1 6

Eastern Economist, Annual No 1962

(B) सामान्यतया यह समझा जाता है कि कम-विकसित देशो में कृषि व अन्य क्षेत्रो मे कम पूजीगहन तक्नीक के कारण पूजी-निपज अनुपात कम रहेगा परन्तु निम्नलिखित तालिका को अध्ययन करें तो हम कोई निष्कर्ष नही निकाल सकते.

1946–47

उद्योग	भारत	आस्ट्रेलिया	कनाडा	न्यूज़ीलैंड
गेहूँ	1·83	1·31	·35	
फल व सब्ज़ी	1 44	74	·85	
शक्कर	1 49		·86	
पेन्ट व वारनिश	·38	·52	·74	·89
सीमेन्ट	1 75		3·97	·87
कपड़ा	·58		·67	
इस्पात	1·30		1·04	

भारत के सम्बन्ध मे पूजी-निपज स्थिति निम्न तालिका से देखी जा सकती है :

करोड रुपयो मे

	1948 के मूल्यों पर		तृतीय योजना में 1960-61 मूल्यो पर
	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	
1. योजना के शुरू मे राष्ट्रीय आय	8850	10480	14500
2 योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय	10480	12530	19000
3. वृद्धि (उत्पादन) (2–1)	1630	2050	4500
4. शुद्ध विनियोजन	3360	6750	10400
5. पूंजी-निपज अनुपात 4÷3	2 06	3·29	2·31